QUEDATESID GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj)

PORROWER'S

Students can retain library books only for two weeks at the most

No.		DUE DTATE	SIGNATURE
			!
	l		i
	1		ł
	1		1
	1		
	l		Y
	1		1
	1		
	1		l
	ì		i
	1		
	J		
	1		
	1		1
	1		1

भारतीय शासन ऋौर राजनीति

हाँ० जे० ए० एल० नोहा, एम० ए, एल एल० बी०, पी एव० डी० (विक्रम)

भारतीय शासन श्रौर राजनीति

Published by Madhya Pradesh Hindi Granth Academy under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and literature in regional languages at the University level, of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

भारतीय शासन ग्रौर राजनीति

डॉ० जे० ए० एल० नोहा, एम० ए०, एल एल० बी०, पी एच० डी० विभागाप्यक्ष एव प्राप्यापक, राजनीति विभाग, इन्दौर विश्वियत महाविद्यालय, इन्दौर, म० प्र०



ग्प्रृदेश हिन्दी ग्रन्थ ऋकादमी 🛭 मोपाल

मारतीय शासन ग्रौर राजनीति

प्रकासक

मच्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी। ६७, मालवीयनगर, मोपाल

©

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ झकादमी,

_

प्रथम संस्करण १६७३

भुल्य

पुस्तकालय सस्करण १२ रूपये ४० पैसे साधारण सस्करण १० रूपये ४० पैसे

> मुद्रक पर्वेतीय मुद्रणालय

१८ राय रामचरन दास रोड, इलाहाबाद-

प्रस्तावना

जनतत्र में बालिंग मात्र को मतापिकार प्राप्त है। वैचारित प्राम्ब्यिकि की स्वतन्नता के साम मिलकर इस निर्वाचनाधिकार ने प्रनेक राजनीतिक पार्टियों को स्रितित्व म ला दिया है स्रोर प्रत्येक दल को सविधान की सीमा के भीतर कार्य करने की पूरी स्वतत्रवा है। हमारा सविधान स्वय विरोधी पढा को न केवल सहत्त है, प्रत्येक सावत कार्य प्रहा भी मानता है। इस दृष्टि से हिमिन राजनीतिक विश्वासों भीर वादों के बीच चलने वाल मारतीय शासन के कई मनोरजक पहले हैं। डॉ॰ नोहा की पुस्तक इन सब पर प्रवास खालती है।

डा॰ जे॰ ए॰ एल॰ नोहा द्वारा लिखित ''मारतीय घासन ग्रीर राजनीति' बस्तुत मारतीय सविधान एव उसने प्रयोगात्मक पक्ष से सर्वन्यित ग्रन्य है। मारतीय

मारतीय सिवयान इंग्लैंब्ड घीर धमेरिका के सविधानों ने श्रेष्ठ घशी को सेनर बना है। ये सविधान कई सी वर्षी से परीक्षित भीर प्रयुक्त होते माये हैं। इंग्लैंब्ड का सिवधान को विश्व का प्राचीनतम सविधान माना जाती है। मनेव सागों को इस बात पर प्रापति है कि मारतीय सविधान किन्ही प्रत्य सविधानों का विश्वला। बनकर क्यों रहे। कमी कमी तो यह विरोध काकी प्रयुद्ध वर्ग की भीर

ताना न दुस बात पर अन्तरा हु तम नारतान वारतान न नहा का जान्यना न नार्या का जान्यना न नार्या का जान्यना न नार्या पिछला बनकर क्यो रहे । कमी कभी तो यह विरोध काफी प्रवादित का की भी र स जुतत के बनाये रखने का प्रयत्न निया पया है । इसम कोई किसी से घटकर नहीं है । किंचु कमी-कमी इतने बीच भी सधर्ष की स्थित प्रा जाती है। बैंको के राष्ट्रीयकरण और मुक्ती कानन के न्यायिक फैसती एव नदी योजना विवादी है इस

बात को भीर भी उजागर कर दिया है। जनमत के दवाब के कारण भी सविधान मे

सबीयन हुए हैं भीर स्वामाविक है, वि उससे सब पक्ष सबुष्ट । नही नोई सविधान स्वय पूर्ण नहीं होता और ने कोई वासन प्रणाली ही सबवा निर्दाष हो सबती हैं । फिर भी मारतीय बासन यथांत सबिधान और उसके उद्देश्य निम्नतम विवादा-स्वद प्रचलों को छूते हैं । देश के प्राया सभी राजनीविक स्त जनतम में विश्वास रखते हैं । पत्रसाला निर्वाचन वे मापदण्ड हैं जिनसे इन दलों की गक्ति और प्रमाव

रतते हैं। पत्तसाला निर्वाचन वे मापदण्ड हैं जिनसे इन दलो की वक्ति और प्रमाव का मूल्याकन होता रहता है। जनतत्त्रीय प्रपाली के प्रति समस्ति होने के कारण हो इस देश को स्वतन्ता के बाद स्थायो एव सुदृढ सरकार मिल सकी है। वायद भारत ही एक-माश विवासमान देश है जिससे व्यक्तिकारी राजनीतिक

परिवतन नहीं हुए ग्रीर न कमी कोई ऐसा ग्रान्दोलन हुग्रा, जिससे जनतंत्र की

नीव हिती हो, इस देश की परस्परा, विधान-निर्मातामी भी सूभ-तूफ, सावन खनानेवानों की व्यावहारिक दसता, जनता की सहित्युता मोर भाविष्मवा स्वावनाओं को व्यावहारिक दसता, जनता की सहित्युता मोर भाविष्मवा स्वावन्य विवाद के सुर काम. अर्थक देश को सैनिक बातन का स्वापन कर काम की सिन्क बातन की स्वापन का स्वापन कर स्वापन का स्वापन का

दुक्त संगाहित थे। स्तिल्य इस वेस में राज्यत का स्थान सेने के लिए प्रजानन को नरविल नहीं देने पड़ी।

मारतीय सवियान, केवल जासकोताया राजनीतिजी ने मार्गदर्शन के लिये ही
गही, बल्कि मारत के प्रत्येव नागरिक के विभिन्न-विषकारों की दृष्टि से भावस्थक
है। प्रश्चुत सम्प्रयम में, विवहर कीर्यक गारतीय जासन और राजनीति है, मारत
के सवियान के सर्वात सक्ष साथा राज्य सरकारों के स्वरूप साम्द्रन, प्रत्यासाधी के स्वरूप सम्प्रत्य, मार्गदायों के स्वरूप साम्द्रन, मार्गदायों की स्वरूप साम्द्रन, मार्गदायों की मारतीय करतात में प्रविचय दक्षे की यूनिका, नागरिकों ने मूल सविवारों, मारतीय जासन प्रदूष साम्द्रिक साम्द्रिक सहस्य साम्द्रक साम्द्रिक साम्द्रक साम्द्रिक साम्द्रक साम्द

तथापि, सह स्मरण रसला धाववयक होता वि मूलत' सारतीय सविनान के दायरे में ही, भविष्य में, भारत अगति वर सकता है और विवव वे बढे तथा समुद्रशाली राष्ट्रों के प्रप्ता उपित स्थान बना सकता है। यदि राष्ट्रीय प्रपति में स्वाबर्ट भाती हैं, तो जैसा हॉं वी ब्यार अम्बेटकर ने सवियान-निर्माण वे समय वहा था, इसवा वारण यह नहीं होगा कि सवियान बुद्दा है परन्तु यह वि भागत बुद्द हैं।

इन सब बातों के प्रकाश में यदि हम बर्तमान मारतीय शासन-पदि धीर राजनीति का प्रप्यत्म करें तो प्रतेशों मनोरोजक तथा सामने पांकी। डॉ॰ नीहां के सपनी हित में इन सब बातों पर खुले मन से विचार किया है। उनकी यह इति विकारियालयीन स्राध्यत्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगयान है।

y. 4. 2 922N)

(डॉ॰ प्रभुदयालु ग्रिग्तिहोत्री) संगलक मध्यप्रदेश हिन्दी धन्य ग्रहादमी

विषयानुक्रमणिका

	3103-0
₹.	मारतीय सविद्यान का निर्माण तथा उसके मूल सिटान्त
•	नागरिक्ता
3	नागरिको के मूल ग्रविकार
¥	राज्य नीति-निर्देशक तत्व

11 (1 (1)	
गरिको के मूल ग्रविकार	
ज्य नीति-निर्देशक तत्व	
_a ir maaram amrib	

7	(जिय नारत-ानदशक तत्व
7	नारत में ससदात्मक प्रणाली
3	गरत में संघवाद श्रीर संसदीय प्रजातत्र
,	விர சமீரகொ •—

मारत म संसदात्मक प्रणाला	
भारत में संघवाद श्रीर संसदीय प्रजातत्र	
सघीय कार्यपालिका :	
क—-राप्ट्रपति,	
2 2 6	

ও	सघीय कार्यपालिका:	
	र− -राप्ट्रपति,	
	खसधीय मन्नी परिपद	
_	च्लीग समय	

क— राष्ट्रपति,			
खसधीय मत्री प	रिपद		
सघीय ससद			
webr stringform	00 mma 3.	TT TT	

	लसधीय मन्नो परिषद	१३७
=	सघीय समद	१४३
3	संघीय कार्यपालिका एवं ससद के संबंध	850
0	मारतीय ससद में प्रतिपक्ष दल	२१४

= सघीय ससद	१५३
६ सघीय कार्यपालिका एव ससद के सबघ	१६०
० मारतीय ससद में प्रतिपक्ष दल	२१४
१. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय	२४३

भारतीय ससद मे प्रतिपक्ष दल	7
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय	२
राज्य-सरकार	२
	-

?	राज्य-सरकार		२६।
	वराज्यपाल ,	***	२६
	स्त्रराज्य-मन्नी-परिपद,		२७

	7 11-4 11/1,	•••	74
	स्त∽—राज्य-मन्नी-परिपद,		२७
₹.	राज्य-विधान मण्डल		₹=

१३. राज्य-विधान मण्डल	२≂५
१४. राज्य न्यायपालिका	300
१४. सघ तथा राज्य-सवध	301

१६. राज्य न्यायपालिका	30
१४. सघ तथा राज्य-सवध	30
१६ लीक सेवा ग्रायोग	३२

	7.5
सघतया राज्य-सबध	30
लोक सेवा ग्रायोग	75

. सघ तथा राज्य-सवध	७० ६
लोक सेवा ग्रायोग	३२७
सदर्मं प्रन्यो, पत्रो, पत्रिकाग्रो की तालिका	३३३

भारतीय सविधान का निर्माण तथा उसके मूल सिद्धान्त

स्वतत भारत वे सविधान वा निर्माण-वार्य विधीनेट मित्रा-योजा। वे धन्तंगत स्वतत्रता प्राप्ति वे नौ माह पूर्व धारम्म हो गया था। तिययान समा वे सदस्यो वा चुनाल, १६४६ म प्रान्तीय विधान-समामी द्वारा धानुपातिव प्रतिनिधिस्य यद्यति के आपार पर विचा गया। इस सविधान निर्मात्री समा मे कुस सदस्य-सह्या २६६ ची, जिसम वाग्रेस वे २०४, मुस्तिमतीय वे ७३ धीर १८ स्यतत्र प्रतिनिधि थे।

सविषान समा वा प्रथम प्रधिवेशन ६ दिसम्बर, १६४६ वो डा॰ सच्चिदान्द सिन्द्रा वी प्रस्थायी प्रध्यक्षता में सम्बद्ध हुमा । तदुवरान्त ११ दिसम्बर, १६४६ वो प्रधिवेशन म इस सविषान निर्मात्री समा वे स्थायी प्रध्यक्ष पे पर स्वर्गाय डा॰ राजेक्द प्रसार प्रासीन हुए । २२ जनवरी, १६४० वो सविषान समा वे प्रपत्ता चढ्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution) पारित विधा । यह प्रस्ताव प० जवाहरलावजी नेहर द्वारा प्रस्तुत विधा गया । इसमें सविषान निर्माणार्थ पांच सम्बर्गन्य उद्देश्य अपी की प्रोर सविषान निर्माणार्थ पांच सम्बर्गन्य उद्देश्य अपानुसार इस प्रकार ये —

१—मारत म स्वतंत्र एव सार्वभीम गणराज्य की स्थापना भीर भपना सविधान निर्माण करना ।

२ — भारतीय सघ एव सघ भी इनाईयो (राज्यो) मे समस्त सार्यमोम सत्ता वा स्रोत जनता होगी ।

३---भारत ने समस्त निनासियो को (1) सामाजिन, मार्थिय तथा राजनीतिक न्याय (11) पद, प्रवतर एव वानून ने समक्ष समानता तथा (111) विचार, भाषण, म्राभिव्यक्ति भीर विकास रखने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

४-- ब्रत्यसरयना, पिछडे वर्गो सया बनुसूचित जातियो मे हिनो मी रक्षा मे सिए व्यवस्था नरना। गया था, विन्तु इसमें भारत के सभी राजनीतिक दलो, वर्गी तथा विभिन्न हितो ना पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। भारतीय रियासतो ने भी प्रतिनिधि इसम सम्मितित विषे गय थे। इसने धतिरिक्त, चूँगि वेवल भाग्नेस ही एन राष्ट्रीय दस था, धौर नाग्नेस नो सविधान सभा के २६६ सदस्यों में से स्पष्ट बहुमत (२०४ स्थान) प्राप्त हुना था, यह वहां जा सनता है नि माग्नेस द्वारा सविधान-समा म राष्ट्रीय हितों ना व्याप्त प्रतिनिधित्व था। अत्वर्ष, सविधान-समा ने जो सविधान पारित क्या, उसने एक लोनतात्रिक सविधान माना जा सकता है।

य—यदि सर्विधान की प्रस्तावना के पहले ग्रीर ग्रन्तिम वास्यों के उपयुक्त ग्रंबों को बोडा जाये, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि न्यय सिवयन की प्रस्तावना में इस विषय पर बल दिया गया है कि सिवयन बास्तव में जनतात्रिक है। प्रस्ता-वना के पहले बावय का उपयुक्त हिस्सा है — 'हम ग्रारत के लोग', भीर प्रन्तिम वायव का उपयुक्त हिस्सा है, — 'इस सविधान को स्वीष्टत, निर्मित एव प्रास्माणित करते हैं, यदि इन दोनों हिस्सों को साथ-साथ जोडा जाये तो पूरा वावय इस प्रवार होगा '—

'हम मारत के लोग इस सविधान को स्त्रीष्टत, निर्मित एस धात्मापित करते हैं।' दूसरे शब्दों में, भारतीय-सविधान मारतीय जनता का, जनता के लिए, जनता (जनता के प्रतिनिधियों) द्वारा निर्मित सविधान है। यह भारतीय जनता की सार्वभीक्वता को प्रतिविध्यत करता है। धमरी-सविधान की प्रस्तावना के सार्वभीक्वता के सो से तक्षत में भी लगम ऐसे ही गब्दों का प्रयोग किया गया है। धमरिका के सविधान के प्रसावना के कार्यम में ये खब्त हम प्रवाह है:—

'हम अमरीना ने सोम', एव प्रन्त मे 'इस धमरीनन सविधान नो निर्दिष्ट एव स्वापित नरते हैं'। अमरीनी सविधान नी प्रस्तावना ने इन दोनो मागो नो जोडा जाये तो बानय यह होगा :—

'हम ग्रमरीना ने' लोग, इस ग्रमरीनी-सविधान को निर्दिष्ट एव स्थापित न रते हैं। ग्रत स्पष्ट रूप से यह ग्रमरीनी-सविधान ने लोनतात्रित्र स्वरूप का सूचन है।

इसने श्रतिरिक्त, भारतीय-संविधान द्वारा नागरिनो को वयस्क मताधिनार दिया गया है, भौर प्रत्येक नागरिन को ससद या निसी राज्य-विधान सम्रा ने लिए उम्मीदवार के रूप में, चुनाव लडने का भी श्रधिनार है।

सविधान के प्रध्याय तीन में मारत के नागरियों के सात मूल प्रधिवारों का उल्लेख है। वे प्रधिवार हैं—(१) समानता का प्रधिवार, (२) स्वतप्रता का प्रधि-वार, (३) भोषण ने विरुद्ध प्रधिकार, (४) धार्मिय स्वतप्रता का प्रधिकार, (४) सम्पति वा प्रधिकार, (६) सास्त्रतिय तथा शैक्षणिक प्रधिवार धीर (७) सर्व- थानिक उपचारो का ग्रधिकार । इन ग्रधिकारो से मारत में राजनीतिक लोकतंत्र ना ग्राप्तासन प्राप्त है।

सविपान के ग्रध्याय चार में विभिन्न ग्राधिक सिद्धान्तों का उल्लेख है, जिनको राज्य-नीति निर्देशक तत्वी की सज्ञा दी गयी है, क्योंकि भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अपने कार्यों में इन सिद्धान्तों के मार्ग दर्शन में चलना आवश्यक है। इनका उद्देश्य मारत में ग्राधिक लोकतत्र की स्थापना करना है, जिसमें किसी भी नागरिक के साथ सामाजिक तथा शायिक श्रन्याय नहीं होगा ।

सक्षेत्र में, संविधान न केवल स्वय सोवतात्रिक है किन्तु इसका उद्देश्य मारत में सोवतंत्र की मीत्र को शक्तिशाली करना है।

प्रस्तानना में इस विषय पर बल दिया गया है कि संविधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य मारत में एक सार्वभीम लोकतवीय गणराज्य की स्थापना करना है। 'सार्व-भौम' रुप्द का प्रमोग किया जाना इस दान का द्योतक है कि मारत के ग्रान्तरिक तथा बैद्रशिक मामलो म भारत सरकार सार्वभीम तथा स्वतंत्र है। 'लोकतन' राष्ट्र का प्रयोग इस बात का द्वीतक है कि मारतीय-सविधान के अन्तर्गत सार्वनीमिकता बनता में निहित है। मारतीय बनता का, बयाक मनाधिकार के आधार पर अपनी इच्हानुगार सरकार-निर्माण करने का स्वतंत्र ग्रविकार है, जो ग्रान्तरिक तथा बाह्य दोनो मामलो मे पर्णनवा सार्वमीम तथा स्वतत्र होयी ।

'गणनव' हाज्य का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालवा है, कि दो प्रकार को लोक्तवीय ध्यवस्थामी-कानुबत सीक्तव तथा सीक्तवीय गणनव. मे से मारतीय-मवियान के प्रत्यांत लोकतशीय गणनत को धारताया गया है।

बंगानगत लोकतव के बन्दर्गत राष्ट्राध्यक्ष किसी विशिष्ट क्या का होता है, वो प्राना पर बंगानुषत सिद्धान ने प्राचार पर प्राप्त बरता है, हिन्तु राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वह केवल नाममात्र का शामक होता है। उदाहरण स्वरूप इंगलैंग्ड में सबैधानिक-राजनन मा लोकतानिक-राजनन है, क्योंकि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष (सम्राट था मम्राज्ञी) को भ्रमना पद बशानुसन प्राप्त होता है।

नोक्तवीय-स्पत्त में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन जनता द्वारा प्रायक्ष या भप्रत्यक्ष रूप में विचा जाता है, अर्थात बादाजिक राज्य में राष्ट्राध्यक्ष को धपना पद जनता द्वारा उसके निवांवन के एउ स्वरूप ब्राप्त होना है। एदाहरण स्वरूप समरीका एवं नारत म राष्ट्राज्यस्य का निर्वाचन जनता करती है। सतएवं मारत तथा मनरीका दोना नगराविक-राज्य है।

भारतीय-संविधान की प्रस्तादना म तथा संविधान के प्रध्याय तीन में धर्म-निरदेश राज्य के मिद्धाना पर ग्रंप यक्ष रूप में बन बिया गया है। प्रस्तावना में मारत ने समन्त नागरिनो नी विभिन्न प्रकार भी स्वत्यताको एक प्रकार दाला गया है।

पर्य-निर्देश राज्य के सन्दर्भ में, प्रस्तायना म उल्लेगिन नागरिय में विश्वास, सर्म तथा उपातना सम्बन्धी स्वतना को प्रमान परना प्रावयण है। इसी प्रकार, मिवान के प्रस्थाय तीन प्रमुच्येद २५, २६, २६, २२ और २६ अपने प्रकार, मिवान के प्रस्थाय तीन प्रमुच्येद २५, २६, २६ अपने रच अपने मारात म सभी व्यक्तिया ने पामिन स्वतना प्रवता प्रदत्त भी है। इसी प्रवार समानता के मूल प्रविवार से सन्दर्भ में साविवान में यह प्रावयान निया गया है कि राज्य नागरियों ने मध्य पर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी प्रापार पर मेदमान नहीं करेगा। पर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, या इनमें से किसी प्रापार पर मेदमान नहीं करेगा। पर्म, जाति, लिंग, जन्मवान ने नारण किसी नागरिय को साविवार प्रवार नहीं करेगा। पर्म, जाति, त्रिन, जन्मवान ने नायेपा। मौतियान साविवार प्रवार मार्ग के स्वतन वे उत्योग से नहीं रोगा ज्येपा। प्रवाणित तथा सावहरिता प्रविकार के धन्तर्गत प्रविकार प्रवत्त प्रवत्त प्रवत्त स्थान के स्वतंत्र तथा प्रवत्त प्रवत्त स्थान के स्वतंत्र स्थान प्रवत्त प्रवत्त स्थान के सुरक्षित रसने का तथा स्थानित स्थायों के स्थापित वरते ना प्रविवार है।

वस्तुन प्रस्तावना धौर सविधान के प्रध्याय तीन में, भारत में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों को, जो धार्मिक स्वतन्तता का धिषकार प्राप्त है, उसको मारत में धर्म निरपेश राज्य का ठीस घावार माना जा सवता है, क्योंकि धर्मनिरपेश राज्य की सजा उस राज्य को दी जा सकती है, जितमें सभी व्यक्तियों का समान क्य से धार्मिक स्वतन्तता का घिषकार उपलब्ध है, प्रवीन, राज्य की वृद्धि मसमी धर्म समान है धौर सार्वजनिक मामको ना सवालन किसी विजिध्द धर्म के सिदालानुमार न वर सोकनादिक सिदालों पर किया जाये।

मारतीय सर्विधान की प्रस्तावना में तथा सिंवधान के घटवाय चार में, जिसमें विमन राज्य-गिति-निर्देशक तहवों ना उल्लेस हैं, लोग-गटबाजनारी राज्य का विचार दृष्टिगोचर होता है। दूसरे घट्टो में, मारतीय निवधान के ग्र-तर्मन लोग करा-जनारी राज्य के सिंदाल को मानवता दी गई। मान-जीवन के सामाजिक, माधिक, राजनीतिक, एव घामिक पदा महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य के ब्यविद्य के सर्वाभिक राजनीतिक, एव घामिक पदा महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य के ब्यविद्य के सर्वाभिक विकास हेतु उत्तकों जीवन के इन समी महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए मुख्य पएँ उत्तक्ष्य होनी चाहिए। लोक-चल्याजगरी राज्य का प्राविधिक उद्देश हैं कि मानव-जीवन के इन सहत्वपूर्ण पहलुओं से सर्विधान समस्त मुद्रवाधों के लिए प्राविधान करें, जिससे ब्यविद्य का पहुँचुती विकास हो सर्व।

मारतीय-सविधान नी प्रस्तावना में समस्त नागरिकों वो सामाजिन, राजनीतिन, तया प्राविष्ठ न्याय का प्राव्यसन दिया गरा है। मारत ने नागरिकों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में न्याय का प्रार्थासन दिया गया है। नागरिकों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में न्याय उपलब्ध करने के लिए सविधान में विधिष्ट सामनो

भारतीय शासन भौर राजनीति का उल्लेख है। सामाजिक न्याय का अर्थ है—समी नागरिको को सामाजिक क्षेत्र

में समान प्रविकार प्राप्त हो ।

(१) सामाजिक न्याय का ग्रास्वासन, जो सविधान की प्रस्तावना द्वारा दिया गया है, नागरिको ने समानता ने मूल ग्रविकार पर ग्रावारित है, जिसके प्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बानून के द्वारा समान शरक्षण का ग्रविकार प्रदत्त किया गया है। इसके प्रतिरिक्त, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वश, जाति, लिंग, जन्म स्यान ग्रथवा इनमें से विसी भी ग्राधार पर भेदमाव नहीं वरेगा। इसी प्रकार विसी भी नागरिक को केवल धर्म, वश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान, भ्रथवा इनमें से क्सी एक ग्राधार पर, (क) टूकानो, सार्वजनिक मोजनालयो, होटलो, ग्रीर सार्वजनिक मनोरजन के स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जायेगा; (स) पूर्ण या आधिक ब्राह्मर पर राज्यनिधि द्वारा बने हुए या जनता के लिए बनवाये गये कृत्रो, तालावो, स्नानघाटो, सडको तथा सार्वजनिक स्वानो के उपयोग करने से नहीं रोका जायेगा।

समानता के प्रधिकार के धन्तरांत प्रत्येक नागरित को राज्य के धवीन किसी मी पद पर नियुक्त किये जाने के लिए समात अवसर प्राप्त होने और किसी भी नागरिक के साथ धर्म, बन्ना, आति, लिंग, उत्पत्ति या जन्म स्थान ग्रयवा इनमें से किसी भी कारण से भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

समानता के ब्राधकार के ब्रन्तगैत सामाजिक न्याय उपलब्ध करने के लिए यह भी प्रावधान क्या गया है कि महमूखना का मन्त कर दिया गया है और जो व्यक्ति ग्रस्पृत्यता से उलक्ष विभी प्रयोग्यता को लागू करता है, वह दण्ट का पात्र होगा ।

(२) राजनीतिक न्याय का अर्थ है, सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में समान प्रधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक न्याय का स्नाव्यासन प्रस्तादना म दिया गया है; इसके व्यावहारिक स्वरूप मुख्यत दो झामारी पर धवतम्बित है। ये झाधार हैं-

(व) नागरिको के विभिन्न मूल मधिकार, विशेषकर, स्वत्त्रता, तथा सवैधानिक उपचारों के ग्रधिकार ग्रीह

(स) प्रत्येक मारत ने नागरिक को दयस्क मताधिकार के सिद्धान्तानुसार

मत देने के ग्राधिकार। संशेष में मारत के प्रत्येक नागरिक को ग्रपने दिचारों की प्रमिञ्जन्ति करनः सगदन बनःना ।

भारतीय प्रदश ने एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने तथा ग्रथनी प्रमन्द के

प्रत्यामी के लिए मन दने की स्वनवना है। (३) माधिर न्याय रा बर्च है, कि बार्षिक क्षेत्र म सभी नागरिको को समान

मधिकार तथा मनसर प्राप्त हा। भारतीय नागरिको को को मार्थिक न्याय को माश्वासन सविधान की प्रम्तावना में दिया गया है, उसके क्रियान्वयन हेनु सविधान

में तीन भाषार है।

- (क) समानता दे प्रधिकार दे प्रतर्गत प्रत्येव नागरिव दो राज्य के प्रधीन पद प्राप्त करने हेतु समान प्रधिकार प्राप्त है।
- (स) स्वतंत्रता के प्रधिवार के प्रन्तगत प्रत्येव नागरिव को किसी भी अवसाय, वृत्ति व्यापार तथा घ वा करने की स्वतंत्रता है।
- (ग) सविधान के प्रत्याय चार म मतिषय राज्य नीति निर्देशन तत्वा वा उद्देश्य देश म प्रत्यक नागरित को प्राणिक न्याय प्रदस्त करना है। उदाहरण स्थरूप य राज्य नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार हैं —

१-समस्त नागरिका, पुरयो तथा स्त्रियो को ध्रपनी पर्याप्त जीविका ध्रर्जन करने का ध्रीयकार है.

करने का प्रधिकार है, २–समाज के भौतिक साधनो का स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस प्रकार वितरित

हो जिससे सामा य रूप से जनहित समव हो, ३-देश की ग्राविक व्यवस्था का सचालन इस प्रकार न हो, जिससे घन का

के द्रीय करण होते हुए सामा य हित वो हानि पहुँचे, ४-परण तथा हत्री को समान कार्य वे लिए समान वेतन प्राप्त हा,

प्र-श्रमित), (पुरप एव स्त्रो) श्रीर कम श्राप्त के वालनो ने स्वास्त्य तथा शस्ति का शोषण न ही श्रीर नागरितो नो अपनी श्रापिक श्रावस्त्वनताशा मी पूरा करने के लिए उननी श्राप्त तथा शनिन ने दृष्टिकोण से श्रनुप्युक्त व्यवसायो म प्रवेश

होने के लिये वाध्य न होना पड़े, ६-वचपन एव युवायस्था का शोयण न हो,

६-वजपन एवं युवावस्था का आयण न हा, ७-राज्य थम एवं प्रसूति सहायता से संवधित शर्तों को मानवीय स्वरूप प्रदत्त

करने के लिए प्रावधान करेगा,

द-राज्य अपनी आर्थिन क्षमता के दायरे मे नागरिको ने लिए नौकरी, शिक्षा, एव वृद्धावस्या, योमारी एव वेरोजगारी की स्थिति मे सावजनिक सहायता करेगा,

६-राज्य बानून या धार्षिक सगठन द्वारा समस्त श्रमिको को (इपि उद्योग, या ग्राय कार्यों से सम्रिक्त) उपयुक्त कार्य, जीविका, एव कार्यों की शर्तों के लिए प्रावधान करेगा, जिससे जीवन का उत्तम स्तर स्वाधित हो।

१०-राज्य नघु उद्योगो को प्रोत्साहित करेगा।

११~राज्य विशेष रूप से पिछड़े वर्गो तथा प्रनुसूचित जातियो ने शैक्षणिक तथा श्राधिक हितो वा सरक्षण करेगा।

उपर्युक्त राज्य-नीति निर्देशन तत्त्रों को सविधान में स्थान इसी उद्देश्य से दिया गया है जिससे भागरिकों को धार्थिक न्याय उपलब्ध हो सके। ये ही तत्त्व धार्थिक न्याय के घाषार हैं।

(४) राज्य-नीति निर्देशक तत्थो का महत्व भारतीय सविधान मे दिसम्बर, १६७१ मे २४ वें संशोधन से और प्रधिन बढ गया है। संशोधन के दूसरे भाग मे भारतीय शासन धीर राजनीति

यह प्रादचान निया गया है कि यदि किसी कानन में यह लिखा है कि उसका उद्देश्य किसी राज्य-तीति निर्देशक सत्व का क्रियान्वय करना है और यदि उस कातन का संघर्ष किसी मूल अधिकार से हैं, तो उक्त कानून को अबैध नहीं ठहराया जा सकता है। यदि इस प्रकार के कानून का उद्देश्य सामान्य हिनों के दिष्टिकोण स सायिक न्याय उपलाच करना होगा तो वास्तव में यह एक प्रगतिशील कदम माना जायेगा ।

समेप में, सविधान की प्रस्तावना में, सविधान के इस मूल सिद्धान्त का जन्तेल है कि मारत एवं लोक कल्याणकारी राज्य होगा जिसम प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, श्रायिक एव राजनीतिक न्याय उपलब्ध होगा ।

(५) प्रस्तावना में सर्विपान के एक ग्रन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्त का उल्लेख है। वह यह है कि इसमें राष्ट्रीय एक्ता पर बल प्रदान किया गया है। भाषा, धर्म ग्रादि की विविधना के होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है। इस सदमें में, प्रस्तावना का महत्व इसलिए प्रतिक हो जाता है कि इसमे उन दो विशेष घाषारो पर बल दिवा गया है, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एनता दढ होती है !

सर्वप्रयम, प्रस्तावना में व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा महत्व पर बल दिया गया है। व्यक्ति को, लोकतत की एक महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए, राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण आधार माना है। राष्ट्रीय स्वामिमान की भावना की जायुति, व्यक्ति के स्वामिमान की मावना से सवियत है। परन्त व्यक्ति के स्वामिमान की भावना राज्य एव समाज में, उसके महत्व को स्वीकार करने पर निर्भेर है। यदि राज्य तथा समाज म व्यक्ति का उसकी उदिन प्रतिष्ठा तथा ध्रविकार प्राप्त है, यह स्वामाविक है कि नागरिक के एवं म देश के प्रति उसकी धास्या बनी रहेगी धीर इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय मावना तथा एकता दद्र होगी।

दितीय. एक उपसिद्धान्त के रूप म यह भी कहा जा सकता है कि समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं ग्रीवकारा की स्वीकृति, राज्य तथा समाज म नागरिनों ने मध्य बम्दव या सौहाद नी भावना प्रश्वितन करेगी. जिससे राष्ट्रीय एनता दृढ होगी ।

इन दो माधारो पर सर्वियान निर्मातामा ने राष्ट्रीय एकता को दृढ बनाने का धारवासन दिया है।

उपर्युक्त पाँच सिद्धान्तो ने अतिरिक्त जिन पर सर्वियान की प्रस्तावना मे प्रकाश बाला गया है, कतिपय निद्धान्तों को स्वय सविधान में चन्लेखिन विधा गया है। मुख्यत यह सिद्धान्त मारतीय संधीय व्यवस्था सरकार एवं सिविधान के स्वरूप से सद्यापत है। इनका सम्ययन विस्तृत रूप से सगले सम्याया में किया जावेगा, जिन्तू यहाँ पर इनका उल्लेख सभेप म किया जा सकता है।

£

सर्वप्रयम, सविषान ने धनुरुदेद १ वे धनुसार भारत एन सप (सूनियन) है। भारतीय-सविदान में सपबाद ना सिद्धान्त प्रधनाथा गया है, वयोषि इसम राज्य नीतीनो धावश्वनताएँ निहित है, जो ये हैं १-निस्तित सविषान, २-नाधीय तथा राज्य सरकारों के मध्य शनिवयों ना विमाजन, २-मध्य प्रीर राज्य सरकारों ने मध्य शनिन विमाजन, सविषान में उल्लेनित तीन सूचियों (प्र-यम मूची, व-राज्य सूची धीर सन्तमतर्ती सूची) ने आधार पर चिया गया है।

सपीय मूची मे ६७ विषय है, जिन पर सय सरवार वा क्षेत्राधिवार है। राज्य मूची मे ६६ विषय है, जिन पर, साधारणतथा राज्य सरवारो वा क्षेत्राधिवार है। सावर्ती सूची मे ४० विषय है, जिन पर सथ तथा राज्य सरवारो वो विषि निर्माण ने लिए तमवर्ती अधिवार प्राप्त है, निन्तु यदि इस सूची मे उल्लेखित निसी विषय पर सचीय भीर राज्य वानृत मे सध्य है तो सथ वानृत वो हो मान्यता दी जावेगी। प्रतण्व यह स्वष्ट है कि सधीय सरवार वो राज्य सरवारो वी प्रवेशा प्रयिव सन्तियाँ प्राप्त है। इसके प्रतिरिक्त, वितयय, विशेष परिहि बतियों मे सवीय सरकार वो भीर प्रयिव सविवार, वो राज्य सूची से सविषय हैं, प्राप्त हो जाती है। इनवा उल्लेख स्वय्य भव्याय मे निया गया है। प्रत. सपीय वियोषताओं ने होते हुए भी मारतीय सविवार में एकारस प्रवृत्तियाँ निहित हैं। परन्तु मारत वा सविधान मुख्यत सघीय सिद्धान्त पर प्राधारित है।

द्वितीय, सररार के स्वरूप के दृष्टिकोण से मारतीय सविवान के अन्तर्गत सवस्तान पद्धित मो अपनाया गवा है। ससदात्मक पद्धित में वार्यपालिना के दो प्रराद होते हैं, नाममात्र को कार्यपालिना को दो प्रराद होते हैं, नाममात्र को कार्यपालिना को रूप में प्रति है। मनी मण्डल का सामूहिक रूप से सबद के निचले सदन के अपने प्रति हो। सनी मण्डल का सामूहिक रूप से सबद के निचले सदन के अतु उत्तरदावी होना ससदात्मक पद्धित का प्रति सिद्धान्त है। मारतीय-सविवान के अनुच्छेद ७४ उपवन्य (३) मे इस सिद्धान्त को मान्यता दो गई है। सब के समान राज्यों के मनी मण्डल मी अनुच्छेद १६४ (४) के अनुसार सामूहिक रूप से राज्य विवान-सामा के अति उत्तरदायी है। अतः यह सब्द है कि मारतीय-सविवान के अन्तर्यंत्र ससदारमक पद्धित को अपनाया या है।

तृतीय, सिवपान के सशोधन के दृष्टिकोण से मारतीय-सिवधान ना स्वरूप कुछ मात्रा में नमनीय है भीर कुछ मात्रा में कठोर। मारतीय सिवधान के विभिन्न प्रावधानों में सबोधन के दृष्टिकोण से उन्हें तीन मागों में विमाजित निया जा सरता है। प्रतिष्ट मार्ग में उन्हें तिन सिवधान के प्रावधानों ने सबोधन के तिए एन पृथक सबोधन प्रणाली है। सिवधान के ये तीन मार्ग निम्ना-नृतार हैं.— 80

कर सकती है, सब के किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकती है; सब ने किसी राज्य के क्षेत्र में क्मी या बद्धि कर स्वती है, एवं किसी भी सुध राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। नागरिकता सबबी प्रावधानों में भी ससद को संशोजन करने का एकाधिकार है। यदि संघ के किसी राज्य में उच्च सदन है किन्तु प्तनी आवश्यनता नहीं है तो राज्य नी विवान-समा के अनुरोध पर ससद सर्विधान में प्रावश्यक संशोधन कर सकती है। प्रतिएव उपयुक्त विषयो पर सर्विधान में सरलता से सहोजन किया जा सकता है।

(ख) द्विनीय धेणी में सविधान के कतिषय विशिष्ट प्रावधान हैं, जो बास्तव में सथ एवं राज्यों, दोना से संबंधित हैं। इनके संगोधनों के लिए संगोधन विधेयन को दो चरणा का पार करना होता है। सर्वप्रयम, संशोदन विषेयक को ससद के विसी मी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ससद के प्रत्येक सदन में विधेयक को सदन की कुल सरमा के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में हिस्सा लेनेवाले सदस्यों के दो तिहाई बहमन से पारित किया जाता आवस्यक है।

हिनीय, मसद द्वारा उपर्युक्त प्रक्रियानुसार जब विधेयक पारित हो जाता है तो वह दूसरे चरण मे प्रदेश करना है, जिसमें उत्तन मजोधन विधेयक को सम के राज्यों में से सम से सम ग्राये राज्या के विजान-मण्डला द्वारा स्वीकृति मिलना चाहिये । तन्त्रश्वात् राष्ट्रपति की सहमति से सविधान म झावश्यक संशोदन लागू होगा । मविपान संशोधन की यह प्रतिका सविधान के उन विकास प्रावधानी के लिए बावश्यक है, जो निम्नात्रित विषया स सब्धित है।

१--राष्ट्रपनि का निवाचन (अनुन्धेद ४४) २--राष्ट्रपति भी निर्वासन-प्रणाली (ग्रजुन्हेद ४४)

२—मघ की कायपालिका शक्ति की सीमा (ग्रनुच्छेद ७२)

Y-मन व राज्या की कार्यपालिका शक्ति की मीमा (प्रमुख्टेद १६२)

१-नन्द्र-प्रशामित क्षेत्रा क लिए उच्च न्यापाउथ (धन्च्छेद २४१) ६—मधीय स्टावपानिका ।

अन्मध के विभिन्न राज्यों में उच्च स्यायासय ।

५-सप एव राज्या के व्यवस्थापन सबयी प्रावधान (सातवी धनुमुची में सप, राज्य एवं सनवर्ती मुनियाँ।

६—मनद भै साम्यो का प्रतिनिधिन्त ।

१०—मंदियान के मंत्रीयन की प्रक्रिया, जो बहुक्केंद्र ३६० में *निहित है ।*

भारत के सविधान ने उपर्युक्त प्रावधानों ना संशोधन करने की प्रश्निया जटिल है जिसके फलस्वरूप इन प्रावधानों को कठोर माना जा सकता है ।

(ग) तृतीय श्रेणी में सिवधान के वे समस्त प्रावधान रसे जा सनते हैं जो प्रथम दो श्रेणियों में नहीं हैं। इनने संशोधित करने के लिए समद में किसी सदन में संशोधन के लिए विधेयक को प्ररुप्त किया जा सकता है। समद के प्रत्येव सदन में विधेयक को सदन की बुत्त सदस्य सरदा के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में विधेयक को सदन्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तत्वकात, राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर विधेयक पारित माना जायेगा, और सविधान में आवश्यक सिश्चित की सहमति मिलने पर विधेयक पारित माना जायेगा, और सविधान में आवश्यक सिश्चित की सहमति होगा। यह प्रत्रिया घोडी जटिल है वयोंकि यह साधारण विधि-निर्माण प्रक्रिया से मिश्न है।

सक्षेत्र में, सविधान के विभिन्न प्रावधानों में सशीधन के सन्दर्भ में गह क्या उचित है कि भारत का सविधान कुछ मात्रा में नमनीय है, तथा कुछ मात्रा में कठोर है।

चतुर्यं, प्रारत ना सर्वियान लिखित होने के साय-साथ देश ना सर्वोच्च नानृन है। प्रमरीकी सवियान ने सद्या प्रारतीय सवियान नो मूल नानृन तथा साधारण नानृनो नो फिप्तता के सिद्धान्त के सन्दर्भ में, देश ना सर्वोच्च या मूल नानृन माना या है। प्रसरीकी सदियान में प्रतुच्छेद ६ के प्रन्तमंत सवियान ने देश ने सर्वोच्च नानृन नी सत्ता दो यई है, निन्तु भारतीय सवियान में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि पारतीय सविधान में नागरिन के मूल प्रियंकारों एव सपवाद नो भाग्यता देने के प्रसदस्य सविधान स्वत देश ना मूल कानृन (सर्वोच्च नानृन) हो जाता है, जिसके सरकाण ना दाधिरत न्यायपिनिना के नन्यो पर है। प्रस्य प्रव्याम में प्राप्त विस्तृत प्रकाश दाला गया है।

नारतीय सविधान की प्रस्तावना एवं सविधान के ग्रन्य प्रावधानों के ग्रष्ययनोपरान्त हम सविधान के ग्रधीलिखित उल्लेखनीय सिद्धान्ती का ग्रामास होता है .--

१—मारन के सिवधान वा स्वरूप लोच तत्रतासक है, क्योंनि न केवल इसका निर्माण जनतात्रिक पद्मितनुसार किया गया है, ग्रपितु इसके ब्राधारभून सिद्धान्त मी जनतात्रिक है।

२—मारत के सविधान के प्रन्तर्गत मारत को एक सार्धभौम लोकतशीथ गण-राज्य के रूप मे प्रगीकृत किया गया है ।

रे—सर्विधान के अन्तर्गत एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। ४—भारतीय सर्विधान लोक-कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्तो पर आधारित है।

४—मारतीय सविधान द्वारा राष्ट्रीय एकता के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है ।

\$ 2 भारतीय शासन धौर राजनीति

६-मारतीय-सविदान में संघवाद को मान्यता देने के साध-साथ कतिपय एकात्मक प्रवृतियों को भी स्थान दिया गया है। ७-- भारतीय-सविधान के धन्तर्गत संयीय एवं विभिन्न राज्य-सरकारें, सस-

दात्मक पद्धति के सिद्धान्त पर बाघारित हैं।

 मारत के सविधान में नमनीय एवं कठोर संशो का समावेश है। ६-- नारत का सविधान लिखिल होने के साथ-साथ देश का मूल या सर्वोच्च

कानुन है।

नागरिकता

१६४७ मे मारत के दो सार्वभीम देशों से विमाजित होने के कारण, मारत तथा पाकिस्तान में प्रापिक वडी सध्या में नागरिकों का देशातर हुमा । प्रतएव मारतीय सविधान निर्माशाओं को भारतीय नागरिकता नी परिभाषा को निर्धारित करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उत्तरा पड़ा राज्य एवं एविस्तान ते माना सालों शरणाध्यों नो नारत माना पड़ा, प्रत्य हुछ लोग पाकिस्तान ते माना चाहते थे, किन्यु नागरिकता सबधी अधिनियम ने निर्मित होने तक उनको मारत माने का प्रवस्त प्रदेश ने स्वत स्वाप्त मारत से पाकिस्तान चले गये थे, किन्यु हु समय पड़वात् ये मारत लोट प्राये, भीर मन्त में, बुछ लोग विदेशों में रह रहे थे, किन्यु ने मारत ली नागरिक्ता को प्रहण किये रखना चाहते थे। प्रत, दन सभी वर्गों के लिए नागरिकता सबधी व्यवस्था बरना सविधान समा बी प्रारप समिति के लिए एन सत्यध्य करीन कार्य था।

इस सदर्भ में सविधान में, सविधान लागू होने के समय केवल इसका उत्लेख किया गया कि, नागरिकता के लिए किन-किन योग्यताओं की मावश्यकता है। नागरिका से सवधित मविष्य में समस्त मामले, जैसे नागरिकता की प्राप्ति एवं नागरिकता का सुप्त होना, सविधान के अनुच्छेद ११ के मनुसार सथ ससद-कानून द्वारा तय करेगी। जिन व्यक्तियों को सविधान के लागू होने के समय से नागरिकता प्राप्त हुई है, से उस नागरिकता के प्रथिकार को प्राप्त निये पहेंगे, किन्तु ससद को इस विषय पर कानून, निर्माण करन का पूर्ण मधिकार है। मत सांवधान में नागरिकता के सबध में कोई स्थायों व्यवस्था नहीं की गयी है।

सविषात के प्रारम्भ होने के समय पांच श्रेणियों के नागरिकों को मान्यता प्रदक्त की गई। ये श्रेणियाँ निम्नानुसार हैं।

श्री मास्तीय उद्भव के समस्त व्यक्ति धर्यात जो स्वय या जिनके माता-पिता मास्त्र में उत्पन्न हुए हैं तथा वे समस्त व्यक्ति जो मास्त्रीय क्षेत्र में ग्रिधिवासी रहे है या वे समस्त व्यक्ति जो सविवाग के प्रारम्म होने के पूर्व की क्षम से कस पांच वर्ष की प्रविध तक मास्त्र के निवासी रहे हो। प्रविकाश मास्त्र के नागरिक इसी श्रेणी के है। भारतीय शासन मीर राजनीति

२ वे ध्यक्ति जिन्होंने पाणिस्तान से भारत को जुलाई १६, ११४६ से पूर्व देशावर किया तथा को देशावर करने ने परवान मारत में निवास कर रह है भीर व । उनके माता-पिता से से नोई एक या उनके पितामह प्रविकाशित मारत में पेदा हुए हो। इस स्वी में स्रविकाश हिन्दू तथा विश्वस है जिनको भारत विभाजन के परवान पाणिस्तान से मारत साना पडा। जुलाई १६, ११४६ से इस प्रकार देशान्तर के जिमे सनुसायन प्रणाली प्रारम्म की

३ वे ब्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान से मारत को जुलाई १६, १६४८ के पश्चात् देशातर किया, और मारत मे छ माह निवास करने ने पश्चात् उनने छावेदन पत्र देने पर योध्य प्राधिकारी द्वारा सविवान ने लागू होने के पूर्व

जनवा पत्रीकरण कर विद्या गया है। धूँकि ऐसे व्यक्तियों की वस से कम ख साह तक सविधान के प्रारम होने के यूर्व, मारत में निवाल जरजा सावध्यक है, सब यह स्थय है कि मारत में जनना निवास जुलाई २४, १९४६ के बाद नहीं प्रारम हुमा है।

* साजारणतंत्रा वे ब्यक्ति जिल्होंने मारत से पानिस्ताल मार्च १, १९४७ के बाद से सातर किया है वे भारतीय नागिरता के धीय नहीं होंगे, वरण्यु करो से जिलनों पुर्तनवाल के विषय पान्य लिए समुत्राजन दिया गया है जनकों ने निवास प्रारम करती है, वसले के जन कारों को पूरा करते हैं, जो जन बत्तियों के निवास साती है जनहों ने पितरहाने पानिस्ताल से सात से जो बुद्ध है।

उत मुस्तिम परिवारों के लिए निया गया था जो सामप्रवायिक उपहची या बायकारी परिस्थितियों के बारण भारत छोड़कर चले तमें थे, सयिर उनकी भारत छोड़के की विस्कृत इच्छा नहीं थी। इस बारण, भारत सरकार ने उनको बागत लोड़ने की स्नृतिर्दे दे थी थी। इस बोगों की

सच्या दो बा तीन हजार से स्रियम नहीं थी।

प्र यदि विदेशों से रह रहे मारतीय उद्भव के स्थित सिष्यान के मारस होने

ने पूर्व या उसने पत्थात नागरित्वा के निष्य सोददन देते हैं भीर मारतीय
दूशावात द्वारा उनना पत्थीत्यल र निया जाता है, तो उनको मारतीय
नागरित्वा प्राप्त हो जायेगी। कोई भी स्थित जिनाने दिसी दिसेशी
राज्य की नागरित्वा पहण कर सी है यह सारत वा नागरित नहीं हो
सक्ता है, तो

सनता है। सामान्यतः नागरिन के तीन माचार होते हैं। सर्व प्रयम, रक्त मुख्यी सिद्धात (जस संगवितस) नागरिनता ना एन प्राचार माना जा सनता है। रक्त सबसी सिद्धान ने प्रमुक्तार नागरिकना किसी ध्यक्ति को उसके माता-पिता की नागरिकता के प्रमुगार प्राप्त होनी है। इस सिद्धात के प्रतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के लिए जनम्बान या निवास का कोई महस्त नहीं है। पान एवं इटनी सादि देशा में नागरिकना रक्त मित्रक के प्राप्त पर ही नियपित को जानी है। इस दृष्टिकाण से मान्योमी या इनालदो माना विना को सतान को, उनका जन्म बाहे कही क्या न हुया हा, मात या इटली का कमना नागरिक हो माना जायगा।

द्विनीय, जन्म भूमि मिदान नागरिनता प्रदान नरने वा दूसरा धायार है। जन्म-भूमि सिदात (जन सातो) ने धनुसार विभी व्यक्ति नी नागरिनता उसने जन्म-पान के धायार पर निर्धारित नी जागगी। दूसरे प्रध्या में, एव व्यक्ति उस देश ना नागरित है, जहाँ उसना जन्म हुंधा है।

तृतीय, बनित्य देना न रक्त सबबी एव जन्मपूमि भवनी, दाना निदाना में म्रतुमार नागरित्वा निर्मारित नी जाती है। बदाहरण स्वरूप, बिटन में बाना निदानों को मान्यवादी गई है। बिटना माना-पिता की सनान जिनका जन्म विदेश में हुमा है, बिटिन नागरित हो माने जायें। इसके मनिरित्त, विदेशिया की सजान जिनका जन्म बिटेन में हुमा है, को भी बिटिन नागरित माना जायेगा।

मुट्यन भारतीय मविकात निर्मातामा ने नागरिकता के जन्म-स्थात-मिद्धात (जस सोती) को हो मान्यना प्रदत्त की है, क्योंकि, प्राथमिक रूप मे भारतीय सर्विज्ञान द्वारा नागरिकता जिम्मतिक्षित श्रीषया के व्यक्तिया को प्रदत्त को गई है।

- (क) जो व्यक्ति मारत के स्वाबी निवासी हैं, खीर वे या उनके माता-पिना भारतीय सूभाग में पैदा हुए हैं, बा
- (स) वे व्यक्ति जो मात्रारमतया भारतवर्षे में क्य में कम पांच वर्षतक निवास कर चुके हैं।

तवारि, नुद्र माना म नारतीय-सिवधान द्वारा नागरिनता के रन सबधी मिद्धान को भी अपनाया गया है। हिसी व्यक्ति की नामरिनता के नियं सिवधान के प्रकार यह नहीं झावक्यर है कि वह व्यक्ति स्वय मारत में पैदा हुमा हों, किन्तु यदि उसके माता-पिता या उनमें से हिमी एक या उसके पितामह वा जन्म सारत में हुआ हो तो, उत्त व्यक्ति को नागरिनता मिन सकती है। इस दृष्टिकोण से यह बहुता उचित्र होगा कि बुद्ध मात्रा में, सारतीय-सिवधान के स्रतनंत नागरिकता के रक्त सबधी सिद्धान को स्वीद्धत किया गया है।

सिविधान के नागरिसमा सबयी प्रावधान प्रतिम नहीं है। सविधान ने प्रतुच्छेद ११ के धनुसार नागरिसता ने विषय पर समद को विस्तृत शक्तियाँ प्रदत्त नी गई हैं। प्रनएव १६५५ में समद ने मारतीय नागरिसता प्रीयनियम, १६५५ पारित 9 € किया, जिसमें नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति एवं ग्रन्य संविधत विषयों का विस्तृत

भारतीय शासन और राजनीति

मारतीय नागरिकता अधिनियम १६५% का अवस्थन विम्नलिखित मुद्दो के ग्रामार पर किया जा सकता है :

१. नागरिकता को प्राप्ति-मारतीय नागरिकता अधिनियम १६५५ के अनुर्गत नागरिकता पाँच प्रकार से

प्राप्त की जा सकती हैं जन्म के द्याधार पर—

रुप से स्पष्टीकरण किया गया है।

जनवरी २६, १९४० को या इसके पश्चात जो व्यक्ति भारत में पैदा हथा है, उसको भारत का नागरिक माना आयेगा । किन्तु विदेशी दूतावास के उन लोगी को जो मास्त के नागरिक नहीं हैं. सतान को भारतीय नागरिक रही माना

जायेगा । इसके घतिरिक्त, विदेशी शत द्वारा कब्जा किये हुए क्षेत्र मे पैदा हुए शत की सनान को भी भारत का नागरिक नहीं माना आयेगा । उदभव या वशाधिकार के बाधार पर-

प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म जनवरी २६, १९५० को या इसके पत्र्वात मारत के बाहर हुआ है, परन्तु उसके जन्म के समय यदि उसके पिता मारत के नागरिक रहे हो, उसको भारत का नागरिक माना आयेगा । पंजीकरण द्वारा-

पत्रीकरण द्वारा निम्नलिखिन पाँच प्रकार के व्यक्तिः भारत की नागरिकता

प्राप्त कर सकते हैं।

(न) मारनीय नागरिको से विवाहित स्विद्या ।

(स) मारतीय नागारको की नावालिक सन्तात ।

(ग) देव्यक्ति ओ साधारभतया मास्त में निवास कर रहेती और बा पजीकरण कराने हेतु फावेदन पत्र देने से पूर्व कम से कम छ। माह

में भारत में रह रहे हो। (ष) वे मारतीय जो प्रविमाज्य मारत के बाहर किसी देश या स्थान मे

साधारणन निवास कर रहे हो।

(ड) राष्ट्र महत्रीय राष्ट्री तथा सामस्तैह के गणनत्र के बयस्क ।

नागरिकोकरता द्वारा-नागरिवीकरण या देनीयकरण द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की

था सबती है। नागरिकीकरण के लिए भावेदन देना मादम्यक होगा। अत्यक्षात.

१७

सध सरकार धपने निर्णयानुसार नागरिकता प्रदत कर सक्ती है । नागरिकीकरण के लिए किसी विदेशी को निम्नलिसित धावक्यकताम्रो को पूरा करना होगा ।

- (क) वह व्यक्ति वालिग हो ।
- (त) वह जिस देश का है, उसकी नागरिकता को उसने त्याग दिया हो सीर इसकी मुक्ता भारत सरकार को दे दी हो।
- (म) भागरिनीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से तत्काल पूर्व चम से कम एक वर्ष भारतवर्ष में निवास कर चुका हो या मारत में किसी सरकार की नौकरी में रहा हो, या भारत में निवास या कोई नौकरी करते हुए क्ल एक वर्ष पर्य कर तिया हो।
- (प) उपर्युक्त उल्लिखित एक वर्ष से पूर्व सात वर्ष तक मारत में रह सुका हो या मारत में किसी सरकार के प्रमीन वार्य कर चुका है प्रपदा मारत में निवास करने ग्रीर मारत में किसी सरकार के प्रयीन वार्य करते हुए दूल सात वर्ष पूरे कर लिये हो।
- (ड) वह ऐसे देश ना निवासी या नागरिक नहीं हो जहाँ मारत के नागरिको ना, कानून या व्यवहार के फ्रनसार नागरिकी करण वर्जित है।
- (च) उस व्यक्ति का चरित्र उत्तम हो।
- (छ) उस व्यक्तिको किसी एक मारतीय मापाका ज्ञान हो।
- (ज) वह व्यक्ति मारत मे निवास बरना या भारत मे किसी सरनार वे प्रयीन या विसी अतर्राष्ट्रीय सस्या मे, जिसवा मारत सदस्य है, या भारत मे स्यापित निसी सस्या में या वस्पती मे नीवरी वरने का इंच्छुक हो ।

यदि प्रावेदन ऐसा व्यक्ति है जिसने विज्ञान, दर्शन, क्ला, साहित्य, विश्वज्ञाति एव मानव-प्रगति के क्षेत्र म विशिष्ट सेवा की हो तो मारत सरकार उपर्युक्त समी या किसी शर्त को उस व्यक्ति ने सवस मे समाप्त कर सकती है।

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नागरिकीकरण हुआ है मारतीय सविधान के प्रति निरुठ की शपय प्रहण करना प्रायस्यक है तथा उसकी यह भी शपय लेनी होगी कि वह पारत के कानूनो एक प्रपत्ते (भारत के नागरिक के रूप में) कर्तव्यो का पारत निरुद्धिक करेगा।

भारत में किसी क्षेत्र के निगंमन द्वारा-

यदि किसी क्षेत्र का निगंमन मारत क्षेत्र मे हो जाता है तो भारत सरकार भादेश द्वारा यह पोषित कर सकती है कि उस क्षेत्र के किन व्यक्तियो को नागरिक साना जायेगा। ऐसे व्यक्ति पोषणा की तिथि से मारत के नागरिक माने जायेंगे। १८ भारतीय शासन छीर राजनीति

मारताय नागरिकता अधिनियम १६५५ व अतर्गत निम्नलिखित तीन प्रकार

२ नागरिकता की समाप्ति-

से नागरिकता का धत हो सकता है।

स्याग द्वारा-

मारत ना नाई भी नागरिन जो निसी बिदेश ना भी नागरिक है भोषण द्वारा नारत ना नागरिनता स्थार सनता है। जब इस पापणा ना पण्डेनस्प, स्वपित प्राधिनारी द्वारा नर तिया जाता है, इस विधि से वह व्यक्ति मारत ना नागरिक नहीं स्था।

समाप्ति द्वारा-

यदि मारत का कोइ नागरिक नागरिकीकरण पत्रीकरण या किसी ख्राय तरीके से किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त करता है उसकी भारतीय नागरिकता सपान्त सानी जानगा !

नागरिकता से बचित करके-

मारत सरकार को निम्निविद्या व्यक्तियों को नागरिकता से बिचन करने का प्रविकार है। यदि किसा व्यक्ति ने पोछे या फठ से या तथ्या को छिसा कर नागरिकता

प्राप्त नी है तो मारत सरनोर उसको नागरिकता संबंजित कर सकती हैं या गरिकोट नागरिक मण्डे व्यवसार मा माण्या होता मारताग्र सनिवाल के

यदि कोइ नागरिक अपने व्यवहार या मापण द्वारा भारताय सविधान के प्रति अपन का भान्याहीन तथा होहा प्रदक्षित करता है ता मारन सरकार उसको नागरिकता से विकार कर सकती है, या

यदि किसा नागरित न एन युद्ध म जिन्नम भारत सम्मितित है, प्रत्रु से मंगिया या एका ताल होना वर मी मिनित है, प्रत्रु से मंगिया या एका ताल होना वर मी कि बह कार प्रतु के गुद्ध म सहस्रवा जुनैवादगा, एका मान किया या यदि साराग जागरिकता प्राप्त करने म प्रत्रु का प्राप्त वर्षों म दश के विसी स्मायान स्व प्राप्त का कम-स-म यो वर्ष ना कर मिना हो। या

यदि शह नागरिक सात्र वर्षों तक लगातार साधारणत भारत स बाहुर निवान करना रहा हो और इस समयातीय म नारत क बाहुर दिवस म दिवा वैद्यानक सम्बा म विद्यार्थी गृही रहा हा या भारत म किमी सर कार या क्लिय मदर्गीहों सस्या कुनियक्त मारत एक स्टस्स है, प्रयोज स्वा म न रहा हो, भीर न ही उदल मारत के नागरिक कर रहन के निए जिदेश म भारतीय दूतावास म पजीवरण वराया है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत सरवार नागरिकता से बचित कर सकती है।

विसी मारतीय नागरित को उसको नागरिकता स विवत करने के पूर्व भारत सरागर को उसको लिखित नोटिस देना आवश्यक होगा, जिससे उस नागरिक को, नागरिकता से विवत करने के कारण बतलाय जाना भाव-क्यक है। भारतीय नागरिक्ता स्रीयिनयम में एक जीच समिति के लिए प्रावधान विचा भया है, जो ऐसे मामनो की जीच गरेगी। साधारणतः मारत सरकार इस विवय पर जीच समिति हे प्रतिवेदन के मनुवार धणना

मारतीय नायरिकता अधिनियम १६५५ द्वारा राष्ट्र महलीय नागरिरता थे लिए मी प्रावधान निया गया है। इत अधिनियम नी पारा ११ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति मो, को निर्देन, आस्ट्रेनिया, मनाइ, तमा, न्यूनीनेण्ड पानिस्तान, रोडेशिया एव न्यासातेण्ड सव तथा आयरत्येण्ड ने गणनत्र मा नायरिक है, इस प्रवार को नायरिता के आपार पर मारत मे राष्ट्र-मण्डलीय नागरित माना जायेगा। इसके प्रतिरक्ति इत अधिनियम की पारा १२ वे अनुसार मारत सरवार परस्पर सम्बन्धो के शाधार पर उपर्युक्त राष्ट्र मडहतीय देशो के नायरिता को मारत के नागरिक के समस्त एव हुछ अधिकारों को देने के लिए प्रादेश द्वारा शायधान कर सवती है।

मारत में सिवधान में अतमेत नेवल एन ही नागरिकता ने लिए प्रावधान विमा गया है। सम्मूर्ण देश में लिए मारतीय सिवधान एनल नागरिकता ने ही साम्यत देता है, और डॉ॰ अम्बेदन र के गथ्यों में यह मारतीय नागरिकता है। समुद्रा राज्य अमरीचा एव दिन्नवर्तनेष्ठ में, जो सम राज्य है रोहरी नागरिकता को अपनामा गया है, सम नागरिकता भेर सम के जिस राज्य में एक व्यक्ति अधिवासी है, उस राज्य नी नागरिकता। में मारत में प्रतिधि एव सकीणें माननाधी नो रोने तथा राज्येय से एक जान-रिक्ता को समित की मानवाभी नो साम मित्रीय एव सकीणें मानवाधी नो रोने तथा राज्येय से एक जान-रिक्ता को ही मानवादा दो गई है। इसने भतिरिक्त प्रयोग नागरिक को मारत के सिम्यान में अतमेत समान प्रधिनार एव वर्त्वव्य प्राप्त है।

नागरिको के मूल ऋधिकार

सामान्यता, एक जनतात्रिक राज्य की दो मूल धावस्वकताएँ होनी है।
सबैप्रध्य यह धावस्वय है कि महकार के तीन मागे—नायंगरिका, व्यवस्थापिका
एक व्याद्यानिक ने स्थानन तथा मिक्सो का साधार जनतात्रिक सिद्धात हो।
दिवीय, यह भी भावस्वक है कि राजकता तथा नागरिको ने मूल धावस्थाते हो।
दिवीय, यह भी भावस्वक है कि राजकता तथा नागरिको ने मूल धावस्थाते हो।
स्थान जनतात्रिक सामुक्त हो। जनतात्रिक सरकार प्रण्ये नागों और नीतियो से
जनतात्री के प्रध्याधी का प्रतिविधित्य नरती है। इसके मितिस्ता, जनतात्रिक स्वरकार का यह क्षेत्रक है कि नागरिक ने मूल धावस्थार का प्रदान नागरिको वा
इस अवस्थार के पतिक्रमण से सरक्षण करें। इस प्रवार सरकार का प्रमुक्त जनतात्रिक
हो जाता है कि नागरिको हो परकार के दिवों को सम्भवस्थ तथा सहुन जनतात्रिक
धावार पर करें, क्षोणि वास्तव मे राज्य भीर नागरिको के दिवों ने को स्थान प्रधार पर करें, क्षोणि वास्तव मे राज्य भीर नागरिको के दिवों ने को मुक्त हो स्वरकतापूर्वक कर सक्ती है, न कि भागी इन्स्तुनार । एव जनतात्रिक राज्य मेन तो राज्य भीर के ही नागरिको के प्रधीमित धीयनार हो सकते हैं। यहि राजकता और नागरिको के प्रसामित से प्रधानित सञ्चन नही है, तो जनतात्र का कोई दूस्त नही हो सकता है।

"एव नानुनी परिनार एक ऐसा हित है जिसना सरक्षण नानुन हारा होता है भीर जिसनी न्यायानय लागू करते हैं। जबनि एन सामारण नानुनी परिनार ना सरक्षण भीर लागू नरना देन के सामारण नानुन हारा होता है, एक मूल परिनार ना सरक्षण भीर सामायान राज्य ने निस्तित महितान हारा हाता है। इन परिनारों नो मूल प्रियंत्र नहां जाता है क्यों नि सामारण महिता का अध्याप मिला के अध्यापना हारा सामारण विध-निर्माण प्रविद्यानुसार परिवर्तित किया जा अवस्थानिया हारा सामारण विध-निर्माण प्रविद्यानुसार परिवर्तित किया जा सनता है जबनि एन मूल परिवर्ति ने सिर्मान महोगन प्रविद्या के सलावा निस्ती भन्य प्रविद्या हारा सामारण विध-निर्माण का सत्ता है। दूसरी भीर मूल प्रविद्यान के मूल प्रविद्यान स्वारत ना देश के मूल नानुन (सिर्मान) हारा धारतासित होत है प्रवर्ति स्वरार ना नेही स्थान नार्यपालिना, व्यरसाधिना या स्थायपालिना, इनके विरक्ष नार्य नहीं कर

सविधान में रखना है।

सकता है भीर इस प्रवार वा कोई भी राज्य-वार्य जो मूल भ्रषिकारा के विरुद्ध है अर्जुष होना चाहिये।""

यह स्पष्ट है नि विसी भी भिष्तार मो मूल अधिवार नहीं नहा जा सन्ता है यदि व्यवस्थापिता या कायपालिना उसना उल्लंधन मरती है भीर सविधान के अन्तर्गत इसके लिए नोई सबैधानिन उपचार न हो। मुख्य-व्यायाधीय श्री माल्यी में भोषातन बनाम महास राज्य के प्रतरण म इस विषय पर वहा था— मूल प्रविकार को सविधान के आदरम में और साथ म ब्यवस्थापिता के इन प्रविचारों म हस्तक्षेप के सबध में एवं विशिष्ट मुमानियत (भनुच्छेद १३) रतना भीर इस मुमानियत को लागू करने के लिए व्यायित पुनरावलीवन का सबैधानिर प्रावधान (भनुच्छेद २३) नरना इस बात ना स्पष्ट छोतन है नि यह प्रविकार साधारण कानृतों म सबींच्य है। "थ

एव सिखित जनतात्रिक सर्विधान में भूत अधिकारा के लिए प्रावधान परने के निम्नतिखित कारण होते हैं, जिनसे भूल अधिकारों की महत्ता मी स्पष्ट हो जाती है।

सर्वप्रथम, सविधान में भूल प्रधिकारों को रखने में गीछे यह तक है कि जन-तत्र में प्ररोवक व्यक्ति की प्रपत्नी महत्ता होती है। वास्तव में जनतात्रिक राज्य का समस्त दर्शन प्ररोव व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्ता पर प्राथारित है। इस धारणा के प्रमुतार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हुए समस्त समाज के कल्याण की प्राप्तिक करता है। परनु इस वहरेश की प्राप्तित की समस्त है जब प्रयोग नामरिक को उसके प्रधिकारों के उपभोग के तिए समान प्रवसर प्राप्त हो ग्रीर इन प्रधिकारों की मुरक्षा का सबसे प्रभावशाली प्राक्तावात इनकी

हितीय, मूल प्रिपकारों को सविधान में स्थान देने से व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक विशिष्ट क्षेत्र स्थापित होता है। ''सविधान म मूल प्रिपबार वह यत्र है नितने द्वारा सरकार की निरकुणता रोकी जाती है, धौर प्रत्येक व्यक्ति के 'शाव्-तिक प्रिपिकारों के 'क्षेत्र को राजनीतित्र हस्तक्षेप से सुरिशत किया जाता है।'' राज्य द्वारा इस क्षेत्र में प्रतिक्रमण नि मदेह प्रवेष होगा। विशेषकर, मास्त मे जहीं एक राजनीतिक दल का विशात बहुमत है जहीं कोई प्रतिपक्षी दल इस

१ डी० डो० यसु-'कमेन्ट्रो म्रान द कान्स्टोट्यूशन म्राफ इडिया', भाग—१, १६६५ पुरु १२६।

२ शास्त्री-गोपालन बनाम मद्रास हाज्य ।

३ सी० जे० फाइड्क-'कान्स्टीट्यूसनल गवमेट एण्ड डेमोक्रेसी', १६४०, पृ० ४२६ :

स्थिति में नहीं है कि केन्द्र में बैकल्पिक सरकार का गठन कर सके, सरिवात में डिल्लिखित मूल अधिकार ही प्रतिपक्षी दलों के लिए उस हिंदिगार के रूप में हैं, जिनके आधार पर अपने विचारों तथा मापण की स्वतत्रता द्वारा, वे सनारूउ दत की निरवृश प्रवृति को रोक सकेंगे। प्रगृति और जनकल्याण के नाम में सत्तास्ट दल ऐसे वई वार्य वर सकता है जो नागरिक के घरिकारों के विरद्ध हो। धनएव, मूल ग्रविकारों को सर्विधान में रखना तथा उनको सर्विधान में उल्लिखित संघोधन-प्रक्रिया के अनुसार ही सशीधन करना, नागरिको को, मूल अधिकारों के लिए एक ठोस आश्वासन है कि सरकार में परिवर्तन के बावजूद मी, उनके अधिकारों में दिना सशोधन-प्रक्रिया को खपयोग में साये हुए, परिवर्णन नहीं निये जा सकते हैं। की एम॰ सी॰ छागला ने ठीन ही नहा है—"मारत में एन बीर डर है, हमारे यहाँ प्रनिपक्षी दल का एन जनताजिन भोषन के रूप में समान है। हमारी संसदीय सस्याओं में, ब्रिटेन की सस्याओं पर आधारित होने के उपरान्त भी, उस अवरोध को कमी है जो इवलैंग्ड में निरतुश भासन के विरुद्ध पाई जाती है। हमारे यहाँ एक राजनीटिक दल का शासन है, जिसके स्थान पर धन्य दल मत्तास्ट हो सकता है। निरक्षण तनो में ममिक सतरनाक निरकुण तन यह है जो जनतानिक मावरण में है। एक निरकुश तत्र की, जो जनता के मत द्वारा सत्तारुह हमा है, न विसी में डरने की, न पछताने की मावस्थकता है, बतएवं हमारे सविधान निर्माताची को श्रेय देना चाटिये कि उन्होंने व्यवस्थारिका की, जो एक श क्तशासी दल के भाषिपत्य में है, सम्मानित निरक्तशता के विरुद्ध रक्ता के लिए ঘাৰঘাৰ কিনা।"

सुद्रीय, नायरिकों के मूल समिकारों को सक्तिमान में उपने का एक महत्वपूर्ण साम यह है कि सक्तिमान में, जो देश का सर्वोच्च कानून है, मूल समिकारों के उरने से इक्को राजनीतिक मजसेदों के दायरे में कपर उटा दिया जाता है। "व्यक्ति के जीवन, व्यवज्ञा, में सम्बत्यवज्ञा, दुवा करने की सौर इन्हा होने की स्वन्यना, सम्मत्ति तथा माध्य देने की व्यवज्ञा और स्वय मूल स्विचार मजदान के लिए प्रस्तुत नहीं किसे जा सक्ते हैं, वे किसी चुनाव के वरियासों पर निर्मार नहीं है।"

नागरियों के मून प्रमित्वारों यो सविधान में रफने के सिमे उपरोक्त तर्यों के दूरिट-वोष के स्वामादिक रूप में मह प्रस्त सहा होता है कि दिटेन में, मूल प्रविवारों को सिनित एवं स्पष्ट रूप से बयों नहीं रखा गया है ? दिटेन में लिखन सरिधान

१. एम० सी० द्यागता—'द इन्हिबिबुत एग्ड द स्टेट', १६५६ पृ० ११ । २ वे० बेहसन—'देस्ट बर्बिनिया राज्य शिक्षा झन्डल बनाम बानेंट', ३१६,

पू॰ एस॰ ६२४, १६४३ ।

नहीं है। बास्तव में ब्रिटिश सविधान के सिद्धान्तों वा विकास ऐतिहासिव रूप से ब्रिटिश नागरियों ने मूल प्रांपवार व विधि शासन में निहित है। इगलैण्ड म सिव्धान के सिद्धान्त सविधान में (जो लिखित सविधान नहीं है) पैदा नहीं होते, परन्तु स्वय सविधान की उत्पत्ति तथा प्राधार मूल प्रांपवारों में है।" प्रिटिश नागरिकों के प्रांपकारों के प्रांतित्व की ब्रिटिश राजनीतिक प्रणासी में हती अधिव महित अधिव होते हैं। यह से प्रांपता के हित के प्रांपता में प्रांपता में हती अधिव होते। हैं। विभागर है पर यह कि प्रांपतारों वो लागू करवाने के लिए बीन से प्रभावशाली क्दम उठाने वाहिय।

मारत मे मूल अधिकारों के अस्तित्व को ब्रिटेन की तरह वोई काल्पनिव या भावात्मक आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता या। अत्तप्व मारत वे सर्विधान में नागरिकों के मूल अधिकारों को एक विशेष स्थान दिया गया है, और साथ ही स्थायपालिका को इन अधिकारों के सरक्षण का उत्तरदायित्व सींपा गया है।

मूल ग्रधिकारो के प्रकार

मारतीय सविधान के तीसरे भ्रष्याय मे मारत के नागरिको के सात मूल प्रधि-कारो का उल्लेख किया गया है। वे हैं १-समानता का सधिनार, १-स्वतन्नता का भ्रष्यनार, १-शोषण ने विरुद्ध भषिकार, ४-भामिन स्वतन्नता का भ्रष्यकार, ५-सास्कृतिक तथा नैक्षणिक भ्रष्यकार, ६-सम्पति का भ्रष्यकार, भौर ७-सद-धानिक उपवारो का भ्रष्यकार।

उपर्युक्त उल्लिखित मूल प्रधिकारों को दो श्रेणियों में उनके स्वरूप के प्राधार पर रखा जा सकता है।

ष-पृथक् सत्तापूर्णं या सकारात्मक प्रियकार, अँसे १-समानता का प्रियकार, २-स्ववत्रता का प्रियकार, ३-सोपण के विरुद्ध प्रियकार, ४-प्रार्मिण स्वतत्रता का प्रियकार १-सारकृतिक भीर प्रशिषक प्रियकार, ६-सम्पत्ति का प्रियतार। इतमे प्रयोक प्रियकार का स्वरूप सकारात्मक है, नयोकि इनके माध्यम से नागरिकों के स्वातित्व के विकास मे सहायता मिलती है। इसके प्रतिरिक्त, इसमें से प्रयोक प्रयिकार को वृथक् सत्ता एव प्रस्तित्व है। इसके प्रतिरिक्त, इसमें से प्रयोक प्रयिकार को वृथक् सत्ता एव प्रस्तित्व है।

य-उपचार सवधी या नार्धावधिक प्रधिवार । मारत के सविधान में सातवें प्रधिकार, सवैधानिक उपचारों के प्रधिकार का स्वरूप इस प्रकार का है । इसका उद्देश्य नागरिकों के सकारात्मक या पृषक सत्तापूर्ण प्रधिकारों के उत्लघन होने पर एक विशिष्ट कार्य विधि के अनुसार पर्याच्य उपचार प्रदत्त करना है ।

जबकि सकारात्मक या पृथक सत्ताधारी अधिकारी द्वारा नागरिको के लिए ऐसे क्षेत्र का निर्धारण होता है, जिसमे सरकार कोई ऐसी पक्षपात पूर्ण कार्यवाही

१. जी० एन० जोशी-'द कान्स्टीट्यूशन झाफ इडिया', १९५२, पृ० ६१।

नहीं कर सकती, जिससे दून प्रथिकारों वा उल्लयन हो, सवैधानिक उपचारों के प्रशिवार के प्रस्तर्गत उस कार्यविधि को निर्धारित किया गया है जिसके प्रमुखार राज्य का, नामित्वों के विसी सकारास्त्रक प्रित्कार के उल्लयन होने की स्थिति हा, यह इस तत्य होना कि पीडित नागरिक के लिए उपचार को ध्वतस्था करें। भारत के सविधान के प्रस्तर्गत सर्वधानिक उपचारों का प्रविकार एक प्रभावनाती प्रीयधि के रूप में है जिसके उपयोग से निर्धी भूत प्रधिकार के उल्लयन के परिपाम करक पीडित नागरित को पर्योग्त अपचार कुरत्व प्राप्त हो सकेगा। प्रतसंद्यानिक उपचारों का प्रधिकार राज्य होरा सता के समस्त उर्देश्या पर,
जिससे नागरितों के प्रधिकारों का हमन ही, एक प्रस्तुवृत्व प्रवर्ग है।

उपर्युक्त भ्रध्ययन से स्वय्ट हो जाता है कि बास्तीय सिववान निर्माताओं ने भवनी इर्द्यांजता एव विद्वता का परिचय देते हुए राज्य एव नामारिनों के उपर्युक्त सबकों में पुट्यूमिं में प्राथसताप पर दो महत्वपूर्ण जनतानिक सबयोगों की रखा, निवते जागरिकों के मुन प्रविवारों को स्वयंति रखा जा तके।

सर्वत्रयम्, तागरियो के मूल ध्रायकारो वो सविधान में रखते हुए इन ध्राय-कारो वो मीतिकता पर प्रकाश हाला प्रया है। सविधान में इन अधिकारो को एक विदेश स्थान देने के फन्दबरूस इनको सविधान वी पवित्रता एवं सर्वोज्यता वा सरस्य प्राप्त हमा है।

१. एम० सी० शामजी-'बान्स्टीट्यूशन धाफ इव्डिया', १६४८ पृ० १४६।

२७ फरवरी, १९६७ वो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलर नाथ बनाम पजाब राज्य थे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसके धनुसार ससद को मृत ध्रियारा म संशोधन वरने का प्रधिकार नहीं रहा । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाय प्रकरण में दिया गया निर्णय, उसने पूर्व ने दो निर्णया ने विरुद्ध था, जो शनरी प्रसाद बनाम मारत सध एव सज्जनसिंग बनाम राजस्थान राज्य व दो प्रवरणा में दिये गये थ और जिनम सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था वि ससद को सविधान म उल्नेखित मूल प्रधिवारा वा सशोधन वरने का प्रधिकार है। ग्रतएव जब फरारी १९६७ म सर्वोच्च न्यायालय ने गोलवनाय प्रवरण म यह निर्णय दिया वि ससद को सविधान के अनुच्छेद १३ के अन्तर्गत मूल अधिकारा म सशोधन वरने का ग्रधिकार नहीं था, राजनीतिज्ञा तथा विधिवास्त्रज्ञो ने, विशेषकर श्रीनाथपाई ने सुभाव दिया कि सविधान के अनुकेद्देद ३६८ को सशोधित बर इसम स्पष्ट रूप से यह प्रतिरिक्त प्रावधान जोडा जाये वि सविधान वे प्रध्याय तीन म उल्लिखित मूल ग्रधिकारों को संशोधन करने का ग्रधिकार संसद को प्राप्त है। ग्रत नवम्बर ५, १६७१ को सविधान का रथवाँ संशोधन पारित किया गया, जिसके प्रनुसार प्रमुच्छेद ३६८ में यह प्रावधान जोड दिया गया है कि संसद को मुल ग्रविकारों में संशोधन करते का श्रविकार है। सर्विवान के २४ वें संशोधन के . फलस्वरूप ससद को पुन मूल प्रधिकारों के संशोधन का यह प्रधिकार प्राप्त हो गया है जो उसको सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाय प्रकरण म दिये गये निर्णय ने पर्वप्राप्त था।

मूल प्रिषकारों वे सबय में यह भी याद रराना प्रावश्यन है ति यह प्रिषित्रार प्रसीमित नहीं है। यह एन राजनीतिन सत्य है नि प्रसीमित प्रिष्वारों ना जन-तात्रिक राज्य में कोई स्थान नहीं हो सकता है। विजेयकर, यह ब्रिटिश एक प्रमरी की सविधानों ने प्रन्तांत स्थापित जनतात्रिक व्यवस्थाप्रों के सन्दर्भ में सत्य है। प्रमरीवा में नागरिकों ने सीमित प्रिषकारों के सिद्धान्त नो प्रमरीकी सर्वोच्च नगासालय ने मान्यता दी।

१. ऐडकीन्स बनाम चीलरनस हास्पिटल, १६२३, २६१ यू० एस० ४२४ ।

परक दृष्टिकोण से भी कि इसके द्वारा भ्रषिक संख्या में व्यक्तियो की स्वतंत्रता भ्राप्त होती है। ""

क्षतं जब नि राज्य सत्ता पर एन और नागरिको के दून ग्राधिकारों ने सन्दर्भे से सीमाएँ सर्वियान द्वारा समाहें यह हैं, दूसरों कोर नागरिको ने पूल ग्राधिकारों पर भी गर्वशनिक भोगाएँ सगाई गई है, जितसे जनतव एव राज्य वा ग्रास्तरव विद्यमान रहें।

क्षत्र यहाँ उचित होगा कि भारतीय सविधान द्वारा सात भूल समिकारो का विस्तार पूर्वक भध्ययन किया आये।

समानता का श्रविकार

स्विधान के धनुष्येद १४-१० में नागरिकों के समानता के प्रधिकार का विवरण दिया नया है। इस धिकार के सम्बर्ध में राज्यला पर वितय विकेष स्वदीस लागू किये गये है। राज्यला के प्रश्न के दृष्टिकोण ने समानता वा प्रधिकार निर्माशनक है। इस मुदे पर निर्मेषण प्रमुख्य १४, १४, व १६ में बल दिया गया है, को निम्नित्तिलत हैं।

धनुष्टेद १४ के अनुमार राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समा-नता का या कानून द्वारा समान सरक्षण के अधिकार का, भारतीम प्रदेश पर, निषेष नहीं किया जायेगा।

सनुष्केद ११ (१) के सनुसार राज्य किसी नागरिक के विरक्ष धर्म, वग, जाति, निग, जगर के स्थान सपका इनमें से किसी भी झाधार पर गेदमान नहीं करेगा। सनुष्केद ११ के ज्यवन्य २ के सनुसार धर्म, वग, जाति, निग, एव जग्म स्थान सप्या दनसे से निक्सी एक भी झाधार पर नागरिक के क्रिस्ट निम्मणिखित मानसी में मेदमान नहीं विशा जावेगा —

१-दूरानो, सार्वजनिक मोजनालयो, होटलो, सार्वजनिक मनोरजनगृही के प्रवेश के सवय में।

२-पूण या प्राणित धावार पर राज्य निधि द्वारा वने हुए या जनता ने लिए बताय गये नुष्, तालाब, स्नानधाटो, सङको तथा सार्वजनिक स्थानो ने उपयोग के सबध में।

भगुल्टेंद्र ११ वे दो धपदाद हैं। सर्वप्रमा, राज्य दित्रयो तथा बच्चा की प्रयति ने लिए विशेष नदम उठा सनता है। द्वितीय, धनुच्छेद्र ११ में चिल्लालित विसी भी प्रावसान से या धनुच्छेद २१ वे उपबन्ध २ से राज्य को दिशा एव

१ गोपासन बनाम मद्रास राज्य, १९५०, एस० सी० धार० मन, (२६२) ।

सामाजिक क्षेत्र में पिछडे हुए वर्गी एव घनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए काई विशेष व्यवस्था करने म किसी प्रकार की बाबा नहीं होगी।

अनुच्छेद १६ (१) वे अनुसार समस्त नागरिना को सरकारी पद पर निमुक्ति के लिए समान अनसर उपलब्ध होंने । अनुच्छेद १६ (१) के अनुनार केवल धर्म, वज्ञ, जाति, लिग, उत्पित, जन्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर किसी नागरिक को सरकारी नौकरी या पद से बिचत नहीं किया जायगा और न मेरमाव किया जायेगा । सक्षेप में अनुच्छेद १६ राज्य पर एक प्रतिक्चय के सद्देश है, जिसक लारण सरकारी नौकरी या पदा के सबस म धर्म, वज्ञ, जाति, लिंग, उत्पित एवं जन्म स्थान के कारण मेरसाव नहीं किया जा सकता है । परन्तु इसके सन्ध म कतिपय अपनाद हैं जो निम्नलिखित हैं।

(क्) ससद विधि द्वारा राज्य-सेवाम्रा से समिति पद या स्थानीय पद का वहाँ के निवासियों के लिए ब्रार्राक्षत कर सकता है।

(त) यदि राज्य की राय से विश्वडे हुए वर्ग के नागरिका की राज्य सेवायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो राज्य इनके लिए नियुक्तियों या पदो की आरक्षित कर कबता है। परन्तु अनुरुद्धेद २२४ द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रावधान क्या गया है कि पिछडे वर्गों की नियुक्ति करते समय प्रनासन की कुशतता को स्थान में एकना ध्रावयक है।

समानता ने प्रियनार ने सन्दर्भ में सिवयान ने प्रमुख्येद १७ ने प्रन्त-गंन प्रस्मुयता ना प्रन्त नर दिया गया है। इसने प्रतिरिक्त, प्रस्मुम्यता से उत्पार नी गई निर्माणता नो लागू नरना ध्यराघ होगा, जो नानून ने प्रन्तर्गत रण्डनीय है।

ससद ने, १९४५ मे, समानता ने प्रधिकार को प्रभावकाली रूप से लागू करने के लिए धरपुम्यता प्रयाग प्रधिनियम १९४५ पारित किया, जिसका उद्देश्य प्रपुसूचित जातियों ने साथ किये जाने वाले मेदसाब को प्रवैध घोषात करता प्रोप्त
ज्वित उपक के लिए प्रावधान करना है। वरतुता जो मुनिवाएँ जनसामारण एव सवगं हिन्दुम्यों को प्राप्त है, इस प्रधिनियम के प्रत्यांत वे सुनिवाएँ जनसामारण एव सवगं हिन्दुम्यों को प्राप्त है, इस प्रधिनियम के प्रत्यांत वे सुनिवाएँ प्रतृचित जातियों को भी प्रदत्त है। यदि कोई व्यक्ति विलाव, नुएँ या जनकान में स्तान करते से रोजता है। उसे हमाइ की कैद या पांच सो रुखा या जानानों में स्वान करते से रोजता है तो उसे हमाइ की कैद या पांच सो रुखा या सकतों में प्रत्या वा सकतों है। यह एक उनको भी दिया जा सकता है, जो हिंदिकों को दूसना, सार्वजनिक जलपानगृह, होटल, प्रमंगाला, सराय, नदी, कुएँ, गानवाट, समझान, निवास स्वान, सर्वाल के प्रत्या के प्रत्यांत से उपयोग से वचित करते ने प्रयान करते। भन्त मं भ्रमुच्छेद १८ के भ्रमुसार उपाधियों को समाप्ति ने लिए निम्नलिखित प्रावधान किये हैं —

राज्यान रूप ह — १—सेना या शिक्षा संबंधी उपाधि के सिवाय ग्रन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा

प्रदान नहीं की जावेगी । २—मारत के किसी नागरिक द्वारा विदेशी राज्य की कोई उपाधि स्वीकार

२---मारत के किसी नागरिक द्वीरी विदेश राज्य की कोई उपाध्य स्थान १० नहीं की जायेगी।

३ — कोई विदेशी जो भारत में ,राज्य के प्रयोग साम के किसी पद पर हैं, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्त्रीकार नहीं कर सकता है।

४--- मारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भेट या उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नही कर सकता है।

. त्यापि, जनवरी २६, १६४० को राष्ट्रपति ने यह घादेश मसारित किया कि राष्ट्राय (कायनदेव) के निशी मी देश ने नागरिक को विदेशी नहीं समग्र जायेगा, जब तक कि यह बात समद्र हाथ पारित किसी विधि के विद्श्व न ही। प्रताद वह वादिश के फलस्कल प्रारतीय नागरिक राष्ट्र सथ (शामनदेव्य) के किसी देश की राष्ट्रपति विकास र सकता है।

मारत ने नागरिकों के समानवा के प्रिकार ने दृष्टिकोन, राज्य की भूमिका ने दो पहुत है। सर्व प्रयम्, राज्य को भरानी कारित को वार्थमेग सीमित स्थ से करना आवश्यक होगा, जिसके उनके द्वारा मार्गिकों के कानून के मार्ग सामानवा या नानून के द्वारा समान स्था के जरहा सरसान को पर्व, बस्त, बादि, सिंग, स्वाय या नानून के द्वारा समान स्था के जरहा सरसान को पर्व, बस्त, बादि, सिंग, स्वया या नानून के द्वारा समान स्था के उनके स्था कर स्था के कारण सामान नाम स्था स्था के स्था का स्था या किरारों का उपयोग नागरिकों ने धनवार से समानता ने प्रदिवार ने धनुष्टूल ही उपयोग में साना होगा।

समानता के घिषार के घ्र-तर्यत मास्त्रीय नागरिकों को एक विशेष वर्तव्य, स्विष्यात द्वारा सीमा तथा है जो नि ध्रमुख्या निवारण से बाविषा है। इसका उद्देश सामानिक सानता जो रावाराना रहता है। असतुत सर्मुख्या-निवारण सबयों प्राथमा वह ध्यारिकों है ध्रावरण पर समवत. एक महत्वपूर्ण अवरोध के रूप में रहे गय हैं जो सनिवान में निहित वतानिक मुख्यों – स्वतवता, समानता तथा तथा ना, हुन खुत के व्यवहार से, विनाद करने हा प्राथन हों

स्वतंत्रता का ग्रधिकार

भारतीय सविधान के धनुच्छेद १९ से २२ में नागरिकों की स्वतंत्रता के धार्षिक कार का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। "एक प्रकार से इनको व्यक्ति के नागरिक प्रविवार माना जा सकता है परन्तु एव दृष्टियोण से इनवी राजनीतिय महत्ता प्रत्यिवय है नयोचि वे व्यक्ति एव जनतत्र वे लिए प्रति धावश्यव हैं भीर जनतत्र इनके माध्यम से तथा इनवे प्राधार पर ही जीवित रहता है। जब एर व्यक्ति को समुदाय एव राजनीतिक दल निर्माण बरते वा प्रियवार है, प्रपेने विचारा को प्रतारित बरते वी स्वतत्रता है भीर विना सत्तास्त्व देत वे हस्तयोप वे चुनाव जीतने तथा सरकार निर्माण करने वा प्रवसर है, तब ही हम जनतत्र वे प्रास्तित्व की करनाता वर सकते हैं प्रत वे (स्वतत्रता वे प्रियवार) सदियार वा जीवन श्रीर प्रास्ता है। '

मारत के नामरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार के दो पहलू हैं। सर्वअपम नागरिकों को सविधान द्वारा सात मूल स्वतंत्रताएँ प्रधान की गई हैं। अनुन्छेद १६ (१) के अनुसार इन सात स्वतंत्रतायां का उत्लेख विधा गया है, जो निम्न-

लिपित हैं।

१-वाक् स्वातत्र्य तथा ग्रमिव्यक्ति की स्वतत्रता ।

२-मान्ति पूर्वन एव अस्त्र रहित सम्मेलन नरने की स्वतंत्रता । ३-समदाय और संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता।

४-भारतीय प्रदेश में स्वतंत्रता पूर्वेव भ्रमण करना ।

५—मारतीय प्रदेश के किसी भी हिस्से में निवास करने तथा बसन की स्वतंत्रता।

६-सम्पति ने प्रजंन नरने, रसने श्रीर वेचने नी स्वतंत्रता। ७-कोई व्यवसाय, वति, व्यापार या धन्या करने की स्वतंत्रता।

प्रमास अपसास, बृह्य, क्यानार या वर्षाम पर न र देवानुना।

मारतीय सविष्यान द्वारा प्रदत्त स्वतन्नता ना प्रियमार आगिमत नही है।
सवियान द्वारा इस प्रियमार पर नितयन 'बृह्यिन्युक्त सीमाए' तमाई गई हैं जो इस
सिद्धान्त के प्रतुक्त है नि कानून धीर स्वतन्तता में वास्तय म नोई विरोधामास
नहीं होता है और वास्तविक स्वतन्ता नानन ने धन्तमंत हो प्राप्त हो सनती है।
यह सावयानी रवते हुए कि स्वतन्तता उच्छुवत्तता में परिवर्तित न हो जाये, सिन्
धान मिर्माताभी ने राज्य को निक्त प्रदत्त नी, जिससे सामान्य जनता ने हित मे
ध्यिकारों पर सीमाएँ रखी जा सर्वें। "जो बात स्विपूर्वन ज्ञात नरने योग्य है,
वह यह है नि उन्होंने हरको सीमाभी नो युक्तियुक्त प्रयांत त्याय योग्य निर्धारित
विद्याह है, जिससे मित्रय में कोई न्यायालय अपने नो इस प्रधिवार से संवोध पूर्वन
विवान नर ते।" "

१. वी० के० राव--'पार्लियामेन्टरी डेमोब्रेसी इन इव्डिया, १६६१ पृ० १४६-१४७।

२ यही-पृ० २११।

स्रतएत सविधान में नागरिकों ने स्वतंत्रता का जो झाववासन है, उसके साथ ही यह भी स्पष्ट है नि इस स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा दुनित्रता सीमाएँ भी रखी जा सकती हैं और राज्य जिस कानून द्वारा इन सीमाफ्रों ने तातू नेरेग, स्वकृतन्त्र नाया-चोया दें होगा, प्रयति उक्त कानून को न्यायानन से चूनीती दी जा सनती है। वस्तृत जिन सीमाफ्रों को राज्य द्वारा अनुन्देद १६ ने सन्वर्गन स्वतंत्रता के प्रापकार पर लागू विया जायेगा, वे निरकुत नहीं पच्छु सुनित्रुक्त होगी। इस ग्यापिक सहुन के कारण व्यवस्थारिका, स्वतंत्रता के स्रापकार व प्राविक्रमण नहीं कर मनेत्री।

ग्रसीमित तया ग्रनियमित स्वतत्रता ग्रवश्य ही उच्छृखलता मे परिवर्तित हो सवती है ग्रीर इसके परिणाम स्वरूप न केवल ग्रन्य व्यक्तियों की स्वनत्रता की हानि पहेंचाती है परन्त इससे राज्य की सरक्षा एव अस्तित्व को मी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए स्वतत्रता का सही बिमिश्राय ऐसी स्वतत्रता से है, जो कानन से नियमित है, क्योंकि कानुन जनतानिक राज्य में जनता की इच्छा का ठीस रूप होता है। दूसरे शन्दों में कानून द्वारा ही अनतात्रिक राज्य में अनता की इच्छा ना ब्रियान्वय समय है। ब्रतएव जनतात्रिक पद्धति से निमित कानून के दायरे में ही व्यक्ति की स्वतनता समव है, जिससे ग्रन्थ व्यक्तियों की स्वतनता का हतन न हो सके। परन्तु इसके साय ही यह प्रावश्यक है कि राजसता का उपयोग भी सीमित तथा जनतानिक रूप से किया जाना चाहिये, विशेषकर जब कि राजसता के उपयोग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया जाता है। इस दिट से नागरिकों के प्रविकारों का सर्वियान में स्नब्द उन्तेव करना राजसत्ता पर प्रावश्यक सीमाएँ निर्वारित करता है. जिनका राज्य सत्ता द्वारा उल्लाघन करना स्पष्ट रूर से अवैद्यानिक होगा। मारतीय सविद्यान में मूल अधिकारी के उल्लेख करने के साथ उन सीमाओं को स्थापित क्या गया है जिनसे ये स्वित्तार सीमिन रहेग । हमारे सविवान से प्रश्त मून ग्रविकार ग्रन्थ ग्रसीमिन नहीं हैं। "प्रत्येव मामले मे ग्रविकार, न कि सीमाएँ मूल हैं और देश मे सर्वोच्च न्यायाल । तया प्रत्य न्यायालया का यह वर्तव्य है कि इन अधिकारा वी जल्माहपर्वक चौक्सी ग्रीर रक्षा करे।"

नागरित। के स्वनवना के प्रविकार में निहित सान स्वतन्ताओं पर इस दूष्टिन नोग स धारमस्य मुक्तिमुक सीमाएँ सविदान द्वारा सवाई गई है, त्रिवका दूरेर मारत में नागरिकों ने स्ववत्ता और रावस्ता के मध्य में वनताविक सनुवत्तं स्वापित करता है। नागरिकों में स्वनवता पर इस प्रकार ने सीमाएँ, प्रयेक स्वस्य समाज में पाई जानी है, त्रिवके विना सम्याव का प्रसिद्धन नहीं रहे सक्तार

१. एस० द्यान-'द कान्स्डीट्यूशन प्राफ्त इण्डियां, १६६४ पृ० १०२ ।

है। नोई राज्य प्रपते नागरिकों नो असीमित स्वतप्रता नहीं देसत्ता है। भारतीय सविवान द्वारा प्रदत्त मूल अधिनारों की यह एन विशेषना है नि इनवें सबय में सविवान म ही मुत्तियुक्त सीमाधा नी धावस्थतता पर वल दिया गया है। निन्तु यह जात रूरन ने लिए नि तिसी नानून द्वारा सगाई य सीमाएँ स्थायाचिन है मा नहीं न्यायपालिका नो अनिम अधिनार प्राप्त है। भारतीय नागरिन ना अनुरुद्धद १६ ने प्रत्योग प्रदत्त सात स्वतनाताग्री पर निम्नलिखित सीमाएँ हैं।

१—वाक् स्वत्वता तथा ध्रमिष्यक्ति को स्वतवता पर सीमाएँ। वाव स्वतवता तथा ध्रमि प्रक्ति को स्वतवता के ध्रमाय मे अनतव ना कोई मूल्य नही है। प्रत. प्रत्यत जनतानिक सवियान के ध्रमतगंत वार् स्वतवता एव विवारा की ध्रमिष्यक्ति की स्वतवना को मान्यता दी जाती है। परन्तु जैसा देवा जा चुना है, प्रसीमिन स्वतवता न केवल प्रवर्शन हो आयेगी किन्तु यह जनता के सामान्य हितों के लिए हानिवारक सिद्ध होगी।

प्रारम्म म मास्तीय सिवधान द्वारा वेवल चार विषयो ने सत्रय म नागरियों भी बाद तथा प्रमिन्धान्त को स्वतत्रता पर सीमाएँ रही गई (प्र)-प्रभान-तेष, (व) न्यायालय नी निन्दा, (स) जिल्टाचार और नैतिनता एन, (ट) राज्य की मुर्सा। सीन्धान ने लापू होने के पक्षात् यह प्रमुखन निया गया नि उपर्युत्त चार विषयो सत्रयी सीमाधों के वावजूद भी स्वतत्रता का प्रयिवार इतना प्रक्षित्र विस्तुत था नि न केवल हत्या और प्रस्त हिसारमक अपरायों के लिए उत्तिज्ञ करने के वार्य इत सीमाधों के सोन में नहीं आते हैं, किन्तु जीसा सर्वोच्च यायालय ने रोमेत थापर वताम मदास राज्य के प्रवर्ण में अपने निर्णय य वतासारों है दि राज्य की नीव पर आयाल पहुँचाने वाले या राज्य को समाय वरताया है कि राज्य की नीव पर आयाल पहुँचाने वाले या राज्य को समाय वरताया है कि राज्य की नीव पर आयाल पहुँचाने वाले या राज्य को समाय करने के सार्य कर स्वार्य के प्रवर्ण अपनिवास की निवास का स्वार्य पर सीमा वागा उपनिवास नहीं होता। करतावस्त है स्थि प्रमास सार्थाय पर सीमा वागा उपनिवास नहीं होता। करतावस्त है प्रश्च में प्रमास सार्थाय क्रियनिय प्रार्थित वागा सार्य है हिस पर निवास की वाल स्वार्य प्रमास सीम्य की रस्ततत्रता पर बुत्तियुक्त सीमाधा के क्षेत्र म वृद्धि को जा सके। अत. उपर्युक्त उन्हित्तित्रत वार विपयों में तीन सीर विपय को इदि । में निम्मतितित हैं। वार के विप्र हैं। विपर्य के प्रवर्ण के विपर्यक्त सीमाधा के के विप्र के विद्व हैं। वे निम्मतितित हैं।

- (एक)—विदेशी राज्यों से मित्रता पूर्ण सद्ध रखने के लिए,
- (दो)—सावंजनिक सुरक्षा के लिए ग्रीर.
- (तीन) ग्रपराघ को न प्रोत्साहित करने के लिए।

सज़ेप में, राज्य नागरिको के बाक् तथा विचारो की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित सात विषयों के सन्दर्भ में प्रतिवन्त्र लागू कर सकता है। (१) ध्रपमान क्षेत्र, (२) न्यायालय को निन्या (३) विष्टाचार तथा नैतिकता (४) राज्य को सुरक्षा, (४) विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण-सबस्र (६) अपरायों के सम्बन्ध में (७) सार्वजनिक सुरक्षा के लिए।

सम्बन्ध में (७) सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ।

"रन सीमाओं को पुलिसुक सीमाएँ इस्तिय माना गया है कि बाँद क्सी

उपजुक्त-गावासव की सम्पति से बाँदि क्सी कानून सा सादेव द्वारा मुलिटीन प्रतिवन्ध,

काक व विवारों की अमिन्धांति की स्वतन्त्रता पर सागु विचे गये हैं, इनको सबैध

जपुक्त-धामालय नी सम्पर्ध से मार्ट निसी कानृत या मारेण हाय पुलिशीन प्रतिबन्ध, हाल् व विचारों ही प्रनिष्यात्ति नी स्वतन्तता पर लागू निये गये हैं, इनहों प्रवेष माता जा सन्ता है। कदाएं नामारिंगों की स्वतन्तता पर सीमाएं नागति ना व्यव स्वाधित्ता और वर्गयात्तिना ना सर्पिकार सन्तिम नहीं है। क्योंकि न्यायव्यक्तिना इन सीमामा के श्रीस्था नी जांच कर उन्हें अवेश दहरा सन्तती है। 'यूनं पर मातिश्री सत्तियान ने समरीशी सविधान के व्यवस्थातिना है। यहा न्यायव्यक्तिना के कार्यो ना न्यायव्यक्तिना हार्था निरोक्षण के सिद्धान्त को सप्तावाद है। यहा न्यायव्यक्तिन मायप्रयोग नामाल प्रवेश में स्विधान हैं या नहीं। ''' विन्तामण्याय व्यवस्थात्रिका मायप्रयोग नामाक प्रवेश में सर्वोच्च न्यायाव्यक्त ने यह निर्णय दिया है कि व्यवस्थात्रिका हार्था निर्धारित 'पुतिसुक्त सीमाएँ प्रनित्त नहीं है। न्यायव्यक्तिन नो यह व्यवस्थे ना सर्धवरार है कि व्यवस्थापित्वा हार्था निर्धारित सीमाएँ पुत्तिनुक्त हैं या नहीं है।

या नहा ह।

- णानिजुर्बक तथा धरत्ररहित सम्मेतन नरन नी स्वतत्रता जारत के
नागरिनो को सविधान के धनुष्येद १६ द्वारा प्रस्त है। इस प्रनार नागरिनो को
राजभीतिक या धन्य प्रकार के सम्मेतन करने ना धरिनार है, परन्तु यह शानित
पूर्वक होना जाहिय जिससे सार्वजनिक सुरक्षा नो धापात न पहुँच। प्रानुद्धत १६
उपत्रस्य ३ के धनुसार राज्य नो नागरिना है स क्षित्रमार पर सार्वजनिक मुरक्षा
के दित में पुण्लियुत्त सीमाएँ सार्वजिक सा क्षित्र होते

काह्त म 'शुन्तपुत्रत सानाए तथात्र ना आधनार है।

2-महुत्रत एव सर्व निर्माण नरते हो स्वतन्तत्रा भारतीय नामरिना नो
सविधान के मनुष्टेद १६ (१) (सी) द्वारा प्रवत्त है। इस प्रवार नी स्वनन्तत्र के साधार पर नामरिको नो राजनीतिक दल, व्यापार तथ, और समायो न निष् स्वत्यस्था नरते ना सर्धिनार है। इस प्रवार को स्वन्तत्रता पर सनुष्टेद १६ उपकृष्य
(४) के सन्तर्गत राज्य सार्वजनिक मुख्ता एव नीतिकता के हिन से 'मुनिन्यूनन

सीमाएँ तथा सनता है। इस दृष्टिभोण से यदि बोई सगठन विसी बाजून के प्रियानयवर में इसकेंप बरखा है या सार्वजनिव नैविवता के विरुद्ध है, तो राज्य इसार जन सगठन को प्रवेध ठहराया जा सनता है। ४—मारतीय प्रदेश में एक हिसी से प्रया हिस्सों में अमय बरते की स्वत्रता

मारत ने नागरिकों को सविधान के धनुब्देद ११ (१) (टो) के धन्तर्गन प्राप्त

१. डो॰ डो॰ बमु—'पूर्वोक्त पुस्तर', पृ॰ ५६३।

है परन्तु इस स्वतत्रका पर भी राज्य 'युक्तियुक्त सीमाएँ' लगा सरता है । ये सीमाएँ प्रमुच्छेद १६ (५) ने घन्तर्गत सार्वजनिन या घनुमूजित जनजातियो में हित मे राज्य द्वारा लगाई जा सनती हैं ।

५—मारतीय प्रदेश ने विसी भी हिस्से म निवास गरने तथा वसने भी स्वतप्रता धनुन्देद १६ (१) (इ) ने प्रत्यपता भारत ने नागरियों नो प्रदत्त है। परन्तु अनुन्देद्व १६ उपवन्य ५ ने अनुसार सार्वजनिय या जनजातिया ने हितों में बुटिशोण से, इस स्वतप्रता पर भी राज्य द्वारा 'युनितयुक्त सीमाएँ' लगाई जा सनती है।

६—सम्पति वा धर्जन वरने, रसने भीर अपने वी स्वतंत्रता, मारत के नाग-रिको वो सविधान के अनुच्छेद १६ (१) (एक) के अन्तर्गत आन्त है। वरन्तु इस स्वतंत्रता पर भी अनुच्छेद १६ (४) डारा यह भुनित्युमत सीमा सगाई गई कि इस स्वतंत्रता वा उपभी आर्यच्छेद १६ (४) डारा यह भुनित्युमत सीमा सगाई गई कि इस ही निया जा सनता है। उदाहरणार्थ जुमा पर, अनिष्ठत अस्त्र, धराय की अनिष्ठत महिमो राज्य डारा जब्त की जा सनती हैं। यहाँ उत्तेरतनीय है कि सम्पति प्रजित वरने तथा राने का मह प्रियागर अनुच्छेद ११ (भ) या (२) के अन्तर्यद्व २१ के अत्रत्यत तमपति गो लेने के श्रविकार के प्रयीग है अपनित यदि अनुच्छेद २१ के अत्रत्यत राज्य तिसी व्यक्ति की सम्पति को प्राप्त करता है ती स्वायन्त्रित को अनुच्छेद १६ (१) (एक) डारा प्रदत्त सम्पति प्रजित करन एव रातने के अधिकार को राज्य को अनुच्छेद २१ डारा प्रदत्त व्यक्तिगत सम्पति प्राप्त करने के अधिकार के प्रयोग माना जामेगा।

७—िहसी व्यवसाय, बृति, व्यापार या प्रन्या नरने वी स्वतनता भारतीय नागिरवो वो अनुस्देद १६ (१) (जी) मे प्रत्यांत प्राप्त है। विन्तु यह स्वतनता प्राप्त-देद १६ उपवष्य (६) वे प्रनुसार राज्य द्वारा, सार्वजित हितो मे दृष्टिवनेण से मुतिबहुवत सोमाधा के माध्यम से सीमिस वी जा सवती है। इसने प्रतिदित्त, नागिरवो वो इस प्रवार वो स्वतन्तता से राज्य वे इस प्रधिकार पर, वि वह निसी मो व्यवसाय, वृत्ति, व्यापार या प्रम्ये ने सम्बन्य म गानृत द्वारा व्यवसायिन या तवनीवी योग्यता निर्वारित वर्र, कोई रोज नही त्वार्ती है। राज्य को व्यवसायिन य तवनीवी योग्यता निर्वारित वर्र, कोई रोज नही त्वार्ती है। राज्य को व्यवसायिन य तवनीवी याग्यता निर्वारित वर्र, कोई रोज नही त्वार्ती है। राज्य को व्यवसायिन व तवनीवी याग्यता निर्वारित वर्र, कोई रोज नही त्वार्ती है। याग्य रावार विवार से स्वत्या स्वार्ति विवार से स्वत्या स्वार्ति के प्रतिकार स्वार्ति विवार से स्वत्या स्वार्ति के प्रतिकार स्वित्या से स्वत्या से स्वत्या स्वार्ति करने व्यवसाय, विवेषक दिनन्तु प्रत्यक्ष रूप से इनवा सम्बन्ध जनता से मी है।

मारतीय नागरिको ने स्वतत्रता वे ग्रीघवार वा दूसरा पहलू विशिष्ट रूप से यानून एव स्वतत्रता वे सम्बन्धा पर प्रवास डालता है। यह वर्णन क्रनुच्छेद २० से ब्रनुच्छेद २२ तक में दिया गया है। वस्तुत: इन तीन धनुच्छेदों में भारतीय सर्विधान में ब्रिटिश सर्विधान के सदृश 'विधि-शासन' के सिद्धान्त पर प्रकाश काला गया है।

प्रो॰ डायसी ने ब्रिटिश सविधान के धन्तर्गत विधि शासन के तीन सम्बन्धित धर्म निविच्ट किये हैं, जो निम्नानसार हैं.

भ्या नादण्टाक्य हु, जा रामानुसार हु, १—क्सी नागरिन को न हिरासत में लिया जा सकता है मौर न ही उसके जीवन एवं सम्पति पर अतिक्रमण ही क्या जा सकता है, अब तक कि उस नाग-

रिक ने बिसी बानून का उल्लंघन ने मिया हो, २---बानून की दृष्टि से समस्त नागरिक समान हैं; एव २---विधान के सामान्य सिद्धान्त ऐसे क्यायिक निषयी से उल्लंब हुए हैं जिनसे विशिद्ध प्रकलों में, जो क्यायालयों के समस्त बाये गये थे, नागरिकों के प्रक्रिकारी

वा निर्वारण विमा गया है। विदेत में विधि जातान ने सन्तर्गत नाणरियों के स्रीवनरों के स्रास्तित को साम्बता देने और कानून तथा नाणरिय के स्रीवनारों का सन्वरण स्पष्ट करते हुए, यह स्पष्ट विमा गया है कि राजसत्ता का उपयोग, नागरिक के स्रीयकारों ने सन्वर्ध

मे तभी होगा, जब कि नागरिक न किसी कानून का उल्लंघन विधा है। भारतीय सर्विधान के धनुच्छेद २० से धनुच्छेद २२ तक में यह स्पष्ट किया गया है कि नागरिकों के धविकारों के लिए कानून की भूमिका गया है। यह तीन

ग्रदा है कि नागारका वे भागकारा वे लिए कानून का भूमवा गया है। यह तान प्रवार की है। सर्वप्रथम, मनुष्केद २० (१) के मनुसार कोई व्यक्ति किसी सपराध के लिए डोपी किंद्र गड़ी माना जायगा, जब तक वि उसने अपराध करने के समय किसी

स्थापित कानुन वा स्रीतिक्षण न विचा हो और न ही कोई स्थिति करते स्रीपति बच्च वा पात्र होंगा जो उसरो स्थापा वरने के समय स्थापित वानुन के स्रयीन दिया जा बसरा था। सन्देश २० (१) के सनुसार विची मी व्यक्ति को एक ही स्थापत्र के लिए

एत बार स धनिक धनियोजिन तथा दण्डित नहीं किया जा सकता हुए साचुन्हेंद्र में 'दण्ड से धनित्राय न्यायानय द्वारा दिया गया दण्ड है, न कि किसी दिनाम द्वारा दियं गय दण्ड से हैं। धनएय किसी प्रणासकीय कर्मवारी की न्यायालय द्वारा दण्ड मितन के धनितितन, उसके विषद्ध सरकार अनुवासनात्मक कार्यवाही कर, दण्ड देशकरी है।

रण्ड र नवता है। भनुष्टेंद २० (३) वे मनुसार विसी व्यक्ति को जो कि विसी भ्रमसाम के निए ममिनुका है, क्या के विकट्स साक्षी देने के लिए आप्य नहीं किया जायेगा । यह प्रियक्तर मास्त म दोवानी भीर फीजदारी दोनो प्रकार के मामलों के निए

है, जब कि भ्रमरीका में यह केवल भीजदारी मामलों के लिए है।

डितीय, मनुस्टेह २१ वे धनुसार नोई व्यक्ति धन्ते जीवन धीर व्यक्तिस्वत्रता से 'विधि सम्पन्न प्रत्रिया' द्वारा, न नि निसी धन्य प्रत्रिया से, विचित्त निया जावेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने गोरालन बनाम महास राज्य थे मामते में 'विधि सम्पन्न प्रत्रिया' ना धर्म स्माट परते हुए, यह निर्णय दिया नि यदि व्यक्तिस्वापित्र समा, जीवन धीर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से विच्य वरने ना पानून पारित करती है तो न्यायालय इस वानून ने चुनौती नही दे सर्वे। मुग्य न्यायाधीय वानिया से निर्णय देते हुए वहा—"विधि सम्पन-प्रत्रिया" सन्दो गो धनाने से परिणाम स्वरुप, सविधान द्वारा व्यवस्थापित्रा समा नो वानून निर्णारित वरनो में धन्तिम प्रपित्र इसिंग प्रदा व्यवस्थापित्रा समा नो वानून निर्णारित वरनो में धनितम प्रियान इदिया गया है।""

पतिषय लेतनो ने व्यवस्थापिना समा के हाथ म इम विषय पर प्रतिमा प्रिमिनार छोड़ने के घोषित्य पर मना व्यवत मी है। प्रो० धीनिवागन ना न दन है— "विधि सम्पन्न प्रतिया मन्दी ना उपयोग, व्यक्तिगत, स्वतनता ने रक्तारमा प्रावधानों को शीण वर देते हैं, नयोनि एक व्यवस्थापिना निसी प्रतियाना, जो नि व्याय ने सिद्धान्तों ने विरद्ध है प्रथनी सीमाधों में ही रहनर नार्यं परते हुए, निर्धारण पर सनेगी।" "

यह सत्य है कि मास्तीय सविषान में 'विधि सम्पन्न प्रतिया' (प्रीसीजर स्टेब्स्तुतर वाय ला) अच्टो ने उपयोग ने नारण न्यायपातिना जो व्यवस्थापित हारा पार्तित कानून से सन्तर्वर्ती गुण धीर दोध ने आधार पर वानून नो प्रवेश धीर दोध ने आधार पर वानून नो प्रवेश धीरत वरने ना प्रियार नहीं रह आता है। यह न्यायपातिना इस तिल्परें पर पहुँचती है कि स्वयस्थापिता ने सबैधानिम क्षेत्र में रह नर, स्थियान के प्रमुत्तार नानून पार्रित विषय है, तो उनत वानून नो वेथ मानना ही होगा। इससे साते न्यायपातिना नहीं वा सवती है भीर नानून नो वेथल उसके प्रत्यंती दोध के कारण प्रवेष नहीं ठहरा सवती है। इस इंटिवनोण से यदि सारत में व्यवस्थापित क्यायपातिन वे स्वरंग, केंद्र सोर नजरवन्दी नरने या नानून पारित वरती है, त्यायपातिन वे स्त प्रवार के नानून को प्रवेष ठहराने ना प्रविवार नहीं है। त्यायपातिन वो इस प्रवार के नानून को प्रवेष ठहराने ना प्रविवार नहीं है। स्थायपात्यों को, 'विधि सम्पन्न प्रतियां प्रविवार के निवन को स्वरंग प्रवार प्रवार के स्वरंग प्रवार प्रवार के स्वरंग प्रवार प्रवार के स्वरंग स्वरंग प्रवार के स्वरंग स्वरंग प्रवार के स्वरंग ना प्रवार के स्वरंग ना स्वरंग मंत्र के स्वरंग ना स्वरंग स्वरंग ना स्वरंग ना स्वरंग स्वरंग स्वरंग स्वरंग स्वरंग स्वरंग स

१. गोपासन बनाम मद्रास राज्य-ए० ग्राई० ग्रार०, १६४०, एस० सी० २७।

२. एन० थीनियासन—डेमोक्रेटिक गर्वमेन्ट इन इंडिया, पृ० १७३, १६५४ :

भारतीय शासन झौर राजनीति

प्रमरीता में, सविधान के पांचवें और भौरहवें सत्तीयनों में 'वैषिक प्रतिया'
(ह्म्मीकेंस प्राप्त ला) जायों का उपयोग, व्यक्तिगत स्वतवता से सर्पण के लिए
तिया गया है। 'वैषिक प्रतिया' के बनुसार प्रमर्थती सर्वोच्च प्रयास्तव की,
व्यक्तिगन स्वतवता के बरसाण के लिए, प्रतियम प्रधिकार है। स्थेनि, प्रमरीकी
सर्वोच्च व्यासालय 'वैषक प्रतिया' के सत्यमें में हिसी मी वानून की जीच दो
क्सीटिंग के साधार पर कर सत्वता है।

सर्वप्रथम, अमरीकी सर्वोध्व न्यायालय कानून की औद इस झावार पर कर सकता है कि क्या व्यवस्थापिका समा ने अपने क्षेत्राधिकार के झन्तर्गत कानून पारित किया है।

द्वितीय, यदि व्यवस्वाधिका ने कानून प्रथने प्रवैधानिक क्षेत्राधिकार वे प्रात्मेंत प्रात्न के प्रात्निक को वर्षोंच्य व्यापाल्य यह भी जीव कर सकता है नि ज्यन वानून के प्रात्निक न्याप्त के सब्दर्भ ने का स्वयन्ति मुंग की देश हैं। यदि दश दृष्टि-शोण से बानून ने दोप हैं, तो धमरीकी सर्वोच्य न्यापाल्य जसे प्रवेध घोषण कर सकता है। यहाँ पर प्रयत्निक सर्वोच्य न्यापाल्य, 'विधिक प्रतिमा' के प्रमुक्तार ही, प्रात्निक त्यान ने कहींदों पर प्रयत्निक प्रात्निक प्रात्न प्रयोग करेगा।

महाभाग नाम पाप पाप पर प्रथम आपकार पा प्रथमित र राम प्रमाण का स्थान कर्या । स्थान पह स्पष्ट है कि मारत में 'विषि सम्पन्न महिला' के सनुसार व्यक्तिगत स्यानता के दिवस पर स्थानस्थापित भी सिना समित है, सौर समरीना में 'वैषिक प्रक्रियों ने सनसार रामपालिता को सिनास समित प्राप्त है।

सर्वापि, यहाँ पर यह प्रका उल्लब होना है कि सबिधान के धनुष्टेर २१ में विधि सम्बन्ध प्रक्रियों का प्रावधान करके नवा नास्तव में सर्विधान निर्माण अनितात उन्तरना के सम्बन्ध में उनस्वाधिका नो धीनस मलित प्रसा करना पाहते में, ज्याके पन्तस्वक्ष्य नामिलने भी स्वतनता के मूल स्विधरार या स्रस्तित्व

व्यवस्थारित की इच्छा पर ही निर्मर रहे।

यारि, ऐसा प्रतीव होता है कि 'विषि सम्मन्न प्रत्नियां' को स्नानाने से व्यवस्मास्त्रित ने प्रतिन्त प्रतिन्त, व्यक्त्मित स्वयत्त्रता और व्योवन के लिए प्राप्त है,
किंग्नु इस तथ्य को नहीं पूर जाना चाहित कि व्यवस्थापिता स्त्रम तिवधान के
प्रायमान द्वारा विर्वत है। प्रताय, व्यवस्थापिता स्त्रमी स्वित्त का उपयोग सिक् पान में उक्तितित प्रति हो। प्रताय, व्यवस्थापिता स्त्रमी स्वतित का उपयोग सिक् पान में प्रतिकृतित प्रति को समुद्द हो कर सकेसे। इसिल् व्यक्तिपत स्वतन्त्रता व जीवन के मूल प्रतिकार के सम्बन्ध में, सिव्यान के प्रमुख्द २२ में उन प्रतिकार वास्तित्रम स्वतन्त्रता भीर जीवन के मूल प्रविकार से बाद्य तिया आ सन्तर्त्व है।
प्रताय स्वत्रस्त्र १२ से 'प्रतिवासक-कानुत्व' (सीक्तरस-मा) को समाविष्ठत है।
प्रताय है बरावि 'विष्य सम्पन्न प्रतिकार्य के भ्रतुकार व्यवस्थापिका को व्यक्तिगत स्वतत्रता ग्रीर जीवन के मूल ग्रधिकार के सम्बन्ध में जो शक्ति प्राप्त हुई, उसनी द्रधित किया जाये ।

ग्रनुच्छेद २२ मे निहित 'प्रक्रियात्मक वानुन' इस प्रकार सविधान मा, जो कि देश का मूल कानुन है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन बाता है भीर जिसनो साया-रण विधि द्वारा व्यवस्थापिमा परिवर्तित नहीं कर सम्ती है । ग्रतएव, यह स्मण्ट है कि, व्यवस्थापिका द्वारा जो भी प्रक्रिया, नागरिक को उसक स्वतवता ग्रीर जीवन के मूल अधिकार से बचित करन वे लिए निर्धारित की जाती है, उसका ग्रनुच्छेद २२ मे उल्लिखित प्रक्रियात्मर कानून' व ग्रन्बून ही होना चाहिये। तो यह नहीं कहाजास क्ता है कि व्यक्तिगत स्वत्यता और जीवन के प्रियार के सम्बन्ध में ब्यवस्थापिका की शक्ति ग्रमीमित है।

श्रनुच्छेद २२, उपबन्य १ के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को बन्दी किया गया है, उसको बन्दीकरण के कारणों से यथाशीझ अवगत कराये विना हवालात मे रोका नहीं जायगा और न ही उसको इस ग्रधिकार स विचन विया जायेगा वि वह ग्रपनी पसन्द के बकील से परामण करे तथा ग्रपना बचाव करवाये ।

अनुच्छेद २२, उपबन्य २ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसको बन्दी किया गया है और हवालात में रखा गया है, बन्दी बनाये जाने के २४ घण्टे के अन्दर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश विधा जायेगा, और वाई ऐसा व्यक्ति जिना न्यायाधीय की सहमति के उक्त अवधि से अधिक समय तक हवालात मे नही रखा जायेगा ।

ग्रनुच्बेद २२, उपबन्ध ३ के ग्रनुसार, उपबन्ध १ एव २ मे उल्लिखित नोई बात किसी विदेशी शतुया किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस निवारक निरोबी भ्राविनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया है, लागू नही होगी।

सक्षेप मे, अनुच्छेद २२ के द्वारा प्रक्रियात्मक निवमी का निर्धारण किया गया है जो कि कार्यपालिका भ्रोर व्यवस्थापिका पर लागू है। यह निम्नलिखित है।

१—वन्दी व्यक्ति को बन्दीवरण के कारणा से ग्रवगत कराया जाना चाहिये।

२--बन्दी व्यक्ति को ग्रपने पसन्द के वकील की सलाह लेने तया बचाव कर-

वाने का ग्रधिकार है। र-किसी व्यक्तिको बन्दी करने के २४ घण्टे की अवधि मे निकटनम न्याया-

धीश के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये।

४--वन्दी को, बिना न्यायाधीश की अनुमति के २४ घण्टे से अधिक समय तक हवालात में नहीं रखा जायेगा।

धनुच्छेद २२ मे निहित, उपर्युक्त 'प्रक्रियात्मक कानून' मे कतिपय त्रुटियाँ

हैं. जिनके फलस्वरप ग्रमियुक्त को क्दाचित न्याय प्राप्त न हो। य पुटियाँ निम्नलिखित है।

१—सर्विघान में यह प्रावयान नहीं है कि मुक्दमें की सुनवाई जल्दी और सार्वजनिक रूप से हो, ग्रौर न ही यह प्रायधान है कि धनियुक्त को ग्रपने बचाव

दे लिए ग्रपील वरने का ग्रविवार है। ?—बहाँ इस प्रकार ना कोई प्रावधान नहीं है कि मुकदमा कम खर्चीला हो, जब कि प्रतुच्छेद २२ के उपयन्ध १ एव २ का विषय साधारण बन्दीकरण है, इस अनुच्देद के उपवन्य ४ से ७ तक का विषय निवारक निरोध है। निवारक निरोध भारतीय सविधान का एक अत्यन्त मतमेदपूर्ण विषय है, जिसकी कडी धालीचना हुई है। यह नदाचिन अजीव-सा लगना है कि निवारन-निरोध-जैसा विषय सविवान के तीसरे ब्रध्याय म, जिसमे भागरिकों के मूल अधिकारों का उल्पेख है, सम्मिलित विया गया हो । परन्तु निम्नलिखिन दो तकों के ग्राघार पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि ऐसा क्यो किया गया।

. सर्वेप्रयम, राष्ट्र की स्रक्षा एव एक्ता के विशिष्ट महत्व के कारण, सविधान निर्माताको ने निवारत-निरोध सन्दन्धी प्रावधान हमारे मंदिधान में रखे। विना राज्य के ग्रस्तित्व के मूल ग्रविकारा की कल्पना करना, वेमतलब होगा। मूल अधिकारो को असीमित नही होना चाहिये, किन्तु राज्य की मुरक्षा एव अधण्डता के दिष्टकोण से युविनयुक्त सीमाओं में ही इनकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है। स्वतंत्र मारत के इतिहास से विदित होता है, कि इसको खान्तरिक सीर बाह्य श्वतरों का सदा सामना करना पड़ा है। बल्कि ग्राज य खनरे विकराल रूप बारण किये हुए हैं। विशेषकर १६६२ म चीनी आक्रमण, तत्वश्वात् १६६४ मे पाकिस्तानी भाइमण और बागला देश के सन्दर्भ में, पाकिस्तान से हुए युद्ध के रूप में देश की एक निरन्तर खतरे का सामना करना पडा है। "अनतातिक स्वतत्रता मारत मे एक नये तथा कोमल पौषे के सद्द्रण है जो उन तत्वों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अति-क्रमणो से स्वय की रक्षा करने में ग्रसमर्थ लगना है, जिनको जनतानिक स्वनत्रना एव प्रगति से कोई सहानुमूर्ति नहीं है, कठिनाई से प्राप्त राष्ट्र की स्वतनता को तोड पाड करने वाले और हिसात्मक तत्वों से बचाने के लिए चौकसी की आव-म्यवता है। जब तक प्रत्येक दल या संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वेमानिक साधनो को स्वीकृत नहीं कर लेता है, निवारक-निराध-जैस विशेष प्रावधान मारत के लिए ग्रावस्थक हैं।"

द्वितीय, यदि निसी व्यक्ति को निवास्त निरोध में रखने की ग्रावश्यकता हो, तो यह सविपान म उन्लिखित प्रक्रिया के प्रनुसार ही किया जाना चाहिये, जिससे

१ एम० वी० पायली—'इण्डियाज कान्स्टीट्यूशन', १६६२, गृ० १०५।

ध्यवस्थापिका या नार्यपालिका सर्वयानिक क्षेत्र से बाहर जावर सत्ता वा निरकुण दुरुप्योग न कर सकें। इसी कारण डा॰ प्रान्वेटकर ने सविधान समा के सदस्यों वा ध्यान इस ग्रोर ग्राक्षित कराया। वे निवारच निरोध के प्रग्त्यमंत बन्दी व्यक्ति के 'प्रक्रियास्मक श्रीयकारों' वो सविधान में मुरक्षित रस्ता बाहते थे। परन्तु साथ ही उनका ध्यान राज्य की सुरक्षा नो ग्रोर भी था। इस्तिल् जहाँ प्रमुद्धेद २२ में राज्य की सुरक्षा पर वल दिया गया है, वही साथ ही बन्दी ने प्रश्रियास्मक ग्राय-कारा वो नो स्पष्ट वर दिया गया है, विस्ति उनको न्याय प्राप्त हो गरे।

धनुरुद्धेद २२ के उपबन्ध (४) के धनुसार निवारक-निरोध सम्बन्धी कोई कानून द्वारा तीन माह से श्रीवक समय तक दिसी व्यक्ति को हवालात में रखने के लिए प्रविद्यत नहीं विया जा सकता है, तिवाद निम्ननिधित परिस्थि-वियों में :—

अ—जब एक परामधं मण्डल ने, जितके सदस्य ऐसे व्यक्ति है, जो उच्च स्वायालय के त्यायाधीश है, या रहे हैं या त्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने भी सोग्यता रखते हैं, उपयुक्त उल्लिखित तीन माह की ब्रविध समाप्त होने के पूर्व, यह प्रतिवेदन दिया है कि बन्दी के निरोध के पर्याप्त वार्ण विद्यमान है। परन्तु उपवन्य (७ व) के अन्तर्गत ससद द्वारा निर्मित वानून द्वारा जो वन्तीकरण को प्रविक्तम सीमा निर्मारित की जायेगी, उससे अधिक समय तब वन्ती नो निरोध में नहीं रखा जायेगा। या.

व-जब वन्दी को ससद द्वारा, अनुस्हेद २२ उपवन्ध (७ झ) के अनुसार एव (व) के अन्तर्गत वन्दी रखा जा रहा है।

धनुक्देर २२ उपबन्ध (४) वे धनुसार जब किसी व्यक्ति का निरोध, निवा-रम-निरोब कानून के धन्तर्गत किसी आदेशानुसार किया गया है, जिस प्रियकारी द्वारा यह प्रादेश दिया गया है, उसका यह वर्तव्य है कि बन्दी व्यक्ति को उसके बन्दीकरण के वराण शोध बताये जिससे वह उस धादेश के विरुद्ध शोधातिशीध्र प्रमिवेदन कर सके।

अनुष्टेद २२ उपवन्य (६) के अनुसार उपवन्य (५) में किसी विषय पर प्रादेश देने वाले अधिकारी के लिए उन तथुगों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिनको वह जनहित के विरुद्ध समग्रता है।

। जनका वह जनाहत का विरुद्ध समस्तता है। अन्त में, अनुच्छेद २२, उपबन्ध (७) के अनुसार ससद कानून द्वारा यह निर्धा-रित कर सकती है कि

क-किन परिस्थितियों में और जिस प्रकार की श्रेणी या श्रेणियों के प्रकरण में एक व्यक्ति का निरोध तीन माह से ग्रधिक समय के लिए निरोध-निवारक

कानून के ग्रन्तर्गत परामशे मण्डल की सम्मति के बिना किया जा सकता है।

या श्रेणियो के प्रकरण में अधिक से अधिक कितनी अवधि किया जायेगा । ग—परामर्थं मण्डल द्वारा उपवन्य (४ अ) के अन्तर्गत किस प्रक्रिया को

ग्रपनाया जाये ।

सक्षेप मे, सविधान द्वारा सघ और राज्यो की सरकारो को, व्यक्तियो का निवारक निरोध, सविधान में उल्लेखिल प्रक्रिया के बनुसार करने का प्रधिकार प्रदत्त किया है। यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति का निरोध करते हुए यदि अनुच्छेद २२ मे उल्लिखिन कानुनी प्रक्रिया की सीमाओं का पालन नहीं किया जाना है, यह बन्दी के मूल अधिकारों के विरुद्ध होगा, जो उसकी अनुच्छेद २१ और २२ उपबन्ध ५ द्वारा प्राप्त हैं। निवारक निरोध सम्बन्धी अधिकारों का सरकार द्वारा द्रख्ययोग रोकने के लिए भारतीय सविधान में निम्नशिखित सबैधानिक अवरोधों के लिए प्रावधान किया गया है।

१--साधारणतया. किसी भी व्यक्ति को बन्दी बनाकर तीन माह से अधिक समय के लिए निवारक-निरोध में, दिना परामर्श मण्डल की सम्मति के नहीं रखा जा सकता है, जिसमे एक उच्च न्यायालय का म्यायाधीश है और शेप दो सदस्य ऐसे होगे जो कि उच्च न्यायालय के या तो न्यायाधीश रह चुके है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं। यदि परामर्श मण्डल की राय है कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के लिए बन्दी बनाये रखने का कोई कारण नहीं है तो उस व्यक्ति को तत्काल रिहा करना होगा। बस्तर के महाराजा प्रवीणसन्द्र भजदेव को परामर्श मण्डल के निर्णयानुसार बन्दी रक्षने ने कोई कारण नहीं थे, ग्रत उनको रिहा कर दिया गया । सर्विधान मे परामर्श मण्डल के लिए प्रावधान ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सरकार की निरक्ताता के विरुद्ध एक ठीस धारवासन है।

२---निवारक निरोध मे रखे गय किसी व्यक्ति को, ब्रनुच्छेद २२ उपवन्ध ५ के मनुसार उसके बन्दी बनाये जाने के कारणों की जानकारी देना आध्यस्यक है। इसके घरितिस्त बन्दी को शीझातिशीझ यह ग्रवसर प्रदान किया जाना चाहिये, जिससे वह निरोध के विरुद्ध प्रमावपूर्वक अभिवेदन कर सके। इस उद्देश्य से कि वन्दी प्रपने निरोध के विरद्ध प्रमावपूर्वक ग्रमिवेदन कर सके, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि "यह प्रश्न कि बन्दी वो उसके निरोध के सम्बन्ध मे पर्याप्त जानकारी दी गई है या नही दी गई है, एक न्यायिक प्रश्न है भौर इस विषय पर न्यायपालिका को निर्णय देने का ग्राधिकार है।"5

१ शिक्वनलास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए० ब्राई० श्रार०, १६५४, एस० 1 305 018

प्रताप्त निमी व्यक्ति ना निरोध नरने वाते अजिवारी ना यन वर्तव्य है नि वन्दी को उसर निरोध नरन न वारणों ना स्मष्टता पूर्वन वतताय, अन्यया बन्दी ने अपन निरोध ने प्रिष्ट अमिवेदन नरन ने अधिकार ना वाई मूख्य नहीं होगा। न्यायपालिका को सह निर्वारित नरन का अन्तिम अधिकार है नि निरोध नरने के कारण विजिद और स्पष्ट हैं या नहीं है। यदि वन्दी ना जा जानवारी उसके निरोध के सम्यन्य मंदी गई है वह अनिचित्त है ता उसका निराज म नहीं रुपा

३—ध्रतुष्ट्वर २२ उपप्रत्य (७ ॥) व ध्रतुमार ससद वा वातृत द्वारा यह निर्वारित वरत वा धाउरार है वि वित्त परिस्थितिया मधीर रिस श्रेणी या श्रेणियों के प्रवरण म किसी व्यक्ति को निर्वारक-निराध म, तीन माह से प्रविक्त ध्रविक व लिए परामर्थ मण्डन वी सलाह व जिना रुगा जा सरना है। इसी प्रवर्ग ससद रिसी व्यक्ति का रिसी श्रेणी या श्रेणिया व प्रवरण व प्रत्यां तत्र सरा सर रिसी व्यक्ति के प्रविक्ति सरा स्वयायित निर्वारित कर सम्बात है।

इसी प्रवार, ससद धनुबदेद २२ उपवन्य (७ वी) व धनुसार किसी व्यक्ति व विसी प्रवरण के प्रत्येस निरोध के निष् प्रधिवतम समय की सीमा निर्धारित कर सन्ती है। ससद उम प्रक्रिया का भी निर्धारण कर पवनी है, जिमर प्रमुखा पर प्रस्ति के स्वत्य के स्वत्य

४—"डॉ॰ घन्येदशर के प्रनुसार सबसे बढ़ा सुरक्षण ग्रह है कि निवारक-निरोध कानून के प्रनुसार ही किया जा सकता है। यह कार्यपालिका की इच्छानुसार नहीं किया जा सकता है।"

इन सब बचाव या सुरक्षा के प्रावचानों के होने हुए भी निवारर-निरोध सम्बन्धी मक्ति ग्रावस्यक होते हुए भी खतरनाक है। इस विचार को स्पष्ट करते हुए

१. एम० बी० पायली-पूर्वाक्त पुस्तक, पृ० १०३-१०४।

٧z

क्षाँ० एम० पो० शर्मा बहते हैं—''स्थापित सरकारो की यह प्रवृति हो सकती है कि वे उनके स्वापित रहने के प्रकृत को वे राज्य के स्वाधित्व एवं सुरक्षा के प्रकृत से मिता दें। राज्य के शत्रुची को उसके ग्रन्तर्गत स्वतवता की माग करने का कोई ग्रामिकार नहीं है, पर यह क्रावश्वक है कि उनमें तथा सत्तारूट दल के विरोधियों में अन्तर क्या जान, और यह नागरिक का कर्तव्य है कि यह देखें कि प्रतिपक्षी दन जो सर्वधानिक सापना म बिक्बाम करने हैं उननी ही स्वतनता के पात्र हो, जिननी मत्तारण दत व नमर्थना ना प्राप्त है। सिन्धात म, जो दिना मृतवाई ने निरोध में रखे जान ती बटि है वह जनमन द्वारा व्यवस्थानिका पर प्रमाध डाल दूर की जा सक्ती है। इस यह नहीं भूद जाता चाहिर कि व्यवहार में जतना वो उनती ही स्वतनता प्राप्त हानी, जिसक वह लायक है बीर जो वह खपने चीकमी में प्राप्त करती हैं।"

यहां यह उल्लेस करना प्रावस्थन है कि ततना और समद सी सतनेता के सारत निवास-निराम सानून १८५० क प्रत्यर्थन भारत म नेन्द्रीय धीर राज्य सरनारा तो सिमी व्यक्ति सा निवास-निरोध करने या प्रधिमार है, यदि उनसो सत्तोप हो जाता है कि उस व्यक्ति में १ — मारत यी मुस्सा हिसो है साथ मारत वे सन्दर्भ सा, २ — स्टान की मुस्सा एवं शान्ति सा, १ — राष्ट्र में लिए स्रावस्थन वन्द्रशो त्या भेवासा को बताव रुक्ते के विरद्ध कार्य किये हैं।

रेट्य के मूर बानून के धनुतार उस्तुबन केवल तीसरे वर्ग के धम्मर्गन बन्दी निये हुए वर्गन्तवा के लिए एसामश्चे मण्डर की उपमान निया जा सकता था, जब कि प्रथम धरेर दूसर वर्ग के धन्तवेत बन्दी बनारे उस व्यक्तियों ने वह मुख्या नारों दी गई थी। इन कानून द्वारा जिल्लाभीम (विस्ट्रिक्ट मिजन्ट्र) एव उप-मण्डतीय न्यायांचीत्र (सब डिविजनल मित्रहुँद) दाना ना उपर्युवन नानून प्रक्रिया-तुनार किमो ध्वनित का बन्दी करन का ग्राविकार या । गोपासन बनाम महास राज्य नामक प्रकरण में सर्वोच्च ज्यायात्रमं न यह निर्णय दिया कि निवारक-निरोप्त प्रायिनियम की बारा १८ छाउँच थी क्योंकि इसके द्वारा निराध करने के निरात प्रायानयम का पार्ट १० अवस पा कार्य पा कार्य कार्या निराह के बननाना बब्जि किया गया था, जा कि प्रमुक्तेद २२ (४) व बिरुद्ध था। निवारत निराम प्रायानयम १९४० व सम्बन्ध में ग्रापिक प्रमुतीय व्यवस विचा गया । पत्रस्वतत इस प्रवितिवस स हुन्न समोपन तिवे गरा । स्रत स्रत, प्रदान निवारत निरात के सामत को एक प्रधासने सम्बद्ध के समक्ष किसी व्यक्ति के दन्दी करन के तीम दिन के घन्दर रखना चाहिय। बादी को यह प्रक्रिकार भी प्राप्त हुमा है कि वह स्वयं परामर्श मंद्रत की समग्र उपस्थित हागर प्राप्त तर्मे

रै एम० पी० शर्मा—द गर्बमेन्ट भ्राफ द इन्डियन रिपस्थिक, १०६१ go xo i

देसके। यदि परामर्श-मण्डल वी राग यह है वि विसी व्यक्ति वो बन्दी रसने के वोई कारण नहीं हैतो सरवार उस व्यक्ति वो रिहावर देगी। निमी मी व्यक्ति को भ्रिमितम वी मार्ग (११९) वे भ्रतुसार बन्दी बनाये जाने वो तिथि से १२ माह से प्रीपत्त समग्र के सित्त पत्ती नहीं रसना जा सकता है। इसी प्रवार निरोप प्रादेश वी समग्रवीस समाध्त होने के पश्चान् उसी व्यक्ति में निराम वे तिए नग्ना प्रादेश नो तब्यो वे भ्रामार पर ही दिया जा सवेगा।

इसने वाबजूद की न्यायिक पुनरवलोकन का क्षेत्र निवारक-निनगध के दृष्टि-कोण से सीमित है, किन्तु न्यायपालिका टस मामले में विल्कुल क्षमहाव गरी है। न्यायपालिका निवारक-निरोध मम्बन्धी ब्रादेश का पुनरवजोजन ब्राप्तिन्ति प्राधारों पर कर सकती है।

क—यदि निवारक-निरोध सम्बन्धी धादेश में निए यह कहा जाना है कि यह प्रकारी (मैनेकाइन्ड) है। धादेश के प्रकारी होने से प्रह तारवर्ष है हि यह निवारक-निरोध धीनव्य के उद्देश्यों के विरद्ध है, ऐसी स्थिति में धादेश का खबैध क्या जा सकता है। "

स-न्यायालय इस बात भी भी जींच कर सकता है कि जो निवारच-निरोध के काश्ण बतलाये गये हैं, वे इतने प्रतिक्षित हैं कि उनको प्रपकारी माना जाय। दे या उनका स्वरंप इस प्रकार का है कि व्यक्ति के इस प्रिथकार का हतन होता है। 3 बन्दी व्यक्ति का यह प्रियकार है कि उसको बन्दीकरण के काश्ण बतलाये आयें।

ग—स्यामालय इस बात की भी जीव कर सकते हैं कि क्या निवारक-निरोध के कारणो का विश्वेकपुत्रत सावक्य निवारक-निरोध के उद्देश्यों से, सविधान या निवारक-निरोध प्रधिनियम के प्रन्तर्गत है या नहीं। ४ प्रदि न्यायालय द्वारा सह निर्धारित कर दिया गया है कि इस प्रकार का विवेकपुत्रत सम्बन्ध नहीं है तो बन्दी को खुटकारा प्राप्त हो जायेगा।

घ—न्यायालय इस बात की भी जींच कर सकते हैं कि निवारक-निरोध के लिए कानून द्वारा जिस प्रक्रिया का निर्वारण किया गया है, उसका निवाररा-

१. गोपालन बनाम मद्रास राज्य-ए० ब्राई० ब्रार०, १६४०, एस० सी० २७।

रे. शिब्बनलाल बनाम उत्तर प्रदेश-ए० झाई० झार०, १९५४, एस० सी० १७६ ।

३. गोपालन घनाम मदास राज्य, ए० ग्राई० ग्रार०, १६४०,एस० सो० २७। ४. शिब्वनलास बनाम उत्तर प्रदेश—ए० ग्राई० ग्रार० १६४४, एस० सो०

^{1 308}

४४ निरोध श

निरोध श्रादेश जारी करते हुए पालन किया गया है या नहीं। यदि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो बन्दी को रिहा किया जाना चाहिये।

शोषण के विरुद्ध ग्रधिकार

मारिनीय सविधान के अनुन्देद २३ तथा २४ शोधण के विरुद्ध अधिकार के सारक्षण में हैं। जनदातिक मुख्यों के अनुकृत यह अधिकार समाज में व्यक्ति कि सित्ता है। वन्द्रित यह मानवार्श के उस सिद्धानात्तातुमार है जिस पर वर्षन धार्मावार्थ ने वार्तिक विद्यान स्वाप्त में अधिकार आप सित्तातुम्पर है जिस पर वर्षन धार्मावार्थ ने दार्तिक बाग्ट ने इन जन्मे मिन्ना का सिंह में प्रकृत के दिन के प्रमुख्य के प्रकृत के प्रवास के प्रकृत के प्रकृत के स्वाप्त के प्रवास के प्रकृत के सित्ता के स्वाप्त के प्रकृत के स्वाप्त है कि उन्देश मानवार के प्रकृत के स्वाप्त के प्रकृत के स्वाप्त के प्रवास के प्रकृत के स्वाप्त के प्रवास के प्रकृत के स्वाप्त के प्रकृत के स्वाप्त के प्रकृत के स्वाप्त के प्रकृत के स्वाप्त के प्रकृत के प्रकृत के स्वाप्त के प्रकृत के प्रकृत के स्वाप्त के प्रकृत के स्वाप्त के स्वा

मारत के सहियान में इस प्रतिकार को समाविधित करने का कारण यह पर कि इसके द्वारा मारतीय सनाव में से बाध्यकारी श्रम की नुरी सामन्तवादी प्रवा को समान्त किया जाय। इसके प्रतिस्तित इस प्रतिकार वा उद्देश्य स्विती एव का साराध्य करना है, जिससे उनते मा कोई का करने या वृत्ति अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सके, जो नैतिकता के विकट हो।

परन्तु अनुन्धेद २२ (२) में सार्वजनिक चहेश्यों के सन्दर्भ में एन अरवाद का उनलेस है, जिबने अनुवार राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य तेवा की अवस्था कर सत्ता है। अधिक सिवान मं, भाग्वजनिक उद्देश्यों का स्प्योक्श नहीं है, किन्दु दूसना अमें विकित्सेश पान्य प्राप्त होनांच वर्ग से सत्व पित है। परन्तु सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य द्वारा अनिवार्य तेवाओं में व्यवस्था करते हुए अमें, वस, जाति, वर्ण या इनमें से किसी एक के कारण में स्वयस्था करते हुए अमें, वस, जाति, वर्ण या इनमें से किसी एक के कारण

धगुच्छेद २४ के अनुसार १४ वर्ष से कम झायु ने बच्चो को कारखानो, खदानो, या ऐसे कार्यों म दिनसे उनके शारीरिक या मानुसिक स्वास्थ्य को खतरा

९. चरमीसहबनाम पताब राज्य-ए० ब्राइ० ब्रार०, १८४८, एस०सी० १५२ ।

है, नियुक्त नही दिया जायेगा। सक्षेप में शोषण के विग्द क्रपिकार के धन्तर्गत न बेवल राज्य परस्तु ग्रन्य नागरिकों के कतिपय क्रतेंच्यों का स्पष्ट रूप से उल्केग्र क्रिया गया है।

धार्मिक स्वतंत्रता का ग्रधिकार

भारतीय सविधान द्वारा वर्स निरमक्ष राज्य की स्वापना नी गई है। धर्म-निरमेश राज्य का सर्थ है, वह राज्य जो किसी धर्म विनेष के सिद्धान्त। पर प्रापा-रित न हो कर न्याय, क्वतनता, समानता एक पारस्परिक सीहाद्र के सिद्धान्तो पर प्राधारित है जो जनतत्र के सिद्धान्त हैं, भारत के सनियान म धम-निरमश राज्य के दो साना है।

सर्वप्रयम, सविधान की प्रस्तावना म न केन्द्र भारतीय गणतम के ग्राधारमूत सिद्धान्तो का, जैसे न्याम, स्वतमता समानता एव आतृत्व ग्राहि, उत्स्त्र निया गया है, वरत यह मी स्पष्ट रूप से नताया गया है कि प्रत्येव नागरित को प्रत्य स्वतन्तात्राम के साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धान्ता म विषयास ग्रीर उपामना करने की भी स्वतन्ता प्राप्त है।

द्वितीय, सविधान में बर्म निरीक्ष राज्य वा दूसरा प्राचार नागरिका व धार्मिक स्वतन्ता के मूल खरिकार के रूप में हैं। सविधान ब्राइन्द्रेंद २५ स २८ नागरिता के बामिक स्वतन्ता के मल ब्रविकार का उत्लेख करते हैं।

धनु-देद २४ (१) वे धनुसार समन्त व्यक्तिया वो स्वनन्नतापूर्वच विसी भी धर्म वो मानने, उसवा पालन वरन तथा प्रचार वरन वा ध्रियदार प्राप्त है विन्तु इस ध्रियवार वा उपमाग सार्वजनिव मान्ति, नैतिवता ग्रीर स्वास्थ्य तथा धन्याय तीन वे ध्रन्य प्रावयानो वे ध्रयीन रहेवर ही विया जायगा। धनु-देद २४ (२) वे धनुसार राज्य निम्निलिति विषयो पर वानून निर्माण वर सहता है।

- (व) जिससे विसी धार्मिक प्रथा से सम्बद्ध प्रायिक, वितीय, राजनीतिक या प्रत्य विभी कार्रवाई को नियन्त्रित या सीमित किया जा सके, और
- (स) जिससे सामाजिक-करवाण एव सुवार या सार्वजनिक स्वन्य की हिन्दू पार्मिक मस्याधो म समस्त वर्गों के हिन्दुधो के प्रवेश के लिए व्यवस्था की जाये :

अनुष्टेद २६ के अनुसार अत्येक धार्मिक इकाई या उसके किसी हिस्से को सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता तथा स्वास्थ्य को सीमाओं के अधीन निम्नलिखत अधिकार हैं।

व-धर्म ग्रीर दान के उद्देश्यों से सस्याग्रों का निर्माण ग्रीर पीपण वरना.

ध--वार्मिक मामलो में स्वयं प्रवस्य करना.

ग-चन एव ग्रचल सम्पत्ति के स्वामित्व ग्रीर प्राप्त करने का ग्राधिकार, ग्रीर

च-इस प्रकार की सम्पत्ति का संचालन कानन के अनुसार करना ।

अनुच्छेद २७ के अनुसार किसी व्यक्ति का ऐसे घन के लिए कर नहीं देना होगा जा कि किसी धर्म विशेष या धार्मिक इराई, की प्रगति या पोपण पर सर्च हया है।

थन्त म अनुच्छेद २० (१) के अनुसार जिस शिक्षा संस्थान को सम्पूर्ण खर्च राज्य निधि से प्राप्त हो रहा है, वहां कोई धर्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। अनुच्छेद २८ (२) के ग्रनसार किसी शिक्षा संस्थान का प्रशासन राज्य द्वारा किया जा रहा है, परन्तु जिसकी स्थापना एक ऐसे धर्मादा-प्यास द्वारा की गई है, जिसकी शर्त है कि उनन सस्थान में घामिक शिक्षा दी जाये, बहाँ अन्बहेंद २० (१) नहीं लागू हागा, प्रयान् उत्त शिक्षा सस्यान मे पामिक शिक्षा दी जा सकेगी । धनुन्छेद २८ (३) के अनुसार यदि किसी शिक्षा संस्थान को जिसे, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या उसका राज्य निवि से अनुदान मिल रहा है, किसी व्यक्ति को जी वहाँ पढ़ रहा है, धार्मिक शिक्षा म, जो वहाँ दी जा रही है, या उस सस्था में या उससे सलग्द जगह मे की जाने वाली घाष्टिक उपासना में माग नेते के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, सिवाय, जबकि उस व्यक्ति ने और यदि वह व्यक्त न हाता उसके ग्रीममावक ने सहमति दी है।

यह स्पष्ट है कि भारत में घमें निर्पेक्ष राज्य की नीव, सविधान की प्रस्ता-थना और नागरिकों के धार्मिक स्वतवता के मूल अधिकार में निहित है। इन दोना आचारो पर स्थित है, नागरिको की 'समान व्यप से प्राप्त धार्मिक स्वतन्ता' । मारत म राज्य की धर्म निरपेक्षता इसी से विदित होती है कि राज्य के बिना हरनक्षेप ने प्रत्येक नागरिक को समान रूप से घामिक स्वनंत्रता का अधिकार प्राप्त है और जो भी सीमाएँ नागरिक के घामिक स्वतंत्रतः के ग्रधिकार पर सवि-थान द्वारा रखी गई है, वे समस्त नागरिको के लिए समान हैं।

मारतीय नागरिको का धार्मिक स्वतवता का अधिकार असीमित नही है। सर्विधान के अनुच्छेद २४ व २६ में छन कारणों का उल्लेख है, जिनके प्राधार पर धार्मिक स्वतंत्रना के अधिकार को राज्य द्वारा, सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता एव स्वास्मय के हिन म सीमित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप किसी भी यामिक सम्प्रदाय को ग्राम रास्ते पर जुलूस निकालने का ग्रविकार है, परन्तु इसन द्वारा वे उस धाम रास्त को जपयोग में लाने वे अधिवार से जनता की विचत नहीं कर सकत हैं। यदि उस समय न्यायाबीश ने सार्वजनिक शान्ति बनाय रखन के लिए कतियय धादेश दिये हैं तो वे उनका भी उल्लंधन नहीं कर सकते है। यह स्पष्ट है वि राज्य द्वारा पामिन स्वतन्नता वे म्नपिकार पर समाज के हित में, सविधान ने भनुसार प्रतिवन्ध समाये जा सकते हैं। इस प्रकार पामिन स्वतन्नता ने कारण किसी स्यक्ति को, इस पर भी कि मानव-बिलदान किसी धर्मे द्वारा स्वीकृत है मावन-बिलदान करने नहीं दिया जा सकता है। (जैसे मुद्ध तथों में) या नाई ऐसा कार्य जो कानानू में अस्तर्गत एक ध्रप्याय है, या तिसी वर्ग की धामिन मावनाम्ना का जानवूसकर धामात पहुँचाना। किसी धान के लेसे धी दोन का क्यन है— 'धामिन या धरत करण वी स्वतन्त्रता पर आधुनिन समाज में विशेषकर भारतीय समाज जैसे विविध-स्वरूपी समाज में, सोमार्ण ध्रवस्थमानी है।" र

सास्कृतिक एव शैक्षणिक ग्रथिकार

मारतीय सविधान में साहरतिक थ्रीर बैटाणिक घिषवारी वो रपने ना उद्देश्य प्रस्तास्ता में हिना की रहा नरता है। मारत एवं बहु पर्म, भ्रीर बहु-मापी राष्ट्र है, ध्रतएवं सारतीय मणतत मं अस्वसहस्वा नी विशेष स्थित के सन्दर्भ , उनने हिना की राष्ट्र है। क्रांत की राष्ट्र के स्थान के स्थान हिना की राष्ट्र की स्थान प्रस्ता रिवा है कि उनने अन्तर्भत (अस्य सस्यव) पद है। इन प्रधिवारों वी एवं बहु विवेदता है कि उनने अन्तर्भत (अस्य सस्यव) पद सहस्ता मारता है। इस सन्दर्भ में ग्रह्त सर्पण पद्द से ताल्पर्भ केया प्रसार की सम्यवी अस्यवस्था अस्य स्थान ही ही ही ही ही उननु भाषा, लिपि, श्रीर सस्यृति सम्यवी अस्यस्थानों से भी है। यारत में एवं दर्जन से ग्रांधर विवक्षित भाषाएँ हैं प्रत इस ग्रंधन राष्ट्र विवक्षित महस्त है।

अनुक्छेद २६ (१) वे अनुसार भारत या भारत ये विसी भी भू-भाग में रहने वाले नागरिनो वे विसी मी ऐसे जन-समृह नो जिसवी अपनी पृथव माया, तिषि या सस्वति है, यह अधिवार है नि वह अपनी भाषा, निषि या सस्वति वो बनाये रखे। अनुस्छेद २६ (२) वे अनुसार यदि बोई शैक्षाणिक सस्या राज्य द्वारा याय वो सहायता से सचालित की जा रही है तो उसमें प्रवेश हेतु वश, जाति, पर्म ग्रीर भाषा या दामें से निसी एक वे आधार पर मेंद-भाव नही विया जा सकता है।

घरप सरपनो ने हित में धनुःखेद २० (१) द्वारा यह प्रावधान निया गया है कि समस्त प्रत्यसख्यनों को पांहें ने घमें या नापा सम्बन्धी थयों न हो प्रपते इच्छा की सैदाणिन सस्याधों ना सचालन वरने ना प्राधिनार है। धनुच्छेद ३० (२) ने प्रमुसार शैदाणिन सस्याधों नो प्रनुदान देते समय राज्य इस नारण

१. डो० डो० वसु---पूर्वोक्तः पुस्तवः, पृ० १५४।

२, टी० के० टोपे---द कान्स्टीट्यूशन द्याफ इष्डिया, १९६३ पृ० १३३।

मेद-भाव नहीं करेगा कि क्सी शैक्षणिक सस्या का सम्रालन किसी घर्म या गाया सम्बन्धी श्रह्मसध्यकों की इकाई के हाथों में हैं !

नागरिको के ग्रीशांकिक और सास्कृतिक मूल प्रभिकारों की एक प्रस्य विकेषता यह है कि राज्य तथा नागरिक के सम्बन्धों के सन्दर्भ में यह प्रशिकार असीमित है प्रमृति हन प्रशिक्तारों को राज्य को बिना किसी सीमा के बाध्यकारी हुए से मानना होगा।

सम्पति का ग्रधिकार

सामतः धांपवासे में, जीवन, स्वतंत्रता एवं सम्पति के धांपकार प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। राजनीतिक चित्तन में प्राचीन समय हे इन धांपकारों के मध्य पर स्तय-माम पर बन दिया गया है। समति व मधिकार, बास्तव में उद्य पत्र के हम में है, जिससे मानव व्यक्तित्व का विकास होता है ४ धरस्तू जो राजनीति स्रोत ना जनक माना गया है, व्यक्तिगत सम्पत्ति को मानव व्यक्तित्व के मिनास के लिए प्रायस्थ्य समझता है।

रासेच्य, यसरीवा, जांस, बायरसंख्य झारि देशो के सर्वेधातिक वानून में व्यक्तिमत सम्पति का महत्त्व वृद्धियोवन होता है। इसी प्रकार मारतीय संविधान के सर्वृद्धिय १६ (१) (एक) के मुत्राद्ध १६ होता है। वा प्रतिक्षा संविधान के सर्वृद्धिय १६ (१) (एक) के मुत्राद्ध १६ होता है। दाके प्रतिचित्र, मारतीय सिवधान के स्वृद्धिय ११ के स्वृद्धिय ११ के स्वृद्धिय वा प्रतिक्षा प्रतिक्ष सिवधान करने, प्रतृद्धिय ११ (१) के मुत्राद्ध किया में व्यक्ति को सिवधान कर्त्य है। इत्यक्ष होता किया में व्यक्तिय सम्पति से प्रत्यक्ष ११ (१) के मुत्राद्धिय स्विधान सम्पति से विश्व त्यक्ष सिवधान क्रिया च्या होता का स्वृद्धिय ११ (१) का प्रतृद्धिय के सिवधान क्रिया व्यक्तिय स्वर्धान क्रिया क्ष्य स्वर्धान क्रिया व्यक्तिय स्वर्धान क्रिया व्यक्तिय स्वर्धान क्रिया व्यक्तिय स्वर्धान क्रिया क्ष्य स्वर्धान क्रिया स्वर्धान क्रिया क्ष्य स्वर्धान क्रिया व्यक्तिय क्ष्य स्वर्धान क्रिया व्यक्तिय क्ष्य स्वर्धान क्ष्य स्वर्धान क्ष्य स्वर्धान क्ष्य स्वर्धान क्ष्य स्वर्धान स्वर्धन स्वर्यन्य स्वर्यन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्यन स्वर्धन स्वर्यन्यन स्वर्धन स्वर्यन्यन स्

भग यह स्पष्ट है कि मुद्रावज का निर्धारण करने में व्यवस्थापिक सभा को ही सन्तिम प्रधिकार है।

हा यान्तम प्राधवार है। सक्षेप में प्रमुक्टेद ३१ (१) व (२) डारा निम्नलिखित तीन मुद्दों का उल्लेख क्याग्या है।

१-किसी मी ब्यक्तिको विना कानून के उसकी सम्पति से बन्ति नही विचा जा सकता है। २—सरकार किसी व्यक्ति या सस्पा वी सम्पति को 'सार्वजनिव उद्देश्य' वे लिए मंजित वर सकती है भौर इसवे लिए उसे मुभावजा देना होगा।

३—मुद्रावजे नी राशि का निर्यारण व्यवस्थापिना द्वारा होगा छोर न्यायासय को इसे उचित या धनुचित ठहराने ना धांपिनार नहीं है। धमरीना में सरनार द्वारा सम्पति भाजित करने पर जो मुद्रावजा दिया जाता है, उसने सम्बन्ध में न्यायालयों को ध्रयिकार है कि यह निर्धारित करें नि मुग्रावजा उचित्त है या धननित।

अनुन्धेद २१ (२) ने अनुसार यदि निसी राज्य नी विधानसमा द्वारा ऐसी विधि, जिसका उटनेत अनुन्धेद २१ (२) मे निया गया है, निमित नी गई है, तो यह तब तन प्रमाची नहीं होगी, जब तन नी राष्ट्रपति ने उक्त विधि नो अपी

स्वीकृति न दे दी हो।

मनच्छेत २१ (४) ने भनुतार भी यदि नोई विषेषन निसी राज्य विधान सभा ने समक्ष सविधान ने सामू होने ने समक्ष रहा गया है, भीर उनत विधानि, क् सभा झार पारित होन्द उसे राष्ट्रपति नी स्त्रीहति प्राप्त हो जाती है, सो उना विधा पर निसी न्यामात्स ने समक्ष स्म नारण श्रापति नहीं नी जायेगी नि वह भनुच्छेत २१ (२) ने विषद है।

अनुच्देत ३१ उपनम्य ५ वे अनुसार उपनम्य २ में उस्लेखिन मुमायने सम्मन्धी बानून का निम्नतिष्वित विषयो पर कोई प्रमान नहीं होगा ।

य--- विसी भी स्थापित कानून पर, क्षेत्रल ऐसे कानून को छोडरर जिस पर उपबन्य ६ लागु होना है।

प्र—ऐसा बानून जो राज्य द्वारा निम्नलिखित विषयो पर निर्मित हुन्ना है —

१-- नोई बर या प्रयं उण्ड लगाने के लिए।

?--सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने प्रयवा जीवन या सम्पनि के सहस्र के निवारण के निष्

३--ऐसे समझीतो वी गर्नो को पूरा करते के लिए जो मारतीय डोमोनिया की प्रथवा मारत सरकार एव किसी घन्य देश की सरकार के मध्य किया गया है, प्रथम निष्यान्त सम्यति से सर्वधिन कातून ।

ष्रतुःदेत ३१ (६) के धनुषार यदि बोई कानून सविवान के लागू होंने के १० मार से प्रिक समय पूर्व राज्य द्वारा बनाया गया है, तो तीन महिने के प्रदर उक्त बानून की राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित करा देता है, तो किसी ज्यायालय में उक्त बानून पर इस प्रावार पर प्रापति नहीं की जावेगी कि वह उपवाय २ के विकद है।

٧o

सविधान लागू होने के पश्चात् यह भ्रमुमद किया गया कि भ्रमुच्छेद ३१ के विभिन्न उपवन्य मारत मे विभिन्न सरकारो द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके प्रतिरिक्त, जब विमिन्न राज्यों की, जैसे— बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सरकारों ने जमीन्दारी उन्मूलन के लिए कदम उठाये, न्यायालयो ने इसे अनुचित ठहराया । पटना उच्च न्यायालय झारा बिहार-भूमि-सुधार अधिनियम १९५० को इस कारण अवैध घोषित किया गया कि वह अनुच्छेद १४ द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसार समानता के अधिकार के विरुद्ध है। इसके फलस्वरूप सर्विधान संशोधन अधिनियम १६४१ द्वारा सर्विधान में संशोधन कर दो नये ग्रनच्छेदो ३६ (ग्र) ग्रीर ३१ (ग्र) एव एक ग्रन्य ग्रनसुबी (नवी) को जोडा शया ।

भनुच्छेद ३१ (म) के सनुसार यदि किसी कानून द्वारा किसी सम्पति के स्वामी या जमीन्दार के अधिकारी की सीमित या समाप्त किया जाता है तो उक्त कानन को केवल इस कारण अर्वध नहीं माना जायेगा कि उसके द्वारा अध्याय तीन मे प्रदत्त मूल अधिकारों में कभी कर दी गई है या उन्हें समाप्त निया गया है। धनुच्छेद ३१ (ब) नवी धनुसूची मे उल्लिखित अधिनियम इस आधार पर अवैध नहीं ठहराये जा सकते हैं कि अध्याय तीन के अनुच्छेदी एवं नियमी का उल्लंघन करते हैं। धौर किसी भी न्यायालय के विपरीत निर्णय, डिकी या आदेश के बावजूद मी इनकी वैध माना जायेगा। धनुच्छेद ३१ (व) द्वारा स्थापित नवी अनुसूची मे इस प्रकार के १३ अधिनियम हैं।

परम्तु राज्य द्वारा अजित की हुई सम्पति के लिए, जमीदारी सम्पति की छोडकर मुझावजा देने के लिए अभी भी कठिनाइयाँ थी। सन् १९४४ में जब सरकार ने अस्थायी रूप से शोलापुर के सूती मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया. सर्वोच्च -यायालय ने इसे इस धाधार पर धर्वेष ठहराया कि कोई मुमावजा नही दिया गया या । इसके फलस्यरूप सर्विद्यान संशोधन अधिनियम १६५५ (चीया संशोधन) पारित विया गया, जिससे उपर्युक्त उल्लिखित कठिनाइयो की दूर किया जा सके। चौथे संशोधन अधिनियम १६४४ के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान किये समे ।

(१) जो सम्पत्ति धनिवार्षत अजित को गई है उसके लिये मुझावजे का निर्यारण राशि के रूप में निर्यारित किया जाये या विशिष्ट सिद्धान्ती का निर्धारण किया जाये जिनके बाधार पर मुझावजा दिया जायेगा। िस्ती भी कानन को जिसके द्वारा राज्य धनिवाय एप से सम्पति का धर्जन करता है किसी न्यायालय मे इस कारण चुनौती नहीं दो जायेगी कि मुभावजा पर्याप्त नहीं है।

- (२) जहाँ पर कानून द्वारा राज्य को सम्पति ने प्रमुख ग्रीर रखने का ग्रामिकार हत्तान्तरित नहीं किया गया है, निन्तु केवल प्रवन्य करन का ही प्रमिक्त कार दिया गया है, उदाहरण स्वरूप होतापुर मिल प्रकरण में, वहीं यह नहीं माना जायेगा कि उस कानून द्वारा सम्पति के प्रनिवार्य प्रजन के लिए प्रायवान किया गया है, यह उस कानून द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी सम्पति से विवत्त किया गया है, ग्रीर ऐसी स्थिति से मुमाबक का प्रकर्ण नहीं होगा।
- (३) जो उन्मुक्त अनुन्देद ३१ (भ्र) के द्वारा जनीवारी उन्मूलन के कानूनो नो न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से, ऐसे बानूनो को मीलिक प्रधिकारों से समर्प में होन की स्थिति म, दी गई थी, उस प्रकार की उन्मुक्ति को निम्नलिखित विषयों के लिए भी लागू किया गया।
- (न) कोई कानून जिसके द्वारा राज्य निसी सम्पति या उसस सम्बत्यित ग्राविकारो को प्रजित करता है या जिसके द्वारा ऐस ग्राविकारो को समाध्य या परिवर्तित करता है, या,
- (ख) कोई कानून जिसके द्वारा राज्य विसी सम्पति का प्रवन्य अपने हाथ में सेता है, या,
- (ग) ऐसा नानून जिसके द्वारा दो या श्रिष्ट निगमों नो सार्वजनिक हित मे या इनमें से किसी निगम के उचित प्रवन्ध ने लिए साथ मिलाया जाता है, या,
- (प) कोई ऐसा कानून जिसके द्वारा किसी प्रवन्धन ग्रमिक्ती, सचिव या निगमी के प्रवन्धकों के ग्रीषकारों को समाप्त किया जा सकता है, या,
- (ह) कोई ऐसा कानूम जिसके द्वारा किसी ऐसे प्रधिवारों को समाप्त या परिवित्ति किया जाये, जिनकी उत्पत्ति विसी समझौते, पट्टे या लायसेन्स से स्वित्व पदार्थ या सनिव तेल खोजने और प्राप्त वरने से हुई है, या ऐसा कानून जिसके द्वारा किसी समझौते पट्टे या लायसेन्स को उसकी समयाविष पूरी होने के पूर्व ही समाप्त किया गया है।

सन १६५५ के चीपे सर्विधान संघोधन के फलस्वरूप नवी प्रमुख्नी में उल्लेखित १३ प्रधिनियमों की सस्या में वृद्धि करके कुल २० प्रधिनियम कर दिय गये।

सक्षेप में, १९४६ में चीये सर्वियान सक्षीयन प्रधिनियम के लागू होने के फनस्वरूप राज्य द्वारा सम्पति प्रविपृष्टीत करने पर मुजाबजे के प्रश्न पर अधिग्रहण कानून को न्यायालय म चुनौती नहीं दी जा सकती है। मुजाबजे के विषय पर स्थवस्थापिका का निर्णय प्रतिन्त होया। "यदि सम्पति का प्रधिकार न्याय्य नहीं है तो प्रव वह मुल प्रधिकार नेया हो है तो प्रव वह मुल प्रधिकार नेया हो है तो प्रव वह मुल प्रधिकार की विशिष्टता मह है कि इसको न केवल कार्यपालिका की स्वेष्ट्याचारिता किन्तु वियापी बहुमत

को निरकुतता के विरक्ष भी बत्याभूत किया जाता है। यह पहलू झब सम्पति के प्रिचनार पर, जो मूल प्रिचितारों के सम्प्राय में निहित है, कम लागू होता है। दूसरे कदों से जहीं तक सम्पति के प्रधिकार का सम्बन्ध है, ससद ही स्वानेश हैं।"

ХŞ

स्रतप्त सनुष्टेंद्र २१ के सन्तर्गत यदि राज्य निक्षी सम्पति को सार्वजनिक उद्देश्य के तिए स्रियमृहीत करता है, तो १६४४ के चौथे तथीयन स्रियमियम के स्रमुक्तार पुष्तानजे के प्रमन् पर त्यासालय मे चुनीती नहीं दी जा सकती। परन्तु सस्य दे जब के राज्येशकरण समिन्तुन पारित निक्ता तो हर कानून को सर्वोच्य स्वायासय के समक्ष चुनीती दी गई थी। सर्वोच्य स्वायासय ने स्नृच्छेद २१ की व्यास्था न रते हुए निर्णय दिया कि मुधायना अमपूरक नहीं होना चाहिये सुधायने कि निर्यारण में न तो गलत सिद्धानों को लागू करना चाहिये और न ही सही सिद्धानतों की उपेक्षा परनी चाहिये।

सर्वोच्च नायात्वात ने यह निर्णय भी दिया चि मुप्रावजे के प्रश्न के सम्बन्ध में न केवल प्रमुख्य ११ परन्तु अनुन्ध्य ११ (१) (एक) श्री धारयण्यन्तायों नो भी पृथा निया जाना चारिये। धनुन्ध्य ११ (१) (एक) प्रायेक नायांकि को सम्वत्त एको का प्रशिक्त र उत्तर करता है, परन्तु सार्वजनिक हिन में तर्क समद सीमाएँ समाई का सनती हैं। बैक राष्ट्रीयकरण कानृत के समस्य में सर्वोच्च नायात्व्य क उपर्युक्त निर्णय वे कारण भीमती याथी की सरकार ने पारणे सार्थाव्य क्या सार्यक्क भीतियों को सारन बनाने वे निए यह धाययण्यता मृद्धुस को कि सत्तर को मूल घरिवरां ने संस्थावन करने वा प्रशिक्त होना चाहिये और सम्पत्ति के स्थिकार में कुछ भीर सत्तेष्ठन नियं का ने चाहिये। प्रत २४वें वविषान सर्वोच्य प्रविचित्तम को १ तबस्य १६०१ से लागू करने के परिणाग स्वच्य सत्तर को पुत-मूल प्रशिक्तरों के सत्त्रीयन करने ना प्रशिक्तर प्रायत हुष्मा, जिससे उत्तरों १६७ संबोच्य नायात्व्य द्वारा सोकन्यत्व प्रस्त को परिणाग स्वच्य सत्तर को सुत-स्त्रीक स्वायात्व्य द्वारा सोकन्यत्व प्रस्त को परिणाग स्वच्य सात्र हो होने के तत्काल बाद १२वर्ष सत्त्रीयण विधित्त्वम पारित निया गया जिससे सम्पत्ति के प्रशिवत्व प्रस्त स्वार के प्रश्निवत पर स्व

वन्त्रीसर्वे संवोपन के दो मुख्य भाग हैं। पहले माग ना उद्देश्य २१ में संघोषन करता है। जेला देवा जा चुका है, प्रमुद्धेद २१ के प्रस्तर्गत यदि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य में जिए सम्पति धर्मिज नगता है। तो अपने लिए सुप्रावदा देना होगा। यदिंग, मुधान्दा ग्याप्य नहीं होगा। पन्त्रीसर्वे संघोषन प्राप्तित्यम के प्रमुखार

१ एम० बी० पायली—'पूर्वोक्त पुस्तक' पृ० १३०।

सविधान म से 'मुम्रावजा' शब्द को हटाकर उसके स्थान पर 'राशि' झस्द रखा गया है।

पच्चीसबे सबोधन प्राधिनयम ना दूसरा भाग अनुच्छेद ३१ म एन नई धारा ३१ (सी) जोडता है। इस नई धारा ३१ (सी) वे अनुसार यदि निसी मानून म यह निला है कि इसका उद्देश्य उन राज्य मीति निर्देशन तत्या वो जियान्यमन करता है जिनका उत्तेश अनुच्छेद ६९ (वी) एव (सी) मे है घौर जिसना उद्देश्य समाज ने मीतिन साधनो वे वितरण हारा सामाग्य हिन की आदि करना उद्देश धान तथा उदायदन ने साधनो वे एवधीनरण यो रोगना है तो निसी व्यक्ति नो यह प्रधिवार नहीं होगा नि ऐसे नानून नो अनुच्छेद १४, १६ एव ३१ ने प्रधार पर चुनीनी दे। इसने प्रतिरिक्त, इस अनार ने यानून नो, जिसरा उद्देश्य उपर्युक्त साधार पर चुनीनी नहीं चा वियानयम करना है, दिसी न्यायालय में इस प्रधार पर चुनीनी नहीं दी जा सवेगी वि उसने द्वारा उक्त नीनि या व्रियान्ययन नहीं किया गया है।

पच्चीसर्वे सशोधन प्रधिनियम की कडी धालोचना की गई है, जिसके निम्न-तिखित धाषार हैं।

१—इसके परिणाम स्वरूप मूल प्रधिवारो नी वस्तुस्थित यह हो गई है वि इनको राज्य के नीति-निर्देशक तस्वो के प्रधीन कर दिया गया है।

२—इस समोधन प्रधिनियम द्वारा धारा ३१ (सी) जोडने से एन ऐसी विधित्र स्थिति हो गई है कि यद्यपि मूल भविकार सविधान मे तो है, परन्तु बास्तव म इस नई ३१ (सी) धारा की भ्राड मे मूल प्रधिकारों को बम या समाप्त विया जा सकता है।

यह विचित्र-सा लगता है नि जबनि किसी मूल फ्रियिकार में सशोधन के लिए ससद के उपस्थित और मतदान करते वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमल प्रावस्थन है, प्रगुच्छेद ३१ (सी) वे अन्तर्गत कानून, जो मूल फ्रियकारों के विकद ही सकता है, व्यवस्थापिना समा वे केवल साधारण बहुमत से पारित निया जा सकता है।

३—इस नई धारा ३१ (सी) से न केवल सम्पति वे प्रधिकार का प्रति-क्रमण होता है, परन्तु प्रन्य प्रधिकारों का जो कि सम्पति के प्रधिकार से सम्बन्धित नहीं है, जैसे—सायण और प्रमिव्यक्ति की स्वतत्रता, समुदाय व सथ निर्माण करने की स्वतत्रता मारत में विसी भी हिस्से में निवास फरने की स्वतत्रता का भी प्रतिक्रमण, धार्थिक सत्ता के केन्द्रित होने वे बहाने, किया जा सकता है।

४—ऐसे कानून को, जिसका उद्देश्य राज्य के नीति-निर्देशक तत्वो का क्रिया-न्वयन वरना है नागरिक इस घाघार पर चुनौती नही दे सवता है कि वास्तव मे उक्त कानून द्वारा नीति-निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन हो सकेगा या नहीं । समवत इसका परिणाम यह हो सकता है कि ऐसे कानून से यदि मूल अधिकार राजनीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के प्रयत्न में समाप्त होते हैं परन्तु वास्तव में राज्य नीति-निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन नहीं हुमा है, तो जनता की एक साय दो ग्रन्यायो को सहना होगा।

५--- घारा ३१ (सी) के अनसार राज्य विधान समाएँ मी ऐसे कानून पारित कर सकती हैं जिनसे मूल ग्रथिकारी का हनन होगा। यद्यपि साधारणतया किसी राज्य विधान समा को एक मूल अधिकार में भी संशोधन करने का अधिकार नहीं है, किन्तु बारा ३१ (सी) के अनुसार यदि कोई विधान सभा ऐसा कानून पारित करती है जिसमे यह लिखा है कि उक्त कानून का उद्देश्य किसी मीति-निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन करना है, तो इसके बावजूद कि यह कानून भूल अधिकारी का हनन करता है, वह वैध होया।

६—ग्रन्त में. पच्चीसर्वे सशोधन ग्रधिनियम से ग्रत्यमतो के ग्रधिकारो पर जो कि सर्विधान के अनुष्छेद २५ से ३० में निहित हैं, आधात पहुँच सकता है। धन तथा ग्राधिक सत्ता के वेन्द्रीयकरण को रोकने के बहाने ग्रल्पमती के बिमिन्न श्रविकारो का कानन द्वारा श्रतिक्रमण किया जा सकता है।

धतः पच्चीसर्वे सविधान संशोधन के फलस्यरूप, सम्पति के प्रियंगार का ग्रस्तित्व पूर्णे रूप से व्यवस्थापिका की उच्छा पर निर्मर हो गया है।

सर्वैधानिक उपचारो का ग्रधिकार

नागरिको के उपर्युक्त छ. भूल अधिकार जिनका अध्ययन किया गया है, पृषक सत्तापूर्णं या सकारात्मक प्रधिकार हैं। परन्तु नागरिको को प्रदत्त सातवाँ मूल भविकार, वास्तव मे 'प्रक्रियात्मक अधिकार' है क्योंकि इस अधिकार के अन्तर्गत, . भन्य किसी अधिकार के लिए उपचार प्राप्त करने के लिए नागरिक उपयक्त न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस ग्रविकार के ग्रनुसार सर्विधान मे उल्लिखित प्रक्रियानुसार नागरिक ग्रंपने किसी मूल अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति मे न्यायालय मे जाकर उपचार प्राप्त कर सकता है। इस सन्दर्भ में प्रनुच्छेद ३२ (१) के प्रनुसार नागरिकों को अपने मूल प्रविकारों को लागू परवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाने का अधिकार है। अनुच्छेद ३२ (२) के धनुसार, मूल ग्रविकारों के लिए उपचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश, घादेश या रिट जारी वरने का ग्रधिकार है। यह रिट विभिन्न प्रकार को है।

१—बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लिए मपुक्त शब्द Habeas Corpus लेटिन मापा के शब्द का अर्थ है, 'शरीर दो !' यदि किसी व्यक्ति को बन्दी बनाया गया है, तो न्यायालय इस स्टि द्वारा बन्दी व्यक्ति को पेश करने की श्राजा देता है। श्रत यह स्टि बस्तुत बन्दी बनाने वाले व्यक्ति को न्यायालय के एक श्रादेश के रूप में है कि बन्दी व्यक्ति को २४ घण्टे मे न्यायाधीश ने समक्ष उपस्थित किया जाये।

भारत मे इस रिट को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जारी कर सकताहै।

२—परमारेश (Mandamus) परमारेश के लिए प्रमुक्त गन्द Mandamus सैंटिन माया का गन्द है, जितवरा धर्म है—दिन धाता देत हैं। इस रिट द्वारा उपयुक्त न्यायालय किसी व्यक्ति या सस्या को यह धारेश दे सक्ता है कि यह धरने वानुन द्वारा निर्धारित कर्तव्यो तथा दायित्यो ना समुचित, रीरयानुसार निर्वाह करे। उदाहरण के लिए, यदि किसी मिल मे ध्रपना कार्य करते हुए कोई श्रमिक हताहत हो जाता है तो मिल प्रपिकारियो को श्रमिक को श्रमिक कानूनो के धन्तर्यंत उचित मुमावना देना चाहिये। यदि यह मुधावना नही दिया जाता है तो उच्च न्यायालय द्वारा परमारेश जारी कर मिल प्रधिकारियो को छितत मुमावना देने सिल प्रधिकारियो को छितत मुमावना देने के लिए वाध्य क्या जा सकता है।

२---प्रतिषेष (Prohibition) यह रिट एवं उच्च न्यायालय द्वारा निम्न-न्यायालय के लिए निम्नलिखित कारण वश जारी की जा सनती है।

(1)--यदि निम्न न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है, या,

(11)--प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन किया है।

यह रिट किसी ऐसी सस्थाके विरुद्ध भी जारी नी जा सनती है जिसनो भ्रद्धेन्यायिक मधिनार प्रदक्त हैं।

Y--उत्प्रेषण (Certioran) Certioran शब्द वा धर्म है--'पूर्णतम सूचित होना !' इस रिट के प्रतुसार विसी उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय या धर्द न्यायिक प्राप्तकारी नो यह प्रार्देश दिया जाता है कि जो मुतदमा उसके समक्ष विचारार्य पड़ा है उसे उच्चतर न्यायालय के सम्मुख मेज दे। उत्प्रेषण रिट को जारी करने ने टी नारण है।

(क) यदि किसी निम्न न्यायालय या प्राधिकारी नो कानून के झन्तर्गत सुकदमे पर विचार नरने का प्रधिकार है, या

(ख) यदि भ्रन्याय होने का डर है।

५—प्रधिकार पृच्छा (Quo Warranto) Quo Warranto का प्रषं है— 'किस प्रधिकार से।' इस रिट के द्वारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को, जो निसी पद पर कानून के धनुसार निर्वाधित या नियुक्त नहीं हुधा है, परन्तु जो उस पद को ग्रहण निये हुए है, या उस पर दावा करता है, यह धपने दावे का समर्थन करता है। बत यह स्पष्ट है कि ब्रविकार-पुच्छा रिट नो लागू करने का उद्देश्य किसी पद के अवैद्यानिक रूप से धारण किये जाने की रोकना है।

सर्वेषानिक उपचारो का मूल प्रविकार दो प्रकार के ग्राश्वासन देता है। सर्वप्रयम, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका पर सविधान में इस ग्रंधिकार के

होने से एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक अवरोध है जिसके कारण वे नागरिको के मूल ग्रविकारो का उल्लघन करने ने लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे।

हितीय. यदि किसी नागरिक के मूल श्रधिकार का व्यवस्थापिका या कार्य-पालिका के कार्यों द्वारा हनन होता है तो पीडित नागरिक को सबैधानिक उपचार का ब्राख्वासन है। "जो रिट (लेख) हमारे सविद्यान में उल्लेखित हैं, वे मूल हैं। यह व्यवस्थापिका पर एक सीमा के रूप मे हैं। सविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रधिकार प्रदत्त निये गये हैं, और इन रिट को समाप्त नही किया जा सकता है, अब तक कि स्वयं सर्विधान का संशोधन ऐसे साधनों द्वारा जो व्यव-स्थापिका को प्रदत्त है, नहीं किया जाता है।""

नि सदेह सर्वधानिक उपचारो का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यह प्रधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यह प्रधिकार प्रन्य अधिकारो का पोषक है। सनिधान समा में, अनुच्छेद ३२ के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए डा॰ घम्बेदकर ने कहा---"यदि मुक्त से सविधान में सबसे महत्वपूर्ण धनुज्छेद के लिए पूछा जाय-ऐसा धनुच्छेद जिसके बिना सविधान निरयंक हो जायेगा,

तो मैं सिवाय इस अनुच्छेद के किसी अन्य अनुच्छेद की और सकेत नहीं कहेंगा। यह सविधान की ग्राह्मा है. उसका हदय है।"2

१. एम॰ जी॰ गुप्ता—बास्पेक्ट्स ब्राफ द कान्स्टीट्यूसन ब्राफ इण्डिया, पृ० १वेद, सन् १६६४।

२। बी॰ घार॰ बाम्बेदकर-कालटीट्एस्ट ब्रसेम्बली डिवेट्स, भाग-६ स॰ ₹**₹ १० ६**१३ ।

राज्य नीति-निर्देशक तत्व

प्रापृतिक युग म लोक्तन ने सन्दर्भ म राजनीति निज्ञान ने प्रन्तर्गत यह सत्य है कि लोकतम ने दो पहलू होत हैं (1) राजनीतिक धौर (11) प्रापित्र । साधारणतदा एक लोकजानिक संविधान का उद्देश राजनीतिक लाक्तन ने स्था-राज करता होता है किन्तु प्रापिक समानता को प्रनुपत्थित म राजनीतिक सक-तत्रता का कोई मूल्य नहीं होगा । प्रतप्य राजनीतिक लोक्तन ने लिए सविधान मे प्रावधान प्रपन्ने धाप मे पर्याप्त नहीं हैं । इस कारण राजनीतिक लोक्तन की बड़ो को सबक्त करने के लिए प्रापिक लोकतम का होता प्रत्यन्त धावस्यक है । जिस देश म राजनीतिक लोक्तन ने सचका करने के लिए प्रापिक लोक्तन नहीं है वहाँ निरकुरता को स्थापना मे निक्चय ही देर नहीं होंगी । यदि मूल प्रविकारो द्वारा मारत म राजनीतिक लोकतम ना प्राव्यासन दिया गया है तो राजनीति निद्याक तत्व द्वारा प्राप्त ने लोकतम न विकास के लिए प्रारक्षात्व दिया गया है जिसमे उसकी (राजनीतिक लोकतम ने विकास के लिए प्रतप्त राजनीति निद्याक तत्व भारत मे वास्तविक लोकतम ने लिए सबस यहा प्रायक्षात्व है ।" ।

प्रव प्रश्न यह है कि राजनीतिक लोकतंत्र का क्या धर्म है ? राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमित्राय ऐसी सरकार से हैं, जो जनता द्वारा प्रमित्र्यत बहुमत के प्राचार पर स्थापित है, पर्यात ऐसी सरकार जिसके निर्माण के लिए नागरिका ने भवनी व्यक्तिगत धीर राजनीतिक स्वतत्रताधों का पूर्ण उपयोग किया है धीर जो विधि सासन पर प्राचारित होते हुए नागरिकों के विचारों की धीमव्यक्ति तथा सगठन निर्माण करने की स्वतत्रता प्रदत्त करती है।

नि सदेह, राजनीतिक सोकतन की मादस्यनतामा नो मारत के सविधान के मन्तर्गत मान्यता दो गई है। परन्तु माधिक लोकतन के उद्देश्य नी पूर्ति के लिए मारत म विभिन्न सरकारो पर सविधान द्वारा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व रक्षा गया है। जैसे डा॰ एस॰ सी॰ डेब का कहना है—'सामाजिक एव प्राधिक क्षेत्रों मे

१. एम० बी० पायली, 'इण्डियाज कान्स्टीट्यूशन, १६६२ पृ० १५४।

ग्रमी मी मारत का गमीर उत्तरदायित्व है। राजनीतिक लोकतव का समाज की उन सीमाग्री को जो समाज के विभिन्न बगों में मेदमाव स्थापित करती है, दूर क्यि जिना राजनीतिक लोक्तिव वा कोई धर्य नहीं होगा । इसी प्रकार, गरीबी तथा जीवन का ग्रत्यिक निम्न स्तर मास्त की जनता के राजनीतिक पिठडेपन

के नारण थ । मामन्तवादी जमीदार ग्रीर पूजीपति सरलना पूर्वन राजनीनिक ग्रिज्ञारों में व्यापार करके जनता के राजनीतिक जीवन को भ्रष्ट कर सकते हैं.

यदि सापारण नागरिक को अपनी बावक्यकताओं और मूख से छ्टकारा प्राप्त नहीं होता है।" वस्तुत , विना ग्राधिक नोकतत्र के राजनीतिक लीवतत्र केवल इन्द्रचात के

मदम हो होगा। सोक्तव म राजनीतिक स्वतवताएँ धर्महीन हैं, जब तक नाग-रिको का समान ग्रायिक ग्रवसर नहीं प्राप्त हैं। प॰ जवाहरताल नेहर न इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है—'हम स्वतवना की चर्चा करते हैं, हिन्तू जब तक ग्राधिक स्वतवता नहीं है, तम तक वेदल राजनैतिक स्वतत्रताही हमें ग्रापे नहीं से जासक्दी। वास्तव में, एक व्यक्तिओं मूला मर रहा है या एक देश जो गरीब है, उसके लिए स्वनत्रता का कोई धर्म ही महीं हैं।"रे

समाज में ग्रायिक ग्रममानताथों के विद्यमान होने से, राजनीतिक ग्रयिकार ग्रन्यावहारिक हो जाते हैं। प्रो॰ हेरल्ड लाम्की का क्यन है— 'दसका तालयं है वि रूम मान्यवानी व्यक्तियों की भौतिक तथा बौद्धिक परिन्यितिया का निरक्ता-सापूर्वक निघारण करना । इसका तात्पर्य है सरकारी-यत्रा का नियन्त्रण, उनकी हानि के लिए करना।"3

टमक ग्रतिरिक्त प्रा॰ साम्की कहते हैं—"राजनीतिक समानना वास्तदिक नहीं है, यदि इसके साथ श्राधिक समानता नहीं हैं, प्रत्यथा राजनीतिक सत्ता (ग्रधिकार)

ग्रायिक सत्ता के कवत सायन के रूप में हा जायगी।"¥ राजनीतिक क्षेत्र म ग्रधिकारा का कोई उपयोग नहीं रह जाता है-विका

प्राय दुरुपयान ही होना है, यदि नागरिका की ग्रायिक ग्रावश्यकताग्री की पूरा नहीं विवा जाना है। उदाहरण स्वरूप साम चुनाव के दौरान प्राय पैसा क बन

१ एम० सी० डेंग-'द कालटीर्युशन झाफ इण्डिया', १६६०, पुरु 1558 २. प० नेहरू-'द कवीन्टऐसेन्स बाफ नेहरू' (के० टी० नर्रासह चर द्वारा सम्यादित) १६६१, पु० १४६।

२. एच ॰ सास्त्रों-'ए ग्रामर ग्राफ पालिटिक्स', १६३७ पु० १६१।

४. एव० सास्को--'पूर्वास्त पुस्तक' वृ० १६२ ।

पर धाविन मारो से लदे हुए गरीब मतदाताधों मी विनिन्न प्रकार ने लोगों से निसी एवं पढ़ा में मत देने ने लिये प्रमावित तथा अपट नरते में प्रयत्न विच जाते हैं, जितने चुरे परिणाम इस सत्य नी पुष्टि नरते हैं नि राजनीन पर सोचता नो सोचता मार्चिन ने धाविन भाविन परिचार करते ने नरते की प्रायमिक महत्न दिया जाना चाहिन।

राजनीति विज्ञान वो इन पारणामा वे सन्दर्भ में जुनुगारिक प्रविद्याला है। नगरिकों के राजनीतिन एव माधिन मधिनारों वो सहस्त्रिण हुना दिये। जानो है। इन राजनीतिन एव माधिन मधिनारों वो सहस्त्रिण हुना दिये। जानो है। इन राजनीतिन एव माधिन मधिनारों वे सहस्त्रिण मधिनारा द्वींग प्रिमान है दो पूरवन रच होते हैं। सविधान म उल्लिखित राजनीतित मधिनारा द्वींग प्रेमा क्षेत्र स्थापित निया जाता है। मतिस्य राजनीतित माधिनारों वो स्थापनार राजनीतित मधिनार पाजनीतित के साथ में नगरा मन है। कैनन, एगी परिन्त्रिण म जब रिगो मून राजनीतित मधिनार मा उल्लिखन हुमाई, सीयपोलिना वो मूनिरा ना प्रवन पदा होता है।

इसरे विपरीत, सविधान में चल्लिखित विभिन्न प्रापिक प्रधिरारी, उदाहरण स्वरूप-मारतीय सवियान मे राज्य नीति-निर्देशन तत्वो मे निहिन ग्राधिक भ्रविकारों का क्रियान्वय राज्य संस्कार की संकारात्मक भूमिका से ही समय है। इन ग्रविवारों को सविधान से रधने के पलस्वरूप, राज्य के नागरिकों के प्रति निर्विषय महत्वपूर्ण कत्तंथ्यो का निर्वारण होता है। "सरकार वा स्वरूप ग्राप्तिर-बार विसी उद्देश्य की प्राप्ति के निए केवल एक साधन ही है। स्ततनना भी वें वल एक साधन है, जबकि उद्देश्य है-सोक करयाण, मानव प्रगति व गरीबी, बीमारी और पीडा को समाप्त करना और प्रत्येक व्यक्ति को मौतिक तथा बौदिक दृष्टि से 'ब्रच्छे-जीवन, व्यतीत बरने का ब्रवसर प्रदान करना ।" वस्तुन सरकार एक ग्रामिकरण है जिसका उत्तरदायित्व नागरिको के 'ग्रच्छे जीवन' को सविज्ञान में निहित राजनीतिक, प्राधिक ग्रीर सामाजिक ग्रधिकारों के ग्रनुकुल व्यावहारिक रूप देना है। यह नि सदेह सत्य है कि राजनीतिक स्वतंत्रना एव सायन ग्रीर एक ब्रावश्यक सायन है, जिसके द्वारा सामाजिक-ब्रायिक उद्देश्यों को प्राप्त निया जा सकता है। "परन्तु राजनीतिक स्वतवता अपने मे केवल एक उद्देश्य नहीं हो सकती है। वास्तव में राजमीतिक स्वतंत्रता का इस देश के करोड़ी लोगा के लिए मोई महत्व नहीं जबित वे गरीबी तथा उससे उत्पन्न विमिन्न सामाजिक बुराइयो

१. प॰ नेहरू-'पूर्वोक्त पुस्तक' पृ० १४७ ।

से भीडित हैं और जब तक उनको राजनीतिक स्वतत्रता में निहित सामाजिक-श्राधिक श्रधिकार श्राश्वासित न किये गये हैं।"

राजनीतिक स्वत्रता को व्यावहारिक रूप देने के वित्र मारव के सिष्मान नर्मातायों ने सिष्मान ने नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक एव धार्मिक धिकारों का स्पष्ट रूप से उत्कील किया है। जेसा पूर्व में देवा जा चुका है, सिष्मान की प्रस्तावना में नागरिकों के ये धिकार प्रतिविध्यित होते हैं। मुख्यत सिष्मान के प्रध्याय तीन में जिन मुलाधिकारों ना वर्षन है, उनके हैं। मारवा मा राजनीतिक तोजनत की नीव स्थापित नी में हैं। राजनीतिक लोकतव के विचार का सर्विधान के अनुच्छेद ७५ (३) धीर अनुच्छेद ८१ (१) (ए) में स्पष्ट स्थाने देवा जा सकता है, जिनके हारा क्रमत सम्प्रीयक्त के सामृहिक उत्तरदायिक के विद्वारत वाग सबस के निजसे सदन को नोक्तमा के लिए प्रस्ता

इसी प्रकार प्राधिक लोकतन की नीन मुक्तत मारतीय सर्विधान के प्रध्याय चार मे समावेशित राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के रूप से है। प्रतएव मारतीय सर्विदान में नागरिकों के दो प्रकार के प्रधिकारों पर कल दिया गया है (१) राजनेतिक तथा (२) प्राधिक एवं सामाजिक। ये एक दूसरे के परक हैं।

निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दी गई है।

भारतीय सिवधान के प्रध्याय चार में विस्तिबित राज्य नीति-निर्देशक तत्व के लिए सिवधान मिर्नातायों को सायरलेक्ट के सिवधान से प्रत्या मिली। में सायरलेक्ट के सिवधान से प्रत्या मिली। में नाम नीति निर्देशक तत्व मोली के सायर हो। परन्तु मारतीय सिवधान में राज्य नीति-निर्देशक तत्व सायरलेक्ट के स्थित्यान की तुनना में, प्रविक्त सख्या में और विमान कारते के हैं। मारते में बित ननतात्रिक सार्यिक व्यवस्था के रायरिव स्थान है। वारते में बित ननतात्रिक सार्यिक व्यवस्था को रायरिव स्थान है। वारते में बित ननतात्रिक सार्यिक व्यवस्था को रायरिव स्थान है। वारते हैं। परायर में तिन निर्देशक तत्व प्रधान स्थान के सारतीय सार्या में तिन निर्देशक तत्व, जैया प्रो० एक्डिकेटररिविज कार्य कर्या के प्रार्थी सार्या के सारतीय सारतीय सार्या के सारतीय स

राज्य नीति निर्देशक तत्थो द्वारा एक ऐसा क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिसमे राज्य (विभिन्न सरकारो) की सकारात्मक मूमिका प्रपेक्षित है। सविधान के

१ पी को गनेन्द्रगडकर-सा, लिक्टी एण्ड सोशल जस्टिस, १९६४,

पृ० १२४-१२४ । २. सी० एल्डेजेन्डरोविवन—काल्डोट्यूरानल डेवलपमेन्टस इन इण्डिया, १९४७ प्र० १०६.

धनुन्देद ३७ के भनुसार ये सिदान्त (राज्य नीति-निर्देशक तस्त) देश वे प्रशासन में मूल हैं और राज्य का यह वर्तव्य है कि बानून-निर्माण कर इन सिदान्तों को सामू करें। भारत के सिवधान निर्माताओं को इस बात के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए है कि धार्षिक लोकतन्त्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने सीन क्लाणकारी राज्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए राज्य नीति-निर्देशक तस्त्रों क्यी साधनों के लिए मी प्रावधान किया, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य का धारणें प्राप्त विया जा सके। श्री टी के टीपे के मनुसार—"एक सोक कल्याणकारी राज्य की प्राप्त विया जा विजीवताए निम्नालिसत हैं।

- (१) सरकार के कार्य क्षेत्र, में निजी स्वामित्व की श्रामित सस्यामों वे नियम्त्रण के लिए व्यापक वृद्धि ।
- (२) राष्ट्रीय समाज के प्रत्येक मदस्य यो प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदत्त वरना-बेरोजगारी तथा सेवा निवृत्ति सर्वाधित लाम, परिवार सर्विमी मले, वम रार्च पर गृह-निर्माण, चिकित्सा सेवा धादि ।
- (३) ऐसे उद्योगो एव व्यापार में सरनार के स्वामित्व तथा वार्यों में वृद्धि जिनका सचालन व्यक्तियो या निजी निगमो द्वारा निजी लाम प्राप्त करने वे लिए हो रहा था, या, होगा। (")

राज्य नीति-निर्देशक तस्यों का उद्देश्य लोक कत्याणनारी राज्य ती स्थापना करता है। इनके द्वारा जनता के प्रति सलाव्ह तथा धन्य राजनीतिक दलों के कर्तव्यों का सप्ययोकरण निया गया है। "उनने द्वारा राजनीतिक दलों की भाव-कर्तव्यों का स्पर्योकरण निया गया है। "उनने द्वारा राजनीतिक दलों की भाव-मान्नों के सदा चरित्वतंत्रशील नमूने पर, जब इनको सविधान के प्रमुक्तार सरकार सवाबित करने के तिए प्रामनित किया गया है, धवरोध लगाया जाता है। यह सत्य है कि यह व्याय्य नहीं है, किन्तु व्हिन में मेनाकाटाँ एव प्रमरीका में स्वत-जता के घोषणा पत्र के सदूब इन तिद्धानों में व्यायाधीक, सविधान तथा देश के कानुन की व्याख्या करते समय प्रवस्य प्रमावित होते ।"

मारतीय सविधान के बौधे घष्णाव में घनुच्छेद २६ से ४१ तक विभिन्न राज्य-नीति निर्देशक-तत्वों का उल्लेख किया गया है। इनमें मारतीय नाणरिकों के वित-पय महत्वपूर्ण मधिक तथा सामाजिक प्रधिकार निहित्त है। सविधान के घनुसार केन्द्रीय घोर राज्य सरकारों को प्रपने दैनिक प्रशासन में इन सिद्धान्तों को क्रिया-चिंत करना प्रावश्यक है। राज्य नीति-निर्देशक तस्व निम्मलिखित है।

१--राज्य, विशेषकर, प्रपनी नीति का निर्धारण, इस हेतु करेगा कि,

१. टी० के टोपे—'द कन्स्टिट्यूशन झाफ इण्डिया' १६६३ पृ० २०० । २. 'वहो' प्र० २००-२०१ ।

(क) समस्त नागरिको, पुरुष तथा स्थियो को पर्याप्त जीविना ग्रजैन करने वा प्रिपकार हो; (ख) समाज के मीतिक साधनो का स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस प्रकार विज-

रित हो जिससे सामान्य रूप से जनहित समय हो ।

 (ग) देश की धार्थिक व्यवस्था का सवालन इस प्रकार न हो जिससे घन का केन्द्रीयकरण होते हुए सामान्य हित को हानि पहुँचे ।

कन्द्रायकरण हात हुए सामान्य हित का होना पहुच। (घ) पुरुष तथा स्त्री को समान कार्य के लिए समान बेतन मिले,

(४) पुरुष तथा स्त्री को समान कांध के लिए समान वतन मिनत, (३) श्रीमको, (पुरुष एव स्त्री) तथा कम ब्रायु के बालको के स्वास्थ्य फ्रीर सिन्त का शोषण न हो घोर नागरिको को घपनी धार्षिक ब्रावश्यक्ताधो को पूर्व करने के लिए उनकी ब्रायु वश्य शिन्त के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त व्यवसाणे में

प्रवेश करने के लिए वाध्य न होना पड़े, च—वचपन एव युवावस्था का शोषण न हो, तथा नैतिक एव भौतिक परि-

च--वयपन एव युवाबस्या का शावण न हा, तथा नातक एवं मातक पार-त्याम से उनका सरक्षण हो (भनुच्छेद ३६) २--राज्य द्वारा प्राम-पंचायतो को संगठित करने की दिशा में कदम उठाये

२—राज्य द्वारा प्राम-पशायती को सगिठत करने की दिशा में करम उठायें जायेंगे और राज्य उनको धारास्यक शक्तियाँ प्रदत्त करेगा जिससे वे स्वायत-शासन की इकाइयों के सद्गा कार्य कर सके 1 (प्रनुच्छेद ४०)

३---राज्य धपनी धार्षिक क्षमताग्रों के दायरे में नागरिकों के लिए नौकरी भौर शिक्षा की व्यवस्था करेगा भौर बृद्धावस्था, बीमारी एवं बेरोजगारी या धरा

हानि होने पर सार्वजनिक सहायता करेगा (धनुन्छेद ४१) ४—राज्य श्रम तथा प्रसृति सहायता से सर्वायत शर्तो को मानवीय स्वरूप

क्ष्याच्या अने पात्र प्रश्नित स्वत्या के स्वाच्या के साम के निर्माण के स्वत्या के से कि के कि स्वत्या के स्वाच के के कि एवं प्रावदान करेगा (भनुकेंद्र ४२) ५—राज्य कानून या भाविक सगठन हारा समस्त श्रीमको को हपि, उद्योग या भन्य नायों से सविवत उपयुक्त जीविका एवं कार्यों की वारों के लिए प्रावदान

करेगा विससे जीवन का उत्तम स्तर स्थागित हो गके तथा नागरिक सामाविक मौर साम्हर्तिक भ्रयसरो ना उपयोग कर सकें। राग्य व्यक्तियक और सहकारिता के भाषाद पर तथु उदोगों को प्रोताहित करेगा। (सनुष्टेश ४५) ५—पज्य समृग्ये मारतीय प्रदेश में नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार

सहिता उपन॰प कर्युग नारताय प्रदेश में नागारका के लिए एक समान व्यवहार सहिता उपन॰प करवाने का प्रयक्त करेगा। (धनुच्छेद ४४) ७--राज्य सविधान के लागू होने के दस वर्षों में चौदह वर्ष तक की धायु के

समस्त बातको को धनिवार्ष जिला हेने के लिए प्रावधान करेगा (धनुक्छेद ४५) — स्पन्न दुर्वन धनों के विशेष कर धनुष्टिन कानियो नवा पिछली जातियों के, निश्ता धोर धार्षिक हिलों नी उनिति के लिए व्यवस्था करेगा धौर उनक सामाजिक मन्याय तथा धन्य प्रकार के शोषण से रसा करेगा। (धनुक्छेद ४५) ६—राज्य प्रपत्ती जनता के प्राहार सबयो एवं जीवन के स्तर को ऊँचा करने के तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य मे सुचार करने के वार्यों को प्राथमिक महस्व देवा तथा यह प्रयत्न करेगा कि उन मादक पैयो को छोड़चर, जो विवित्सा में श्रावश्यक हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनका निषेष हो। (समुच्छेर ४७)

१०—राज्य कृषि एव पशुगालन का धानुनिन भीर वैज्ञानिन भाषार पर सचालन करेबा, विशेष तौर से गोवश के सरक्षण भीर नहन में सुधार ने लिए तथा गाय, बखड़े, दूभ देने वाले भारवाही पशुमा ने बय वा निर्णेष नरने वा प्रयास करेबा। (मनच्छेद ४५)

११—राज्य का यह कर्तव्य होगा नि प्रत्येक स्मारन या नतात्मन तथा ऐतिहासिक दृष्टि से मह्स्वपूर्ण स्थान या वस्तु ना, जिसनो ससदीय नानून द्वारा राष्ट्रीय महस्त ना निर्धारित नर दिया गया है, सरक्षण नरे। (धनुष्टेद ४६)

१२ — राज्य द्वारा न्यावपालिका को कार्यपालिका से पृथक वरते के लिए कदम उठाए जायेंगे।

१३-राज्य द्वारा निम्नलिखित विषयो के सबय मे प्रयत्न किये जायेंगे ।

- (क) ग्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ग्रीर सुरक्षा की उन्नति के लिए,
- (क्ष) राष्ट्रों के मध्य न्यासपूर्ण धौर सम्मानपूर्ण सबयों को बनाये रखन के लिए,
- (ग) प्रन्तर्राष्ट्रीय विधि और और सिंघयों में निहित वर्त्तव्यों के प्रति
 राष्ट्रों के व्यवहार में झादर बढाने के लिए,
 - (घ) ग्रन्तर्राष्ट्रीय वाद-विवादों को पच-निर्णय द्वारा निवटाने वे लिए ।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रधिकाश राज्य गीति-निर्देश तरवी का सवय नागरिको के सामाजिक तथा प्राधिक प्रधिकारों से है। ये प्राधिक प्रधिकार सोकतन के मूल प्रधार है। राज्य गीति-निर्देशक तरक मूल प्रधिकारों से इस दृष्टि से मिन हैं कि मूल प्रधिकार स्वाव है, प्रधांत इन के पीछे न्यायालयों को प्रधांत है, किन्तु राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय्य नहीं है। तथापि, देश के प्रधासन का ये मूल प्रधार है। मारतीय सविधान में नागरिकों के मूल प्रधिकार तथा राज्य नीति निर्देशक तत्व प्रधान करने के लिए सर्वेधात पहलुसी-व्यक्तिमत स्वावन को प्रधान करने के लिए सर्वेधातिक साधन है। दूसरे गल्डी में यह नहां जा सकता है कि चूंकि सोकतन में प्यविवागत स्ववनता और स्वोक्त कि के हन स्वावन के प्रत्यतिवागत स्ववनता और स्वोक्त के इन दो पहलुसी के प्रधान के कि लिए स्विवागत स्ववनता और स्वोक्त के के इन दो पहलुसी की प्रधान के लिए निर्दारित साधन, मूल प्रधिकार प्रोर राज्य के नीति निर्देशक तव, मी एक हुतारे के पूरक है नयोकि इनके माध्यम से हो मारत में मती प्रधान तव, मी एक हुतारे के पूरक है नयोकि इनके माध्यम से हो मारत में मत्वी स्ववन स्वाधित विधान तव मार देश की नितनिर्देशक तव्यो की स्व

प्रात्तीचना की जानी है, कि यदि राज्य इनका पासन नहीं नरता हैं तो इनका कि प्रात्त्रण न्यान्य हैं हारा, मूल प्रार्थित के सहस नहीं सिया जा सकता है। स्व दृष्टि है, प्रात्तीचने का नहता है कि इनको सियान में रखने जा नोई मृद्य नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि राज्य के नीति-निर्देशक तत्यों को न्यायात्र्यों हारा सामू नहीं क्याया जा सकता है; किन्तु में विद्यान्त वर्षमान भीर मिय्य से सत्यान्त होने कारे राजनीतिक कर को के स्विष् एक निरम्यत देवात्राचित है कि इन सिद्धान्तों का दैनिक प्रमासन में उपयोग होना प्रावस्थ है, प्रम्यण जनता प्रति पांच वर्ष के वाद प्राप्त चुनाव के घोरान स्वारास्त्र दक्त को सत्या है हर सकती है। पत्त - यह सत्य है है क्याया नीतिन्वित्यक तत्यों के पिद्धा न्यायाप्त्रों की सित्त - मही है, परस्तु सत्तार्ज इन पर इनके द्विप्यान्यम ने भदमें मे नैतिक तया भनो-वैद्यानिक प्रयोग है, नगोकि में शिद्यान्य पार्ट्याम प्रदेशकों के क्य में ही स्वेदिक तत्या भनो-यानिक प्रति एक स्वेद के स्वीतान के का में है भूष्ट राम्य नीति-तीव्यक्त तत्यों नो तापू नरने के लिए स्थायासयों को कोई विक्त प्राप्त नहीं है, यह प्रकार स्वापा-विक्त है है इन सिद्यानों के पीछे इनके क्रियान्यमन के लिए कीज-कीज सी शिक्त है। है इनके सित्त प्रस्ता है।

(१) मनदातागण तथा

(२) व्यवस्थापिका समा ।

(१) व्यवस्थानित सभी ।

सासीय सोनवन में प्रतादासी नी मान्ति सरकार पर एक ऐसे प्रत्यपूर्व
स्वारीय ने क्या में मान्ती या सबती है दिससी सरकार वां मिल्यान में उनिवासित
उद्देशों के विरद्ध जान से रोक्त का सकता है। मतदानामी तथा व्यवस्थावित
नो क्रुमिना पर प्रकार वात्ते हुए दां थी। ध्यार प्रवच्चकर ने नहां—"श्येक
सरकार दैनित माम्यों म तथा एक विभिन्नत समय पत्रवाल निश्ची नगीदी
पर रखी जायमी अर्थीक मतदानामी और निर्वाचित्र समय पत्रवाल निश्ची नगीदी
पर रखी जायमी अर्थीक मतदानामी और निर्वाचित्र निश्ची नमें राजनीतिक
सोवान में स्थापन की है, हमारी यह भी इच्छा है कि मार्थिक लोकजन ने स्थापना की है, हमारी यह भी इच्छा है कि मार्थिक लोकजन ने स्थापना
की निर्मारित नरें।"। "विधियान निर्माण नरने में हमारे दो उद्देश रहे हैं भानतीति
वेदेश तथा सर्माणिक तथा का मार्थिक तथा के स्थापन क्या में स्थिति पर परता।"।"

सर्वप्रयम—प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण समय में ससद सदस्यों द्वारा निया जाता है। द्वितीय, जुनाव के समय सरकार की नीतिया तथा कार्यों का परीक्षण और मूल्याकन स्वयं मनदाता करते हैं। सरकार की नीतियों तथा कार्यों का परीक्षण

१. बी प्रार. भ्रम्बेदकर-काम्स्टीट्युएस्ट ग्रसेम्बली डिबेट्स-माग ७ पृ० ४६२-४६५।

२. वही पृ० ४१।

(ईय परीक्षण) सिवधान में निर्वारित क्सोटियों ने धावार पर ही विया जाता है भी सिर यह भी मात किया जा समता है कि सरकार की नवा उपलब्धियों या क्या मसकताएँ रही हैं। यदि सरकार ने सिवधान के अनुसार जनता की आवश्यनताओं को पूरा किया है तो निक्यम ही जनता द्वारा सत्ता की वागडोर पून उससे सौरिन की प्रवल समावना होगी। किस्तु यदि सरकार ने सिवधान म उल्लिखित जनता की भाव हामाओं में भवहेलना की है तो मतदातामा को सरकार की यदनने का पूर्व प्रवास हो।

प्रव जीता नि पूर्व म देशा जा चुका है, राज्य के नीति-निर्देशन तस्य देश थे प्रशासन ने लिए प्राधार हैं । बोई सरकार दा मूल सिद्धान्ता वी, जिन पर प्राधिक सोरात्म निर्म है, प्रवहेलना नहीं कर सकती हैं ? 'यदि जनता एव व्यवस्थापिया समाधीं म उनने प्रतिनिध इत मिद्धान्तो ने सान्यमं वार्यपालिया ने कार्यों ने स्ति सहसे के एवं में बाद के नार्यों ने सित् सहसे के एवं में बाद के नार्यों ने सित सहसे के एवं में बाद के नार्यों ने सित सामाधीं सोत सिद्ध होंगे।"' राज्य नीति-निर्देश में पीछे सबसे प्रमावनात्मी सोत सिद्ध होंगे।"' राज्य नीति-निर्देश में पोछे सबसे प्रमावनात्मी सत्ता सोकमत्त है। यह सत्व है कि नान्ती दृष्टिकोण से इत सिद्धान्तों मा वम उपयोग है, निर्म तुमान तिस्त सित एवं प्रसाव के स्तर कि स्तर करता का सारकार के सित एवं स्थापी स्मरणवर्तों के सद्भ हैं, जिससे स्मरण रह सके कि का विधा जाता चाहिये।" रे मुत्र राज्य नीति निर्देशक तथों में पीछे कानूनी नहीं बदिक सोन-मत के रूप में, राजकीतिक शत्ति हैं। प्रश्वेस पीच वर्षों के प्राप्त ने समय मतदाता इस मान्त्र के लिए एवं स्ता होंगे कि एवं ऐसी सरकार को जिसने इत सिद्धान्तों भी प्रबहेलना की है, पुत सतान सीपें।

इस नारण सिवधान सागू होने वे पश्चात् वेन्द्रीय एव निमन्न राज्यों यो सर-कारों ने इन सिद्धान्तों मो व्यावहारित रूप देने वे प्रयत्न निमन्न स्व वर्षाय योजनाओं मे बिवोप रूप से मित्र तिविध्यत्त है। सिवधान वे लागू होने के पश्चात् तीन यच वर्षीय योजनाओं मे तथा वर्षनात चतुर्ष व वर्षीय योजना वे प्रत्यात्त तीन यच वर्षीय योजनाओं मे तथा वर्षनात चतुर्ष व वर्षीय योजना वे प्रत्यात राष्ट्रीय विकास वां जो नम्ना है यह सविधान मानिहत उद्योग से सम्विध है। राज्य गीति-निर्वेशव तस्त्रों के प्रतुक्त जिस तरय वो प्राप्त व रना है, वह है 'सम्प्रवादों डीचे पर प्राधारित समाज' और इसनो इसरी पच वर्षीय योजना मे इन शब्दों में स्पट विधा गया है, ''इससे तात्त्य है वि प्रताति ने सित्य नतिहीटी निजी लाम नहीं दिन्दु सामाजिक लाम होना चाहिये और विवास वा नम्नात तथा सामाजिन प्राधिव सबयों वा डीचा इस प्रवार नियोजित विधा जाये वि न वेवल

१ टी० के० टोपे—'पूर्वोवत पृस्तक' पृ० १९४।

२ एम० पो० शर्मा—व गर्वमेन्ट झाफ व इण्डियन रिवस्तिक, १६६१, पृ० ६० ।

राष्ट्रीय आय और रोजगारी मे ठोस वृद्धि हो निन्तु लोगो की आय तथा घन मे अधिकतर समानता हो । आधिक विकास के लाग अधिकतर समाज के पिछड़े हुए वर्गों को उपलब्ध हो और भाय, घन तथा आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण में क्रमिक रूप से कमी होती जाये।"1

द्वितीय पन वर्षीय योजना के उपर्यक्त उद्देश्य तथा राज्य नीति-निर्देशक तत्वीं के उद्देश्य की समानता को देखते हुए, यह विदित होता है कि इन सिद्धान्तों को एक अव्यावहारिक आदर्श के रूप में नहीं माना गया है, किन्तु इनकी व्यावहारिक जीवन में उपयोग में लाने के सफल प्रयतन किये गये हैं। कतिपय उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि वास्तव में इन सिद्धान्तों को ब्यावहारिक रूप

प्रदान करने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं। ये उदाहरण निम्नलिखित हैं। (1) पिछले वधौँ में समाज के भौतिक साधनों नो काफी मात्रा में राज्य के नियन्त्रण मे लागा गया है। जीवन बीमा तथा बैन-राष्ट्रीयकरण इसके क्तिपय उदाहरण हैं । इसके अनिरिक्त, बहुउद्देश्यीय नदी योजनाएँ, जैसे--- मान्वरा-नगल, दामोदर घाटी योजना, हीराकुण्ड बाघ, मिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इत्यात कारखाने, विद्यालापट्टनम का जहाज-निर्माण कारलाना, सिन्द्री साद कारलाना, हिन्दुस्थान मशीन टल्स, चितरजन का रेलने इजिन का कारलाना, हिन्दस्थान ऐयरजापट,

मादि द्वारा राष्ट्र के भाषिक विकास में सहायता मिलती है। राज्य ही इनके सचा-(u) यद्यपि रोजगार की समस्या का समाचान नहीं हुन्ना है किन्तु राज्य द्वारा रोजगार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कदम उठाये गये हैं। (111) राष्ट्र के कई हिस्सो मे, सामुदायिक विकास योजनाम्रो को ग्रामो की ग्रामें

व्यवस्था में सुघार के लिए लागू किया गया है, इसका प्रमाद क्रीय तथा पशुपालन के क्षेत्रों में विशेष रूप से देखा जा सकता है।

(iv) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में भी प्रगति हुई है 1

(v) भाषिक क्षेत्र में पिछड़े हुए वर्षों की सहायता के लिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है।

(vi) धन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने पचशील के सिद्धान्त के प्रतिपादन मे महत्वपूर्ण योगदान दिवा है।

राज्य नीति-निर्देशक तत्वों में पीछे दूसरी शक्ति व्यवस्थापिका सभा है। व्यवस्थापिका समा का कार्य, देश में लोक कल्याणकारी राज्य को व्यावहारिक रूप देने के तिए राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के द्याघार पर नानून निर्माण करना

सन तथा प्रवन्ध के लिये उत्तरदायी है।

१. द्वितीय पव वर्षीय योजना पु०-२२ ।

है। इतने मतिरतः, चूनि मारत में समदातम पद्धति वो मणामा गया है, हा वानुनों ने प्रियान्ययन में लिए वामेंपासिना को उत्तरमधी दृहरों वा प्रस्था मिनार भी अवस्थापिना को प्राप्त है। ससदाराम पद्धति में वामेंपादिना (महोमहाल) व्यवस्थापिना का एक हिस्सा होती है तथा उसने मित उत्तरमधी होते हैं। साधारपत्या वामेंपादिना का निर्माण ससद में निर्मेश समर में महान प्राप्त किये साधारपत्या वामेंपादिना का निर्माण ससद में निर्मेश समर में महान प्राप्त किये परिणाम स्वस्य समय में निवस सदत यर उचत राजनीतिक देत को माधितपत्र तथा गित्रमण एका है। जूकि सदिवान के समुज्येद २० के महुतार राज नीतिन दिवस तथा मो देश में प्रमात में भाषा के समुज्येद २० के महुतार राज नीतिन दिवस तथा को देश में प्रमात में प्रमात के समात में प्रमात के समात के समुज्येद २० के महुतार राज नीतिन के स्थानहार माधित प्रमात है। उत्तर स्थान स्था

"यह प्रतिवश ने हामों में एक मिन्त्रकाती तृषिमार होता कि यह सरनार भी निन्दा इस फाषार पर नरे कि उसका कार्यवानिका या व्यवस्थापा सबधी

बोई वार्य राज्य नीति-निर्देशक तत्व के विरद्ध है।"

ध्यजहारत सत्तर मे प्रनिवक्षीय दलों ने राज्य नीनि-गिर्देशन तरना वे प्राधार पर सरवार को प्राधान पर कडी प्रलोकना की है। उदाहरण स्वस्थ हम तिद्वालों के विज्ञानकन के लिए सरवार के उत्तरदाखित के दृष्टिकोण से १६४० से लीर गाम में श्री नुवार चर्र्जी (साम्यवादी दल के सदस्य) द्वारा एग प्रताब रचा गया। इस प्रस्ताव से पन्द्रह सदस्यों की एक समिति निवृत्त करने वा मुक्ताव दिया गया, जो यह जीव बरती कि वित्त हद तक, राज्य नीति निर्देशन तरने वा सरकार में विद्यालका किया। परन्तु देर प्रमुख १६४० को सोचसमा ने इस प्रस्ताव को सल्केष्ठ कर किया। इस प्रस्ताव को सदन सं रराते हुए श्री वुदार चर्ठाओं ने वहां कि सामान्य नागरित के लिए समस्याओं का, उत्ति-तावा, शिता और स्वास्थ, समाधान नहीं हुमा है भीर साधारण जनता वा जीवन धीर मारपूर्ण व कठि हो यदा है धीर वे ऐसा सहसूत करने को है वि सविधान से नीति-निर्देशन सत्य एन गमीर पोपणा नहीं वित्त वेवल सजावट मात्र ही हैं। दे इस प्रालीका। वा उत्तर देते हुए सुह सत्रावव के श्री धी० एन० दातार ने वहां कि नीति निर्देशन तत्व एन "उद्देश्यों वो सहिता" के स्वत है धीर इनविधात स्वताल प्रस्ति होना साम

२. द्रिम्पून, सितम्बर १, १६५८ ।

६८ भारतीय शामन श्रीर राजनीत

नहीं है, किन्तु सरकार न सदैव प्रपत्ती नीतियों में इन निदानतों को समवेतित्र करन ना प्रयत्त किया है और इन निदान्तों के प्रमावों को योजना आयोग क कार्यों तथा निर्मायों मुख्यक कर में देवा जा सकता हैं।

तिस्मद्द न ता मरबार इन निद्धानों के विरुद्ध कोई नाम करेगी न ही रत निद्धानों न प्रतीम रहनर प्रमानन वा सवानन वर सबती है। तसर में प्रतः मामन पर बारास्त्र नीति-निदेशन तत्वों में मशिन है, सरवार को माने वारों तथा नीतिया का फीक्टर बनतात होगा, प्रत्या मरवार के विरुद्ध सबद से प्रविद्यान प्रत्याव पारिल विद्या जा मनवा है। इसके प्रतिद्वित, गतार से

साम पर को धान नातन्वतन करने ना नावना, तम हो है विद्ध समय में ज्या नीतिया का सीचित्र व नताना होगा, प्रत्या सरकार के विद्ध समय में मत्रवाताना का साम जुनाव के समय सम्मेत का स्थिति में ही सित्र संकात में सरकार न स्वत्त कार्यकाल के जनता के हिंतों को ध्यान में एवं कर कार्य से सी सीचें में, मत्त्रवात वार्यक्षमाधिका समा राज्य नीति-निर्देशन व को में पीचे आवस्यत मोता है। सन, दन्ते पीचे वार्यन नहीं किन्तु राजवीतिय स्वित्त है

सावस्य नार्ता है। अ. इर्सर पाठ मुन्ना गुर्ना एवं एक्ट्रा स्वार्गित के सावस्य ने सावस्य के सावस्य के सावस्य के स्वार्गित के स्वार्गित के स्वार्गित के सावस्य के स्वार्गित के सावस्य के प्रश्न के सावस्य के सावस्य के सावस्य के सावस्य के सावस्य के सावस्य के प्रश्न के सावस्य के साव

सबा सम्यति ने प्रपिनारा गर सीमाएँ लगाई गई है। स्वजनना ने मून प्रपिनार ने सबज में सविधान में 'गुन्तिपुन्त' मीमाप्रीशब्दोना उपनाग निया गया है, सम्यति ने प्रपिनार ने सबज में यह प्रावधान निया गया है

हि सम्पति वा प्रिमिष्ट्रमा राज्य वेचन 'मार्वजनिक छहेस्य' से ही कर सहता है। इमें बात वो निर्पारित करन के नित्र वि 'युनियुक्त सीमाओं तथा 'सार्वजनिक बहेस्य' ने बता जारूम है हमान्यानिका वा निर्पार होता। इस सन्दर्भ में त्यापासिका वो सार्व्य मीति निर्देश्य तस्त्रों का कहारा केना परेशा। वास्त्रव से, पिट्टी वर्षों में जब बानुना डारा व्यक्तिमन क्वत्ववा पर सीमाएँ समाई महे, त्यापनािनित्रिया स्टू बहु बौबरे के नित्र कि से सीमाएँ युनियुक्त थी था नहीं, राज्यमीिनित्रिया स्ट्रां का स्ट्रां के सार्व्य के स्ट्रां के स्ट्रां केन निवा। व्यवपातिका की यह प्रारणा रही है, कि जिन निवानों का सवियान डारा मान्यना प्रवस्त है व युनिस्तित्र नहीं हो महते

जब बानूना द्वारा व्यक्तियन ब्लानजा पर शीमाएँ लगाई महे, व्यावशीता है मह बीचेले ने लिए कि से सीमाएँ मुल्लियुका थी या नहीं, राग्यमीतिनिर्देशक साथे को साथे होने विवाद नाये व्यवस्थित हो यह पाएला एएँ है, कि जिन निवादों का सिदान द्वारा भाग्यना प्रस्त है से मुल्लियुक्त नहीं हो सकते है। विवाद मुन मिहारा तथा राग्य मीनिनिर्देशक तथी के मार्ग्यभंत से, सायुक्त साथा में मिहारा हो से सायुक्त हो त्यायस्थातिका को एए महिता को सायुक्त मुक्त से सायुक्त साथा महिता को एए होने के साथ से ही त्यायस्थातिका को एए मस्त गमीर तथा महत्वपूर्ण मुक्तिया प्राप्त हुई है, जिससे व्यक्तियन स्वतना , एवं तीन करायस्थारी राज्य के मध्य पैदा हुए विद्योगी की दूर कर इन दोनों में

समन्वय स्थापित किया जा सवे । दूसरे शब्दों में व्यवस्थापिता तथा कार्यकालिका के मितिरिक्त, सविधान द्वारा भारत में राजनीतिक लोकतन्न तथा माधिक लोकतन को, व्यवहार मे एव दूसरे के पूरक बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका न्यायपालि । रा मो भी सीपी गई है। मुख्यत · यायपालिका ने इस वार्य को नागरिकों वे मूत ग्रधिवारा तथा नीति-निर्देशक तस्यो वे सदमं म किया है। नागरियों में मूल ग्रधिकारा द्वारा एक ऐसे क्षेत्र का निर्धारण किया गया है, जिसम राज्य हस्तर्शेष कर नागरिको के अधिकारों का उल्लंधन नहीं कर साता है। अत यदि अत्याधिक उत्साह म सरवार ने लोव गल्याणवारी राज्य वे भ्रादर्श वी प्राप्ति वे लिए ऐसा वानन पारित विया जिससे विसी मूल प्रधिवार या प्रधिवारो वा प्रतिज्ञमण हुपा तो न्यायपालिका ने ऐसे कानून को अवैध घोषित किया । इसी प्रकार न्यायपालिका ने सविधान द्वारा लीव क्ल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को ध्यान म रागते हुए जर किसी बानन वी जाँच मूल अधिवारों वे सन्दर्भ में इस आधार पर की वि उता कानुन द्वारा धनुच्छेद ३१ (२) वे धनुसार सम्पति वा ग्रिधिप्रहण राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया था या नहीं, तो न्यायपानिका ने सविधान मे उल्लिखित नीति-निर्देशक सत्वो का मार्गदर्शन लिया । उदाहरणस्वरूप, यदि किसी कानुन को न्यायालय वे समक्ष इस तर्वपर चुनौती दी गई है कि इसमे अनुच्छेद १६ द्वारा अदत्त मूल अधिकार वे विरुद्ध युक्तिरहित गीमाएँ लगाई गई हैं, तो न्यायपालिया उक्त तर्व को स्वीकार नहीं करेगी, यदि ये सीमाएँ राज्य नीति-निर्देशन तत्वो ने श्राघार पर हैं बयोगि यह मानना स्वामाविन है, नि जिन सिद्धान्तो को सविधान मे रखा गया है ये युक्ति रहित नहीं हो सकते हैं। इस दृष्टि-बोण में कई कानू हो थो, जिनको न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी न्यायपालिका ने सबैधानिक ठहराया है। उदाहरण स्वरूप, श्राुच्छेद ४७ मे निहित नशायन्दी निर्देशक तत्व के भाघार पर ऐसे कानून को न्यायपालिका द्वारा वैय घोषित विया गया जिसके द्वारा भादक द्रव्यों के रतने तथा क्रय करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया या। अनुच्छेद ४ में निहित निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार गो-वय निर्पेष के सिद्धान्त पर भाषारित कानून का न्यायपालिका ने बैध माना ।

इसी प्रकार राम्पति के मूल प्रधिवार ने सन्दर्भ में प्रमुच्छेद ३१ (२) के प्रमुतार यदि राज्य निजी सम्पत्ति वा सायंजनिक उट्टेक्य के लिए कानून द्वारा प्रधिवहण, प्रमुच्छेद ३१ (व) एव (स) में निहित राज्य नीति-निर्देशक तस्त्रो (३१ (व) समाज के मौतिन साधनो वा स्वामिस्व तथा वितरण इस प्रवार का

१ मोहम्मव हनीक झौर श्रन्य बनाम विहार राज्य झौर झन्य—ए० झाई० झार० १६४८ एस० सी० ७३१ (

७० भारतीय शासन स्रौर राजनीति हो कि जिससे सामान्य रूप से जनहित हो; ३६ (स) देश की धार्थिक व्यवस्था

हा पा जात प्रांतान के पंचारत है। जिससे पत्र को कैट्रीयकरण हीते हुए सामान्य हित को हानि पहुँचे) की प्रांति के लिए करता है तो ऐसे कानून वो प्रवेष नहीं मानना चाहिये। इस सिद्धान्त ने सविधान सत्रोपन पत्नीसम् प्रितियम मे स्पनाया गया जो दिसम्बर १९७१ में वारित दिया गया। इस सनीयन के सनुसार यदि निसी गानून से यह जीलाबित कर दिया जाता है कि उक्त पानून

क्षत्रनाता गया जो दिसम्बद १६०१ में चारित दिया गया। इस संगायत कर प्रमुतार यदि निर्मो नानून से यह उत्तिवित कर दिया जाता है कि उक्त बन्दून का उद्देश्य किस राज्य नीति-गिर्देशक तत्र को लागू करना है तो इसके बावजूद कि वह कानून किसो पूल यिकार के विकट है उक्त बन्दून को सबैप प्रोधित निर्देशक तत्वों के विकट मही किसा जो सकेगा। पत्र्योशित संबोधन, राज्य नीति-गिर्देशक तत्वों के विकट स्वाच्छेद १६ में निहित निर्देशक तत्वों के दृष्टिकोण से स्वयन्त सहत्वपूर्ण है। इस संबोधन के प्रवृद्धार प्राधारण कानून डाग व्यवस्थानिक हमा ऐसे नीति-

निर्देशक तत्व को जिसका उल्लेख कक कानून में है, मून प्रिथिकारों से उच्च स्थान प्रदान कर सबती है जो रथ्वें सभीषण लागू होने की नीति निर्देशक-तत्वों की पूर्वें स्थिति से बिल्कुल सिन्न हैं। पण्चीसवें सभीपल लागू होने के पूर्व बानूनी दृष्टि से नीति निर्देशक तत्व यून स्थिकरारों के स्थान से । स्थानिका की इस विशेष पूरिका का महत्व दिसम्बर १९७१ तक रहा अवित्तिवृद्धिक तत्वों के सबस में नायापालिका के दो प्रचार के स्थिकार से, संबंधमा, यदि राज्य नीति निर्देशक तत्व पर प्राचारित क्षिमी वानून तथा नायार्थिक के किसी मूस प्रिकार में समयें होता, तो ऐसे कानून वो भयेष उद्धाना, संयोक्त सूत्र प्राप्तार त्याय्य है, राज्य नीति-निर्देशक तत्व त्याय्य नहीं है, और दितीय, कई मूल प्राप्तार त्याय्य है, राज्य नीति-निर्देशक तत्व त्याय्य नहीं है, और दितीय, कई मूल प्राप्तार त्याय्य है, राज्य नीति-निर्देशक तत्व त्याय्य नहीं है, और दितीय, कई मूल प्राप्तार त्याय्य है, राज्य नीति-निर्देशक तत्व त्याय्य नहीं है, और दितीय, कई मूल प्राप्तार त्याय्य है, राज्य नीति-निर्देशक तत्व त्याय्य नहीं है, और प्रत्योक्त या सहता है। मूल-प्रिकारों से बद्धार्थ पुष्टिवृद्ध सीमास्थी, त्या (सर्वेंबिक प्रत्याय ने व्यायाय करे ना प्रयिक्तार नायत्यात्रिका को है भीर इस कार्य में नि मौतिकरात्र तथा होना प्रत्यावनिक प्रदेशयें से क्या ताय्य है, त्यायपालिका

भूत प्रशिवार लाय है, राज्य नीति-विदेशक ताल लाया नहीं है, धौर दितीय, कई मूज प्रशिवार 'शुतियुक्त तीयाधी' दारा सीमित है तथा तमार्थित के मूज प्रशिवार के स्वत्यंत रामार्थित का प्रशिवार के सुव प्रशिवार के स्वत्यंत रामार्थित का प्रशिवार के सुव प्रशिवार के स्वत्यंत प्रशिवार का प्रशिवार के सुव प्रशिवार के स्वत्यं के स्वत्यं है। सुक्त प्रशिवार के सित है। तथा प्रशिवार के देखाँ ने लिए ही निया जहें वर्ष में नियार का सित है। तथा प्रशिवार के देखाँ से क्या तारार्थ है। तथा प्रशिवार का नीति-विदेशक तरले द्वार प्रश्न प्रवांत किया गता, येखा कि करियय महत्युण महत्यां के स्वत्यं के साथ होता है। विद्वार राज्य बनाम कानेक्वर मिह नाक प्रकरण में करिय प्रश्ना के स्वतंत्र के

लगाई, तो यह विदित करने के लिए कि ये सीमाएँ युनिनयुन्न मी या नहीं, न्यायपालिका ने राज्य नीति-निर्देशन तत्वी ना सहारा लिया।

प्रत्त में यह कहा जा सरता है वि मास्त ने सविधान में राज्य नीति-निर्देशन तरवों का धार्षिक लोनतम के साधनों ने रूप में प्रत्याधिक महत्व है। सविधान ने पण्डीसवें संगोगन (१९७१) से इनका महत्व भीर धार्षिक हो गया है क्योंनि इतके परिणाम स्वरूप सरकार ना उत्तरदायिक धार्षिक लोनतम ने प्राणि के तितृ स्थाट रूप से सामने उत्तर प्राता है। राज्य नीति-निर्देशन तत्वों द्वारा सविधान की प्रस्तावना में उत्तिविधान की प्रस्तावना में उत्तिविधान तात्वों द्वारा सविधान की प्रस्तावना में उत्तिविधान तथा धार्षिक उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक स्थानीक का प्रता है। "ये एव नसीटों ने सद्वा हैं जो मतदाताभो द्वारा सतास्व दल सरकार पर सामू को वा सचती है। इतके द्वारा यह क्योंटो प्ररक्त की जाती है जिससे एवं राजनीतिक दल की सफसता या धसपलता जात की जात स्वेत ही विससे एवं राजनीतिक दल की सफसता या धसपलता जात की जात से की

१. एस० पो० प्रव्यर—'कासटोट्यूमानित्रम इन इण्डिया' इन स्ट्डीख इम इण्डियन देमोक्सी १६६४, प्र० ७६८ १

भारत में संसदात्मक प्रणाली

पाधुनिक युन में सरकारों के वर्गीकरण का मुस्य प्राचार सरकार ने दो भग, व्यवस्थापिका समा एवं कार्यपालिका समा, के सबबों के स्वरूप पर प्राधारित है। इस रुख्तिण से जननानिक सरकारों को दो वर्गों में रखा जा सकता है।

हा इस दृष्टकाण संजननात्रिक सरकारा का वा वर्णा न रखा जा सकता हा सर्वेत्रयम, ससदात्रक सरकार, जियमे कार्येगानिका (मत्रीमण्डल) का उत्तर-दायित्व ससद के निम्न-सदन के प्रति होता है।

होतापत कराद के राग्य-पायन के प्रायः होता है।

हितीय, प्रध्यात्मक सत्यक्ष दिवामें कार्यवासिका तथा व्यवस्थापिका-सभा
मरदार के दो धतय-धत्तम घोर स्वतंत्र भग हैं। धनएव रस पद्धित में कार्यपासिका धौर व्यवस्थापिका ने वाँच धनित वस्त्र नहीं होता है, जबकि समस्यस्थ्र
पद्धित में वार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका वा एक हमरे दे इनना प्रमिन्छ सवध्य
होता है कि नार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के विश्वसाययेंत ही। पद्मासीत पह् सकती है। साथ ही, वार्यपालिका (मंत्रीसन्त्र) का कार्यकाल व्यवस्थापिका से

बहुमत पर निर्मेद रहता है।

सदातम सरकार को उत्तरदायों सरकार की सबा मी दो जाती है।
सदातमक सरकार को जुल विद्वारत को हुय वास्तरिक कार्यसाविता (महीमण्डल)
एव प्रवस्मित्तम के सकते में निर्दृत्त देशों है कोर्गेल बास्तरिक कार्यसाविता
म नामकाल व्यवसाविता में बहुमत पर ही प्रधासिक पहुंग है। का समझसक सरकार के धन्यमें यदि ध्यवसाविता ने समझक कार्यसाविता (मसीमण्डल) के कार्यों एवं नीतियों के प्रति बहुमत से धन्या धविद्यास ध्यवत करती है तो कार्य-पाविता (सीमण्डल) को प्रसाद स्वारत्य के सामझक कोर्या।

प्रो॰ गेटेन ने समदातम सरकार की परिमाधा इस प्रकार की है—"मधी-मध्यकासक सरकार, यह सरकार है जिसमे बास्त्रीवन कार्यशालिका, जिसमें एक प्रधान सबी एक सभीसकात का समावेदा होता है अपने कार्यों के लिए विधिवत कर के स्वरक्षाणिका के प्रीत जुलत्यांग्री है।"।

१. भारः जीः गेटेल-पोर्लिटक्स साइन्सं १६४४, पृ० २१।

हा० गार्नर ने ससदातम सरकार की परिमाया देने हुए नहा है—"मप्री-मण्डलात्मक सरकार बहु प्रणाली है जिसम वास्त्रविक कार्यपालिका (कंप्रीनट या भग्नीमण्डल) प्रत्यक्ष एव विधिवतरूप से व्यवस्थापिता या छाते एत मदन के पति (सापारणत्या प्रतिनिधि सदन) भीर अप्रत्यक्ष या अन्तिम रूप से निर्वाक्षों के प्रति अपने राजनीतिक नीतियो एव कार्यों के तिए जिम्मेदार है, जबकि च्वतमाय या नाममाय को कार्यपालिका (राज्याच्यक्ष) की स्थित उत्तरदायिक्हीन होती है।"

ससदात्मक सन्वार की भावश्यक शर्ते

जर्पान्त परिमापाधों से यह विदित होता है वि ससदारम्य सरकार ये प्रत्यांत वास्तविक कार्यपालिया वा व्यवस्थापिया के प्रति जतरदायित्व होना--इस सरकार वा मूल सिद्धान्त है। व्यावहारिक रूप से इस सिद्धान्त के दो पक्ष है।

प्रथम—बास्तविक कार्यपालिका विधिवत् एव प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका के प्रति जत्तरदायी होती है।

दितीय-श्रप्रत्यक्ष एव अन्तिमरूप से कार्यपालिका का उसरदायित्व मन-दाताम्रो ने प्रति है।

इन दोनो पहलुयों को व्यावहारिक सफलता के लिए न केवल व्यवस्थापिका एव मजदातामों को यपने राजनीतिक कर्तव्यों एव दासिहाँ के प्रति मतत सजग भीर तक्षम होना धावस्थम है, परव्य हम भी धावस्थम है कि व्यवस्थापिका समा प्रीर निर्वाक्त में (मतदातामों में) वह क्षमता हो, जिसके द्वारा वे कार्यपालिका मारे निर्वाक्त में (मतदातामों में) वह क्षमता हो, जिसके द्वारा वे कार्यपालिका (घरकार) को उत्तरदासिक की भावना है प्रेतित कर सके। वास्तव में सम्बदासक प्रावती में व्यवस्थापिका एव मतदातागणों का धारपिय महत्व है, व्योंकि इन दोनों में ऐसी पारियों निहित है, जो भावस्थक जनतापिक प्रवरोधों के रूप में कार्यपालिका की सक्तियों वो वैद्यानिक दायर में सीमित रखते हुए, उसकी निरदुज प्रविचित्त को सक्तियों वो वैद्यानिक दायर में सीमित रखते हुए, उसकी निरदुज प्रविचित्त को सक्तियों वो विद्यानिक दायर में सावस्थकतानुसार सतुलन की स्थित स्थापित करती है। इसमें संदेह नहीं कि वार्यपालिका पर यदि बुख निश्चित भीर धायस्थक प्रवर्तिय न हो तो वार्यपालिका निर्हेतता की ब्रोर प्रवर्ति कार्यों के प्रति स्थापी मंद्रान्यपारामा की स्थापति कार्यों के प्रति स्थान होगी में स्वरद्यापारा की स्वर्तिक स्थापी के प्रति स्थान होगी मार्यपारिक है।

१. के० बस्यु मार्कर-विधिवारकम लाइला शन्द गर्वधार १६३२ पृ०-३२३ ।

भारत में ससदात्मक सरकार

मारतीय सविधान के अन्तर्गत केन्द्र और विनिन्न राज्यों में ससदात्मक प्रणानी की स्थापता की मई है। "भामन वर स्वकृष केन्द्र और राज्यों में विद्वार अणानी के तहुन सम्बाद्ध का अपने किया के पानी का विद्या के पानी के तहुन सम्बाद्ध के स्वाद्ध की स्वाद्ध के स्वाद्ध की स्वाद्ध के स्वाद्ध की स्वाद्ध के स्वाद्ध की स्वाद्ध के स्वाद्ध के स्वाद्ध की स्वाद्ध के स्वाद्

अस्तरीत सरकार के उत्तरदाशित को देनिक और सामगिक सामोद्या होती है। "
विदिश्य सदरीय प्रणाली के विकरीत जिसका जिसास ऐतिहासिक प्राथा र र गर्ने ने मुख्य का भित्रसानों ने आधार पर हुआ, नारत से सम्वतराक्ष्य करकार को उत्पाल निर्मित समिक्षान के विधिष्ट प्रावधानों पर प्राधारित है। इस तरम् यह नहां जा सक्या है कि जबकि इपलेख्य में समदाराक्ष्य सरकार पुख्यत. सर्वधानिक मित्रसानों पर स्वाधारित है, भारत्व में समदाराक्ष्य सरकार प्रचेत्यात्म करणाली के विकास में पत्रिसमयों के लिए कोई स्थान नहीं है। तथ्य तो यह है कि मारती राजनीतिक कथानी में सक्ष्यी सक्तरा के विकास के लिए विभिन्न विध्यों से सवस में, प्रामित्रमयों के प्राप्तता देने की प्राथित के लिए विभिन्न विधायों में स्वरूप, सविवाद में यह नहीं जिसा है कि राष्ट्रपति मंत्रीमण्ड का स्वरूप स्वरूप में ने लिए वार्य हैं । यही, निविवाद पर से, एक प्रमित्रम को धावस्थकता इसूत्त होती है। 'हमारे सविवान ने विदिश्य सविधान का सनुकरण दिया है धीर हमारी समयीन पढ़ित धीर परम्पाएँ विदिश्य सविधान विश्व एपरप्रपत्ता पद्धित एवं परप्परपत्ता प्र

यह निर्धारित करने के लिए कि मारतीय सविधान के झन्तर्गत केन्द्रीय सरहार ना बया स्वरूप है हमे सविधान के बुछ विशिष्ट प्रावधानी का अध्ययन करता लोगा

करना होता। मारतीय सविधान के धनुष्टेद ४० के धनुसार देन्द्र से एक राष्ट्रपति के पद की स्थापना की गई है। धनुष्टेद ४३ (१) के धनुकार सच भी कार्यपतिका सविधान कमक प्रतिची राष्ट्रपति से निहित की गई है धीर इन अतियों की

रे. एन० थीनिवासन-'डेमारेटिक गर्वमेच्ट इन इच्डिया', १६४४, वृ० १४४।

२ एष० एम० पटेल- विजिते गर्वमेण्ट इन इण्डिया (स्ट्रेडीत इन इण्डियन डेमोर्ड हो मे,) सम्पादित प० स्थार घ० र० निवासन द्वारा १८६५ पु० १६७ ।

राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सिवधान ने धनुसार प्रपने प्रधीन नर्भवारियों भी सहायता से उपयोग में सावेगा । धनुन्देद ७४ (१) ने धनुसार प्रधान मनी नी प्रध्यक्षता में एक मनोभण्डत होगा जो राष्ट्रपति नो उसने नार्यों ने सिए सहायता पर सत्त्वाह देया । धनुन्देद ७४ (१) ने डारा यह निर्चारित विधा भाग है कि मुनीएडाल सायहित रूप से सीनतामा ने प्रति उत्तरकार्यो होगा । धनुन्देद ७६ ने
धनुवार सथ के निर्णाल समद होगी विद्याम राष्ट्रपति व वो सदन होगे— राज्यसमा
और लोनतामा । धनुन्देद ७४ (१) ने धनुवार यदि नोई मन्नी लगातार ६ माह
तन सतद के निर्मा एक सहन का सदस्य गही बनता है तो इस समय ने पश्चात्
यह मन्नी यद दर नहीं रह सनता है।

भारतीय सविधान के उपर्युक्त प्रावधानों का ससदात्मक सरकार की परिभाषा श्रीर श्रावश्यवताश्रा वे सदमं मे श्रध्ययन करते हुए यह निश्चयपूर्वक वहा जा सकता है कि भारतीय सविधान द्वारा ससदात्मक सरकार की स्थापना की गई है। ससदात्मक सरवार की परिभाषा से ज्ञात होता है कि इस सरवार में दी प्रकार की कार्यपालिकाओं का होना धावक्यक है। सर्वप्रथम—नाममात या घ्वजमात्र की कार्यपालिका, जिसका मूर्तरूप राज्याध्यक्ष होता है। मारतीय स विधान के ५३ (१) के अनुसार नायेंगोसिना से सबिधत शक्तियाँ राष्ट्रपति मे निहित होती हैं भीर इन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरप ातिह होता है भार दून शास्त्रा का उपयोग राज्याति प्रकार प्रकार प्राचित्र होता कि प्रकारपार से करेगा पित्र प्रदूष करेगा कि स्वतिक के प्रनुसार साधारण स्थिति में वार्षपालिका—सविद्या प्रतिवयों को प्रयोग में सा सकता है। अनुच्छेद ४३ (१) के प्रवैधानिक अर्थ को सही सवर्ष में सममने के लिए, इसका प्रध्यवन धनुच्छेद अर्थ (१) धीर अनुच्छेद अर्थ (३) के साथ करना उचित ही नहीं प्रसिद्ध प्रत्यावस्थव है। यह कहना भी कोई प्रतियोगित नहीं है कि वस्तुत उपर्युक्त ये तीन अनुच्छेद भारतीय समदीय प्रणासी के जीवन-थापार हैं। ग्रनुच्छेद ७४ (१) के ग्राधार पर सधीय मत्री मण्डल का निर्माण होता है जो प्रधान मनी को अध्यक्षता मे राष्ट्रपति को सहायता एव सलाह प्रदान करेगा। परन्त मारतीय ससदीय ढाँचे का रीटहपी सहारा भ्रतुच्छेद ७५ (३) मे पाया जाता है, जिसके अनुसार मत्रीमण्डल सामूहिक रूप से लोकसमा के प्रति उत्तरदायी है। इस सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के प्रमुसार यदि लोकसमा द्वारा बहुमत से, मत्रीमण्डल वे विरुद्ध प्रविश्वास प्रस्ताव पारित विया गया है ती मत्रीमण्डल को त्यागपत्र देना आवश्यक है। देश नी सरकार ग्रीर प्रशासन को दक्षतापूर्वन चलाने का सारा उत्तरदायित्व मत्रीमण्डल का प्रत्यक्षरूप से ससद के प्रति ग्रीर भ्रप्रत्यक्षरूप से मतदातागण के प्रति है। सविधान द्वारा सरकार की नीतियो ग्रीर कार्यो का उत्तरदायित्व मत्रीमण्डल के ग्रतिरिवत किसी ग्रन्य व्यक्ति या सस्या को नही सोंपा गया है। भ्रतः सरकारी एव प्रशासकीय श्रुटियो के लिए दोप केवल मत्रीमण्डल ना ही होगा। घत यह तकसगत वात है कि ब्रीक सरकार ना नीतियो एव नार्यों ने सबन म सारी जवाबदारी मत्रीमण्डल की ही है. राष्ट्र-पति सावारण परिष्यितियों में केवल नाममात्र का राज्याव्यक्ष ही रहेगा।

द्वितीय, ससदात्मक सरकार के घटवर्षत वास्तिवन वार्षपालिका मुगीपण्डत. के रूप में होता है। वार्ष्टाविक कार्यपालिका को सता मधीमण्डत को सी जाती है क्योंक व्यावहारिकता में सरकार वो गीतियों एवं कार्यों के सित्त हरका उत्तर-दागित वार्ष्टाविक है। यह सरव है कि घटुन्हेंद २५ (१) के घटवर्षत प्रधान मधी वो गियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होनी है, और घट्य मधीमण राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के राज्यपादिक्तार निवृत्त होता है। वस्तु वह केवल एक सीवयारिकात है स्थोंकि साजरणवार राष्ट्रपति इसी करित मधीमण प्रधानमंत्री गियुक्त करता है, ओ लोवनमा में बहुमत दश्य को नेगा है। इसके घडिरास्त, पनेगे पद के लिए प्रधानमंत्री द्वारा मानेशित व्यक्ति को राष्ट्रपति स्वरीक्ष प्रधान हो। कर सकता है। सागूहिक उत्तरदायित्व का तिद्धान्त को पार्ट्यात संवरीय प्रधानों को पुरी है, पो मुख बायारी पर, व्यवहारिकार्य को दिल्ह में गियं र है।

(क) बेचल उन्हों व्यक्तियों की नियुक्ति सभी पद पर हो, जिन्हें प्रयोगमधी सनोनीत करता है।

(स) उन व्यक्तियों को मजीपद से पदच्युत किया जाये, जिन्हें प्रधानमंत्री भन्नीमण्डल में नहीं रखना चाहता है।

जण्युंक प्रावच्यताची को ध्यान मे रखते हुए राष्ट्रवित, सविधान के मनुसार संवच्यत्वा प्रधानमधी के प्यान्तानुसार, एक सर्वधानित राज्यान्यत के रूप से ही वार्ष के मान से ही वार्ष के व्यवस्थानित हा जान्यान्यत के रूप से ही वार्ष के प्रधान के स्थान से हिंदी वार्ष के विद्या के प्रवित्त के स्थान से निवति सदन के प्रवित्त विद्या साम के निवति सदन के प्रवित्त विद्या साम के निवति सदन के प्रवित्त विद्या साम के निवति सदन के प्रवित्त निवास के स्थान के स्थानित के स्थान स्थान के स्थानित का स्थान के स्थानित का स्थान है। भीभाष्यत के स्थानित राज्यो में जवस्थापिका साम विस्तानस्थान होती है, मंत्रीमण्यत के समा विस्तानस्थान होती है, मंत्रीमण्यत के स्थान कि स्थान सिवास के सिवास के स्थान स्थान स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान

विमागा ने क्रध्यक्ष रहनर वार्ष गरते हैं। एव सक्या पे रूप में वे राज्य की विधि-निर्माण एव दित सबधी नीति वा निर्देशन वरते हैं।"

भारतीय सर्वोध्य त्यायालय ने 'रायसाह्य राम जन्ध्यमा वपूर एवं धाय बताम पजाव राज्य' के प्रतरण म १२ मप्रेल १६४६ म निर्णय देते हुए निम्निनिति गर्दा में मारतीय सरकार के ससदासमा स्वरूप पर प्रताण हाला है।

"मारतीय सिवधान व प्रत्तमत वार्धपातिका का जिन सोमाप्रा वे दायर म कार्य करना है, उनका निर्वारण उस सरकार व स्वरूप व मदर्भ में विद्या जा सक्ता है जिसकी स्वापना सिवधान द्वारा की गई है। हमारा सिवधान सगठनारमा दृष्टि से समीय होने के वावजूद ब्रिटिंग समतारमन प्रणाती के प्राचार पर निर्मित है जिससे यह माना गया है कि नायंपालिका का प्राथमित्र उत्तरराधिक नीनि-निर्माण करना तथा उत्तकों कानूनी व्यावद्वारित्तता देता है परन्तु इस कार्त पर कि बहु राज्य को व्यवस्थापिका की विद्यास-पात्र बनी रहे। वार्थ-गालिका का वार्य नीति निर्मा-रण एव उसको कार्यान्वित करना है।"

यह सिद्ध करने के पश्चात् कि भारतीय समदीय प्रणाली की स्यापना सरियान द्वारा की गई है, जिसके ग्रन्तगत राष्ट्रपति साधारणतया नाममात्र वा णासव है श्रीर वास्तविक कार्यपालिका मत्रीमण्डत है यह श्रावश्यक है कि हम इस ससदीय जनतत्र म मतदातागण की भूमिका पर प्रकाश डालें, क्योकि विसी मी जनतत्र का मल ग्राधार उसके मतदातागण हैं) विशेषकर ससदीय प्रणाली मे मतदातागण का महत्व ग्रत्याधिक है वयोवि समदीय प्रणाली का मूल सिद्धान्त वार्यपालिका वे साम-हिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त—एक निरन्तर जीवित—सिद्धान्त है ग्रीर इस साम-हिन उत्तरदायित्व की सिद्धान्तरूपी श्रुखला मे तीन मुख्य कडिया जुडी हुई हैं, मत्री-मण्डल (वास्तविव कार्यपालिका) गिखर पर, व्यवस्थापिका मध्य मे ग्रीर सबसे नीचे किन्तु सबसे महत्वपूर्ण भूमिना, मतदातागण नी है। यदि इन तीनो मे से नोई मी एक सस्या जनतत्र के प्रति उदासीन हो जाती है तो जनतत्र प्रवश्य ही एतरे म पड जायेगा। यह सत्य है कि किसी भी जनता को ऐसी ही सरकार प्राप्त होती है, जिसके योग्य जनता है । यदि मतदातागण घ्रपने क्तंब्यो के प्रति सजग हैं तो सरकार श्रपने उत्तरदायित्व के प्रति प्रधिक सचेत रहेगी, पर येर्दि मतदाता श्रपने कर्तव्यो के प्रति उदासीन हैं, तो ऐसी दशा में सरकार पर से वह प्रकुष निकल जाता है, जिससे वह ग्रपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रखी जा सकती है। यह

१ ब्रार० जी० गेटेल—पूर्वोक्त पुस्तक पृ० २१८

२ मुकर्जी मूल्य न्यायाधीश—मुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस १६४४, भाग—१ जुलाई ऋगस्त १६४४ पृ०-२३०-२३७ ।

एव मतदातागण को वार्यपालिका के नियन्त्रण के लिए दैनिक तथा सामिषक शक्तियाँ प्रदत्त हैं।

मारत मे मतदाताम्रो ना विशेष महत्व है। वास्तव म यह वहा जा सकता है कि भारत में ससदीय प्रजातय की सफलता मतदाताग्रो की निष्ठा, क्षमता ग्रीर सज-गता पर ही निर्मर है। यह भूमिना, विशेषनर झाम चुनाबो ने समय म महत्वपूर्ण है, जब देश ने नानून-निर्माताओं और शासनो के निर्वाचन ना प्रमन जनता ने समक्ष ग्राता है। मतदातागण अपने राजनीतिक कार्यों को किस हद तक सफलता-पूर्वक करते हैं, यह इस बात पर निमर करती है कि वे क्सि हद तक निष्ठाबान, सम्म तथा सक्रिय हैं। मतदातागण यदि प्रकर्मण्यता, निरक्षरता, जशासीनता और ग्रायिक विषम्नता (विषमता) के शिकार हैं तो जनतत्र को विषल कर देते हैं। इन दोपो भ्रीर शृटियो के नारण वे भ्रपने प्रतिनिधियों ग्रीर शासको वा चुनाव सही रूप से नहीं कर सकेंगे। मारत में सविधान द्वारा ससदात्मक प्रणाली की स्थापना की गई है, इसका श्रमित्राय यह है कि यहाँ पर मतदाताओं का शिक्षित, सजग भौर ईमानदार होना नितान्त मानस्य है। भारतीय सविधान के अनुध्छेद ३२४-३२६ निर्वाचन समयी मामला पर प्रकाश ढालते हैं। सविधान द्वारा नागरिको को वयस्र मताधिकार दिया गया है। मारत ने प्रत्येक नागरिन को जो २१ वर्ष की मायुका है मत देने का अधिकार है। परन्तु उसको पामल तथा प्रपराधो नहीं होना चाहिए। इस तरह, स्वय सवियान द्वारा भारतीय मतदाताम्रो वे लिए प्रावधान विया गया है। सर्विधान द्वारा नागरिको को प्रदत्त मताधिकार, किसी भी राष्ट्रीय प्रान्तीय, तथा स्थानीय कानून द्वारा, सिवाय सविधान द्वारा निर्धारित प्रणाली के, भपदूत नहीं किया जा सकता है। सविवान द्वारा जनता को प्रदत्त वयस्य मताधिकार, सर्वियान निर्माताओं के उस विश्वास ना चौतन है, जिसके ग्राधार पर भारत में ससदीय प्रणाली की नीव डाली गई है।

स्वतनता के परचात् मारत में ग्रमी तक पाँच ग्राम चुनाव (१६५१-५२, १६५७, १६६३, १६६७ एव १६७१) सम्पन्त हुए हैं। इन चुनावों ने पूर्व जनता- त्रित्र सरवार में कार्यव्यव्यक्ति ना सरतीयों वो वोई प्रमुख नहीं था। अत अपन प्राम चुनाव के समय यह अद्मुख किया ग्राम कि मारतीय जनता वो न केवल जनतात्रित्र केवल जनतात्रित्र कार्याच्य का मार प्रमुख पह मी देखा गया कि प्रयिवाग मतदाता निरक्षर थे ग्रीर कई विभिन्न मामलों में प्रपत्ने विभिन्न राज्य- नीतिक अपित्रात्र कि सम्बद्ध के प्रमुखार प्रमुखन करने में प्रसम्प्र रहे। इसके वाववृद्ध, यह कहना गतद होगा कि इस सद कठिनाइयों वे रहते हुए भी मारत में जनतत्र की स्थापना तथा दृदता वे तिए प्रावस्थन करम एन सही दिशा में नहीं उठाये गये। वास्तविकता तो यह है कि प्रयुव्ध प्रमुखन वाह भी दिशा में नहीं उठाये गये। वास्तविकता तो यह है कि प्रयुव्ध प्रमुखन करम प्रमुख कोत

क्षारम्म सही दिशा में हुमा। डा॰ नामन पामर कहते हैं—"जबिक बहुत से उदाहरण, मतदान के उद्देश्यो तथा प्रणाती के न समम्रते के बीर इनके उल्लेषन के पाये गये, प्रथम यो स्नाम नात्रम व्यविकात निरक्षर जनता के बुद्धिपूर्ण मतदान करने की समता के प्रमाववासी प्रवर्षन थे।"

परन्तु इस में कोई सदेह नहीं है कि चार ग्राम चुनावों के प्रतुमव के प्राधार पर मारतीय निर्वाचकों की भूमिका में कुछ गमीर त्रुटियाँ उत्तर कर सामने सायी, जिनकों जनतज के हित में दूर करता प्रावयक है। इन विभिन्न त्रुटियों को निम्नानुसार प्रस्तुत विद्या दा सनता है। सर्वप्रपम-एक मुख्य जूटि वा यह ग्रानुमव विद्या गया कि एक गौसत निर्वाचक

भारत मे राजनैतिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से, बास्तविकता से अधिक दूर रहता भ्राया है। यह मारतीय जनतत्र प्रणाली का एक गमीर दोप है। इसका केवल यह तारपर्य नहीं है कि कितने नागरिक मत देते हैं, पर यह कि वे मत कैसे देते हैं। यदि मतदान किसी प्रलोमन या दबाद या व्यक्ति-विशेष या सम्प्रदाय के हित पर धार्धारत हैं तो निश्चय ही यह राष्ट्रीय जीवन की खावण्यकताओं की भारत-विक्ताग्रो से दूर है भीर इसके प्रभाव राष्ट्र के लिए वास्तव मे मताधिकार को प्रयोग में नहीं लाने के प्रभाव से अधिक हानिकारक सिद्ध होंगे। जानरोच इस सदमें मे कहते हैं- "मारतीय राजनीति मे एक तरह से वास्तविक्ता की कमी इसलिए है कि जनता की रचि किसी मूल बात में बहुत कम है।" यद्यपि यह सत्य है कि सविधान के लागू होने के कई वर्ष पत्रवात तक अधिकाश भारतीय निर्वाचको का रख राजनीतिक मामलो के प्रति उदासीन रहा है, किन्तु पिछले वर्षी के राजनीतिक बनुमनो के कारण निर्वाचको की राजनीति में दिलचस्पी धायक बढ़ी है। किन्तु यह विदित रहे कि यह दिलचस्पी प्राय उन मूल मुद्दों से ही सविधत नहीं रही है जिन पर राष्ट्रीय हित ब्राधारित हैं, परन्तु यह मी ब्यान देने योग्य तथ्य है कि यदि बुछ निर्वाचक राजनीतिक जीवन के प्रति उदासीन हैं तो हुछ निर्वाचक ऐसे भी हैं जिनमे घपने राजनीतिक प्रियराधे तथा कर्तव्यो के प्रति स्वस्य चेनना की जागृति हुई है। "यही जारण है कि घव समरातक जनतव के मियप के प्रति धाजा की वा सक्ती है।" इसमें सहेह नहीं है कि यह प्राप्ता प्राप्तका निर्वाचकों के प्रतो प्रतिकार एव कर्तव्यो के प्रति जातक होने दर निभंर है।

१ एन॰ पामर—'इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम,' पृ०२१७, स० १६६१ ।

२ जें ० रोच-'इण्डियात १९५७ इतेकामा' फार ईस्टर्न सर्वे, २६ मई, ५७ । १. भार० बर्नेहेम-'पार्तियामेन्ट इन इल्डियन डेमोक्रेसी' स्ट्डीब इन इल्डियन मोक्रेसी-मध्यर ग्रोर धौनिवासन १९६५ पु० १७०-७१।

द्वितीय-राजनीतिक जागहरता के लिए निरक्षरता एव धनिमञ्जता का दूर करना भ्रत्यावश्यन है। निरक्षरता एव प्रनिमन्तता, मारतीय जनतत्र म उन धुराइया के रूप म हैं जिनसे भारतीय निर्वाचको के जनतन के प्रति स्वस्थ रख के निर्माण म बाघा पहुँचती है। मतदान के प्रधिकार का उपयोग निर्वाचक की उस कार्यक्रमलता एव क्षमता पर निर्मर है, जिससे वह प्रपने दायित्वा को समक्त सकता है। निर्वाचक की इस योग्यता का विवास शिक्षा एव ज्ञान के माध्यम से ही किया जा सकता का इस नायता नाया जिल्ला है । वृत्ति मारत की प्रतिकार और अशिक्षित है, पिछान स्वरूप प्रशिवन विवासक अपने मता मी निरक्षर और अशिक्षित है, पिछान स्वरूप प्रशिवन विवासक प्राप्त के विभिन्न आम-चुनावो म चिठा।दयो को दूर वरन के लिए, निर्वाचन अधिकारियों ने कुछ विशेष चिन्हा और प्रतीको को, निर्वाचना की सहायता के तिए प्रयुक्त स्थित है। डा॰ पामेर का क्यन है— "करीब ग्रस्सी प्रतिकृत निर्वाचका की निरक्षरता द्वारा उत्तक हुई बुछ समस्याधी को दूर करने में लिए चिन्हो एव बहु मतदान पेटियो को रखा गया है। युछ राजनीतिक दला को उन्ह प्रदत्त किये हुए चिन्हों से अधिव लाम हुमा। उदाहरणार्थ वाग्रेस दल को, बैल जोडी का चिन्ह प्राप्त हुआ जिसके अनेर प्रकार के लामपूर्ण अर्थ लगाये जा सबते है। वई मारतीयों को यह समझाया गया कि वे वैला के विरद्ध मतदान न करें बयोबि बेल उनवी जीविका, शक्ति, यानायात ग्रीर कदाचित उनके धामिक विश्वास में चोतन थे। साम्यवादियों मो हथोड़ा श्रीर हौसिया ने लिए सहमति प्राप्त नही हुई, उनको हांसिया और मेहूँ की वाली चिन्ह के लिए सहमति मिली जो भारतीय विसान के लिए एक बहुत आवर्षक चिन्ह है।" इन पुटियों के बावजूद भी पांच माम चुनावो ने माधार पर, यह निश्चियपूर्वन पहा जा सकता है कि भारत मे जनतत्र सबधी जा परीक्षण हुमा, यह पर्याप्त मात्रा मे सफल रहा । परन्तु पूर्ण सफलता ने लिए वर्तमान त्रुटियो को दूर करना आवश्यक है। "वयस्य मताधिकार की कार्य सबधी उपयुक्तता को स्वतंत्र एव गुप्त मतदान प्रणाली के अन्तर्गत जीचने में लिये अर्द्ध शिक्षित या अर्द्ध प्रगतिशील देशों में दृष्टिमोण से, जिनमी जनता अधिनतर अनपढ रीति-रियाज से दबी और मतदान में विचार तथा व्यावहारिनता भीर जनतत्र ने तरीनो एव सिद्धान्ता से अपरिचित हो, भारत एक महत्वपुण प्रयोग शाला है। २"

तृतीय---राजनीति-विज्ञान वायह एक सत्य है वि श्राधिक श्रधिवारो वी अनुपरियति म, राजनीतिक प्रधिकार अयहीन हो जाते हैं । यह सत्य है कि सरकार

१ एन० पामेर-(पूर्वोकत पुस्तक' पृ० २१८। २ एन० पामेर-वही प्० २१६।

के प्रयत्नों के बावजूद भी, एक श्रीसत नागरिक की ग्रार्थिक स्थिति भारत में दयनीय है।

मार्थिक विश्वनता के कारण नागरिक मणने राजनीतिक मिणिकारों का रही । उपयोग नहीं कर सकता है। मार्थिक विश्वनता एवं सहमानता के बणुल में नकरें होते ही निर्मेश्वन विश्वनता एवं सहमानता के बणुल में नकरें होते ही निर्मेश्वन के दूराने में भागता राजनीतिक प्रियंकारों को स्वत्य तथा सञ्जीत निर्णेश सेने में प्रमुक्त कर सके। इसके परिणाम स्वत्य नवदान के समय बहु पूर्व मार्थि दुराइयों का मिकार हो जाता है। साम जुनाव के दौरान पत्रकार यह देशा स्वता है कि निर्वाक पूर्व में मार्थित होकर मतदान करते हैं। सदावात की स्वता है कि साम स्वता में यो बुराइयों है— (१) मार्थिक महमानता तथा (व) मत देने के निर्व भूत देने भीर सेने की मुर्वित।

श्री सरभातम का कहता है—"सर्वप्रथम यह प्रावश्यक है कि तिविकारों में सूप देन पर रोक लगाई जाये। पूस के प्रपराधे को जात करने और प्रपराधियों को सजा देने के तिए किये की कार्य करने और प्रपराधियों को सजा देने के तिए किये की कार्य के किये का गठन निया जाता नाहिंदे । यह भी प्रावभात होता चाहिंदे कि भूताव-प्रदश्मों द्वारा या निर्वाचकों की गून सक्या, उदाहरण के लिए एक हंतार निर्वाचनों, की भीन करने पर निरास जीक की जाय। यह जत कर इस दियों में के नवस्त निर्वाच जायें, जुना कु कुम के क्ये कि तियह जायेंगे, जिसमें केवल पनी और उनके अभिनर्ता ही माग के सकेंगे।" ।

जपर्युक्त मुख्य पुटियों के मितिरिक्त, माय मीने न निटयों भी माम जुनाबों के सार्व्यक्त मुख्य पुटियों के उत्तहरण स्वष्टम, विचारों की समीर्थना, मामा, सेन, जाित, मारे, मारेन, जाित, मारे, मारेन के सार्व्यक्षेत्र में सार्व्यक्ष्य के सार्व्यक्य के सार्व्यक्ष्य के सार्व्यक्ष क्ष्यक्य के सार्वक्ष्य के सार्व्यक्य के सार्वक्ष्

१. एन० सन्धानम, 'द्रानजीशन इन इण्डिया', १९६४ पृ० ६१-६२ ।

स्वतत्रता पूर्वेग अनुसरण गरने की दामता, तथा हिंसा वे बजाय प्रतिसा सवा जनतात्रिक सिद्धान्ती स्त्रीर प्रणालियों में ससीम विश्वास स्नादि आवश्वतताओं पर भारतीय जनतत्र का मविष्य और शक्ताता ग्राधारित है।

सक्षेप में, ससदारमव पद्धति की सक्तता के लिए मारत में निर्याचको की भ्रपने राजनीतिक भ्रधिकारी एवं वर्तथ्यों को ईमानदारी भीर निष्टापुर्वेक प्रवक्त षरना अत्यावश्यव है। विशेषवर, जब देश में आम धुनाव या समय आता है, निर्वाचको के केवल मतदान के अधिकार का ही प्रकानहीं है, परन्त इससे भी श्रवित सहत्वपूर्ण उनने इस बर्तव्य मा प्रश्न है कि पिछते पाँच यथे देश में राज-नीतिर प्रधिवारियो ने राजसत्ता ग्रपने हाथ में रगते हुए जा बार्य निये हैं. उनरी निष्पक्ष रूप से समीक्षा बारते हुए मतदान बारें । मादान बा प्रयोग, हम मा मे विविचा वे हाथ में एवं ग्राम के समान होगा. जिससे देश के शामकों के राज वितिव शाचरण की नियन्त्रित विया जा सबेगा । धता मतदान वा ग्रधिवार जनतत्र में एथ जातांत्रिक भ्रवरोध के रूप में है. जिससे व्यवस्थापिता. भ्रीर व्यवस्थापिता के माध्यम से बार्मपालिका पर, जनता का नियन्त्रण बास्तिविक श्रीर निरन्तर रागा जा सकता है। "बुढरो-जिल्मन पहा बरते थे, जनतत्र एव प्रति पठिन प्रणाली है। यह विदित है वि इसने लिए बुछ राजनीतिव परिपननता भी प्रावश्यमता है, पर यह बात प्राय विकास-उन्मुख देशों में मही पाई जाती है। इसके श्रतिरिक्त, मुख मत नेप जिनात कुछ सामा में मार्थिक सुदृष्टता, उत्तरदायिस्वपूर्ण नेपृत्व श्रीर पर्याप्त सर्वा में णिता, बुछ मामा में मार्थिक सुदृष्टता, उत्तरदायिस्वपूर्ण नेपृत्व श्रीर पर्याप्त नागरिकता मी मावना जिसमें जनता लोग गायाँ में मधिय हिंग्मा ले मने सीर नागारकता वा नावना । जसमा जनता साव नावा म आधव । हरना न नव आर भूस में वम नर सवे । ये वोई असमय याने नहीं हैं। यह सरी है वि बहुत से नये उमरते हुए देशा वो जनतत्र वो बुछ या सभी भूत आवश्यवताओं वी प्राप्ति नहीं है। पर यह विदित्त है कि इनमें से सिधा मो (यहाँ उदाररण में लिए मनेशिया, मारतवर्ष और पिलिशीन वा उल्तेस विया जा सबता है) जातत्र भी मुख्य आवश्यवताएँ उपलब्ध हैं। इनवो प्रेरित रिया जाना अधिव आवश्यत है। "

भन्त में यह वहना उचित होगा वि मारत में जनसत्र वे सपत्र संचालन के लिए विभिन्न भावश्यकताएँ उपलब्ध हैं, पर मारत की जनता और राजनीतिक नेतृत्व वो यह चुनोती है वि इन झावश्यवताओं वा उपयुक्त प्रयोग करे अन्यया यह समन है रि जनतन भी सूल झावश्यवतारों चाहे वे खमी अधिनशिल रूप मे ही वयो न हो एउ वे पश्चात एक समाप्त हो री चली जायेगी।

१. एस० पेडोवर--'व झमेरिकन रिपोर्टर' झगस्त १८, १६६५ ।

सपवाद वह यत है जिसके द्वारा राज्य की सारी प्रक्तियों का विभाजन दो प्रकार की सरकारों के मध्य होजाता है। ये दो प्रकार की सरकारें—वेक्टीय मी

٤

घतता है।"३

प्रकार को सरकार के गच्छ हाजाता है। य दा प्रकार का सरवार--वन्ध्र्य भार राज्यों भी (साप भी दबादयों) सरकारों के रूप में होती हैं। प्रो० द्वायसी ने सण् बाद पर प्रकाग बालते हुए कहा है----थह तह राजनीतिक यब है, दिसके हार राष्ट्रीन एकता और राज्यों (इबादयों) के स्विकारों में सामजस्य स्थापित विग

सपवाद राष्ट्रीय सार्वभीमिक्ता और राज्यों (इकाइयो) के प्रियंकरों की पृष्क मायों में जिस सायन डारा समन्वय और एवता स्वाधिव करता है—वह है सितांत संविदान, दिवलें अपतांत सार्वभीमिकता सवयी शांत्रियों ने पितानन केशीय एवं राज्यों की संवत्तरों के मध्य निया जाता है। वास्त्रत में, सम्बद्ध का तिडानंत सीमित सरकार के सिद्धान्त में सर्वभित है। सीमित सरकार से तास्त्रय है कि सरकारों (विजीध तथा राज्यों) की विभिन्न सांच्यों की सीमायों को स्पष्ट रूप से निर्मात सर्वभाव करना सर्वधित हों। "सिवाय रूप से सीमायों से निवर्त कर शक्तियों ना प्रयोग करना सर्वधितन होंग। "सिवाय रूप से सीमित सर्व-

भौमितना प्राप्त राज्य ही सम् राज्य है, जिसमें सीमाम्रो का निर्मारण इसकी इक्तरायों की मुर्रिक्षत सार्वभौमितना के द्वारा ही निया जा सत्ता है। यसीय राज्य की सार्वभौमितना सीमित होने के बावजूत में या सार्विक होते हैं। "व

इस तरह सपबाद ने भन्तपंत सरकारों के सीमित होने ना भूस नारण गर्ति के विभाजन का सिद्धान है। बात विहित्य के मुद्धार—"स्पीप सिद्धान से मेरी तासर्प गर्ति के विभाजन के तरीके से है जिससे सामान्य (सपीप) एवं क्षेत्रप्रिवारी (पान्ये) सरवारे भपने क्षेत्र म ससान एव पूचन होती हैं।"

१. प्रो० ए० यो० डायसी—'सा घाफ द कान्स्टीट्युशन', १६३८ पृ० १३८। २ ग्रार० मैकाइवर—'मार्डन स्टेट' १६२६ प्र० १८०।

३. डा० विहियर—केंडरल गर्वमेच्ट, १६५१ पृ० ११।

"सम सरवार वह है जिसमें सार्वमीमिनता या राजसता वा विभाजा पेन्द्रीय एव स्थानीय सरकारी के मध्य में हुआ हो, जिससे दामे से प्रत्येव एवं दूसरे से अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो।" 4

यह स्पष्ट है नि सपवाद द्वारा निसित सनिधान ने दायरे मे निभिन्न सरमारी पर सर्वधानिक सीमाम्रो ना निर्धारण होता है। सपवाद द्वारा निभिन्त ये सीमार्थ केन्द्रीय एव राज्यों की सरनारों ने सधीय सबघी में एन म्रावश्यन सतुनन एव समन्वय स्थापित वरती है, जिसने बिना सारा सधीय द्वीना एव पतीय हो सचता है। साधारणतथा नेन्द्रीय सरनार-सबधित सीमाम्रो ना उन्तेस निम्नलिखित है।

ह । साधारणवया व काम सारा स्टिमायस्य सामाआ व । उत्तय गानास्याख्य ह ।

क्षित्र संपीय व्यवस्थापिका सित्यान वा सशोधन नही नर साती है ।

सारीय व्यवस्थापिका को वेवल सिव्यान द्वारा निर्धारित क्षेत्र में ही
कानून बनाने की क्षमता है ।

३-सिंधीय नार्यपालिना नो भी वेवल सविधान द्वारा सीमित दायरे मे भादेश

तथा डिक्री घोषित वरने वा ग्रधिकार है।

उपमृत्त सीमाएँ राज्यो नी विधान समाध्रो और नार्धपालिनाध्रो पर भी लागू होती है। इत सदस्ये मे न्याय विभाग नी भूमिरा प्रस्थत महत्वपूर्ण होती है। वास्तव मे समीय राज्य में स्वायपालिना को सविधान ने सरकाण था प्रधिवार होता है। व्यापिन पुत्रवक्षोनन ना प्रधिवार इस उद्देश्य से प्रयोग में साते हुए, न्यायपालिना, व्यवस्थापिका या नार्थपालिना हारा पारिव नानूनो या प्रार्थितो ने धर्मेयानिन ठहरा सनती है। निसी भी सयीय व्यवस्था वा प्रसित्तव, यहाँ ने विखित सविधान की सर्वोच्चता ध्रीर सर्वेष्ण नित्तव की नार्य रखने में निव् व्यायपालिना ने सरकाण वी ध्राययक्तता होती है। इसना नारण प्रो० हायती ने सा प्रशार सपट निया है—'वृत्व सर्वोच परिवा प्रपान प्रतिवत वत सेरस-पन से प्राप्त नरता है जिसने हारा उस की स्थापना हुई है। ध्रत प्रत्येच समित जो राय-पालिका, व्यवस्थापिन एव न्यायपालिना से सर्वाप्त है, पाहे वह सम्पूर्ण राष्ट्र भी हो या निसी एव राज्य भी, सर्विधान के प्रयोग निव्यत्तित है। "व सर्वीच राज्य भे लिखित सर्विधान सर्वोच्च कानून है। सर्विधान ने <u>मार्येच्यता</u> निम्न सिवित तस्यो पर प्राप्त प्रत्य भी स्थापित है।

स<u>र्वप्रथम</u> सर्विधान का लिखित स्वरूप होना धायक्यव है, जिससे इसमे स्पन्टता रहे धीर संधीय मामलो में मतमेंद होने की समावना बहुत कम हो जाये।

१ प्रार० गेरेन-व रिपोर्ट भ्राफ व रायल कमीशन ग्रान श्रास्ट्रेलियन कानस्टी-द्युगान ।

२ प्रो० ए० यो० हायसी—'पूर्वीवत पुस्तक पू० १४०।

सभीय सर्वियान वास्तव में एक मनुबय के रूप में है, दिवसे मुद्ध श्रीवस्तर करों को, विसिन्न सभीय हमाइयों को सहमति से, हेन्दीय एव राज्यों को सरकारों में शिस्त्यों को उस्ति बिन्न एवं परिमापित करने के तिए वीमित किया गर्वा है। विश्वित सिद्धान में नहीं कर महत्य सभीय प्रणाती में इस दृष्टिमेंच से पाया जाता है कि इसके मन्त्रांत तथ भीर राज्यों के सबसे में गड़वारी और सम्बेह की समावना नहीं रहती है। सावारण कानुनों की तुलता म तिबित्त सिद्धान स्थायों है। इसके ब्राय सरकारों के सपट मीर वार्यों का समृत्यों की स्वत्य स्थाप का स्थाप तथा स्थाप का स्थाप के स्वत्य सीर स्थाप का स्वत्यों के स्वत्य भीर स्थाप का स्थाप तथा स्थापित स्थाप

दिरोप चूरि निवित सरिवार सब सौर राज्यों के सर्वेषातिक समसीत है सहाय है सत तुर्वे <u>वार-कार समीति है</u> जिल्ला साहिश । सविवार को निरन्तर समायाने है सत हुने बार-कार समीति है सता ता दी निरुव्य ही सवीप वाँचे के नण्ट होने की समावना पैदा हो सरवी है। सन, प्राय यह देशा प्रया है कि विन राज्यों ने सब स्वत्स्या तो प्रपादा है उनके सविधान संग्रीयन के दूरियों से निर्देश हैं। सन, प्राय सह देशा प्रया है कि निर्देश कि निर्देश हैं। सन सावार ना संग्रीय के दूरियों से निर्देश दिक एक विरोध सत्रीयन रमावा है। सावार ना निर्देश की निर्देश के कि निर्देश को स्वत्या ने को सावार स्वत्या है। भी क्षायत के करिए में प्राय तरि स्वार्य की सावार स्वत्यापिक सावार सावार सावार स्वार्य सावार से सावार स्वत्यापिक सावार से स्वार्य स्वत्यापिक सावार से सावार स्वत्यापिक सावार से सावार स्वत्यापिक सावार से सावार से सावार स्वत्यापिक सावार से सावार स्वत्यापिक सावार से सावार से सावार स्वत्यापिक समावार (स्वाय सावार) है सर्वेषा निम्ह है। "

मापुनिक पुग्ने से तोव करनाणवारी राज्य को मुर्त कर देने के जिए प्राण्य पह प्राण्य कर हो जाता है कि सर्विचान ना समीधन, सामाजिक मीर माणिक त्याप के साधार पर राष्ट्र की मानवरनामुद्धार दिना जाते । एरन्तु मह प्राण्य म रहे हि समीच राज्यों में महिष्यान का समाजित के महुनार ही हो केगा । "मह निविचन है कि नहीं कही भी सम सरकार है, वही सरकार ही ही कोगा । "मह निवचन है कि नहीं कही भी सम सरकार है, वही सरकार के निर्माण का सम्प्रेम प्राण्यों को सिद्धान रहे के ने प्राप्तिक मटन्त देते हैं । समूर्य सर्वयंगी व्यवस्थान सता सर्विचान के मन्तर्यंग मुर्तिक रूप से किसी सामायर व्यवस्थानित काम म निहित नहीं को जा सहती है, क्योंकि दस तरह से सम्प्रेमीय व्यवस्थान सता वा निहित नहीं हो जा सहती है, क्योंकि दस तरह से सम्प्रेमीय व्यवस्थान सता वा निहित नहीं, राष्ट्र पह स्थानित होता । " दे

सधीय राज्य म अत्यक व्यवस्थापिका समा, सधीय सविधान के मन्तर्गत एक सत्रमान विधि निमाणात्मक सस्या है, जिसके द्वारा निमित कानन, उपनियमो, के

१ प्रो॰ शयसी-पूर्वोस्त पुस्तक पृ॰ १४२।

२ वही प्र० १४३।

--

का सगठन एवं छिल्तियों, भौर नागरिकों भीर सरकार के बनतादिक संववों की तिप्रोरित करने ने निए निम्नानिस्ति तीन हुष्य सावस्यवताएँ होनी चाहिये— (क) सिवधान का निनित हाना, (स) सिवधान का सनसनीय या कडोर होना, धीर (ग्रेन्द्रतव एव गृक्तिगानी संधीय न्यायापालिका का हीता ।

एउम्बेन्त विवेचन के ब्रामार पर हमारे समझ दो महत्वपूर्ण प्रस्त बाते हैं। सर्वप्रयम-नारत के सविवान के बन्तर्यंत संवीय व्यवस्था किन हद तक स्यापित की गई है, और, द्वितीय, क्या मारत का स्विधान मेमेरिका के सविधान के तुल्य देग का सर्वोद्य कानन समना जा सबदा है।

भारत में सचवाद की ब्रावस्वकताएँ--प्रथम प्रश्न के सदर्म में यदि भारत के स्वितान के विभिन्न प्राथमानों की मनीक्षा की जावे तो उनके प्राथार पर गढ निश्वितपूर्वेत वहा जा सबना है कि भारत में सब राज्य की व्यवस्था की गई है । परन्तु सवियान में, विभिन्द रूप में सब (बेंडरेशन) शब्द का उपमीग कहीं नहीं विना गया है, प्रतुष्केद र ने प्रतुसार मारत राज्यों ना एवं 'मृतियत' साना गया है। हा॰ अम्बेदनर ने, जो प्रारुप समिति के अध्यक्ष थे, 'फेंडरेशन' शन्द की अपेक्षा 'यूनियन' वा ही उपयोग विया । उन्हानि कहा-"विसी नाम को उपयोग में लेने से कोई अन्तर नहीं होता है। समिति न ब्रिटिश नार्य बमेरिका एक्ट १८६७ को माया का प्रमुखरण करना ही पनन्द किया है, बीर यह निर्णय तिया है कि कारत की 'युनियन' की शता देने में कुछ लान है, परन्तु भारत का सविधान स्वरूप न संधातक £ 1773

व्यावहारिक्ता के दृष्टिकोण ने यहाँ सूत्र प्रन्त यह है कि चूंकि भारत को सकि-मान द्वारा 'यूनियन', न कि 'फेडरेशन' की सजा दी गई है, तो क्या सविधान में संबोध प्रवानी की बनिवादी बावस्वक्ताएँ निहित हैं ? संबोध प्रभारी के परस्वरा-बादी निद्धान्त क प्रतुपार सुपीय सुविधान को निश्चित होता प्रावस्यक है, सुविधान में सब भौर राज्या की सरकारा के कथा क्षांट हम स बक्तियों का बँदवारा होना पार्टिये. भीर मन्त्र में, संघीय व्यवस्था के बन्तर्यंत्र सर्वोस्त्र न्यायालय के निए प्राव-धान होना चाहिये, जिसके बारण सनिवान का सरक्षण किया जा सकेगा । सारत के मदियान में इन वीनों मावस्त्रकताओं को मान्यता दी गई है। सतः यह बहना स र होता कि मारतीय सविदान में सपवाद के विद्वान्त को भारताया गया है। उपर्वतः वीतो विशेषतास्रों को दृष्टि से. निम्ननिवित रूप में भारत के संविधान का विश्वेपण किया जा सकता है, जिसके इसके संघीय स्वरूप पर प्रकाश हाना जासके।

१ बी॰ बार॰ ब्रम्बेदकर—हास्ट कान्स्टोटयुशन, भाग ४ १

मारत में संपीय प्रणाली नी डिनीय झावश्यनता सम एयं रें रेण्या पहिन्दों ना स्पट और दिस्तृत विमानन है। सरियान में सनुच्छेद २४४-२६३ सब और राज्यों से मध्य पहिन्दों ने विमानन पर प्रशास डाउते हैं। "मारन को सवियान में सभ और राज्यों ने मध्य सता-विमानन से दो विधिष्ट परन्तु पृथन् सतायुक्त गोतन नेन्द्रों ना निर्माण हुमा है।",

सिवियान की सात की प्रमुखी के द्वारा विकारपूर्वक कास्तियों के विमाजन का उल्लेख किया गया है। क्षतिन-विमाजन के जिस नमूने का सवियान में उपयोग किया है, वह मारत सरकार प्रचितियम १६३५ के क्षत्तर्गत सब एव द्वाइयों के वीप्राधिकारों के विमाजन के सद्दा है जो तीन सूचियों द्वारा निर्धारित किया गया या। ये तीन सुचियों, इस प्रकार सी।

 सभीय सूचि, स राज्य सूचि, सौर म. समवर्ती सूची। इसी नमूने ने प्राधार पर मारतीय प्रविचान की सातथी अनुसूची द्वारा सथराज्य व्यवस्थापन सबची विचयो का उन्तेख कुरते के लिए निक्नानियित तीन गूचियो को रक्षा गया है।

(व) सपीय सूची—इसने अन्तर्गत हुए विषय हैं। सवियान, वेवल सघ ससद को, इस सूची में उल्लेखिन विषयों पर विधि-निर्माण करने वा अधिकार देता है।

(स) राज्य सूची—इसमें ६६ विषय हैं । साधारणतया इस सूची में विणत विषयों पर राज्य-विद्यान समाग्रों के क्षेत्राधिकार के होते हुए भी, सरिव्यान में कुछ

१ मास्टरपार्ड-डेमोक्नेसो इन इण्डिया 'इन डायलाग्स माफ डेमोक्नेटिक पालिटिश्स इन इण्डिया'-सन्पादित जी हलप्या द्वारा १९६६ पु० २१७।

भारतीय शासन श्रीर राजनीति

श्रपवादो को मान्यता प्रदान की गई है, जिनका वर्णन विस्तृत रूप में, ग्रागे किया

20

(१) समयती सूची — इस सूची मे ४७ विषय हैं, समवती सूची में जीलांखित विषयों पर सबद और राज्यों नी विधान समझों नो समती क्षेत्रीकों क्षेत्राधिकार दिवा में त्या के हैं। प्रमुच्छें द २४ न बसुतार सेत सबीय कानून और विशी राज्य कानून में समनवाँ सूची में उदिलांतित निसी विषय पर मतमेंद या सपर्य होता है तो ऐसी दाग में सध्येश मानवता प्राप्त होगी, परन्तु बाँदि राज्य नानून को प्रदेश मानवता प्राप्त होगी, परन्तु बाँदि राज्य नानून को प्रदेशत एपड़पति की सहसति प्राप्त हो गई है तो ऐसी स्थिति में राज्य नानून को हो मानवता प्राप्त होगी।

मारतीय सविभान में प्रविष्यः गृतिकायों के जिए भी उनिल प्रावणान विभा गार है। प्राविष्यः शिक्तारों से हैं, जो शिक्त-निमानन सवयों सुविद्यों में ए किल्तिक नहीं है। यह मानव वृद्धि के लिए समय नहीं है नि प्रविद्या से उत्तर होने वाली प्रयोग समया या निष्य का सही रूप से अनुमान तपाकर, सिद्यान में उनके लिए प्रावपान कर सरे। इस समावना वा सामान रूप के लिए प्रविच्या के उनके लिए प्रविच्या के उनके लिए प्रविच्या के सिद्यान में में में में में में में में मानवान के स्वविच्या के तिया होता के सिद्यान के सिद्यान के सिद्यान के में में मानवान कर से लिए एविन्त प्रवादान निया गया है। विकास उत्तरी हैं हाता निषय निवच्य प्रयादा कि नियान उत्तरी के सिद्यान के सिद

भारतीय सविधान में सशीधन प्रणाली—सभीय सविधान की स्थिरता के लिए सिवीपतास विधान ने गणिन-विमानन वस्त्रीय प्रावणाने की स्थिरता के लिए, सविधान में कठोरता या प्रमानशेतता बातन कर महित प्रावणक है। महास्त्र है कि यह स्वमती-यता वारतव में सथ प्रीर राज्यों के शेत्राधिकार से, जिनका निर्माण्य शिक्षा विभा-जन द्वारा होंग है सर्वाधन होना चाहित्र। मारतीय मविधान के बुद्ध हिस्सी जिन एर सारतीय स्थायत का प्रसित्तत्व निर्माण कर है कठोर या प्रनमनीय है। जारत के सर्वाधन को बुद्ध हट तक नमनीय प्रीर चुद्ध हट तक प्रनमतीय मा कठोर माना जा सकता है। यह बात करने के लिए कि मारत का सर्वाधन कही वक नमनीय है धौर कहीं तक नजेर है, हमें उसकी सहीधन प्रणाली का सम्यवन करता होगा। मारतीय सर्विधान के संकोधन के हम्विधन से इंटिकोण से इंडिक विमिन्न प्रावधानों की

- विभिन्न कीन श्रीणयो मे रखा गया है। प्रत्येक श्रेणी मे रखे ग्रंथ सविधान के प्राव-

यान सविधान ने अनुच्छेद ३६० मे चिल्निसित एक विधिष्ट प्रणासी ने अनुसार समोधित क्षियं जा सनते हैं।

बस्तुत मारत ने सविधान ने अन्तर्गत तीन पृषक् प्रनार नी संशोधन प्रणासी हैं। सविधान सदीधन की इन प्रणालियों नो सर्वधित प्रावधानों में अनुसार इन प्रनार दर्शामा गया है।

(क) भारतीय सर्वियान के कुछ प्रावधानों को केवन संसद में माधारण विधि-निर्माण प्रणाली वे उपयोग द्वारा संशोधित विया जा सवता है। इसवा यह तात्पर्य है कि ससद के द्वारा ऐसे प्रावधाना के मणीयन के लिए केवल साधारण बहुमा मे विषेयक पारित करना ही पर्याप्त रहेगा । यह समोघन प्रणाली ब्रिटिण सरियान की सशोधन प्रणाली से मिलनी-जुनती है, बयोति इमलैण्ड में सर्वियान का सशोधन केंबन ससद द्वारा साधारण बहुमन द्वारा पारित कानून से विया जा सकता है। उदाहरण स्त्ररूप, सर्वियान के अनुच्छेद ३ व अनुसार मेघ के नये राज्य की स्थापना और राज्यों ने नाम या सीमान्नों में परिवर्तन ससद द्वारा पारित किये कानून से जिया जा सक्ता है। इसी तरह धनुच्छेद १६६ वे धनुसार सप के उन राज्यों मे जहाँ दितीय सदन नहीं है, वहाँ उनशे स्थापना श्रीर जिन राज्यों में दितीय सदन है, परन्तु श्रनावश्यकता वे बारण, उनका समापन वेजल ससदीय कानून के माध्यम से निया जा सरता है। सरिधान के नागरिक सबधी प्रावधान एवं अनुसूचित क्षेत्रों और श्रनस्चित जातिया सत्रयी प्राप्तवान ससद के कानन के द्वारा ही सशीधित निये जा सकते हैं। भारतीय सर्विधान के ये प्राप्तधान सर्विधान में नमनीयता की झलक प्रद-शित नरते हैं क्योरि इनके अनुसार सशीयन सरलनापुर्वक ससद में सायारण बहमत हारा किया जा सकता है। संघवाद के दृष्टिकीण से जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके संशोधन की भ्रत्य निधि है।

(स) समीधन की दूसरी श्रेणी ने झन्तर्गत झत्यन्त महत्वपूर्ण प्रावधानो को रपा गया है जिनका सबैधानिक एव राजनीतिक महत्व इनने सधीय स्वरूप से प्रदक्षित होता है। वास्त्य मे मिबधान के ये प्रावधान मारन मे सपवाद के जीवन-रक्त के तुल्य हैं। इनमें निम्तनिसित प्रावधान विचारणीय हैं।

१—मनुष्टेंद ४४ एन ४४ जिनने घाषार पर राज्या नी तियान समाम्रो ने निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति ने निर्वाचन मे हिस्सा ने सनते हैं, मनुष्टेंद ७३ एव १६२, राज्यों नो नार्षपासिनाम्रो ने सबम मे, भीर मनुष्टेंद २४१, समीय भू-माग पर स्थापित जन्मतम न्यायासय ने सबस मे।

२—सविधान वे चौथे प्रष्याय वा पांचवां मान, सधीय न्यायपानिना वे सनय में । सविधान में ११वें माग या पहला प्रथ्याय, सघ धौर राज्य वे व्यवस्थायन सबसी मामलो के सबय में । ३--- मिवधान के वे प्रावधान जिनके आधार पर राज्यों को सहाद में प्रति-विशित्व प्राप्त है।

४—सर्विधान का ग्रनुच्छेद ३६६, सशोधन प्रणाली के संबंध में ।

चैंकि उपरोक्त प्रावधान, भारत के सविधान के ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिन पर भारतीय सब का सम्पर्ण ढाँचा प्राधारित है. इनके सज्ञोबन के लिए एक विशेष क्ठीर पद्धति को ग्रपनाया गया है। यह कहना उपयुक्त होगा कि भारतीय सविधान के इन प्रावधानों की संशोधन प्रणाली ग्रमरीकी सविधान की संशोधन प्रणाली से बहुत कुछ मिलती-जुलती है, क्योंकि बमरीकी सर्विधान में भी सघवाद के सिद्धान्तो को समाविष्ट विया गया है। ग्रमरोकी सविधान के अनुच्छेद ५ के अनु-सार काग्रेस (सधीय व्यस्थापिका) ग्रपने दो-तिहाई बहुमत के ग्रावार पर समीधन प्रस्तावित कर सकेंगी या विभिन्न राज्यों के दो तिहाई राज्यों के विधानकों की माग पर, सविधान में संशोधन के लिए, एक सम्मेलन बलाया जायेगा । यह विदित रहे कि उपर्यक्त दोनो ही तरीको में से किसी भी एक के अनुसार अगरीकी सर्विधान मे सशोधन प्रस्ताबित किया जा सकता है। परन्तु यह अमरीकी सविधान की सशोधन का प्रथम चरण ही है। द्वितीय या अनिम चरण सविधान में सशोधन को पारित नरता है। जब उपर्यक्त दोनों में से किसी एक तरीके के द्वारा संशोधन प्रस्तावित किया गया है, निम्नलिखन दो में से किसी एक तरीके के अनुसार प्रस्तावित सशोयन पारित किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधन तीन-चौयाई राज्यों के विधायको द्वारा या तीन-चौथाई राज्यो में तथा सर्वेषानिक सम्मेलनो द्वारा पारित किया जा सकेशा 1

हती अन्तर मात्रीम सविचान के उन्मूंक प्रावदान, दिनला बनंग दिनीय भंगो में विचा जा चुका है, एक विषेष एव जटिल प्रणाली द्वारा हो समीचित हो सनते हैं। इस समीचन प्रणाली के धनुवार समीचन विषेषक नो स्वार के दोनों सदनों के समस्त सब्दानें के बहुमत से एव उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहार्ट बहुमत है गारित विचा जाना धाना प्रकार के है। इसके पचनात् यह मी आवश्यक है कि सस्य द्वारा पारित उन्तर समीचन विचेषण ने सम्यान यह मी स्वारों पार्ची की विचान समान्यों नो सहस्ति प्रणाल है। हो से तिहानी से स्वारों के स्वार से की राज्यों (इस्तार्ट प्रणाल है) के विभाग प्रविचारों से प्रतिस्ता निस्ता से स्वारोत नहीं है, वेशक स्वार के एन प्रशीव नामें द्वारा सभीचन निया जा सन्या है। धीर जहीं पार्ची के धरिकार एवं सतिवारी है, वहीं तथ धीर राज्यों के है। धीर जहीं पार्ची के धरिकार एवं सतिवारी है जह से प्रधार राज्यों के

१. एम॰ पी॰ शर्मा—द गर्वमेंट झाफ दी इण्डियन रिपब्लिक, १६६० पूर्व

में संवासन विषयों से संविधत प्रावधानों में सर्विधान की सर्वोच्चना की संसक विधेष रूप से पाई जाती है। सर्विधान की इस विशेषना के सदमें में श्री जीठ एनठ जोगी का क्यन है कि 'यह प्रावधान संघासक सिंद्धान्त के स्पृतुत्व है कि प्रस्तावित संघोधन यदि संघीय प्रधासी के मूल सिद्धान्तों को जिनको मूल संघीय समझौते में मान्यना दी गई है, प्रमावित करता है, राज्यों की विधान समामों की सहसीत मावस्यक है।"

(ग) सदियान के संशोधन के दृष्टिकाण से हमने उपर्युक्त को श्रीणया में निहित सविधान के प्रावधानो तथा उनके संशोधन के लिए दो संविधत संशोधन प्रणालिया ना प्रध्ययन दिया । इन दो श्रेणियों से सर्राधन प्रावधानों ने प्रतिरिक्त भारत के सविधान में बुख ग्रन्य प्रावधान शेष रह जात हैं। वस्तुन, इन प्रावधानों को तृतीय श्रेणी में रखकर हमारे समक्ष प्रकृत यह है कि इन प्रावधानों को जिनको हमने तृतीय श्रेणी में रखा है किस विद्याप्ट प्रणासी द्वारा समोधिन किया जा सकेगा। सविधान में इन प्रावधानों के संशोधन के लिए जिस प्रणाली का उल्लेख किया गया है वह इस प्रकार है कि समद के किसी एक सदन में प्रस्तावित संशोधन के लिए विषेयक प्रस्तुन किया जा सकता है और यदि इसका उक्त सदर्म में सदन की 'कुल सदस्य सस्या के बहुमत से एव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो निहाई भ्रजो के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो उक्त विधेयक को दूनरे सदन में विचार विमर्श के लिए भेज दिया जायेगा, जहाँ पहले सदन द्वारा अपनाये उपर्युक्त तरीने के अनुसार पारित होते और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त 'करने के परवात इसको सबैधानिक कानन का रूप प्राप्त हो जायेगा, जिससे सर्वियान में आवश्यक संशोधन लागू हो सकेगा । यह सशीधन प्रक्रिया योडी जटिल है, क्योंकि यह कानून निर्माण करने की सरल प्रक्रिया से थोडी मिस्न है, जिसके लिए ससद में साधारण बहमत ही मावश्वक होता है।

मारत के सविधान में संघोषन के दृष्टिकोण से उसे उपर्युक्त तीन श्रीणियों में विमालित किया,गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम श्रेणी में उल्लिखित सविधान के प्रावधानों का संघोषन सरल संघोजन प्रणाली द्वारा किया जाता है। सामाज्यत: या तिसी सविधान की संघोषन प्रणाली साधारणत: सरल है तो यह निष्कर्ष निकास जाता है कि सविधान को धवस्य हो नमतीय या संघील होना चाहिया। चूँकि नारल के सविधान के दुख्य प्रथम, जिनका उल्लेख उपर्युक्त प्रथम श्रेणों में कि नारल के सविधान के दुख्य प्रथम श्रेणों में किया गया है, सरल प्रणाली द्वारा संघोषित किया जा सकते हैं, धन. हम यह वह सवते हैं कि सविधान कुछ हुद तक लियात है।

१. जी० एन० जोशी-द्वानस्टीट्युशन झाफ इध्डिया, १९४२ प्० ३७४।

धाव हमे यह देशना है कि भारतीय सविधान में समयान की सीसरी भौर आयरमहरता के लिए क्या प्रात्मान निया गया है । मारतीय सतिधान के धानुकेद १२४ के सद्भार एक सर्वोच्च व्यात्मस्य ऐसा, विस्तव एक मुख्य त्याया-पीत्र होगा और, जब तक सत्तर कानृत द्वारा नहीं निर्मारित करती है, सात धान्य सावाधीय होंगे । सुनीय कोर्ट सधिनियम १२४६ हारा, मुख्य न्यायामीय के पति-रिक्त द्वार प्रत्य त्यायाभीयों के सिए प्राव्मान निया गया है। सविधान के सरक्षण के ख्य में मारतीय सर्वोच्च व्यायालय के गाविध्यों ना स्वायार सर्विधान में निम्न-स्वित्तर सौ स्वीत्र के छूप में पात्म खाता है।

(क) प्रमुख्दर १६१-१६३ के घन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय राज्य मूची मे उन्होंतित विषय पर सबद द्वारा निर्मित नानून को प्रवेच भोषित कर सकता है। यदि इस कानून का निर्मीच साद ने लेकिया के प्रमुखार न दिया है तो सर्वोच्च ग्यायालय, व्यवस्थापन सबयो क्षेत्राधिकार की ब्रावश्यक्ता ने नारण उक्त कानून की प्रवेषानिता पर प्रमाना निर्मीय है सकता है।

(स) अनुन्देर ३२ (२) के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को नक्षेत्रल यह प्रधिकार है किन्तु उसका उत्तरदायित्व भी है कि नागरिकों के भूत प्रधिकारों की रहा करें।

इसम सदेह नहीं कि उपर्युक्त दो घरिकारों के कारण सर्योच्य न्यायालय प्रारत। में सर्विवान की सर्वोच्यन को सुदृष्ठ कार्यि रायने के लिए, एक प्रत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। धत. सुख्त प्रारतीय सथवाद वा घरिताद इस न्यायालय स्व चित्रतार्थ सर्योग प्रतिका पर ही साधारित है। इस घरध्यन के आवार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मारत में संघवाद की तीनो धावश्यक्ताएँ विद्यमान हैं, जो निम्नलिखित है।

- (क) लिखित सविधान,
- (ख) सथ एव राज्यों में शक्तियों का विमाजन, ग्रीर
 - (ग) सर्वोच्च सधीय न्यायालय

"नारत का गणराज्य एक सब हैं, परन्तु इसके कुछ विशिष्ट गुण है जिनके द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के बुद्ध संघीय स्वरूप में कुछ परिवर्तन-सा हुमा है।''

भारत में संघवाद एवं ससदीय सार्वभौमिकता

समवाद और नागरिकों के मूल अधिकारों को सविधान में समावेशित करने के फलस्वरूप सविधान देश के सर्वोच्च कानून का रूप धारण कर लेता है। लिखित रूप में सविधान में, सविधान की सर्वोच्चता का कही भी उत्लेख नहीं किया गया है। कराविज्ञ सविधान में, सर्विधान की सर्विधान ही की सर्वाधान की सर्वोच्चता के लिए प्रावधान करना दालिए बनावथ्य समभा कि सर्विधान की सर्वाधान के लिए प्रावधान करना दालिए बनावथ्य समभा कि सर्विधान की संग् एव राज्यों की सरकारों के विभिन्न भगों की शक्तियों एव अधिकारों वा लोते हैं और सर्वाध के सिद्धान के प्रवृक्ष सर्विधान का संशोधन नेवल एन विभिन्न विद्या सर्वाधान के स्वाधान की साधारण विधि निर्माण करने की प्रक्रिया से संशोधित नहीं किया जा सर्वाधान के सहीय पर भी, सर्विधान देश का सर्वोच्च कानून है भीर जनता की साबंभीमिकता ना दर्गण है।

भारत में सबवाद की मान्यता का महत्वपूर्ण प्रमाव सथ भीर राज्य की सरकारों के सीमित सरकारों के रूप में कार्य करता है। सबवाद द्वारा राज्य-सत्ता का विमाजन होता है भीर विमाजित राज्य-सत्ता का विमाजन होता है भीर विमाजित राज्य-सत्ता का सरकारों एवं उनके विमाजन मंगों को सीमित रूप से ही प्रदत्त की जाती है, जिनकी उत्तरित का स्रोत स्वय सविधान है। इस दृष्टिकोण से मान्तीय संसद की शत्वयों का सीमित होता साववयक है। बत: मारतीय संसद की सार्वमीमिकता भीर बिटिस संसद की सार्वभीमिकता में पूर्व मिनता है। इसर्वेड में ब्रिटिस संसद की सार्वभीमिकता में सूर्व मिनता है। इसर्वेड में ब्रिटिस संसद की सार्वभीमिकता कि स्वयंचित संविधान की सर्वोच्चता स्वयंची मारत की संसद की सार्वभीमिकता महत्वपूर्ण विषय है। ब्रिटिस संसद के द्वारा संस्वानुसार पारिल

१. एन० पामर—इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम, १६६१ पृ० ६४।

सर्वयानिक वानुनों को धान विटिश सिवधान का एन हिस्सा माना जाता है। दस्तिये विटिश ससद नई सर्वयानिक वानुन की स्रोत है। वस्तन ने विटिश ससद व्यावधानिश होने के साथ घिष्यान साथी भागी जा सनती है। यर एक निरात स्वावधानी विद्यान समा है। परणु मादिवा संसद मादिवा सर्वयान नी मिष्ठ है। स्वर एक निरात स्वावधानी विद्यान समा है। परणु मादिवा संसद मादिवा सर्वयान नी मिष्ठ है। स्वियान द्वारा यो गई है। स्वियान द्वारा निर्माण संभायों का उत्तवपन करके मादिवान सर्वाय स्वावधानि होगा। विटिश सर्विवान का स्वावधानि करियान विद्यान सर्वयान के स्वावधान के स्वावधान के स्ववधान के स्

भारतीय सविधान के ग्रन्तर्गत एकात्मक तत्व

भारत में सथवाद की स्वापना के साथ ही सविधान के अन्तर्गत वेन्द्रीय सरकार को कुछ विशेष शनितयाँ प्राप्त हैं, जिसके कारण यह कहा जाता है कि मारत के सिवधान का ढाँचा संचारमक है, विन्तु धारमा एकात्मक है। भारत के राजनी-क साजवान का उस राजा करा है। तिक इतिहास को सविधान निर्माताको के धपनी दृष्टि मे रखते हुए और इतिहास द्वारा यह सबक सीसत हुए कि जब कभी भी मारत में केन्द्रीय सरकार निर्धेल रही मारतीय सरक्षा एव एकता को भाषात पहुँचा सविधान के बन्तगंत सधीय व्यवस्था के लिए प्रावधान करते हुए इस बात पर बल दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार को हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ देना आवश्यक या । साघारणतया यह देखा गया है नि ससार ने मुख्य सध राज्यों म निसी न निसी तरीके द्वारा समीय सरकार ने राज्यों की शरकारों की अपेक्षा स्वय की शक्तिशाली बनाने में प्रत्यधिक सफलता प्राप्त की है। प्रमरीका का उदाहरण इस सदमें में उचित है। मूलमूत रूप से सविधान के धनुसार धमरीनी सथ सरकार को केयल १८ शक्तियाँ और ग्रन्य समस्त शक्तियाँ राज्यों की सरकारों को प्रदान की गई है परन्तु यह सर्वे विदित है कि बाधितक सुग मे ब्रमरीकी सध सरकार ने ब्रपने व्यवस्था-पन क्षेत्राधिकार में संविक वृद्धि करने में सफ्तता प्राप्त की है। इस दिशा म अपने प्रयत्नो मे नाग्रेस (सधीय व्यवस्थापिका) को श्रमरीकी सर्वोध्च न्यायालय से महत्वपूर्ण सहायता मिली है ! सक्षेप में सर्वोच्च न्यायालय ने धमरीना म निहित शक्तियों के सिद्धान्त ना प्रतिपादन नरते हुए, यह निर्णय दिया कि नाग्रेस नो १८ मूल शक्तियो

ने अन्तर्गत सविधान ने अनुन्त बुख निहित शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो सविधान ने दायरे में हैं। वाग्रेस नो इन शक्तियाँ ने आधार पर विधि निर्माण नरने ना पूर्ण अधिकार होगा। पलस्वरूप आज समरीनी वाग्रेस ना विधि-निर्माण नरने के क्षेत्र म सिन्धान हारा, १= मूल शक्तियों ने निर्मारित क्षेत्र में अत्विधन वृद्धि हो गई है। इसी तरह, आधुनिन समय में सप राज्यों म नेन्द्रीय सरनार नो शक्तियों जो, जननवाण, मुख्ता आदि महत्वपूर्ण मामला ने वृद्धिना से, अधिन वृद्धि हुई है। "सारे सप राज्यों ने प्राप्त सुधान का सिन्धों ने अन्तर्भाण, स्वाप्त अधिन वृद्धि हुई है। "सारे सप राज्यों ने प्राधन वृद्धि हुई है। "सारे सप राज्यों ने प्राधनिन सविधानों से नेन्द्रीयन रण वी प्रवृत्ति पाई आती है।"

सविवान निर्माताको पर मारतीय इतिहास ना प्रभाव वेन्द्रीय सरनार नो शिवत्याली बनाने ने पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णयामन तत्व या, नयोनि मारतीयों ने लिए इतिहास से जो प्रवन्त महत्वपूर्ण निर्णयामन तत्व या, नयोनि मारतीयों ने लिए इतिहास से जो प्रवन्त महत्वपूर्ण निर्माण प्रवह्म प्रवृत्ता प्रवृत्ति के ति प्रविचन रो साई में घने ला। मुम्मित्र विघटनानरी प्रवृत्तिकों, उदाहरण के लिए—साम्प्रदाविनता, जातिवाद, प्रान्तीयता, भाषाबाद, ने न ने क्ल विटिस राज के समय मारत की एनता नो नष्ट विचा सरन प्राज भी इन तत्वों ने प्रवन्त स्वाच सरना उत्त्व चे त्राव से स्वाच हित यदि इनको सरकार विधेषण स्वाच सरनार नुलवने में हिविच सहाह स्वाची है ति यत्व वेश में स्वतन हो से एनता ने लिए पातन सिद्ध हो सनते हैं। केन्द्रीय सरकार को शिवताली राज ने क्ल में भी ने एनर मुझी ने तिवाम समा भ एक ऐतिहासिन तथ्य पर प्रवाच डातते समय वहा था .—"मारत के लिए वेयल वे हो गौरवपूर्ण दिन ये जब कि देश में एक शिवताली से नेद्रीय सरनार स्वापित इत्त्व ये थी प्रवाधिक इत्त्वय दिन वे थे, जब देश में एक वेन्द्रीय सरनार प्रान्ती के विरोव ने कारण नष्ट हो जाती थी। !"

भारत के सविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित तत्वों ने एकात्मक प्रवृत्तियों को, ग्रीर उनके फलस्वरूप एक अक्तिशाली केन्द्र को जन्म दिया है।

१. एन० पामर—पूर्वोक्त पृ० ६५ ।

२ के॰ एम॰ मुशी-कान्स्टीट्युशन ग्रसेम्बली डिवेट्स भाग द पृ० ६२७ । ३. डा॰ प्रम्वेदकर-कान्स्टीट्युशन ग्रसेम्बली डिवेट्स भाग १ प्० ६६ ।

⁹

भारतीय शासन धौर राजनीति

सर्वप्रयम-संघ एव राज्यो ने मध्य शक्तियो का बेंटवारा इस तरह किया गया है कि संघ सरकार को राज्य सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई है।

निम्नलिखित-विश्लेषण से यह भौर भ्रधिक स्पष्ट हो जायेगा ।

(क) सविधान के २४३ से २६४ तक के अनुच्छेदो में और सातवी अनुसूची में, सघ एव राज्यों के मध्य में शक्तियों का विभाजन तीन मुचियों द्वारा क्या गया है। (१) सम सूची-जिसके अनुसार सच नो ६७ विषया के चिश्रकार दिये

गये हैं।

£۶

(२) राज्यसूची--जिसके अनुसार राज्या को ६६ विषयो के अधिकार दिये गमें हैं।

(३) समवर्ती मुची—जिसके बनुसार सम व राज्यो, दोनो को ४७ विषयों के समवर्ती अधिकार दिये गये हैं। अनुच्छेद २५४ के अनुसार यदि किसी राज्य विधान समा द्वारा निमित कानून का कोई माग सब ससद द्वारा निमित कानून से सवर्ष मे है, राज्य विधान समा द्वारा उनत निर्मित नानून को उस हद तक धर्वेध माना जायेगा, जिस हद तक वह संघीय कानून से संघर्ष में हैं। सक्षेप में, संघ सरकार के प्रियतार समवर्ती सूची के सबध में, राज्यों की सरकारों के प्रपेक्षा सार्वभीम हैं. इससे यह भी तात्पर्य है कि जब सब ससद हु + ४७ = १४४ विषयो पर सार्वभीम रूप से बातून निर्माण कर सकती है, राज्य सरकारों का क्षेत्राधिकार स्वतंत्रतापूर्वक केवल राज्य सूची में उल्लिखित, ६६ विषयो तक ही उपयोग में लाये जा सकते हैं। राज्य सरकारों के अधिकार समवर्ती सुची म उल्लिखित ४७ विषयों पर इस बात पर निमंद रहेगे कि इनका सवर्ष संघीय कान्तों से नहीं होना चाहिये। इसके धति-रिक्न, मनशिष्ट शक्तियो पर, मनुन्देद २४६ (१) के अनुसार केवल सथ सरकार को हो कानन बनाने का मधिकार है।

(स) सघवाद की कसौटी मुश्यत केन्द्र एवं राज्यों में शक्ति विभाजन के सिद्धान्त को लाग करना है। जहाँ सथ एव राज्यों की सरकारों में शक्तियों का विमाजन स्वय निलित सविजान द्वारा नर दिया ग्या है, राज्यों को उनके क्षेत्र में कानन निर्माण करने की पूर्ण स्वतवता होती है और साधारणतया राज्यों के क्षेत्र में संघ सरेकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। परन्तु मारतीय सविधान के धन्तर्गत प्रक्रित विमाजन सिद्धान्त के सदमें से ही कतिएय परिस्थितयों के तिए विशेष रूप से प्रावधान वियं गये हैं, जो शक्ति विमाजन सिद्धान्त के प्रप्वाद माने जा सकते हैं. ग्रीर जिनके मनुसार सथ सरकार को राज्यों के क्षेत्राधिकार (राज्य सूची) में हस्त-क्षेप करता वैच है। यह भपवाद निम्नानुसार है।

(१) अनुच्देद २४६ के अनुसार यदि राज्य सभा के दो-तिहाई वहमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाये कि राज्य सूची मे धक्ति किसी विषय का राष्ट्रीय महत्व हो गया है तो सम ससद को उक्त विषय पर वानून निर्माण करने का भ्रियिकार प्राप्त हो जायेगा ! इस प्रकार के प्रस्ताव की भ्रविष एक वप से भ्रियिक नहीं होगी परनुराज्य समाद्वारा प्रस्ताव पारित करके प्रस्ताव की भ्रविष में एक वप के लिए ग्रीर बृद्धि की जासकती है।

(२) अनुच्छेद २४० (१) के अनुसार सप ससद वो जब देग म सक्टवालीन स्थिति वी घोषणा राष्ट्रपति वे द्वारा की गई है, सम्पूण देश वे तिए वानृत निर्माण करने का प्रधिवार प्राप्त है । सपीय ससद तीनो सूचिया म लिखित किसी भी विषय पर कानून वना सकती है । चूनि सकटवालीन स्थिति वे दौरान सपीय ससद को समस्त विषयो पर वानून निर्माण करने के अधिवार प्राप्त होने यह स्पन्ट है कि के द्वीय सरकार का स्वच्य सथात्मक से एकात्मक म परिवर्तित हो जायेगा । राष्ट्रपति द्वारा सिव्यान के अनुच्छेद ३४२ वे अत्याव सक्टकालीन विश्वति वे घोषणा द्वारा सम सबद राज्यो के लिए अनच्छेट २४० वे अनुसार विन्नृत अवित्यो से उपयोग म ता सकती हैं जिसके परिणाम स्वच्य वे द्वीय सरकार वा स्वच्य समीय सरकार से एकात्मक सरकार मे सक्टारालीन घोषणा है कायकार तक परिवर्तित रहेगा क्योंकि ऐसी परिस्थिति म सधीय ससद को सिव्यान म उस्पिति की अवस्थापन सबयो सूचियो (सघ राज्य एव सम्वती) पर वानून वनाने वा अधि अगर रहेगा अनुच्छेद २४२ ३४४ के अनुसार सब गयपालिका को राज्य वी वाय पालिकाक्ष को कोच कायपालिका सबयो बनितयो वो उपयोग म साने क सिए निर्देश दियं जा सकते हैं।

इस तरह सकटकालीन पोपणा के दौरान ससद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है चाहे वह विषय सम-सूची के झतिरिक्त झाय दोनो सूचियो म क्यो न उल्लिखित हो।

(३) सिवधान के अनुच्छेद ३४६ के अन्तमत यदि निसी राज्यपाल द्वारा राज्यपित को यह सूचना दी जाती है कि राज्य ना सवैधानिन यन सिवधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है राज्यपित उक्त राज्य में सकटकालीन घोषणा द्वारा राज्यपित का शासन लागू कर सकता है। ऐसी परिस्थित में राज्यपित के सकटनालीन घोषणा के दुलामी कानूनी प्रभाव होने क्योंकि सध ने द्वारा राज्य की समस्त कायपालिका सर्वधित शक्ति के अध्यान जा सकता है मौर यह घोषणा की जा सकती है कि राज्य की विधान समा की शक्तियाँ ससद द्वारा या ससद के अधीनस्य उपयोग में लाई जा सकती है। " भै

१ सी॰ एल्केजे डरोविकज-कान्सटीट्युशन डवलमे ट इन इण्डिया, १९५७, पृ॰ ६२।

१६५० स सविद्यान के लागू होने के पश्चात् समय-समय पर भारत के नई राज्यों में राष्ट्रपति शानन अनुच्छेद रेश्ड् के अन्तर्गत लागू किया जा चुका है परनु बुछ राज्यों में राष्ट्रपति भासन की तीत्र ब्रालीचना की गई है। राष्ट्रपति भागत लागू करने के ग्रीचित्य का प्रश्न विशेषकर उस परिन्थित में उत्पन्न हाना है जर बह एवं ऐम राज्य में स्थापित दिया गया है जहाँ सत्तारूड दल केन्द्रीय सत्तारह दल से मित है। प्राय. ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन की आलोचना का कारण यह होता है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को गिराने क लिए ही राष्ट्रपति शामन लागू किया है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की स्थिति तद ही पैदा हो सबनी है, जब बेन्द्रीय सरकार खीर राज्य सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के नियन्त्रण में हो । ग्रालीचकों का यह तर्क है कि सर्विधान के ग्रनुच्छेद १५५ एव १५६ के अन्तर्गत राज्यपालों की नियक्ति राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के सलाहानुमार करता है धौर धनुच्छेद ३५६ के ब्रन्तर्गत यदि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह मुचना दो गई है, कि राज्य की शासन व्यवस्था भग हो चुनी है भीर इसको सवियान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति उस राज्य में सबटकालीन स्थिति की घोषणा कर राष्ट्रपति शासन स्थापित कर सकता है श्रीर चुनि राज्यपाल प्राय नेन्द्रीय सत्ताहर दल से संबंधित रहे हैं, राष्ट्रपति शासन को लागू वरवाने में उन्होंने केन्द्रीय सरकार को घपना सहयोग दिया है। स्त्री तम्बूद्रीपाद ने कहा है कि "वह स्यक्ति जो जीवन पर्यन्त कांग्रेस म रहा है. चाहे क्तिना भी निष्पक्ष होने का प्रयत्न करे परन्तु राज्यपाल करण में उसे राजनीतिक दवाओं को सहन करना ही होगा।"1

१६५७ के आम चुनाव में केरल में, साम्यवादी दल को सबसे अधिक मन प्राप्त हुए । बुछ निर्देशीय सदस्यों के सहयोग से विवान सभा म बहुतम प्राप्त कर साम्यवादी दल ने केरल सरकार की स्थापना की। जब काग्रेस की साम्यवादी सरकार को गिराने में रू⊏ महोन तक सफलता नहीं मिली, तब उसन केरल की साम्यवादी सरकार को गिराने के उद्देश्य से प्रेरित होकर प्रत्यक्ष कार्यवाही को उपयोग में लान का निन्चय किया। इस प्रत्यक्ष कार्यवाही से काग्रेस का ताल्पर्य राज्य के विद्यालया, यात्री-परिवाहना एवं दश्तरों का घराव करना था। ग्रगस्त ६१,६५६ वो वेरल की सरकार के विरोधी दलों ने काग्रेस के नतृत्व म सरकार ने विरद्ध प्रान्दालन को धौर प्रविच उप बनाने का निर्णय लिया। राज्य के गवर्नर डॉ॰ रामकृष्ण रामाराव ने ग्रान्तरिक ग्रमान्ति होने की समावना का देखते हुए। राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन भेजा कि राज्य में धान्दोतन की स्थिति इस

^{1.} ई॰ एम॰ एम॰ नम्बूडीपाद-हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, ग्रगस्त २२, lexe i

स्थिति तक पहुँच चुकी थी कि राज्य मंशासन एवं सरकार का मुताब्द रूप में चलाना सन्तर नहीं है।

डम दृष्टिकोन मे यहाँ यह देवता धारस्या है कि कित परिस्तितिया में राग्य के क्षेत्र में संवीयहरूपक्षेत उचित माना जा सकता है। गरियान के प्रत्यान, राग्यों के क्षेत्रा में संवीय हरूपक्षेत्र केयत निम्नतिय्तित दो परिस्थितिया में हो उचित्र माना जा सकता है।

(1) अनुच्छेद 392 ने अनुसार जब राष्ट्र में गमीर मनट पैदा हो जाये, जिममें राष्ट्र की मुख्ता पर आधान पहुँचने का कर रहना है तो राष्ट्र की मुख्ता के दृष्टिनोज से देन में मनटवालीन विवित्त की खर्बा है आपन्ताली मोगा की जा सनों है। मित्रवान के सन्तान राष्ट्रीय जीवन में यह मोगेर मरटवालीन स्थित जब हो मानी जा मनती है, जब देन पर बाह्य आप्रमान हुआ हो या आगिरिष्ट समानित पैदा हो मंदी है या यदि राष्ट्रपति के मनानुसार ऐसी स्थित के पैदा हान की ममानना है ता भी राष्ट्रपति मनटवालीन स्थित की उद्गीपणा कर सक्ता है।

उपर्युत्त स्थिति में मेव सरकार का हम्मक्षेप राज्यों के क्षेत्र में बैब माना जा सरता है।

(n) सन के निर्मी राज्य में सतीय हम्मजैन अनुष्ठेद ३४६ के अरार्गन सभी उपकुत तथा येन माना जा मकता है जब राज्य का सर्वमानिक जामन-गत्र ममान्त हो चुना है। राज्य सरकार के आमन-गत्र के ममान्त होने में यह साम्यमें है कि राज्य मरकार का राज्य की निज्ञान समा में ममान्त हा चुना है और राज्य मरकार का बहुमा उस राज्य के निज्ञान समा में ममान्त हा चुना है और राज्य मरकार का में सहुद्ध है कि अन्य निश्ची राजनीतिन दन या दनी झरार जिज्ञान प्रमा में बहुमन पर आचारित सरकार नहीं बनाई जा सकती है। इसमें यह भी साम्यमें है कि यदि राज्य की सरकार ने कियान ममा में बहुमन आगते हैं परन्तु हुए राजनीतिक दन निजी राज्यों के सुष्टु कर राजनीतिक दन निजी राज्यों के सुष्टु कर राजनीतिक राज्य के स्वतान समान्त करते हैं, तो मज्जित के अनुकेद ३४४ ४ अनुवार मन जानन का यह

करों ब्या है कि राज्य सरकार की सुरक्षा करें, जो बहुमत पर प्राथारित है थीर विसकी स्थापता सर्वेषानिक रूप से हुई है। सक्षेप में, सम सरकार का यह कर्तव्य है कि प्रमुच्छेद २४५ के प्रतुसार प्रयोक राज्य सरकार का जो बहुमत पर प्राथारित है, बाह्य प्राक्रमण एव प्रामारिक काशिन से रह्मा करें, न कि ऐसी राज्य सरकार की राज्यपित ज्ञानन के साध्यम से वर्षास्त करें।

बस्तुत उपर्युक्त विषेषन से यह विदित होता है कि राज्यों के क्षेत्रों में राष्ट्र-पति-भागत स्थापित करते के लिए के क्षेत्र इस्तर्काष केवल दो ही परिस्थितिया में उचित माना जा सनवा है। इस पृथ्विकास स यह कहने में कोई सरिक्योंनित नहीं होंगी कि १६४६ में जब राज्यपाल रामकृष्ण रामगाव में केव्ल के सबय में राष्ट्र-पति को यह प्रदिवेदन मेजा कि राज्य सरकार का शासन तन दूट चुका है तो बह कैव्ल की यास्त्रीक सर्वेद्यानिक स्थिति के धनुकूष नहीं था क्योंकि मुख्यमत्री गान्ध्रदीयाद की सरकार को बर्धारित किये जाने के समय तक राज्य दियान समा में स्थाद बक्तन प्राप्त था।

प्रत्येक राज्यपाल को पद प्रहण करने के समय यह घपय दी जाती है कि 'में धपनी पूरी पांपता से सविधान एव वानून के प्रसित्तल को बनाये रजूना एव उनका सरक्षण करूँमा '

इसी प्रकार की शाया राष्ट्रपति को भी पर शहण करने के पूर्व लेना धावश्यक है। भत यह स्पष्ट है कि राज्यपाल एव राष्ट्रपति दोनों का भी नम्बूडीमाद के मत्रीनण्यल की रक्षा करना सर्वमानिक कर्तव्य था। नि सरेह यह कहा जा सकता है कि भी नम्बूडीमाद के मश्रीनण्यल ने सर्वभानिक कारणों के वजाय राजनीतिक कारणों के वजाय राजनीतिक कारणों के वजाय राजनीतिक कारणों के वजाय राजनीतिक

सारत में किसी भी राज्य में, राष्ट्रपति धासन पीदित करने ने लिए राज्य-पात की मुमिका का प्रत्यक्ति महत्त्व है। राज्यकाल नी निमुक्ति राष्ट्रपति करता है, धत दस कर ते बनना किन होगा कि राज्यकाल रुप केश्मी सरकार का प्रमाव नहीं होगा । स्वस्य जनमत तथा जनतव के लिए यह धरवावस्थन है कि राज्यकाल की गरिक्या पर इस सक्त्रमं मुद्ध वैद्यानिक ध्वस्योव हो। बातत्व मा, यह वर्षयोगिक सवरोग ने एक परमाया के रूप में मानवान प्राप्त हुई है, जिसका निरुवार पातन करना धावस्यन है। परम्परा यह है कि राज्यकाल की निमुक्ति राज्यकी सरकार, जिसको पात्र्य विधान सभा में बहुमत है, भी सलाहानुसार किया जाय।

४—समवाद ने सिद्धान्त ना एवं प्रमुबाद और सिद्धमान के अनुच्छेद २५२ (१) में उत्तिखित है, जिसने अर्जुन्तर यदि सम के दो या दो से अधिन राज्यों की विपान समाप्रों के तिए यह वाद्यनीय प्रतीत होता है कि ऐसे विपयों पर जिन पर सिवाय अनुन्छेद २४६ एव २५० के अन्तर्गत सथ ससद को कानून निर्माण करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार उत्तर राज्यों ने सबंद में सथ सवद को प्रदर्श किया जाये और यदि इस उद्देश के लिए उक्त राज्यों को विधान समामों में प्रस्ताद गारित किये जाते हैं, तो सथ-ससद को ऐसे विषयों के सबय में कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होगा। सरस रूप में यह नहां जा सकता है कि अनुन्छेद २४२ (१) के अन्तर्गत दो या दो से अधिक राज्यों की विधान समामों द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि राज्य सूची में उत्तिविद्य विश्वय पर सप-ससद उन राज्यों के लिए कानून निर्माण करे तो सथ ससद राज्य सूची ने उक्त विषय पर कानून वना सकेगी।

५—प्रप्रत्यक्ष रूप से प्रमुच्छेद २५३ वे प्रन्तगंत सघवाद का एव प्रत्य प्रपवाद देखा जा सकता है। उक्त प्रमुच्छेद के प्रत्यमंत सघ सरकार को किसी देश के साथ की गयी सिंग, समभिते या उपसिष भीर किसी प्रन्तरांद्रीय समा, सस्या या प्रत्य सगठत द्वारा लिये गये निर्णय को कार्याम्वत कराने वे लिए कानून निर्णय को कार्याम्वत कराने वे लिए कानून निर्णय करा का प्रिकार है। इस प्रमुच्छेद २५३ मे उपयोग से लाये गये स्वयं प्रत्य सगठत प्रत्या है और इस स्पट्टा के कारण इनकी व्यास्था एव उपयोग सेय सरकार द्वारा किसी सीमित भीर राष्ट्रविरोधी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। डाठ जैनिष्य का कहना है कि "बन्तमंहाविद्यालयीन मण्डल, जो एव ऐसा धन्तरांद्रीय सगठत है, जिसमे वर्गा तथा तथा का कहानी हो कि "बन्तमंहाविद्यालयी के प्रतिनिध् हैं, के निर्णय के सरस माध्यम इता महाविद्यालयीन सिक्षा पर सप सरकार प्रयना क्षेत्राधिकार स्थापित कर सकती है। 'कामिनकार्म एव फोर्म एटरनेशनल' मी प्रस्तरांद्रीय सगठत हैं। इस प्रमुच्छेद मे कतिप्रय घट्टो के रखे जाने से यह राज्यों के प्रधिकारों का, चौकानेवाला प्रतिक्रमण है कि इसकी उपयुत्तता सदेह्रमद सगती है। '"।

६—अनुच्छेद २४६ के अनुसार सब सरकार को राज्यों के सबब में कुछ प्रशासकीय शक्तियाँ मी प्रदक्त की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार सब सरकार राज्यों पर प्रपना नियन्त्रण रखती है।

इस अनुन्देद के अनुसार राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग इस तरह से क्या जाना चाहित कि सम समद के नानूनों को माय्यता मिस सके और सम की नार्यग्राजिका कार्कियों का ज्यायों कर दूर्णिकांग है, राज्यों को निर्देशन देने के लिए किया जा सकता है। अनुन्देद २५७ के अनुसार सम के किसी भी राज्य की कार्यगालिका शक्ति का उपयोग इस तरह से करना चाहिये कि जिससे

१. घाई० जीनग्ज-'सम केरेक्टरस्टिक्स झाफ दी कान्स्टीट्युशन झाफ इण्डिया, १९५२ गु० ६६ ।

(11) उन सिद्धान्तो का निर्धारण करने के सम्बन्ध में, जिनके प्राचार पर सप सरकार राज्यों को प्रमुदान देगी।

(m) सथ तथा विसी राज्य वे मध्य विसे गम विसी विसीम सममीते वो

कायम रसने या उसमे परिवर्तन करने के सम्बन्ध म । (भ्र) राष्ट्रपृति द्वारा प्रेषित कोई भी विषय जो विक्त की दृष्टि से महस्व-पुर्ण है।

पूष हैं।

(ग) अनुच्छेद २६० वे अनुसार राष्ट्रपति नो बित्त सत्रयो सनटनाशीन स्थिति वे तिए द्वुछ विशेष वावित्रयो प्रदत्त वी गई हैं। यदि राष्ट्रपति प्राश्वस्त हो जाता है कि राष्ट्र में परिस्थिति इस प्रनार की हो गई है वि तिससे सारत या मारत थे निसी हिससे की वितीय व्यवस्था पर हानिकारक प्रमाव पहुँचा है, वह सारत म वितीय सत्र यो भोषणा वर सकता है। इस प्रवार की सन्दन्तातीन स्थित में साम की नार्यपातिका किला गा उपयोग राज्यों की वितीय व्यवस्था को सुदृश्व सनान के तिस्था वित्तेय व्यवस्था को सुदृश्व सनान के तिस्था के तिन तथा मत्तों में कमी की सामती है। राष्ट्रपति राज्यों को वर्म-वारियों के वेतन तथा मत्तों में कमी जा सनती है। राष्ट्रपति राज्यों को यह निर्वेशन सो से सनता है कि राज्य विधान समाप्त में परित दिन वियय कमने राष्ट्रपति) विवार के तिए मेंने जायें। वित्तीय सनटनालीन परिस्थिति के सत्य में भी हरवाय विद्या हो वित्तीय सनट सम्बी प्रावधान से राज्यों की स्वासत्ता नो एव गमीर खतरा है।

तृतीय-राज्या वी स्वायत्तना वी एक धन्य कारण से भी हानि पहुँचने की समावता है। राष्ट्रीय योजना भाषोग की कार्यप्रणाली के दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है वि इससे भी भारत में केन्द्रीयकरण की भावना तथा एकात्मक प्रवृत्तियो को प्रतिकाली होने में सहयोग मिला है। राष्ट्रीय योजना स्रायोग की स्यापना १६५० मे हुई, जिसेका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय साधनो का सतुलित उप-योग करते हुए राष्ट्र का विकास करना है। राष्ट्रीय योजना ध्रायोग की सूमिका जो सामने उमर वर शाई है उसका वर्णन श्री सन्यानम ने निम्नलियित शब्दों मे किया है, श्रीर जिससे यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है कि राज्यों की किस हद तन नेन्द्रीय सरकार पर भपनी विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए निर्भर रहना पडना है। उनना वहना है—"बुछ समय पूर्व राज्य समा मे एक वेन्द्रीय मनी के इस वननव्य को सुनकर में ब्राह्चये-चित्र हो गया कि यदि राष्ट्रीय योजना श्रायोग विसी योजना को स्वीवृत कर लेता है तो वह भी उक्त योजना को स्वीवृत कर लगा थोजना मायोग का सविधान में उल्लेख नहीं है और न ही इसकी स्या-पना निसी ससदीय नानून से हुई है। तब भी इसे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सारी योजनाधो को प्रारम्भ करने के लिए, निर्णय देने की प्राप्ति है। योजनाधो को वित्तीय अनुदान देने या न देने से कार्यान्वित किया या नहीं किया जा सकता है। नि सदेह, राज्य सरकार विसी भी योजना को वगैर योजना घायोग के प्रेषित क्रिये, धाररम वर सकती है, यदि वह वेन्द्रीय सहायना केन प्राप्त होने के, न वेक्त उसी योजना ने लिए, परन्तु प्रथ्य योजनाओं के लिए भी, परिचामी का साम्ता करों योजना के हैं।"

चतुर्व-सिवयान के बन्तर्गत कुछ श्रतिरिक्त तत्व विद्यमान हैं, जिनसे नारतीय सभीय व्यवस्था में एकारमक प्रवृत्तियों के दृढ होने में सहायता पहुँचती है ।

उराहरण स्वरूप (क) भारत में श्रांवित नारतीय सेवाधी के श्रांमशीयों भी नियुन्तियों संघीय तीन सेवा धायोग के मुनावानुमार, गृहमवातम को करने का श्रीपतर है। इत श्रीवशीयों की नियुन्ति, श्रीवित सारवीय ततर पर होती है। इन विशेषणा के सारवा संपूर्ण भारत में, प्रशासन के क्षेत्र में समानना स्वाय क्रांस पाई जाती है, जिनके पन्तवरूप केन्द्रीय सामन की इट्टा सान होती है।

(व) मारतीय न्यायरातिका का सगठन एव कार्यों वा निर्योत्तर सविधान के धन्तर्गत एव किशोपात्मक सायरर यर दिवार मधा है, दिवहें धामार यर इस दिक्षेण के सित्तर पर प्राराण सर्वेच्च न्यायात्मय को सविधान के धनुष्येद १२४ के धनुष्यात निर्याण के धनुष्येद १२४ के धनुष्यात पर पर परिचान के धनुष्येद १३४ के धनुष्यात उच्च न्यायात्मय की प्राराण के धनुष्येद १३४ के धनुष्यात उच्च न्यायात्मय की प्राराण के धनुष्येद १३४ के धनुष्यात के धनुष्येद १३४ के धनुष्येद १४४ के धनुष्येद १४ के धनुष्येद १

निर्णेय से सबैपानिक दिवानी तथा फीनदारी मामलो में ब्रांपील की जा सकती है। बन्नी यह स्वष्ट है कि भारतीय व्यायपातिका के समुद्रन तथा कार्यों के दास्ट-

कोण से, न्याधिक क्षेत्र में एक रूपना स्थापित की गई है।

(क) आरक्त के सबिवाज में कैवन एक नागरिक्ता (आरमीय नागरिक्ता) का प्रावधान दिया गया है। निस्तरेह हुस प्रावधान का उद्देश आरक्त की स्थासक व्यासि में, मनौर्वतानिक दृष्टिकों से सम्पूर्ण मारक के प्रीत नागरिकों की प्रास्था को सिक्ताओं करात हुए एका गय प्रवृत्ति के स्थायों को मिक्ताओं करात हुए एका गय प्रवृत्ति के स्थायों को मिक्ताओं करात हुए एका गय प्रवृत्ति के स्थायों को मिक्ताओं करात हुए एका गय प्रवृत्ति के स्थायों के मिक्ताओं करात है। एक स्था की नाग-रिक्ता प्रवृत्ति है। एक स्था की नागरिक्ता जहाँ पर व्यक्ति निवास करता है।

उप्युक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट हाता है कि जारतीय सप ध्यवस्या में पुतासक प्रवृत्तियों स पन्न मिलागानी हैं, परन्तु इमने यह नित्तर्थ निवासना कि इन एवारासक प्रवृत्तियां द्वारा भारतीय श्रम स्वयस्या का सधीय स्वरूप सुन्त हो गया है, जबत होगा। वास्त्रक म मारदीय सविधान के मन्त्रर्थेत एक मध राज्य की स्थापना की भई है, निश्चन मर्पेयू सरकार महत्त्वात्र मिलागानी है

१. के० सन्यानमे-्द्रान्बीशन दल इण्डिया, १६६४ यून २० ।

संघीय कार्यपालिका

पूर्व प्रध्यायों के प्रध्यायन से यह जात हो चुना है नि मारत वे सविधान वे प्रमुच्छेद १३ (१), ७४ (१) तथा ७४ (३) मारतीय समयीय प्रणाखी ने मूल प्राचार है। राष्ट्रीय प्रान्दोलन ने समय मारतीय नेतायों ना उदेश दिश्य राज्य समयोत प्रधावत प्राप्तकर मारत में समय मारतीय नेतायों ना उदेश दिश्य राज्य समय में इस विषय पर १६५७ में प० नेहरू न कहा था— "हुमने इस ससदासम प्रणाली को कोच क्षममन्तर चुना है। हमने यह प्रणाली केचल इस लिए नहीं चुनी है कि पूर्व महम प्राय इस विषय पर विचार नरते रहे, परन्तु हमने यह सोचा कि यह हमारी प्राचीन परम्परायों के मतुकूल हैं । हमने इस चुना—जहाँ पर हमें श्रेय देश है, हम देना चाहिये—वयीं हम इसने कार्य प्रणाली से, जैसी इसरे देशों में, विकेशकर हिटेन में हैं, सहस्त थे।" "

इसी वे फलस्वरूप, मारत की समदीय प्रणाली म सपीय नामंपालिना के दो माग हैं। (क) मारत का राष्ट्रपति-राष्ट्राध्यक्ष, धौर (क) सपीय मशी परिपद — एक उत्तरदायों मशी मण्डल ने रूप में, जिसना सामृहिन उत्तरदायित्व प्रणती नेतियों तथा नावों ने लिए सतद के निलं सदन के प्रति है। मारत में कार्य-पालिना की सिंत पर सबसे महत्वपूर्ण प्रवरोग मारतीय ससदीय प्रणाली के अत्वर्गक मंत्री मारत के सामृहिन उत्तरदायित्व ना सिद्धान्त है। इस प्रवरोग की विशेषक प्रमित्यक्षित नार्यपालिका एव व्यवस्थापित। (सतद) के सम्बन्धों में प्रदा्धा के प्रमान म रपना प्रति प्रावश्यक है कि साम्यक की प्रावश्यक है कि साम्यक है कि

सधीय कार्यपालिका का प्रध्ययन निम्नलिखित तीन प्राधारो पर किया जा सकता है।

१. प० मेहर-जवाहरताल नेहर च स्पीचेज खड ३. प्रगस्त १६५७, पवलिकेशन्स डिविचन मिनिस्ट्री झाफ इन्फारमेशन एड बाडकास्टींग ।

१--राष्ट्रपति एव मनी परिपद की स्थिति तथा सम्बन्ध । २--सधीय कार्यपालिका (राष्ट्रपति तथा मत्री भण्डल) की शक्तियाँ।

३-मित्रयो के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त ।

मारतीय सर्विधान के अनुच्छेद ५२ के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का पद स्थापित किया गया है और अनुच्छेद ५४ के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होगा, जिसमे दो प्रकार के सदस्य होते हैं, (क) सच के विमिन्न राज्यों के विधान समाम्रों के निर्वाचित सदस्य, भीर (ख) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ! इस निर्वाचक मण्डल के सदस्यों की समान सस्या मे मत प्राप्त नहीं हैं । यहाँ महदान का सिद्धान्त 'एक व्यक्ति एक भव' ना नहीं है, परन्तु यह है कि प्रत्येक मतदाता को उस धनुपात में मत प्राप्त हो, जिसमे कि वह एक विशिष्ट जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।

चुंकि राष्ट्रपति के दिवांचक मण्डल के दो प्रकार के सदस्य हैं बात. राष्ट्रपति वे निर्वाचन के लिये इन दोनो प्रकार के सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने मत प्राप्त हैं, यह जात करने के लिए निम्नलिखित दो सुत्रों की, सविधान के धारतगत मान्यता दी गई है।

(क) राज्य विधान समा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतो की सख्या =

राज्य की जनसंख्या राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों रे०००

की सम्पर्ण संख्या (स) ससद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतो की सख्या ==

समस्त राज्य विधान समाधी के निर्वाचित सदस्यों को प्रदत्त मतों की सख्या

ससद के सारे निर्वाचित सदस्यों की महता

राष्ट्रपति का निर्वाचन, असा सविधान मे उल्लिखित है, अनुपातिक प्रति-निधित्व पद्धति ने एकल सहमणीय मत प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है 13

राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी नतीजों को मालम करने के लिए निस्नलिखित बावश्यक्ताएँ हैं। सबंप्रयम, सही मतों को प्रयम विकल्पों के बाधार पर बलग-मलग करना भौर प्रत्येक प्रत्याची ने प्रयम वरीयता (विकल्प) के मती की

गणना क्यना ।

१. भारतीय सविधान धनुब्छेद ४४ ।

२ भारतीय सर्विद्यान—प्रातुच्छेद ७१-७३ ।

द्वितीय, यह निर्वास्ति वरना वि निर्वाचित होने वी स्यूनतम मन सस्या वया है ? इत स्यूनतम मत सम्या वो निम्नितिस्ति सूत्र के प्रापार पर निर्यास्ति किया जा सक्ता है। उदाहरणायं जहाँ यदि सही मतो वी सस्या २०,००० है तो निर्वाचन वे लिए वोटा २०,००० २ १ वे वराप्तर होगा। इसा प्रयं यह है कि विसी मी प्रत्याची वो १०००१ मता वे प्रास्त होने पर निर्वाचित घोषित

यह बिदित रहे नि पदि नेवल दो प्रत्याची राष्ट्रपति पद ने लिये हैं तो उवर्युक सूत्रानुसार, दोनों में से सिंबी एन को न्यूनतम मत सब्या में रूप में यहुमन प्राप्त हों सबता है। परन्तु यदि प्रत्याधियों ने सदया दो से प्रयिष है तो यह समय हो सकता है नि उनेसे से दिसों को न्यूनतम नोटा न प्राप्त हो। उदाहरणार्थ, यदि चार प्रत्याची हैं, मनो ना विमाजन निम्नलिधित रूप से हो सबता हैं

यहाँ पर निसी मी प्रश्वाची को न्यूनतम मत सत्या या १०,००१ मन प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में जिस प्रत्यामी को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, उसके मत जन पर उस्तिलित इसरी बरीयता के धाधार पर शेप प्रत्याभियो को हस्तावरित किये जायेंगे।

यदि मान लिया जाये कि दूसरी वरीयता के श्राधार पर यदि श्र को ३००, ब-को २,६०० श्रौर स-को १०० मत, द-को ३,००० मतो मे से दूसरी वरीयता के श्रनुसार दिये गये हैं तो निम्नलिखित स्थित हो जायेगी —

परन्तु घव भी निसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुधा है, इसलिए पुन स के मत, क्योंकि इसकी सबसे कम मत प्राप्त हुए है, प्रमसी बरीयता के प्रनुसार, जेप प्रत्याधियों को हस्तावरित कर दिये जायेंगे। यदि स के ३,७०० यती में से २,४०० म- की, फ्रीर १,३०० य- की प्रमाली वरीयता के प्रतुसार हस्तांतरित कर दिये जाते है तो स्थिति निम्मलिखित होंगी —

स- हस्तातरित द- हस्तातरित यहाँ व को स्पष्ट रूप से, निर्वाचन कोटा (१०,००१) से प्रचिक्त मन प्राप्त होने से उसका निर्वाचित घोषिन कर दिना जायेगा, क्योंकि अ-को उक्त कोटे से कम मन प्राप्त हुए हैं।

डा॰ एम॰ पी॰ शर्मा ने इस निर्वाचन पढ़िन की दो किंटिनाइबो पर प्रकाश डाला है । $^{\circ}$

सबंद्रयम, पराबिन प्रश्नाती को ट्वांन की प्रतिया में बनी ऐमा होता सबत वह वह बन मन पराद किये दी प्रत्याधी ऐसे हो, जिनके मदो की सहया मनात हो। ऐसी स्थिति च इत दोनों में से उस प्रत्याधी को पराजित पोरिय क्या जायगा, जिले प्रयम वरीयना में सबसे कम मन मिलें हों। यदि इत दोनों प्रयाशिया को प्रयम वरीयना के मी समान मन मिले हो, तो इसना निर्मय साट (विट) श्रालय निया चायेगा।

डिडीज, यदि कुछ मन पत्रा म डिनीज, कृतीय या ग्रमणी बरीयना का उत्तेष नहीं है, तो एसी स्थिति म मेथ प्रत्यामियों को, महो का हमाननरण प्रसंसव हो जायमा। जिन मन पत्रा पर डिडीज, हृतीय या प्रवती वरीयना का उन्तेष नहीं मिना नया है, उनको समाप्त माना जारेगा।

सिंचान ने सनुष्टेंद्र १० ने अनुमार निसी मी झालि नो राण्ट्रपति ने पद रा दिन्सीलंग उस तह ही विचाननेया बाँद (न) बंद मारत वा नागांति हो, (ख) १५ वर्ष नी उस हो, (भ) यो तोननमा ने दिन सदस्य नियंतित होने भी सोम्बा रमता हो, भीर (भ) यो मारत सरकार या राज्य सरकार या निमी सामित सरिवारी ने स्वीन निसी नैतिन पर पर निकुत न हो। परन्तु नुद पर ऐसे है निन पर पह प्रतिक्त लागू नहीं होना है, जैसे उपराष्ट्रपति, राज्याल, नेन्द्रीय एव राज्य सरकारों के मित्रों ने पर। राण्ट्रपति कुर कर्मोड पास सात, नेन्द्रीय एव राज्य सरकारों के मित्रों ने पर। राण्ट्रपति को नहीं, स्वागनिय सात्रीयकी हारा दिल हा बाता है तो प्रदूषदेंद १५ (२) ने बनुसार ६ महीने से राण्ट्रपति हो राण्ट्रपति न नाम जा करता। राण्ट्रपति के निवारील होने तन उपराष्ट्रपति है राण्ट्रपति न नाम जा करता। राण्ट्रपति को स्वागत है। यह उपराष्ट्रपति स्वागत को उपने भेषन, मारो तथा विगयपिकार के सबन में निर्मेय तेन का प्राप्त-वार है। प्रकाग प्राणि ने प्रयान दुवारी प्रतिकार १५००० र ० नेपन एक देशका पर से ने दूर में प्रवान है। प्रदेश पत्र को एक पत्री को पत्री प्रतिकार है।

१. एम० पी० शर्मा—'व गर्वमेण्ट झाफ द इण्डियन रिपब्लिक्,' १९६१ पृ॰ १०म । २ भारतीय सरिवान—मनुस्देद ४६ (१)

सघीय कार्यपालका

पित को यह गापय प्रहण करना धावश्यन है, "मैं श्रद्धापूर्वक का पालन करूँगा तथा धपनी पूर्ण योग्यता से सविधान तथा एव प्रतिरक्षण करूँगा तथा मैं मारत की जनता की सेवा तथा करूँगा " पहुँगा।"

इस दृष्टियोण से, पिद राष्ट्रपति सविषान या उल्लंपन बरता है तो उस पर महामियोग लगानर उसे पदच्युत विचा जा सबता है। रै सबद वे बिनी भी सदन में महामियोग प्रस्ताय प्रस्तुत विचा जा सबता है। रै सबद वे बिनी भी सदन में महामियोग प्रस्ताय पर उक्त सदन वे बन से बन एवं पोपाई तस्दयों यह हातायर होने चाहित । इस प्रवार के प्रस्ताय को सदस्यों पह स्ताय को सदस्य के प्रस्ताय को सदस्य के प्राचित होने पर महामियाग भी सर्वे पूर्व मिनी बाती है। इस प्रस्ताय के सिंद सितित नोदिस बन से दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो इसवा अर्थ है कि राष्ट्रपति पर अमियोग लगा दिया गया है और हुगरा सदन इन आरोपों भी जाय वरिया। राष्ट्रपति स्वस सदन में उपस्तित हो अता है तो इसवा अर्थ है कि राष्ट्रपति पर अमियोग लगा दिया गया है और हुगरा सदन इन आरोपों भी जाय वरिया। राष्ट्रपति स्वस सदन में उपस्तित को तिहाई बहुमत हारा राष्ट्रपति पर समाये गये प्राचीग सिद्ध हो जाते हैं तो महाभियोग वा प्रस्ताव सिद्ध माना वायेगा, और फलस्वस्प, राष्ट्रपति हसता विच्वत होने यो विवार विच्वत होने साथेगा।

राप्ट्रपति की सबैवानिक स्थिति और मंत्री मण्डल से उसका सब्ध

सभीय वार्यपालिका वी शांतिक्यी भारतीय सविधान के अनुच्छेद १३ (१) के अनुसार एक मनी मण्डल की स्वापना राष्ट्रवित में तिहित है। अनुच्छेद ७४ (१) के अनुसार एक मनी मण्डल की स्वापना राष्ट्रवित को उसने वार्यपालिका संवधी वार्यों में सहायता तथा सलाह देने के लिए की जायेगी। मनी मण्डल का अध्यत प्रथान मनी होता। परतु, भारत में सनदारकार प्रवासी का मूल विद्यानत, सविधान के अनुच्छेद ७५ (३) में निहित है। इस सिद्धान्त के अनुसार भन्नी मण्डल सामूहिक रूप से ससद के निकले सदन, लोकसाम, के प्रति उत्तरदायी है—जो सतद का प्रतिनिध सदन है क्योंक इसका निवधिन सार्वजनिक यसका मताधिकार के सिद्धान के अनुसार होता है। राष्ट्रपति तथा मनी मण्डल के सत्यों वी वस्तु हिन्दी को आत करने के लिया प्रजुच्छेद ७५ (३) में निहित सामूहिक उत्तरदायित के सिद्धान्त की प्रमुख

१. भारतीय सविवान-ग्रनुच्छेद ६०,

२. वही -- अनुस्देव ६१,

एवं महत्व को समभता ब्रांत बावश्यक है। सरकार की नीतियों तथा कार्यों के दृष्टिकोण से, मंत्री मण्डल प्रत्यक्षरूप से लोकसमा ब्रौर ध्रप्रत्यक्षरूप से या ब्रातम रूप से मतदातागण के प्रति उत्तरवायी है। चूंकि संविधान में स्पष्ट रूप से सामू-हिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है, इसका केवल यह धर्म ही नहीं है कि मंत्रीमण्डल को ससद (लोकसभा) में बहुमत की इच्छानुसार सरकार की नीतियो एवं कार्यों को चलाने का कर्तव्य है, परन्तु यह भी अधिकार है कि सरकार की नीतियो एवं कार्यों को अपने सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के श्रनसार उपयोग में लाने के लिए इस सिद्धान्त की कार्य-प्रणाली में किसी का हरनक्षेप तब तक न होने दे, जब तक उसे बहुमत प्राप्त है, अन्यथा संसदीय सरकार का कोई मूल्य ही नही रहेगा, क्योंकि बास्तव में संसदीय सरकार की झात्मा सामृहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त है। यदि इस सिद्धान्त को नष्ट किया जाता है तो संसदीय पद्धति नष्ट हो जायेगी। साधारण परिस्थितियों में, जब मशीमण्डल को लोकसमा के बहुमत प्राप्त हैं राष्ट्रपति केवल नाम मात्र ब्वजमात्र का कार्य-का ताकस्ता के बहुमत आपता है पद्भाग करता गांग गांच वजा गांव आपता है। साविवार के रूप में मंत्रीगुण्ड मिलाता के बहुआर कार्य करेगा, क्यों किया राष्ट्रपति इसके विषयेत कार्य करता है तो मनीमण्डल के समश सिवाय प्रपत्ने स्त्रीक देने के कोई विकल्प नहीं रहेगा। यदि माम चुनाव में पूरा पूरीने मंत्री मानने के सित्य बाध्य होना होगा। सधीय मंत्रीमण्डल के सोकसाम के प्रति सामू हिक उत्तरदायित्व को संविधान द्वारा मान्यता देने का कोई प्रयं ही नहीं रहता, यदि मंत्रीमण्डल को लोक समा में बहुमत रहते हुए, सरकार के नीतियो एवं कार्यों के लिए अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता। सविधान निर्मातामों की मार्वाक्षामों को सही रूप से मालूम करने के लिए, संविधान के धतुच्छेद ७८ उपवन्य (ग्र) एव (स) जिनसे, मंत्रीमण्डल के निर्णय लेने के ब्रायकार पर प्रकाश डाला गया है, ध्यान में लेना ग्रावश्यक है। ग्रमुख्देद ७८ (ग्र) के अनुसार प्रधान मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को मत्री मण्डल के लिए गये सारे निर्णयों से स्रवगत कराना स्रावश्यक है। सनुच्छेद ७८ (स) के सनुसार यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि प्रवान मधी किसी मुद्दे को जिस पर केवल एक मंत्री द्वारा निर्णय सिया गया है, परन्त जिस पर मत्रीमण्डल द्वारा विचार विमर्श नहीं किया गया है, तारी मनी-गर्यक से निवार के लिए प्रस्तुत करें, प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि उक्त मुद्दे को मंत्री मण्डल के समय रखे। सर्वियान निर्माणांमी कनुन्छेर ७७ उन्तरम (श) पूर्व (म) दोनों में 'रिशंब' सब्द का उपयोग किया है, वो इस बात का धोतक है कि 'निर्मंब' तेने का मधिकार मंत्रीमण्डल को ही सीघा गया है। पर नेहरू ने कहा है कि "हमारे संविधान द्वारा राष्ट्रपति को इगलैंड के राजा या रानी के समान रखा गया है। यदि ऐसा नहीं हो, तो मंत्रीमण्डल भ्रौर ससदके उत्तरदायित्व के सारे प्रश्न पर म्राघात पहुँचेगा । ससद सार्व-भौग है।"ै

सर्विधान ने प्रमुख निर्माता डा॰ धम्बेदनर ने इसी पक्ष पर बल देते हुए सिव-धान समा में चार नवम्बर १६४८ नो यह कहा — राष्ट्रपति नो नहीं स्थिति है जो, राजा की प्रिटिश सविधान म है। वहु राज्य का, न नि कार्यपानिना वा प्रध्यक्ष है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व वरता है ने कि शासन करता है। वह राष्ट्र वा प्रतीन है। शासन में उसका स्थान उस यत्र के मीहर ने समान है जिससे राष्ट्र के निर्णय प्रयोजत होते है।"

भ्रपने मापण मे डा॰ राजेन्द्र प्रसाद ने २६ नवस्वर, १६४६ को सविधान समा मे कहा—"स्वय समिधान मे ऐसे प्रावधान नही है जो राष्ट्रपति को मत्री-मण्डल की सलाह मानने के लिए बाध्य करते हैं, परन्तु यह मान्य है नि विटिश सविधान की यह परम्परा है कि राजा प्राय मश्रो मण्डल के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, इस देश में भी स्थापित की जायेगी, और राष्ट्रपति सब मामलों में सबैधानिक राष्ट्रपति (सम्पक्ष) ही रहेगा।"

इस दृष्टिकोण से यह कहना जिंवत है कि यदि मारत के राष्ट्रपति के पद के सर्वयानिक स्वरूप को सही रूप से समफला है, तो यह सावयप्त है इस मामले को भारतीय ससदीय प्रणाली के मूल सिद्धान्त — मशीमण्डल के सामूहिक लियात्वा के सिद्धान्त के सदार्थ में ही समझा जाना चाहिये। यदि राष्ट्रपति के पद के सर्वयानिक स्वरूप की व्याख्या, इस तस्य से पृथक् रहकर की जाती है कि सविधान द्वारा ससदात्मक प्रणाली स्वापित की यई है, तो राष्ट्रपति के पद के वास्त-वित स्वरूप के सम्बन्ध में सही झान प्राप्त न हो सकेगा। प्रतुच्छेद ७४ (१) की कठोर तथा सकीण व्याप्ता करने से यह पलती हो सकती है कि सविधान द्वारा स्वापित समदात्मक प्रणाली को घ्यान में न रखा लागे, शीर राष्ट्रपति की स्थित तथा शक्तियों की केवल प्रपूर्ण या एक तरकी जानकारी प्राप्त हो। यह सत्य है कि राष्ट्रपति की तथा मान के सलह सावयान में लिखित कोई वाध्यकारी प्राव्यान नहीं है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति की मशीमण्डल की सलाह मानने के लिए सविधान में विखत कोई सावयान कानूमी दृष्टिकोण से झावश्यक होगा। उत्त प्रोट और ९० एन० वैनर्जी का महान मुनी दृष्टिकोण से झावश्यक होगा। उत्त प्रोट के पर पर वैनर्जी का महान मुनी दृष्टिकोण से झावश्यक होगा। उत्त हो का स्वीक्त करने के लिए वाध्य है विष्त प्रपत्न मान के स्वत करने के लिए वाध्य है विष्त प्रपत्न मान के साव स्वत करने के लिए वाध्य है

१ प॰ नेहरू-हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 🗷 जुलाई १६५६ ।

२ यो० ब्रार० ब्रम्बेदकर—कान्स्टीट्युधनट ब्रमेस्यली डिबेट्स भाग ७ पृ० ३२। ३ डा० राजेन्द्र प्रमाद—कान्स्टीट्येन्ट ब्रमेस्बली डिबेट्स भाग १०, पृ० ६८८।

मनीमण्डल की जलाल, सगठन, तथा वार्य प्रणाली, प्रमरीकी प्रतिनिधि सदन के स्मीवर (प्रष्यक्ष) की मनित्र्यों का विश्वास धीर राष्ट्रपति के विद्यास प्रणाली का प्रप्रताल के विद्यास प्रणाली का प्रप्रताल के प्रस्ता निर्मास प्रणाली का प्रप्रताल के प्रताल का प्रमाल के प्रताल का प्रमाल के प्रताल का प्रमाल के प्रताल के प्रमाल के

प्रे नेहरू ने सविवान समा म बहा था कि सीवपान निर्मातामा का उद्देग्य राष्ट्रपति को बास्तविक मस्ति नहीं देश था, परन्तु उसरी स्थिति वो प्रतिष्ठापूर्ण

वनाना था।

कैनेडा ने सविधान के अनुसार धवनेर जनरण को बुद्ध सिनियाँ स्य-वियोगनुसार उपयोग में लाने के लिए प्रदत्त हे और अपन सिनियान। यह मित्रयो के परामनं पर उपयोग में लाता है, परन्तु धास्तव में कैं डिस मृत्य सिन्या के परामनं पर उपयोग में लाता है, परन्तु धास्तव में कैं डिस मृत्य परन्तु मानतों पर मानतों पर न्यत्र हों महें है, विश्वीक स्विधिक से सिन्या सिन्या मानतों पर मों वो उत्तके स्विधिक में दायर में है, मित्री मण्डल की सलाह अनुसार अपने सिन्या है। इस्तिय पर प्रति मित्रु के हैं पर्वा के सिन्या है। इस्तिय पर अपने मित्रु के हिंदि सामा मित्रु को हिल्ला किया में दाग पर सिन्या में ति है। मुक्यत विद्या सिन्या मानविवानिक परिपत्तं सीमित सामा विवानिक सामा सीमित सामा विवानिक सामा सीमित सामा विवानिक सामा सीमित सामा सीमित सामा विवानिक सामा सीमित सामा सीमित सामा सीमित सामा सीमित सामा सीमित सामा सीमित सीम

सुवीव, सिषपान में विविष्ट बाध्यकारी प्रावधान, जिसने होने से सान्द्रपति नो मसीसण्डल की सलाइ के मनुसार समस्य परिस्वितियो म कार्य करना होता, न गावित् द्रभवित नही रक्षा गया कि यदि कियो वरिस्वित में राष्ट्रपति को स्वत्रज्ञता-पूर्वेय कार्यवाही बरने की मावस्यवता हुदै तो यह सियान ने मनुबूल ही हो। सवेष में राष्ट्रपति ने राष्ट्र ने हित में स्वत्रवतपूर्वेय वार्यग्रही बरने ने तित्र सिंद

१ प० नेहरू—'कान्स्टोटुएव्ट झसेम्बली डिबेट्स भाग ४ पृ० ७३४ ।

·घान निर्मातामो न किनी सर्वधानिक रुकावट को सविधान मे नही रखा । परन्तु ऐसी परिस्थितियाँ बहुत कम होयी और राष्ट्रपति को ऐसी परिस्थिति में इस बात से मान्यासित होता चाहिये कि ससद एव राष्ट्र दोतो उसके साम हैं, मौर जिसकी भाग करते के लिये तत्वाल भाम चुनाव करवाना भावस्यक होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सविधान निर्माता इस तथ्य से भनमिन्न नहीं ये कि हमारी संवात्मक प्रवासी के स्वरूप के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जहाँ राष्ट्रपति के लिए मत्रीमण्डल की सताह न मानना भावण्यक हो । ऐसी परि-स्यिति की कल्पना करना कठिन नहीं है, उहाँ सधीय मत्रीमण्डल का मत किसी राज्य की सर्वधानिक यत्र के समाप्त होने के कारण राज्नीतिक हो, भीर जिसके भाषार पर वह ऐसा निषय से जो उसके राजनीतिक हित मे हो, पर राष्ट्र के हित मे न हो । ऐते मामले में राष्ट्रपति का मारत सब के भ्रष्यक्ष के रूप में यह कर्नक हो जाता है कि वह यह देखे कि राज्यों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार किया आपे हो बाता है कि वह यह देशे कि राज्यों के साथ न्यायपुर्वक प्रवहार किया जाये सेर के डाय सरकार का निष्यंत ऐसे मामले के बदय में रावनीनित सत्य में न किया बादे । हुत्य ऐसो परिस्तिपीयों के दृष्टिकोंच में हो सविधान में नोई बाय-कारी प्रावधान नहीं रखा गया, जिससे पाप्पति के सदा मदीमध्यत की सताह के मनुसार चलता होगा । परंचु यह नित्तिका है कि इस तरह के मोने बहुन नम हों होंगे । साधारणाया राप्पृति मन्नीमध्यत को सताह के मनुसार ही प्रवत्त को स्वतंत्र । प्रयत्त के स्वतंत्र । के स्वतंत्र के स्वतंत्र । इस नित्तिकार । इस नित्तिकार के स्वतंत्र । इस नित्तिकार । इस नितिकार । इस नित्तिकार । इस सके, व ही कि राष्ट्रपति निरक्त हो सके। लोक समा ने प्रत्येक पाच वर्ष के पत्रवान भग करने का प्रावधान, राष्ट्रवनि पर समद द्वारा महासिवीय संगाने का प्रावधान, मत्रीमण्डल व लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व क सिद्धान्त के लिए प्राव-धान, इन सारे प्रावधानो से यह निष्वध-निकाला आ सकता है कि राष्ट्रपति किन्तता से ही निरकुण हो सकेगा। इस तरह मारत के सर्विधान में राष्ट्रपति के निरनुश न होने हतु न तो उसे मधिक पत्रिशाली बनाया है न ही, प्रधान मधी एव मत्रीमण्डल को देग का प्रशासन उनके राजनीतिक दल के हिलो में न चलाने देने के लिए राष्ट्रपति को कमजोर बनामा है।"

देने के लिए राष्ट्रपति वो बमनीर बनामा है।" राष्ट्रपति एव सपीम ममीमण्डल ने सबयों के दृष्टिकोध से, धन्त में मारतीय सर्वोच्च स्थानत्व के राम साहव 'याम अस्था बहुद सीर स्था बनाम पत्राव राज्य के प्रकल्प में दिन यम निर्माय को प्रकृत किया जा सक्ता है। पारत में इंग्लेख ने तुल्य वार्ध्यानिका को पत्रने वार्ध, स्वतस्थानिका के नियम्बण में एहंकर करता है। हमारे सविधान के मनुष्येद ४३ (१) के मनुसार सच को बार्यशनिका सन्तिया

१ टी० के० टोवे-इ कास्टोट्युग्नम द्याफ इन्द्रिया, १६६३ पृत २४१।

राष्ट्रपति में निहित हैं, परन्तु प्रमुच्छेर ७४ के प्रत्यंत (इसरो प्रमुच्छेर ७४ (१) के साथ पत्र जाना चाहिये) एन भन्नोमण्डल, जिसना प्रध्यक्ष प्रधानमन्त्री होगा, राष्ट्रपति को सहायना तथा सलाह देन के लिए होना चाहिय । राष्ट्रपति इस तरह कार्यपालिका का प्रीपचारिक या सर्वधानिक प्रध्यक्ष है, बाल्निक कार्यपालिका फान्यमा मन्नीमण्डल या भन्नी परिषद में निहित हैं। इसिनए मानले सबिधान म इगलंड के समान ससदात्मक कार्यपालिका है, जिसमें व्यवस्थापिका सभा के सदस्य है, जिससे व्यवस्थापिका सभा के सदस्य रिक्त करनुए के रूप में राज्य की ब्यवस्थापिका प्रीर कार्यपालिका ने जोडा धीर बीध जाता है।"

सधीय-कार्यपालिका की शक्तियाँ

मारतीय सपीय नार्यपालिका ने ससदात्मन स्वन्य से यह विदिन होना है नि इसकी प्रात्तियो तथा कार्यों का विक्लेयण इसके दो हिस्सो के साधार पर ही निया जाना चाहिए। ये दो हिस्से निम्नतिषित हैं:—

- (न) राष्ट्रपति—जो ग्रीपचारिक नार्यपालिका है, ग्रीर
- (स) मत्रीमण्डल-जो वास्तविक नार्यपालिना है।
- (क) राष्ट्रपति की शक्तियाँ—बिटिस सविधान के प्रत्यांत सिदान्त कि राजा कोई 'गलती नहीं कर सकता है', इस प्रसम में उपयोग में लिया जाता है कि राजा कानून से परे हैं और प्रपंत्र प्रायरण के स्पर्टीकरण के लिए, किसी न्यायत्वय में उपस्थित होने के लिए उसे बाध्य नहीं किया सकता है। बाल्य में इस उपस्थित होने के लिए उसे बाध्य नहीं किया सकता है। बाल्य में इस सिद्धान्त का धर्म सर्वधानिक वृद्धिकोश से यह है कि सिवाय ममीपण्डल के सलाहां-पुनार राजा प्रपंत्र स्व-विवेदानुसार न तो कोई सार्वजनिक वार्य कर सकता है, न ही विसी पित का उपयोग कर सकता है, वसीकि प्रत्येक कृत्य के लिये, जो राजा के नाम से क्या जाता है, मनीमण्डल को 'निर्चय' सेने वा प्रायनार है, विससे सायारणतया, राष्ट्रपति बाध्य माना जायेगा। इस तरह मारतीय राष्ट्रपति विदिश्य राजा के समान सिवाय मंत्रीनण्डल के सलाहानुसार घोई ऐसा सार्वजनिक कार्य नहीं करेगा, जिसमें उसका स्व-विवेद निहित है। की प्रत्यादी कृष्णस्वामी स्थ्यर (सिवाम रूपरेसा समिति के सदस्य) ने सह सही ही कहा था कि मंत्री-पण्डल सोकसमा के प्रति उत्तरावानी है, धीर यदि कोई राष्ट्रपति, मंत्रीमण्डल को स्वावत्व के सिकसमा के प्रति उत्तरवानी है और प्रदि कोई राष्ट्रपति, मंत्रीमण्डल को सकता है। के स्वावत्व है। हम से मंत्र हम स्वावति हो से स्वावत्व के स्वावत्व के लोकसमा के प्रति उत्तरवानी है और प्रायत्व के स्ववत्व हम से मानता है तो स्वावत्व हम से मानता है तो

२. डी॰ एन॰ वैनर्जी—'सम धास्पेश्ट्स धाफ द इण्डियन कानस्टीट्युशन' १९९२, प्र० ६९ ।

वह सविधान का उत्तयन करने का दोधो होगा और उस पर महामियोग भी लगाया जा सरता है। राष्ट्रपति को वो विभिन्न अधिना सिवधान द्वारा प्रदत को गई हैं, उनका उपयोग वह मशीमण्डल के परामर्थाल्यार करेगा। निम्नलियित श्रीमानों के स्वतंत्र दुरु शिक्षा का सम्बन्धन किया जा सकता है।

१-नार्यपालिका शक्तियाँ

मारत का राष्ट्रपति एक ऐमे राज्य का ब्राध्यक्ष है, अहाँ पर ससदारमक सरकार की स्थापना की गई है। क्लस्वरूप राष्ट्रपति के नाम से ही श्रीपचारिक रूप से, सरकार तथा धासन के नार्य सम्बन्न किये जायेंगे। सवितान के अनुच्छेद ७७ के ब्रनुसार भारत सरवार के वार्यपालिका सबधी वार्य राष्ट्रपति के नाम से सम्मादित क्षित्रं आयेते। अनुत्येद १२ के अनुसार सम की कार्यपाविका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुत्येद ७४ के अनुसार समीय मश्रीमण्डल, जिसका अध्यक्ष प्रधान मत्री होसा, राष्ट्रपति को उसकी कार्यपाविका शक्तियों को उपयोग मे सेने थे लिये, सलाह तथा सहायता देगा । ब्रनुच्चेद ७= वे ब्रनुसार प्रधान मत्री का यह वर्तव्य है कि राष्ट्रपति को मत्रोमण्डल के सथ प्रशासन एव व्यवस्थापन सबधी प्रस्तावो की मूचना दे, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है। राष्ट्रपति की इच्छा-नुसार प्रधान मन्त्री द्वारा ऐसे मामले को जिस पर केवल किसी मन्त्री ने निर्णय तिया, मत्रीमण्डल के विचार के लिए स्थाजा सकता है। कमी-कमी ग्रनुष्छेद ७६ नी व्याख्या करते हुए, यह गननपहमी हो सकती है कि राष्ट्रपनि सरकार के कार्यों के क्षेत्रों में अपना स्व-विवेक उपयोग में ला सकता है। प्रो० एक्केंप्रेग्ट्रो-विक्ज का बहुता है—"अनुन्हेंद्र ७५ की व्याख्या इस रूप में करते में कीई कटिनाई नहीं होगी कि राष्ट्रपति को अपने स्व-विवेक को उपयोग में लाने दिया किंगी है नहीं होंगी हि राष्ट्रपति को घरने स्व-वेज्जंक का उपयोग से जात दिया थाने, वह (राष्ट्रपति) इस सनु-देद ने सन्तर्गत प्रधानमंत्री से हिसी मी प्रकार की जातकारी हासिल करने ने लिए मीर वर्षर मंत्रीक्षण्य हासिल करने हे लिए मीर वर्षर मंत्रीक्षण्य हासिल करने हे लिए मीर वर्षर मंत्रीक्षण्य सह याद रहना चाहित कि विना पत्रीर परिचानों के सनु-देद ७० की न्यास्था ससदासक प्रणानी में मूल किहानी के लिए में परिचानों के मुल्येद ७० की न्यास्था ससदासक प्रणानी में मूल किहानी के लिए में परिचान में के मुन्यार ही क्या वर्षर परप्यरा, जो इस्लंड में स्थापित है कि साधारस्थला प्रायुक्त मंत्रीक्षण्य के महुनार ही क्या है के मुन्यार ही कार्य करी, गारत में भी विना विसी सदेद धीर मजनेद के सम्बार्गत की जाला चाहिये, बर्योवि इस परम्परा के न होते से जो जननाविक सतुलन ससदारमक प्रणाली

१. एतेक केन्द्रोदिक्ज-कामरीट्यूरानल देवलपमेन्ट्स इन इन्डिया, १६५७ पृ० १६४।

में ग्रीपचारित एवं वास्तवित्र नार्यपालिता ने मध्य होना चाहिये, वह नहीं रह सनेगा। नार्यपानिता मंत्रधी राष्ट्रपति नी मस्तियौ निम्नलिखित हैं .—

१--मध की निम्नानियन मुख्य नियुक्तियों राष्ट्रपति करता है।

(क) प्रमुच्छेद ७५ (१) के प्रमुमार ग्राम चुनाव म विजयी राजनीतिक दन
 के नेता की नियुक्ति प्र<u>यान म</u>न्नी के पद पर करता है।

(स) ग्रतुच्छेद ७६ (१) व ग्रन्तर्गन महान्यायाधिवतः। (एटनी जनरस) वी नियुक्ति करता है।

(ग) भारत व नियम्बरक-महालेखा परीक्षत की नियुक्ति भ्रमुच्छेद १४८ (१)

के ग्रन्तर्भन करना है।

(म) सर्वोच्च न्यायात्रय तया राज्या ने उच्च न्यायात्रया वे न्यायाधी<u>नो</u> मी निवृक्ति क्रनुस्टेद १२४ एव क्रनुस्टेद २१७ व क्रन्टर्गन वरना है।

(इ) प्रमुच्छेद २६३ ने घन्तर्गत, एवं प्रन्तर्राज्यीय परिषद (<u>१९८र स्टे</u>ट नीन्मित) नी नियुक्ति नरता है।

(च) प्रनुष्टेद ३१६ के प्रन्तर्गत नय लोक नेवा प्रायोग के प्र<u>प्यस्त</u> तथा सदस्या की निमुक्त करता है। राष्ट्रपति कुछ राज्यों के एक समूह के लिए एक समुत्त प्रायोग्र-की मी निमुक्ति कर सकता है।

(छ) वित्त स्रायोग की नियुक्ति सन्दर्भेद २८० के सन्तर्गत करना है।

(ज) चुनाय थायोग की नियुक्ति ३२४ (२) के प्रन्तर्गत करता है।

(स) धनुमुचिन प्रदेशो पर प्रनिवेदन देने वे लिए धनुच्छेद ३३६ (१) वे ब्रन्तगंन ब्रापोग वी निमुक्ति वर सकता है।

 (व) प्रनृष्टेद ३३० (१) ने प्रनुमार प्रनुमूचित जातियों तथा प्रनुमूचित जन-जानिया ने लिए एक विशेष पदाधिनारी नी नियुक्ति नर सकता है।

(ट) अनुच्छेद २४० के घन्नगंत पिष्टटे वर्गों को दना को जांबने के सिए एक प्रायोग की नियुक्ति करता है।

(ठ) ३४४ (१) के प्रनुमार भाषा प्रायोग नियुक्ति वरने का श्रविकार रखना है।

नारत म मसदारमन सरकार के प्रमण म यहाँ यह कहना आवश्यक होगा कि य सारी निष्ठतियाँ राष्ट्रपति मत्रीमण्डल के परामर्श पर ही करेगा।

२—राष्ट्रपति को सम के निम्निसिसित ग्रियकारी गण के परच्युत करने का अधिकार है —

ग-अनुच्छेद १४६ (१) के बस्तर्गेत राज्यपाल को ।

य-अनुच्छद ११४ (१) क अरुगत एउपमान का । ध-प्रमुच्देद १२४ (४) व २१७ (१) वी के अन्तर्गत सर्वोच्च तथा उच्च न्यायात्व के मुख्य न्यायाधील तथा अन्य न्यायाचीलों को ।

ड-सिवधान म उल्लेखिन प्रक्रिया के प्रतृत्वेद ३१७ (३) तथा (४) के भन्तपैत सच लीक तेवा प्रायोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की, सविधान में उल्लेखित प्रक्रियानुसार।

२—सैनिक शक्तियाँ

मारतीय सविधान के मनुच्छेद ५३ (२) के धनुसार राष्ट्रपति को देश की विभिन्न सेनामो (जल,थल मीर नम) का सर्वोच्च मधिनारी माना गया है। राष्ट्-पति के द्वारा इस शक्ति का उपयोग विधिवत् किया जाना चाहिये। ससद की ही (ग्रनुस्को सात, मुची एक विषय क्रमाक १, २, १५ के ग्रन्तर्गत) सेना, युद्ध सया शान्ति के लिये विधि निर्माण करने का अधिकार है। अतः राष्ट्रपति की उपर्युक्त विषयो पर जो शक्तियाँ प्रवत्त की गई हैं, उनका उपयोग वह ससद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार करेगा । ससद की अनुमति विना, राष्ट्रपनि न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है, न ही भारतीय सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। श्रीपचारिक रूप से युद्ध की धोषणा का ग्रीयकार ससद मे ही निहित है। श्रमरीका मे राष्ट्रपति की शक्तियाँ मारत के राष्ट्रपति की तरह विवि द्वारा नियन्त्रित नहीं हैं। यद्यपि समरीकी सविधान में यह उल्लिखित है कि यद की घोषणा धमरीकी नांग्रेस हो करेगी, तथापि धमरीनी राष्ट्रपति विदेशी मामलो के क्षेत्र मे कार्यों का सम्पादन इस रूप से कर सकता है कि काब्रेस के समझ, सिवाय युद्ध की घोषणा करने के कोई विकल्प ही नहीं रहें। ग्रारम्म में, जब राष्ट्रपति जानसन ने वियतनाम में अमरीनी सैन्य शक्ति में बद्धि करने की आवश्यकता महसूस की तब काग्रेस की भनुमति प्राप्त करने के लिए उन्होंने वियतनाम की टोपिन की खाड़ी के मामले को, जिसमें अमरीकी जहाज पर साम्यवादियों द्वारा आक्रमण के आरोप संगाये गये थे, कांग्रेस के समक्ष रखा । इस तरह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वियतनाम युद्ध में प्रमरीकी सैरव शक्ति के उपयोग के लिये, काग्रेस की अनुसति लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई ।

भारत में यथि युद्ध तथा शारित सम्बन्धी विषयों के लिए श्रान्तम निर्णय लेते का प्रियानर सतद को है किर भी मारतीय संधीय कांध्यासिका (स्थीय स्वीमक्का) के हाम में सत्यपिक सहियाँ हैं। अपनी सत्तियों को उपयोग में नाले में मत्री-मण्यत ऐसी सत्यपिक सहियाँ हैं। अपनी सत्तियों को उपयोग में नाले में मत्री-मण्यत ऐसी सत्यपिक संस्था है नो घोषणा करने के प्रतावा कोई विकल्प ही नहीं रहे। धतः युद्ध एवं मान्ति के सम्बन्ध में ससद द्वारा धन्तिम निर्णय लेने वा प्रधिवार एक प्रौपचारिका मात्र है। परन्तु यह विदित रहे कि वास्तविक रूप में इन मक्तियों वा उपयोग राष्ट्रपति नहीं, बर्ल्क प्रधान मत्री (मन्नीमण्डल के प्रध्यक्ष के नाते) करेगा।

३—राष्ट्रपति की वैदेशिक शक्तियाँ

राष्ट्रपति के नाम से ध्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मारत के वैदेशिक मामलो पर सवालन होता है। उसी के नाम से समस्त प्रधिकारो ना प्रयोग होता है। राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति ध्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशो के राजदूत, नूटनीतिज्ञो तथा वाणिज्य दूतो को ध्रीपवारित्य समारोह में उनके प्रमाण-वन स्वीकृत कर राष्ट्रपति हो उन्हें मान्यता देता है। विदेशो में राजदूती, याण्ज्य दूतो तथा प्रतिनिधियो को नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम में ही को जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय सिंघयो तथा अन्तर्राष्ट्रीय समक्षीतो के लिये वार्ताएँ राष्ट्रपति के काम से ही सचालित की जाती है। इस प्रकार की सिंघयो तथा समझौतों के लिये अनुक्षेद्र ७३ के अनुसार सबसीय अनुसमर्यन आवश्यक है। इसलैंडड में ससीय अनुमर्यन उन सिंघयो या समकौतों के लिए आवश्यक है, जिनसे राज्य नी मूमिं ना हस्तान्तरण होता है या जिनके द्वारा घनराशि का दिया जाना आवश्यक है।

श्रमरीका में सिनेट (वावेस वा उच्च सदन) में, उन संधियों को दो-तिहाई बहुमत से स्वीष्ट्रित होना चाहिये जिनके लिए राष्ट्रपति ने श्रन्य देशों से बाती की है, श्रन्यया वे श्रवीनानिक मानी जायेंगी।

४-राष्ट्रपति की व्यवस्थापन शक्तियाँ

संविधान के प्रनुष्टेद ७६ के प्रनुसार भारतीय सध के लिए सध ससद वी स्वापना का प्रावधान निया गया है, जिसमें राष्ट्रपति तथा दो सदन हैं। उच्च प्रतन, राज्य सच्च है, तथा जिचला सदन, लोक सभा है। सबस के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में और राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति को मारतीय व्यवस्थापन प्रणाती में व्यवस्थापन सम्बन्धी निम्मालिखित शांतिकों प्रवत्त हैं।

(क) राष्ट्रपति को, अनुच्छेद न्ध्र (१) (२) (अ) एव (व) के अन्तर्गत ससद को आमित्रत एव स्थिति करने और लोकसमा को मग करने का अधिकार है। परन्तु ससद आमित्रत करने सम्बन्धी राष्ट्रपति की शक्ति का नियत्रण इस धर्त से, को पोपना करने ने प्रचावा कोई विक्ता हो नहीं रहे । पतः पुढ एव गानि ने सन्दर्भ में समद द्वारा प्रतिमानियम तियेष तेने का प्रतिकार एक पौनवारिका मात्र है। परन्तु यह विदित रह कि वान्तविक रूप माइन गनियों का उपगोग राष्ट्रपति नहीं, बन्ति प्रयान मदी (मदीसण्डन के प्रस्तात के नाते) करेगा।

३—राष्ट्रपति की वैदेशिक शक्तियाँ

राष्ट्रपति के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मारत के बैदेशिक मामयों का संवातन होता है। उसी के नाम से समन्त अधिकारों का प्रभोग होता है। राष्ट्रान्यस होने के नाने राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देग का प्रतिनिध्तित करात है। विदेशों के राजदूर, कूरनीतियों तथा वानिस्त हुनों को भोगवारिक समार्थह में उनके प्रमान्यत न्वीहत कर राष्ट्रपति हो उन्ह मान्यता देगा है। विदेशों में राजदूरी, वादिस्त हुनों तथा प्रतिनिधियों की निवृक्ति राष्ट्रपति के नाम में ही वादीनी

धनराष्ट्रीय स्थियो तथा धनराष्ट्रीय समझीतो ने नियं बानाएँ राष्ट्रपति के ने नाम में हो सवानित की बाती है। इस प्रकार की स्थियो तथा समझीतों के नियं घनुन्देर ७३ के धनुनार सनदीय धनुन्तमर्थन धावण्यक है। इसलेग्ड में समझीय प्रतुम्पेर उन मियो या समझीतों के निए धावण्यक है, जिनये राज्य की मूनि का हन्नान्तरण होता है या जिनके द्वारा धनरानि का दिया जाना धावण्यक है।

प्रमरीका में निनेट (कांग्रेन का उच्च सदन) में, उन सचियों को दो-निहाई बहुमन में स्वीकृति होना चाहिये जिनके लिए राष्ट्रपति ने प्रन्य देशों से बार्ना की है प्रस्वया के प्रवैदानिक मानी जायेंगी।

४-राष्ट्रपति की व्यवस्थापन शक्तियाँ

संविधान के अनुन्देद ७१ के अनुसार भारतीय सथ के लिए सथ समर की स्वानना का प्रावधान दिया गया है, विवस राष्ट्रपति तथा दो सदन है। उच्च अवत, राज्य कमा है, वशा निकास करना, लोक समा है। सबस के एक महत्वपूर्ण हिस्से के हम सीर राष्ट्रास्था होने के नाते राष्ट्रपति को मारतीय अवस्थापन प्रमानों से ब्यवस्थापन सम्बन्धी निम्मतिस्थात शक्तियों प्रदात है।

(क) राष्ट्रपति को, सनुब्धेद २५ (१) (२) (घ) एव (व) के झन्तर्गत समद को प्रामितन एव स्विति करने मीर सोक्समा को सम करने का प्रियक्तर है। परन्तु समद प्रामित करने सन्वन्त्री राष्ट्रपति की ग्रास्त का निषत्रण इस गर्ने से, एव पासीबत) का मर्प मनुष्देद १११ के मन्तर्यंत यह हो सकता है कि जितने संधिक समय तक राष्ट्रपति बाहुता है। (एस साग एक दि मेसिकेट बुवेक) "पाएप्रति के सबतन्यत के निर्मेषाधिकार का बास्तव मे, पातीस सत्तरासक प्रणाती में विशिष्ट महत्त्व है। यह एक सर्वमानिक, स्वरोध न कि रोडे (वेक) के रूप में है। इस निर्मेषाधिकार को राष्ट्रपति को रेते हुए सर्विधान निर्मालाओं का कर्ताबित वह निर्माट वा कि सबद-वेली व्यत्त सरसाएँ यदि राजनीतिक तत्त्रों से प्रमावित होकर स्थित विश्वेष पर पूर्वेत्वया विचार राष्ट्रित में नहीं कर सकी हैं तो राष्ट्रपति सप्तव्या कर्म के स्वत्या के स्वितिविध्यो द्वारा निर्मोक्त राष्ट्राध्या होने के तात्रे पर प्रमुख्य का स्वत्य स्वत

समरोकी सिचपान के सन्तर्यन जब कांग्रेस से वियेवक पारित होकर राष्ट्रपति के समझ बाना है तब राष्ट्रपति का दिन में कपने विचारों सहित वियेवक को कांग्रेस के पास विचारत कोटा देश है। यदि राष्ट्रपति का दिन है। यदि राष्ट्रपति कपनी सहित वियेवक को कांग्रेस के पास विचारत कोटा देश है। यदि राष्ट्रपति प्रपनी सहित वियोव का ता है। तो वियेवक प्रचित्त प्रपास का ता है। तो वियोवक प्रचित्त विया जाता है, विचारत को सामने के है। ते उन्दर्श ति के स्वाचित्र माना जातेश । भारत के राष्ट्रपति के समत समयेक है। विवाद के स्वप्ताद समरीकी राष्ट्रपति का यह प्रधिकार प्रचलका का निवेधारिकार माना जा सकता है। सिवाया के समुद्राद समरीकी राष्ट्रपति को स्वाच हा समरीकी राष्ट्रपति को स्वाच हा समरीकी राष्ट्रपति को निवेधक को का तरित का स्वप्ति कर के सित्त का करता है पत्र प्रसास के सित्त एक सकता है पत्र प्रमुद्राद समरीकी राष्ट्रपति को कि तथा हो स्विवेधक के साल प्रधिकार के सित्त एक सकता है पत्र प्रसास के कि एक स्वाच के सित्त एक स्वाच के सित्त हो से की वियोव के स्वाच हो, वैद्या कि स्वाच हो स्वाच के सित्त हो स्वाच के सित्त हो सित्त हो साला है। तो उचके द्वारा को है वर्षाव्यक्त के दिन हो वियोव कर तथा स्वाच हो पूर्व हो वायेगा, व्योवित स्वाच हो प्रसास के स्वाच स्वाच हो प्रसास का स्वाच हो पूर्व हो स्वाच सामल होने के पूर्व हो साला हो प्रसास का स्वाच हो पुर्व हो स्वाच सामल होने के पूर्व हो साला हो प्रकार का प्रधान सामल हो पुर्व के प्रसास का स्वाच हो पुर्व हो साला हो सुर्व हो साला हो पुर्व हो साला हो सुर्व हो सुर्व हो साला हो सुर्व हो स

(प) मारत के राजुपति को व्यवस्थापन के धेन में एक घरवन्त ही व्यापन प्रतिकत्व को यह है। संस्थापन के घनुन्केंद्र १२२ (१) के घनुनार जब सबद का प्रविचेतन न हो रहा हो, पाजुपति प्रचारोत सामु कर सकता है। पाजुपति इसरा लागू किये गये प्राणादेश की चर्चिक सबद द्वारा निमित विधि के समान होगी। परस्तु सबद के प्रविचेतन के पारस्य होने पर तत्काल घष्णादेश की सबार के दोनो सबने नै समाद सबता धानवण्क है। विष्ट सबद उस धर्मादेश स्वापन की साम्यान

१. डा॰ के॰ वी॰ राव-'पार्लियामेन्द्रो डेमोकेसी इन इष्डिया। १८६१ पृ० ४६।

समाप्त हो जायेगा, परन्तु यदि समद श्रध्यादेश से श्रसहमत नहीं है तो श्रध्यादेश को, ससद की बैठक के ६ सप्ताह पश्चात् समाप्त माना जायेगा ।

- (इ) राष्ट्रपति को ध्रमुच्छेद ५० (३) के ध्रन्तगंत राज्य समा वे १२ सदस्या को मनोनीन करने का प्रविकार है। राष्ट्रपति दन १२ सदस्यो को उन व्यक्तियों में से मनोनीति करेगा, जिनको साहित्य, विज्ञान, क्ला धौर समाज सेवा वे धेन में विषेष झान या ध्यावहारिक प्रनुसव है। राष्ट्रपति एली-इण्डियन सम्प्रदाय म दा व्यक्तियों को कोक समा के लिए सनोनीत कर सबता है यदि लोकसमा में उक्त सम्प्रदाय में से कोई सदस्य निवासित नहीं हुआ है।
- (क) सघ के राज्यों से सर्वाघन राष्ट्रपति की ब्यवस्थापन सबधी शक्तियाँ
- (1) सिवधान के घनुष्छंद ३ के घन्तर्गत राष्ट्रपनि वो घनुमति वे विना, किसी मये राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्यों को सीमाध्ये, क्षेत्रा या नामों में पोरवर्तन करने के लिए किसी भी विषेषक को समद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उसकी प्रमुखि के बाद ही उक्त विषेषक पर विचार किया जा सकता है। इस सबय में राष्ट्रपति के लिए सबित राज्यों की विद्यान समाध्यों के विचार झात करना प्रावयन है परन्तु यह राष्ट्रपति पर निर्मर है कि उन विचारों वा पालन करे या न करे।
 - (॥) राज्यों की विवान समाग्रों में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही कुछ विषेषक प्रस्तुन किये जा सकते हैं, जैसे—अनुच्छेद ३०४ के प्रत्तमंत यदि कोई विषेषक जो व्यापार, वाणिज्य या ग्रन्तरीज्योध सम्पक्तों पर प्रतिवन्य लगाता है।
 - (111) राज्य विवान समाप्रो द्वारा पारित ऐसा विषेषक जिसका सवध प्रमुच्छेद २१ के दृष्टिकोण से सम्पति के प्रधिप्रहण से हो, उसको राष्ट्रपति को स्वीकृति से ही कानन का रूप दिया जा सकता है।
- (nv) राज्य विवान समाम्रो द्वारा पारित ऐसे विवेधक जिनके द्वारा उन वस्तुम्रो पर नर लगाया गया है, जो समद द्वारा, प्रतृष्टेद २-६ के मन्तर्गत पारित विधि के प्रतृषार सार्वजनिक जीवन के लिए प्रावस्थक घोषित नर दी गई है।
- (v) राज्य विधान समा द्वारा, समवर्ती सूची में दिये गये किसी विषय पर पारित विषयक—जिसका समर्थ ससद द्वारा पारित किसी विधि से है, अनुक्टेद २५४ के प्रस्तृंगत राष्ट्रपति के विचाराय रखा जाना चाहिये।
- (ग) जब किसी राज्य का सबैधानिक तन प्रसम्पत्त हो जाता है तब राष्ट्रपति जक्न राज्य मे सकटकालीन स्थिति, धनुच्छेट ३५६ के धन्तर्गत, भौषित कर राज्य सरकार के किसी भी ख्रंग की, सिवाय उच्च न्यायालय की, शक्तियों को धपने हाथ

- (क) जहाँ दण्ड विसी मैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया है।
- (स) जहां दण्ड उस वानून के विरुद्ध प्रनराध ने लिए है, जो सब की वार्य-पालिका केक्षेत्राधिकार मे हैं ।
 - (ग) जहाँ दण्ड मृत्यु दण्ड वे रूप मे हो ।

राष्ट्रपति को शक्तियाँ, इस दृष्टिकोण से सघ-सूची तज ही सीमित हैं। "न णित्रयों को समर्वतीं सूची में उल्लिखित विषय के सबय में उपयोग म नहीं जाया जा सकता है सिवाय बन मामलों के जिननों ससद ने स्पष्ट रूप में राज्य की कायपालिका शक्ति के धनाधिकार से मतना रहा दिया है।

धनुष्पेद १४३ के ब्रन्तगत राष्ट्रपति शिसी भी सावजानन महत्व वे मामसे पर सर्वोच्च न्यावालय की राय मालूम वर सरता है। एव विकिट्ट दृष्टिकोण से, राष्ट्रपति का यह प्रिकार व्यवस्थापित समा पर एक सर्वथानिक ध्रवरोध वे रूप में १, वयोवि इस प्रिकार के उपयोग द्वारा अप्युपति किसी वर्षयक को, तिसके सर्वधानिक स्वरूप वे सवध में शका है, सर्वोच्च न्यायालय की राय नेते वे लिए मेंबरूर यह मालूम वर सकता है कि विषयक वास्त्रव म सविधान के ध्रवरूत है या नहीं है।

इसी प्रकार, राष्ट्रपति व्यवस्वाधिक के निसी नाय ने सवध मे यह मालूम करते के लिए कि वह सर्वधानित है या नहीं है, सर्वोच्च न्यायासय थी राम ले सकता है। उदाहरण स्वच्य, उतार प्रदेश की व्यवस्वाधिना साम ताया नयान्यालिका ना मामाना १९६४ में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायात्रय वे पास उसनी राम प्राप्त करने के लिए मेजा था। मुख्य न्यायाधिपति भी गनेन्द्र-मडकर ने सर्वोच्च न्यायात्रय की बहुमत की राय की मिश्यित्वस्ति करते हुए, एव महत्वपूर्ण सर्वभानिक विद्यान्त पर प्रकाल डाला। उन्होंने कहा यदि उत्तरप्रदेश विधान सभा ने दाव नो, कि विधान सभा ने हाते नो, कि विधान सभा ने हाते नो, कि विधान सभा को निसी न्यायापीश के विद्यु वास्ट्य प्राप्त करते ना प्रविचार है भीर न्यायालय को इस नार्यवाही की वैधता को जात चरने ना प्रविचार हो है, मान्यता ये वाती है, ती इससे न्यायालय नी स्वतत्रता वे भूत विद्यान्त पर प्राप्तात पहुँचेगा।

भत. यह स्पच्ड है कि राष्ट्रपति भपने इस भिषवार का सविधान वे सरक्षण हेत उपयोग कर सकता है।

५--राष्ट्रपति वी ग्रापत्तिकालीन शक्तियां

सविधान के मन्तर्गत, (मनुन्छेद ३५२, ३५६ एव ३६०) राष्ट्रपति को, तीन प्रकार की मापतिकालीन स्थितियों ना सामना करने के लिए भापतिकालीन म निनमी प्रदत्त की गई हैं। प्रस्थेक राज्य में सकटकाल में उसने मस्तित्य को बनाये रखने के तिए निसी ऐसे समित-सम्पद प्रधिनारी का होना भागवणक है, जिसको सकटवालीन प्रिरिचिति का सामना बरने के लिए सता धावस्थर रूप दी जा गते। 'समीय देश म यह सता धावस्थर रूप से, राष्ट्रीय सरकार में निहित्त हैं।

'सभीय देश म यह सत्ता धावण्यन रूप से, राष्ट्रीय सरकार में निहित की जाती है—यहां यह मी उल्लेखित किया जा सकता है कि सक्टकालीन परिस्थित का सामना करने ने लिए मुख्य उत्तरदायित्व राष्ट्रीय कार्यमानिका वा ही होता है।"

राष्ट्रीय कार्यपालिका में सहरकालीन परिस्थिति के दौरान स्थापिक प्रक्रियों निहित कर दी जाती है सब यह समत्र है कि नार्यपातिका निरकुत रूप भारण करने ना प्रस्त करें। सरियान ने इस सबसी में पात्र कुछ विषों "रक्षन-ग्रथमां" समावीकत किए जाते हैं, जो कार्यपालिका के निरकुत वनने की प्रकृति पर प्रवरोध के रूप भक्तपं करेंगे। सामान्य रूप से इन रफ़्क प्रवयानों का उद्देश्य यह होता है कि सकरकाल में राज्य मा हहत्वलेश मानियाने के प्रकार में मृत् हो और सीमितकाल ने लिए हो। परस्तु इनने साथ ही पह भी पायम्यन है कि जनता प्रपत्न प्राथितरों के अपि सजय हो। सक्षेप में, जनताशिक सिक्यान से राज्य के प्रसिक्त को जनार्य रक्षमें के लिए यहि सकरकाल में जप प्रोर तह घावश्यक्त क्रानिक को जनार्य रक्षमें के लिए यहि सकरकाल में जप प्रोर तह घावश्यक प्रकृतिक को जनार्य रक्षमें के लिए यहि सकरकाल में जप प्रोर तह घावश्यक प्रकृतिक की जनार्य राज्य में सकरकालों न परिश्वितयों का सामना नरने ने लिए शीवलालि किया जाये, तथा भारणिकों के प्रयोग र प्रमान

भी प्रत्यावण्यक है कि ये सथं बातें उन साथनों के रूप में हैं; जिनका सक्ष्य यह है कि जनतार्शिक मूल्यों का सस्तित्व बना रहें। अन्तर्राक्ष के सविधान में निम्मलिखित तीन प्रकार की सक्टकालीन परिस्थितियों का उत्तरेख किया गया है —

संबंधनम अनुरुदेद ११२ के सन्तर्गत, मंदि राष्ट्रपति को यह विश्वसत् हो । जांद कि राष्ट्र पर मुरता को बाह्य साक्रमण, युद्धावस्था, या झालरिक समानि का सकट है तो बह सक्टकालीन विश्वति को उद्योगणा कर सकता है। यह उद्योगणा राष्ट्रपति उपर्युक्त सकट की समावना ने भी कर सकता है। इस कार से उद्योगणा का मत्त, मंदि किन कारणों से यह भी गई थी के समान्त हो चक् है, राष्ट्रपति हुगरी उद्योगणा द्वारा कर सकता है। रह सामित्तरानीन उद्योगणा को ससद के समय महत्त्व करना साम्यक्ष है। रह सामित्तरानीन उद्योगणा का ससद के समय महत्त्व करना साम्यक्ष है। स्व

१. एम० श्रीतिवासन~डेमोक्रेटिक गर्वमेन्ट इन इण्डिया, १९५४ पृ० ३६९ ।

यह उद्भोषणा समाप्त मानी जायेगी । यदि उद्भोषणा के पूर्व क्षोक समा मग हो जाये या दो माह की अवधि मे मग होती है, तो केवल राज्य समा की स्वीकृति ही आवश्यक है। परन्तु राज्य सन्ना की स्वीकृति मिल जाने के पत्रवात् श्चापतिकालीन उद्भोषणा को नई सोक्सा की प्रयम बैठक के तीस दिन के ग्रन्टर स्वीकृति मिल जानी चाहिते, अन्यया उद्भोषणा समाप्त ही जायेगी।

राष्ट्रपति के, अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत, उद्घोषणा करने के प्रभाव

व—सल समद को सम्पूर्ण मारत या मारत के किसी भी हिस्से के लिए दिसा नी विषय पर उन चिपयो पर भी जिनका उल्लेख राज्य सूची मे हैं, विष निर्माण करने का प्रायन्तर होगा। ससद को यह प्रायन्तर सुजुल्देद २५० (१) के प्रमुसार है, प्रमुच्छेद २५० (१) के प्रमुसार प्रापतिकालीन उद्योगणा के समाप्त होने के ६ माह पत्रचार सबद हारा इस तरह निम्त विषि को समाप्त माना जायेगा। प्रमुच्छेद २५१ के प्रन्तानंत यदि राज्य विषान समा द्वारा निर्मित कोई कानून ससद दारा निर्मित कानून ही सप्त साम प्रायन माना जायेगा। यदि सकटकाल मे ससद का प्रायन्ति विष हो हो रहा है तो राष्ट्रपति राज्य सा विवास समा वारा निर्मित कोई कानून ससद वारा निर्मित कानून से सप्त में है तो राष्ट्रपति राज्य स्वा में उल्लेख है। सप्त-ससद प्रमुच्छेद २११) के प्रन्तार प्रपत्न के प्रध्यावाल में सह सम्पत हो हो रहा है तो राष्ट्रपति प्रमुच्छेद २१ (२) के प्रन्तार प्रपत्न कार्यकाल में एक समय में एक वर्ष तक की वृद्धि कर सकती है। इस प्रकार की वृद्धि आपतिकालीन उद्योगणा के समाप्त होने के तिथि से ६ महीने से प्रधिक समय तक नहीं की जा सबती है। ससद प्रमुच्छेद २१३ (व) के प्रन्तानंत पारतीय सरकार प्रीर उसके प्रधिवरारी गण को, विधि द्वारा मुख्य प्रधिवरात वाष्ट्रपति सकरी है, जिससे वे प्रापतिकाल में ससद द्वारा निर्मित विधियो वे कार्योग्वत करा सकते।

ख—सध सरकार किसी भी राज्य शम्कार को, कार्यमालिका को शक्तियो के उपयोग के लिए आदेल दे सकती है और सबद समीय प्रिकारियो को राज्या-धिकारियो के किसी मी प्रधिकार तथा कर्तव्य सींग सकती है। ससद को यह प्रधिकार अपने के किसी मी प्रधिकार तथा कर्तव्य स्वाप्त स्वाप्त है।

ग—राष्ट्रपति वो अनुच्छेद ३५४ के अन्तर्गत यह अधिकार है कि सकटकाल भे, आदेश द्वारा अपनी इच्छानुसार सविधान के अनुच्छेद २६०-२७६ मे निहित आय वितरण प्रणाली के सबय मे परिवर्तन करे, परन्तु यह आदेश ससद के दोनो सदनो के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

धतुच्छेद २४६ के धनुसार धापतिवालीन उद्घोषणा के दौरान, प्रतृच्छेद १६ मे उल्लिखित स्वतत्रता का ग्रिपकार स्थमित हो जायेगा । इसी तरह, सलटकाल मे राष्ट्रपति के प्रादेशानुसार यनच्छेद ३५६ (१) के धनुसार ग्यायालयो द्वारा मूल ग्रिपकारों के लामू करने के प्रथिकार की भी स्थिपित किया जा सकता है श्रीर इस सदमें में स्थायालयों के समक्ष जो कार्यवाही है, वह मी सकटकाल के धीरात या निविद्ध प्रविध तक के लिए स्विगित मानी जायेगी।

सक्षेत्र म, अनुच्छेद ३२ म जिल्लिखित सर्वेपानिक उपचारों के प्रिमितर को सरकरात में पाट्यति आदित हारा स्वीतिक कर सक्ता है। परजु देस अकार का आदित समस्त के तीनों सदनों के सम्बन्ध सद्धा किया जाना चाहिये। यह सपट है कि सर्वेपानिक उपचारों के चित्रकार को स्वीतिक करते में सम्बन्ध म राष्ट्रपति वा अधिकार धानिम नहीं है, वधाकि समर विधि हारा ऐसे आदेशों को समाप्त कर सकती है।

दितीय, सिवधान के प्रतुच्धेद १६ के धन्तर्यंग हिसी राज्यपाल स गहु प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि राज्य न ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसस प्राज्य सरकार को सिद्यान के प्रनुसार नहीं चलाता वा सकता है तो उस प्रविवेदन से सबुद्ध हो जान पर राष्ट्रपित उद्योगणा द्वारा राज्य सरकार के समस्त या पुछ कार्य पहुण कर सचता है, जिदस सिवाय राज्य विधान समा को शिस्त्यों के राज्यपाल या राज्य की प्रत्य सस्या या सता के कार सिमितित होंगे। राष्ट्रपति राज्य के उक्त नावायवों न प्रविकारों को अहम नहीं नर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा यह मी प्राचमान किया जा सकता है कि राज्य की विधान समा नी गितितयों को सतद या ससद द्वारा स्थिकृत सता द्वारा उपयोग म लाया जाये। राष्ट्रपति इस इनार की उद्योगणा का अन्य या उत्यम परिवर्तन दूसरी उदयोगणा द्वारा यह सन्वार है। राज्य क सबैधानिक द्वार के प्रसम्भ होने के परिणान स्वस्त राष्ट्रपति हार सालू हो गई उद्योगणा को सतद के दोनो सरनो ने समस्र रखना

यदि सोकसमा का प्राधिवकान नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति राज्य की सचित निर्िम से से ब्यय के लिए ब्रादेश भी दे सकता है।

सप क किसी राज्य म अनुन्देद २५६ न अन्त्यन सकटपातीन उद्घोषणा ने सदम मसय सरकार एव राज्य सरकार के मार्गदर्गन ने लिए निम्नलिखित मत्रियान क मार्गदर्गक अनुन्देदी एव परम्पराधी की ध्यान म रखना झति आवस्य है।

१—अनुच्छेद ३५५ ने अनुसार सय सरकार ना यह कर्तान्व है कि प्रत्येक सब के राज्य की, बाह्य आहमण एव धान्तरिक स्वानित के समय सरकार दें। इस तरह स्वप्त सरकार यह नुनिश्चित नरेगी कि राज्य सरकार प्रद्वाचान सत्तार प्रद्वाचान स्वप्तार क्षाचान स्वप्तार का प्रत्यान स्वप्तार का प्रत्यान स्वप्तार का प्रत्यान स्वप्तान स्वप

ने घनुसार निर्वाचित राज्य सरकार का, जिसको राज्य विधान समा मे यहुमत प्राप्त है, बाह्य आक्रमण एव ग्रान्तरिक प्रशान्ति से सुरक्षा करे, न कि राज-गीतिन मतमेदो के वारण राज्य सरकार को गिराने का प्रयस्त करे ।

२--प्रतृच्छेद १६५ के प्रनुसार सम सरकार के, सिवधान के प्रन्तर्गत दिये गये प्रादेशों का राज्य सरकार द्वारा पालन न करने के फलस्वरूप यह सकट-कालीन उद्योगणा की जा सकती है कि राज्य सरकार का शासन तन सिवान के प्रनुसार नहीं चलाया जा सकता है। प्रत. राज्य सरकार के लिए वेजल विसान समा में बहुमत होना ही प्रावश्यन नहीं है, प्रसिद्ध यह मी प्रावश्यन है कि सघ सरकार द्वारा सविधान के प्रन्तर्गत दिये गये धादेशों का पालन भी करें।

३—सत्तदात्मक प्रणाली मे इस परम्परा को मान्यता प्रदत्त की गई है कि यदि प्रयात मदी या मुख्य मती को यह प्रतीत होता है कि व्यवस्थापिका समा मे उसे यहमत प्राप्त होने के बावबूद भी ध्याम जनता का इस उसकी सरकार के प्रति दिखापूर्ण है, तो प्रयानमत्त्रों या मुख्यमत्री ग्राम चुनाव के माध्यम से जनता की इच्छा मालूम कर सकता है।

केरल में ३१ जुलाई १६४६ में, जब राष्ट्रपति ज्ञासन लाग्नु विचा गया तब सारे देश में इसके ग्रीभित्य के सान्याय में विभिन्न प्रकार के तर्न प्रसुत किये गये। साधारणतः केरल में राष्ट्रपति ज्ञासन लागू करने में तीज प्रालीचना की गई। प्रालीचकों का कहना था कि केरल में राष्ट्रपति ज्ञासन राजनीतिक, न कि सर्वधानितक, कारणों से लागू किया गया। डां० एम० पी० शर्मा का कहना है,—"ऐसी परिस्थितियों में ग्राम चुनाव द्वारा जनता को प्रमील करने के जनतानिक तम नो उप पराख कर देखा जा सरवा है। इसके पूर्व कि राज्य के सर्वधानित तम को उप तरोजे द्वारा समाप्त किया जाये, सधीन प्रथिकारियों का जनता कि प्रति यह नर्नाव्य है वि उनको, ग्राम चुनाव के दौरान प्रथन सार्वभौम जनतानिक मतदान के प्रथिकार होता, स्थित को मुखारने के लिए प्रवसर प्रदत्त करें। यदि श्राम-चुनाव द्वारा मी स्वायों सरकार स्वापित करने के प्रयस्त ता मिततों है, तो राष्ट्रपति द्वारा में स्वायों सरकार स्वापित करने का ग्रीचत्य ग्रत्यापिक प्रयत्न हो जायेगा।"

इसी दृष्टिकोण से डा॰ एस॰ सी॰ डेब का कथन है—"मध्यावधि प्नाथ जनता की इच्छा, चुनावो के मध्यकाल में, बात करने के लिए बैरोमीटर रूपी यत्र के समान है, बीर इंग्लैंड तथा मारत जैसे देवों में यह सरकार की वृत्ति सुधारने

१. एम० पी० शर्मा—पूर्वोक्त युस्तक, पृ० १२३।

के लिए, जो इन चृनाबो से मतदातागण पर ग्रपने प्रमाव को मातूम कर सकती. है, उपयुक्त ग्रवशेष है।" ।

भ्रतपृत्व नित्ती राज्य मे यह मातूम करने के तिए दि, बास्तव में, मतुन्धेर १५६ के मतुत्वार राज्य का सर्वेचानिक यम समाप्त हो चुका है या नहीं, उपपूर्ति सीत नुद्दों के मार्ग दर्जन में ही सच तथा राज्य के प्रिकारियों को भ्रपने कार्य करना चार्तिये।

सुतीय, विधान के धतुन्छेद २६० (१) के प्रतार्गत राष्ट्रपति को, विस-सबधी सहर नातीन स्थिति के लिए, परि वह सबुक्त हो बाता है कि ऐसी स्थिति करता है। यह प्राप्ति को स्थान के स्थानित को स्थान है। यह स्थानित को स्थान है। यह हो स्थानित को स्थान है। यह विधान को स्थानित की स्थान है। हो से स्थानित की स्थान है। हो से स्थानित की स्थान है। हो से स्थान है। से से स्थान है। से से स्थान है। से से स्थान है। से से स्थान होने से प्राप्त नहीं होगी है। तो इस्योग्या माणा हो सार्थी । यदि इस में महीन की प्राप्ति के दौरान सोहसाना माण हो बार्यों को राज्य समा की स्थानित की होगी, भीर तत्यकात नई सोहसान के प्रयुत्त प्राप्तिकार के तीता दिनों के मीतर उपानी स्थान हो जानी साहित हो। कार्यों को होगी होगी।

वित्त सबधी उद्भोषणा के फलस्वरूप सधीय सरकार, राज्य सरकारों को सार्विक निरंश दे सबती है, जिनके सनुसार राज्य सरकारों को कृतियय किसीय मूल सिद्धानों का पाउन करना सावस्वक है। इन सार्विक निरंसों के सनुसार राज्य सरकारों द्वारा राज्य सेवा के सारे या किसी भी वर्त के सीवकारियों एव वर्षसारियों के बेनन या फांगे में करीती की वा सबती है। इन निर्देशों के मन्तर्यत राज्य विषय समार्थी द्वारा पारित किसी विदेशक की राष्ट्रपति की स्थी हित के निरंह, न्युरिसंव किसा काला स्वावस्थक है।

इस विशोध सक्टबालीन मिसति के दौरान राष्ट्रपति को, संघ तेथाओं में बार परिवासियों तथा वर्षवास्थित के बेनन तथा मदो को कटीनी के लिए निर्देश देने का प्रिपेशन है। इस प्राधिकारियों को क्यांच्या तथा उच्च न्यायानय के न्यायाधीयों को मी सम्मिन्त किया जायेगा। यह स्पष्ट है कि विशोध सहस्य कालीन उद्योगमा के चरिणामस्वक्ष्म, राज्यों की विशोध स्वामन्ता नपट हो जाती है

इंग्लंड म, मुद्र या धान्तरिक धशान्ति के समय, सन्टनासीन शनियाँ नार्य-पालिना नो मयुर द्वारा धरिष्ठत नो जाती है। धमरीनी सन्धिन मे तिलित स्व से, निर्दार के सुद्रोत स्थित ना बर्गन नहीं है। तथापि गुद्र के समय प्राय:

१. एस० सी० देश, द कामटोट्युशन भ्राफ इंग्डिया, १९६० पृ० १९८ ।

काग्रेस ने राप्टपित को सकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए विधि प्रारित कर, विशेषाधिकार प्रदत्त किये। घत. इन दोनो राप्ट्रो म सकटकालीन शक्तियो, के उपयोग करन के लिए कार्यपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा शिषकृत किया जाता है।

इग्लैण्ड तथा भ्रमशेवाम नागरिक वे मौलिव ग्रधिवार पर सक्टवालीन स्थिति वाप्रमाव निम्नलिधित रुप मदेखा जा सकता है।

इत्लेज्ड म सत्तद ने जायगालिका वो विभिन्न प्रवार की विधिया वो पारित कर सदेहास्यद व्यक्तिया वो हिरासत म लेने का प्रधिवार प्रदत्त विष्णा है। उदा-हरण ने लिए डिफंस खाफ देला एकर १६१४ (Defence of Realm Act 1914) इमरजन्ती पानर डिफंस एकर १६३६ (Emergency Power Defence Act 1939) धत इप्लेख्ड म नागरिना के मूल अधिकारा के सदमें म सत्तद को ही प्रतिम शक्तियो प्राप्त है। अमरीना ने सुल अधिकारा के सदमें म सत्तद को ही प्रतिम शक्तियो प्राप्त है। अमरीना ने सिवान के प्रवुक्तर १ उपवन्य ६ (२) न प्रमुक्तर बन्दी प्रत्यक्षीकरण का प्रधिकार, सिवाय धान्तरिक विद्रोह या बाह्य प्राप्तमण की दिवति म, स्विषत नहीं किया जा सत्त्वा है। प्राप्त्रोय चर्चा वा प्रधिकार काग्रेस को ही प्रदत्त है, और त्यावलया नो यह निर्पारित चरते ना प्रधिकार हि स्थिति मग्नेस हो प्रदत्त है, और त्यावलया नो यह निर्पारित चरते ना प्रधिकार काग्रेस को प्रस्ति वा ना ना विद्रा हो प्रस्ति ना ना विद्रा हो प्रस्ति को स्थित म मूल प्रधिकार वो स्थित म स्थापनार प्रदत्त है। उपयोग्त म सानि वो स्थित म मूल प्रधिकार वत्ते है।

मारत म सक्टनानीन उद्योषणा करने का प्रथिकार सविधान द्वारा नार्य-पालिना को प्रदत्त है। इस सदसें म, उद्योषणा दिना ससद को प्रेषित क्रिये दो माह तन वैष रहेगी जबकि इसकैट तथा प्रभावना म सक्टनालीन स्थिति म अवस्थापिना की भूमिना प्रयक्ष एव तत्काल है।

मारत म, अनुच्छेद ३५२ थे अन्तर्गत सकटकालीन उदधोपणा के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद ३२ न प्रदत्त सर्वधानिन उदचारा के अधिकार को अनुच्छेद ३५ मन्तर्गत आदेश द्वारा प्रस्तित कर सकता है। इसी तरह आपतिकालीन उदयोपणा अनुच्छेद १६ द्वारा प्रदत्त नागरिको को विभिन्न सात स्वतन्तराएं स्थागित हो जाती हैं। सर्वधानिक उपचारा के अधिकार को स्विगत करने में आदेश को सविधान के अनुसार राष्ट्रपति ययाश्री असत्तर के समक्ष रखेगा। इससे यह प्रतीत हाता है कि सर्वधानिक उपचारा के अधिकार को अपनिकालीन स्थित म स्थागित करने विख् राष्ट्रपति वो जो शक्ति अपनिकालीन स्थित म स्थागित करने के स्थानिक उपचारा को प्रकार के अपनिम नहीं हैं। इस प्रकार के आदेश को राष्ट्रपति द्वारा ससद के समक्ष यथाश्री अस्तुत करना आवश्यक है। एस्ट्रा वहाँ सर्विकाल की एक जुटि दृष्टिगोचर है। सविधान निम्हताओं ने राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के आदेश की ससद के समक्ष किसी विश्रिष्ट अपविध मे

भारतीय शासन ग्रीर राजनीति

रखने ने बजाय राष्ट्रपति ने निर्णय हेतु छोड दिया है कि वह प्रादेश को 'ययाशीध्र' समद ने समक्ष रखें।

इसने परियाम स्वरूप राष्ट्रपति, यदि उसनी ऐसी इच्छा हैतो ससद नोइस मामले से प्रवयत करते के प्रवसर को टालने के लिए प्रयत्न कर सकता है।

१—सनटनालीन घोषणा दिना ससद नोप्रीयत निये दो माह तन वैध रहेगी। ससद नो दो माह तन सनटनालीन उद्घोषणा के सम्बन्ध म नार्यवाही नरने से अलग रखा जा सनदा है।

२ — अनुष्टेद १६ के अनुसार सात स्वतनताएँ सकटकासीन उद्योषणा के फलस्वरण स्थमित हो जायेंगी । राष्ट्रपति नागरिको के सबैनानिक उपचारो के अविकार को मी, आदेश द्वारा स्थमित कर सकता है।

३—राज्यों ने सर्वेवानिक तत के सबय में राष्ट्रपति को मकटकालीन शिंक ना मतुष्टिद ११६ के फत्तर्गत दुरुपयोग ऐसी स्थिति में जी समय है, बबिल राज्य सरकार नी स्पष्ट बहुन्तर प्रायत है। केरल न १६१६ में राष्ट्रपति डाग्य सकट-कालीन उद्योगपा शाप्तू करते ने समय श्री नम्बूडीपाद को केरल विधान सभा में स्पष्ट बहुन्त प्राप्त था।

द्रत बृध्यमें वा निवारण स्वस्य परम्परा, मिलगाली जनमत, तथा सतद में
मुद्द विरोधी दस (दली) द्वारा दिया वा सनता है। बाо मामली या वर्गत है,
'यह स्वामायिन है वि सम्दर्शालीन दता म नायंगतिन म पिनातिनाती हो बारी
है। सरवार की मह प्रवृत्ति कासाल या एवारान प्रणाली में समस्त नसार में
पार्ट जाती है। सस्वारान प्रणाली दिन देशों में है, उनके प्रमुख्य इस वार वें
योतक हैं कि ससद सतते हैं और विरोधी दली के सदस्यों के माध्यम से वार्य-पार्टिता को उनमें नायों ने बाहि उत्तरदार्गी रहन ने लिए बाध्य करती है। बब बाग्यपारिना क्रमणे सीमाधों से बाहर जाने वा प्रयूत्त ने तिहा बाग्य करती है। अब बाग्यपारिना सम्मी सीमाधी से बाहर जाने वा प्रयूत्त में स्वाप्य साव माम करती है। स्वरूत माम क्रमणे स्वाप्य के साध्यानी स्वाप्य से साम्याप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य के साध्यानी का प्रयोग किया है तो थे (ससद) मनी मण्डल वो पदच्युत तब वर सवते है घोर उसने स्थान पर दूसरे मनी मण्डल को रख सबते हैं।"

भारतीय मत्री परिषद ग्रीर प्रधान मत्री

मारत में ससदारमक प्रणाली के धन्तर्गत मधीय वार्यपालिका का दूसरा हिस्सा मत्री मण्डल है, जिसका प्रध्यक्ष प्रयान मत्री है। भारतीय मत्री मण्डल को उत्पत्ति सविद्यान के कतियन विविद्ध प्रावधाना पर प्राधारित हैं। इस्लेण्ड में, मधी मण्डल का उद्मत्त एव समस्त वार्यक्षणाली प्रलिखित परम्पादी पर प्राधारित है। भार-तीय त्रविद्यान के प्रमुच्छेद ७४-७८ में मत्री मण्डल के सगठन वार्यों तथा मूल दाखिलों का उल्लेख मिसता है। धनुच्छेद ७४ के मनुसार प्रधान मन्नी की प्राव्यक्षता में एक मशी मण्डल होगा, जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए सलाह सवा सहायता देया।

अनुच्छेद ०५ (१) में विश्वत है कि राष्ट्रपति प्रधान मधी की नियुक्ति करता है। प्रत्य मित्रयो की नियुक्ति प्रधान मनी की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति करेगा। इस अनुच्छेद के उपयन्य २ वे अनुसार मित्रयो का वार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छापर्यन्त रहेगा। इस सदम में भारतीय सविधान के अन्तर्गत सिद्धान्त एव व्ययहार में मूल अन्तर पामा जाता है। ससदासक पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधान मंत्री वे पद पर नियुक्त बर सवता हैं, जिसको ससद वे निचले सदन मे बहुमत प्राप्त है। सविधान के धनुच्छेद ७५ (३) वे धनुसार मधीमण्डल वा सामू-हिक उत्तरदायित्व ससद के निचले सदन वे प्रति है। सामूहिक उत्तरदायित्व वे सिद्धान्त को सविधान द्वारा मान्यता प्रदत्त गरने के कारण राष्ट्रपति वे पास इसके सियाय कोई विकल्प नहीं रह जाता है वि उसी व्यक्ति को प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाय, जिसको ससद के निचले सदन (लोकसमा) मे बहुमत प्राप्त है, श्रन्यया, किसी श्रन्य व्यक्ति को प्रधान मंत्री नियुक्त करने से राष्ट्रपति द्वारा साम-हिंग उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का अवश्य उल्लंघन होगा और राष्ट्रपति पर सर्वि-धान के उल्लंघन करने के कारण महामियोग लगाया जा सकता है। अत्तर्व, राष्ट्र-पति को प्रधान मनी नियुवत वरने वा अधिवार तो है, विन्तु इस अधिकार का उपयोग ससदारमक पद्धति वे द्वारा निर्धारित सीमाग्रो वे ग्रन्दर ही किया जाना चाहिये । इसी प्रकार सविधान के ग्रनुसार मित्रयों का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्मर है किन्तु जब तक मन्नी परिपद को लोकसमा में बहमत है, राष्ट्रपति जनको सबैधानिक रूप से पदच्यत नहीं कर सकेगा।

१. एम० बी० पायली—'इण्डियात कान्स्टीट्युशन' १६६२, पृ० ३०८।

भारतीय शासन और राजनीति

पदि सोहस्ता म बहुमब बन म तेवा प्रस्ता दान पत्र दे देवा है घोर पदि दन में मेहून में निए सपर्य है, या दन में मेहून में सबस में दियों एन महित्र का नाम निम्मत नहीं दिया या एकता हो, तो ऐसी निपत्ति में पानुपति माने विकेत नाम निम्मत नहीं होता । मारवर्ष में बर्ग्हर होनी प्रसाद में परिस्थितियों माने दक बनना मही होई है।

सहितों की निवृत्तित उदा सही परिचार ने पात्र ने नित् सी बन्दुस्पिति सह है कि राप्पृति प्रवान सही ने व्यापर्य का पात्रत नरित ने नित् बाम्प है । इत हुए ने नश्चन के दें तित एक बात्रुष्टी कर यह है कि बार्ची प्रतिकृति रोप्पृति ने निहित हैं, परन्तु प्रवतीक्षित एवं ब्यावहारित तथ्य यह है कि यदि प्रयान-नती नो लोकना न बहुनद प्राउ है, तो दें मंतितार वान्तत संप्रयान सत्री ने ही हैं।

मितियों के नवय ने मित्राल के कित्रस धतुन्देद धीर है, जितहों ब्यान से प्रवास सारस्य है। महुन्देद अर (४) के महुनार नवी का पर महुन्दा करने के पर पहान करने के प्रदूर्ति उसर पढ़े के प्रमान करने के प्रदूर्ति उसर पढ़े के प्रमान करने की कित्र की उसर्य है। यह प्रमान करने से करने की उसर्य दिनाई बातसे । इसे महुन्देद के उस्का (४) के महुनार पदि कोई मन्त्रें के महुनार पदि कोई मन्त्रें के प्रात्त करने एका है, तो उसे प्रमान करने कित्र करने के प्रमान करने प्रमान है, तो उसे अपन्त्रत अपने की प्रमान करने प्रमान के प्रमान करने कित्र के प्रमान करने कित्र के प्रमान करने करने के प्रमान करने कित्र करने के प्रमान करने कित्र कित्र करने कित्र करने कित्र करने कित्र करने कित्र करने कित्र कित्र करने कित्र कित्र

उन्हें हा नदनों ने दन बात का बहेत दिया जा चुना है हि जारतीय जनी-परेशर को कर्ज प्रमानों का जुन विदान—साम्मिक उत्तरशासिन का विदान है। इन विदान के प्रमुक्त प्रकोजनीरदर तोगतना के वाल पर्यने कान्य कार्यों के चित्र जामूहिक चन के उत्तरशासि है। विद्यान निर्मातीयों ने दूस विदान्य जा स्थार चन प्रकृति २१ (१) में बस्त करते हुए होने मारतीय कटतीय पदानि की स्रामार चिला माना है। प्रो० श्रीनियासन का कहना है—"परम्परानुसार सरकार के प्रसन में जिसकी स्थापना सविधान द्वारा की गई है, राष्ट्रपति की इच्छा को ससद तथा मतदातागण की इच्छा—के प्रमुसार उपयोग में लाना होगा।"

सघीय मत्री परिषद का सगठन ः मत्रीमण्डल एव मत्री परिषद (केविनेट व मिनिस्ट्रो)

इत्लैण्ड मे मत्रीमण्डल तथा मत्री परिषद में अन्तर है। मत्री परिषद एवं पृहित् सहया है जिसमें लगनग १०० सदस्य होते हैं। इसम मत्रीमण्डल ने सदस्य, अन्यमत्री, ससदीय सचित्र एव अवर सचिव सम्मिलत है। मारत मं भी मत्रीमण्डल तथा मत्री परिषद में अन्तर है। मारतीय मत्रीन्यरिषद में भी समस्त मत्री गण तथा सपत्रीय सचिव होते हैं, जत्रि मत्रीमण्डल में नेयल नेत्रीतेट स्तर ने मत्री ही हात है। मारतीय मत्री परिषद में चार प्रवार ने स्तरों के मन्त्रियों को मान्यता दी गई है।

सर्वश्रयम्, येनीनेट स्तर वे मत्री है, जो महत्त्रपूर्णं मत्रालयो वे प्रव्यक्ष है। इत वेनीनेट स्तर वे मित्रयो द्वारा मत्रीमण्डल (केनीनेट) वा निर्माण होता है। ये मत्रीमण्डल वी बैटको मे सिम्मलित होते हैं। इनको २,२५० एपये प्रतिमाह वेनन और ५०० एपये प्रतिमाह मसा मिलता है। इनके साथ, इनको प्रन्य सुविधाएँ उपसन्तर है।

डिनीय, नितपय राज्य-स्तर थे मणी है, जो निसी न दिसी निमास या उप-विभाग के लिए उत्तरदायी हैं। परन्तु इनवा स्तर मेगीनेट स्तर थे मित्रयों से निम्न है। सामाग्यता ये मश्रीमण्डल को बैंटको मे सम्मिलिन नही होने हैं, जब तक कि उनको निशेष सामत्रण न दिया गया हो। ये ससद वे प्रति उत्तरदायी हैं। इनको नैयोनेट स्नर के मित्रयों ने सद्दा २,२४० रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है; परन्तु इनको नोई नता प्राप्त नहीं है।

तृतीय, वितय मधी उपमधी-स्तर ने होते हैं। इनका वार्य मधालय ने नायों में सहयोग या सहायना पहुँचाना होना है। इनकी प्रतिमाह १,०५० रुपये वेतन मिलना है।

चतुर्वे, उपमित्रयों से नीचे संसदीय सचिव होते हैं। उपमत्री एव संसदीय सचिव विभी विभाग के प्रध्यक्ष नहीं होते हैं विन्तु इतका वार्ये मित्रयों तो, जिनने वे संबंधित हैं, प्रशासतीय एवं संसदीय कार्यों में सहायता पहुँचाता है। ये मत्रीमण्डल की बैठनों में सम्मितिन नहीं होते हैं।

१. श्री एन॰ श्रीनिवासन-'पूर्वोक्त पुस्तक', पृ० २१८ ।

विभिन्न स्तरों के मुत्रियों के बेतन तथा भत्तों ना निर्घारण सम्रद द्वारा पारित मुत्रियों के बेतन एवं मत्ते ना क्रयिनियम १६४२ (सेसेरीज) एण्ड अलाउन्सेज आफ मिनिस्टरम् एनट १६५२) द्वारा विया गया है।

मत्री परिषद धपने झस्तित्व को लोक सभा के बहुमत समर्थेन पर ही अनाये रख सकती है, और इस तरह झपने कार्यों तथा नीतियों के लिए लोकसभा के प्रति

रस सकती है, और इस तरह अपने कार्यों तथा गीतियों के लिए लोक्समा के प्रति बार्मिक कार्यपालिका होने के नाते सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी। मत्री परिचट की बार्म्यक कार्यपालिका के रूप में सर्वयानिक स्थिति इस

मनी परिपद की बार्शिक कार्यपालिक के रूप में सर्वधानिक स्थिति हमें धात से भीर दृढ हो जाती है कि हमने सहस्य सार सरस्य मी ट्रेनि और प्रत्यक्ष रूप से लोन साम ने प्रति उत्तरदायों होंगे। यह देशा आ चुना है, कि प्रयान मनी तथा अप्य मनियों को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, पर-पु इन मिलारों का उपयोग राष्ट्रपति रहेच्डापूर्वक नहीं कर सकता है। सरपार के नार्यों तथा मीतियों के लिए, प्रत्यक एक प्राथमिक उत्तरदायित्व मनी परिपद ना है। मत मनी परिपद के बागे एक मतियों का व्ययपन इसी प्रसम में करना बास्त्रीय ही गही, प्रसिद्ध आवश्यक भी है। इस द्विकोण से मारतीय मनी परिपद तथा जिटिया मनी मण्डल में कोई सन्तर नहीं है।

इंग्वैंग्ड म, १९२६ में हालडेन समिति (विटिंग सरकार ने तन पर नियुक्त समिति) ने प्रपत्ता प्रतिदेवत विटिंग सरकार को प्रस्तुन किया, निवसे विटिंग समिति हो तो पार्टी में एक हिन्दी के होई प्रतिभावत के लगों एक जीताओं का विरक्षेत्वण किया नगा है। यह पहने में कोई प्रतिवादीकीन नहीं होगी कि मारतीय सविधान ने धन्तर्यंत गर्धीय मन्नी परिवर्द के नार्यं तथा विर्मा, विटिंग मनीभण्डल के हालडेन समिति डारा उल्लेखित कर्मी नार्टी क्षार्टिंग के स्वर्धंत कर्मी कर्मी कर्मा कर्मी क्षार्टिंग के स्वर्धंत कर्मी क्षार्टिंग कर्मी कर्मी क्षार्टिंग कर्मी क्षार्ट्या कर्मी क्षार्टिंग क्षार्टिंग कर्मी करिया कर्मी कर्मी कर्मी कर्मी कर्मी करिया कर्मी कर्मी कर्मी कर्मी कर्मी कर्मी कर्मी कर्मी कर्मी

कार्यों तथा महिलायों के सद्दृष्ण हैं। ये निमानिशिता है —

(क) राष्ट्रीय शीवियों का मनिया रूप निर्मारण करना, जिसके परवास, समय
के समय दर्दे रवा जा सके। सक्तरात्मक पद्धित में इस नियम के सक्त में कोई यो
भव नहीं हो सकते, कि किसी राष्ट्रीय विषय के सक्त में, राष्ट्रीय प्रभवि तथा
भव नियम के स्वित्य में प्रति के निर्मारण का उतरसावित्य मंत्री परिषय
का है।
होता है।
होता है।
होता है।
होता है।
होता है,
हरवायनां स्वत्य सदस्य नियम निर्माण होता के लिए मदी भव्यव
का निर्माण होता है,
तथायनां स्वत्य की स्वीति के निर्माण स्वत्य
स्वत्य आप साम स्वत्य
स्वत्य आप साम स्वत्य
स्वत्य स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य
स्वत्य

355

निमित किया गया । धोर इसी बानून के धावार पर राज्यों का एक नये धावार पर पुनर्गठन निया गया । धनः प्रजासन को सही हप से बताने के निष् विधि-निर्माण करने की धावस्थनना होती है। मर्ना-परिषद सरकार के क्षेत्र में बहु नड़ी है जो प्रमासन को तथा समय को जोड़नी है, धन राष्ट्रीय सीनि निर्माण को निष् द्वार्थ लागू नरवाने म मनी परिषद कार्यपानिन गया व्यवस्थितिका ने मन्द्रगोग धोर समक्व रक्षांपिन करती है। इस दृष्टिकोण से मनी परिषद नया नमर एक दूसरे पर क्रियासन एव प्रक्रियासन प्रमाव डालत है। मनी-परिषद समद म प्राप्त बहुमन क धावार पर समद को नार्यवाही को निर्मार उद्देश्य की दिन्ना म राष्ट्रीय नींति को स्थितन करना को प्रविचिध सन्ध्य हान के नाते, मनी-परिषद कार्य निर्माण परनी है। इस तरह मनी परिषद एव समद के सम्बो को निर्माण र धावार पर समार परनी है। इस तरह मनी परिषद एव समद के सम्बो का उत्तरिक सन्तुनन, परस्पर प्रवर्शनों के धावार पर स्थापित किया जाता है। ससरात्मक प्रविच स्थार हम से देवा जा सनता है।

ससद ने अधिदेशनो ने दौरान साधारणनया प्रतिदिन, प्रन्न, स्यग्न प्रश्न भ्रादि रखकर नार्यपालिका (मनी परिषद) पर प्रनिदिन का अवरोध लगाया जा

सक्ता है।

सत्तदीय प्रणाली म नार्यपालिना पर मूल धररोत या नामपित धरोध मत्त्रातागण द्वारा सामान्यत प्रत्येक पांच वर्ष ने परवाल, ध्राम चुनावों ने समय उपयोग में लाया जा सनता है, जब मतदाताओं नो सरनार के नार्यों एवं नीतियों ना परोक्षा चरन ना परोक्ष धरिनार प्राप्त होना है। यदि मतदातागण प्रपंत दासियों ने प्रति सत्राग हैं, तो सरकार पर जनतातिक व्यवस्था में इसमें प्रिष्ट महत्वस्था में इसमें प्रिष्ट महत्वस्था में इसमें प्रिष्ट महत्वस्था जनतातिक धवरोत प्राप्त होना विकार होगा। ध्राम चुनाव ने समय मतदातागण न नेवल ससद ने प्रतिनिधियों ना निवीचन करते हैं, परन्तु प्रस्ति मंत्रों परिषद (बरनार) ने नार्यों तथा मीतियों ना मूल्याकन करते हुए पर निर्यारित करते हैं कि पिछनी मनी परिषद को पुत्र सत्ता की वागडोर सीपी जायें या नहीं।

(स) मारतीय मसदात्मन पहाति मे मनी-परिषद वा एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार एव प्रसानन पर प्रमानमाली निकन्नण रहता है, जिसने मनी परिषद द्वारा निर्मित्र कोर सम्बद्ध हारा क्रमणित्र कीरिक्यों कर नहीं मत्त्वन हो तके । अवके नवीं, यदि वह एक विमानाष्ट्रस्य है तो विमान के नामी के लिए व्यक्तियत रूप से उत्तर-समी होगा। प्रत्येक मनी, पर वास्तव से सपने विमान सम्बन्धी उन नीतियों को बार्यवित्त करने का उत्तरदाखित है, जिनका समूर्ण मनी परिषद का सम्बन्धन प्राप्त हो गया है। बस्तुत- मनी परिषद का सरकार एक प्रशासन के सारे क्षेत्र के सार्वनीम एव विस्तृत नियन्त्रण रहता है। नि सदेह सपने कित्तरी एक प्रीवकारी का उपयोग प्रस्यक मनी सम्मूणं मनी परिपद के निर्देशन में ही करेगा। किसी मी मनी द्वारा इस सिद्धान्त के उत्स्यमन के परिणाम स्वरूप समदीय पद्धति के माधार-भूत दसीय प्रणाली के कठीर मानुसासन के सिद्धान्त पर माधात पहुँच सकता है भीर उससे सबधित मनी को मणने पद पर से स्तीका देने के लिए बाष्य किया सा सकता है।

जा सबता है।

(ण) मनी परिषद का तुनीय वार्त प्रवासन के विलिश्न विमाणों की विधासों
म समन्या स्थापित करते हुए, इन व्रिवाधों को सीमासों ना निर्वारण करना है।
मनी परिषद की यह भूमिमा, उसको बास्तिक राष्ट्रीय कार्यपालिका होने के
नोत प्रांच है। यह सारत है कि ब्राप्तन के विभिन्न विमाण पृषक हकादयों ने रूप
में रहकर वार्य नहीं कर सकते हैं, मही इनको प्रवासन की पृषक् या स्तत कर इक्क्ष माना जा सकता है। प्रतिवादत सरकार के विभिन्न विमाणों म पारस्परिक सद्योग होना आवस्यक है, प्रान्या प्रवासन के विश्वर ने का बर हो सकता है। प्रवासन पर समूर्य दक्क्ष है और इस्ती सफलता का व्यक्ति की विमाणों में पारस्पर पर समूर्य दक्क्ष है, और इस्ती सफलता का वादित्व विभिन्न विमाणों के पार-स्परिक सहयोग एवं सान्यय स्थापित करने की क्षमता पर निर्मर करता है। यह केत्रियद परिस्थितियों में यो पा हो सो स्थाक विमाणों के प्रस्तुयों के वारण पर्णुय हित को हानि पहुँचने की समावता होती है तो समूर्य मनी परिपद की बैठक में सर्वायत विभागों ने यतभेदों को दूर किया जा सकता है। इस्तिए साधारावता प्रसासन के निरीक्षण, निर्वेशन, एवं नियन्त्रण ने कार्य मत्री परिपद

उपर्युक्त सीन प्रकार ने कार्यों ने प्रतिरिक्त भन्नी परिपद ने एक ग्रन्य कार्य पर प्रकाश डालना उचित होगा ।

(य) राष्ट्र की विसीध अवस्था को सही रूप से सवासित करने वा उत्तर-दायित्व मंत्री परिषद वा है। यन मंत्री-परिषद, विशेषकर विस्त मंत्री का नियन्त्रण, राष्ट्र की वित्त व्यवस्था पर होना न नेवल रवामादिन है, परनु शावश्यक सी है। वित्त मंत्री प्रति वर्ष वार्षिण नवट सैयार करना है, विसमें वित्तीय वर्ष के ग्राय-व्यव का विवरण होता है। जब वजट समाद के समझ उपस्थित है, तब मंत्री परिषद उपमे परिवर्शन करने की मान कर सकती है। वजट पादिक होने के पत्रवात इसना विचान्यर एवं समस्त वित्त व्यवस्था ना संवालन मंत्री मण्डल करता है। प्रत वित्त ना नियन्त्रक भंत्री मण्डल होता है।

मित्रयों के विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व

ससदात्मक पद्धति का मूल प्राचार मित्रयों के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त है। वास्त्रव में मित्रयों के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त उस जनतात्रिक यत्र के सदुश है, जो एक मोर तो ससद तथा मत्री मण्डल में और इसरी भोर राज्यति तथा मत्री परिपद में सतदातमक प्रणाली के प्रमुक्त प्रावश्यक सन्तुलन स्थापित बरता है। यह स्पष्ट है कि सतदातमर पढ़ित में कोई सबैधानिन श्वरोध इतना प्रमाववाली एवं श्यापक नहीं है, जितना कि मित्रयों के उत्तरदायित्व वा सिद्धान्त है बयोकि एक जत्रीर के रूप में इस सिद्धान्त द्वारा, सतदीय जनतातिक श्वाली के चार सतमा-राष्ट्राध्यक्ष, मत्री परिपद, सतद एवं मतदातागण वो पारस्परिक जनतातिक सम्बन्धों से जोड़ा जाता है। सत्वात्मक पढ़ित में मित्रयों के निम्नतिश्वित चार विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व हैं।

तकनीकी या ग्रीपचारिक उत्तरदायित्व

प्रीपचारिक रूप से, ससदात्मर पद्धति में प्रत्येव मत्री वा उत्तरदापित्व राष्ट्रा-च्यात के प्रति होता है। ब्रिटिज सम्बदात्मक प्रणाली में सम्राट वे अधिवारों पर प्रवाण डालते हुए, सम्बद्ध वेजहाट ने वहा या कि सम्राट् वे सरकार वे सबय में केवल तीत प्रवार वे अधिकार हैं, (क) परामर्थ देने वा अधिवार, (स) प्रोत्साहित करने वा अधिवार, ग्रीर (ग) चेतावनी देने वा अधिवार।

सरकार के सबध मे ब्रिटिश सम्राट् के कोई निर्देशक कार्य नहीं है, परन्तु इसके बावजद मी, मित्रयो ना उत्तरदायित्व ग्रीपचारिक रूप से सम्राट के प्रति होता है। ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश सम्राट साम्राज्ञी की सरकार कहते है। ब्रिटिश सरकार (मत्री परिषद) अपने पद पर सम्राट्या साम्राज्ञी के प्रसाद-पर्यन्त रहते है । इसी तरह भारत के सविधान के अनुच्छेद ७५ (२) के अनुसार मनी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त तक ही रहेगे। परन्त ससदातमक प्रणाली में, सरकार तथा शासन ने क्षेत्रा में राष्ट्राध्यक्ष नी प्रसन्नना से तात्पर्य है, ससद की इच्छा । ग्रनएव मनियों का उत्तरदायित्व राष्ट्राध्यक्ष के प्रति केवल ग्रीपचारिक ही है। ग्रीपचारिक उत्तरदायित्व ने सिद्धान्त ना ग्रप्रत्यक्ष रूप से प्रतिविम्व भारतीय सविधान ने म्रतुच्छेद ७५ (म्र) के म्रतुसार प्रधान मत्री का यह क्तंच्य होगा कि राष्ट्रपति को मत्री-परिपद के सारे निषयों, जो सघ के मामलो के प्रशासन एव विधि-निर्माण प्रस्तावों के सबध में है, ग्रवगत कराये यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहता है। इसी प्रमुच्छेद के उपवन्य (व) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है, तो प्रधान मत्री ना यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति नो सघ मामलो के प्रशासन एव विधि सबधी प्रस्तावो पर सूचना दें। इसी अनुच्छेद के उपवन्य (स) वे अनुसार, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है तो प्रधान मनी का यह नतंत्र्य होगा कि किसी ऐसे मामले को, जिस पर एक मत्री ने निर्णय ले लिया है, परन्तु जिस पर मत्री परिपद ने विचार विमर्ण नहीं किया है, मती परिषद के विचाराय रखे । नि सदेह, ग्रनुच्छेद ७८ उपवन्य (अ) (व) एव (स) में ससदात्मक पद्धति की कतिपय मूल परम्पराग्रो को समावेशित किया गया है, जिनके माध्यम से, ब्रिटिश सम्राट् के सदश भारतीय राष्ट्रपति ना सरकार के सबय मे परामग्रं देने, प्रोत्साहित करने तथा जेतावनी देने ने प्रियमार प्राप्त होते हैं। इन प्रियमारों के बायार पर राष्ट्रपति सरकार के परामग्रंताता, भिन, प्रात्तोषक एवं वार्शनिक के रूप में प्रपत्ती भूमिका निमा सकता है।

व्यक्तिगन उत्तरदायित्व का सिद्धानत

हुन्नैज्य के सत्तरास्तम प्रणालों में, मनिया के व्यक्तियत उत्तरपायित्व के सिद्धान्त्र को उत्तरित सबी मण्डल के सामृहित उत्तरपायित्व के सिद्धान्त्र के मूर्य हुई है। प्रशेष्ट प्राथमी के बनुसार व्यक्तित्त्व उत्तरपायित्व के सिद्धान्त्र के दो अर्थ है। प्रयस्त प्रयं यह है कि बनुत्त को बृद्धि संस्माद के नायों के लिए उत्तरपायी होना, जिसके यह तात्व्य है कि सम्राद्ध द्वारा वार्यपाणिक से सब्धान्त किने पर्य वार्यों के लिए सम्बद्ध के उत्तरमार के साथ किनो मानी के स्तावस्त्र का लोगा प्रायस्थ्य है।

द्वितीय समं यह है नि राजनीतिक दृष्टिकोण से मंत्री वा उत्तरवायित्व ब्रिटिश ससद के निचल सदन, कामन्स सभा, के प्रति है। फ्लस्ट्टर यदि वामन्स सभा वित्री मंत्री के प्रति क्रिकियाना स्टल्क करें तो मंत्री प्रपत्ने एक से स्वीप देगा।

भारत के सविधान में, मित्रयों के ध्यक्तिगत उत्तरदायित्य के लिए कोई ग्राधार-भून लिखित प्रावधान नहीं है। मारन के खर्द विकसिन देश होने के नाते यह उत्तम होता. यदि सविधान के निर्माता इस विषय पर सविधात में विशिष्ट रूप से वाबयान रचत । स्वक्तियन क्रम से भनियो पर यह एक महत्वपूर्ण सबैधानिक प्रवरोय होता । चॅकि इस विषय पर सविवान म लिखित प्रावधान नही है, इस कारण यह उचित होगा कि इस विषय में सम्बन्ध में एक स्वस्थ परम्परा विकसित हो । परंत् मारंग की राजनीतिक प्रणाली में पिछने कछ वर्षों में, कतिपय उदाहरणों के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि इस विषय पर ग्रत्यना ही कम विचार किया गया है। यह सत्य है कि ब्राचनिक समय में, सरकार की क्रियाग्रा की जटिलता एव व्यापनता क नारण प्रत्येक मनी के निर्णय के लिए अन्तर्विभागीय, विचार-विमर्श स्नावश्यक है। इस दृष्टि से मुत्री के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के प्रवन को इस ग्राबार पर जाँचना चाहिये कि किस सीमा तक मनी स्वय दोषी है। यदि मत्री का व्यक्तिगत दोष ससद में स्पष्ट हो जाता है तो उसे स्तीमा देने में कोई सकोच नहीं होना चाहिये। इम्लैण्ड म पिछले बुछ वर्षों म व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ने बाबार पर मित्रयों ने व्यक्तिगत भूल, जैसे बजट प्रस्तुत होने के पूर्व बजट सबधी बानों नो प्रकट करना, व्यक्तिगत अध्टाचार या सरकार की खुली आलोजना के नारण स्तीफे दिये। सर सेम्युल होबर ने, १६३५ के होबर-लवाल समभीते मे भूल होने के कारण अपना पद त्याग दिया, क्योंकि वे उस समय विदेश मनी थे

ग्रीर उन्होंने फ़ान्स के प्रवान मधी लवाल ने साम इटली-इथापिया ने मुद्ध के दौरान, यह मोपनीय समर्क्षाता किया कि मुद्ध का ग्रन्त करन के लिए ग्राधा इथा-पिया इटली को दे दिया जाय।

श्री हमुडात्टन न जो बित्त मत्री ये, बजट प्रस्तुत वरन व पूर्व, १६४६ म बजट सबसी बुछ बाता व प्रवट हो जाने व वारण प्रपता स्तीफा दिया। इसी तरह युद्ध मत्री जान प्राफ्यमा वा, वीलर वाण्ड वे प्रसय म १६६३ म ध्रपना स्तीका टता पदा।

मारत म भी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व वे दृष्टिवाण स वतिषय मित्रया न ग्रपना पद स्वय त्यागनर राजनीतिक नैतिकता, एव परिपक्वता का परिचय दिया । श्री लालवहादुर शास्त्री न एव रेल दुघटना हाने ने तुरत बाद रेल मंत्री स त्याम पत दे दिया। श्री चागला न, सररार की मापा सबधी नीति पर मतमेद हान से, शिक्षा मंत्री का पद त्याग दिया । मारतीय मतिया हारा व्यक्तिगत भूल ये कारण ग्रपना पद त्यान करन के मामल ब्रिटिश परम्परा की तुलना म अपवाद है, न कि परम्परागत व्यवहार ने बातर है। नइ मामलो म मत्री भूल प्रवट होन पर भी ग्रपन पद पर विना सनीच के दृढ बन रहे। डा० के० बी० रीव का कथन है—' वे कई व्यक्तिगत मुलें, जिनके परिणाम स्वरूप इंग्लैण्ड म निश्चय ही मनिया न व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के ग्राधार पर त्याग पन दिय, भारत म दना दी जाती है, जब प्रधान मनी (ससद म) खड़े होकर घापणा करता है कि वह सारी जिम्म-दारी ग्रपने क्या पर लेता है। जिसका तात्पर्ययह होता है कि प्रधान मनी के व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा उसके बहुमत दल की शक्ति का पूर्ण उपयोग उस विषय पर त्रागे विचार विमर्श को रावने के लिए विया जायेगा। हम यह महसूस वरन है वि सविधान निर्माताचा ने फान्स वे चौथे गणतन के सद्या, यदि सविधान म व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की समावेशित किया होता, तो यह उपयुक्त होता ।"ी

पारस्परिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त

मत्री परिपद एन इकाई होती है ग्रव , सत्रियो म पारस्परिक एकता तथा सगठन मिनवार्थ है। बास्तव म मत्री-परिपद का ग्रस्तित्व तब ही बना रह सकता है, जब मत्री गण पारस्परिक सबय के इस सिद्धान्त के ग्रनुक्त अपना आवरण रखें हिन या वो हम चब साब-खाम ही ठेरेंचे या मब साम ही दूब जायेगे। मत्री-परिपद क सदस्यों में एनता और सहयोग ही उसकी दूबता तथा स्थापित्व का

१. के॰ बी॰ राव-'पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ७०-७१ ।

क्षाचार है। सन्त्रूणं मनी-मरिपद वो एक सबुक्त मोर्चे के रूप में कार्य करना धावस्त्रक है, धन्यचा पारस्परिक सूट होने से मनी-मरिपद निखर सबती है। पारस्परिक उत्तरसायिक को मावता से मनी-मरिपद के ब्रान्टिक संगठन ने एक रुपता एक एक्टा स्थापित होती है, जो राजनीतिक मच पर पिरोपी दनो के मानता करने के लिए प्रति-पात्रक्षक है।

सामृहिक उत्तरदायित्व

मनी-परिपद ने सामृहिक उत्तरपामित के सिद्धान्त से यह प्रक्रिया है कि संसदात्मक पद्धित में नगी-परिपद एक इकाई के रूप में प्रश्ने नायों तथा नीतियों ने लिए प्रत्यक रूप से सबद ने निवत्ते सदन तोक्समा और प्रप्रदेश या प्रतिम कर से सदस्तात्मक के प्रति उत्तरपादी है। मंगी-परिपद ने सामृहिक उत्तरपादिव ने सिद्धान्त के प्राथा र र ही सबद में, मनी-परिपद ने कारों का सेखा-जोना निवा जाता है, जो सामाद वत पर एक महत्वपूर्ण कनतानिक प्रयोग है। इसी प्रवाद स्वाद के प्राप्त है के सिद्धान्त के प्राथा तथा है। सिद्धान्त के प्राथा तथा है। उत्तर स्वत्य है के स्वत्य प्रदेश के स्वत्य के उत्तरपादिक के सिद्धान्त के सीद को सिद्धान्त के सीद को सिद्धान्त के सिद्धान्त के स्वत्य प्रथा प्रति हो के स्वत्य प्रथा प्रवाद के सीद के सामित प्रवि के सामित प्रयोग के सिद्धान्त के सीद के सामित प्रयोग के सिद्धान के सिद्धान्त के सिद्धान्त के सिद्धान्त के सिद्धान्त के सिद्धान्त के सामृहिक उत्तरप्तायिक के सिद्धान्त का उत्तरपाद के सिद्धान्त के सिद्धान के सिद्धान्त के सिद्धान के सिद्ध

यहाँ यह जात करना उपमुंबत होगा कि किन सामनो द्वारा सामूहिक उत्तर-धांवित्व के सिद्धानत को बागू किमा जाता है। डा० धरो-दक्तर ने इस सदक में सिदमान समा में करा बार- किन प्रधान में बीके सुमानेश के साम्प्रणत से ही सामूहिक उत्तरधांवित्व के सिद्धानत को वार्धानित्व किया जा सकता है। मेरे विधार में, सामूहिक उत्तरधांवित्व के सिद्धानत को बो पिद्धानतों के लोगू करने हो हो मार्थावित किया जा सकता है। एक दो मेर हि किन्दी भी स्थितिक को, विधार प्रधान मंत्री की सलाह के मंत्री-परिषद वर मनोनीत न किया जाये। इसरा विद्धानत यह कि किसी मी व्यक्ति को मंत्री-परिषद के सदस्य के क्य में न रखा जाये, यदि प्रधान कोने वहता है हि उसे वरदश्व कर देना चाहिये। उन परि--िस्पांत्वमी में ही जब मनी-परिषद के सदस्यों को उनकी नियुवित तथा जाहे पदन्युत करने ने दोतो मामतो मे प्रधान मत्री को नियन्त्रण मे रखा गया है, हमारे सामूहिक उत्तरदायित्व ने धादर्श को प्राप्त रिया जा सकता है।" रै

इती मुद्दे पर प्रााश डानते हुए डा॰ पायनी या महना है— इस तरह तामूहिन उत्तरदायित्व ने सिद्धान मा व्रिया वय मित्रयों को उननी नियुक्ति भीर पदन्तुति ने सबर म प्रयान मत्री ने नियात्रण म रखने में द्वारा ही समन हुमा है। रे सतद नी शाय प्रणासी ने मियम १६८० (दि रूत्स आप प्रोसेक्टर एण्ड वन्डन्ड आफ विजनेसेज) ने अनुसार मशी मण्डल ने सामूहिन उत्तरदायित्व ने तिद्धा परिवशता प्रस्ताव रहा ना सन्ता है।

भारत म व्यावहारिक दृष्टिकोण से सामूहिक उत्तरदावित्व के सिद्धान्त के सबध में कुछ बाधाएँ हैं। भारत की अधिकाश जनता अजपढ़ है। ऐसी स्थिति म मतदात्रामो ती समदात्मव प्रणाती ने मुल सिखान्तो सवसी मनमिकता ने पत-स्वरूप कदाचित ससद मे राजनीतिक सन्तुता सही रूप से त रह पाये । उदाहरण स्वरूप ऐसी स्थिति ससद मे उत्पन्न हो सक्ती है जब किसी एक ही दन को इतना भारी बहुमत ससद मे प्राप्त हो कि प्रतिपक्ष के दना की स्थित नाममात्र की रह जाये। मारतीय राजनीति मे प० नेहरू के समय म १६४० से १६६४ तक देखा गया नि वाप्रेस वे बहमत वे वारण संसद मं दलीय स्थिति एव तरफ की श्रसतुलन श्रवस्था मे रही। १६७१ मार्च म हुए धाम चुनाव म पून वाग्रेस को श्रीमती गांधी के नतृत्व म लोक समा में श्रत्यधिक बहुमत श्राप्त हो गया । स्वस्थ ससदातमन पद्धति वे अनुसार ससद म राजनीतिन दलो नी स्थिति म सन्तानन होना मायश्यव है मौर यह मी मायश्यव है वि राजनीतिय दलो वी सख्या तीन से प्रधिय न हो। यहाँ पर मतदाताग्री के दायिखों के महत्व का प्रामास मितता है बयोति यदि वे ध्रपने मत वा उपयोग इस तरह वरें, जिससे दि स्यानीय, ग्रप्रजातात्रियः, राष्ट्र-विरोधी बातो तथा धार्मिर ग्रन्य विश्वासो से डवे रहने याने राजनीतिक दलो की अपेक्षा राष्टीय, धर्म निरपेक्ष तथा जनतानिक सिद्धा ता म त्रिश्यास वरने वाले राजनीतिव दलो वो ही उनवे मत प्राप्त हो तब ही स्वस्य प्रजातका विकास हो सकता है। ससद में यदि केयत दो या सीत राजनीतिक दलो के प्रतिनिधि निर्वाधित होते हैं और सत्ताधारी दल का बहमत इतना प्रधिव नहीं है वि प्रतिपक्ष दल या स्वस्य प्रावाक्षात्रा को राँद सके, ऐसी

१ यो ब्यार अन्येदकर-कास्टीट्युरात असेन्यली डियेट्स भाग ४ पृ० ११४६-६०।

२ एम० बी० पायसी-पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १७६।

स्यिति मे मत्री-परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का सही रूप से उपयोग होगा । ग्रीर सरकार अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए ससद के प्रति सजग और जागहक रहेगी। परन्तु मार्च १६७१ मे सम्पन्न हुए धाम चुनाव के परिणामस्वरूप श्रीमती गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (नई) को पून प० नेहरू के जमाने की ठोस तथा बगाय बहमत लोक समा मे प्राप्त हमा है, जबकि प्रतिपक्ष दलों को जिनकी ग्रविक संस्था होने के कारण प्रत्येक दल को नाग्रेस की जुलना में केवल नाममात्र के स्थान लोकसमा म प्राप्त हुए हैं। प्रतिपक्ष के ग्रापस म ग्रनेक दलों में निमात्रित होने के कारण, मारतीय राजनीति की सबसे बडी कमी धाज भी एक स्वस्य एव दृढ प्रतिपक्ष की अनुपश्यिति है। यह विदित रहे कि एक स्वस्थ एव दढ प्रतिपक्ष द्वारा ही, ससदात्मक पद्धति म सामृहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का वास्तविक रूप से क्रियान्वयन कराया जा सकता है।

सक्षेप में उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्वष्ट है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के व्यावहारिक उपयोग के लिए निम्नलिखित दो ग्रावश्यकताएँ हैं -

सर्वप्रयम, सबी परिषद के निर्माण तथा विघटन के अधिकार प्रधान मंत्री में ही निहित हो। प्रधान भनी की इच्छानुसार ही बन्य मनी की नियुक्ति तथा पदच्यति की जाय।

द्वितीय, सरकार को जागरक तथा सजग रखने के लिए, जिससे सामुहिक रूप से वह अपने दायित्वों को निमा सके, ससद में एक ठोस तथा सुद्ध प्रतिपक्ष विरोधी दल हो, जिसकी अनुपस्थिति में सरकार लापरवाह, अक्षम तथा निरक्श न अन सकेती ।

प्रधान मत्री एव मत्री परिषद

भारतीय ससदात्मक प्रणाली में, इंग्लैंग्ड के समान प्रधान गत्री का ग्रत्यधिक महत्व है। दोनो देशो म प्रधान मत्री की सर्वधानिक स्थिति तथा शक्तियो मे समानता पाई आती है, परन्तु जलात्ति के दृष्टिकोण से दोनों से कुछ प्रन्तर है। ब्रिटेन के प्रयान मंत्री के पद की जलात्ति, ब्रिटिश सर्वधानिक इतिहास की एक रीचकपूर्ण पटना पर मापास्ति है। बन् १७१४ में सामाजी ऐन की मृश्यु ने परवाल इन्लैंग्ड की राज गद्दी हेनोबर के राजकुमार जाने को प्राप्त हुई। जाने, प्रयेती मापा, रीति रिवाज एव राजनैतिक परम्पराधी से धनमित्र से। सामाजी ऐन के समय तक मत्रीमण्डल की अध्यक्षता सम्राट् या साम्राज्ञी द्वारा होती थी। परन्तु जार्ज की खनमिज्ञता के कारण, सबसे वरिष्ठ मत्री को अध्यक्ष मानते की परम्परा स्थापित हुई। ब्रतएव जार्ज प्रथम के समय रावर्ट बालपोल इंग्लैंग्ड के प्रथम प्रधान मत्री, अपनी वरिष्ठता के कारण वर्ने । वास्तव में प्रधान मत्री पढ का जल्लेख

त्रिटिण संविधान में लिखित रूप से कही भी नहीं है। नहीं १८०५ तक इस पद वा उल्लेख किसी कानून में पाया जाता है। १९०५ में प्राथमिकता क्रम की निवास्ति करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया, उसके अपनतंत प्रधान मंशी को पौचतों स्थान दिया गया। यह प्रधम कानून या जिसमें प्रधान मंशी के पद को सर्वप्रधम लिखित रूप से मान्यता प्रदस्त की गई। येतन निर्धारण के ट्रिन्टिकोण से विटिश संसद ने क्राउन के मंत्रियों संबंधी अधिनियम १९३७ में प्रधान मत्री पद का उल्लेख करते हुए, यह निवास्ति किया गया है कि प्रधान मत्री का वेतन १०,००० पोण्ड प्रति चर्ष होगा।

श्रतः इसलैण्ड के प्रयान मंत्री के पद का श्राचार त्रिटिश सविधान की एक परम्परा के रूप में है। जिसके श्राचार पर बहुमत दल के नेता को ही प्रधान मंत्री

के पद पर नियुक्ति किया जाता है।

भारतवर्ष में प्रधान मंत्री के पद का उल्लेख संविधान के अनुन्छेद ७४ (१) में पाया जाता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को परामशे देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। मंत्री परिषद की अध्यक्षता का दाविदन प्रधान मंत्री

🕔 में निहित किया गया है।

मारत के संविधान के अन्तर्गत, जैसा देखा जा चुका है, प्रधान मंत्रो की निमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु सामारणतथा राष्ट्रपति का यह प्रधिकार नगप्य है, वर्षोक्त राष्ट्रपति प्रधान मंत्री के पद के तिए उसी व्यक्ति की प्रामंत्रित करेगा जिसको संसद में बहुमत दल का नेता माना गया हो; प्रयोत, कोकताम में यहुमत प्राप्त दल के वरिष्ठ नेता को ही उसे प्रधान मंत्री के पद पर निमुक्त करना होगा।

ब्रिटेन के प्रयान मंत्री के लुस्य, मारत के प्रयान मंत्री का मारतीय संसदासका पद्धति में अध्ययिक महत्व है। हेरास्ट लास्की का, ब्रिटिश प्रयान मंत्री के लिए यह कदून है कि, "मंत्री परिषद के निर्माण का यह केन्द्र विन्दु है, मंत्री परिषद के जीवन का यह केन्द्र विन्दु है। मंत्री परिषद के जीवन का यह केन्द्र विन्दु है। धार मंत्री परिषद के स्वादन में प्रयान मंत्री, मंत्री-परिषद का केन्द्र विन्दु ही नहीं है, परन्तु यह सम्पूर्ण राष्ट्र का केन्द्र विन्दु है। है, परन्तु यह सम्पूर्ण राष्ट्र का केन्द्र विन्दु है, जैसा थीव्य कहते हैं—"सरकार राष्ट्र का स्थामी है। धार यह सरकार का स्थामी है। धार यह सरकार का स्थामी है। भार

प्रधान मंत्री के संबंध में कहा गया है कि यह 'समकतों में सर्वश्रेष्ठ' है (Primus inter pares) परन्तु रेमजे सूर का कहना है कि प्रधान मंत्री के लिए

१. एच० जे० लास्की-पार्लियामेन्टरी गर्वमेष्ट इन इंग्लैण्ड, १९३८, पृ० २२८ ।

२. एच० बार० प्रीब्य-'द ब्रिटिश कान्स्टीट्युशन' १६५१ पृ० १०८-६।

285 उपर्मुत शब्द ग्रर्थहीन सादित होते हैं, जबनि उसमे अपने सहयोगियो को नियुक्त तथा पदच्यत करने की प्रत्ययिक शक्तियाँ निहित है। सर प्राइकर जैनिग्ड का

बहुना है कि, " प्रधान मंत्री बैवल समक्क्षों में मर्बेथेप्ठ ही नहीं है, वह उन सूर्य के तस्य है, जिनके चारो ग्रोर नक्षत्र पिछत्मा करते हैं।" प्रचान मत्री की महत्वपूर्ण संबैधानिक स्थिति के सबय में ५० नेहरू ने जुनाई

२०, १९५६, में कहा या-"मैं जानता हूँ कि प्रधान मंत्री के क्या कर्तव्य हैं ग्रीर मुख्यान के ब्रन्तराँत प्रदान मनी उम कील के सद्द्र है जो सरकार रूपी चक्र की चुरी पर समी है और चक्र को गिरने से रोके रहती है। "रे सर विलियम वर्तन हारकोर्ट ने बिटिश प्रधान को जयमगाते सितारों के मध्य चन्द्रमा की उपमा दी है (Inter Stellas Luna Minores) प्रधान मत्री की मर्वधानिक स्थिति का -महत्व उसकी विभिन्न शक्तियों के आधार पर ज्ञान किया जा सकता है । ये निम्न-लिखित हैं।

मंत्री परिषद के सबध मे-पूर्व में इस विषय पर वस दिया जा चुका है, कि ससदात्मन सरकार के मूल सिद्धान्त मती-परिषद के सामृहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के सही क्रियान्त्रयन के लिए यह आवश्यक है कि मित्रयो की नियुक्ति तथा उन्हें पद-मुक्त करने का अधिकार वास्तव मे प्रधान मनी मे निहित हो। ग्रत: ब्रिटेन ने प्रधान मत्री ने लिए यह उचित ही नहा ग्रमा है कि वह ग्रपने समृह (मत्री मण्डल) के सदस्यों को स्वेच्छा से बदल-बदल सकता है। बस्तु स्थिति यह है कि प्रचान मनी ही मनी-परिपद का निर्माण करता है। सम्राट द्वारा मित्रयों की नियुक्ति का अधिकार केवत औपचारिक ही है। परन्तु इस अधिकार का उपयोग प्रयान मनी निरक्त रूप में नहीं कर सकता है। प्रधान मनी को मतियों की नियुक्तियों के सबध में अनेक तत्वों को ध्यान में रखना होगा। डदा-हरण स्वरूप दतीय एक्ना, मौगोलिक प्रतिनिधित्व परम्पराएँ एव राजनीतिक स्यिति आदि तस्यो को मनियो की निद्धिक करते समय प्रधान मन्त्री को ग्रपने ध्यान में रखना हाया । यन प्रवान मधी स्वेच्छा से तो इस श्रविकार का उपयोग कर सकता है, परन्तु जैमा डा॰ पाइनर ने कहा है-वह कैसर (जर्मनी के निरक्षी शासक) के सद्ध नहीं है, इसम कोई सदेह नहीं है कि अलिम निर्णय प्रचान मंत्री के हाथ में ही है। विमानों का, भित्रयों में वितरण करने का अधिकार भी प्रधान मत्री ना ही है ज्याहरण स्वरूप श्रीमती गांधी ने मार्च १९७१ के साम चुनाव के पश्चात जिसमें उनको सौकसमा में विशास बहुमत प्राप्त हुया विमासी का

१. भाई० जैनिग्ड-देवोनेट गर्वमेन्ट, १९५१, पृ० १८३।

२. प॰ नेहरू--द द्रियान, जुलाई ३१. १६५६।

विवरण प्रवते निर्णयानुसार निया। इस मामले वे प्रसत में भी प्रथान मंत्री पर वितयत तस्वो का प्रमाव रहता है। दल ने वितयस सरस्यों वे प्रमावकाली, एय जनता द्वारा प्रवल रूप से सम्भित होने ने कारण, इन सदस्यों भी इच्छात्रों को ठुकराया नहीं जा सकता है। श्रीमती गांधी की मनी परिषद में, जिसना निर्माण मार्च, १६७१, में हुआ, श्री जनजीवनराम, प्रतिरक्षा मंत्री, श्री चस्हाण, वित्त मंत्री, श्री स्वणसिंह, विदेश मंत्री, एवं श्री फकस्ट्रीन ग्रहमद, साद्य मंत्री, पुन नियुवत कियं गये। इस तरह विशागों के वितरण के समय दल के सदस्यों की बरीपता तथा प्रमाव का ध्यान रखा जाता है।

प्रधान मंत्री तिसी मंत्री वे वार्यों या धातरण से असतुष्ट होने वे वारण उससे स्वाप्तन्त नाम सकता है। जैसा श्रीमती गांधी ने उप प्रधान मंत्री एव सत्वाली विस्तामती श्री मीरारणी देसाई वी १९६६ से मंत्री परिष्य पर से इस नारण से हटा दिया कि वे करकी विस्ता स्वयों नीतियों से सत्वुद्ध नहीं थी। यदि मंत्री प्रधान मंत्री से सत्वेद्ध नहीं थी। यदि मंत्री प्रधान मंत्री से सत्वेद्ध होने पर भी स्थापपत्र नहीं देता है तो प्रधान मंत्री उस मंत्री वे पे पर्याप्त करते के विष्ट राष्ट्रपति वो परामणं दे सत्वता है। पर नेहरू वे कार्यवास में श्री श्यामाप्रसाद मुकर्जी, श्री सीर औठ देशमुख और श्री टीठ टीठ हुण्णाचारी ने और सीमती गांधी व मार्यन से श्री चामला, श्री पुनाचा एव श्री वस्तुद्धाल हांधी श्रीद मित्रपी ने प्रधान मंत्री से सत्वेद वे वारण स्थाप पत्र दिये थे।

प्रपान मत्री वो विसी मी मत्री की पदोजति या पदावतित वा भी प्रिपिवार है। श्रीमती गाँधी ने १६६७ के भ्राम चुनाव वे पत्रवात् श्री दिनेशसिंह वो राज्य मत्री से केशीनेट स्तर के मत्री (विदेश मत्री) वे पद पर नियुक्त विद्या।

प्रवान मनी मत्री-परिपद का प्रध्यक्ष मा समापति होता है। उसने द्वारा ही मत्री-परिपद की कार्य भूमी निर्मारित को नाती है। मत्री-परिपद की सारी पिति-विधियों एव कार्रवाई ना सनासन प्रधान मत्री ही नरता है। यथि मत्री-परिपद के निर्णय मत्रवाई ना सनासन प्रधान मत्री ही नरता है। यथि मत्री-परिपद के निर्णय मत्रवाद के सावार पर ही विधे जाते हैं, प्रधान मत्री का प्रमाव एव सताह बहुनत निर्णय पर पहुँचने ने तिए निर्णयम होते हैं। मत्री-परिपद ने प्रधान में नाते प्रधान मत्री ना एक महरवत्रण वार्ष यह है नि मत्री परिपद मे एकता तथा पुरुद्धता कावम परे क्योंनि मत्री परिपद के महित्त का आधार निम्मत्तितित विद्वारतों भे निहित मान्रवा पाया जाता है। 'हिसारा प्रतित्तव हस्तिए है नि हम सव एक हैं, विभन्न होने पर हमारा प्रसित्तव नप्ट हो जायेगा', स्त्रीर 'हम सव एव साम्रवित है वर हमारा प्रदित्तव एकता की मान्रवा की सुद्धता प्रधान सत्री के दक्ष नेतृत्व पर ही निर्मर है। यह स्वामाविक है कि बुख परिस्थितियों मे कितप्य मत्रियों या विमागों म मत्रवेद उत्पन हो जाते, ऐसी परिस्थिति मे प्रधान मत्री परने नेतृत्व, व्यक्तित्वत तथा मध्यस्थता है स्वित को सुधार कर पुन एकता स्थापित कर सकता है।

राष्ट्रपति एव मती मण्डल के मध्य कड़ी के रूप मे प्रधान मती की भूमिका

ब्रिटिश सनदा नर प्रणानी के प्रन्तर्गत सम्राट् के श्रविकारों के सम्बन्ध में ग्रपने विचारों को ध्यक्त करते हुए माउर वेजहार ने कहा या कि ग्रीपचारिक प्रधान होने के नाने, सम्राट् के कैवल तीन ही ग्रायिकार बच्चे रह गये हैं। वे ग्रायिक नार इस प्रकार है, १-प्रो साहित करने का ग्रविसार, २-चेतावनी देने का ग्रिपिकार, एव, ३-विचार-विमर्श करने का ग्रिपिकार । यह विदित है कि यह श्रिविकार राष्ट्र के सार्वजनिक मामलों के सम्बन्ध में हैं। चूँति राष्ट्र की प्रगति का उत्तरदायित्व प्रयान मनी के नेतृत्व में मनी मध्यल पर निर्मेर स्ट्ना है ग्रदः राष्ट्राप्यक्ष ने निए सार्वजनिक मामलो की जानकारी का सब से प्रमावशाली माध्यम प्रधान मनी ही है, जिसके नेतृत्व में मनी मञ्जल राष्ट्र की नीतियों एव कार्यों का निर्मारण करता है। ब्रिटेन में प्रधान मनी को राजा एवं मनी मण्डल के मध्य एक कड़ी के सदश, परस्परा के आचार पर, माना गया है। मारतीय सविधान मे प्रयान मंत्री की इसी प्रकार की मूमिका को अनुच्छेद ७६ के अन्तर्गत मान्यता दो गई है। इन अनुच्छेद के अन्तर्गत मन्नी मण्डल द्वारा भारत सब सबधी विषयो पर लिये गये निर्णय अधान मनी द्वारा राष्ट्रपति को प्रेपिन किये जायेंगे। झतः यह स्पष्ट है कि नारतीय प्रयान मंत्री, राष्ट्रपति तथा मंत्री मण्डल के बीच की एक भट्ट बपूर्ण बड़ी है, जिससे प्रधान मंत्री, मत्रीमण्डत ने सध-सम्बन्धी सामली पर लिये गरे निर्णयों से राष्ट्रपति को ग्रवंगत कराता है।

शासन के कतिपय महत्वपूर्ण पहलुखों से संबंधित प्रयान मत्री की मूमिका

मारतीय नमदान्यक पद्धति में प्रमान मनी शामन का बान्नविक प्रमान है। वान्तव में, यदि प्रमान मनी के दल को मसद के निवर्त सदन में बहुमन प्राप्त है तो राष्ट्रपति को प्रपती किस्सों का उनसोग मनी मन्डल की, जिसका प्रध्यक्ष प्रमान मनी है, सलाहानुसार करना शावस्थक है।

मारत के महात्माववादी (Attorney-General) का पद सपीय कार्यवालिका सं सबनित है। इसकी निमुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह प्रधिकारी मारत सरकार का प्रमुख विनि प्रभिक्तारी है। केवल उन व्यक्ति की ही निमुक्ति इस पद पर हो सक्ती है जो सर्वोच्च न्यामालय के न्यामानीय के पद के योग्य है। महात्मायवादी का बेवन राष्ट्रपति द्वारा निर्माणित निममों के प्रन्तर्गत, ४,००० रममे तथा ३४० स्यो नती प्रधिनाह स्वोद्धत है। महान्यायवादी के मारत सरकार के कानूनी मामलो के सम्बन्ध में निम्न-तिखित नार्य हैं —

क-मारत सरकार को कानूनी मामलो पर परामर्श देना एव उन कानूनी कार्यों का सम्पादन करता जो उसको मारत सरकार द्वारा सीपे गये हैं।

स-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार के समस्त मामलो का प्रति-निभिन्न करना ।

ग—सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मारत सरकार का प्रतिनिधित्व ऐसे प्रशरणो के सम्बन्ध में करना, जो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के धनुच्देद १४३ के धन्तर्गत प्रेषित किये गये हैं।

ध—महान्यायवादी को ऐसे कार्यों का सम्पादन करना धावश्यव है जो उसकी सविधान या वर्तमान कानन के धन्तर्गत सौंधे गये हैं।

संघीय संसद

भारतीय सिवधान के अनुच्छेद ७६ के अनुसार सधीय व्यवस्थापिका समा को सधीय ससद की सजा दी गई है। सधीय ससद के प्रमुख अग राष्ट्रपति तथा दो सदन है। इसमें से निम्न सदन कोकसमा (House of People) और उच्च सदन, राज्य समा (Council of States) कहा जाता है। राष्ट्रपति के सधीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने पर मी, जसे सधीय ससद के सबस में सिवधान के अनुसार बुद्ध महत्वपूर्ण कार्य सीवे गये हैं।

ससद का सगठन

क—राज्य समा (Council of States) मारतीय ससद के उच्च सदन को राज्य समा नाम दिया गया है जिसमे २४० से घ्रषिक सदस्य नहीं होंगे। इतमें से १२ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है धीर शेष सदस्यों को निर्वाचन सम के विभिन्न राज्यों की विधान समाधों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकत सक्रमणीय प्रणाली के ग्राधार पर किया जाता है। ग्रानुच्छेद ८० के अनुसार केन्द्र प्रशासिन क्षेत्रों के प्रतिनिधि ससद द्वारा निमित्त विधि में निहित प्रक्रिया के ग्राप्तार आर्थेगे। राज्य समा के १२ सदस्यों को राष्ट्रपति उन व्यक्तियों में से मनोनीत करेगा विन्हें साहित्य, विज्ञान, कता, सामाजिक सेवा ग्रादि के क्षेत्रों में विशेष जान या प्रमुत्तव है।

विशेष ज्ञान या अनुमद है । राज्य समा की सदस्यता के लिए सविचान के ग्रन्तगंत निम्नलिखित श्रहताँएँ होनी चाहिए —

- १. भारतीय नागरिक होना चाहिये,
- २. तीस वर्ष की ग्रायु होनी चाहिये ग्रौर
- रे अन्य वे सभी अहतींएँ जो समदीय कानून द्वारा निर्धारित को गई हो। जन प्रतिनिधित्व कानून १९५१ (People's Representation Act 1951) के अनुसार राज्य सभा में निर्धालित होने के लिये एक व्यक्ति को समदीय निर्वाचक

न्युतार राज्य तमा न गया। यत होन क लिय एक व्यक्तिका ससदाय निव होना ग्रावश्यक है, जहाँ से वह राज्य सभा के चुनाव के लिए खडा होता है।

भारतीय शासन ग्रीर राजनीति

राज्य समा एक स्थायी सस्या है, जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष ध्रवकाश प्रहण करत हैं। इस तरह राज्य समा के प्रत्येक सदस्य का कार्यशाल ६ वर्ष का होता है।

भारत कर उपराष्ट्रपति राज्य समा का समापति हाना है। यमरीको उप-राष्ट्रपति वे सद्द मारतीय उपराष्ट्रपति उपन सदद ना सदस्य नहीं है और स्वर्यदिनी उपराष्ट्रपति के समान हो सिवाय मदत्र न को समापता वे निस्वति से, उसे सन्दान करते का प्रयिक्तार नहीं है। राज्य समा के समापति को नुष्प महत्व-पूर्ण मिकार प्राप्त हैं। वह किसी मी सदस्य को जाव-विवाद में हिल्सा तैने के तिए प्रिष्टण कर तकता है। उसे सदस्य के प्रयुक्ताण कमाये एतने का भी प्रियुक्ता है। सदन के पटल पर प्रक्रम रक्ष्में और परिधामों को चौपित करने वा प्रयिक्तार समापति को है। अनुष्येद नदं (२) वे क्षत्रापर राज्य समा एक ज्यसनावित (आदा का जयराष्ट्रपति) राष्ट्रपति पद पर है, उपसमापति राज्य समा की सप्यक्षाता करता है। दोना—समापति तथा उस्तमापति की प्रवृत्तिपति न, सदन के निवामों के स्वत्मति, पाय समा समापति निवृत्त्व करती है।

ख-लोशसमा ससद ने निम्न सदन की, जी जनता का प्रतिनिधि सदन है, लोकसमा (House of People) कहा जाता है । लोक समा के सदस्यों की सल्या. बन्व्बेद द१ के बन्सार ५०० निर्वारित की गई थी, परन्तु सातवें सशोधन सन् १९५६ द्वारा यह सस्या वडा कर ५२० कर दी गई है। लोक्सभा के सदस्य मत-दाताओं द्वारा विभिन्न राज्यों से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के बाधार पर निर्वाचित कियें जाते हैं और २० सदस्य सधीय भू-मानो (Union Territories) और उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्रो में से ससद द्वारा निर्घारित प्रक्रियानुसार चुने जाते हैं। सविधान के अनुच्छेद ३२६ के अनुसार लोकसमा के चुनाव वयस्य मताधिकार सिद्धान्तानुसार सम्पन किये जायेगें। सक्षेप मे, इस सिद्धान्त का यह अर्थ है कि मारत के प्रत्येक नागरिक को, जो २१ वर्ष की बायुका है और किसी कारण सविधान के अन्तर्गत ग्रयोग्य नहीं है, लोकसभा ने चुनाव में मतदान करने का ग्रविनार है। लोकसभा के प्रत्येव सदस्य का निर्वाचन इस तरह होगा, कि वह ४,००,००० से प्रयिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व न करें। अनुख्येद ३३१ के प्रनुसार राष्ट्रपति को स्रोकसमा के लिए दो चान्त-भारतीयों को भनोनीत करने का ग्रविकार है, यदि उसके विचार में आग्ल-मारतीय समाज का अतिनिधित्व लोकसमा में पर्याप्त नहीं हैं। इसी तरह ग्रनुच्छेद ३३० (१) के अनुसार लोकसमा मे निम्नलिखित वर्गी के लिए स्थान मुरक्षित रखे जाते हैं (१) बनुसूचित वर्ग, (२) बनुसूचित जातियो, सिवाय उन जातियों ने जो ब्रासाम ने बनुसूचित क्षेत्र म है, ब्रोर (३) ब्रासाम के स्वायत्त जिलो की ग्रनुसूचित बातियो ।

लोकसमा का कार्यकाल पांच वर्ष का है, यदि इससे पूर्व यह मंग नही हो जाती है। अनुच्छेद (२) के अनुसार जब देश में संकटकालीन उद्योवणा लागू है तब लोकसमा के कार्यकाल में संसदीय कानून हाग्र, एक समय में एक वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकती है। परन्तु किसी भी परिस्थित में संकटकालीन उद्योवसा के समा होने के बाद ६ माह से अधिक के लिए यह लागू नहीं को जा सकती है। लोकसा के सहस्य कराय निवास के आवार पर सम्पन्न किया जाता है। लोक सामा के सदस्य का चुनाव सार्यजनिक घयरर-मताधिकार के आवार पर सम्पन्न किया जाता है। लोक सामा के चुनाव के लिए मतदाता की बीमलताएँ इस प्रकार हैं:—

- १. वह मारत का नागरिक हो।
- २. उसकी ग्रायु २१ वर्ष की हो।
- ३. यह निर्वाचन क्षेत्र में वम से कम १८० दिन तक निवास वर चुका हो, श्रीर ससद द्वारा घोषित कोई ध्रयोग्यता उसमें न हो।

लोकसमा की सदस्यता के लिए संविधान के धनुच्छेद ८४ के धनुसार परयेक सदस्य को श्रधोलिखित भहतीएँ पूर्ण करनी होंगी ।

- १. भारत का नागरिक होना श्रायश्यक है।
 - २. २५ वर्ष से कम आयुन हो और,
- ३. वे अन्य शहलीएँ होनी चाहिएँ जो संबदीय कानून द्वारा निर्धारित को गई हैं। अनुच्छेर १०२ (१) के अनुसार कोई भी व्यक्ति लोक समा सदस्य नहीं हो सकता है यदि
- (१) यह भारत सरकार या विशी राज्य सरकार के स्रधीन छाम के पर पर है, सिवाय उस पदाधिकारी के जिसके संबंध में संसद ने यह कानून पारिस किया है कि यह इस स्रयोग्यता से मुक्त होगा।

सन् १९११ में जांच समितियों, निगमों तथा धायोगों के सदस्यों, तथा १९५४ में विक्वविद्यालयों के उपकुखपतियों, संसद के उपप्रधान सकेतकों तथा नेकनल कैडेट कोर क्रीर क्षेत्रीय सैन्य इस के ग्राधिकारियों को, इस संदर्भ में उपर्युक्त प्रयोखता से मुक्ति प्रदान की गई है।

- (२) वह किसी न्यायालय द्वारा यावल घोषित किया गया है।
- (३) यह दिवालिया है।
- (४) भारत का नागरिक नहीं है प्रयवा उसने किसी विदेशी राज्य की नाग-रिक्ता प्राप्त करली है, अथवा वह किसी श्रन्य राज्य के प्रति मक्ति रखता है।
- (१) संगद द्वारा निर्मित किसी कानून के द्वारा या ग्रन्तगैत श्रयोध्य न हो । इस संदर्भ में संसद ने १९५१ में कुछ ग्रयोध्यताओं का निर्धारण किया है जो निम्ना-नुसार हैं:—

- (क) यदि उस व्यक्ति ने निर्वाचन सबधी कोई ग्रपराध किया है। (ख) यदि उस व्यक्ति को किसी अपराघ के लिए दो दर्प से अधिक की सजा
- किली है तथा दण्ड से महित मिले उसे पाँच वर्ष से अधिक नहीं हुए हैं। (स) ग्रांट जमे किसी सरकारी नौकरी में से भ्रष्टाचार के कारण निकासा
- गया है।
- (ध) यदि वह सरकार से सर्वाधत किसी धनुबन्य या कारखाने में मागीदार

है । यदि लोकसभा के सदस्य होने के पश्चात् उपर्युक्त कारण से कोई व्यक्ति ग्रयोग्य हो जाता है तो वह लोकसमा का सदस्य नहीं रह सकेगा । किसी सदस्य के बयोग्यता सबधी भामले का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन खायोग की सलाह से करता है । यदि कोई सदस्य लगातार ६० दिवस तक लोजसमा की कैरको से क्रनपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

सन्ध्यो के विजेतातिकार

सविधान के बन्तर्गत ससद के सदस्यों को कतियय विशेषाधिकार प्रदान किये गयें हैं। अनुच्छेद १०५ के अन्तर्गत सदस्यों को सदन में या सदन की किसी भी समिति में भाषण देने की स्वतंत्रता होगी और मायण में अभिव्यक्त विचारों के कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। दीवानी मामलों के लिए, ससद के अधिवेशन प्रारम्भ होने के चालीस दिन बाद तक, किसी सदस्य की गिरफुरारी नहीं की जा सकेंगी। परन्तु फीजदारी मामलों के लिए किसी सदस्य को गिरफतार किया जा सकता है। ससद के सदस्यों को वेतन तथा मसे ससद द्वारा पारित विधि के अनुसार दिय जावेंगे।

लोक सभा का ग्रह्मक्ष (स्पीकर)

लोकसभा के विभिन्न पदाधिकारियों में ग्रध्यक्ष (स्पीकर) का पट ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। वास्तव में, भारत में ग्रध्यक्ष पद का विकास, ब्रिटिश कामन्स समा ने ब्राच्यक्ष ने पद के ब्राघार पर हुआ है। १६२१ से, जब प्रयम भ्राच्यक्ष सर फेडरिक व्हाइट की नियक्ति केन्द्रीय व्यवस्थापिका के निचले सदन के ब्राध्यक्ष के रूप में मारतीय गवर्नर जनरल द्वारा चार वर्ष के लिये की गई थी, मारत मे नेन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के निचले सदन के सात ग्रद्धक हुए हैं, जिन्होंने इस सस्या की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये मध्यक्ष (स्पीनर) हैं-सर फेंडरिक व्हाइट, श्री वि० जे० पटेल श्री जी० वी० मवलकर, श्री एम० ए० भ्राय्यवर, सरदार हुकुमसिंह, श्री एन० सजीव रेडडी. एव वर्तमान ग्रध्यक्ष श्री गुर दवाल सिंह ढिल्लो । इन्होने ग्रन्यक्ष पद के गौरव ग्रीर प्रतिस्टा को अपने सबक प्रयत्नो द्वारा बढाया है ।

मारतीय सर्विधान के बनुच्छेद ६३ के अनुसार लोकसमा स्वय अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। ग्रनुच्छेद ६४ (ग्र) के ग्रनुसार ग्रन्थश को सदन का सदस्य होना जरूरी है। धनुच्छेद १४ (स) के प्रनुसार, ग्रध्यक्ष को लोकसभा के बहमत प्रस्ताय से पदच्युत किया जा सकता है, परन्तु इस प्रस्ताव को पारित करने के पूर्व चौदह दिन नी मूचना देनी ग्रावश्यन है । ग्राव्यक्ष स्वय इस्तीफा दे सकता है । सविधान द्वारा उपाध्यक्ष के पद वा भी प्रावधान किया गया है, जो ग्राम्यक्ष की ग्रनुपस्थिति म या ग्रध्यक्ष पद वे लाली हाने पर ग्रध्यक्ष वे वार्यों को सम्प्रत वरेगा । ससदीय कार्य प्रणाली वे नियम १६५० वे अनुसार (नियम ७) ससद वे श्रारम्म होने वे समय या समयानुसार बच्यक्ष, सत्तद वे सदस्यो म से ६ सदस्यो की एक सुची बना लेगा, जिसमे से एक सदस्य श्रष्ट्यक्ष एव उपाध्यक्ष की अनुपस्यिति में सदन की ग्रध्यक्षता बरेगा। यदि इन ६ सदस्या म से बोई भी उपस्थित न हो तो सदन श्रपने सदस्यों में से किसी को भी श्रघ्यक्ष पद पर निर्वाचित कर सकता है। श्रनुच्छेद १६ (१) के श्रनुसार न तो श्रध्यक्ष, न उपाध्यक्ष उस वक्त सदन की श्रध्यक्षता करेगा, जब उसने स्वय ने पदच्युत करने ने मामले पर बादविवाद हो रहा है, परन्तु ऐसी स्थिति मे ग्रनुच्छेद ६६ (२) वे श्रनुसार श्रद्धाक्षा सा उपध्यक्ष को विवाद में हिस्सा लेन तया अपना बचाव करने ना पूर्ण अधिवार होगा।

ष्रध्यक्ष ने वेतन तथा भरो वा निर्धारण संसद करती है। उसनो भारत की सचित निधि में से वेतन तथा भरो दिये जायेंगे।

ग्रध्यक्ष के कार्य तथा शक्तियाँ

श्रिटेत में, एक सबैयानिक श्रामिसमय के अनुसार श्रिटिश श्राम्यात को समान मतदान की स्थिति में निर्णायक मत देने का श्रीयकार है। मारतीय सविधान अनुष्येद १००(२)ने पनुसार लोकसान के प्रम्यत को समान मतदान की स्थित में निर्णायक मत देने वा श्रीयकार है। लोकसमा की अप्यादाता, प्रम्यका (स्पीकर) ही करता है। वह लोकसमा की नार्यवाही की नियम सबयी आपतियो पर निर्णाय देता है। उसका निर्णय श्रीत्यम होता है। लोकसमा में बाद-विवाद में हिहसा लेने ये तिष् वह सदस्यों को मान्यता देता है। सविधान के श्रानुच्छेद ११० (३) के श्रानुसार श्रामक्ष को इस विध्यय पर निर्णय देने का श्रीयकार है कि एव विधेयक श्रामुद्धार लाई सा विका विधेयक। वह ससद के दोनो सदनों की समुबत बैठकों की श्रामक्षता करता है।

भव्यक्ष वे कार्यों तथा शक्तियों का विस्तृत रूप से उल्लेख ससद वी कार्य-वाही वे नियम १९४० में विया गया है, जो निम्नानसार है।

मारतीय शासन और राजनीति १५८

१—सदन क नजा की सताह से राष्ट्रपति के मायण म उल्लालत विषयों पर वाद विवाद न लिए बच्चन द्वारा समय का निपारण किया जाता है। राष्ट्रपति क भाषण पर घायबाद प्रस्ताव म संशोधन के स्वस्त का अध्या हा निर्धारित करता ह । ब्राप्त का यह ब्रापकार भी है कि राज्यति क भाषण से सर्वित विषयों पर सदस्या क निए भाषण की समयात्रिधि मा निजारत करे।

२-- पदन के नेता की संवाह अनुसार अध्यात सदन की कारबाइ का क्रम

नियारत करता है। ३--प्राप्त इस विषय पर निगय लना है कि सदन के समन प्रस्तान प्रकार

स्वातार करन याम्य है या नहा । नियम के विरुद्ध प्रश्ना को वह अस्वाकृति करता है । ४—किनी मर दर्गसावज्ञातक मन्मेचे पर बार दिवाद करने के लिए काम

राहा प्रन्तात्र मारत करन के निए भाजन की सनुमात बावस्यक है । भीर एसे विरम पर स बचा के निए स्र मन हारा ही सनमाव में का नियारण किया जाता है। ५--- बाद ब्रायन गजर म हिमा विधवत के प्रकाशन के ब्रादेश दे दला है तो

उदर दियार का सदर म प्र तुत्र करन के प्रत्ताद की प्रावश्यकता नहां होती है । ६—प्रवर समितिया (सतेक्ट कमरीज) व ब्राब्यता की नियक्ति ब्राध्यत

विभिन्न समितिया वं सदस्यान संबन्दता है। ७- क्सि विजयम पर बाद विवाद स्यमित करन के लिए प्रस्ताव के लिए

ग्रध्यात का सहसात ग्रावश्यक है।

 प्राप्त किमी प्रशाब को स्वीहत करने क लिए निणय लता है। वह बित विप्रान सबनी कारवाइ को पूरा करन के निए प्रावस्थक कदम ले

सकता है। १०-- प्राप्त न ताप्त न तथा समझ ने मध्य सम्पन-साधन का कहा क रूप

म नाय नरता है।

११—वह सदन म सदस्या को मापण दने व लिए भायता प्रदन करता है। साय ही वह भाषणा का क्रम भी नियास्त करता है। सदत के सदस्य ब्रायस भ प्रश्न द्वारा एक दूसर का सबाधन न करन हुए अध्यन को हा सबाजित करत है।

१२---ग्रह्म सदत की काववाही की नियम सबबी ग्रापत्तिया पर निणय

दता है और उसका निपन योजिन होता है। १३ - मध्यत सदन म अनुसायन बनान रखता है और इस उत्तरप्र की पृति

न लिए उतना बातरान शास्त्रा भी उपनत्त्र हैं। तिभा सदस्य को सदन की व्यवस्या मग करन पर ब्रध्यन उत्तको चेतावनी दे सकता है। और ब्रावस्यकता- नुसार ऐसे सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिए बाध्य कर शकता है। यदि सदन में, प्रशान्ति तथा प्रव्यवस्था से गंभीर स्थिति ही जाती है तो प्रध्यक्ष सदन की बैठक को स्थानत कर सकता है।

१४--- ग्रध्यक्ष सदन में दर्शकों के प्रवेश पर नियन्त्रण रखता है । साथ ही

जनको सदन से बाहर जाने के लिए वह सकता है।

१४--- प्रध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकास दे जो उसके मतानुसार मानहानिजनक, प्रक्षिप्ट या अससदीय है।

१६--जब भ्रष्टियक्ष सदन को सर्वोधित करता है तब सदस्यों को बाहर नहीं

जाना चाहिये।

अध्यक्ष के उपर्युक्त कार्यों के दृष्टिकोण से उसको सदन के मुखरूप के सुत्य माना जा सकता है। वह सदन के अधिकारों का अभिभावक है और विशेषकर सदन के प्रत्यसंस्थकों के हितों का रक्षक है। वह सरकार द्वारा सदन के क्रियकारों का ब्रतिक्रमण करने से रोकता है। जब मंत्री सदन में पूछे मधे प्रश्नों के उत्तर देने में ब्रानाकानी करते हैं या जब उनके द्वारा संदन को प्रयाप्त जानकारी नही दी जाती है, तो सदस्यगण श्रध्यक्ष से सदन के श्रधिकारों की रक्षा करने की श्रपील कर सकते हैं। वास्तव में, मारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसमा का श्रध्यक्ष उस संतुलन चक्र के तुल्य है, जिससे कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के संबंधों में जनतांत्रिक सन्तलन स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि जैसा देखा जा चुका है, श्रव्यक्ष में ऐसी शवितयों को निहित किया गया है, जिनसे वह सदन के विरुद्ध कार्यपालिका (शासन) के अतिक्रमणीं पर अवरोध लगा सकता है। अध्यक्ष की उपर्यंक्त मिमका को ध्यान में रखते हुए, पं० नेहरू ने, जब वे संविधान समा में श्री बी ॰ जे॰ पटेल की तस्वीर का ग्रानावरण कर रहे थे, मार्च = सन् १६४ = को निम्नलिखित ऐतिहासिक शब्द कहे—"सरकार की स्रोर से मैं यह कहेंगा कि हम यह चाहेंगे कि माननीय अध्यक्ष अब और हमेशा सदम की स्वतंत्रता की रक्षा प्रत्येक प्रकार के सतरे से करेंगे—कार्यपालिका के अतिक्रमण के सतरे से नी । यह सतरा हमेशा बना रहता है कि एक राष्ट्रीय सरकार भ्रत्यसंख्यकों के विचारों के दमन हराया था। रहारा हरा रहार रहार रहार रहार रहार हराया जा स्थाप करने का प्रशास का यह स्थित हो जाता है करने का प्रशास करें और ऐसी स्थिति में ही प्रध्यक्ष का यह स्थित्व हो जाता है कि वह सहन के प्रत्येक सहस्य तथा प्रत्येक इकाई की एक प्रमृत्यपूर्ण सरकार से रक्षा करें।...विहठल भाई पटेल ने इस परम्पराधों की मीव डाली जो क्षय मध्यक्ष पद से स्थायी रूप से संबंधित हो गईं।—मैं ग्राशा करता हूँ कि यह परम्परा बनी रहेगी क्योंकि भ्रष्यक्ष का पद किसी व्यक्ति-विशेष की प्रतिष्ठा नहीं है। मध्यक्ष सम्पूर्ण सदन की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है श्रीर चूँकि-सदन सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्य करता है अतः अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जा सकता है । यह उपयुक्त है कि भ्रष्यक्ष का पद निव्यक्ष पद हो,

भारतीय शासन ग्रीर राजनीति

१६०

एक प्रतिट्ठा पूर्ण पद हो भौर इस पद पर हमेशा विशेष क्षमनावान तथा निष्पक्ष व्यक्ति स्राप्तीन हो।"

इस्तैष्ड म प्रपत्ने निर्वाचन के तुरन पश्चात् नाममा समा जा अध्यक्ष दलनक राजनीति से सत्यान से लेना है, और सतद के समूर्त नार्यमत तर अपने पद पर रहना है । इस्तैष्ट म सम्मक्ष पद से सर्गापन बुद्ध स्वस्य तया महस्ति परमप्ताची ना विद्याल हुआ है, जी उत्तक्षे पद नो एक सन्ता मर्वधानित एव न्याधिक महत्व प्रदत्त करती है, जिनसे न नेवल प्रध्यक्ष ने पद नी प्रतिष्ठा वही है परातु इनके डारा अध्यक्ष पद की एक ऐसे मारन ना क्य मिना है जो सपन के स्वत्यक्ष के प्रधिकारी तथा उननी स्वतनतायों के रक्षक ने रूप म सम्म मिद्ध हसा है।

खाराय मारावीय लोरममी ना ध्रायक राजनीति से सर्वास्त है। बहु एक दस से सम्बद्ध व्यक्ति है। इस नारण उसके पद की कानी प्रतिष्ठा नहीं सनती है, जिदनी की घिटन ने काममा समाने प्रव्यक्त नी है। सोकसमा के प्रव्यक्त के दरगन होने के प्रीक्तिय के चाहे, क्लिन तर्क नमो न दिने आगें, यह स्प्यक्त है कि इसके मिषक प्रीक्तिय उस प्रस्माय का है जिसके प्रमुक्ता दिनेत का प्रव्यक्त निर्देशित और प्लास्त्रम्य निष्पक्त होता है। यह स्वामाधिक हो है कि यदि प्रव्यक्त ने लोनसमा के ध्रीकारों तथा स्वतनतामी की उत्तित हम् से रक्ता

१. जो० वो० सवसकर—'प्रास्पेबर्स प्राप्त इस्टियन कानस्टोर्युशन' समक जी० गुप्ता द्वारा सम्पादित, १६६४, १० २४६-४७ ∤

828

बरता है तो उसका निर्देगीय होना प्रति-भावस्यन है। सविधान ने लागू विये जाने के पश्चात सत्तारूढ नाग्रेस दल के लिए यह श्रेयस्वर होता, यदि उसके प्रयत्नो से ध्रध्यक्ष का पद निर्देशीय स्वरूप मा विकसित होता । दसगत मामलो की दृष्टि से ही दिसम्बर १६, १९४४, को ब्रध्यक्ष के विरुद्ध प्रविच्यास प्रस्ताय पारित करने वा प्रयत्न दिसा गया था। खत यह प्रत्यावश्यक है नि निर्धाचन के तुरन्त पश्चात प्रथवा समस्त स्वात सवधा नो छोडनर दसगत राजनीति से सत्यास से विषया जाये।

भारतीय ससद की सार्वभौमिकता एव सबैधानिक स्थिति

सभीय व्यवस्थापिका के रूप म भारतीय सभीय समद के लिए, सिवधान के प्रम्तगंत प्रमुच्छेद ७६ में प्रावधान किया गया है। सिवधान के प्रम्तगंत समद को सभीय एव समवतीं पूचियो म उल्लिखित विषय पर विधि निर्माण करने वा प्रधिकार है, और न तिवय विशेव परिस्थितियो म उन विषयो पर मी जो राज्य सूची में हैं। ससद की सार्वमीमिकता ना धिचार विदिश्व सविधान की एक मूल विशेषत है। प्रोठ ए० बी० डायसी के प्रमुसार विदिश सविधान की एक मूल को विशेषत है। प्रोठ ए० बी० डायसी के प्रमुसार विदिश समद की सार्वमीमिकता का विशेषत हुए में स्वष्ट किया गया है।

वानूनी दृष्टिकोण से, ब्रिटिश ससद को साईभौन शक्तियां प्रतीमित है। परन्तु प्रिटिश ससद की सार्वमीमिकता की कतिषय नैतिक राजनीतिक एव प्रत्यराष्ट्रीय सीमाएँ हैं जिनको जिना ष्यान रसे, वह कानूनो का निर्माण नही कर सकती है।

१ ए० यी० डायसी-सा ब्राफ दी कान्स्टीट्युशन, १६३८, पृ० ३७-३८ ।

भारतीय शासन और राजनीति १६२

ग्रत , यद्यपि ब्रिटिश ससद की कानूनी दृष्टि से सार्वमीमिकता ग्रसीमित है, पर यह नैतिक तत्वो जनमत एव सन्तर्राष्ट्रीय नानून की महत्ता से सनीमत रहकर विधि निर्माण नहीं कर सकती है। तथापि ये सारी सीमाएँ, आधुनिक समय मे समस्त जनतीतिक राज्यों की व्यवस्थापिका समाग्रो पर लाग हैं।

मारतीय ससद की सार्वमीमिकना उपर्युक्त नामान्य सीमाधो के ग्रुनिरिक्त हमार लिखित सर्विधान के विभिन्न प्रावधानों द्वारा सीमित है विशेषकर, सर्विधान व उन प्रावधानो द्वारा जिनके संशोधन का एकाधिकार संसद को नहीं है। इन प्रावधाना म स, सपवाद सवधी प्रावधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है । "मारतीय ससद एक मधीय सविधान के ब्रन्तर्गत व्यवस्थापिका समा है। ब्रिटिश ससद के सद्ग इसकी शक्तियाँ असीमित नहीं है।""

मारतीय ससद एक लिखित सविधान का, जो कि देश का सार्वमीम कानून है, तिजु है। ग्रमरीकी प्रणाली के सद्दा मारतीय प्रणाली में दो प्रकार के कानुनी म मूल अन्तर पाया जाता है। सर्वप्रयम देश ने नातून ने रूप मे लिखित सविधान, ग्रीर दिनीय, साधारण कानन जिनका निर्माण सविधान क अन्तर्गत स्थापित विभिन्न व्यवस्थापिका समाध्री द्वारा किया जाना है। अन यह स्वामाविक है कि सर्विमान द्वारा स्थापित विमिन्न व्यवस्थापिकाएँ सर्विधान के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं कर सकती हैं। मारतीय ससद तथा अमरीकी कांग्रेस, दोनों ही की, यही स्विति है। मारतीय मिवयान के अनुन्धेद २४५ (१) द्वारा यह स्पष्ट रूप से बदलाया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग ससद मविधान के धनुसार करमी।

त्यापि ससद, सविधान द्वारा निर्धारित अपने क्षेत्र में सार्वमीम है, परन्त ब्रिटिश ससद की दुनता में इसकी शक्तियों कम हैं। यदि भारतीय ससद किसी ऐने कारन था निर्माण करती है, जिससे सविधान का उल्लंघन होता है तो मारतीय सर्वो च न्यायालय समरीकी सर्वोच्च न्यायालय की तरह, सविधान विरोधी कानन को ग्रवैव घोषित कर सकता है। भारतीय सर्वोच्च स्थायालय द्वारा मान्यता देना प्रावश्यक्ष है। इसके अतिरिक्त, सर्वियान द्वारी यह भी प्रावधान क्षिया गया है कि सर्वोच्च न्यामालय की सहायता के लिए सारे राजनीतिक, मिविल तथा

न्यादिक प्रतिकारी कार्य करेंगे । सर्विपान के लागू होने के पश्चात् कई ऐसे अवसर आपे, अविक सर्वोच्च न्यायालय न सर्विधान ने सरक्षण ने लिए समद द्वारा पारित नितपय नाननो हो ग्रईंग घोषित किया। इनमें से कुछ काननों को उदाहरण स्वरूप ध्यान में लिया द्रा सक्ता है।

१. टी॰ के॰ तोपे~'द कास्टोटयशन भारु इण्डिया ११६३, प॰ २१६ ।

- (१) हमदर दवालाना तथा अन्य बनाम मारत सरकार तथा अन्य सम ससद ने १९४४ में 'द क्षा एष्ट मैजिक रेमेडीज' कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य कतियम, उपचारों ने, जिनके लिए यह कहा गया था दि इनमे जादुर्द गुण है, जिज्ञापन पर रोक लगाना था।
- (1) इस कानून की वैधानिकता को हमदर्द दवाखाना तथा अन्यों ने इस आधार पर चुनीनी दी वि इसके द्वारा अनुच्छेद १६ (१) (अ), और (१६) (१) (एफ), और (जो) से उल्लिखित नानिकों के मूल अधिकारों (भाषण एव अभिन्यितित की स्वतंत्रता और ध्यापार-व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता) का उल्लिखन किया गया। सर्वोच्च स्थामालय ने उपयुक्त बानून के नुख्य हिस्सों को अवैध टहराया। सर्वोच्च प्यापालय के निर्णयानुसार उपयुक्त कानून के माग २ उपस्तव्य (डी) वे द्वारा कार्य-पातिका को असीमित अधिवर्य अपातिका को असीमित अधिवर्य अपातिका को असीमित अधिवर्य अपात्र स्वाप्त की प्रत्योगित विधि की दृष्टि से गतत है।
- (॥) उपर्युक्त कानून के मान ८ को भी न्यायालय द्वारा प्रवैध घोषित किया गया । इस सबध में न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया वि "ध्यवस्थापिका कानून निर्माण जनता की प्रावश्यकतात्रों की पूर्ति के लिए करती है, प्रतएय कानूनी का निर्माण वह उनके उद्देश्य के घन्त्रगंत करती है।""
- (२) यहाँ एक मन्य प्रकरण का घष्यवन वाधनीय प्रतीत होता है। यह प्रवरण है—ए० के० गोपालन वनाम महास राज्य । श्री गोपालन की जो १९४७ से बन्दी थे, निवास्क निरोध मधिनियम १९४० जो सप तथा राज्य सरकारों को निर्दास के बन्दी बनाने के लिए जिसने गारत की प्रति रक्षा, मारत के किसी विद्या से सबस , मारत मा मारत के किसी राज्य की सुरक्षा या शांति क्यसमा भीर ग्रावश्यन सेवाधों को बायम रखने के विरुद्ध कार्य किया है, ग्रादेश जारी करने के लिए प्रविकृत करता है) के भन्यांत उनके विरुद्ध ग्रादेश जारी किया मारा था। इस ग्रादेश की वैधवा को श्री गोपालन ने न्यायालय में चुनीनी दी। उनका जई पा कि निवास्क निर्देश के द्वारा सर्विधान के भनुक्छेद १३, १६, भीर २१ का उल्लंघन किया गया। उपर्युक्त भिवान के भनुक्छेद १३, १६, भीर २१ का उल्लंघन किया गया। उपर्युक्त भिवान के विनास प्रविचान के मानुक्छेद स्वा सरकार मारा कि इस प्रविचान के मानुक्छेद स्वा जा कि निवास्क हुया सानहीं हुया । क्यायाधीकों ने पुक्तत होकर निर्देश स्वाध नियान के निरास प्रविचान मा मार १४ सविधान के विकट है, वर्षीन इसने हारा अनुक्छेद

१ हमदर्वे दवालाना व घन्य बनाम भारत सद्य व ग्रन्य-ए० ग्राई० ग्रार० १८६० एस० सी० ५५४ ।

२२ (४) का उत्तयन निया गया था। भाग-१४ ने धनुसार न्यायालय पर प्रति-बन्ध सम्माया गया कि बन्दी नो भेत्री गई सूचना में उत्तितिन बन्दी बनाने के नगरमों के सबय म न्यायालय द्वारा नोई सादय या बननव्य नहीं लिया जा सन्ता है। "

इस प्रकरण म यह भी स्पष्ट है कि सबद के द्वारा पारित कानून का पुनरस-सीनन कर सर्वोच्च स्वातावय ने इसके एक माग को प्रवेष पीयिन किया। इसी तरह १६६६ म पारित बैन-टाप्ट्रीयकरण कानून के एक माग को सर्वोच्च स्वाया-सन ने भूजेय उदारण।

यत नारतीय सार की सार्वभीमिक्त सिंवचात द्वारा निर्वारित श्रीमाधी म ही वैवानिक रण से उपयोग म लाई जा सरवी है । जैसा, न्यायमूर्ति एस० म्रार० दास ने गोपालन बनाम महाम राज्य में निर्वेष देते हुए बहु। बा—"हुनारे सविचान हारा, दिख्य से विचान के विवर्षते न्यायालयों की सर्वेच्ना को मान्यता ही गई है परलु यह सर्वोच्नता प्रतान सीमित है क्योंकि यह उस व्यवस्थापन क्षेत्र तक सीमित है, वहाँ व्यवस्थापन क्षेत्र के सीमित है, वहाँ व्यवस्थापन क्षेत्र म स्वापालय नामूल के गिरीक्षण के पश्चाल दसको प्रवेष प्राप्ति के साम व्यवस्थापन क्षेत्र म स्वापालय कार्य है वाहर है। इस सीमित सर्वधानिक सीमामो के दायरे के वाहर है। इस सीमित सर्वधानिक सीमामो के दायरे के वाहर है। एक सीमित सर्वधानिक सीमामो के साम से में साम से स्वाप्ति व्यवस्थापन क्षेत्र में साम से स्वप्ति के स्वाप्ति है। "पर्वेष्ठ व्यवस्थापन क्षेत्र को साम से में मान्य के भी क्षात्र को है व्यव के सित प्रतिक

लोकसभा एव राज्यसभा के सम्बन्ध

प्रापृतिक समय म जनतज की सफलता के लिए, विनिन्न देशा ने सता कर विभिन्न प्रकार के जनतानिक प्रवरीमों का उपयोग किया है। इस दृष्टिकोण से व्यवस्थान के सम्बन्ध में दिवस्थानक प्रणाभी को सिद्धान एक महत्वपूर्ण जन-तानिक प्रकार माना जा सकता है। राजनीति विज्ञान का यह एक महत्वपूर्ण सन्द है कि एक व्यक्ति की निरदुष्टला को तुक्ता म बहुसस्थकों की निरदुष्टला स्थाप इंगिकास्त तथा लवस्थांक होंची है। चूंकि जनतानिक राज्य म ध्यवस्थान के कार्य व्यवस्थानिक मार्य व्यवस्थान की

१ ए० के० गोपालन बनाम महास राज्य—ए० खाई० धार० १६५० एस० को० खार० ५६ ।

२. एस॰ धार॰ दास॰ गोपालन बनाम मद्रास राज्य १९५० एस० सी०

है कि इन कार्यों ने लिए व्यवस्थापिका का सगठन द्विसदनात्मक सिद्धान्त पर हो, क्यांकि ऐसी स्थिति में बिना पारस्परिक सहमति के दोनों में से एक सदन प्रपनी इच्छा कानून के रूप म पारित नहीं फर सकेता। यह सत्य है नि श्राधुनिक समय भे द्वितीय सदनों की शक्तियों सीमित कर दो गई हैं परन्तु सभी जनतात्रिन देशों में उच्च सदनों का होना इस बात ना प्रमाण है कि यह वास्तव में जनतत्र के लिए न उच्च सदना का होना हुस वात ना प्रभाग है। क यह वास्तव में अनतन के लिए ने केवल उपयोगी परन्तु मावस्थक भी है। उच्च सदन का मौजिय वेबल दसिलए हो नहीं कि यह निम्म सदन द्वारा जन्दबाओं में पारित त्रृदिशूर्ण प्रस्तावों पर रोक लाते हैं परन्तु मानोवेज्ञातिल दृष्टिकोण में इसके रहते से निचले सदन में यह वेतता जागृत रहती है जि विधि निर्माण में उसका एवाधिकार नहीं है। जानस्टूपर्ट मिल ने व्यवस्थापिता के सगठन के सम्ब घ म दिसदनात्मव प्रणाली की स्नावस्थतात पर कहा है कि उसके मत में सबसे महत्त्वपूण तक मह है वि दिसद-अपने मत को लागू करने वा अधिकार नहीं होना चाहिये। एक सस्या में यदि कुछ व्यक्तियो का बहुमत स्थायी रूप प्राप्त कर लेता है और जिनको सदन मे विजय प्राप्त करने का भारवासन हमेशा मिलता रहता है वे भासानी से निरक्श वन सकते है यदि उनको यह विदित रहता है कि उनके कार्यों के लिए उनको अन्य सोगो की सहमति लेने की ब्रावश्यकता नहीं है।"

जैसा दि देवा जा चुना है भारतीय सभीय ससद द्विसदनात्मक भणाली के तिद्वान्त पर आधारित है। ससद ना निचला सदन लोकसमा, जनता का प्रतिनिधि सदन है जिसमें जनता के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते है। ससद के उच्च सदन, राज्यसमा का सगठन सम्बद्ध से प्रद्यानगृहसर किया गया है। प्रत्यक्षण राज्यसमा मारत सम के विभिन्न राज्यों ना प्रतिनिधित करती है। पर वु राज्यसमा और समर्थकी उच्च सदन सिन्द के सारक में एक सन्तर है, इसके वावजद कि दोनों सदन सपने सच के राज्यों ना प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्यु राज्यसमा और समर्थकों के स्वच के राज्यों ना प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्यु के सार्वे स्वच के प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्यु के सार्वे स्वच के प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्यु के प्रत्यु के प्रत्यु के सार्वे स्वच के प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्यु के सार्वे स्वच के प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वप्तिक स्वच के प्रतिनिधित्व करते के सार्वे स्वच्या से सामान रूप से में ने के सार्वे स्वच्या के साम्यर पर निर्वादित किया गया है।

१ जे॰ एस॰ मिल-'रिप्रजेन्टेटिह्य गर्वमेण्ट' १६८४, पृ० ६७-६८ ।

दिसदनात्मन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रकृत यह पैदा होता है कि दोनो सदनी में क्सि प्रकार के सम्बन्ध होने चाहिया। क्या दोनो सदनो को समान तथा सम-वर्ती ग्रामित होने चाहिय^{े ?} क्या उच्च सदन को केवल एक सलाहकार सस्या के रूप म नार्य करने चाहिय । मारतीय सविधान निर्मानाओं ने इन जटिल प्रश्नो का हल बुद्धिमनापूर्ण तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रस्तुन करने का प्रयास किया है। कुछ मामलो में लोक्समा तथा राज्यसभा को समान खथिकार प्रदत्त किये गये हैं, परन्तु वित्त सम्बन्धी मामनो म बौर कार्पपालिका के उत्तरदाशिय के सिद्धाना नो लागू करने में केवन लात्समा को ही अधिकार प्रदत्त हैं। अनएव भारतीय राज्यसमा की स्थिति अमरीकी सिनेट तथा ब्रिटिश लाउँ समा के मध्य की जा सकती है। राज्यसमा न तो धमरीकी सिनेट के तुल्य शक्तिशाली है और नहीं वह ब्रिटिश लाउँ समा की मौति कमजोर ही है।

राज्यसमा तथा लोकसमा के विभिन्न सम्बन्धां का ब्रध्ययन निम्नलिखित तीन ग्राचारो पर विया था सकता है।

राज्यसभा तथा लोकसभा की समान शक्तियाँ

(क) सिवाय किल सम्बन्धी विषयों के धन्य विषयों पर लोक्समा सथा राज्य समा के समान अधिकार हैं। घन (वित्त) विषेयक को छोडकर धन्य विषय सम्बन्धी विषेयक दोनो सदनो में प्रम्युत किये जा सकते हैं। वास्तव में यह समानता केवल सैदान्तिक ही नही है, परन्तु सरकार ने समयानुमार इस समानना को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिये राज्यसमा में विध्यक प्रस्तुन किये हैं। उदाहरण स्वरूप हिन्दू विवाह (हिन्दू मेरेंड) क्या तलाक सम्बन्धी विषेषक राज्यसमा में ही प्रस्तृत निया गया था। जब तन एन विवेषन दोनो सदनो हारा पारित नही हो जाता, उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए नहीं मैदा जा सकता है। यदि दोनो सदनों म किसी साधारण विधेयक पर समयं है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनो सदनो की मयुक्त बैठक युलवाकर सक्ष्यं का निषटारा किया जा सकता है। सविधान के प्रमुख्देर १०८ के प्रमुमार यदि ससद के दोनो सदनों म किसी विषेषक म समोधन के सबय में समर्प है या ६ माह से अधिर दूसरे सदन में विजेयन प्रस्तुत करने के पश्चात् हो चुने हैं, राष्ट्रपति उक्त विधेयक को विचार तथा मतदान करने के लिए दानो सदना को सयुक्त बैठक मे मेजेगा एव सयुक्त बैठक म पारित विषेपक ससद द्वारा पारित माना जायेगा ग्रीर राष्ट्रपति ने पास उसनी सहमति ने लिए मेजा जायगा। सर्विधान म सयुक्त बैठक का श्रावधान एक रक्षानली के तुन्य है, जिससे दोनो सदन विवाद का निपटारा कर सकते हैं।

ल-राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा उस पर महानियोग लगाने के लिए लोकसभा तया राज्यसमा को समान ग्रामिकार है।

संघीय संसद १६७

ग-संविधान के संगोधन के लिए दोनो सदनों को समान अविकार प्राप्त हैं। य-सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायायाम, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक तया मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पदच्युन करने के सबस्य में दोनों सदनों को समान अधिकार है।

राज्यसभा की वे शक्तियाँ जिनकी दृष्टि से राज्य सभा लोकसभा से कम शक्तिशाली है

व-बित सबवी मामलों के सन्दर्भ में राज्यसमा में एव लोक्समा की प्रिविनयों में सम्पट रुप से प्रन्तर है। मिंववान के धनुन्धेद १०६ वे धन्नर्भन वित्त विधेषक, राज्यसमा में प्रस्तुन नहीं किये जा सकते हैं। वित्त विधेषक देवल लोकसमा में प्रस्तुन नहीं किये जा सकते हैं। वित्त विधेषक लोकसमा में प्रस्तुन विहें भीर उन्हें पार्थित करने के लिए राज्यसमा के प्रमुक्ती सावध्यक नहीं हैं। धनुन्धेद १०६ के धनुसार वित्त विधेषक लोकसमा पारित करती है, उत्तरे प्रकात विधेषक निर्माण पार्थित करती है, उत्तरे प्रकात विधेषक निर्माण पार्थित करती है, उत्तरे प्रकात विधेषक ने राज्यसमा के सुमावों के लिए में वा जायेगा। राज्यसमा के लिए यह धावध्यक नहीं है कि राज्यसमा के सुमावों को सहस्त के सावध्यक स्ति के सुमावों को सहस्त है तो विधेषक ने राष्ट्रपति की सहस्ति वे लिए में बा जायेगा। यदि राज्यसमा हारा दिये गये सुमाव लोकसमा को मान्य नहीं है तो उत्तर विस्त माना जायेगा, विधिम उत्तरे हो सि प्रकात कि स्ति प्रकात कि सावध्यक कर सावध्यक सावध्यक ने सावध्यक ने सावध्यक कर सावध्यक की सावध्यक ने सावध्यक ने सावध्यक ने सावध्यक कर सावध्यक सावध्यक के सावध्यक सावध्यक कर सावध्यक सावध्यक ने सावध्यक ने सावध्यक में सावध्यक ने सावध्यक में सावध्यक कर सावध्यक सावध्यक सावध्यक में सावध्यक ने सावध्यक में सावध्यक सावध्यक सावध्यक में सावध्यक सावध्यक कर सावध्यक सावध्

ल-सिविधान ने धनुसार सधीय मनीमण्डल वा सामूहिक उत्तरक्षायित्व केवल लोकसमा के प्रति है। राज्यसमा को मनी मण्डल के सबब म वोई विशेष प्राक्तियाँ नहीं हैं। राज्यसमा मनी मण्डल के विरुद्ध धवित्रवास प्रस्ताव नहीं रख सक्ती है धौर न ऐसे प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सक्ती है। परन्तु लोकसमा को सविधान के प्रत्योत यह धिवतार प्राप्त है कि मनी मण्डल के विरुद्ध धवित्रवास प्रस्ताव पारित कर उसे स्थान्यन देने के लिए बाष्य कर सक्ती है।

राज्यसमा एव लोलसमा की इन असमानताम्रो के होने पर मी कुछ ऐसे तत्व हैं, जिनके द्वारा राज्यसमा सरकार को निश्चित रूप से प्रमावित कर सक्ती है। वे तत्व निम्मानुसार हैं।

१-मवियान में कोई ऐसा प्राववान नहीं है कि मनियों की नियुक्तियाँ राज्य-समा से नहीं की जाये। अतएव समय-समय पर राज्यसमा से भी मनियों की नियुक्ति हुई है। उदाहरण स्त्रस्य प० गो० व० पन्त, जो राज्य समा के ही सदस्य ये मत्री गण्डल में एक महत्वपूर्ण विमान के मत्री ये (मृहमत्री)। श्रीलातवहादुर्जी हास्त्री के मत्री गण्डल में श्रीमती गांधी राज्यसमा के ही सूचनाएय प्रसारण विमार प्रशी नियस्त की गई थी।

२--राज्यसमा के महत्व का बांसास इस परम्परा से मी प्राप्त होता है कि केन्द्रीय मत्री प्राय राज्य समा में उपस्थित रहते हैं और विचार विमर्श तथा बाद-विवाद में माग लेते हैं।

२—राज्यसमा को उत्पित के समय से ही, सरकार ने राज्यसमा के सदस्यों के मित्रयों से प्रतन पूछने के मित्रयों रो स्वीहत किया है। यह मारतीय ससद की एकं स्वस्य एवं महत्वपूर्ण परन्यर है, जिससे सत्वार तो गीतियो तथा नार्यों का स्वस्थित एवं पहत्वपूर्ण परन्यर है, जिससे सत्वार तो गीतियो तथा नार्यों का स्वस्थी करण राज्यसमा में विचा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा राज्यसमा के सत्वार नी गीतिया की प्रतीत होशी है।

उपमुक्त जिलाबित तक राज्यसमा को सरकार की नीतियो तथा कारों पर स्वस्य तथा जनतामित्र प्रमाब हालने में मदद ग्रुहेंचाते हैं। परन्तु यहाँ यह ध्यान में रखना धारायक होगा कि सरकार पर राज्यसमा ना प्रमाब सोवसामा नी त्वना में बढ़त नम होगा।

राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ

राज्यसमा को सब के राज्या के प्रतिनिधि सदन होने के नाते कतिपय विशेष शक्तियाँ सविधान द्वारा प्राप्त हैं। ये दो प्रकार की हैं।

१—प्रमुख्देर २४६ के प्रत्ननत यदि राज्यसमा यह प्रत्नात बहुमत हारा पारित करती है कि किसी विषय (राज्य सूची मे डिल्लिसित विषय पर मी) पर सबद को राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण नरना प्रावण्यन है तो सबद उत्तर विषय पर सम्प्रण मारत या उसके किसी भू-मान या हिस्से ने लिए विधि निर्माण कर सकेगी।

२—राज्यसमा दो तिहाई बहुमन द्वारा किसी मिखल मारतीय सेवा को स्था-पित करने का निर्णय ले सकती है।

राज्य सभा को उपयुक्त दो शक्तियों ने सन्दर्भ में डा० एन० बी० पायली कहते हैं—'सबैयानिक दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।'' इन दोनो विषयों के सबब में राज्यसमा और लोकसमा की शक्तियों की तुलना करते हुए वह कहते

रै बा॰ एस॰ बी॰ पायली-इन्डिया च कान्स्टीट्युशन १६६२, पृ० १६८।

है—"अत दोनो मामलो में लोकसमा सामने तब ही आती है, जब राज्यसमा निर्णय से चुकी है, और लोकसमा, राज्यसमा के साथ इन दोना परिस्थितियों में निर्णय सेने के लिए हिस्सेदार नहीं हैं। सविवान से इन प्राववानों द्वारा राज्यसमा को सरकारी मणीनरी के एक महस्वपूर्ण हिस्सो न कि विभूषित ढाँचे या प्रमावययन स्म के रूप में निर्मित किया गया है। इतका छोटा तथा फलस्वरूप ठोस, ग्राकार इसका स्वायी स्वक्त, जिसके द्वारा इसके विचारों व कार्यों में स्थापित्वता और निरन्तरता प्राप्त होती है, और इसका विस्तृत प्रावार वाला प्रतिनिधि स्वरूप—पूर सबके द्वारा इसको भविष्य म न केवल एक प्रनिष्ठित, परस्तु लामदायक और प्रमावयील सस्या के रूप में, परन्तु जो समा के समान शिस्तशाली नहीं होगी, स्थापित होने में सहायता सिसेती।"

प्राय सभी ध्राधुनिक जनतानिक राज्यों में व्यवस्थापिका के सदस्यों के स्वतन्न रूप से वार्यों को सम्पत्र करने की शवित पर वित्तप ध्रावश्यक जनतात्रिक ध्रवरोधों वा उल्लेख करते हुए मेकधाइवर कहते हैं वि "इनमें से एक व्यवस्थापिका के दो सदनों के रूप म है, नयोंकि प्रत्येक सदन को एव दूसरे वी सहमति ध्रावश्यक है। बिना इसके विधि का निर्माण नहीं हो सकता है।"

गारतीय सविधान के प्रत्यांत राज्यसमा तथा लोकसमा भी सवैधानिय विकास करा ते यह स्पष्ट है कि भारतीय ससद के दोनो सदन आवश्यकवानुसार एक दूसरे के प्रति जनतानिय अवरोधों के रूप में पूमिया निमा कर वास्त्व में करता भी इच्छा को जासन भी गीतिया तथा कार्यों को साम करा करा के प्रता का महत्व सविधान से सवीधन कराने में समय विदित होता है। इस भूमिका का महत्व सविधान में सवीधन करने में समय विदित होता है। सविधान के सबोधन के लिए दोनो सदनों को समान प्रविचार है। परन्तु परित कर दिया जाता है तो राज्यसमा में सदस्य अपने अनुमत वाधा पर्वचाना पूर्वक पारित कर दिया जाता है तो राज्यसमा के सदस्य अपने अनुमत वाधा परित्वचा वा लाग एक खानियुर्ण ना इरोजारहित बातावरण में, जो प्राय. राज्यसमा में पाया जाता है, उपयोग में बाते हुए, लोकसमा पर किसी मूल सर्वधानिय विधान करने के सर्वों स्वाचान करने के लिए पारित किया था, राज्यसमा में इस विधेय करने पाविधान करने के लिए पारित किया था, राज्यसमा ने इस विधेयक को पादित होने से रोक दिया, क्यों के स्वाच पर स्विधान करने के लिए पारित किया था, राज्यसमा ने इस विधेयक को पारित होने से रोक दिया, क्यों के स्व वस्त जनमत राजाओं के प्रीविपार के सवध में पूर्ण स्वरंप से स्वरंप मारित होने से रोक दिया, क्यों के स्व वस्त जनमत राजाओं के प्रीविपार के सवध में पूर्ण स्वरंप से सवध में पूर्ण स्वरंप में स्वरंप से सवध में पूर्ण स्वरंप में साथ से प्रायं से सवध में स्वरंप से सवध में स्वरंप से सवध में स्वरंप से सवध में सुर्ण स्वरंप से सवध से पूर्ण स्वरंप साथ साथ से सुर्ण स्वरंप से सवध स्वरंप साथ से सुर्ण स्वरंप से सवध से सुर्ण स्वरंप साथ से सुर्ण स्वरंप से सवध से सुर्ण स्वरंप से सवध से सुर्ण स्वरंप स्वरंप से सवध से सुर्ण स्वरंप स्वरंप स्वरंप से सवध से सुर्ण स्वरंप सुर्ण स्वरंप से सवध से सुर्ण स्वरंप स्वरंप स्वरंप स्वरंप से सवध से सुर्ण स्वरंप सुर्ण स्वरंप से सवध स्वरंप से सवध से सुर्ण स्वरंप स्वरंप सुर्ण से सवध स्वरंप सुर्ण स्वरंप सुर्ण स्वरंप सुर्ण सुर्ण सुर सुर्ण सुर

१ डा॰ एम॰ वी॰ पावली—इण्डियाच कान्स्टीट्युशन पृ० १६८ १ २. ब्रार. मेकब्राइवर—'द मार्डन स्टेट, १६२६, पृ० ३०४ ।

तमा को विश्रूपित करते हुए, भारतीय सिवधान निर्मानाधी ने धपनी दूरदियता तथा बुद्धियता वा परिचय दिया। हम को मह बिदित है कि राज्यसमा भीर लावसमा अपने पारस्परिक सबयो में एक दूसरे के प्रति जनताबिक अवरोब के समान तो वार्य कर सबती है, परन्तु राज्यसमा, बोबसमा के रास्ते में एक रीड़े के रूप म एकर उचित रूप से प्राप्त वार्य को क्यों मी क्यों मी हम रही कर सोगी।

म्रारतीय जनतातिक व्यवस्था में, ससद के दोनों सदन एक दूसरे के प्रनिद्वन्दी नहीं, बरन उनतत्र को सफल बनाने के कार्य में सामेदार हैं। झत यह आवश्यक है कि राज्यसमा तथा लोकसमा पारस्परिक सधर्षी का निपटारा इस उद्देश्य को ग्रापन समक्ष रायत हुए करें, कि इन दोनो को जनता के इब्द्धानुसार व्यवस्थापन के कार्य, मान्ति पूर्वक सह अस्तित्व की भावता से प्रेरित होकर करना है। प्रो० भोरित जोन्स का कथन है—"यह स्पष्ट है कि यदि दोनो सदन समान कार्यों को बरने के इच्छुक हैं तो शान्तिपूर्वक सह-ग्रस्तित्व की मावना बनी रहना कठिन है। साध ही यदि इत सदनों की भूमिका में स्पष्ट अन्तर नहीं किया गया तो इनमें प्रतिद्वन्दिता नी भावना वनी रहेगी ...। प्रतिद्वन्दिता, राजनीतिक क्षमता के लिए अत्यन्त हानिकारक है। इसमें जनता की निगाही में समद की प्रतिष्ठा कम त्रापु अद्यान हारानार कहा है। इसने जेनता ने शिनाहर में बन्दे को आपका करें हैं। सबती हैं। "" कविजया मामको से यह प्रतिवादमों पेंडा हो गई हैं कि राजन सजा लाकसा के प्रतिक्षती के रूप में नामें करना चाहती है। सर्वश्रम १६४६ के बढ़ट प्रविवेशन के बीरान दोनों सदनों में नमीर सपर्य हुआ। प्रयीत २६, १९४३ को राज्य समा ने प्रायन्त (स्वीयन) विवेशन पर विवार-विवर्ग प्रारम क्या, जो लाक्समा द्वारा पारित हो चुका था। लोक्समा के अध्यक्ष द्वारा पूर्व मे ही प्रमाणित कर दिया गया था कि यह विधेयक वित्त-विधेयक था, परन्त राज्यसमा के कुछ सदस्यों ने आपत्ति उठाई कि यह विधेयक विता-विधेयक नहीं था। विधि मत्री थी विश्वास ने, जो किन केबल राज्यसमा के सदस्य थे, परन्त् उसके नेता भी, ऐसी स्थिति में कहा-'यदि राज्यसमा को कहा जाता है कि लोक-समा के अव्यक्त ने इस प्रश्न का पूर्णरूप से परीक्षण किया है और विशेषक संबंधी प्रमाण सदन म स्दतत्रता पूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से विचार-विमर्श करने के पत्रवात् ही दिया गया है तो राज्यसभा सन्तुष्ठ हो जायेगी। यगले दिन लाक्समा के एक सदस्य न यह प्रस्तावित करने का प्रयत्न किया कि विधि मनी का बकाव्य श्रीचित्यहीन या तथा अध्यक्ष की प्रतिष्ठा के विरद्ध था। फलस्वरूप सोकसमा के अध्यक्ष ने क्हा कि सदन में इस विषय पर वाद-विवाद के दौरान विवि मंत्री की उपस्थिति बाधनीय होगी । तस्तपश्चात् राज्यसभा मे एक प्रस्ताव पारित किया गया कि सदन का यह मत है कि सदन के नना को निर्देश दिये जाये कि किसी भी

१. डब्लयु॰ एच॰ मोरिस जोना—वार्लियारेन्ट दन दरिसार, १९५७ यू० २९३ ।

हैितियत से वह सोनसमा में उपस्थित न हो। तब सोनसमा में राज्यसमा वे प्रस्थक्ष की प्रोर से एक सदेव पढ़ा गया कि निसी मी, धौर विशेषकर, राज्यसमा के नेता की कमी मी यह इच्छा नहीं थी कि सोवसमा के प्रस्था की सद्यात तथा निप्पस्थता पर मानव पर जीवड कि हो। इस सदन का उद्देश्य (राज्यसमा का) हमेशा यह रहा है कि सोकसमा वे घष्यधा की प्रतिष्ठा का, धौर उस सदन के प्रयास की प्रतिष्ठा को, धौर उस सदन के प्रयास की प्रतिष्ठा की, धौर उस सदन के प्रयास की स्वास तथा की स्वास के प्रदेश की की प्रसास के प्रदेश की परन्तु से स्वास स्वास के प्रदेश की परन्तु से स्वास की प्रतिष्ठा करने की स्वास स्वीप स्वीप

राज्यसमा तथा लोक्समा मे सघर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण मामला, राज्यसमा के कुछ सदस्यो की, राज्यसमा के लिए अपनी प्राकरलन तथा लोरलेखा समितियो की माग सं प्रारम्भ हुन्ना था। उनकी माग थी वि राज्यसमा वे प्रति-निविद्यों को लोक्समा की प्राक्तलन तथा लोक्लेखा समितियों में रखा जाये। जनवरी, १६४३ म राज्यसमा ने इस विषय पर एक सयुक्त समिति स्थापित वरने ने लिए सुफाव लोनसमा नो मेजे गय। साय ही यह मी सुफाव दिया गया कि चूर्कि लोगसमा की लोक्लेखा समिति मे १५ सदस्य तो थे ही समिति में राज्यसमा ने, प्रतिनिधियों नो ग्रीर मिम्मलित नर लिया जाये। तत्पश्चात् यह मामला लोक्समा की नियम समिति को प्रेपित किया, जिसके समक्ष पहले ही ही लोकलेखा समिति वा प्रस्ताव था वि सब्बत समिति, या राज्यसमा वे लिए एक पृथक् समिति का गठन करना सविधान में निहित सिद्धान्तों के विरूद्ध होगा। लोगलेखासमिति वे उपर्यक्त प्रस्ताव मे इसी बात पर बल दिया गयाकि लोग समा के अध्यक्ष को सदन एव लोकलेखा समिति के अधिकारों का सरक्षण करने के लिए बुछ कदम उठाना तथा राज्यसमा को सूचित करना, ग्रावश्यक है कि उसव सुभाव प्रवेधानिक है बयोकि यह लोक्समा के वित्त सबधी मामलो के क्षेत्र म, जिसम लोक समाको सर्वाधिकार है, हस्तक्षेप होगा। लोकसमाकी नियम समिति ढारा उपर्युक्त बात की पुष्टि की गई। लोक समा की नियम समिति ने यह भी वहा कि वित्त क्षेत्र म लोक्सभा का विशेष उत्तरदायित्व है. जिसम यह अन्य किसी वो हिस्सेदार नहीं बना सक्ती है। अन्त में प्रधान मधी ने लोक्समा मे प्रस्तावित किया कि राज्यसमा को लोक्सेखा समिति पर सात सदस्य मनोनीत वरने की धनुमति दी जाये। प्रधान मत्री ने लोक्समा को सबो-धित करते हुए वहा कि इस मामले म लोत्समाकी लोकलेखा समिति का डर वि राज्यसमा वे ग्रधिवारो वा विषटन होगा, ग्राधार रहित है। परिणाम स्वकृष दिसम्बर, १९४३ में उपर्युक्त प्रस्ताव स्वीकृत हो गया थीर पान्यसमा में प्रतितिथियों को नई लोकलिया समिति में सिम्मितित वर लिया गया। राज्यसमा सीर लोकस्ता के गण्य सर्पे होगा। सीर लोकस्ता के गण्य सर्पे होगा। सीर लोकस्ता के मान सर्पे होगा। सीर लोकस्ता में नेता, ने एक मायण के दौरान यह कहा था कि सत्तद हो जा चाहित, व्याविश्वति स्वावद्याह कर रहे हैं। राज्यसमा के स्वयाद ने सिक्त के सीर हो ने सिक्त हो भी त्याद सीर लोकस्ता कर स्वावद्या हो स्वयाद कर रहे हैं। राज्यसमा के स्वयाद ने सिक्त के सी एन सीर लाकस्ति हो सहस्त हो ने सहस्त हो ने सहस्त हो ने सहस्त हो लोकस्ति हो सिक्त करने भी कहा ने तस्त्रस्त हो साम से सारी जानकारी हो सिक्त करने भी एन सीर लाकस्ति हो सिक्त हो सी पत्त ने सिक्त हो सी पत्त ने सिक्त हो सी पत्त ने सिक्त हो सी पत्त हो सी सीर हो सिक्त हो सी पत्त ने सिक्त हो सी सिक्त हो सिक्त हो सिक्त हो सिक्त हो सिक्त हो सिक्त हो स्वया हो सी सीर हो सिक्त हो सिक्त हो सिक्त हो स्वया मा से हा सिक्त हो सिक्त हो स्वया मा से हा सिक्त हो स्वया मा से हा स्वया हो से हा सी सीर उल्लेख स्वत्वी हो सिक्ती नी स्वयं ने स्वया हो सा सा के हा सिक्त हो स्वया मा से हा सा के हा स्वया हो से हा स्वया मा के हा सिक्त हो स्वया मा से हा सा से हा सा से हा सा के हा सा से हा से सा से हा सा से हा से सा से हा से सा से से सा से से सा से हा से से सा से से सा से हा से सा से से सा से सा से से से सा से से सा से से सा से से से सा से से सा से सा से

उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ तक राज्यसभा तथा लोक ज्येचुक उदाहुल्य संबुध्यस्य होता हु। का अहा तत प्रथमध्या प्रथम का सम्बद्ध कर प्रवस्त प्रवस्त प्रविद्या क्षिण के सावकार प्रवस्त है कि दोनों सहस्त प्रतिस्त्यों की मानना स्वाप्कर सरिवान इररा निर्धारित दायरे में एक दूसरे के प्रति सहस्त्रोग तथा सामजस्य की मानना के अनुसार स्वर्ण गामें करें। प्रतेक सदन को, सिवियान द्वारा निर्धारित सीमामों वस्त्र सितानों को प्रयान में रखते हुए सपने दासियों को उपित के उत्तर हुए सपने दासियों को उपित के उत्तर हुए सपने दासियों को उपित के स्वत हुए सपने हमान के उपित हमान के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वत हुए सपने हमान सिवयान के स्वाप्त के स्वत हुए सपने हमान सिवयान के स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त स्वा भन्तर्गत ढाली जायेगी, वह निसी स्थिति में लोकसमा ने, जो कि जनता का सदन है, प्रविकारो स्था दायित्वों के विरुद्ध नहीं ही सकती है। राज्यसमा, जैसा सर सिडनी लो ने ब्रिटिश लार्ड समा ने लिए नहा है—'राजनीति को साघारण चक्रमार्गं से निवास कर उन मूल सिद्धान्तो तथा दूर ने परिणामो पर घ्यान दें जिनके लिए एक व्यस्त जनसमा और दलीय कार्यपालिका को न तो समय, न विचार है।"¹ राज्यसमा मे वाद-विवाद के स्तर पर टिप्पणी देते हुए, 'मोह्नर सीज स्टेटमेन', ४ सितम्बर १९५४ के राजनीतिक सम्वाददाता ने कहा वि राज्य-समा के विद्धले सप्ताह के विदेशी मामली सम्बन्धी वाद-विवाद में विपुलता की भलक पाई जाती है, जो दूसरे सदन के लिए एक उपयोगी बादर्श हो सकती है। सक्षेत्र में, जिन विषयों के लिए लोकसमा तथा राज्यसमा को समान ग्रीध-कार हैं, उनमें राज्यसभा लोकसमा से समान अधिकार की माग कर सकती है, परन्तु जिन विषयो के सम्बन्ध में सविधान द्वारा राज्यसमा को लोकसमा की भपेका सीमित शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं या कोई शक्तियाँ नही दी गई हैं उनके सम्बन्ध मे राज्यसमाको लोक्समाके साथ प्रतिस्पर्धाकरना अनुचित होगा।

१ सिडनो० लो-'द गर्वनेग्स ब्राफ इंग्लेण्ड, १६३१ पूर २५०।

जनतत्र में निम्न सदन, उच्च सदन वी घ्रपेशा मक्तिशानी होता है घोर उच्च सदन के घ्रस्तित्व का ग्रीवित्य केवल इसी बात में है जि वह निम्न गदन पर विवेश पूर्ण प्रमाव डोले। घरि राज्यसमा जो इस मूल बात वा ग्रहसास हो जास है तो मबिष्य में दोनो सदो। के मध्य सपर्य की स्थिति बहुत कम पैदा होगी।

सघ ससद की शक्तियाँ

भारतीय सतद की प्रक्तियों का क्षेत्र संघीय निधित सविधान द्वारा सीमिन है। ससद द्वारा निर्मित कानूना का न्याधिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानन की बैधता या प्रवैधता निर्धारित वरने के लिए विया जा सकता है। तथापि तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय सबीय ससद की शक्तियाँ घन्य सबीय व्यवस्थापिकामी की मपेक्षा मधिव है। ममरीवी वाग्रेस तथा मास्ट्रेलियन ससद राज्य सम्बन्धी विषयो पर बानुन निर्माण नहीं बर सबती हैं। परन्तु भारतीय ससद को वृतिषय परिस्थितियों में राज्यों वे लिए वातून निर्माण रुप्ते वा श्रीधवार है। उदाहरणार्थ, स्रनु-देद २५३ ने मन्तर्गत निसी सिध या समभीते नी लागू वरने के लिए सप्तद बानून िर्माण कर सबती है, अनुच्छेद २५० वे अन्तर्गंत सक्टबालीन स्थिति मे सप्तद सम्पूर्ण देश वे लिए कानून वा निर्माण गर सकती है। सविधार म भारतीय ससद री शक्तियों का उल्लेख किसी एक श्रव्याय में नहीं निया गया है। सविधान ने भाग पाँच क ग्रध्याय तीन म जिसमें ससद के समहन. श्रविवारियो, सदस्यो की श्रयोग्यताएँ व्यवस्थापन तथा वित्त प्रत्रियाए उल्लिखित हैं. ससद की सारी प्रक्तियो एव कार्यों का उल्केख नहीं है। इन सारी प्रक्तियों को सविधान के विभिन्न हिस्सों के ग्रह्मयन द्वारा ही मालम किया जा सकता है। चैनि मारत मे ससदीय प्रणाली स्थापित वी गई है, ब्रत यह सरलता पूर्वंव वहा जा सकता है कि मारतीय ससद के कार्य, उन देशों की ससद के तत्य हैं. जहां ससदीय प्रणाली प्रचलित है।

भारतीय ससद की प्रक्तियों तथा कार्यों का, निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों हे रख कर, प्रव्ययन किया जा सकता है।

१-व्यवस्थापन, २-कायपालिका वा ियन्त्रण, ३-न्यायपालिका से सबिधत शक्तियाँ, ४-वित्त सम्बन्धी शक्तियाँ और ४-म्प्रन्य शक्तियाँ।

स्वयस्वापन सम्यत्यो मास्त्रयो—सविधान के अनुम्हेद २४४ (१) वे अनुसार समझ, सविधान ने प्रावधाना ने प्रावधान सम्पूर्ण भारत या इसने निशी भी हिस्से ने खिए, तथा राज्य विधान समा सम्पूर्ण राज्य या इसने निशी भी हिस्से ने लिए विधि ना निर्माण कर सनती है। इसी तरह अनुम्हेद २४६ (१) के अनुसार समझ नो सविधान नी सातवी अनुसूची मे उल्लिखित प्रथम सूची (सथ सूची) मे उल्लिखित विषयी पर मानुन निर्माण का अधिनार है।

ग्रनुच्छेद २४६ (२) के ग्रनुसार ससद को सविधान की सातवीं ग्रनुसूची मे उल्लिखित तीसरी सूची (समजर्ती सूची) मे उल्लिखित विषयो पर विधि का निर्माण करने का अधिकार है। धनक्छे- २४६ (३) के धनुसार किसी भी राज्य की विधान समा को राज्य या राज्य के किया। मी हिस्से के तिए, सविधान की सातवी ग्रनुसूची भ उल्लिखिन, हुसरी मूनी (राज्य मूनी) मे उल्लिखिन विषयो पर विधि वा निर्माण वरन का ग्रविकार है।

सक्षेप मे, मारतीय सविवान द्वारा तीन व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचियो का निर्घारण किया गया है, जिनका उल्लेख सविधान की सातवी अनुसूची में है ।

(क) सघसुची-जिसमें ६७ विषय हैं, जिन पर देवल सघ ससद विधि निर्माण कर सकती है।

(स) राज्य सुनी-जिसमे ६६ विषय हैं, जिन पर साधारणतया, नेवल राज्य

विवान समा ही विवि का निर्माण कर सकती है। और. (ग) समवर्ती सुची-जिसमे ४७ विषय हैं, जिन पर दोनो, ससद तथा राज्य विधान समा को विधि निर्माण करने का अधिकार है। अनुक्छेद २४४ (१) के

यनुसार यदि राज्य विधान समा द्वारा निर्मित निसी विधि का, निसी प्राथयान भा, सप ससद द्वारा निर्मित विधि के निसी प्राथघान से समर्प होता है तो संघीय विधि मान्य होगी और जिसे हद तक राज्य विधि का सधर्य सधीय विधि से है, उस हद तक राज्य विधि को अवैध माना जायेगा । परन्तु अनुच्छेद २५४ (२) के ग्रनसार गर्दि समवर्ती सबी में उल्लिखित विषय पर निर्मित किसी राज्य विवि का सपर्य, सभीय ससद द्वारा उसी विषय पर निर्मित विधि से हैं, और ऐसी राज्य विवि को राष्ट्रवित द्वारा सहमति प्राप्त हो गई है तो राज्य विधि को ही मान्यता प्राप्त होगी, परन्त साथ ही उक्त विषय पर निमित राज्य विधि मे जोडने. संशोदन, परिवर्तन या उसे समाप्त करने हेतु विधि पारित करने का अधिकार ससद में निहित है।

सविधान के ग्रनुक्देद २४६ (१) के ग्रनुसार उपरोक्त तीन सुवियो द्वारा शक्ति ने विभाजन ने पश्नात् सर्वाशिष्ट सक्तियाँ सघ ससद मे ही निहित है।

निम्नलिखित कुछ विशेष परिस्थितियो में सथ समद राज्य भूची सम्बन्धित

विषयो पर विधि निर्माण कर सक्ती है। क-जब राज्य समा द्वारा दो-तिहाई बहुमत के ग्राघार पर अनुच्छेद २४६

के ब्रनुसार प्रमाणित कर दिया है कि राज्य सुबी मे उल्लिखित किसी दिएय का महत्व राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, परन्तु राज्यसमा का प्रस्ताव एक वर्ष से ग्रचिक समय तक नहीं रह सकता है।

स-अनुच्छेद २५० (१) के अन्तर्गत सब ससद सम्पर्ण देश या उसके विसीट दिस्ते ने लिए सनदरातील रियति में नातन नगा सनती है ।

ग—प्रतृच्देद २५२ (१) के प्रनुसार यदि दो या दो से प्रधिक राज्य की विधान समाधों को वाएनीय है कि उनके सम्बन्ध में, सस ससद राज्य सूची में उल्लिपित किसी विवय पर विधि का निर्माण करें। ससद को उन राज्यों के लिए फीर मनिष्म में ऐसे राज्यों के लिए मी जिनकी विधान समाधी में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित निर्मे गय है, विधि निर्माण करने वा प्रधिकार होगा।

मारतीय सविधान के झन्तर्गत मिक के विभाजन की विशिष्ट प्रत्रिया ध्रवनाने के पत्तस्वक्ष यह स्पष्ट है कि समद को प्रत्यधिक मिक्तपाँ प्राप्त हुई हैं। सविधान के अनुब्देद २४६, २४६, २४६, २४६, २४६, २४, तथा २४३, सधीय सिद्धान्त के बावजूद मी, भारतीय सधीय व्यवस्था के झन्तर्गत सथ ससद को एक प्रक्तिगासी सहया बनाने मे सहायक हुए हैं, जिससे राष्ट्र की बुनियादी एकता के डीचे को स्था बनाने मे सहायक हुए हैं, जिससे राष्ट्र की बुनियादी एकता के डीचे को स्था बनाने म

ससद मी व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियों की ऋतक ससद म विधि निर्माण प्रश्निया में प्रतिविभ्नित होती हैं । सविधान में विधि निर्माण प्रश्निया के सम्बन्ध म कोई विस्तृत उल्लेख नहीं हैं । साधारण विधेवकों को (चित्त विधेवकों को छोड़ कर) सित विधेवकों को सित विधेवकों को छोड़ कर) सर के किसी मी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। श्रीर एक विधेवक को सद हारा पारित तभी माना जायेगा, जन विधेवक दोनों सदनों म पारित हो चुका है। ससद के किसी भी सदन में समक्ष विचार के लिए विधेवक ससद के स्थापत होने से समाप्त नहीं हो जायेगा। थोकसमा के विध्वन संस्त्र के स्थापत है, या जो उससे पारित होकर राज्यसभा को गया है, समाप्त हो जायेगा, परन्तु एसा विधेवक निसकों उपयों राज्यसभा में हुई है, लोकसमा के विधवन समाप्त नहीं होगा। यदि लोकसमा के विधवन से पुन राज्यसभा में हुई हो, लोकसमा के विधवन से समाप्त नहीं होगा। यदि लोकसमा के विधवन तही होगा। स्विध्व लेकसमा के विधवन तही होगा।

संसद द्वारा विधि निर्माण करने के लिए सविधान में नेवल उपर्युक्त वातो वा हो उस्तेल हैं। निधि निर्माण प्रश्निया ने भ्रतनोत्त भरण वातो हो ससद ने नियमों के अनुसार निर्पारित निया गया है। इन नियमों ने अन्यर्गन दोनों सदनों ने लिए समान विधि निर्माण प्रत्रिया का निर्मारण निया गया है। बदन म प्रत्येन विध्यक्ष ने निर्माण निया प्रत्ये ने सावर में प्रत्ये ने सावर में स्वयं सदस्य के तीन वाचन होने चाहिये। साधारण विध्यक्ष को निसी मनी या प्रत्य सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत साधारण विध्यक्ष सरना में प्रस्तुत निया जा सकता है। मनी द्वारा प्रस्तुत साधारण विध्यक्ष सरनारी विध्यक कहाता है, जब कि साधारण सदस्य द्वारा प्रशासित विद्यक्ष को तथा साधारण सदस्य विध्यक को विध्यक्ष का स्वर्णा साधारण सदस्य विध्यक को विध्यक्ष का स्वर्णा के साधारण सदस्य विध्यक को लिए पाव चरणों को पार करना होता।

प्रथम याचन-सदन में जिथेयन का प्रस्तुनीवरण ही प्रथम चरण (स्तर) है। सदन के सर्विदालय नो विधेयन की एक प्रति सुपुद वरना होता है। तस्परवात

वो सदन मं प्रन्तुत करन की ग्राज्ञामागता है। इस पर ग्रध्यक्ष खडे होकर कहना है कि विधियन को प्रस्तुत किया गया है। बास्तव में विधेयक का प्रस्तुतीकरण एक ग्रीपचारिकता मान है। प्राय परम्परात्मार इस स्तर पर विशेषक के सबेब म बोई बाद विवाद नहीं होता है। परन्तु पूर्व म, बुछ परिस्थितिया में इस स्तर पर विवेदत का विराध किया गया है। यदि विजेदक का विरोध सबैधानिक द्याधार पर क्या गया है तो श्रष्यक्ष बाद-विवाद के लिए बनुमति दे सकता है।

विवेधन के प्रस्तुतीकरण के पश्चात, उसका प्रकाशन भारतीय गजट में कर दिया जाता है। दितीय बादन-विवेयक के प्रस्तृतीकरण के दो दिन पश्चान ही दितीय वाचन प्रारम्म होता है। यदि श्रव्यक्ष की राय में विवेयक का अत्यधिक महत्व है, तो

प्रस्तुतीवरण वे तुरन्त बाद, द्वितीय वाचन प्रारम्भ विया जा भवता है । द्वितीय वाचन के दौरान विश्वयक सबधी प्राप्त जानकारी तथा सम्भव के सक्षिप्त रूप मदन के सदस्यों के उपयोग के लिए वितरित किये जाते हैं। यदि प्रध्यक्ष प्रनुमति देता है तो उस विदेशक पर बाद विवाद हो सकता है, परन्तु यह विस्तृत रूप से

नहीं होता है। यह चर्चा देवल विषेषक के मूल मिद्धान्ती, मूर्घ्य उपवन्धी तक ही सीमित रहती है। प्रस्तावक सदस्य विवेयक को प्रवर मामिति मा दोनो सदनो की समक्त समिति को भेजने के लिए प्रस्ताय कर सकता है। क-समिति स्तर-मारतीय ससद मे बेवल महत्वपूर्ण तथा अटिल विघेयको को समिति के पास मेजा जाता है। प्रवर समिति के सदस्यों की सख्या २० से ३० तक होती है। प्रवर समिति म सत्तास्य तथा विपक्षी दली व सदस्य होते हैं। प्राय सत्तारुढदल के सदस्याकी सख्या ग्राधिक होती है। समिति में

विजेयन पर गहराई से विचार-विमर्श होता है। विधेयन के उपवन्धों में संशोधन भी लाय जा मनत हैं। यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति या कागजात की ग्राव-श्कता होती है तो प्रवर ममिति इसकी भाग करती है। जनता या बेस प्रतिनिधि अँटको में प्रदेश नहीं दर सबते हैं। धन्त म समिति अपना प्रतिवेदन सदन को भेजती है, जो प्रकाशित विद्या जाता है।

स-प्रतिवेदन स्तर-जैसा देखा जा चना है, समिति नो निवेयन ने सन्वय में अपना प्रतिवेदन भेजना आवश्यक है। सामारणतया प्रतिवेदन की तीन माह के अन्दर भेजना बावश्यक है, परन्तु यदि सदन द्वारा कोई समयावीय निर्धारित कर दी गई है तो समिति को उसके अन्दर ही प्रतिवेदन देना होगा। प्रतिवेदन शर समिति के प्रध्यक्ष में हस्ताक्षर होना प्रावश्यक है। प्रतिवेदम स्तर के दौरान

विधेयक पर गहराई से बाद विवाद होते हैं। विधेयक के प्रत्येक माग पर बाद-विवाद होता है तथा संशोधन प्रस्तृत विये जा सकते हैं। बाद विवाद के पश्चात् विधेया ने प्रत्येव माग और सक्षोधन पर मतदान होता है। यहमत से विधेयन तथा उसमे विभिन्न समोधनो वे स्वीवृत होने पर, विधेयक सदन में विधि-निर्माण-प्रक्रिया के प्रन्तिम चरण पर पहुँचता है।

तृतीय याचन-सदन में विवेधन पर तृतीय वाचन, उत्तना प्रतिम चरण है। इस मन्तिम चरण म विधेयक के सप्रध म यह प्रस्ताबित किया जाता है कि उसे पारित विया जाये। इस समय विधेयक पर गहराई से विचार विमर्श नहीं विया जाता है। परन्तु विधेयव वे पक्ष या विपक्ष म तब प्रस्तुत विये जाते हैं, तथापि इस स्तर में लम्बे मापण नहीं होते हैं। यदि उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विधेयक पारित हो जाता हैं तो उसे सदन द्वारा परित माना जायेगा। अन्त मे विधेयक को इसरे सदन में मेजने के पूर्व सदन के ग्रध्यक्ष या सचिव द्वारा विधेयक था प्रमाणीवरण होना श्रावण्यव है।

दूसरे सदन में भी उसी प्रकार की विधि-निर्माण प्रक्रिया का अनुसरण होगा, जिस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग पहले सदन में किया गया था। दूसरे सदन के समक्ष दो विकल्प हैं। प्रथम, विधेयन को उसी रूप में पारित करना जिस रूप में वह पहले से उसके समक्ष आया था। दितीय विकल्प विधेयक में समीपन करना है। ऐसी स्थिति में विधियन पुन पहले के सदन वे समक्ष मेजा जायेगा। यदि दूसरे सदन द्वारा प्रस्तावित संशोधन वे फलस्वरूप दोनों सदनों में मतमेद उमरते हैं तो ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति दोनो सदनो ना सयुक्त ग्रथिवेशन ग्रामत्रित नरेगा, जिसना समापति लोर सर्माना भ्रध्यक्ष होगा। इसं प्रकार की समुक्त बैठक मे साधारण बहुमत द्वारा ही विधेयन पारित निया जा सकता है। स्पष्ट है नि लोन सभा के सदस्यों भी सख्या राज्यसमा ने सदस्यों के लगमग दुगुनी होने के बारण, लोक समाका भत ही भ्रन्तिम होगा।

दोनो सदनो द्वारा पारित होने ने पश्चात्, विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीवृति में लिए मेजा जाता है। राष्ट्रपति वे समक्ष दो विवरूप है। पहला यह उस विधेयक को स्वीवृति प्रदान कर दे जिसके फलस्यरूप विधेयक विधि के रूप में प्रगी-कृत हो जाता है। द्वितीय राष्ट्रपति अपने सुभावो सहित, विधेयक को ससद के पुनविचार के लिए लौटा सकता है, परन्तु ऐसी स्थिति मे, यदि विषेषक ससद द्वारा पुन पारित विया जाता है, तो राष्ट्रपति वे सुफाव सहित या विना उन सुफावो में पारित करना होगा। ऐसे विवेधकों को राष्ट्रपति धनुमति देने के लिए बाध्य

होगा। राष्ट्रपति वो स्वीटति से विदेवन, बिकि से परिवर्तित हो जावेगा। साधारण-सदस्य-विदेवन (प्रायव्हेट मेम्बर्स विल) सत्रमी विधि निर्माण प्रक्रिया बीर उपरोक्त उदिनतित सरवारी साधारण विधेयन विधि निर्माण मे थोडा-सा ही

प्रनत् है। साधारण-सदस्य-वियेवक को साधारण-वियेवक समित (प्रायल्हेट विये-यक समिति) के पास में वा जाता है। १६५३ में इस समिति को स्थापित किया यात्रा था। इस समिति में प्रध्यक्ष सहित १५ सदस्य होते हैं। समिति के प्रध्यक्ष को सदस के प्रध्यक्ष मनोनीत करते हैं। समिति के प्रतिवेदन की प्रतियों को सदस्य के सदस्यों को वितित्त किया जाता है। यही वियेधक का सदस्य में स्पेन्यारिक प्रस्तुनिकरण है। इसके बाद वियेधक को पारित करने के लिए उदी प्रतियां के उपयोग में साथा जाता है, जो सरकारी साथारण (प्रतिदिधि) वियेधकों के निए उपयोग में साथा जाता है, जो सरकारी का स्वरत्य-वियेधक को पारित करने के लिए, प्रस्तुत्वतां को सरकारी सदस्यों के सहस्योग की निरस्तर प्रावस्यक्ता रहती है, उनके सहस्योग के बिना साथारण-सदस्य वियेधक (प्रायल्हेट मेम्बर्स विव) के पारित

कार्यपालिका को नियन्त्रण करने सबधी शक्तियाँ

ससद की कार्यपालिका सबयी शक्तियों के मुख्यत तीन स्रोत हैं, जिनके भाषार पर ससद कार्यपालिका का नियन्त्रण करने में समर्थ है।

सर्वप्रयम, प्रमुन्धेद १६ के घन्तर्गत संसद के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन संस्था का एक हिस्सा है। प्रारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रमुन्धेद ६६ के घन्तर्गत, ससद के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन संस्था के सदस्य होते हैं।

हिनीय, ससद की एक घन्य, परन्तु सक्रियात्मक तथा प्रमावपूर्ण शक्ति का उल्लेख सविधान के प्रनुच्छेद ६१ में क्यि भया था है, दिसके प्रनुक्षार ससद राष्ट्र-पित को सविधान का उल्लेखन करने के लिए महामियीन लगाकर पदच्युत कर सकती है। उपराध्युपति को भी ससद इसी कारण से महामियीन हास पदच्युत कर सकती है।

कर सत्ता है।

गुनीय, गार्यपालिका को नियम्तित करने की दृष्टि से, सबद को सबने प्रायक्त

गुनीय, गार्यपालिका को नियम्तित करने की दृष्टि से, सबद को सबने प्रायक्त

गहरवर्ष्ट्रण प्रतित संधीय मंत्रीमण्डल के सबस में है। अनुकोर ७४ (३) के

अन्तर्नात संधीय मंत्रीमण्डल का सामृहिक कर से उनारपालिक सबद के निवाले

प्रदान सोकसान के प्रति है। मंत्रीमण्डल के विश्व प्रतिकार प्रविद्वाना पार्टित

कर, वोकसाना जमे स्थान पत्र देने के निष्याप्यकर सकती है। इसी तरह

लोकसाना मनी मण्डल होया प्रतानिक सकर हो भी पारित करने से इन्यार

कर, सकती है निकके पत्रस्वरूप, मंत्री मण्डल को अपना साम्यण्य देना

होगा। सविधान के अनुकोर ७४ (३) में, धारत्यक म, वह भाषारपूत सिदान्य

निहित है, निवाके मण्डलरूप, पत्री मण्डल मोर्यान साम्यार्थ, सिदान्य

निहित है, निवाके मण्डलरूप, पत्री मण्डल मोर्यान साम्यार्थ स्थान

सप्तरीप प्रणाली में, मुत्रीमण्डल की स्वामी है। सनीमण्डल के लोकसमा के प्रति उत्तरवायित्व के सिद्धान्त को विभिन्न प्रकार से कार्योन्वित किया जाता है, जैसे मत्रियों से सदन म प्रका पूछ कर, स्वयन प्रस्ताव रखकर, इत्यादि ।

सरकार वे तीनो ध्रमो पर विशिष्ट जनतात्रिक प्रवरोधो की श्रावश्यकता के सिद्धान्त के प्रनुसार प्रत्येक प्रम के सबस म जनतात्रिक प्रवरोधो के रूप में कुछ मितवारों उपलब्ध होनी चाहिये जिनसे सरकार के तीन ममो के वास्परिकं सबधो वा निर्धारण जनतात्रिक ध्राधार पर किया जा सके। मारतीय सिवधान निर्माताक्षों ने इस सिद्धान्त का अधुकरण करते हुए सच ससद को न्यायपात्रिका के सबय म मुद्ध लिक्तयाँ प्रदक्ष की है प्रीर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सबस में कुछ शक्तियाँ प्रदेश दे हैं जो राष्ट्रपति वे सबस में कुछ शक्तियाँ प्रदेश दी हैं और राष्ट्रपति वेस उपराष्ट्रपति के सबस में कुछ शक्तियाँ प्रदेश दी हैं ओ न्यायिक प्रक्तियों के रूप म हैं। वे निम्नावित हैं।

(क) सविधान के अनुच्छेद १२४ न अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मे एक मुस्य-त्यायाधीय तथा सात अत्य न्यायाधीय होंगे। परन्तु ससद को न्यायाधीयों की सस्या मे वृद्धि करने ना अधिनार है। अत, ससद ने सर्वोचच न्यायाधीयों की सस्या १६६६ पारित कर न्यायाधीयों की सस्या, मुख्य न्यायाधीय को मिलाकर, ११ निर्धारित कर दी है। न्यायाधीयों की नियुक्ति राष्ट्रपति वरता है।

ग्यायाधीशो नो पदच्युत करने स संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसी न्यायाधीश को पदच्युत राष्ट्रपति के धादेशानुसार ऐसी स्थिति मे ही किया जा सकेगा, जब सक्त का प्रत्येक सदन न्यायाधीश नो उपने दुव्यंवहार या ध्रवासता के कारण पदच्युत करने के लिए सदन की सारी सदस्यता के वहुमत से एक प्रस्ताव पारत कर दता है। सत्तर को अधिकार है कि त्यापाधीश ने दुव्यंवहार या ध्रवन्मता को साबित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रत्रिया का निर्धारण करे। यहाँ पर सत्तद की भूमिका के दे पद्यो पर बल देना आवश्यक है। सर्वप्रयम, विना सत्तद की भूमिका के दे पद्यो पर बल देना आवश्यक है। सर्वप्रयम, विना सत्तद के प्रस्ता वारित किये हुए, राष्ट्रपति क्षेत्रस्ता होती भी न्यायाधीश को पद- च्युत नहीं कर नकता है। हितीय, सतद की यह शक्त त्यायाधीश के प्रतुत्तरदायी व्यवहार को रोकने के लिए एक प्रमावशील करताजिक स्वतरोध के सदस है।

(य) ससद को सर्वोच्च न्यायालय ने क्षेत्राधिकार मे, प्रतुच्छेद १३६ के प्रतु-सार, वृद्धि वरने ना प्रधिवार है। ससद सर्वोच्च न्यायालय को, सभीय सूची मे उत्तिखित विसी भी विषय ने सबय मे प्रतिस्थित क्षेत्राधिकार विधि द्वारा प्रदत वर सकती है।

यदि मारत सरनार और निसी राज्य सरकार के मध्य सर्वोच्च न्यायालय को निसी विषय के सवय मे प्रतिरिक्त क्षेत्राधिकार प्रदत्त करने वे लिए समक्रीता हुपा है घोर सप्तद कानून हारा प्रपनी सहमति देती है, तो सर्वोच्च न्यायालय को उक्त विषय पर क्षेत्राधिकार होगा। प्रमुच्देद १३६ के प्रमुसार सप्तद सर्वोच्च स्यायालय को, उन उहेश्यों के मलावा जो मनुष्युद्ध २२ (२) में विणत है, बन्दी प्रताक्षीकरण, परमादिश प्रतिपेग, उत्तेषण भीर प्रियमगर-पृथ्य ध्वारि केल, लागू करने वा भाषिकार प्रयस्त पर सहसी है। मन्त्री मृत्युद्ध ११० के प्रतानंत यदि सबद मावश्वन या बाधभीय समभती है तो सर्वोच्च न्वायालय को ऐसे म्रतिश्वन प्रविकार, जो सर्विकार के मनुद्दत है, मध्ये काशों को म्रमावपूर्वक वरते के लिए प्रशान करेगी।

(म) राष्ट्रपति पर सविधान का उस्तम्म करने के लिए महामियोज तथाइन्द्र, उसे परन्तुन करने की प्रतिक सतद को एक प्रकार की न्याविक मार्कि है। राष्ट्रपत्र पर महामियोण चताने के लिए सत्तक कि किसी भी स्वत हारा प्रारोण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रारोप लगाने के लिए सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर प्रोर १४ दिवस पूर्व की विशिक्ष पूचना होना भी प्रावच्यक है। इसके स्वतिरक्त, प्रस्ताव की सत्तर की सारी सदस्यता के यो-तिहाई बहुमत से पारित विधा आगा चाहिये।

. जब द्यारोप का प्रस्ताव ससद के एक सदन द्वारा पारित हो जाता है सब दूसरा सदन झारोपो की जाच करेगा। राप्ट्रपति को ऐसी स्थिति मे उपस्थित होने हुतरों सतन भारता का जाय करता। रिष्टुशान का पूर्वा स्थान स्थान व उतास्यत हुए मा स्थान में उतास्यत हुए मा स्थान म मा स्थान मंत्रितिस्य करवाने का यूर्च प्रियम्पट है। यदि इसने सतन द्वारा भ्रारोगों के जांच के फलस्वस्य स्थन भी सारी सदस्यता के दो-विहाई बहुमत द्वारा प्रसाव पारित दिया जाता है कि राष्ट्रपति के विद्या द्वारोग सही है तो प्रसाव के पारित निये जाने के समय से राष्ट्रपति को परस्युत सममा जातेगा। राष्ट्रपति को महामिश्रोम तमा कर पदस्युत करते श ससद मा प्रियमत, राष्ट्रपति है निरदुश दाने की प्रयूति पर एक महत्यूप्रा कनतानिक सबगेष है, परस्युत्तिव्यान निर्मादायों का ध्यान एक गमीर नुटिकी धोर नहीं धार्कायत हुखा। इस कारण कतिपय परिस्थितियों में राष्ट्रपति पर ससद का उपर्युक्त झबरोय प्रभावहोन हो सकता है। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पर महामियोग तब ही समव है जब ससद की बैठक हो रही है, यदि समय की बटक नहीं हो रही है और राष्ट्रपति ऐसे समय सिधान का उल्लामन करता है तो यह स्थामानिक है कि अपने उत्तर महामियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति ससद की बैठक क्दापि नहीं बुलायेगा। ग्रनुच्छेद ८४ (१) के अनुसार ससद के अधिवेशन बुताने का अधिकार राष्ट्रपति का है। अत यह अत्या-वश्यक है कि इस सदर्भ म सविधान वा उचित संशोधन किया जाये । अनव्हेद ८५ (१) वासमोदन वर ससद वाद्राहुत वरने वे लिए न केवल एक उचित प्रणाली को ग्रपनाया जा सकता है, परन्तु कार्यपालिका पर ससद के एक जीवन विहीन अवरोध को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। प्रो० टी० के टोपे का सुकाव है, "तयादि, एक वैद्यानिक उपचार, सनिधान सशोधन करके और प्रावधान करके कि समद ना प्रधिवेशन, वर्ष में एक निश्चित दिन स्वत आहत हो. रखा जा

सकता है। यह घमरोजी सविधान में जिया गया है। समबत तोर नमा वे प्रव्यक्ष को सप्तर ने दोनो सदनों को ब्राहुन करते के लिए प्रधिष्टन विया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति सप्तर को बैठक को, घष्ट्यक्ष की प्रार्थना करन पर मी नहीं बुलाता है।"

विसीय शक्तियाँ—गविधान के अन्तर्गत देश की बित्त व्यवस्था पर मसद का पूर्ण प्रधिकार है। जनतानिक राज्य म विदा व्यवस्था मिन मा। (मनद) की अनुसार के कोई कर नहीं सगाया जः सक्ता। मारत म मनद द्वारा दिसा व्यवस्था पर नियन्त्रण, ब्रिटिश ससद के उस देश की वित्त व्यवस्था पर नियन्त्रण, ब्रिटिश ससद के उस देश की वित्त व्यवस्था पर नियन्त्रण के महत्त्रल है।

सर एरस्तीन मय सबद द्वारा ब्रिटिस बित व्यवस्था व नियन्त्रण के मिद्धान्त वा उल्लेख इस तरह वरते हैं—"ब्रिटिश ब्राउन वो मित्रयों को सनाह ने अनुमार वार्यपालिका अधिन होने के नाते, देश की आध और लोग्सेवाओं पर व्यव का प्रवाय करते वा उत्तरदायित्व है। यत ब्राउन सर्वप्रयम, कामन्स समा वो सरकार की जिल सबयी आवश्यवत्यों को यूप करने के लिए प्रावश्यक जानवारी प्रदत्त वरता है। इस तरह प्रावज द्वारा वित्त की माग की जाती है और वामन्स समा प्रपत्नी सहमति प्रदत्त करती है।"

ब्रिटिश परम्परा के अनुकूत सारत में, समद को कार्यगतिका की वित्त समयी माना को न्वीकृत करन का अधिकार है। समिवान के प्रन्तर्ग प्रत्येक वित्तीय वर्ष राज्यति समद के समझ, वाधिक वित्तीय अनुमान प्रम्तुत करवायेगा, जिसम सच सत्वार के वित्तीय वर्ष के निष्ठ प्रमानित आध-व्यय का उन्तेन होता है। व्यय को दो वर्षों म रसा जा सकता है।

(क) मारत की सचिन निधि में प्रदेशित व्ययं, और (ख) ग्रन्थ व्ययः। मारत की मीचन निधि में निम्नलिक्षिन विषयोसप्रधी व्ययः वा उन्लेप हैं:----

१--राष्ट्रपति पद के विसीय लाम, मत्ते, तथा व्यय ।

२ — लोब समावे प्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष धौर राज्यसमा वे समापति लया उप समापति वे बेनन तथा मत्ते ।

रे.—मारतीय सरवार वे ऋण तथा उतना व्याज, निशेष निशि व्यय, निष्त्रमण व्यय तथा ऐमे व्यय जो मारत सरवार वे ऋण में सर्वायत हो।

१ टी० के वटोपे—'पूर्वोक्त पुस्तक' १६६३ पृत २५१।

२ टी॰ ई॰ मेय-प्र ट्रीटाइन प्राप्त द ला, प्रियोलेनेस, प्रोसिडिन्स एण्ड पूजेस प्राप्त पार्लियामेन्ट, १३ सस्टरण, पु० ४६३।

भारतीय शासन घौर राजनीति

₹52 ४-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायायीशो के बेतन तथा मतो ग्रीर सेवावृत्ति,

व संघीय न्यायालय के संबंध में दी जाने वाली सेवा वृत्तियाँ। ५---उच्च स्थायालयो के त्यायाधीओं को दिये जाने वाले वेतन मत्ते ग्रीर

सेवा-वत्तयाः ।

६-- मारत की स्वतंत्रता के पर्व. भारत क्षेत्र में किसी स्वायालय के न्याया-धीश को सेवावत्ति ।

७--सधीय लोक सेवा द्वायोग के सदस्यों के वेतन मत्ते तथा सेवावत्ति !

 मारत के नियन्त्रक तथा महालखा परीक्षक के बेनन, मतो तथा सेवा वत्ति ।

६—ससद के सदनो के समापति और ग्राध्यक्ष के वेतन तथा मले । १०-- किसी न्यायालय या पच न्यायालय के आदेश या निर्णय द्वारा स्थापित दायित्वो को परा करने के व्यय।

११-सर्विचान के ग्रन्थ प्रावधानो द्वारा सचित निधि सवधी व्यय, जैसे-धनुच्छेद १४६ (३) के धनुसार सर्वोच्च न्यायासय के प्रशासकीय व्यय । धनुच्छेद १४८ (६) के अनुसार नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रशासकीय व्यय, अनुच्छेद २७३ व २७५ (१) के अनुसार राज्यों की सहायता सबधी व्यय और देशी रियासती के शासको के प्रिवीपमें।

१२-- ग्रन्य व्यय जो समद द्वारा सचिन निधि के श्रन्तर्गन निर्धारित किया जाये ।

सचिन निधि के बन्तर्गन व्यव के लिए ससद की स्वीकृति की बावश्यकता नहीं होती है। ग्रन्थ प्रकार के व्यय के लिए ससद की स्वीकृति की ब्रायस्यकता है। सनित निधि में उल्लिखित ब्यय पर ससद में मतदान नहीं हो सकता है। अन्य थ्यम के लिए अनुदान सबधी माग ससद में की जाती है। अनुदान की माग को लोक्समा राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृत पर ही रखा जा सकता है। लोक्समा को अपनी स्वीकृति या श्रस्तीकृति देने या अनुदान की माग मे कभी करने का पूर्ण ध्रमिकार है।

दबट को पारित करने का कार्य, ससद का एक मुख्य कार्य है। ससद का वजट अधिवेशन प्रतिवर्ष परवरी के दूसरे सप्ताह ने पश्चात् ग्रारम्भ होता है। मारत में सर्वप्रथम, रेल मनी द्वारा लोक्समा में रेलवे वजट प्रस्तुत किया जाता है। इसके पत्रचात् वित्त मत्री लोक्समा मे बाधिक बजट प्रस्तुत करता है। इस समय वह प्रपते बजट मापण से सरवार की विल तथा प्रयं नीति पर देश की ं व्यवस्या के सदमें मे प्रकाश ढालता है ।

बजट की प्रतियां सबद के सदस्यों को विचार-विमां के लिए वितरित की जाती हैं। इस प्रवस्था में दजट पर बाद-विवाद विस्तार पूर्वक नहीं होता है। परन्तु सबद सदस्य इस प्रवसर को, सरकार की नीति तथा वासन के विभिन्न विमान के नार्यों की प्रात्तीयना करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं।

जैसा देखा जा चुना है, ससर की सचित निधि में उल्लिखित क्या पर मतदान करने का प्रधिकार नहीं है प्रत बाद-विवाद के पश्चात् लोकसमा उन विभिन्न मानो पर मतदान करती है जो सचित-निधि से सविधत नहीं है। विभिन्न मना लयो थे मानो पर पृथक रूप से विचार होता है। यहाँ पर सोकसमा को प्रत्येक मत्रालय के विगत वर्ष के कार्यों तथा नीतियों का मृत्याकन करने का प्रवसर प्राप्त होता है, यहाँ कि प्रवन्ती मानों के सीचित्य को बतलाते हुए प्रत्येक मत्रालय प्रपने विगत वर्ष के कार्यों तमानों के सीचित्य को बतलाते हुए प्रत्येक मत्रालय प्रपने विगत वर्ष के कार्यों सो सोकसमा वो प्रवन्त वर्ष के कार्यों से सोकसमा वो प्रवन्त करता है।

मागो की मतदान द्वारा स्वीवृत के पश्चात् वाधिक विनियोग विषेयक लोक-समा द्वारा स्वीवृत मांगो तथा संचित-निधि सवधी व्यय को साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जहाँ वाद-विवाद प्राय: सार्वजनिक मुद्दो तथा सरकारी नीतियों तक सीमित रहता है। विशेषनर वाद-विवाद उन प्रमो पर होता है, जिन पर पूर्व में विचार नहीं हुमा है। विसी विषय पर वाद-विवाद के लिए प्रम्यक्षा की पूर्वादुमति प्रावस्थक है, और प्रम्यक्ष वाद-विवाद में माग तेने वाले सदस्यों को पहुंत ऐसे विषयों के सवस में सुचना देने ने लिए यह सकता है।

हमके परवात् वितियोग विषेयक को उन सब स्तरों को पार करना होगा जो एक सामारण विषेयक के विधि निर्माण के लिए धावयक है। लोकसभा जब वितियोग विषेयक पारित कर देती है तब धावश माणित करता है कि विषेयक हो विधेयक है। तस्यवात् वियोयक को राज्यसभा के समझ मेना जाता है। राज्यसभा के लिए, विषेयक पर विचार-विमाण कर धपने मुख्यो सहित, १४ दिन में विधेयक को लोकसभा के पास वापिस लोटाना धावयक है। परन्तु यह लोकसभा पर निर्मार है न राज्यसभा के मुख्यों को स्वीकार करेया न करे। विधेयक पर धालिस निर्णय लोकसभा का ही है। लोन सभा हारा पारित होने के पत्वात् वियोयक राष्ट्रपति के पास जसकी स्वीकृत के लिए मेना जायेगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति भीपवारिक है। विनियोग विषेयक को पुनविचार के लिए वापिस नहीं कोटाण का सकता है।

षन विषेयक निर्माण वा मन्तिम चरण संसद द्वारा विसीय विषेयक पारित करता है। सरनार के तर संबंधी प्रस्ताव मनके वर्ष के निए वित्त विषेयक के रूप में सोकसमा के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। बित्त विषयक को पारित करते की प्रत्निया उपर्युक्त विषित्त विनियोग विषयक को पारित करते की प्रक्रिया के समान है। सरन में, विषेयकर समिति स्तर के साद विषयक पर विस्तार पूर्वक विवार किया जाता है। सबोधन, प्रस्ताव करों को समाप्त वरने या पटाने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं, पर करों को बढ़ाने के प्रस्ताव प्राय प्रस्तुत नहीं होते। वित्त वियोग प्रप्रेत माह में ही पारित किया जाता है क्योंकि प्रतिवजनत केवनज प्राफ देसेड एस्ट १९३१ के प्रतिकृति प्रतिकृति प्रस्ताव, वापिक वित्त प्रस्तावों के प्रस्तुत करते ही प्रमावशील हो जाते हैं।

सत्य में लिल प्रजियों के प्रध्यक्ष ते यह स्टच्ट है कि देश की नित्त तथा प्रयं यवस्याओं पर सदय का पूर्ण नियम्बण है। परन्तु यह प्रोभमा मत्तत होंगा कि सबद का नियम्बण विसीय विधि निर्माण तब ही सीमित है। बनट के पारित होने के पत्रवात् भी सतद का नियम्बण देश नी निवा एव वर्ष चयदस्थाने पर स्वाताद वना पहता है। परन्तु सतद का यह नियम्बण अप्रयक्ष रूप से निया ताता है। वात्तव म कार्यपालिका पर सतद के नियम्बण मारद्वस्थुण सामन निता है। विच यनस्था के नियम्बण की प्रक्रिया में कनिपय सामनों को प्यान में रखा जाना चाहिने, जिनके माध्यम से सबद निरम्बर प्रयन्ता नियम्बण कार्यवालिका

१--सफ्तात सेको का सेका परीक्षण — लेला परीक्षण यह प्रक्रिया है, जिसका उपयोग सेको का परीक्षण, उनकी या उनके सन्तर्गत, कार्यों के उपयुक्तना विदित करने के लिए क्रिया जाता है। सर्वयं में, अर्ज्जानरीक्षण द्वारा विस सम्बन्धी कार्यों का भौजिए में भागारों पर निर्मारित किया जा सनता है।

क-वित्त सम्बन्धी कार्यों को विधि के अनुकृत होना चाहिये, और

ख—वित्त सम्बन्धी कार्यों की वित्त नियमी के प्रस्तगत उपयुक्तवा इस दृष्टि-कोण से निर्धारित करना कि वित्त सम्बन्धी कार्यों द्वारा श्रनुपदुक्त एवं निरर्धक व्यय तो नहीं हमा है।

मारतवर्ष में सेखा-परीक्षण के कार्य लेखा परीक्षण विमान में निहित हैं, जिसका प्राथक तिप्तनक तथा महालेखा-परीक्षण है। लेखा परीक्षण, एक सपीय विपत है। सिवान के प्रतुष्ठाद १४१ (१) के प्रतुष्ठार नियनक तथा महालेखा परीक्षण के कार्य तथा महालेखा परीक्षण के कार्य तथा महालेखा परीक्षण के कार्य तथा महालेखा परीक्षण करते का प्रयाप करायों के प्राथम करते हैं। यहांपन करते का प्रयाप के द्वारा क्यांपन करते का प्रयाप के प्राथम तथा के प्रत्य पर पायों के प्रयाप व्यापन के प्राय पर पायों के प्रयाप व्यापन के प्राय पर पायों के प्रयाप व्यापन का मी तथा-परीक्षण करते का प्रयाचन है। "व्यय पर पत्रव का नियन-पण, प्रपत्ने प्रयापक तथा नियन हथा महालेखा-परीक्षण के माण्यम तथा के प्रयापन विकास के माण्यम विकास के प्रायपन विकास के प्रयापन करते का प्रयापन प्रित्य करते व्यवस्थापिका को प्रारापन के प्रतापन करता है। "व्यवस्थापिका को प्रारापन करता है।" व्यवस्थापिका को भी प्रतापन करता है।"

९. सी.व यो.व भारमरो—'यम्लिस एडमिलिस्ट्रेसर्ग' १९६० भाग ४ पृत ६२ ३

२—ससद की वितीय समितियाँ—ससद की कार्यपालिका के नियन्त्रण का ग्रन्य साचन, उसकी वित्तीय समितियों के रूप में है। ससद की दो वित्तीय समितियों है।

क—लोक लेखा समिति -- ग्रारम्म में सभीय लोकलेखा समिति में १५ सदस्य थे, जिनका निर्वाचन लोग समा अपने सदस्यों में से करती है। परन्तु १९५३ से राज्य समा के सदस्यों को इसमें सम्मिलित किया जाने लगा। इसका ग्रध्यक्ष सत्तारूड दल में से ही लिया जाता है। लोकलेया समिति, नियन्त्रक तथा महा-लेखा परोक्षक के संसद के समक्ष प्रतिवेदन के प्रकाश में सरकारी लेखों का परीक्षण करती है। प्रत्येक मधालय या विभाग का एक अधिकारी लोकलेखा समिति के समक्ष, समिति द्वारा उठाई गई ग्रापतियों का निवारण या स्पर्धीकरण करने उपस्थित होता है। जिन मत्रालयो या विमागो मे ग्रनियमिनताएँ हुई है उनके सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रदत्त जानकारी, उसके निष्कर्य तथा सुकाव लोकसमा को समिति-ग्रह्यक्ष द्वारा पहुँचाये जाते हैं। लोकसमा से समिति का प्रतिवेदन विस मुत्रालय को मेज दिया जाता है, जो समिति के सुभावी को सबवित मतालय या विमाग से अवगन कराना है। यदि समिति के किसी सुफाव को सरकार ग्रस्थीकृत कर देती है तो उसको ऐसा करने के लिए कारण बनलाने होंगे। यह स्पष्ट है कि लोक लेखा समिति कार्यग्रालिका तथा प्रशासन पर नियन्त्रण रखने के तिए संसद को महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाती है। डा॰ नामन पामर का कहना है—'लोकलेखा समिति न केदल नियम्बरु तया महालेखा परोक्षक के प्रतिवेदन, प्रौर प्रम्य कागवाती की विभिन्न प्रतियमित्रताएँ को जात करने के लिए जीचती है परन्तु साय ही राष्ट्र के वित्त सम्बन्दी प्रकासन से सर्वेथित निर्यंक व्यय, भ्रष्टा-चार, प्रक्षमता एव ग्रन्न युटियों में भी रुचि रखती हैं। ग्रतएव यह सरकारी लापरवाही तथा अध्टाचार के विरुद्ध ससद के हितों की रक्षक तथा अनता की सरक्षक है। इसके प्रतिवेदन महत्वपूर्ण लेख है।"1

लोकलेला समिति की भूमिका के सबय मे यहाँ इसके एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन वा उत्लेल करना धावरक होगा । यह मामला मारत-चीन युद्ध-१९६२ से सबिम है। मारत की पूर्वी सीमा पर हवाई-बहाजों के उतरते की हगाई-पट्टी की तैयार करने के लिए मुख्य इंजीनियर ने रु० १०६-६५ लाल का ठेका इस सर्त पर दिया कि सारा कार्य पीच माह मे पूरा हो जायेगा । वास्तव मे सार कार्य कार्य पर विश्वा कि सारा कार्य पीच माह मे पूरा हो जायेगा । वास्तव मे सार कार्य का प्रमुक्त करने में एक वर्य से प्रविक्त समय सग गया। निर्माण कार्य सारा कार्य समान्त करने में एक वर्य से प्रविक्त समय सग गया। निर्माण कार्य

१. एन० डो० पामर-'द इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम' १६६१ पृ० १२।

भ्रारम्म होने से पूर्व हो गोलीबार स्थागित हो चुना था। नोबलेखा समिति के समक्ष प्रमा साध्य देते हुए सुरक्षा-सिबन ने स्वोकार किया कि यदि युद्ध पुर मारम्म होता तो निर्माण नामें के निर्योदित समय मे समाध्य न होने के एक्सवक्ष्य निश्चित भारतीय बाधु सेना को नामें-द्यस्ता पर साधात पहुँचता। समिति ने भ्रयनी ४-व्हें प्रतिवेदन मे, जो लोकसमा के १६ स्रमेल, १६६६, को मेजा था, सुद्धात दिया कि मृतुमब के आधार पर सबक सीत्तते हुए, प्रतिरक्षा ने मिन-कारियों के लिए, मदिष्य में ऐसे साथतिकालीन कार्य, जिसमें जनता का भ्रयायिक यन तराता है, हाथ में नेते समय सतकतापुक्त कार्य करना चाहिये।

स-प्राप्तकतन समिति—"प्राप्तकतन समितिया स्थायी, तथा निरन्तर कार्यं करने वाली मधीनरी के समान है जो व्यय की दृष्टि से प्रयं-व्यवस्था में बचत की समावना की जांच करती है और उसके लिए सुभाव प्रस्तुत करती है।"

मारत में संबीय प्राव्यक्तन समिति के २२ वेदरल हैं जो सबद द्वारा एक सम्मायि ता द्वारा प्राप्तुपातिक प्रतितिशिद्धर प्रणाली के प्रमुखा ने रात्त कर सम्मायि कर करता है। प्रत्येक स्वाद्ध में शोक्ष सम्माय प्राप्त मानीनीत करता है। प्रत्येक वर्ष प्राक्त मानीनीत करता है। प्रत्येक वर्ष प्राक्त मानीनीत करता है। प्रत्येक समा को प्रतिवेदन में नवी है। विजेवकर प्राव्यक्त समिति विभिन्न मनात्यों में वस्त कथा निभुष्त हासिल करने के तिए पुमाव देशे हैं। समायानुसार प्राव्यक्त समिति ने नई महत्वपूर्ण कुसाव दिये हैं। उदाहुएण के लिए प्रपोन प्रविवेदन स्विम्नीत प्रवासनीय विभागों के समिति ने नार्य सम्माय के सम्माय के सम्माय के सम्माय के सम्माय के सम्माय के स्वविद्ध पुमाद दिये हैं। प्रतिवेदन स्वे के कियद प्रणासकीय तथा विक्त सवाधी पुमारों के लिए मुमाव दिये हैं। प्रतिवेदन से कित्य प्रणासकीय तथा विक्त सवाधी पुमारों के लिए मुमाव दिये हैं। प्रतिवेदन से कित्य प्रणासकीय तथा विक्त प्रवाद के स्वविद्ध प्रणास के स्वयं प्रत्य स्वयं प्रयोग के लिए मुमाव दियों है कि बहुत समाय स्वयं माय वहने हो, विभिन्न प्रवाद स्वति स्वयं प्रयोग स्वाप्त स्वयं प्रयोग स्वयं प्रयोग स्वाप्त स्वयं प्रयोग स्वयं स्

प्राप्तकतन समिति के सुभाव सरकार को मेन दिये जाते हैं वो इनको कार्याणित करने का प्रयान करती है। समिति को, उसके कार्यों में, सबद-सर्विन् सालद द्वारा समुदान हिम्मी हैं बोर विमानीय सर्याकरायि को मेद समिति यह चाहती है तो उसके समक्ष उपस्थित होना झावस्यक है। प्रावक्त समिति सौकलेखा समिति के समान प्रमातन के क्षेत्र में निरस्कं क्यम पर रोक समाती है। प्रास्तवन समिति के सहस्य के सम्बन्ध में में निरस्कं क्यम पर होने समाती

१. एम० पी० 'शर्मा—पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन विद्योरी एण्ड प्रेविटश', १८६० पूरु २७७

"एक महत्वपूर्ण सीमा तक यह समिति केवल मितव्ययता या कार्य दक्षता की नावना से प्रेरित होकर हो नहीं परन्तु वार्षपालिया की निरकुणता को रोकने के विचार से एक वास्तविक विरोधी दल की एवजी में, महत्वपूर्ण स्थान प्रहण करती है। समझ में एक प्रविकासित देश में इस तरह की प्रवत्या प्रधिक उपसुत्त है। समझ में एक उपलिक्तीय है कि प्रावक्त तराह की प्रवत्या प्रधिक उपसुत्त है। समझ में सह उस्तेवलीय है कि प्रावक्त तराह की प्रवत्य प्रधिक उपसुत्त है। समझ के करती है, जो सारत म महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रवम, यह सदन के तदस्यों के तिए महत्वपूर्ण प्रविकास क्षत्र है। इतीय समिति के प्रतिवदन। का, तदन में तथा सदन वे बाहर बहुत कीतिशव मूल्य है। इतकी सहायता ने को क्षत्त के उस स्तर का निर्माण हो सन्ता है जो कात्यक कोर कारित वर्षों के मध्य की शाई को हूर करने के तिए प्रदस्त सावव्यक है। "1"

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि वित्तीय प्रशासन पर ससद का नियन्त्रण धान्तरिक तथा बाह्य साधनो द्वारा निरन्तर बना रहता है।

ससद को ग्रन्य शक्तियां—सवियान द्वारा सबद को कतियस ग्रन्य शक्तियाँ भी प्रदत्त हैं, जिनका निम्नलिखित वर्गीकरण के ग्राघार पर भ्रप्ययन किया जा सकता है:—

१—ससद की सकटकालीन स्थिति सबयी शक्तियाँ—सिविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषित सनटकालीन उद्घोषणा को ससद के समक्ष उसकी सर्गात के लिए रखना आवश्यक है। अब देश में ककटकालीन स्थिति है, तब प्रमुक्छेद २५० के अनुसार ससद को सब तथा समर्वती सुनियो के श्रतिरिक्त उन विषयो पर भी विधि-निर्माण करने सब प्रिकार प्राप्त हो जाता है, जो राज्य-मुची से उल्लिखत है। ऐसी स्थिति में ससद को राज्यो के प्रधानमीय प्रधिवारियों को सविधान के स्तर्गत कोई सी कार्य सौंपने का प्रधिकार है।

२—सविषान में संबोधन का प्रिषकार—पूर्व में देखा जा चुका है कि संविषान में संगोधन हेतु, सविषान के प्रावधानों को तीन वर्गों में रखा जा सनदा हैं। सर्व प्रमा, सविषान के ऐसे प्रावधान है, जिनको ससद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संगोधित किया जा सकता है। उदाहरण श्वरूप इस प्रविधा-पुतार नये राज्यों का निर्माण या बतमान राज्यों के नाम या सीमान्नी में, राज्यों की विधान समान्नी के मत को जानने के पश्चीत् परिवर्तन किया जा सकता है। राज्यों की विधान समान्नी के मत को जानने के पश्चीत् विधे किये जा सकते हैं या जिन विधान समान्नों में दितीय सदन नहीं हैं, वहाँ दितीय सदन स्थापित किये जा सनते हैं, नागरिकता प्रजुत्वित क्षेत्रों का प्रधासन, प्रजुत्वित जातियों क्षोर

१ डब्ल्यु एव० मोरिस जोन्स-पूर्वोक्त, १९४७ पृ० ३०७-३०८।

भारतीय शासन और राजनीति

१८६ बेस्टीय-प्रशासित क्षेत्र में सबधित विचयों से सम्बद्ध सविधान के सारे प्रावधान

ससद में साधारण वहमत के ग्राधार पर पारित विधि द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं।

द्वितीय, संशोधन की दृष्टि से, सुविधान की द्वितीय थेणी में जो प्रावधान रसे गये हैं, उनका मूल रूप से सबच दोनो, सधीय राज्य सरकारों से है। अर्थात् यह सविधान के ऐसे प्रावधान हैं, जो सधबाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। श्रतएव इनके संशोधन में संघ तथा राज्यो दोनों को मांगीदार बनाया गया है। सविवान

के ये विषय निम्नलिखित हैं — (क) ब्रनुच्छेद ५४ तथा ब्रनुच्छेद ५५ जिनके ब्रनुसार राज्य विधान सभाष्रो के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल का एक हिस्सा माना गया है। प्रमुच्छेद ७३ तथा अनुच्छेद १६२ जो राज्यो की कार्य-

पालिका शक्तियों से सविधत है, और अनुच्छेद २४१ जो संघीय क्षेत्रों में स्थित उच्च न्यायालयो से सद्घित है। (ख) सर्विधान के पाँचवें हिस्से के चौथे बध्याय के ब्रानच्छेद जो कि सधीय न्यायपालिका से सर्वावत है, सर्विदान के छठे माग का पाँचवा अध्याय जो राज्यो

में स्थित, न्यायालयों से सर्वाधत है, भीर सर्विधान के स्वारहर्वे हिस्से का प्रथम ध्याय जो सघ राज्यों के सबच पर है।

(ग) राज्यो का ससद में प्र तनिधित्व। (घ) सविधान का भनुच्छेद ३६= जिसमे सविधान सक्षोपन-प्रक्रिया उल्लिखित है ।

सविधान के उपर्यक्त उपस्लिखित ऐसे प्रावधान हैं, जिनमे सघ तथा राज्यो, दोनो के द्वित निहित है, अतएव इन प्रावधानों का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियानसार संघ समद तथा कम से कम आधे राज्यों की विधान समाध्रों की सहमति ग्रावण्यक है। सर्वप्रथम, इनम से किसी प्रावधान के संशोधन के लिए ससद के प्रत्येक सदन म विधेयक, सदन की पूर्ण सदस्यता के बहमत एव उपस्थित

सदस्या के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिये। जब ससद ने सशोधन-विषेयक उपर्युक्त रूप मे पारित कर दिया, तत्पश्चात कम से कम आधे राज्यो की विधान सभाओं द्वारा विधेयक की सहमति मिलना ग्रावक्यक है।

तृतीय, सवियान के अन्य प्रावधान (उपर्युक्त दो श्रीणयो मे उल्लिखित प्रावधानो को छोडकर) ससद के प्रत्येक सदन म सम्पूर्ण सदस्यता के बहमत तथा उपस्थित

सदस्या से दो तिहाई बहुमत के ग्राधार पर सजीवित किये जा सकतें हैं।

ग्रत यह स्पष्ट है कि ससद का एक महत्वपूर्ण कार्य सदिघान का (कुछ प्रावधानों को छोड़कर जिनके लिये बावे राज्यों की विधान सभाछों की सहमति

मावश्यक है) संशोधन करना है।

सघीय संसद १८६

३—ससद देश ना सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर जनता की शिकायदों को दूर करने का प्रयत्न, उनके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रो० मोरिस जोत्म के श्रनुसार विकायते दूर करने के कई धबसर हैं, पर निस्सदेह प्रश्न समय सबसे महत्वपूर्ण है। पर यह नहीं नहा जा सकता है कि सारे प्रश्नो का उद्देश्य शिकायदों को दूर करना होता है।

उदाहरण स्वस्य ससद के १९४३ ने शरद्कालीन प्रधिवेधन में बीस से प्रधिक प्रकानम्त्रलिखत विषयों पर पूछे गये—मूती कपडा, चर्खा तथा खादी-उद्योग, इक्त-मर्भवारी, सेना, शक्कर, धाकाणवार्था, वैज्ञानिक प्रनुस्थान, कोयला तथा खदाने, रेलवे दुर्घटनाएँ, मार्ग, एव सबसे खधिक प्रश्न रेलवे गार्ग पर पूछे स्थे।

ग्रन्य में हम इस निर्क्ष पर पहुँचते है कि मारतीय ससद को, सविधान के अन्तर्गत सम्वाद की सीमाओं में, महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। इनके द्वारा ससद कार्यंपालिका पर नियन्त्रण रखकर, उसे अपनी नीतियों, तथा कार्यों के लिए उत्तरस्तां ठहरा सकती है। परन्तु मारत में सबदीय प्रणाली की सफलता निर्वाचक गण तथा ससद में जनता के प्रतिनिधियों की सतकता तथा कार्यंकुशसता पर निर्मर है।

संघीय कार्यपालिका एवं संसद के संबंध

सधीय नार्यपालिना तथा सबद के सबयो का दो सबधित प्रापारो पर ध्रध्य-यन करना उनित्त होगा। ये दोनो भाषार, मारत में ससदीय सरवार के सेढ़ानिक स्ता बरतार के सेढ़ानिक स्ता बरतार के सेढ़ानिक स्ता बरतार के सेढ़ानिक स्ता बरतार के स्ता स्ताद के सदायाता मारा सार के सबसे को जात करने के लिए हमारे समक्ष भून तथा मार्गदर्शक तथ्य यह है कि सिद्यास कार्य-प्रमाली में बेढ़ानिक कर में, सादतिक नार्यपालिका (भूमी मयन्त्र) सबद के निष्केत सदन के प्रति जेतरात्री में स्ताद के निष्केत स्ताद के स्ता

शक्तिशाली हो गई है। सन्नेष में संघीय कार्यपालिका (मंत्री मण्डल) तथा संसद के सबघों का घट्ययन

तिम्नलिखित थो धावारो पर किया जा सकता है। १--सबदीय प्रणालो के सिद्धान्तो के धनुसार सपीय कार्येशलिका (मत्री-

मण्डल) सवध । २—स्वीय कार्यपालिका (मत्री मण्डल) तथा ससद के ससदीय प्रणाली में

२—सबीय कार्यपालिका (मत्री मण्डल) तथा ससद के ससदीय प्रणाली में व्यावहारिक दृष्टिकोण से सबध ।

— सत्तरीय प्रणाली के तिवालतपुत्रार समीय मन्नी मण्डल तथा सतद के सबय—मैदानिक रूप है, सतदीय प्रणाली के सन्वर्धन मन्नी मण्डल (वास्तविक नर्पणालिका) प्रत्यक्ष रूप है, सबद के निवसे सबत के प्रति उत्तरपत्ती है, जबकि नाम मात्र नामेंपालिका ना, सरकार की नीतियो तथा नामों के लिए कोई उत्तर-दायिव नहीं है। पूँकि सबदीय प्रणाली में कामंपालिका के यो हिस्से होते हैं, प्रत्य ना सुंक है कि इन दोनो हिस्मों से सबद के दिस प्रकार के सबस है।

 (क) मत्री मण्डल (बास्तविक कार्यपालिका) के सबय मे ससद को शनिया—ससदीय प्रणाली का प्रामार भूत विद्वालं मारत सविधान के प्रमुच्छेद ७५
 (३) म निहित है, दिसके धनुसार मत्री मण्डल सामूहिक रूप से लोक्समा के प्रति उत्तरदायी है। सिवधान के इस अनुष्केद के अध्ययन के फलस्वरूप यह स्पष्ट है कि मनी मण्डल सामूहिक रूप से लीकसमा के प्रधीन है और लोकसमा सामूर हिक उत्तरदायित के विद्यान के प्राधार पर मनी मण्डल का निमन्नज करती है। विभिन्न सामने के माण्यम से लोकसमा मनी मण्डल पर अपना नियम्बण करती है। विभिन्न सामने के माण्यम से लोकसमा हारा मनी मण्डल के विद्युत्त प्रस्ती है। प्रस्ताव पारित करना है। सामने विष्या प्रणाली में मनी मण्डल पर नियम्बण रखने के लिए निचले सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है। सामने के लिए निचले सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, प्रनित्त तथा सबसे के कोर तरीका है। श्री लालबहाडुर णास्त्री तथा श्रीमती गांधी वे कार्यनाल में विषक्षी दलो द्वारा सरकार के विद्युत्त प्रस्ताव प्रस्ताव पारित करने के प्रयस्त किये गये, परत दुत्तमें वे सफल नहीं हुए।

सरकार के विरुद्ध प्रविश्वास प्रत्याव पारित करने के प्रतिरिक्त अन्य साघा-रण साधन भी है, जिनका उपयोग ससद मे प्राय प्रतिदिन मशीमण्डल पर निय-न्त्रण रखने के लिए किया जाता है। आगे लिखे हुए साधनो नो इस कार्य के लिए प्रस्तुत किया जाता।

१—समिति प्रणाली ।

२—ससदीय प्रश्न ।

३-ससदीय प्रस्ताव ।

४-ससद मे बहस ।

समिति प्रणाली

जनताजिक राज्य मे समितियों को व्यवस्थापिका के कुशसता पूर्वक कार्य करने के लिए झावस्थक माना जाता है। सिनितयों, न केसत व्यवस्थापिका के कार्यों को पूरा करने, परनु सबस के सबस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए भी झावस्थक है। ससदीय समितियों को किसी लेखक ने ससद के—'शांखों तथा कार्ना' के रूप मे माना है। समितियों के मध्यम से ससद विभिन्न विपयों पर तकनीकी तथा सायारण जानकारी हांसित करती है। "ससदीय समितियों प्रशासन पर महत्वपूर्ण विपन्नण एसती है। वे प्रशासन को कार्यवाही की जॉन तथा निरीक्षण मो करती है।" भारतीय ससद में, समितियों की भूमिका का विशेष महत्व है, स्थोकि एक भागतवासी विपत्नी दश को समुप्तियति में, सरकार की निर्मुक अधिकार से सितियों रोक समातियों है। "इन समितियों से ही विषक्षीय दल सरकार को नीतियों को प्राप्त स्थानियों है। "इन समितियों के भूमि के स्थान स्थान की नीतियों को प्राप्त प्रशासन कर सकते हैं। इन समितियों के भूमि कार्य प्राप्त स्थान स्थान

१. सी॰ पी॰ भाम्भरी-लोक प्रशासन, १६६० भाग ४ पृ० ६० ।

प्रवासी ने एक मनोपजन पहलु हैं। सरकार पर एक प्रमावशासी नियन्त्रण किस समिति । वा है। प्रोक्ष भोरिस जोल्म ने मनस पर सपने महुन्यूर्ण प्राथ्यत मे सह मन दिमारण हैया है हैं "इस प्रदार ने मासित ने वेजन मिन्द्रपतिशास तथा बार्यकुर लगा ने दिवार से, यस्तु एक द्रमदरारी घोर निरकुण नार्यसालिका पर सपरोध के लगा मे होने के विचार से प्रेरित होकर (नार्यम) एक बारतिकर विरोधी हम को एक्सी में, सहस्तुर्ण क्यान प्रहाण करती हैं।"

भारत में ममितियों में एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि सरवार द्वारा प्रसा-वित विषयों पर समितियों में स्वीवन महयोग मिनने की समावना के साथ विषयी दल सरकार को स्वीवन प्रमावित कर सबते हैं।

समय मे एव सर्गाठन तथा प्रमाणकारी विदशी दन वी सनुविध्यति से, यह स्वामाधिक ही है कि मससीय मिनियों का महत्व स्विक्ट हो गया है, अनीति एंगी रिम्मित में मीनियों के माध्यम के हो सरकार वी नीतियों क्या जाती को, जन करवाय के लिए प्रमाधित दिया था सकता है। उदारूप्त स्वक्ष्य, सोक्लेया सिर्मित की जोक के पत्तस्वरण ही रायुष्ट बार सीर और बारू नवसी प्रमित्तिताएं प्रमास से साई परि प्रमाणक स्विति सरकार को स्वत्त नवसी प्रमित्तित्वार प्रमास से साई परि प्रमाणक स्विति सरकार को स्वत्त नवसी पुनात देती है। साक्ष्यमन मिनि मरकार पर सन्तर्गत प्रांत निवाह एक वर उसकी निरमुकता पर पोक लगानी है। इभी तरह स्वामीवनाविधि ममिनि कार्यगानिका की नियम नियोंच मिन पर एक कहन के समझ है।

सोसमा की प्रतिमा तथा कार्यसारी ने मनापन ने नियम ११४७ द्वारा मतद की विषय मीमिठमों ने तिए प्रावधान नियम पता है। इनको दो क्यों में रखा जा सकता है — () स्थामी मीमिठियों, भीर (है) भिगेष मीमिटियों ने निर्मास ने निर्मास की निर्मास नदन न प्रत्यास पर होनी है। सीमिटियों ने घण्या की निर्मास करते की शक्ति प्रकास में निर्मित है, जियने रिपासी तथा मतास्व दानों में से मदस्यों की मीमिटियों में दिया जा सहे। मत्य की निर्मासियों में स्थामिटियों की

१—वार्य संबंधी परामर्ग समिति—(वितिनेम एटवाइकरी केमेरी) सहन के प्रविदेशन के धारम्म में कार्य मक्त्री परामर्ग ममिति का निर्माण मनद के वार्यक्रम के निर्माण के लिए विचा बाता है। इसके १४ महत्त्व है। इसका प्रथम लोक-माना प्राथम है।

१. प्रार बर्नेहेस—'पार्तियामेन्ट एसड डेमोडेसी इन इरिडया, (इन स्टडीड इन इरिडयन डेमोडसी) सम्पादिन एस० पी० प्रस्यर और घार० श्रीनिवासन, सन १६६५ पु० १४६-१६।

२-साधारण (प्राय ट्रेट) सदम्य-विथेयर तथा सरम्य सबधी समिति (रुमेटी मान प्राइ हैट मेम्बर्न दिन एन्ड रिजोन्युगन)-इस सनिति का कार्य सामारन सदन्य-विनेदकों की जाँच कर, उन्हें समद के विचार-विनर्ग के लिए प्रम्तुत करना है। इसन नी १४ सदस्य होते हैं। लोहडना के ब्रम्बंध द्वारा समिति का ब्राम्बंध, इसके सदस्यों न ने मनोनीत किया जाता है। यदि लाक्समा का दमान्यक्ष मिन्नित का सदस्य है, वह स्वतः समिति का ग्राम्यस बन जाता है।

३-प्रवर समिति (सेनेस्ट बमेटी)-प्रवर समिति की तिस्कित एस दक्त होती है, जब सदन न प्रस्ताव पारित किया जाता है कि दिनेपण को प्रदर समिति के समझ रदा जाने । अनन कार्यों के लिए, प्रवर समिति दिनेपत्रों की सम्मति सेती है, ब्रावस्यब्दातुनार साक्षी सेती है, तया नगणता ना भी निरोक्षण करती है। प्रदर समिति की सदस्पता सदन में राजनीतिक दला की रास्ति के सनुगत में ि निर्मास्ति को बाती है । लोक्समा का अन्यक्ष समिति के अन्यक्ष का मनोनोत करता है, परन्त् मंदि लोजनाना का उनाव्यक्ष समिति का नदस्य है तो वह स्वत. समिति का सम्बन्ध हो जाता है। महत्वपूर्ण विवेदकों के लिए सम्बद्ध के दोनों सदनों की सबुक्त समिति में लोकममा के दो-विहाई सौर सन्यनमा के एक-विहाई मदस्य होते हैं। ममुक्त मनिति के सदस्यों की सच्या, प्राय १० होती है। सामान्यतः एक प्रवर समिति में ७ ने १५ तक सदस्य होते हैं।

४-याविका सबनो समिति (क्मेटो ब्रान पिटोसत्म)-सदन के अभिवेशन के बारम्न में, इस ममिति के सदन्यों को सोक्यना के बन्यस द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाविका संदर्भ समिति के १५ सदस्य होते हैं। समिति का कार्य उसकी प्रेपित की गई बाविकामी को जीवता है, यह मनता प्रतिवेदन सदन की देती है। समिति सदन के समझ विजेपक के संदेज में याचिकाएँ ग्रहम करती है और याचिक कामों की प्रतिमों की सदन में विजेबक पर दिवार दिनमें करने के पूर्व दितरित बरदाती है। इन याविकाओं द्वारा समद के समझ दियेयको पर जनमत का रूद विदित होता है और एउन्दरूप मनद में मादस्यक कार्यवाही की आती है।

५—प्रावत्त्रत समिति (एप्टिमेट्म बमेटी)—असद की दो दिलीय समितियों न ने प्रास्कृतन मनिति एक है । प्रास्कृतन समिति को नियुक्ति ससद के प्रथम प्रापन देनत के ही बारन्म में प्रतिक्यें होती है। इनके सदस्यों की सख्या ३० होती है, विनका चुनाव लॉक्समा में अनुरातिक मानार पर होता है। "प्राक्तलन सनिति हा हार्च दिन्तार पूर्वक दण्ड बनुनानों तथा व्यवों हो जीव हरना है, इसिएए मह सरकार को न ने दल दिलीय क्षेत्र में, दरन् क्रन्य क्षेत्रों में भी प्रमादित करने के . लिए मस्तिमानी न्यिति में है।"१

१. एम. वो पावनी—'इन्हियात कान्स्टीट्यूशन, १८६२, पृ० २१२ । \$3

सोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियमो (नियम ३१०) के धनुसार प्राक्कलन समिति के चार प्रमुख कार्य हैं।

- प्रावकतन समिति के चार प्रमुख कार्य हैं।

 (१) यह प्रतिवेदन देना कि प्रावकतन में उल्लिखित नीति के अनुकृत किस तरह मितव्ययिता, सगठन में सुधार, कार्यकृष्णता तथा प्रशासन में सुधार लाये
 - जा सकते हैं। (२) प्रशासन में कार्यकुशनता तथा मितब्यथिता लाने के लिए वैकल्पिक
 - नीतियों का सुफाव प्रस्तुत करना।
 (३) यह जॉच करना कि प्राक्कलन में निहित नीति के धनुसार धन का
 - उचित बितरण किया गया है या नहीं।

 (४) यह मुझाब देना वि प्राक्कलनो को ससद के समक्ष किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

प्राक्कतन समिति के कार्यों के सबय में, घ्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि सबद द्वारा बजर के पारित होने के पश्चत इसके कार्य समायत नहीं हो जाते हैं। सिति सार्य तथ्य रहता के कि सी मी विकाग या प्रिकटन ने लेकर सारे वर्ष जांच का कार्य कर्यों के स्वत्य कर सकता है। प्राक्षत के सित्त में होते हैं। धारकार इनको स्वीहत कर सकता है। यदि सरवार इन्हें भव्योंहत कर ती है। वार कार सकता है। यदि सरवार इन्हें भव्योंहत करती है। वार कार हनको स्वीहत कर ती है। वार कार सकता है। यदि सरवार सित्त मित्र कार सकता है। यदि सरवार सह स्वत्य स्वत हम से होते हैं। वार कार सकता है। यदि सरवार सह स्वत्य में होता ।

६—सोकलेखा समिति—"लोकलेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुडवाँ-बहुन है। यदि प्राक्कलन समिति प्राक्कलनो की जाँव से सवधित है तो लोकलेखा समिति का सबध लोक-निधि के व्यय करने के तरीको तथा गरीजो से हैं।"

लोकलेखा समिति के २२ सदस्य होते हैं, १४. सोकसमा के तथा ७ राज्य समा मे से । वे सदस्य प्रायमातिक प्रतिनिध्यत्त के प्राधार पर निर्वाचित होते हैं। सोकस्वसा समिति के कार्यों का उल्लेख ससर की प्रक्रिया तथा कार्यवाही सचावन के निवामों में किया बाता है. जो निम्मानसार है।

मारत सरकार के वित्तीय लेखी और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करके, लोकलेखा समिति निम्नलिखित बातें विदित करती है।

(1) देखों में जिस पन राशि का वितरण बतलाया गया है, क्या वह वैधानिक रूप से प्राप्त थी मा नहीं, और जिस सेवा में मा उद्देश्य के लिए व्यय किया गया, क्या वह वैधानिक प्राप्तार पर किया गया।

१. एम० बी० पायली—'पूर्वोक्त पुस्तक' पृ० २१२ ।

(11) व्यय उचित ग्रथिकार के ग्रनुसार है या नहीं।

(गा) वित्त का प्रत्येक पुनर्विनियोग, इस समय मे, सक्षम श्रविकारी द्वारा निर्मित नियमो के अनुकृत है या नहीं।

(1V) लोरलेखा समिति सरकारी निगमा के लखा, ज्यापारिक तथा निर्माण योजनायों की जाँच करती है।

लोरलेखा समिति का सबसे महत्वपूर्ण वार्य निधन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच कर यह निर्धारित करना है कि ससद द्वारा स्वीष्टत धन-राशि का उपयोग, उचित रूप से किया गया है या नहीं । समिति के प्रतियेदन ससद के समक्ष रसे जाते हैं, जो प्राय इन्ह स्वीवृत कर लेती है।

लोबलेया समिति की भूमिका की प्राय धालोचना की जाती है कि समिति द्वारा वित्तीय मामलो नी जो जाँच होती है, वह देर से होने ने नारण व्यर्थ हो जाती है, क्यांकि इसका कोई प्रमाय नहीं रहता। यह भी वहां जाता है कि समिति ने नार्य शव-परीक्षा (पोस्टमार्टम) ने समान है, नयोनि घन ना व्यर्थ व्यय एक बक्त होने के परवात उमको पूर्व वापिस नहीं पाया जा सकता है। पर जैसा डा॰ माम्मरी ने वहा है—"यह तक प्रस्तुत विया जा सवता है कि पोस्ट-मार्टम वी प्रपनी उपयोगिया है।" विषक वे व्यय पर समिति द्वारा निरीक्षण उन लोगा पर एक बड़ी रोक है जिनको धन व्यय करने का कार्य सौंपा गया है। 'नेयल इस तथ्य ना श्रहसास कि जो बुछ दिया गया है, उसकी जाँच के लिए नोई है, नार्यपालिका नी सुस्ती ग्रीर लापरवाही पर एवं महान ग्रवरोध है। यदि जांच उचित रूप में हुई है तो इसके द्वारा प्रशासन में नाय-नशनता प्राप्त होती है ।"३

७-प्रत्यायोजित-विधि सर्वधित समिति (कमेटी ग्रान डेलिगेटेड लेजीस्लेशन)-इस समिति के सदस्या की सत्या १५ तक होती है। इन्ह लोक्समा का प्रध्यक्ष मनोनीत करता है। इसका कार्य विभिन्न नियमो, उपनियमो प्रादि की जांच करके ससद को प्रतिवेदन देना है, कि यह ससद या सविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के धनु-सार है या नहीं । ससद वे अभिवर्त्ता के रूप मे इस समिति का महत्वपूर्ण कार्य नार्यपालिका नी नियमो नो निर्माण करने की शक्ति का सतकतापूर्ण निरीक्षण नरता है, जिससे यह विदित निया जा सके कि वार्यपालिका ने अपने निर्धारित क्षेत्र में रहकर ससद या सविधान द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति प्रनुसार विधि निर्माण

१. सी० पी० भाम्भरी—'पूर्वोक्त पुस्तक' भाग ३, पृ० दर ।

२. जी० थी० मावलकर 'स्पीचेज एण्ड राइटिंग्ज—स्पीच टू पब्लिक म्रकाउन्ट्स कमेटी, मप्रैल, १० सन् १६५० प्र० ७६ ।

भारतीय शासन और राजनीति

विया है या नहीं। इन दुष्टिकोण ने यह समिति कार्यपालिका की निरकुश बनन को प्रवृति पर एक प्रमादवाली प्रकृष है। इस समिति पर मित्रयो को नियुक्ति नहीं को बा मक्दो है।

६—विशेषाधिकार समिति (वसेटी धान भिवीस्तेत्रत)—इस समिति वा गठन तांत्रवचना के प्रमास द्वारा मदत के प्राविद्यान के प्रारम्भ में हाता है। इसके १५ सहस्त होते हैं। इस मितित वा कर्मा क्रियोषिकार या विशेषाधिकार उत्तरपत सबसी प्रमा की जीव स्थान है। जीव करने के वश्चान समिति प्रमा प्रतिवेदन सबसी प्रमा की जीव स्थान है। जीव करने के वश्चान समिति प्रमा प्रतिवेदन

सदन को देती है। समिति का प्राप्यक्ष सोक्समा का प्राप्यक्ष होता है। है—सरकारी धावबाक्तेस्वर्धित समिति (क्षेत्रेश प्राप्त वर्षेत्रम्य एम्पूरेत्सेम)— इस समिति मे ११ मदन्य होते हैं। इस समिति का कार्य में प्राप्त प्राप्त स्थार में दिये गये धावबानना तथा बक्ता की और, दक्ष उद्देश्य में करना है कि मतियों द्वारा में क्लों तक कार्योग्नित किये गये हैं। और एम० एन० कील में इस समिति में मुस्तिक पर महमा बालते हुए कहा है—"इस समिति में आपात्रीय वर्षे-

भी मुनिन पर प्रनास बातते हुए नहां हे—"इत समिति ने प्रशासकीय नार्य-कुरतात पर बीचनी स्वत ने साथ प्रयत्ती प्रयातों म से नई दोषों नो दूर दिया है। मुत्रो, भव बचन से सतर्व हैं, धौर प्रशासन द्वारा स्थि हुए बचन पर तक्तात नार्यवाहीं भी जाती हैं। स्टब्सर के मन्नी सब सत्तर ने प्रति सप्ते नर्तव्या के प्रति स्वयम हैं।"

१०—शहर के प्रमुक्तिस्ता रहते वाले सरस्यों महामी (एमेटी भ्रात एससेस्ट मेस्स)—रा तालिंड को सरस्य करवा भी (र हो है, जिनको लोक्डम न समझ एक सर्प ने जिए क्लोकेंड करवा है। सरन के सरस्य में, प्रमुक्तिरित के सहय में, प्रावेदन एका को संवेद पह मिनिड करती है। समिति प्रतार ऐस मामले की जोज करती है। तममें कोई सहस्य ६० वा इत्ते से प्रावेद कियों तहे। समिति एसे सित स्वेद के सुप्रिक्त एए है। समिति एका एसे में सित हरने के सुप्रिक्त एए है। समिति ऐसे सामल में, सहर को जीववेदन मेजको है हि सस्य को मनुस्तित भार की नामे को उत्ते प्रमुक्त एसे सित प्रमुक्ति की स्वावेद में सुप्रमुक्ति की स्वावेद की सुप्रावेद की सुप्रिक्त एसे हैं। समिति ऐसे सामल में, सहर को अनुस्तित आप की सुप्रावेद की

११—नियम समिति (रस्स समेती)—इत प्रमिति हे ११ सदस्य हैं, जा लोक समा के प्रमास द्वारा मनोनीत किय जात हैं। लोकसमा का प्रघास हो इस समिति का प्रमास हाता है। इस समिति का कार्य सदक की प्रक्रिया तथा कार्य-बाही स्वासन के नियमों की बौक करना है, जिसके सदक की प्रक्रिया तथा कार्यवाही स्वासन में साक्यक स्थीपन किया जा सकें।

मारतीय संसद में विभिन्न समितियों की भूमिका का भ्रष्ययन करने के पण्वात्, यह स्पष्ट है कि सबद में एक सुसंगठित तथा प्रमावशाली दल के भ्रमाव में समितियों कार्यपालिका पर सतुलित तथा जनतात्रिक रूप से प्रमाव पहुँचाने में सहायक हुई है।

संसदीय प्रश्न

ससद के हाथों में, सरकार पर नियन्त्रण स्थापित रखते के लिए दूसरा साधारण साधन ससदीय प्रकानों के रूप में हैं। ससद के सदस्यों को मित्रामों से उनके विभागों से सबधित मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार हैं। प्रश्न, ससदीय जनतत्र का एक मूल्यवान साधन हैं। "प्रश्न समय एक तेज प्रकाश बाले किया के समान है, जिसका प्रकाश मित्रा के तमान हैं। लिए उत्ता गया है। गहुं एक स्वस्य असदीय हैं जो मेत्रियों को कार्य करते हैं लिए बाध्य करता है, जिससे वे किसी मी दिन सदन के किसी भी कोने से उठाये पये आलोजनात्मक प्रकात वा अविरिक्त प्रश्नों का सामना कर सकें। यह सदन के सदस्यों को वह अवसर देता है, जिससे उत्तर के सबल जानकारी हासिल की जा सकती है, परन्तु सत्ता के दुल्योंग, इसकी असकता तथा जनता की मागों के और ब्यान आपवित किया जाता है। एक पीडित नागरिक के लिए जो अपने प्रतिनिधि को अपनी मागों के लिये प्रकार भुक्तों के लिए कहता है, यह एक मुख्यवान उपनार है।" भ

सत्तद में प्रत्येक दिन बैठक के पहले घंटे में प्रकृत पूछे जाते हैं। प्रकृत पूछने के लिए मंत्रालयों को तीन वर्गों में बॉट दिया गया है। प्रत्येक वर्ग के सर्वय में प्रकृत के लिए सप्ताह में दिन निर्धारित किये गये हैं। ये तीन वर्ग निम्मा निखित है:—

क-विदेशी मामले, वैज्ञानिक ब्रनुसवान, वाणिज्य-उद्योग कानून सवा पुनर्वास 1

स-कृषि, भावागमन, खाद्य, रेलवे, खदान, भौर शक्ति।

ग-प्रति रक्षा, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, गृह-मामले, व सूचना-प्रसार ।

इस तरह प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित विषयो पर सप्ताह ने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दो दिन की पूर्व सुचना देना प्रावश्यक है। सदस्यों को, सदन के नियमों के धनुसार प्रतिरिक्त प्रश्न पूछने का भी धिषकार है। प्रश्न,

१. एम० पो० शर्मा—'व गर्वमेण्ट झॉफ व इण्डियन रिपब्लिक', १९६१ पृ० १८६।

यदि नियमानुसार नहीं पूछे गये हैं तो इनको सदन की कार्यवाही से छलग किया जा सकता है।

सामान्यत प्रश्नोत्तर प्रविद्यों के यथीन प्रिषकारियों द्वारा तैयार विचे जाते हैं और ननी उत्तरों को सदन में पड़ देते हैं। यदि सम्पट या सतीपत्रनक जरूत मही रिया जाता है तो कोई मी सदस्य प्रतिरिक्त प्रश्न पूछ मनता है। प्रत प्रन्तों द्वारा सबस दस्य निशी मी स्ट्रस्थूम विचय पर जतता ना द्यान प्राविद्यात कर सत्ते हैं। प्रश्न में स्वादेश करते, प्रपित्र प्रशासनीय प्रिकारियों के से तह के तथा नार्य दुख्य होने के लिए नाप्य नरते हैं। यी हुत्य प्रदेश के दिख्य हैं हैं— विस्त प्रदेश हैं को हित्य प्रदेश के स्वादेश प्रशासनीय प्रशासनीय प्रश्न के स्वत्य होने के लिए सबसे मेहत्व होने तथा है, वह पुमसे सहस्त होगा कि लोक नर्यवारियों को प्रयास स्वत्य प्रमुख तथा स्वत्य प्रश्न लेल प्रमुख तथा स्वत्य स्वत

धीनवारिक दृष्टि से समदीय प्रान ना उद्देश्य मनियों से बानवारी हासिल करना है। परचु वालव न प्रान को इस तरह रखा जाता है, कि विश्वती दक को मरकार को नोचा दिलाते हुए छोड़ी चानवीरिक उपवर्धिन हो, या निवसे प्रकासकीय वृत्ताई तथा सत्ता के दुरायोग पर ध्यान केंद्रित हो। छत समदीय प्रका ना यह नवरण उनने। एक तेन चार काले प्रवत्न कें रूप म प्रश्त है, जिलना उपयोग विश्वीय वह प्रानायुक्त कर सकरों हैं।

ससदीय प्रस्ताव

ससद में तिनित विषयों पर प्रस्ताव पारित करके सरकार को प्रमाधित विषया जा सकता है। प्रस्ताव प्रस्ता के मित्र हैं, और उतने क्रभावकारी नहीं होता हैं। "स्वसान कराने हैं से तर हो मित्र होते हैं। स्वस्थान अराने के स्वान मतावित उपयोग में नहीं प्राते हैं। प्रायक्षित हर विषय विश्वक के समान मतदान द्वारा दनको प्रायमित्त को वाती है। द्वितीय, इनका चहुँच जानकारी हासित करना नहीं पण्यु सरकार को कार्य करते मा मुक्तक देता है। "प्रस्ताव भारति करने के लिए मी पूर्व मुकन देता है। "प्रस्ताव भारति करने के लिए मी पूर्व मुकन देता है कि सरकार इनको मान्यदा दे, क्यांकि वास्तव में से मुझाना के रूप म ही होते हैं।

संसद सरकार पर स्वयन प्रस्ताव पारित कर प्रभाव डाल सकती है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य, सामान्य कार्यों को छोडकर किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय

१ एच० गेटस्केल, हेनसार्ड, ग्रवट्० २१,१६४७ ।

^{`^} २ एम० यो० शर्मा—'पूबोंक्त पुस्तक', पृ० १८६ ।

पर विचार-विमर्श करता होता है। स्वान प्रस्ताव, प्रश्न—समय समाप्त होने के तत्काल पृथ्वात् किसी मी दिन रखा जा सकता है। तथापि, जो प्रस्ताव विची सार्वजनिक महत्व के विचय से सविषत नहीं हैं, या किसी तरह स्पष्ट नहीं है, या स्प्रा क्षेत्राधिकार में हैं या दिसी नायालय वे समक्ष हैं, वे सदन वे प्रध्यक्ष द्वारा प्रस्थीवन कर दिये जाते हैं।

स्पान प्रस्ताव गा सदन द्वारा पारित होना सरकार वे विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित होना है। प्रतिष्व सरकार प्राप प्रयत्न वस्ती है वि स्थान प्रस्ताव पर मतवान न हो।

ससदीय वहस

ससद मे बहस एक प्रत्य महत्वपूर्ण साधन है, जिसने द्वारा ससद सरकार पर नियम्बण करती है। बहस द्वारा ससद सरकार तथा प्रवासन की नीतियो एव नायों के सबस में जाननारी प्राप्त नरती है। बहस वा महत्व केवल उस समय होता है, जब ससद के समझ किसी नयी विधि के निर्माण या पुरानी विधि में सोधान या समान्ति के लिए विवयन है। बस्तुस्थित यह है हिन प्राय सारंजनिक महत्व के विषयो पर बहस होती है। 'एव तरह से हम कह सबसे है कि ससद के सदन प्राय किसी न किसी विषय पर बहस करते है कि ससद के सदन प्राय किसी न किसी विषय पर बहस करते है। विधेयन के प्रत्येक उपवन्य, वजद के मुख्य हिस्से, तथा प्रत्येन प्रस्ताव पर विचार-विमर्थ, वास्तव में बहस ही है। एक सुस्पट ससदीय परम्परा के प्रनुसार प्रधान मंत्री कभी भी विषयी वक के नेता के किसी विषय पर बहस करने के निवेदन को प्रस्वीष्टत नहीं करता है।"

इस प्रवार बहस वा महत्व यह है वि इसके द्वारा सरकार को अपनी नीति के विसी पहलू के स्पर्टकेरण और बवाब करने के सिए वाधित होना पढ़ता है। और उसनो उक्त विषय पर निन्न मनो को मापने में सहायता मिलती है। "इनके द्वारा विपसी दल, निची नीति के सीण तत्वों को प्रवाश में साकर उनमें सुधार वे सिए रचनारमव सुभाव दे सकते है। सदनों म हुए विचार-विमर्थ ग्रंस तथा जनता के समक्ष आते हैं, जिससे उक्त विषय पर जनमत का निर्माण होता है।"²

ससद मे यहस का सबसे महत्वपूर्ण विषय बजट है। जब ससद विचार विमर्श करने के दौरान विभिन्न विमागों की विसीय मागों की कडी जांच करती है, उस वक्त प्रत्येव प्रशासकीय विमागों की नीतियों तथा कार्यों का ससद की निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त होता है।

१. एम० पी० शर्मा—'पूर्वोक्त पुस्तक', पृ०१६० । २ वहो प्र०१६० ।

अत्तर्व वजट पर बहुस के समय प्रत्येक मंत्रात्व के नार्य को ससद की करों कर समक्ष लावा जाता है। सबेर में प्रकों तथा बढ़त हारा, प्रमानत वा निरुद्ध एवं प्रमानत इनेरीकाल होता है। "(डोटे-डोटे नियम के प्रत्योक्त महत्व-पूर्ण परिणाम होते हैं। वर्गोंकि विपक्षी दस्तों हारा सारा समय, कार्यपालिका की दुनेवाशों पर दृष्टियात करने ने ध्वतीत होता है धौर बहिर एक बार यह बिदित हो जोश तो विपक्षी तथा उनका उपयोग निरुद्ध करते हैं।"

अतः जैसा धर्न एटली का कथन है-"मेरे विचार मे सदन मे प्रका का समय बास्तविक अनतात्र का सर्वोस्तम खदाहरण है---मन्दियों से प्रका पूछने का, और सार्वजनिक रूप से सदन मे पूछे गये प्रक्तो का प्रमाद खारी लोकसेवा की सतर्क करना है।"

ससद की राष्ट्रपति के संबंध मे शक्तियाँ

मारतीय सर्वियान द्वारा ससद को, राष्ट्रपति पर नियन्त्रण के लिए कतिपय शक्तियाँ प्रदत्त की गईं हैं। राष्ट्रपति के सर्वेष मे ससद को निम्नलिखित शक्तियाँ है *—

१—राज्य विधान समायो के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर ससद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल का गठन होता है। उपराज्यति का निर्वाचन ससद के दोनो सदनो द्वारा किया जाता है।

२— राष्ट्रपति पर धनुक्छेद ६१ के झन्तर्गत महानियोग लगाकर समय उसे परच्युत कर सकती है। परच्यु इस सबय में, अंबे देखा जा चुका है, एक मगीर पृष्ट मुंद कर सकता है। पर पाई सो मार्च देखे समय राष्ट्रपति प्रदिक्त स्वाचन राष्ट्रपति सिवान का उल्लयन करता है तो राष्ट्रपति पर महानियोग लगाना समय नहीं होगा क्योंकि सबद सम में नहीं है और सबद के प्रचिवन धामत्रित करने का धिकार के क्या प्रवेशन धामत्रित करने का धामिकार के क्या राष्ट्रपति पर सहानियोग धामत्रित करने का धामिकार के क्या प्रचित्त करने का धामिकार के क्या राष्ट्रपति को हो है।

का आपकार कवन राष्ट्रपत का हाह । ३ — विधि-निर्माण-कार्य मुख्य रूप से सब्रद का ही उत्तरदायित्व है, परस्तु जब समद के दोनो सदनो द्वारा विषेयक पारित होता है तव उसे राष्ट्रपति की सहमति के जिए मेंबा जाता है । राष्ट्रपति विषेयक पर या तो क्रपनी सहमति

एन० बी० गांडगित, सकाउन्ट्रेबिलिटि झाफ पब्लिक एडिमिनीस्ट्रेशन द इण्डियन जनरल झाफ द पिलिक एडिमिनीस्ट्रेशन, ग्यु देहली भाग—१ न० ३, प्र० १६६।

२. सी॰ एटली—'सिविल सर्विस इन ब्रिटेन एण्ड फान्स, सम्पादित, डब्ल्यू ए॰ रावसन द्वारा—१९५६, प्र० २०।

देता है या ससद के पुनिवचार के लिए वापिस भेजता है। राष्ट्रपति के निषेधा-धिकार के बावजूद भी ससद ही सर्वोच्च है।

४—प्रतृच्देद १२३ वे प्रत्वर्गत जब ससद प्रिष्वेकान मे नही है, तब राष्ट्रपति प्रावश्वतता होने पद प्रध्यादेश जारी वर सकता है। राष्ट्रपति वे प्रध्यादेश लान्न तर वे बाधिकार पर साविधान निर्माताकों ने कत्विष्य महत्वपूर्ण प्रवाद को तित्र सहत्वपूर्ण प्रवाद की जिल सविधान में प्रतिवाद के उस अवदीय विशेषवर ससद की उस शिवत के रूप में है, जिसके द्वारा सबद प्रपत्ती दैठक में प्रध्यादेश को समाप्त कर सकती है। यह सप्त है कि राष्ट्रपति नी प्रध्यादेश जारी करने की श्रावत को दुरुष्योग में लाने से रोकने के लिए ससद को रुद्ध श्रावित है परन्तु पढ़ स्थय है कि स्वत्य को स्थापित एकति है परन्तु पढ़ स्थय है कि स्वत्य को स्थापित एकति है। परन्तु पढ़ स्थय है कि स्वत्य को स्थापित एकति का प्रधिकतम समय स्थापित स्थापित एकति का प्रधिकतम समय स्थापित स्थापित एकति का प्रधिकतम समय स्थापित स्यापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्यापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्यापित स्थापित स्यापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्याप स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थाप

राष्ट्रपति द्वारा प्रध्यादेश जारी करने की शक्ति वे माध्यम से, वार्यपालिका असीमित शक्तियो का अपहरण कर सकती है।

इत मिति वी तुलता, मारत सरकार वे प्रिधिनयम १६१६ तथा १६३५ वे धन्तर्गत गवर्गर जनरत की प्रध्यादेश जारी करने वो शाक्ति से की जा तवती है, जिसने तिटिश राज म वार्य पालिका की अरव्यत शक्तिशाली बनाया था। यद्यपि यह सत्य है कि मारत ने सवियान के धन्तर्गत राष्ट्रपति, मंत्री मण्डल की सलाहानुसार हो धम्प्रदेश जारी करेगा, परन्तु सवियान मे वोई प्रभावपूर्ण प्राश्यासन नहीं है कि कार्यपालिका इस सांक का दुरूपयोग नहीं करेगी। केतल राष्ट्रपति ही इस बात का निर्णाय है कि किन कारणो के वण प्रध्यादेश जारी विया जाये। न्यायालय, राष्ट्रपति के इस वार्य की उपर्युक्तत के प्रश्न की जीव नहीं कर समते हैं नहीं इस बात वी भी नि प्रध्यादेश प्राथा करने निल् प्रधावस्वकता भी था नहीं भर सांक्षित है नहीं इस बात वी भी नि प्रध्यादेश स्वर्ण की जीव वर सकते हैं कि प्रध्यादेश सविधान द्वारा प्रदत्त राष्ट्रपति को शक्ति वे धनुसार लागू किया गया है ध्रववा सही ।

सिवधान समा मे बाद-विवाद के दौरान डा० ग्रम्बेदकर ने, यह प्रश्न रखवर, राष्ट्रपति की ग्रष्टवादेश जारी करने की शक्ति का ग्रीचित्य बतलाने का प्रयत्न

४ ए० बी० लाल-'व इण्डियन पार्लियामेन्ट, १९४६, पृ० २३ ।

किया, "अत वरिस्तितियों की वरूपता करते में कोई कठियाई नहीं हो सकती है, जब बतेंगान कानून किसी घरूरमात एव तत्यात रूप से निर्मित परिस्थिति के लिए प्रयोग्त न हो। कार्यपालिका तब बया करें ? ऐसी गगीर, समस्या का मुदाबला करना होगा, धौर मेरे सतानुसार इस समस्या वा केवल यही समायान है कि प्राप्ट्रित को डक्त समस्या का सामना करने के लिए कानून लागू करने की सक्ति अदल की जारे क्योंकि व्यवस्थायिका सक्त में नहीं है।"

राष्ट्रपति भी कथातेथा लागू नरने में। यतिक के भीष्यत ना परीक्षण से दिवस्थों को ध्यान में एतकर करना वावस्थक होगा । सर्वश्रम मुर्कि राष्ट्रपति को स्विपान के क्ष्मार्थन संबद्ध को आविषान के क्षमर्थन संबद्ध को आविषान के क्षमर्थन संबद्ध होता कि निसी महत्वपूर्ण तथा ममीर प्रमान के सम्बद्ध में राष्ट्रपति की सध्यदेश जारी करने की शांकि करणा नर प्रमारीकी राष्ट्रपति की शांकि के समान प्रमारीकी राष्ट्रपति को शांकि के समान प्रात्तील राष्ट्रपति को संबद्ध स्वयन्त्राधिका समा के विकेष सब ग्रामर्थित न रहे की शांकि स्वयान हारा प्रवत्त की जाती चाहित्व थी, अपवा, द्विनीय, विद राष्ट्रपति को स्वयादेश जारी करने की शांकि प्रदान करना श्रति सावस्थक है तो क्या सावस्थक निर्माण की प्रमारीक समान के निर्माण कर ने स्वयं प्रात्म के सावस्थक करने की शांकि प्रदान करना श्रति सावस्थक है तो क्या सावस्थक नहीं चा ' धीर साथ ही, उचित होता कि स्विधान में इस विषय पर यह प्रावचान तरी राष्ट्र के कामानेय के जारी होने के दुस्त बाद सनद का स्विवेशन सामन्तित किया जारें।

संविधान मे इस प्रकार के प्रावधानी का प्रमाव जनतत्र के लिए हानिवारक है। श्री प्रमान प्रवच अस्वार (बोक समा के एक प्रव्यक्ष) ने "मारत में विधि तथा जनतत्र", विध्य पर १११६ में मायम देते हुए कहा था कि राष्ट्रपति कि अध्यादिस लाग करने की शक्ति स्वयादिय पद्धति में निषेधारसक है।"

५—यदि राष्ट्रपति सतुष्ट है िन भारत की मुरक्षा को, युद्ध या धाहा धात्रभय या धान्यिक व्यवस्था को धतरा है, तो बन्न सर्विधान के धनुन्देद १२५ (१) के सन्तर्यत, प्रापत्कालीन स्थिति की धोषणा नर सकता है। राष्ट्रपति धनुन्देद १४२ (३) के धनुसार उपयुक्त वर्गित खतरे की समावना में भी धाप्यकालीन स्थिति की धोषणा कर सकता है। "धाप्यकालीन गिरुम्ति राष्ट्रपति में निहित्त है। यह राष्ट्रपति नो निर्मारित करना है कि सक्टकालीन स्थिति है, राष्ट्रपति की हकते धोषणा करता है और राष्ट्रपति की हसको समान करना है। धापन्-

१ बी० प्रार० ग्रम्बेदकर, कास्स्टीट्युएन्ट ग्रसेम्बली डिबेट्स भाग म, पृ० २१३।

२. ए० धव्यगर-'ट्रिब्यून' ग्रम्बाला, फरवरी ६, १६५६।

वालोन स्थिति मे, ऐसा प्रतीत होता है वि सविधान स्थिति का सामना वरने वे लिए राष्ट्रपति पर निर्मर है !

तवापि, सविधान समा के वाद-विवादो म श्री श्रन्तादी स्वामी अव्यर ने यह स्पष्ट निया नि 'सविधान मे, वास्तव म, 'राष्ट्रपति' शब्द का तात्पर्य मश्री मण्डल, (बास्तविन कार्यपालिका) से है, जो लोगसमा ने प्रति उत्तरदायी है "² इस विषय पर सविधान में विद्यामान गतिषय श्रटियो नो ध्यान में रखना चाहिय।

श्रनुच्छेद ३५२ (२) वे श्रनुसार राष्ट्रपति द्वारा की गई मापत्कालीन घोषणा दो माह के बाद समाप्त हो जायेगी, यदि इसी बीच ससद के दोनो सदनो द्वारा वह स्वीवृत नही होती है। यदि घोषणा ऐसे समय हुई है, जब लोबसमा विघ-टित हो चुकी है या होने जा रही है, तब घोषणा के लिए दो माह के ग्रन्दर राज्यसमा की स्वीकृति प्राप्त करना श्रावश्यक है और तत्पश्चात् नई लोकसभा की बैठक के तीस दिन के बन्दर उसकी स्वीकृति होना भी बावश्यव है । यदि नई लोकसभा द्वारा घोषणा ग्रस्वीकृत की जाती है तो लोकसमा की बैठक के तीस दिन के बाद घोषणा स्वत समाप्त हो जायेगी । सविधान के अनुसार कार्यपालिका को ससद के समक्ष ग्रापत्नालीन घोषणा प्रस्तुत व रने वे लिए, दो माह की लम्बी ग्रविध दी गई है। जहां तथ आपतकालीन शन्तियों को नार्यपालिका में निहित करने वा प्रश्न है, इसके सबध में कोई ब्रापित नहीं है, परन्तु यह अत्यावश्यक है कि इसके साय ही इस विषय पर ससद की भूमिका को ग्रीर ग्रधिक प्रत्यक्ष, निकट. तथा प्रमावशाली करना चाहिये था, जिससे धापत्यालीन शक्तियो के कार्यपालिका द्वारा उपयोग पर ससद वास्तविक रूप से श्रकृष रख सक्ती है। इंग्लैंग्ड में कार्य-पालिका ग्रापतकालीन स्थिति की घोषणा करती है ग्रीर तत्पश्चात् ससद सहमति -प्रवत्त न रती है, परन्तु ब्रिटिश पद्धति, भारतीय पद्धति, से महत्वपूर्ण रूप में भिन्न है। इंग्लैण्ड म प्रापतकालीन घोषणा का ताल्पर्य ससद का स्वत पाँच दिनो मे थामित्रत होना है जबिक मारत में घोषणा के ससद के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए दो माह तब रोका रखा जा सकता है। अत यह स्पष्ट है कि ससद का कार्यपालिका पर, धापत्कालीन घोषणा की दृष्टि से, अपर्याप्त नियश्रण है क्योंकि यह तत्काल तथा प्रत्यक्ष नही है। इसका उपचार यह है कि ससद, विशेषकर लोकसमा, को भीर अधिक शक्तिशाली बनाया जाये । जब तक सदन (लोबसमा) सत्र मे है और बहुमत इसका विरोध करता है, कोई राष्ट्रपति सविधान के धारुछेद ३५२ का

१ के॰ बी॰ राव॰—'पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी इन इण्डिया, १६६१, पृ० २३१।

२ ए० के प्रयूपर,--'कान्स्टीट्युएन्ट झसेन्यली डिवेट्स भाग-६,पृ० ५४५-४६।

भारतीय शासन ग्रीर राजनीति

दृरूपयोय नहीं कर सकता है और, यदि, सविधान निर्माताओं द्वारा पूर्व में, ही कुछ सावधानी के उपाय, जो निम्नलिखित हैं, किये जाते तो उचित होता ।

एक-राष्ट्रपति की लोकसमा को भ्रामत्रित, स्यगित एव विघटन करने की शक्तियाँ श्रापत्कालीन समय भ स्थगति यह ।

दो-यदि ससद सत्र म नही है तो ऐसे समय मे आपत्नालीन घोषणा होने से ससद की बैठक सात दिन के अन्दर स्वत आमित्रत हो .

तीन-यदि ऐसे धापतकाक्षीन समय म लोकसभा विधटित है धीर धाप चुनाव सम्पत नहीं हुए हैं तो पुरानी सोवसमा स्वत पुन प्रमावी हो । मविष्य मे ऐसी

भावस्मिक स्थिति की समादना को कि राष्ट्रपति लोकसमा को भग करके धापत्-

कालीन घोषणा करे, दूर करने के लिए यह प्रावधान झावश्यक है, चार-लोक्समा को अपने को स्यगित करने, या अपना कार्यकाल बडाने का

ग्रविकार होना चाहिये। उपर्युक्त प्रावधान सविधान के ग्रापत्कालीन प्रावधानी का दुरूपयोग रोकने एवं समद की सार्वमौमिकता स्थायी रखने के लिए सविधान निर्मान ताभो की इच्छा के भीर अधिक अनकल होगे।

६—राष्ट्रपति मारतीय सेनाम्रो का सेनापति है। मनुष्युद ५३ (२) के धनुसार राष्ट्रपति मारतीय सेनाम्रो का सर्वोच्च ग्रधिकारी है। परन्त इस हैसियत मे राष्ट्र पति को ससद द्वारा निर्मित दिनि के धनुसार कार्य करने होंगे। अनुच्छेद २४६ के अनुसार ससद को, सातदीं अनुसूची मं उल्लिखित प्रयम सूची में दिये हुए सार विषयो पर विधि निर्माण करने वा अधिकार है। इस सूची (सप सूची) में विषय क्रमाक १,२ और १५ मारतीय सेना युद्ध तथा शान्ति विषयो से सर्वियत हैं। इस्तैण्ड मे युद्ध घोषणा तथा शान्ति स्यापित करने का अधिकार कार्यपालिका का है, परन्तु भारत में राष्ट्रपति बिना ससद की धनुमति के या विना ससद की बनुमति के पूर्वज्ञान के न युद्ध की धोषणा कर सकता है, न ही भारतीय सेनाग्रो का उपयोग कर सकता है। धतएव राष्ट्रपति मारतीय सेनाध्यक्ष होने पर मी स्वततापूर्वक ससद की इच्छा के विरद्ध, सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं कर

सक्ता है। संघीय कार्यपालिका तथा संसद के विभिन्न सम्बन्धों का सैदान्तिक ग्रायार पर धान्यवन करने के पश्चात्, हमारे समक्ष प्रश्न है कि भारत के सविधान के धन्तगैत व्यवहारिक दिष्ट से सधीय कार्यपालिका तथा ससद मे नया सम्बन्ध हैं ?

व्यावहारिक दिप्ट से सधीय कार्यपालिका तथा ससद के सबध

सैदान्तिक दृष्टि से सधीय कार्यपालिका तथा ससद के विभिन्न सम्बन्धो का

विश्लेषण करने के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि ससद प्रत्यन्त शक्तिशाली है

भीर कार्यपालिका सम्पूर्ण रूप से सबद के प्रधीन है। परन्तु, ससदीय पद्धति की कार्यप्रणाली की व्यारपा में फलस्वरूप, कित्रप्य ऐसे तरव प्यान में रखे जा सकते हैं, जिन्होंने मंत्री मण्डल को वास्तव में, एन प्रत्यन्त प्राक्तिशाली सस्या बना दिया है। फलस्वरूप समदीय पद्धति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका हे सम्बन्धों की स्थित, विज्ञुत पतट गई है। १९वी शताब्दी में विभेषकर त्रिटेन की समदीय प्रणाली की दृष्टि हो, ससद की प्रमुसता पर बल दिया जाता था, किन्तु २०वी शताब्दी में, मंत्री मण्डल की प्रसीमित शत्तियों प्राय चर्चा का विषय है। इसी विषय से सर्व में प्रशेष मोरिस जीत्र वा किया है "मारत म ससद वो एक बाह्य दिखावट के समान बतलाया गया है जो कित्तत से, एक शक्तिशासी निर्दृश्व तक की खिला सकता है। इस मत के लिए श्रेष कुछ तो वाग्रेस दल की शिक्तशाली स्थित को है। तथापि यह बतलाना उपयोगी होगा कि मंत्री मण्डल की निर्वृश्व तक के आरोप से, मारत के बाहर मी (क्षीण) सुपरिचित हैं, वे लीग जिनका यह दिवार पा कि स्वतत्रता का प्रय (सरकारी) नार्यो के शास्ति सी विनंदान ना प्रन्त होगा, जनके यह सीलात होगा कि विटिश ससदीय प्रणाली में सत्तिशाली सरकारो को प्रोत्ताहन मिलता है। "

मारत में केन्द्र में, ससदीय कार्यपालिका (मधी मण्डल) की स्थिति प्रत्यन्त प्रक्तिशाली है। धतएव कार्यपालिका तथा ससद के सम्बन्धों का व्यवहारिक दृष्टि से विश्वेषण करते हुए हमारा उद्देश्य यहाँ पर उन तत्वों का प्रध्ययन करना है, जिनने कल्तवक्ष्य वास्तविक कार्यपालिका (मधी मण्डल) मारतीय राजनीतिक प्रणाली में, एक शतिकाली सस्या हो गई है।

ससद के सबध में मंत्री मण्डल की शक्तियाँ

ससदीय प्रणाली मे मश्री मण्डल ससद के निचले सदन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मारतीय सविधान के श्रनुचार मित्रयो को ससद का सदस्य होना धावश्यक है। श्राधुनिक समय में मश्री मण्डल समदीय प्रणाली में वास्तविक कार्य-पालिका के रूप में एक श्रत्यन्त शक्तिशाली सस्या बन गया है।

मत्रो मण्डल के घत्यन्त शांकिशाशी होने पर मी, ससद केवल एक शक्तिवहीन सस्या नहीं रह गई है। भारतीय सविधान के लागू होने के पश्चातृ, शारतीय ससदीय पढ़ित की जड़ों को शक्तिशाली करने में एवं सरकार के एक उपयोगी ध्रम के रूप में कार्य करने में समय-समय पर ससद ने निश्चित हो महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंग्लैण्ड में भी ससद के प्रत्यन्त शक्तिशाली तथा उपयोगी सस्था होने

१. डब्ल्यु एच० मोरिस जोन्स-पार्लियामेन्ट इन इण्डिया, १६५७ पृ० ३२८ ।

भारतीय शासन और राजनीति

305 पर भी, मंत्री मण्डल की शक्तियों में वृद्धि हुई है। यत ब्रिटिश भंत्री मण्डल के लिए यह कहा जाता है कि यह निरनुश हो गया है। "जब इसकी वहुमत प्राप्त

है, इसनी स्थिति विज्ञान्तियो द्वारा नियत्रित निरमुशता है।"1

मारत भे मत्री मण्डल की शक्तियों म बुद्धि के निस्तावित कारण हैं।

१ —मारत मे, काग्रेस दल को १६७१ फरवरी-मार्च के मध्याविध चुनाव में लोकसमा म मारी बहमत प्राप्त हवा है। एक राजनीतिक दल के रूप में काग्रेस दल ने अपने सगठन एव कार्यों के दुष्टिकीण से एक विशाल यत्र का रूप घारण कर लिया है, जिसना सम्पूर्ण श्रस्तित्व तथा सफ्लता एक नेन्द्रीय इजिन पर निर्मर रहता है। डा० एम० पी० शर्मा का कथन है- कांग्रेस सगठन का मुख्य आधार व्यवस्यापिका मे या बाहर शक्तियो का निम्न-समितियो के अपेक्षा उच्च समितियो में, तथा साधारण सदस्यी की अपेक्षा नेताओं म बेन्द्रीयकरण होना है । यह इसके दलीय अनुशासन एव ससदीय पद्धति के अनुसार कार्य करने के लिए जैसा कि ब्रिटेन में समभा जाता है, ब्रत्यन्त उत्तम है।"2

का ससद में आंल-मंदकर श्रवमोदन ने सिद्धान्त से, ससद में, सामान्य तौर से सरकार के पक्ष म बहुमत बना रहता है। इसी कारण जब श्रीलालबहादुर शास्त्री एव श्रीमती गांची नी सरकारों के विरुद्ध श्रविश्वास प्रस्ताव लाये गये, दलीय भूत्रशासन के कारण प्राप्त हुए बहुमत से इन प्रस्तावों को विफल कर दिया गया। ससदीय प्रणाली मे दलीय अनुशासन के कारणो तथा परिणामी पर प्रो० लास्की

दल में भ्रतुशासन की कठोरता के परिणाम स्थरूप सदस्यों को ग्रपनी सरकार

के ब्रिटिश समदीय पद्धति से संबंधित कतिषय विचारों की, जिन्हें समान रूप से भारतीय पद्धति म भी उपयोगिता-पूर्वक लागू किया जा सकता है, व्यान मे रखना लामदामक होगा ।

'दल मधनुषासन की कटोरताम वृद्धि ने कारण, साधारण नहीं हैं। कुछ माना म, पह इस तथ्य ने कारण हैं नि श्रायुनिक ब्रिटेन के लिए विस्तृत दलीय सगठन की ब्रावश्यकता है। कुछ मात्रा में (समाज के कार्यों में) राज्य द्वारा हस्त-क्षेप की बावश्यकता के फलस्करूप ससद में सरकारी कार्यों में भी वृद्धि हुई है, और यदि उन नार्थों को समय में ही करना है तो और अधिक कठोर दलीय अनुशासन आवश्यक है। कुछ मात्रा मे कदाचित इसलिए मी कि आधुनिक मतदातागण, सिद्धान्तो पर व्यक्तित्व के सन्दर्भ में विचार करते हैं, वे सदस्यों का निर्वाचन, उनके स्वय की अपेक्षा उनके नेताओं के कारण अधिक करते हैं। सम्पूर्ण दलीय व्यवस्था

१. ब्रार० सूर, हाउ ब्रिटेन इञ्च गवर्नड्, १६३= पृ० ६६ । २. एम० पी० शर्मा—'पूर्वोवत पुस्तक, पृ० २६५ ।

ब्रावस्थक रूप से ब्यावसायिक हो गई है । ग्रीर उसके कार्यों के विस्तार के कारण इसको ऐसे ग्रनुवासन की ग्रावस्थकता है जो कि सैनिक ग्रनुवासन के समान है।"⁹

मारत मं भी मंत्री मण्डल को स्थिति के शनितशाली हो जान का एक कारण यही है कि दलीय अनुपासन की कठोरता के कारण, मंत्री मण्डल को ससद में सामान्यत बहमत प्राप्त रहता है।

२—मनी मण्डल की शक्तिशाली स्थिति का एक अन्य कारण सामृहिक उत्तर-दायित्व का सिद्धान्त है। मन्नी मण्डल के एक इनाई के रूप में वार्य करने पर ही सामृहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को सफलतापूर्वक वार्यान्तित क्या जा सकता है। लोकसमा के प्रति मनी मण्डल के उत्तरदायित्व के सिद्धान्त द्वारा के क्या मनी मण्डल में एकता बनी रहती है, परन्तु इसी के प्राप्त बहुमत क प्राधार पर मनी-मण्डल ससद की वार्यवाई या निर्देशन तथा नियन्त्रए कर सकता है।

३-मनी मण्डल की प्रक्तिपाली स्थिति का एक ग्रन्थ महत्वपूर्ण कारण ससद को मग करवाने की उसको शक्ति है। ससदारमक पद्धति म सामान्यत राष्टा-घ्यक्ष प्रधान मनी के परामर्शानुसार ही ससद के निचले सदन लोकसभा को मग कर सकता है। इन्लैण्ड मे यदि मंत्री मण्डल के विरद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव पारित हो चना है तो उसको अपना इस्तीफा देना आवश्यक है। परन्तु ससदात्मक पद्धति की एक सस्पष्ट परम्परा के अनुसार अपना इस्तीफा देने के पूर्व प्रधान मंत्री ससद के निचले सदन को मग कराने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है, जिससे भ्राम-चुनाव करवाये जा सकें। श्राम चुनाव से यह ज्ञात विया जाता है कि वास्तव में, मतदातागण, ससद के मंत्री मण्डल के विरद्ध ग्रविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बावजूद भी मनी मण्डल के समर्थंक है या नहीं । सामान्यत , प्रवान मनी के अनुरोध पर सम्राट् ससद को मग करता है। तत्पश्चात, यदि श्राम-चनाव म मत्री मण्डल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो बहुपुन. सत्तारूंड हो जावेगा, प्रन्यथा नती मण्डल को इस्तीपा देना ही होगा । मारत म मी चूँकि सविधान के अन्तर्गत ससदात्मक पद्धति स्वापित की गई है, इसलिए उपर्युक्त परम्परा को मान्यता दी गई है। सविधान के धन्तगत राष्ट्रपति को लोकसमा को मग करने का अधिकार है। किन्तु सामान्यत राष्ट्रपति इस ग्रविकार का उपयोग प्रधान मनो की सलाह के अनुसार ही करेगा।

ससदात्मक प्रणाली में, ससद ने निचले सदन नो मग करने ने लिए प्रधान मनी का राष्ट्रपति को सलाह देने का ग्रधिकार निश्चय ही ऐसा एक प्रमाववाली साधन है, जिससे मनी मण्डल निचले सदन पर नियन्त्रण नरता है। यदि ससद के

१. एव॰ सास्की, 'पार्लियामेण्ट-गर्वमेन्ट इन इण्डिया' १६३८, पृ० ७४।

२०६ निचले सदन को मनी मण्टल के विरुद्ध प्रविक्वास प्रस्ताव पारित करने का ग्रापि-कार है तो सत्री मण्डल को राष्ट्रपति को सदन मग कराने की सलाह दैने का श्रिधिकार है। ससदात्मक प्रणाली के इतिहास के ग्रध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट हो जावेगा कि मंत्री मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना एक सरल कार्य नहीं है, क्योंकि जैसा देखा जा चुका है, क्योर दलीय धनुशासन के कारण मत्री मण्डल को प्राय बहुमन ना समर्थन रहता है। ऐसी स्थित में यदि मत्री सण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का प्रयन्न किया जाता है, तो मत्री मण्डल इसका बदला सदन को मण करने की सलाह देवर चुका सकता है, क्योंकि ससद के मग होने के परिणाम कनियय सदस्यों के लिए अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो सकत हैं। उनकी झात है कि ससद के मग होने के पञ्चात् उनकी पुन. श्राम-बनाव का सामना करना होगा, जिसम उनको समय श्रीर धन व्यय करना होगा, ब्रोट इसके उपरान्त यह भी सम्मव है कि वे निर्वाचित न हो सकें। परि-लाम स्वरूप, ससद को प्रयासरेत की चेतावनी, सदस्यापर एक महत्वपूर्ण अकुश है जिससे मत्री मध्यत के विरुद्ध उनके कार्य करने पर रोक लगती है। सारतवर्ष म परवरी मार्च १६७१ म मध्याविधि झाम-चुनाव कराने के लिए प्रधान मंत्री श्रीमती गाघी भी सलाह पर राष्ट्रपति श्री बी॰ बी॰ गिरि महोदय ने दिसम्बर १६७० में ससद को मग किया। वैसे तो विरोधी दल समद मग होन के पूर्व वारम्बार भ्राम-चुनाव की मांग कर रह थे, किन्तु जब ससद की प्रधान मंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ने श्राम-बुनाव कराने के लिए मग किया तो विरोधी दलों ने एक स्या राग भ्रतापना भारम्म निया कि प्रधानमंत्री की संसद के भग कराते के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने ना ग्रविकार नहीं था। विरोधी दलों नी इस विचित्र मनोवृति का कारण यह या कि धाम-चुनाव चाहते हुए भी उनकी चुनाव ना मय था, यद्यपि चुनाव के पूर्व प्रपत्ने वननव्यों में उन्होंने सदा ग्राप्ता व्यक्त नी नि श्रीमती गांधी नी नयी नांग्रेस नो वे श्रासानी से पराजित नरेंगे। इस मनो-वृत्ति ने नारण जद चुनाव की वास्तविकता का उनको सामना करना पडा तो उन्होंने प्रयान मत्री पर प्रहार करना प्रारम्म किये कि प्रयान मत्री को राष्ट्रपति द्वारा ससद मग करवाने का कोई अधिकार नहीं या । प्रधान-मत्री द्वारा मसद को मग करने से लिए राष्ट्रपति को दी गई सलाहे का खीकित्य विशेषकर इसमें है कि ससद को मय करने का उद्देश्य धाम-बुनाव समपन्न कराके महदातस्रों की इच्छा ज्ञात करना था, जिसके माधार पर नयी सरकार की स्थापना की जा सके। ससदीय प्रणाली में, सरकार ने प्रति मतदातागण की इच्छा को ग्राम-चुनाद के माध्यम से जात करने के अधिकार के सबध में कोई मतमेंद नहीं हो सकता है।

भनएव यह स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री का, ग्राम-चुनाव करवान के लिए राष्ट्रपति को ससद मग करने की सलाह देने का अधिकार तथा कटोर दनीय भ्रमुगासन ससद में मंत्री मण्डल की स्थिति को प्रावितशाली करने म सहायक हैं।

डा॰ एव॰ पाईनर ने ब्रिटिंग ससदीय पढ़ित में दृष्टियोण (ध्रीर यह भारतीय समयीय पढ़ित पर पूर्णत्या लागू होता है) से, निम्नलिसित गाना मन्पट निया है हि निस्त प्रदार क्यार दलीय अनुसासन ने नारण प्रत्या दलीय सम्बन्ध स्वतार हि निस्त प्रदार क्यार दलीय सम्बन्ध स्वतार ना प्रवार प्रदार कराय स्वतार मा प्रवार प्रवार कराय स्वतार मा प्रवार प्रवार कराय स्वतार मा प्रवार कर स्वतार कर

४—इस प्रवार मत्री मण्डल वो मितियों में बृद्धि वा एवं फ्रीर फ्रन्य महत्व-वृण नारण हमारे समक्ष भाता है वह है ि सभीय ससद में एक समिदित तथा मित्रवाली विषक्षी दल वा प्रवाब । १९५० हो, जब मारत के सविधान वो लागू निया गाय था, साद में एन समिदित विषक्षीय दल वे स्थान पर कई राजनीतिक दल हैं, जिनमें सलास्ट दल वी प्रालीचना बरने वो, विन्यु उसने स्थान पर एक वैवल्पित सरवार वे निर्माण करने वी क्षमता नहीं है। यह प्रमाख यासत्व में मारतीय ससदीय प्रणाली वी एन प्रमोर बृद्धि है, यथोनि ससदीय प्रणाली की वार्यपालिना पर नोई प्रमावशील प्रवृत्य न होने से, वार्यपालिना निरनुषाता वे एवं पर प्रमास हो तकती है।

४—प्रत्यायोजित-विधि वे नारण मी भारत मे वार्यपालिका की सस्तियो मे वृद्धि हुई है। सामान्यतः विधि वे तीन प्रकार है।

क — सर्वोच्च विधि-जो लिखित सविधान ने रूप में देश का सर्वोच्च कानून है।

य-साधारण जिवि-जिसना निर्माण, सविधान ये अन्तर्गत स्थापित व्यवस्था-विका समाध्रो द्वारा सविधान के अनुसार निया जाता है।

ग---प्रत्यायोजित विधि--साधारणतथा, विधि-निर्माण-वार्य व्यवस्थापिया समाग्रो द्वारा निया जाता है, परन्तु श्रायुनिय समय मे, जनतात्रिय राज्य मे,

१एव० फाईनर-'द ब्योरी एण्ड प्रीविटस स्राफ मार्डन गर्वमेण्ट', १६५० पु०६२०. १४

व्यवस्थापिका सभा पर कार्यमार बहुत हो गया है। प्रत्येक सन मे व्यवस्थापिका को एक बड़ी सख्या में विषेषक पारित करने होते हैं। मारतीय ससद भी, देश ने विकास के लिए अनेको विधेयको की पारित करती है। मारतीय सविधान का उद्देश्य एक लोक क्ल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के कार्य क्षेत्र में व्यापक वृद्धि होना स्वाभावित है। लोक क्ल्याण-कारी राज्य में विधि-निर्माण-कार्य के लिए विशिष्ट तकनीकी निपुणता की ग्रावश्य-क्ता है। ब्रतएव यह आवश्यक है कि तकनीकी विषयो पर नियमो का निर्माण कार्य, प्रशासकीय विशेषज्ञी द्वारा विचार किये जाने के लिए छोड दिया जायें। पुरन्त इन विशेषज्ञो को तक्तीकी विषयो पर नियमो का निर्माण ससद द्वारा पारित विधि के क्षेत्र मे ही करना होगा । घत ससद विधि की रूपरेखा प्राय. निर्वारित करती है, जिसके अन्तर्गत नार्यवालिका, समद द्वारा प्रदत्त शक्ति के ग्रनुसार नियमो वर निर्माण बरती है। इसको प्रत्यायोजित-विधि बहा जाता है। कार्यपालिका, प्रत्यायोजित-विधि का उपयोग, ससद द्वारा पारित दिधि के निर्वारित क्षेत्र म. निवमी का निर्माण करने के लिए करती है, जिससे ससदीय विधि को प्रभावपूर्वक कार्यान्त्रित किया जा सके। प्रत्यायोजित विधि के रूप मे निर्मित नियमो का प्रमाव ससदीय दिथि के समान ही होता है और इनको न्याप-लय म तब ही चुनौती दी जा सकती है जब मूल विधि, जिसके धन्तर्गत इसका निर्माण हुन्ना है, अवैवानिक हो । अतः अवत्यक्ष रूप से, भारत मे प्रत्यायीजित विधि से कार्यपालिका की शक्तियों म बृद्धि हुई है।

६ — सिन्तम महत्युमं कारण, जिसमें सारत में कार्यवालिया के सांक्याती वर्तने से सहायना मिनती है, प्रशासकीय न्यास है। ''बुंकि सरकार समये विस्तान प्रकार के वार्यों को पूर्व करे, पता. प्रशासकीय क्यों को विश्वि निर्माण तथा निर्मय देन के प्रविकार प्रवास करने के परिचार वन मनी है।'' विभिन्न प्रयासकीय विद्यापों की निवसी का निर्मय विवादों पर निर्मय देने का सी प्रशासकीय हो। उदाहरण के लिए, प्राप्त-पर प्रणीलीय नामायांचिकरण के प्राप्त नामायंचिकरण के प्राप्त नामायंचिकरण के प्राप्त कर निर्माण का विद्यापा का किए सामायंचिकरण के प्रप्तान तथा सदस्यों की निर्माण का प्रशासकीय नामायंचिकर का स्वाप्त कर का स्वप्तान स्वप्तान का स्वप्तान

१. ए॰ पी॰ हस्स्मानी-'सम प्रॉबनेम्स खोक एडमिनिस्ट्रेटिय लाइन इण्डिया' १६६४ पूर ४

धायोग) निर्वाचन सबसी विवाद, (निर्वाचन-त्यायाधिकरण) रेलवे कर, (रेलवे कर त्यायाधिकरण) धादि । कमी-कमी त्यायाधिकरणो की स्यापना किसी तदर्य उद्देश्य के लिए की जाती है । इस तरह, जीवन-बीमा धर्षिनियम १६५६ द्वारा केन्द्रीय सरकार को एक या धर्षिक त्यायाधिकरणो नी स्थापना करने के लिए धर्मिङ्क किया गया है, जो विभिन्न जीवन बीमा कम्पनियों के मुखाबजे को, उनके व्यवसाय को निगम के लेने के कारण निर्पारित करेंगे।

एक ग्रन्य उदाहरण प्रशासकीय-न्याय का प्रस्तुत किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा धिपितियम १९५७ के धनुंसार विदेशी मुद्रा धिपितियम १९५७ के धनुंसार विदेशी मुद्रा धिपितियम १९५७ के धनुंसार विदेशी मुद्रा सवधी नियमी का उत्तक किया है या नहीं। डायपेक्टर की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है। बायपेक्टर के निर्णय के विद्यु विदेशी मुद्रा प्रायोग को, जिसका अध्यक्ष एक सदस्य होता है, प्रणोत को जा सकती है। धायोग के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है। इस प्रायोग का निर्णय धीवम होता है।

इन उदाहरणों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मारत में कार्यपालिका के प्रशासकीय न्याप के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य है। मन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने हैं कि उपर्युक्त तत्वों के कारण भारत में मत्री-मण्डल (वास्तविवक वार्य-पालिका) की स्थिति शक्तिशाली है।

संसद के सबच में राष्ट्रपति की शक्तियाँ

यवाप सविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को सप्तद के सबय मे कतिप्य शक्तियाँ प्रदत्त है, फिर मी यह विदित रहना भरवावस्थक है कि इस शक्तियो का उपयोग राष्ट्रपति, सविधान द्वारा स्वापित ससरीय प्रणाली की पार्वभूमि मे ही कर सकता है। यह सत्य है कि राष्ट्रपति इन ततियो से सदद पर प्रमाव बाल सकता है, परन्तु यह प्रमाव सकतीय पद्धति के अनुकृत ही होना आवश्यक है। ससद के सवय मे राष्ट्रपति की निम्नलिखित शावनयाँ हैं:—

१--सिवयान के मनुच्छेद न्ध्र के अनुसार राष्ट्रपति को ससद को आमित्रत तया स्विगत करने का अधिकार है।

र--- मजुन्देद १०० (१) के अनुसार राष्ट्रपति को ससद के दोनो सदनो मे, विसी साधारण विषेषक सबधी मतमेद दूर करने के लिए दोनो की सयुका बैठक भागतित करने का भविकार है।

१. ए० पो० हस्समानी—'सम प्रॉबनेन्स मांफ एडमिनिस्ट्रेटिय ला इन इन्डिया' १६६४ पु० ६ ।

भारतीय शासन ग्रौर राजनीति

२—राष्ट्रपति को सिवान के अनुस्देत = ६ के धनतर्गत समय में अभिभाषक देने तथा सदेव मेजने का अधिकार है। इस धिकार द्वारा राष्ट्रपति समय को, जन करवाण के लिए, अवन अनुनत वादा व्यक्तित्व में प्रमावित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी विषय के विदेश के समय से समय को सेवें स मेजन हता है। राष्ट्रपति के सावण देन तथा सदेवा मेजने के अधिकार के आपने का आपने कर तहा है। राष्ट्रपति के सावण देन तथा सदेवा मेजने के अधिकार के आपने कर है। उपाय सद कहा जाता है कि समदीय पढ़ित की पूछ माम में सद अधिकार अध्यक्ति की पूछ से स्वयंत्र में स्वयंत्र के स्वयंत्र में राष्ट्रपति को एक अस्य महत्वपूर्ण स्विकार अस्य

२१२

है, जिसनो निवेवाधिकार नहां जा सकता है। राष्ट्रपति के निवेवाधिकार का उद्देश्य ससद द्वारा जल्दमाजी भ पारित विजेयक पर एक सतुलित एवं जन-उद्देश संसद द्वारा अल्पनामा नगरा तानिक स्रवरोत लगाना है, जिससे संसद उक्त विधेयक पर पुन विचार कर सके। जब सप्तर एक विधेयक को पारित करती है, उसको राष्ट्रपति के विवार के लिए / भेजा जाता है। राष्ट्रपति उक्त विधेयकप र अपनी सहमति वे सकता है,या यदि वह धन विवेयक नहीं है तो सतद ने पुनविचार के लिए वापित लौटा सक्ता है। अपुच्छेद १११ के अनुसार यदि ससद उपन विवेयक को पुन पारित कर भेजती है तो राष्ट्रपति को सहमित देना आवश्यक होगा। सन राष्ट्रपति के निर्येषाधिकार को जनतात्रिक कहना उचित है नयोकि उसके उपयोग द्वारा वह ससद को जनता को इच्छा के अनुकुल पुनर्जिचार करन के लिए बाध्य कर सकता है। किन्तु विधेयक को वह न तो स्वय ही संवाधित कर सकता है, न समाप्त ही कर सकता है। विवेयक पर ससद की शक्ति ग्रतिम है। ग्रमरीका में, जहाँ पर सधीय सरकार की कार्यप्रणाली शक्ति पृथकत्रण एव ग्रवरोध तथा सन्ततन के सिद्धान्तो ने अर्मुत मिथण पर आधारित है, अमरीकी राष्ट्रपति की भी, सविधान के अन्तर्गत निर्वेदाधिकार के रूप में, व्यवस्थापिका सभा (काग्रेस) का विधि निर्माण शक्ति पर एक जनतानिक अपरोध है। अमरीका में यदि कांग्रेस किसी विवेषा को पारित करती है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा विचार किय जान के लिए मेजाजाता है। राष्ट्रपति को इस दिन के ब्रन्दर ब्रपनी सहसरित देना चाहिये।

जारतीय सविधान ने प्रत्यंत यदि राष्ट्रपति विवेयन ने सबस में प्रपत्ने नियोगीस्वार ना प्रयोग नदता है और सबद उस विवेयन को प्रयुत्ते दो तिहाई बहुमत ने पुत्र पारित कर देती है, तो विजेयक, राष्ट्रपति को प्रापति के बावजूद भी क्षेत्रि हो जावेगा। ५—मन्त मे अनुच्छेद १२३ (१) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति नो अध्यादेश लागू कराने का अधिकार है। जब ससद सन मे नहीं है और ऐसी परिस्थित मे किसी विषय पर वानून निर्माण करने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारों कर सकता है। जैसा, पूर्व मे देखा जा चुका है, राष्ट्रपति की अध्यादेश लागू को की चित्र सरक की कानून निर्माण शक्ति का अपहरण नहीं तो उस पर अधिक का से देश

द्वा विषय के अध्ययन के अस्त में इस मूल बात पर बल देना आवश्यक है कि अन्य ससदीय प्रणालियों के समान, भारत में भी ससद के नार्यपालियां पर नियन्त्रण के मूल सिद्धान्त को सियान हारा मान्यता दी गई है, बाहे व्यावहारिक जीवन में मंत्री मण्डल जिंदिताली वियो न वन गया हो। जारतीय सिवान के सन्त्रीय संसद तथा नार्यपातिका के सन्द्रीय को रूप में कतित्रय जीवनों में मूने पण्डल हुस्त के प्रति अवरोध के रूप में कतित्रय जीवनयां प्रदान की गई है, जिनसे संधीय सरनार के में दीनों अग ससदीय सीमाओं में उचित रूप से नार्य कर सके। सिवान में इस वियम पर वितय प्रतियो ही जिनकों सुर वर्गमा आवश्यन है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में सतद की भूमिना अपूर्ण है, उस स्थित में जब कि सहसियोग के संबंध में सतद की भूमिना अपूर्ण है, उस स्थित में जब कि संबद के बिराम-काल में राष्ट्रपति हारा संविधान का उल्लंघन नियम गया है। इसके अतिरिवन, राष्ट्रपति की अध्योश का सुकरने की शावित भी, जुछ परिवित्यतीयों में मम्मीर सिद्ध हो असती है। भारतीय सतद में एवन अम्य महत्वजूल बृद्धि यह है कि एक और तो बाग्रेय तक को मारी यहमत जान्त है तो सूत्ररी और इस बारी वहमत को जनताविक रूप वे सार्य पर ही निर्मेद है। मसन्त्र है ना एक भारती का सार्य है। इसके सार्व रहम को जनताविक रूप है सिद्ध ही सिद्ध ही निर्मेद है। मसन्त्र है ना स्वत्र ही सार्य हिता सार्य हो सार्य सार्य वहमत को जनताविक रूप है सिद्ध ही निर्मेद है। सहनु, इस परिस्थितियों में, मारत में वार्यपालिका पर संसद की स्वत्रता विवाद ही निर्मेद है। सहनु, इस परिस्थितियों में, मारत में वार्यपालिका पर संसद की स्वत्रता विवाद ही निर्मेद है। सरनु, इस परिस्थितियों में, मारत में वार्यपालिका पर संसद की स्वत्रता विवाद ही निर्मेद है। सरनु, इस परिस्थितियों में, मारत में वार्यपालिका पर संसद की स्वत्रता हार्या स्थान हो।

भारतीय संसद में प्रतिपक्ष दल

त्योत्तन भी एन थेट्ड परम्परा तथा धावायनता यह है नि उसमें काता सी सरकार के नामों भी उमुक्त धालोनना प्रत्याक्षीनना करने को स्वीकृति दी जाती है, जन तोगों भी नई सत्तर स्वीतिस्तित सर्च के लिए निमित्त क्ष्म से प्रवस्त एवं स्ततनता दी जाती है, जो प्रचार कार्य द्वारा सगटन निर्माण करते है तथा विनका उद्देश्य धानितृष्णं तरीनों से जनमत को परिवर्तित कर सरकार में परि-वर्तन ताना है।

लोकतन में सार्वमीमिकता जनता में ही निहित होती है। जनता ना अधिकार है कि अपने शासको का सामयिक निर्वाचन करें। मतदाताओ को, प्राय. एक / निश्चित ग्रवधि के बाद ग्रपने शासको की नीतियो तथा कार्यों की समीक्षा करते हुए यह प्रविकार है कि वे निर्णंग दें कि उन्हें पुन सत्ता सौंपी जाये प्रयदा नहीं ? प्रयत्ति श्वाम-चुनाव के समय प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को मतदातामी की सामयिक जाँच सा सामना करना होता है। "इस प्रकार राजनीतिश को अपने कार्यों का लेखा देने की ब्रावस्थकता रूपी पूनर्जीवित-ब्रवरीय का सामना करना होता है।' र परन्तु लोक्तन में सरकार के कार्यों तथा नीतियों के जाँचने ना ना पिंद केवल ग्राम चुनाव के दौरात ही किया जाये, तो सत्तारूड दल को दो श्राम धनाव के दरम्यान निरंकुण बनने में ग्रासानी रहेगी। लोकतत्र तथा स्वतत्रता की कीमत जनता का निरुतर सतर्क होना है। लोनतत्र की इस-बावस्थवता की पूर्ति मे राज नीतिक दलो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंग्लैण्ड तथा श्रमेरिका जैसे जनतात्रिक देशों में मुख्यत दो-दलीय पद्धति पाई जाती है। यूरोप ने नितपय देशों तथा भारतवर्ष में वह दलीय पद्धति है। राजनीतिक दलों की सख्या चाहे क्तिनी हो, मूल बात तो यह है कि लोक्तर में जनता को व्यवस्थापिका में अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार होता है। अनता का अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण है, बयोकि इसके उपयोग द्वारा जनता प्रतिपत्नी दल को सत्तारुढ ग्रीर सत्तारुढ दल को प्रति-

१. एम० स्ट्रुप्रट-ब्रिटिश एप्रोच ट् पॉलिटिक्स, १६३८ प्र० २१४ ।

२. बी॰ वार्ड -डेमोक्रोसी ईस्ट-वेस्ट, १६४६ पृ० १०।

पक्षी दल मे परिवर्षित कर सकती है। अतएव एक समठित प्रतिपक्षी दल माघी वैकल्पिक समा शासक दल हो सकता है, जिसका श्रस्तित्व 'सरकार पर एक श्रावश्यक जनतात्रिक श्रवरोष' पे रूप मे है।

ग्रत लोकतथ मे राजनीतिक दलो की स्रावश्यकता के दो कारण है।

सर्वप्रथम राजनीतिक दलो वे माध्यम से जनता श्रपने शासको का निर्वाचन करती है।

द्वितीय, राजनीतिक दला द्वारा विभिन्न प्रवार की वैविध्यक नीतियौ तथा कार्येक्षम जनता के समझ रखे जाते हैं, जिनसे जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है और वे यह निर्णय ले सकते हैं कि विस प्रकार की सरकार स्थापित की जायेगी।

ं एक राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य जनता ने ऐसे सगठन से है जो कितपर राजनीतिक तिद्धारतो तथा उईश्यो को मानते हुए, सबैधानित्र साधनो के माध्यम से एक साथ कार्य करते हैं। "जोनतव मे कोई भी राजनीतिक त्व यदि अपन-सुनाव मे जनता का विश्वास अपनी नीतियो तथा कार्यक्रमा द्वारा प्राप्त आपने होता है, तो सरकार की वागडोर को सम्हालने का उत्तरायित्व उसे सौंधा जाता है। क्रम्य राजनीतित्व दल, जो नविद्य म सरकार निर्माण करने की समता रखता है। क्रम्य राजनीतित्व दल, जो नविद्य म सरकार निर्माण करने की समता रखता है और जिसकी नीतियों व कार्यक्रम है, व्यवस्थापिका मे प्रतिपक्षी दल के रूप मे होगा।

ससद में सलारूड दल की गीतियों की सतत जांच करने वे लिए एक प्रतिपक्ष दल की धावयनका होती है, अन्यया प्रजातम में निरकुषता में प्रवेश का सदैव मय बना रहेगा। म्रत ससदीय पद्धित में राजनीतिक दलों की भूमिका का अपना विणिष्ट महत्व है। जैसा कि लार्ड लिण्डके का क्यन है- 'उत्तम प्रतिनिधि सरकार के लिए न नेवल एक बितवाली प्रतिपक्षी दल की झावश्यकता है किन्तु उसके लिए यह भी आवश्यक है कि प्रतिपक्षी दल बैंक लिपक सरकार के सदूश हो।"

लोनतम म राजनीतिक दलो था महत्य दो प्रकार का है। सर्वप्रथम, वे जनता को राजनीतिक विषयों के सबस में शिक्षित तथा सजा करते हैं जो सरकार की निरकुण प्रवृतियों थो रोजने के लिए आवश्यक है। इतिया, व्यवस्थापिता में वे स्वय सरकार पर एक अकुण के रूप में है, और विभिन्न साधनों द्वारा सरकार को उसके दायरावी के प्रति सज्जप रखते हैं। वस्तुत लोकतज का अस्तित्व प्रतिपत्नी उसके दायरावी के प्रति सज्जप रखते हैं। वस्तुत लोकतज का अस्तित्व प्रतिपत्नी उसके दायरावी की स्वत्वता पर निर्मार है, जिसके प्राधार पर थे सरकार की नीतियो

१. एम० पी० शर्मा—व गर्वभेग्ट म्राफ इण्डियन रिविलक १९६० पृ०२७७ । २. ए डी. लिण्डसे-ब इस्सेन्शल्स म्राफ डेमोक्रेसी १९४८ पृ० ४३-४४ ।

तया कार्यों में निहित जुटियों की धालोचना करते हैं और मदशातायों के समक्ष वैकटिएन गीतियों तथा कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सकते हैं। "लोकतम की मान्यता है कि एक बगटित तथा निश्चित प्रतिक्षत सरकार के विरद्ध हो। बिना इस प्रकार के प्रतिक्षत के, निरकुत्रता की घोर ध्रम्नतर होते हुए बीकतम का बिनाग होगा।"

सस्वीय लोकतन विना सस्वीय प्रतिप्त के सफल नहीं हो सकता है। विदिश्य संसदीय-व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण किनीयत यह है कि 'सस्वीय प्रतिपत्त' को प्रोम स्विप्त प्राप्त या 'सामानी ना प्रतिपत्त' के नाम के प्रदत्त है। प्रीप्त को क्षेत्र स्वाप्त के प्राप्त के प्रदत्त है। प्रीप्त को क्षेत्र है। प्राप्त के स्वाप्त के प्रता है। प्रत्य है। प्राप्त के स्वाप्त के प्रता है। विदिश्य संस्व देना प्रश्नीमंत्रीय की महत्व की हो ने दिवान संस्व के सिप्त को से महत्व की से निम्मतिवित करने में स्पप्त किया है—''इगलेय्ड में प्राप्त है। प्रतिप्त को महत्व के प्रता है। स्वाप्ति के प्रतिप्त की स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्व

सदि किसी राज्य में दो से अधिक राजनीतिक दल हैं तो जिन दलों के हाथ में सता नहीं है, उनको प्रतिपक्षी (जिरोधी) दल की भूमिका निमाना पढ़ती है रे प्रतिपक्षी दल का कार्य यह नहीं है कि सर्वेदा सरकार का निरोय करें। प्रतेक समय यह देखा गया है कि प्रतिपक्षी दल सरकार को यपना सहयोग देते है, जियोगकर राष्ट्रीय सुरक्षा तथा बिदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण सामलो में।

यहाँ यह सम्रत तेना उपयुक्त होगा कि समरीय प्रमाली मे प्रतिपत्त की परि-मापा नया होती ? ससरीय प्रतिपत्त की एक उपयुक्त परिमाणा थी एए. बी. राजू (स्ततंत्र दल के केन्द्रीय कार्यालय के कार्यकारिणी-सचित्र) द्वारा थी गई है, जो निमानातार है।

१. के. सो. जेना-पोलिटिकल ग्रप्पोजीशन इन इण्डिया, इण्डियन रिध्यू १६५६ । ४० ४५६ ।

२. एस० लो० 'द गर्बनेन्स ग्राफ इंग्लैंग्ड-१९३१ पृ० १२५ ।

"जिस सन्दर्भ में यहां प्रतिपक्ष शब्द वा उपयोग किया गया है, उसवा प्रयं एवं सगठित समुदाय जो (वं) जनतानिक मुख्यो तथा परम्पराधों म प्रास्था रखते हुए सरकारी नीतियों की रचनात्वक आलोचना चरता है, (व) इस स्थित में हैं वि सत्ताहड दल से मिन बक्टियन नीतियों को प्रस्तुत कर सके, (ग) राज्य तथा नन्दीय स्तरों पर आवश्यक प्रमाल तथा सगठन रखता है, जिससे वि राष्ट्र वे राजनीतिक जीवन म उसकी उपस्थित महसूस की जा सके, एव (ग) जिसवा नतृत्व दश एवं स्थस्थ है, जिसस न केवल उसकी उत्तम संस्थार प्रस्तुत हो बरन् जब सत्ता की बागडोर सम्हालने के लिए मतदाता नेतृत्व मागते हैं, तो नेतृत्व वरने की धमता नी हो।"

धी के बी राजू बहुते है—"इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि कोई भी विरोधी दल देश म (भारत) वास्तविक प्रतिपक्ष दल (विरोधी) होने का दावा नहीं कर सकता है।' व

यह स्पष्ट किया जा चुना है कि भारत में ससदीय पद्धति की स्थापना की गई है। किन्तु मारतीय ससदीय पद्धति की यह एक गमीर तृटि है कि सविधान के लागू होने के इनने वर्षी बाद मी एक सगिठत एक समक्त ससदीय प्रतिपत्ती देत (विरोधी) ना विकास नहीं हुआ है। यह सप्तर है कि सबद में, विरोधी देत है, पर-तु इनमें से एक भी ससदीय प्रतिपत्ती दल नहीं माना जा सकता है, क्योनि किसी प्रतिपत्ती करने की क्षासता नहीं है। स्पारत म एक समिठत एवं प्रभावशास्त्री प्रतिपत्ती दल ने होने की कितनी ध्राय- प्रकास हित प्रतिपत्ती क्षाय- प्रकास मिठत एवं प्रतिपत्ती आप स्वपत्ता प्रवास किसी की कितनी ध्राय- प्रकास किसी हित हो सकता है।

१-- प्रतिपक्षीदल वे कार्य।

२-मारतीय ससद मे प्रतिपक्षी दल का स्वरूप ।

१—प्रतिपक्षी दल वे नार्य-सर्वप्रथम, राजनीतिक दलो का प्राथमिक कार्य लोजमत को समिद्धत वरना है। भ्राम-चुनाव के दौरान राजनीतिक दलो वे कार्य होते हैं—प्रवार हारा मतदाताम्रो मे अपनी नीतियो एव नार्यक्रम के प्रति विश्वसा सेदा करा। राजनीतिक दलो के अपनी नीतियो एव नार्यक्रम के प्रति विश्वसा सेदा करा। राजनीतिक दलो के अपने कार्य कार्य मी हैं, जो उन्हें प्राम-चनाव के समान्त होने पर मी करने पढ़ते हैं। इनको ये कार्य निरन्तर वरने होने हैं। साना- रूड दन, जिसने म्राम-चुनाव के दौरान मतदाताम्रो का विश्वसा प्राप्त निया है, प्रवार तथा ग्रन्त क्या है, प्रवार तथा ग्रन्त निया है,

१. कें वी० राजू-'प्रॉवलेम्स झाफ डेवलेपिंग एन झपोजिशन इन इस्डिया' स्टडीच इन इण्डियन डेमोक्रेसी, १९६४, पूठ ६१७।

२. बही पृ० ६१७ ।

प्रवल न रता है नयोकि वह अपने आम-धुनाय मे पुन. विजय आपन करना चाहेगा। इसी प्रवार विरोधी वस और प्रविक सम्बन्ध, प्रचार तथा कार्यों द्वारा मनदावाधी का विद्वास अपने करने का प्रवत्न करेंगे। "अद्वार प्रवृद्ध हरू हा साकता है कि सता कि प्रवृद्ध के प्रवृद्ध करते हैं, उसनी स्वत्न व्यवता की प्रवृद्ध करते हैं। "अ

बरि समाप्ती ग्राम चुनाल में तत्रताताकों को प्रतिपत्ती दल की नीतियों एवं विकारवारा पर विस्वास हो जाता है, तो वे उसनी सता सौर सन्ते हैं। नि सहेंह, एक समीठत तथा प्रमाववाली प्रतिपत्ती रत्त के विद्यारान होने हे, मतदा-ताकों के समझ एन वैकलिक सरकार विद्यान रहती है। प्रतायन गताता स्तावाह्य तथा प्रतिपत्ती दलों की नीतियों ब्रोर विचारवाराओं मी तुलनात्मक समीधा करके निर्णय से सब्दे हैं कि सत्ता नित्त कर की सीधा आये। वस्तुत: इस तुलना-त्मक झाधार पर मत्त्रताताओं के नित्य यह समझ है नि प्रत्येक विषय को सही एतिकेश्व में देश सहं

द्वितीय-प्रतिपक्षी दल का एक घन्य महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह वास्तव मे जनता तथा सत्याद ने बीच की एक महत्वपूर्ण कडी है। चूंकि राजनीतित दक्षी का उद्देश्य सत्ता की बायडोर पर कब्जा करना होना है, सन. इस राजनीतित सवर्ष के परिचाम स्क्ष्य राजनीति के क्षेत्र म सी विनिष्ठ कर्मों का तिर्माण होता है।

दन रहो जो हम सहास्त्र और सत्तािस्होंन को मे वर्गोहत कर सनते हैं। यह समय है कि सत्तास्त्र वर्ग सता के उमाद मे अच्ट होनर जतता की प्रावम्य करायों से समर होनर जतता की प्रावम्य करायों से समर होड़े दो अनुस्तायों सताहर वर जनता की प्रावम्य होता है। देशों के जावत कराया है। प्रतिपत्ती दल का प्रत्यक्ति महत्त्व होता है। वह जनता को जावत कराया है। विलोगत. यह मी मत्त्व है कि प्रमान-पूनां के हार जाने से अदिकारी दन ताताहर वर ना ने जारारात्त्व प्रावमित्र मा रहे के प्रायम्य का स्वावम्य कराया है। विलोगत. यह मी मत्त्व है कि प्रमान-पूनां के सहत्व है से स्वावम्य कराया है। यहां प्रति करी मात्रा जा सनता है। वस्तुविद्य कराया है वस्तुविद्य कराया है वस्तुविद्य कराया स्वावम्य कराया है के सहत्व है कि सहत्व तथा प्रतिविद्यों तथा एक होने पर भावव्यकता मुक्ता प्रतिविद्य तथा सत्त्वकत का कार्य करते हैं। यह नहने में कोई प्रतिविद्यों कि नहीं होगी कि सताहर तथा प्रतिविद्यों हम तस्त्व क्षा की प्रतिविद्या करते हैं। यह नहने में कोई प्रतिविद्यों कि नहीं होगी कि सताहर तथा प्रतिविद्यों वस्त्र की जाति हमें स्वव्यक्त स्वत्य के स्वत्य के स्तर करते हैं। यह नहने में कोई प्रतिविद्यों कि सहस्त की स्वत्य की स्वत्

१ एस न्यूयेन-'मॉडने पोलिटिक्ल पोर्टीख' १६५६ पू० ३६६ ।

स्थिति बिगड जायेगी। ब्रिटिश संसदारमन पद्मित में दृष्टिकोण से सर आइवर जैतिन ना क्यन है—"सरकार प्रतिवशी दल को, एक ऐसी मीटर पर प्रेन के सद्ग मानती है, जो पहाट पर चढ़ रही है, जबिक प्रतिपक्षी दल का विचार है कि मीटर पहाट से उत्तर रही है।"

"नि सदेह ससदात्मन पढ़ित म प्रतिपक्षी दल ना नार्यं जटिल है। प्रतिपक्षी दल, व्यवस्थापिना ना एन महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसरे नार्यं ध्रप्रत्यक्ष रूप से सरदार ने वार्यों साप्त्यक्ष रूप से सरदार ने वार्यों प्रतिपक्षी दल ता प्रयान ने ने लिए बाएम नर ना है।" यह सो सप्तट है नि यदि प्रतिपक्षी दल ना प्रस्तित्व न हो, सत्तारू दल जनता नी मीनिक स्वतप्रताधों ने वुचलते हुए निस्तुण वन सनता है। वस्तुत, प्रतिपक्षी दल सरकार मायणों हारा जनता ने सहायक है। वस्तुत , प्रतिपक्षी दल सरकार प्राप्त करते हैं नि जनने दल भी नीतियों तथा नार्येग्रम हो सर्वेश्वर है। यह स्वामानिक है नि सत्तारू दल भी भीनीत्वी तथा नार्येग्रम हो सर्वेश्वर है। यह स्वामानिक है नि सत्तारू के वृधिक प्रतिपक्षी है। हम स्वामानिक है नि सत्तारू के स्वीवित के दृष्टिकोण से नहां है स्वामादित सरकार ने स्थान पर पूष किक्ट है धीर जनता ने समत्तार्थ को सहात्र के स्वामा दि सत्तार्थ है। सर्वार के स्वाम हो महत्वपूर्ण हैं। यदि प्रतिपक्षी दल नहीं है तो जनतत्र भी मही हो सनता है। इसर्वेष्ट की साम्रामी ने प्रतिपक्षी दल नहीं है तो जनतत्र भी मही हो सनता है। इसरेष्ट के सहत्व के स्थान पर है। पर स्वाम पर है। पर स्वाम पर स्वाम पर है। पर स्वाम पर साम पर स्वाम पर स्वाम पर साम के सहत्व के सूरिय स्वाम पर है। पर साम्यत्व स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम के सहत्व के सूर्य हमा स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम के स्वाम स्वाम स्वाम के स्वाम स्वाम स्वाम के स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम के स्वाम स्वाम के स्वाम स्वाम के स्वाम स्वाम के सुर स्वाम स्वाम के स्वाम के स्वाम स्वाम

ष्रापुनिन गुन में ससदारमय पढ़ित म ससद नी शक्तियों में परिवर्तन हुमा है। सास में सताहद दस ना बहुमत होता है, जिसमें से मनी मण्डल (सरवार) ना निर्माण होता है। चुंकि साबायणताय बहुमत सरकार ने पहां में हो होता है प्रति सरवार पर समद ना नियम्या प्रत्यन्त नम हो गया है आयुनिन समय में ससद प्रियचत वाद विवाद व आलोचना ने मच के रूप में ही रह गई है। सत्ताहद दस के सदस्य सरवार नी आलोचना यहुत कम करते हैं। यह नायं प्रव प्रतिवशी दस हो हो होते हैं। यह नायं प्रव प्रतिवशी स्वाह है हम स्वाह की स्वाह है। यह नायं प्रव प्रतिवशी सालोचना। ' प्रतिवशी दस हो जो संपेक्षा नी जाती है, यह है प्रमावशाली आलोचन। ' प्र

१ ग्राइ जैनिग्ज-'पार्लियामेन्ट' १६५७, पृ० १६७ ।

२. धाई जीनग्ज-'केबोनेट गर्बमेण्ट' १६४६ पृ० १४ ।

३. वही पृ० ४०६।

४. बाई जीनाज-'पार्चियामेन्ट' १६५७ पूर दर ।

समदात्मक सरकार को सम्बन्ध के लिए यह प्रावश्यक है कि सत्तारण दल तथा प्रतिपक्षी दल के मध्य परस्पर विश्वास हा तथा सविधान के सिद्धान्तों से वे पूर्णन्या परित्तित हो, दिवसे व्यावहारिक शीवन से, राष्ट्रहिन के लिए इनका पातन निया जा सके। प्रतिपक्षी दल वा दलों को पत्रने दिसिन्न, दाधित्वों को समभने हए, दिवास्तक साथनों को नहीं प्रयाना चाहिये।

सक्षेप म, प्रतिपक्षी दल को एक उत्तरदायी प्रतिपक्षी दल होना चाहिये। क्योंकि अनुत्तरदायी प्रतिपक्षी दस से उतनी ही हानि हो सकती है, जितनी एक

ग्रनूतरदायी सरकार से।

ध्यावहारित राजनीति म प्रतिवसी दल ने सत्यविन महत्व ने नारण, इस्तैण्ड म मियो ने देनन फ्रांतियम १६३० ने मानवंत प्रावसात किया गया है म प्रतिवशीय दल ने नेता को २,००० पौण्ड मित वर्ष देनन मित्र । नामस समा ने स्वीकर झार नियंशित हिया जाता है दिस ख्यति को प्रतिवशी दल वा नेता स्वीकृत कर यह देतन दिया जाते । यह देतन सनित नित्रि में ने दिया जाता है, विद्य पर मतदान नही हो सदता है। यदापि इन्तैण्ड में प्रतिवशी दल के वाणी मां भीपवारिक रूप से नियारिया ने से सानृत, तही सदत ने नियमो झार दिया नया है, उसकी स्थित स्थापन महत्वपूर्व है, "साधकी वा प्रतिवशीय दल स्वस्था है, देवस्थित सरवार है। प्रतिवशी दल का नेता साम्राजी वा वेनस्विप प्रयान मित्री हो"।

मनी है।"" सस्तारामक पढ़ित में प्रतिपत्ती दल के कार्य तथा पूर्मिका वे अध्ययन से यह स्पारट हो जाता है कि सस्त्रीय अज्ञातन का बोड़े मून्य नहीं होगा यदि वहीं उपयुक्त, परिपक्त, तथा प्रमावशासी प्रतिपक्षी दल नहीं है। "वस्तुत गैर-साम्यवादी राष्ट्री में प्रतिपक्षी दलों का स्थान तथा श्रांति भाग एक उच्च स्तर पर है।"र

भारतीय संसद में प्रतिपक्षीय दल

मह विदित करने के लिए कि मारतीय सलद में विभिन्न विशेषी दली द्वारा महत्वीय सददारमें पदिव के सावस्थक तरकों के रूप म मूमिका विभाई जाती है या नहीं यहाँ पर घावस्थक है कि इन विभिन्न विरोजी दली की स्वित का अध्ययन

हिया जाय । महें वर्ष पूर्व पर नेहरू ने नावेल तथा प्रजा सोवालस्ट दलों के पारस्परिक सहयोग के विषय पर श्री जबत्रकांग नारायण स बार्ता करने के पश्चात, मारत की राजनीतिक स्थिति पर एक बस्तव्य दिया, जो श्रान की राजनीतिक स्थिति क

२ क० सी० जेना 'पूर्वोक्त पुस्तक' पुरु ४५७

"नाभेस को छोड़कर, जो राजनीतिक दल मारत म विद्यमान है, उनको चार वर्गों में विमाजिन किया जा सनता है। तुछ दल है जिनको विचारनारा छाधिन है। अपने सबस्थित सगटनों के साथ ताम्यवादी दल हैं। विभिन्न साम्यदायिक दल पुषव नाम वे हैं किन्तु जो सनीणं माम्यदायिक जिचारनारा का अनुगरण कर रहे हैं, और कई स्थानीय दल और सगटन हैं जिनका छाधार केवल प्रान्तीय बरिक स्थानीय है।" ।

मारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का ग्रध्यमन, यदि प० नेहर द्वारा निय गये राजनीतिक दलों के उपर्युक्त वर्गीकरण के आपार पर किया जाय तो राज-नीतिक दलों को मुख्यत निस्तिलिखित यगी में रखा जा सकता है।

- (क) पहले वर्गम जन महत्वपूर्ण राजनीतिर दलों को रखा जा सकता है जिनकों न केवल क्रार्थिक विचारवा राएँ है परन्तु जिन्होंने जनतत्र तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य का पोषण करना अवना उद्देश्य मान रखा है। उदाहरण स्वरूप कांग्रेस, सोझिसिट दल एव स्वनत्र दल।
- (स) दूसरे वर्ग भ वे दल रसे जा सबसे है जिनकी उत्पत्ति घर्म सवा सम्प्रदाय के माधार पर हुई है। ये हैं मारतीय जनसब तथा मुस्लिम लीग।
- (स) तीसरे वर्ग मे उन राजनीतिन दलो को रखा जा सकता है, जो हिमा मे विकास करते है, श्रीर सविजान में जिनकी श्रान्या सदेहमद है, जैसे साम्यतादी दल (मावर्मवादी) ।
 - १६५० में सविवान लागू होने के पश्चान् कई राजनीतित्र दलो की उत्पत्ति हुई । वर्नमान समय में निम्नलिखित प्रमुख राजनीतित्र दल हैं —
- (१) काब्रेस-मारतीय राष्ट्रीय नावेस वा उदय सन् १००५ में हुया। उस समय दमवा उद्देश्य समस्त मारतासियों के निष् एर सामान्य मच की स्थापना करना था जिससे राष्ट्रीय आदोतन की प्रतित हो गरे। बीसदी गदी के दूसर दम्ब में महास्ता मारी के नेतृद में यह एर मध्यत जिननाली दल यन गया। १००५-१४७ तन राष्ट्रीय आदोतन की वामद्रोर, मुख्यत नावेस के हाथों में ही रही और इस दौरान नावेस को प्रत्यं प्रति के स्थापन करने के स्वत्य प्राप्त हुए। प्रत्युत् यह स्वामाधिक था कि जा वायेस ने हत्तन मारत की सरवार की बामद्रोर समर्थन प्राप्त या, क्योंकि जनता की दृष्टि नावेस प्राप्त स्वापन प्रति की सरवार की साम्य स्वापन स्वा

१ 'द हिन्दुस्तान टाइस्स' सब १८,१६४३ मे प्रशासित प० नेहर का भावण ।

१६६२) मे कावेस को विज्ञाल बहुमत प्राप्त हुमा जिसके फलस्वरूप सतद एव राज्य विधान समाम्रो मे (केरल को छोडकर) कावेस का पूर्ण माधियस्य रहा। परन्तु १६६७ के द्याम चुनावों में नावेस को गहरा धरका पहुंचा, क्योंकि म केवल परन्तु ११६% क साम चुनावा म नाइंस का महुरा प्रस्ता पहुना, बयाक न कंवन कर राज्य विचान समाधी मे इसका बहुन्य समाप्त हो गया किन्तु से स ससद में भी हसका बहुन्य परकर ने कर १४% ही रहु गया। तत्त्वत्वात मातिरिक इन्द्र तया मनमेदो के कारण १६६६ न कार्य से बड़ी फूट हुई, दिसके फतास्वरूप सतद मे कार्येल के एक हिस्से ने बाल रामस्वर्णातिह के नेपूर्व में विचारी सदस्यों कारणा महत्त्व कार्यों के इस्तर्ण मात्र में कारणा परन्तु मुझ्ल हिस्सा, श्रीमत्त्री गांधी के मेनूरव में, नाई कार्येस के राम से सरकार की बागधीर दिसाबर १६७० तक, करियम निर्देशीय सदस्यों तथा किरोपी देशों ने समर्थन के

हैं। इनमे गायीजी के सर्वोदय के ब्रादर्श के साथ समाजवाद के विचार कि, उत्पा दक के साघनों को राज्य के अधिकार में होना चाहिए, निहित हैं। इसके अति-रिवत, निजी आर्थिक प्रयत्नों को भी प्रोत्साहन देने के सिद्धान्त पर बल दिया गया है। नाग्रेस द्वारा इस आधिक विचारधारा को अपनाने के फ्लस्वरूप समाज-वादी तथा साम्यवादी दलों की भूमिका के महत्व में कभी हो जाती है, क्यों कि जनतान तो उपवादी नीतियों के पक्ष में हैं न ऐसे राजनीतिक दलों के जो किसी जतता ने ता जबवादा नातवा क एवं म ह न एक राजनातिक दला क जा सकता विदेशी राजनीतिक दल से प्रेरणा तेते और तक के सताहातुजार कार्य करते हैं। राजनीतिक दिवारपारा के दृष्टिकोण से मी, कारीस की धारम्य तोकतात तथा धर्म-निरक्षेत राज्य में हैं। क्षन्य राजनीतिक दलों के इतिहाल को देखते हुए, जनता को, हन राजनीतिक मुस्तों के सदमें में कारेस रा प्राचिक दिवसास हैं। सक्षय में, इन तत्वों के कारण कारीस भी स्थिति विशेषकर सबस से, धरस्त कविनकाती है। इस बात की दुष्टि कारीस डारा प्रत्वेक धाम चुनास में जितने

स्यान लोक समा म प्रान्त हुए हैं, उनसे की जा सकती है।

पहला प्राप्त चुनाव १६४२ सोकतमा मे स्थान प्राप्त २६४ दूसरा प्राप्त चुनाथ १६४७ सोक सचा मे स्थान प्राप्त २६९ तीसरा प्राप्त चुनाव १६६२ सोकसमा मे स्थान प्राप्त २६१ चौथा प्राप्त चुनाव १६६७ सोकसमा मे प्राप्त स्थान २८१ पौचवा प्राप्त चुनाव १६७१ सोकसमा मे प्राप्त स्थान २४०

(२) प्रजा सोमालिस्ट वस—वितम्बर १९४२ मे समाजवादी एव किसान मजदूर वल के मिनते से प्रजा सोमालिस्ट वस की उपति हुई। बस्तुत तोमालिस्ट वस की उपति हुई। बस्तुत तोमालिस्ट वस की उपति १९३४ मे काग्नेस मे से ही हुई, क्योंकि व्यी जयप्रवास नारायण, अच्छुत पटवर्षम एव श्री प्रकोश मे से ही हुई, क्योंकि व्यी जयप्रवास नारायण, अच्छुत पटवर्षम एव श्री प्रकोश में स्वतंत्र को नेताओं को काग्नेस पर पूजीपतियों या प्राधिपत्य पसद नहीं था। स्वतंत्रता के पूर्व इस दल को काग्नेस-सोमालिस्ट वस नहां जाता था। १९४२ में मारत छोडों प्राथीलन के समय इस दल के नेताओं को येठक कानपुर में हुई जिसमें उन्होंने काग्नेस से पुरक्त होकर एक स्वतंत्र एव मिन्न इस के मिन्न वर्षों में पूर्व होकर एक स्वतंत्र एव मिन्न इस के निर्माण करने का निर्माण स्वतंत्र में स्वतंत्र में से प्रवास काग्नेस का स्वतंत्र में से प्रवास काग्नेस का प्रकास काग्नेस का स्वतंत्र में से प्रवास काग्नेस का पूर्व स्वतंत्र प्रवास मार्थ में विष्यों से प्रवास काग्नेस काग्नेस स्वतंत्र प्रवास काग्नेस काग्नेस स्वतंत्र प्रवास काग्नेस काग्नेस स्वतंत्र सामन करना स्वतंत्र सामन काम्ना स्वतंत्र सामन करना स्वतंत्र सामन काम्माल स्वतंत्र सामन करना स्वतंत्र सामन काम्नाली प्रतिप्रका स्वतंत्र में से स्वतंत्र सामन स्वतंत्र सामन स्वतंत्र सामन वा । इस के प्रतिप्रतंत्र सोमालिस्ट दल का यह विषयास मी या । का कार्य सामन सामन या। का कार्य सामन या। का कार्य सामन या। वा सामन वा सामन या। वा सामन वा सामन या। वा सामन या। वा सामन या। वा सामन वा स

प्रजा सोशलिस्ट टल का विश्वास लोकताविक समाजवाद मे रहा है धीर उनके मुन्तार विकेट्यत लोकत्व, जनता के सार्यजनिक मामलो मे हिस्सा लेने के लिए प्रावश्यक है। इसना उद्देश एक नियोजित प्रावश्यक है। इसना उद्देश एक नियोजित प्रावश्यक है। इसना उद्देश एक नियोजित प्रावश्यक रणा है। सिर्मा प्राविक स्वार्यक्ष रणा हो। अतः प्रजा सोश्रालस्ट दल तथा नाजेस के सिद्धान्तो मे मुख्य प्रनतर यह है कि कायेल हारा स्वीवत प्रार्थिक व्यवस्था एक मिश्रित धार्यिक व्यवस्था है, जिसमे निजी एव सार्यजनिक व्यवस्था हो। सिर्मा प्रया सार्या था; जबिक प्रजा सोशलिस्ट दल का विश्वास केवल ऐसी व्यवस्था मे रहा है जिसका स्ववस्था सार्यजनिक हो। होगा।

१९४२-मे किसान मजदूर दल तया समाजवादी दल का एकीकरण हुमा, जो प्रिक लामप्रद सिद्ध नहीं हुमा । इसका मुख्य कारण यह या कि किसान मजदूर दन का उद्देश्य 'सर्वोदय' प्राप्त करना था, समाजवादी दल की प्रेरणा का

भारतीय शासन ग्रीर राजनीति 258

स्रोत मानुर्सवाद था। फलस्वरूप, शीझ ही दल मे दरारे पडने सगी घाँर दल दो भागों में विभाजित हो गया। (क) दक्षिणपथी-जो नाग्रेस के साथ सहयोग ने पक्ष में थे, एवं (त) वामपथी-

जो नाग्रेस से नोई सबध नही रक्षना चाहते थे। इसलिए जब प० नेहरू ने श्री जयप्रकाशनारायण को राष्ट्र निर्माणात्मक कार्यों में प्रजा सोशलिस्ट दल के सह-योग के लिए ग्रामंत्रित किया तो प्रजा सोशजिस्ट दल के वामपथी नेतायों में डा० लोहिया तथा श्री मध्लिमये को यह बात पसन्द नहीं थाई। सत्पश्चात, प्रजा सोशलिस्ट दल के झान्तरिक भतभेद स्पष्ट रूप से सामने उभर कर झाये । जद नाग्रेस ने अपने खवाडी (मदास) छिछवेशन में भारत म समाजवाद स्थापित करने के लक्ष्य को स्वीकृत किया तो प्रजा समाजवादी दल के अध्यक्ष ने इस पर अपना हुएँ व्यक्त निया और कहा कि यह लोक्तानिक समाजवाद की प्रगति का एक सब्त था । डा॰ लोहिया ने सहयोगियों ने इसे एक वडा धोला बताया । इसी समय श्री मयलिमये ने, जो डा॰ लोहिया ने निनट के सहयोगी थे, श्री धशोक मेहता की

कडी भ्रालोचना की, फलस्वरूप उनको दल से निलम्बित कर दिया गया । परन्त दल की उत्तरप्रदेश की कार्यपालिका ने श्री लिमये का समयंत किया और उनको गाजीपुर में दल के अधिवेशन को संबोधित करने हेतु आमनित किया। इस कार्य को दलीय द्यनुशासन के विरूद्ध मानते हुए समस्त प्रदेश कार्यपालिका को निलम्बित कर दिया गया। बन्त मे जुलाई १६५५ मे डा० लोहिया को दल से निप्कासित कर दिया गया। दिसम्बर १६५५ मे डा॰ लोहिया ने समाजवादी दल का निर्माण किया जो कि प्रजा समाजवादी दल के विरुद्ध था, क्योंकि प्रजा समाजवादी दल का कायेस से

सहयोग नरने मे विश्वास था। इस दल को सयुक्त सोगलिस्ट दल (एस०एस०पी) के नाम से पुकारा जाता है। मई १९६३ में डा॰ लोहिया लोकसमा के लिए निर्वाचित हए । प्रजासमाजवादी दल को विभिन्न ग्राम-बुनाव मे न तो ससद मे न ही राज्य विधान समान्नो मे अधिक स्थान प्राप्त हुए। १९४२ के ग्राम-चुनाव में लोकसभा

मे इसे २१ स्थान मिले। १६५७ के ब्राम-बुनाव में इसे लोक्समा में केवल १६ स्थान ही प्राप्त हुए। १६६२ के ग्राम-चुनाय में लोकसभा में केवल १२ स्यान प्राप्त हुए भीर मार्च १६६७ के भाम-चुनाव मे १३ स्थान प्राप्त हुए। मार्च १६७१ के धाम-चुनाव मे प्रजा सोशलिस्ट दल को लोकसभा मे केवल २ स्थान ही मिले।

डा० लोहिया वे समाजवादी दल को १६६२ के झाम-चुनाव मे ६ स्थान प्राप्त हुए भौर १९६७ के भाग-चुनाव में २३ स्वात मिले। १६७१ के ग्राम-चुनाव मे

इसे फेवल ३ स्थान लोकसभा मे प्राप्त हए। 3-भारतीय जनसध-मारतीय जनसघ की स्थापना १६५१ में डा० श्यामा

प्रसाद मुकर्जी द्वारा की गई। जनस्य वो दक्षिण पथी दल माना जा सकता है।

समाजवादी एव साम्यवादी देता को वामपथी माना जाता है। जनसंघ का प्रभाव मुख्यत मारत म उत्तरी क्षेत्र म है, विशयरर पजाव, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य-. प्रदेश एव राजस्थान । १९५६ म जनसघ, रामराज्य-परिवद तथा हिन्दू महासभा व एवीवरण बरने के प्रयत्न किय गय, परन्तु यह समात नहीं हुए। इन तीना दला की प्राय ग्रानोचना की जाती है कि य साम्प्रदायिक हैं।

'राष्ट्रीय स्वय सेवक सथ एक सास्त्रतिक संगठन होने का दावा करता है, परन्तु इनकी राजनीतिक गतिविधियाँ जनसप द्वारा, संचालित की जाती है। डा॰ मुरजीं एव महान राष्ट्रीय नता थे जिनका राष्ट्रीय सेवा का रिकाई है। जून १९४३ म उनकी दुरुपूर्ण मृत्यु वे परचात जनसम्प राष्ट्रीय स्त्रय सत्तव सम्प का एक मच बा गया।" यद्यपि इसकी स्वापना के बाद, जनसम के स्वरूप म परिवर्तन हम्रा है, प्रपनी सफ्तता ने लिए जनसघ नो प्रावश्यन है कि ग्रपनी विचारवाराग्रों को जनतात्रिक एवं धर्म निरमक्ष सिद्धान्तो पर श्रापारित करे. जिससे ग्रत्पसत्यको का विश्वास इसे प्राप्त हो सक । १६५२ के ग्राम चनाव म जनसम को लोकसमा मे ३ स्थान प्राप्त हुए । १६५७ के भ्राम-चुनाव म इसे ४ स्थान लोगसमा में मिले और १६६२ ने धाम-चुनाव में १४ स्थान-लोकसमा म इसे मिले । १६६७ के ग्राम चुनाव म जनसप को लोकसभा मे ३३ स्यान ग्रीर १६७१ मार्च वे ग्राम-चुनाव मे २२ स्थान लोवसमा म मिले ।

१९६२ ने ग्राम चुनाव ने पश्चात् जनसम नी लोनप्रियता म मोडी युद्धि हुई है बिन्तु एक वास्तविक प्रतियक्षी दल के रूप म विकसित होने के लिये, जनसघ वा लोक्तात्रिक एव धर्म निरपेक्ष स्वरूप को श्रपनाना होगा ।

४-स्यतत्र दल-स्वतत्र दल की उत्पत्ति १६५६ मे एक लोकतात्रिक भ्रनुदार दन के रूप म हुई है। स्वतंत्र दल के उद्देश्य तथा नीतियों का उत्तेरा श्रीमती ऐलन रॉय ने निम्नलिखित रप से निया है, "हमारी राय है नि सामाजिन न्याय तथा लोककल्याण को तथाकथित समाजवाद के साधनों के अलाबा अन्य निश्चिन् एव उपयुक्त साधनी द्वारा प्राप्त विया जा सकता है। सामाजिक न्याय ग्रीर लोग यल्याण मी हिंसा या राज्य शक्ति द्वारा नहीं लाया जा सनता है-- किन्तु इनकी स्थापना गांधीजी द्वारा प्रतिपादित न्यास-पद्धति के द्वारा की जा सनती है। सरवार की भैक्षणिक गतिविधियों प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्ष इस प्रवार की होनी चाहिये जिससे इस यात पर बल दिया जाये कि जिन लोगों के पास धन है, वे इसको समाज की घरोहर के रूप म रखे, ग्रीर जीवन के ऐसे सिद्धान्त पर भी जी इस नैतिक कर्तव्य पर आधारित है, इसके बजाय कि ऐसे सामाजिक

१ एम० जी० गुप्ता, 'पूर्वोक्त पुस्तक' पृ० ४८० 8 %

वृद्धि होती गई है। १६७१ के आम चुनाव में मारतीय साम्यवादी दल (सी० पी० आई०) को २३, भारतीय साम्यवादी दल (भावसँवादी) (सी० पी० एम) को २५ स्वान लोकसमा में मिले हैं।

उपर्युक्त निवरण से भारतीय ससद वे निचले सदम (लोकसमा) म मुख्य राजनीतिक दतो की स्थिति स्पट होती है और यह विदित होता है कि इनमें से किसी दत को 'सास्त्रविक सत्याय प्रतिपक्षी दम' की सजा नहीं दी जा मकती है। पराचु इन मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिदिक्त लोकसमा में बुद्ध प्रत्य स्थानीय पृष छोटे दलों का प्रतिनिधित्य दहां है, जो निम्मिकिखित है —

१—गणतन परिषद-१६६२ के ब्राम-चुनाव म लोकसमा में इसे उडीसा से ४ स्थान प्राप्त हए।

२—िकसान एव मजदूर दल-१८६२ मे इसको लोकसमा मे कोई स्थान प्राप्त नहीं हुन्ना, परन्तु १८६७ मे २ स्थान प्राप्त हुए । यह दल महाराष्ट्र का है ।

२—मुस्लिम लीग-१८६२ मे इसे २ और १८६७ मे ३ स्थान प्राप्त हए। इसका प्रमाय प्रमुख रूप से केरल मे है।

४—-धकाली दल-१६६२ में इसको तोकसमा में ३ स्थान प्राप्त हुए, १६६७ में पुन. इसको ३ स्थान पजाब से प्राप्त हुए।

५—फारवर्ड ब्लाक-१६६२ मे इसको २ स्थान लोकसमा मे प्राप्त हुए, ग्रीर १६६७ मे मी २ स्थान प्राप्त हुए। इस दल का प्रमाव मद्रास श्रीर पश्चिम बगाल म है।

६—द्रविड मुनेत्र कडगम-१९६२ के श्राम-चुनाव मे इसे लोकसमा मे ७ स्थान मिले, श्रीर १८६७ के श्राम-चुनाव मे इसे २५ स्थान लोकसमा म मिले। इस दल वा प्रमाव मद्रास (तमिलनाड) से है।

७--भगरखण्ड दल-१८६२ के स्राम-युनाव म इसे लोकसभा मे ३ स्थान मिले । १८६७ के स्राम-युनाव मे इसे कोई स्थान नहीं मिला । यह दल बिहार प्रान्त का है ।

प्र-हिन्दु महासमा-१९६२ में इसे लोकसमा में केवल १ स्थान मिला, परन्तु १९६७ में इसे कोई स्थान नहीं मिला।

६ – राम राज्य परिषद – १६६२ के स्नाम-चुनाव में मध्यप्रदेश तथा राजस्यान में २ स्थान लोक्समा में प्राप्त हुए।

१०-रिपब्लिकन दल-उत्तरप्रदेश से इस दल को लोकसभा मे १६६२ के आम-चुनाव मे ३ स्थान प्राप्त हुए भीर १६६७ मे इसे केवल १ ही स्थान प्राप्त हुआ।

११--१६६२ में सोक्समा के तिये २० निर्देशीय सदस्य निर्वाचित हुए। २२=

१६६७ में ४२ निर्देशीय संदश्य लोक्समा में निवांचित हुए !

१२--- पात इन्डिया हिल सीडर्स वाकेन्स-१८६७ में प्रसम से इस दल ने सोक्समा के लिए ? स्थान प्राप्त किया था।

१२--महागुबरात जनता परिपद-१६६७ में गुबरान से इस दल को लोक समा के लिए ? स्थान मिला था ।

१४---नेतनन बाकेग-१८६७ में जन्तू तथा कारमीर में १ स्थान लोकसना

के लिए मिला।

१४---नामा नेतलल बारमनाईवेशन-१६६७ में साम-बुनाव में इसको नामा-क्षेण्ड से लोक्समा में १ स्थान प्राप्त हुआ था।

उपर्युत्त मध्यपन से यह ज्ञान होना है कि प्रतिपत्ती दलों में से किसी की भी स्थिति इस प्रशार नहीं है कि उत्तरी एक बास्तविक समदीय प्रनिपधी दल की राज्य र प्राप्त कर किया है। स्वर्थ के साम कुराव में नई कांग्रेस को एक विशास बहुमण प्राप्त हुमा है। अन्यूव केवल कुछ समय को छोटकर, सरियान प्रवास पूर्व से साज तक लोकसमा से वासेत का एक प्रशीय साविष्टम रहा है, जब तात्र एः ए जिल्ला स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था क्षित्र संभारतीय सगदीय पद्धित की कार्यद्रभाती पर दसका हानिकारत प्रमाव हो सबता है; बमीकि जब वह विश्वीय दल है और इनमे से विशी को मविष्य क्षा करणा था । में सरकार निर्माण करने की उम्मीद नहीं है तो व्यावहारिक जीवन में ऐसे दत प्राप: प्रतुत्तरदानी होकर सरकार की नकारामक रूप से प्रातायना में सर्ग रहते भाग अञ्चलका हो । है सौर उनना उद्देश केवल यह ही हो जाता है कि किसी प्रकार ससद में कुछ ्र भार स्थान प्राप्त नर सें । क्योंकि, वे मती-मीनि जानने हैं कि सरकार वे निर्माण क्रे का प्रवसर उनको नहीं दिल सकेगा। इससे यह प्रतीन होता है कि प्रतक विपर्शाप रतों ने स्थान पर यदि एक या अधिक से ग्रंपिक वो दल हो, तो इनम साबंबिक विषयों के सम्बन्ध में, समद म एवं समद के बाहुर, टोस उत्तरवाणिक भी भावना जागुन हो सनेगी। इनको नीतियो तथा वार्यक्रमो म पृथकता तथा सप्टता लागी जा सनेगी जिससे मतदानाधी की भी मतदान के कार्य में सहीत-यत होगी।

बस्तु न्यिति यह है कि लोश्यमा में जब नई कांग्रेस वा प्रकार बहुमत है तो कई विद्याप्ति बतो के पुषक ब्रास्टिख के कारण एक 'बास्तविक सप्तदीय प्रतिपक्ष का विश्वस समय नहीं है। इस प्रमाय की दृष्टि से मारतीय ससदीय पड़िन के सम्बन्ध में एक उपना दो जा सकती है कि यह एक ऐसी मीटर गाडी के सद्धा है जो बाटी में उतर कर बा रही है, बीर जिसके 'बेक' में श्रुटियाँ हैं। ससदीय प्रति- पक्षी बत्त एवं 'क्षेत' वे समान है, जिसता वार्यसरार रूपी मोटर गाउँ पर भावत्रक त्रियनच करता है जिसने बिता सररार तिवन्तम से बाहर हो गर रिर-पुत्रता की मोर भयसर हो समग्री है।

चचित्र मारीय सबद भे प्रतिपत्नी दो में नई पृष्टिंगी है भीर 'समनीय प्रतिपत्नी दो में नई पृष्टिंगी है भीर 'समनीय प्रतिपत्नी पर सी बहु नहीं बहु। जा सनजा है कि सरकार पर हो दो को कोई प्रभाव नहीं रहा है। बहु मुद्द सब सरकार पर हा जागी कि प्रतिपत्नी के दूर में है। मुख्त दो प्राप्त के ऐसे साथा है जिनके प्राप्त र प्रतिपत्नी दा सरकार पर हा जागी कि प्रतिपत्नी का सरकार पर हा जागी कि प्रतिपत्नी का सरकार पर हा जागी कि प्रतिपत्नी के स्वार्ण करते हैं।

१—सरनार के विरद्ध भिष्यांश परतार पारित गरी ना उस सामा । परन्तु यह यर सर्वे सामान्य सापन नहीं है, सिसंग्रे भीषशी दल प्रति दिन सरवार का पितन्य वरी है।

२---कतिया ऐसे साधन है, जिससे अतिषक्षी दा सरकार का दैतिर नियन्त्रण करते हैं। ये दैनित साधन, सिमासितित हैं।

- (क) समिति प्रणाली पान ससद की विभिन्न समितियों पर प्रतिपत्री दसो के प्रतिनिधि होते हैं। शिस हर तम सरकार के कार्यों से सक्तित समितियों का सेनाधिकार है, पनिषत्री दस समितियों में सपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार की सनिविधियों पर शिवन्तव रहते हैं।
 - (त) ससदीय प्रश्न,
 - (ग) ससदीय प्रस्ताय,
 - (घ) याद विवाद,

(इ) स्थवन परनाव धादि, वे ऐसे सामा है, जिनने माध्यम से पितपशी दा सररार पर निरन्तर दैनिय नियन्त्रण रस सदने है।

ससर में प्राप्ति का सराार की नीतियों तथा नाओं पर रिपार विगयें नरों ने निए समय नी मान करते हैं। सराव प्रतिप्ती दसों नो सराार भी नीतियों तथा नार्यों को मानोचा। नरों ना जो मंगिरार है वर्गारतीय ससस में याद विवाद नी स्त्रताता ने सर्वामें पर महत्त्रपूर्ण जनतीयित मंगिरार है। यह मिलार सबद में, सरनार नी मानोचा। तन ही सीमित नहीं है जो नेचल ननारास्ता नार्य है। रचनात्मा या सरारास्त्रम रूप से ससदीय प्रतिप्तीय दस का यह नार्य है वि सरनार नी, राष्ट्रीय हिलों से सबित्त मससूत मुद्दे पर भपरा सहस्त्रीय है। उदाहरण सबस्य, राष्ट्रीय हिलों से सबित्त निसी वियोग निसी स्त्रीय स्त्रता है। ब्रिटिण पदाित स्त्रा के सम्बन्ध म विश्वसीय दल के तेना ने १८३२ में जहा-"ध्वाधि यह सरवारी विश्वेषक है परन्तु इनना निर्माण सरन ने सहस्यों ने सहयोग से हुआ है वहाँ पर पुद्ध सदस्य निद्धानतों पर विश्वेषन ना विरोध करते हैं फिर मो वे उसनी कियानित नरने भ भी क्षाचित्र पहुँचे हैं।"

म्रत्य मामला में मी, जो राष्ट्रीय हितों से संबंधित है, प्राय अंतिपत्ती देती का सहयोग सरकार वो मिलना चाहिये १६६४ तथा १६७१ में पाविस्तानी मात्र-मणों के दौरान प्रतिपत्ती देखा ने सरकार को मपना टोम सहयोग दिना ।

इसने वावनूद भी हि भारतीय संसद में प्रतिशंध द्वारा सरकार पर कुछ हु तक प्रकृत सामाती मानत में महस्मार है हि जब तक प्रतिक्री सकत में स्मातिन तथा असामाती सोनत में मानति मानत में सामित तथा आसामाती सोनतभीय प्रतिश्व वा विकास नहीं होती है, तक तक वर्तमान स्मित सामात्राम सी मानतभी मानतभी सामात्र में एक सामित पर प्रकृत सामात्रीय सी सामात्रीय सामात्रीय सी सामात्रीय सामात्रीय

मार्गनिय विधान से विचारों को समित्यक्ति की स्वनिता ना स्विचार गार्वारों को दिया गया है, तिमने पास्त्रक से सरमार की सामोजना ना र सकते हैं। सत्यत्व स्विचान के सन्तर्गन सत्यत्व प्रतेष्यत्व हैं सित्य पर्योग्न सामार है। यन नेहल ने नहा है कि—"योग्न विचान प्रत्यात्व ऐसी सरकार से हैं, त्रिकंस सामोजन निजर हैं, सीर तिसको विधीप का सामना करना है। यिना सामोजना के जनता तथा सरमार सामरजाह हो जाती है। समस्त सन्तरीय प्रणाली, इस प्रमार को सालोजना पर सामारित हैं—मिं सबस से (सरकार मी) सालोजना जाहता हैं।"

^{ै.} ए० बी० कोथ—'द ब्रिटिश केबीनेट सिस्टम', १९५२ पू० २४२-२४३ । २. एम० भ्रार० मसानी—'पार्टी पालिटिश्स इन इंग्डिया,' (इन बाईटल

४. ५५० आर० मताना—पाटा पातारुक्त इन इण्डिया,' (इन याइटल स्पोनेन एण्ड दानयुनेन्टत धाक द के) जुलाई, १४, १६४२ पृ० ४६३। ३. प० नेहरू—'मेहहूब स्पेनिन' भाग-३ प्रगस्त १९४७ पृ० १४२।

पश्चित्रकात्म डिविजन, मिनीस्ट्री प्राफ इन्कारमेशन एण्ड द्वाडकास्टिंग ।

प्रतएव मूल प्रश्न यह है कि भारतीय संसद में एक सगठित एव प्रभावणानी लोकतत्रोय प्रतिपक्ष के विकास में वौन-वौन सी बापाएँ है, ग्रौर उनवो किस प्रवार दर किया जा सबता है।

(१) चारत म राजितीतिय नेतृत्व की मृत्य यृि यह है कि यह नकारात्मक तथा वाल्पनिय प्रमावो ते मुक्त नहीं है। लोगतिय म राजितीतिक नेतृत्व का विकास एव प्राप्तान वार्ष नहीं है। स्वीमें इसने लिए प्राप्ताम पर्यं एवं कित वी विवास एवं प्राप्ताम वार्ष नहीं है क्यों कि हसने लिए प्राप्ताम विवास की प्राययम्वता है। इसने प्रति कितृत्व के लिए प्राप्तम-विल्वान की प्राययम्वता होती है, जिसने जाता पर उचित प्रमाव हो सने। परन्तु मारत में यह देखा गया है कि राजितीतिक दलों के कई सदस्यों ने प्रयं प्रमुख्य होती है जिसने कार्य कि इस्तर्यों ने प्रयं । कई सदस्यों ने प्रयं । कई सत्य । ने प्रयं । किया । इसने प्रतिरक्त कई विवास । को तत्व होत्य में हिया । विवास ने प्रयोद स्वाप्त ने प्रयं । प्रयोद में के प्रतिरक्त कई विवास वार्ष वा वा नितृत्व के साम में स्वाप्ति क्या होते है के प्रतिरक्त कि प्रयं स्वाप्त ने प्राप्त ने साम में स्वाप्त क्या से वह विवास पैदा होता है कि व्यक्तियत, न कि राजितीतिय वारणों से इन व्यक्तियों ने कार्यस छोड़कर विवासी होते । में सदस्यता प्रवृत्व में हो । पत्त । प्रता प्रवृत्व में छोड़ना मुत्ति है। जनता प्रवृत्व मार्विय ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व में छोड़ना मुर्तिल गही समस्ति है। जनता प्रवृत्व मार्विय ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व में छोड़ना मुर्तिल गही समस्ति है।"

कई राजनीतिक दलों के नेतृस्य में धान्तरिक कलह तथा भगडे है मिससे उन दिनों से सदस्यों में धानतीय की भावना धवती है और साथ ही जनता पर बुरा प्रभाव पहुँचता है, जैसा डा॰ सोमजी, प्रजा सोणितस्ट दल के लिए कहते हैं "नेतृत्व के दृष्टिनोंण से इसने प्रण्य सस्यायनों की मसामयिक राजनीतिक सेवा निवृत्ति होने से धीर धन्य सदस्यों के व्यक्तिगत मेदन नाव का भावों के नारण प्राप्तक हानि सहनी पटी है। "व यह सत्य है नि यदि धारम्म सं ही विपक्षी दलों का जिलत नेतृत्व तथा कांक्रम होता, तो नदांचित ससद में एक सगठित लोगताचिक प्रतियक्ष ने विकत्तित होने में कई पठिनाइयाँ दूर हो सकती थी। परन्तु जैता स्पर्ट हैं मारत में विनिन्न राजनीतिक दल जनताचिक, सामयवादी तथा साम्प्रदायिक प्राप्त में विनिन्न राजनीतिक दल जनताचिक, साम्प्रवादि आधार पर विमाजत होने के धतिरिक्त प्राप्त साम्प्रवादि का साम्प्रदायिक प्राप्त स

१. जी० थी० कान्तिकर—'प्रोयलेम्स झाफ झपोजीशन इन इण्डिया इन स्टबीज इन इण्डियन डेमोक्रेसी' १६५ पु० ६२६।

२. ए० एव० सोमजी-'मोटिबेशन्स एण्ड प्रोपेगेण्डा इन सेमीनार' ३० फरवरी १९३२।

पत्तस्वस्य भोरतन का मूल उद्देश्य-लीन क्लाग, दलगे दृष्टि से भीमल ही जाता है। "एक प्रमानवाली प्रतिपक्ष वा निर्माण ऐसा वार्य है, निर्मान तिष्य पैयें की, निर्माण का पार्च-लेके प्रारिष्ट नवार राजनीतिन दृष्टि है पिएड हुए देश के लिए प्रावश्यकता है। निरस्तार विरोध में रहना, प्रतिपक्षी दस का उद्देश्य नहीं ही सकता। एक प्रमानकाली प्रतिपक्ष को सत्तारह दस का कड़ा विरोध करते हुए, सर्वाताणी में दिवार को मांचिता का निर्माण करना है नि वह सरकार की वार्योद सरकार के सद्देश कार्य करना है। वह सरकार की वार्योद सरकार के सद्देश कार्य करना है। इस बात पर कल दिया जाता भ्रावश्यक है कि एक प्रमानवाली वेत के निर्माण के लिए कोई द्वारा मार्य नहीं है। इस्ते पूर्व कि उत्तके हारा लेकर सरकार की लिए कोई द्वारा मार्य नहीं है। इस्ते पूर्व कि उत्तके हारा लेकर सरकार की लिए कोई द्वारा मार्य नहीं है। इस्ते पूर्व कि उत्तके हारा लेकर सरकार की लिए कोई द्वारा मार्य लिए के तकी में नती पर्योग की स्वाप्त के स्वाप्त के लिए कोई द्वारा मार्य तहीं है। दस्ते पूर्व कि उत्तके हारा लेकर सरकार की लिए कोई द्वारा मार्य है। स्वाप्त के विरोध सरकार है, सारत के देशों ने नती है। प्रतिपक्ष की सरकार ता छुटता भीयें की नमी का सुक्त है। स्वाप्त के वार यह दस्तिया जाता है कि यह विश्वास से श्रीरत की कर लिए कि एक स्वाप्त है कि यह विश्वास से श्रीरत की कर लिए की हिस्स करना छुटता भीयें की नमी का सुक्त है। स्वाप्त के वार यह दस्तिया जाता है कि यह विश्वास से श्रीरत की कर लिए की हमा है। "

(२) केवल निष्ठाबान एवं उत्तम नेतृत्व ही एक प्रमावकाली लोगतात्रिक प्रतिपक्ष के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अनता को प्रभावित करने के लिए एक प्रन्य तत्व प्रावस्पक है।

इस तथ्य को दृष्टि से घोमल नहीं किया जा मकता है दि स्वतकता के परमात् धार्षिक ध्रमानता, प्रास्त्रक बस्तुओं के दानों में बृद्धि, प्रशासन में जाल पीता-गाही तथा अंद्राचार के कारण जनता में ध्रमत्तीय बडा है। परन्तु यह एक विद्रन्दना है कि इस सब कारणों के होते हुए भी जनता ने लातारा, सिक्यान सामू होने के पत्थात् केवल एक ही दल (वाग्रेस) को वेन्द्रीय सरकार को सम्योद सीपी! इस विभिन्न पानतीतिक प्रता के क्या वारण है यहाँ पर दो कारणों का उल्लेख किया जा महता है!

सर्वेत्रयम, वह प्रतिपक्षी दलो द्वारा पाश्चात्य राजनीतिन, धार्यिन एव सामा-जिक प्रादशों या नमूती को ध्रपनाया गया है। परन्तु आरम्भ से ही दाग्रेस में मी इसी प्रकार के राजनीतिक, धार्यिक एव सामाजिक सिद्धानतो को ध्रपनाया

ाजक आरावा या नशूना का समानाया गया है। यर जु आरस्त से हा यावत मी इसी अनर के राजनीतिक, स्राधिक एवं सामानिक सिद्धानों ने प्रप्ताया है। प्रमुख एक सामारण नागरिक ने लिए कमी-कभी यह समझना नठिन है कि 'तोकवानिक स्माजवार' की योगना वस्ते याले दवने प्रथिक राजनीतिक दस

१ एम॰ भार० दण्डवते—प्रोवलेस्त झाफ झपोजिशन इन दृण्डिया इन स्टडीज इन दृष्टियन डेमोक्रेसी, १९६५, ६३८ ।

न्यों हैं, जबिक कार्रेस ने इस सिद्धान्त की घोषणा वी है और इसकी कार्याग्वित करने वा दावा करती है। "केवल यह कहना कि हम यही चाहते हैं, जो सत्ताद्ध दस बाहता है किन्तु हम उसे वेहतर रूप में करने, जनता वो आवदत करने के लिए पर्योग्त नहीं है।" उदाहरण स्वरूप प्रजा सोशिनिस्ट दस का आग्न प्रदेश में साधन, साम्मवादी दस का केरल म जासन, उत्तर प्रदेश में सपुत्र विवायत्व दस का केरल म जासन, उत्तर प्रदेश में सपुत्र विवायत्व दस का का जासन, इस विवायत्व दस का जासन, इस प्रवेश में सपुत्र विवायत्व दस का जासन, इस विवायत्व देश से अपना रखते हैं। "सामान्यत जनता में समस्त राजनीतिज्ञों के प्रति एक प्रकार की अमना रखते हैं। "सामान्यत जनता में समस्त राजनीतिज्ञों के प्रति एक प्रकार की अपना स्वयं प्रति एक प्रकार की विवायत्व हैं। अपना विवायत्व हैं। अपना विवायत्व हैं। इस प्रताप्त विवायत्व होता। इसिलए वे नमें तथा प्रजात सगठन के बजाय एक बात सगठन की समर्थन देते रहते हैं।"

दितीय, सत्तारु दस (काप्रेस) की नृष्टियों के कारण उसके प्रति धारन्तीय होते हुए भी जनता को यह विदित्त है कि इसके प्रसास कोई वैकल्फिक राजनीतिक दल नहीं है जो उनका एक दृढ़ समग्र एवं स्वस्थ प्रधासन देने की स्थित म हैं। प्रताप्त यह विपसी दस या दसों के लिए कुननोती है, जिसका सामना करने के लिए उननो जनता के सामक अपनी एक प्रमाववासी तस्त्रीर रखनी होगी। यह प्रतिपक्षी दसों के रचनारमक कार्यों से ही समय है। उदाहरण स्वरुप, विधेषक स सहवारिता के क्षेत्र मे राजनीतिक दस योजनामी की सफलता के लिए प्रपना योगदान दे सकते हैं धीर जनता के समस यह सावित कर सकते हैं कि इनके सगिठित नार्यक्रीयों म प्रकासन एवं प्रवन्ध-सवी सामस्याप्त के से सावान करने की क्षमा है। प्रताप्त प्रतिपद्धित होते के व्यवहार एवं वार्य ऐसे से होने चाहिये जिससे जनता में उनके प्रतिविधी हती के व्यवहार एवं वार्य ऐसे होने चाहिये जिससे जनता में उनके प्रति विश्वास की मावना जागत हो सके।

१६६७ के ब्राम-चुनाव के बाद विभिन्न प्रतिपक्षी दलों ने, विभिन्न राज्यों में सयुक्त सरकारें स्थापित की। ये सयुक्त सरकारें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बगाल, पजाब, हरियाणा ग्रीर मध्यप्रदेश में स्थापित की गई थी।

परन्तु सिवाय प्रान्तरिक भगडों में घपना समस्त समय व्यय करने के इन सरकारों ने जनता के हिन में कोई विशेष कार्य नहीं निया। "इसके प्रतिरिक्त, कई राज्यों में, विधान समामों के कई सदस्यों ने राजनीतिक नेतिकता को टुकराते हुए घनने स्वार्थों को पूर्वि के लिए दल-यहक और दलीय निकार में परिवर्तन था खिडन दलों का निर्माण किया जैसे बनाल में पीपुल्स डेमोक्रेटिक फन्ट और विद्वार

१. जी० बी० कान्तिकर-पूर्वीतत पुस्तक' पृ० ६३२ ।

२ वही पृ॰ ६३२ ।

में सोधितरहत । ऐने विधादकों के कारण को उचित्र या धरुकिन माधनी से समी यह हुएतों में ही प्राथमिक रूप से पवि रुपते हैं—एक सामान्य ब्यक्ति की समझीब कनत्त्र में ग्रास्था रुपस्या गई है और लोकत्त्र के ग्रान्तित्व को ही उर हो गया है।"

232

(2) जब तक राजनीतिक दलों को मन्या धायधिक रहेगी और वे साम्यदा-तिक, त्यानीय या प्रत्य किमी सक्ती संत्यों से प्रमादिन होकर वार्य करेंग, स्टू स्पष्ट है कि इनके डारा समय में कोई किमी प्रमादमानी मोक्तानिक प्रतिकाश के निर्माण को समादमा नहीं है। "राजनीतिक दलों को धायनत कुन्ध नारणा के धायार पर शोरकर कई दली को पैदा किसा है। एक ऐसा देश जहाँ पर प्रतिकाश दल निर्वेत हैं, इस प्रमार का प्रतनीतिक विचानक नहीं कहन कर नारणा है। बिका जैसे देश में, तिकर दल में प्रमानित प्रतिवक्ता होने के बावबुद्ध मजहर दल के नेना थी एक्युरित बेकन समान बाम पथी उद्य नेनाओं ने कमी भी लेकर दन को विचानिक कर एक निया मण्डा स्थापित करते का प्रयत्न नहीं लेका। बिहान सेवर दल हारा प्रस्तुत सक्क भारत के प्रनिवशी दलों की दृष्टि में बनी ग्रीमन नहीं होना चाहिये।"

सह स्वाट है है जिंद सारण में एक प्रमानमानी लोकतानिक प्रतिपक्ष का विवान करना है, तो जो राजनीनिक दनों की वर्तमान सच्या प्रत्याधिक है, उसकों नम करने दो या स्वित्त में मंदिक तीन तक गीमित करना प्रावस्त्र के हैं। उसकों नम करने दो या स्वित्त में मंदिक तीन तक गीमित करना प्रावस्त्र के हैं। एक प्रत्य के प्रतिक्र नमें है, है जि मंदीन प्रणानी के प्रतिक्रत के निष् क्षीकार करना प्रतानम्बत्त है। इसके तिष् तिज दनों भी विवास्त्रात एवं आदर्श मानि है। उन्हें है तह में देवी स्वृतिकों, उदा-हरण है । तह स्वत्त है ने नमुन्य प्रतिक्रत के एक सम्बद्ध हो से देवी प्रवृत्तिकों, उदा-हरणनः सावजानिक सामाजिक, साम्यवादी एवं 'प्यापूर्व स्थितवादी' प्रतिक्ष म मनी देवी । प्रतान मनी तह स्वत्य स्वतिक्रत हो । प्रतान मनी तह स्वत्य स्वतिक्रत हो । प्रतान प्रतान स्वतिक्रत स्वत्य स्वतिक्रत स्वत्य वर्तमान सावजानिक स्वत्य स्वतिक्रत हो हमा प्रतान स्वत्य वर्तमान सावजानिक हो हमा प्रतान स्वत्य स्वतिक्रत हो हो स्वत्य के स्वत्य वर्तमान सावजानिक हो हमा स्वत्य स्वतिक्रत हो हो स्वत्य स्वतिक्रत हो हमा हमानिक स्वत्य स्

१. के न सी० सक्तेमा-'विडर इण्डियन डेमोर्डेसी' इन सोशनिस्ट कांग्रेसमेन, मार्च २५, १९६६ ।

२. एम० बार० दण्डवते पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ६३६-६३७ ।

ित वरेन्द्र, इस प्रवाद के बस्यामी समझीने, विभी सीमिन उद्देश्य की पूर्वि एस एसन नहीं हो सबने हैं। "बादाती में एसगा, सम्बन्ध, मुगुसावन एवं दोस नेतृब सताहर वर के लिए विजते धावस्यक हैं, वर्षेत्र प्रनिष्या दस के लिए भी धावस्य है। इस गुणी की धस्यामी निर्वादन सबसी समझीनों के साम्यम से विजनी निर्वादन के बाद तक विद्यमान रहने की समावना नहीं रहनी है, प्राप्त नहीं किया बासता है।"?

यह इसरन रकता धावसक है कि प्रतिपत्नी दलों के समान प्रस्थायी तथा प्रसार प्रसानी करने की प्रमुति कार्यस (सहारड) दल ने मी मारत के वतित्वय रासमें में प्रदान को है। १६४० में कार्य में में मारती दल से ममानीता दिया। । इसी बनार केरत में भी पूं एतन देवर के नेनृत में कार्यस ने साम्यवादी दल से सहयोग करने के प्रमुत किये । प्रश्न यह नहीं था कि साम्यवादी सरकार पद्यों या बुदों भी, किए प्रमुत्त को सार्वादिक तथा पूर्व निरक्त प्रसादी की है, प्यतिन् का एक सोक्यांत्रिक, पर्म निर्माण दता की स्थान कार्यस के साथ सहसीय करना वाहिये जो एक जनवादिक सिवान हारा प्रदत्त स्वतवता का साम महस्ति रण से तेने किए कर स्विधान कार्यक किया करना करने पर तथा है ?

सक्षेप में राजनीतिक दली द्वारा समम्भीने किये जाते हैं, उनके तिए निम्न-निजित मुद्दो पर च्यान रखना आवत्यक है।

(क) राजवीतिक सममीत समान विचारपाय, नीतियो एव उद्देश्यो पर सायारित होने चाहिये, तब ही वे स्थायी एव लामप्रद हो सकते हैं।

(ख) धमकोने वा बहुँसा वेबल सत्तास्त्र दल की पराजिन करने का नही, परन्तु रचनात्मक नीतियो एव कार्यक्रमों ने भाषार पर एक वैकल्पिक सत्तार की स्थापना करना होना चाहिन । यदि मारतीय राक्तीतिक जीवन में विदेश रूप ने इन वो मुद्दों पर प्यान रखा जाये तो इसने सत्तरीय सोकतव की नीव को बुढ़ होने में साराया स्तिती।

(४) प्रास्त में एवं सगिंत्र एवं प्रभावभावी सीवतत्रीय प्रतिपत्ती दल के विवास में ये एक भीर उल्लेखनीय रहावट है, प्रविवास जनता वो निरसरना है, तमा पर प्रतिवास करता को निरसरना है, तमा पर प्रतिवास करता के मार्च है, तमा पर प्रतिवास करता है। उसके परिवास करता है, विवास के मार्च में रीड़ वहां जा मतता है। उसके परिवास करता , जुर राजनीतिज्ञों झारा उल्लेखना पूर्व मार्चों से जनता की प्रभावित कर, इनके कन प्राप्त करने से सफलता कित जा करती है। इसके धारिरक्त, विभिन्न प्रकार के तथा किया सामाजिक,

१. एलोटिरियो सोम्रारेज-'पालियामेन्टरी ध्रपोशीशन, इन व इन्डियन रिस्यू नव० १६४१ प्र० ४२० ।

स्नाधिक, स्नामिक प्रजोमनी, धाक्यंणो द्वारा मी निरक्षर मतदाताधा को थोडे से समय के लिए प्रमानित कर उनके मत हृड्ये जा सकते हैं। प्रिटेन म मताधिकार सर्व-कने दिया गया, जबकि भारत म एक ही बार यह प्रधिकार मारतियों नागरिकों को सिक्वान द्वारा दिया गया है। खत्य, ब्रिटेन म मताधिकार प्रदेश करों के को सिक्वान द्वारा दिया गया है। खत्य, ब्रिटेन म मताधिकार प्रदेश करा के से के खिला नागरिकों को प्रपाद राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुइ है। भारत म, इसके विल्कुत विरारीत हुमा है, ध्वान मारतीय नागरिक को पहले मताधिकार प्राप्त हुमा और इसके उपयोग में लाने के साथ साथ उनको स्पत कुछ सीमा तक राजनीतिक शिक्षा मिन्नी है। लाक्तन म शिक्षित नागरिक को महत्वपूर्ण पूर्णिका है। एक शिक्षित नागरिक लोकतन म शिक्षित नागरिक नो महत्वपूर्ण पूर्णिका प्रपत्त विश्वान के शिक्षा मिन्नी है। किन्तु एक निरक्षर या प्रत्यक्ष नागरिक के लिए यह समय नहीं है। खत नागरिक की किक्षा विशेषकर राजनीतिक-शिक्षा पर लोकतनीय यवक्ष्य में विशेष स्थापक निरक्षर या प्रत्यक्त में स्वत्य पर कहते हैं— "मतदाता की स्थापक निरक्षर ता और उनके मत के अर्थ को मामक की प्रधानता का, जिससे अरुवाचार बडा है, कुक्षलतापूर्वक कई सन्य तरीकों से लोपण दिया गया है।

एक मध्याविष चुनाव के दौरान लेखक को व्यक्तिगत रूप से ज्ञात हुमा कि
यह कितनी चतुराई से किया गया। प्रतिद्वन्द्वी दल के समर्थक एक नमूने के
मतदान पत्र एव रवर नी मुहर जिस पर × चिह्नित या लेकर प्रचार कर रहे थे।
जब कभी भी वे यह देखते थे कि मतदाता हुन्छ विरुद्ध है, तो वाग-चपनता से एसे
मतदाताम्रों को नहते कि किसी प्रत्याची के लिए × चिन्ह का उत्पांध उसके प्रति
उनकी प्रसहमति का सूचक या, ब्रत्युक जब कोई प्रत्याभी उनकी प्रसन्द नहीं था
री उनकी केवल यह करना था कि उसके नाम के सामते × प्रवित्त कर है।"\

थी एस० थीं राजू एक श्रन्य उदाहरण प्रस्तुत वरते हैं, जिससे यह विदित होता है कि निरक्षर मतदाता ने मत का ग्रनुचित लाम किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। "उदाहरण-स्वरूप मेंसूर के एक निर्वाचन छोत्र म, जहाँ पर लेखक नो जान ग्रम्पर प्राप्त हुमा, उन्होंने देखा कि कितनी भी कठिनाइयों ने वावजूद सताख्य कांग्रेस दल विजयी होता था क्योंकि उननो बैल तथा जुँगा, का निर्वाचन चिन्ह प्राप्त या ग्रीर इस निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत उन व्यक्तियों का था जो बैल की पूजा करते हैं।"व

यह सत्य है कि चुनावों के दौरान निर्वाचन चिन्ह प्रणाली से निरक्षर मतदा-ताओं के लिए काफ़ी सुविधा हो गई है, किन्तु जैसा कि उपर्मुक उदाहरणों ते

१. एस० बी० राजू 'पूर्वोक्त पुस्तक', पृ० ६२४-६६ ।

२ वही पृ०६२६।

उस राजनीतिक दल के सद्दा होगा जो स्केण्डीनीविया से स्पेन तथा यूगोस्लाविया तक कार्यरत है। परन्तु इसके प्रतिदिक्त, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि दूँ मतदाता निरक्षर है। इसका यह तार्त्यय नहीं है कि वे, उनकी तुलना में जो पढ तथा लिख सकते हैं, कम बुद्धिमान है, परन्तु इसका यह प्रयं प्रवश्य है वि वे प्रापका (राजनीतिक दल का) घोषणा पन पढ़ने में प्रसमर्थ है।

र्(जनातिक पर नार्य है कि ससद में चिये गये भाषणी को भी वे नही पढ सकते हैं जो जन तर शब्दो द्वारा नहीं पहुँचाये जा सकते हैं, और आवागमन के साधन भी अत्यन्त सीमित है। यदि टेलीविजन होता तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। परन्तु भारत के प्रामों में टेलीविजन एक दूर का सपना है। अत्यत्य यह प्रवश्यभावी है कि राजनीतिक दल जनता तक पहुँचने में कठिनता का सामना करें। ऐसी स्थित में विनारधारा का कम महत्व होता है। सगठन का और अधिक महत्व होता है। १९६२ के आम-चुनाव में अत्य आम चुनावों के समान निर्णय राजनीतिक कार्यक्रम या विचारधारा के आधार पर नहीं हुमा था, यह निर्णय राजनीतिक दलों के सगठन-तत्र की सवधित क्रिक के आधार पर महत्व हाता है। १९६२ के साम-चुनाव के समान निर्णय राजनीतिक दलों के सगठन-तत्र की सवधित क्रिक के आधार पर महा हुमा। यदि कांग्रस को अधिक मत प्राप्त हुए तो वह इस-कारण कि इसका मगठन तत्र किसी अत्य राजनीतिक दलों के सगठन-तत्र की सवधित क्रिक के आधार पर हुमा। यदि कांग्रस को अधिक मत प्राप्त हुए तो वह इस-कारण कि इसका सगठन किसी अत्य राजनीतिक दल के सगठन-तत्र वे अधिक प्राचीन, शक्ति-

सगठन तत्र के उच्च कोटि के होने के अतिरिक्त, काग्रेस को विसीय साधनों की कमी नहीं है, जिसते उसकी रियति भौर दृढ होती है । इसका एक मुख्य कारण यह है कि काग्रेस सतास्व हत्य है। १९५२ से पिछले पाँच झाम-चुनाव के अनुमन पर कहा जा सकता है कि आम-चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए प्रया्त वित होना अत्याद्यक्ष है। निवांचन प्रायोग द्वारा प्रकाशित पेनुपुष्रत आफ द इतेक्शन ला' में भाम-चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा प्रकाशित पिनुपुष्रत आफ द इतेक्शन ला' में भाम-चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा प्रकाशित यह है कि साधारणतमा एक प्रत्याशों के लिए इतना व्यय करना उसकी व्यक्तिगत सीमा के साधारणतमा एक प्रत्याशों के लिए इतना व्यय करना उसकी व्यक्तिगत सीमा के साइर है। तथापि जो राशि वास्तव में व्यय की जाती है, वह २५,००० रूपये से कई मुना अधिक होती है। यह इसलिये समय है कि उपयुक्त सीमा, एक प्रत्याशी द्वारा व्यक्तिगत रूप के किये गये व्यय पर है, जबकि प्रत्याशों के लिए उसके दल द्वारा किये गये व्यय पर कोई सीमा नहीं है। इस कारण एक प्रतिचक्षी दल के लिए यह एक कठिन समस्या हो जाती है, क्योंकि न क्षों उसके पास प्रत्यिक करिन हो है न ही ऐसे सामन, जो सत्ताव्य दल को अपनी स्थिति के कारण उपलब्ध होते हैं। श्री रजनी कोठारी का कथन है—'काग्रेस द्वारा प्रत्येक सरकार होते हैं। श्री रजनी कोठारी का कथन है—'काग्रेस द्वारा प्रत्येक सरकार होते हैं। श्री रजनी कोठारी का कथन है—'काग्रेस द्वारा प्रत्येक सरकार

१. एम॰ झार॰ मसानी-'पूर्वोक्त पुस्तक' पृ० ४९६ ।

शाजाल हनना हूर धीर धरिक पैल गया है कि हमके दायरों में सहनारी सिमितनों, प्रवादन, समुदार-विकास प्रधानन, समक्ता धरें, सरकारी संस्थाएँ लो "धोजना, विकास, प्राञ्ज नावी में सार्वीय हैं, मसन्त सस्यारों, जिलका सबय बर्रास्ट, जोटा, व्यायारिक सध, श्रीवारिक सम्यारों, एक सार्वारक प्रधिकारियों से है-सभी भा जाते हैं। इस तब की प्रमाद्य रूप से वायेस समझ्त का दिस्सा बजाकर एक प्रदेश में राज्य स्थापित किया जाता है।"

१. मार-क्ठोरी-चेबलेपिंग पोतिटिक्त पेटर्न, (इन सेमोनार, सस्या ३० फरवरी १६६२ पु० १८।।

वे प्रत्याशी को जो एक स्थानीय वक्षीस था विसीय दृष्टिकोण से काफी हाति हुई । उत्तरा करना थानि नांग्रेस प्रत्याशी देशमगब ३,००००० रुपये व्यय विये जबति उसको उपसुका राजि का एक दशाश मान भी उपलब्ध नहीं था।""

सक्षेप में यह विदर्भ दिनाता जा सवता है कि पुत्राय में राष्ट्री समाजीतो वे शिए था भरग । शायश्यम है भौर प्रत्येन घोष्य गुद्धिमा एव विष्ठापूर्ण व्यक्ति को यह सुविधा उपलब्ध मही रहती है। इस पुटि को दर करो का उसम उपाय मही है ति सत्तारूख दा भयो पर विशिव भावश्यक रोग समाथे रहे भीर गाम दश्यानवेंग पाता गरे।

(६) जैसा देला जा पुता है गारत की ससदीय पद्धित में एक घोर सो शामेत ना विशास बहुमा है तो दसरी भोर प्रशिवशी दस बहुसरमा मे है जिससे भारतीय संसदीय पत्नी भे एव प्रवाद का राज विशिव अस्त प्रता समा रहता है। ' राग्रेस ने एवं सरवी माधिवस्य द्वारा, यह राजाीतिन स्वाधित्य स्थाविस रिमा गया होगा जो स्वानता के बारिन्मक वर्षों मे भारत के लिए बावश्यक था, जैसा रि प्रो॰ पार ो बतलावा है, सिंतु इसी द्वारा एक स्वस्य रामगीतिक दलीय प्रणानी का जिलास रोत दिया गवा है। "र

चाएव यहाँ पर मृता प्रशा बहु है ति सामात्रता एवं मरादाता की क्या भगिता होती पाहिये जिसके द्वारा यह उपर्वत्त विणत राजनीतिन धरा गरा नो दर गरी हुए एवा सुदुइ एव प्रभावशाली प्रतिपक्ष के निर्माण में सष्टायता पहुँ नाथे ।

पॅनि ससदीय पद्धति भी सपराता ने लिए दो या ग्रायिक से ग्रायिक सीन राजीशिव दत ही हो । चाहिने, यह मस्यायस्यव है कि मतदाता धवा मत वेचरा उहीं दत्तों के प्रस्वाविभी को दें, जो तीकत्व, विवातवादी समाजवाद एवं धर्म िरपेक्षणा मे विश्वास करते हैं भौर जो धारतव मे राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। इसके उपरान भी भाषाता को यह जात करा। मायश्यक है कि ऐसे राजातिक दसी में से बीन कीन से दल उपमुक्त हैं भर्मान यदि दो से अधिक दलों की विचारशासाए समा है तो वेयरा उसी दरा यो मा दिये जायें, जिसी भ्रायारा में भ्रमती प्रति-आमो मो निस्वार्थ माय से पूरा वरों में लिए रणारमव प्रयश्च विथे हैं। साम राजाीतिक दत स्वत ही समाध्य हो जायेंगे, बयोबि उत्तवी जाता का समर्थन ाटी भिोगा। पर तुपूर्व मे यह बनाता जा पुता है ति यह ज्ञान मतदाता वी शिक्षा तथा राजातिव विषयो से समधित ज्ञा पर निर्भर है, वयोवि विनित्त

१. पो० सी० चौधरी, पूर्वोक्त पुस्तक पू० २३ । २ एग० डी० पामर-पूर्वीकत पुस्तक पु० १६४ । १६

राजनीतिक दलों के सिद्धान्तो, नीतियो तथा कार्यक्रमो मे समानता या ध्रसमानता तथा गण-दोप मनदाता तब ही जात कर सकेंगे, जब उन्हे राजनीतिक विषयो का पर्याप्त ज्ञान है ।

सक्षेप मे, मारत मे एक लोकतत्रीय एव प्रमावशाली प्रतिपक्ष के विकास के लिए निम्नलिखित सभाव दिये जा सक्ते हैं -

(१) सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर जनता के प्रशिक्षण के लिए विशेष कर राजनीतिक मामलो के सन्दर्भ में, कदम उठाये जाने चाहिये.

(२) सरवार को शीझ ऐसी नीतियो तया कार्यक्रम को क्रियान्वित करना चाहिये जिससे जनता को ग्राधिक स्वतवता प्राप्त हो सके क्योंकि ग्राधिक स्थनवता ही वास्तव मे राजनीतिक स्वतंत्रता का बाघार है।

(३) विभिन्न प्रतिपक्षी दलो का, जो बहसस्था मे हैं, जनता तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है कि समान विचारघारा रखने वाले दलों को मिलाकर, मारतीय राजनीति मे दो या ग्राधिक से ग्राधिक तीन दलीय प्रणाली को जन्म दें जिनका माधार स्पष्ट रूप से सोकतानिक तथा धर्म निरपेक्ष हो !

(४) सत्तारूढ दल का एक विशेष उत्तरदायित्व है कि विमिन्त क्षेत्रों मे रचनात्मक प्रयत्नो द्वारा एक सोक्तात्रिक प्रतिपक्ष दल के विकास में सहायता करे।

(प्र) धन्त म, मारत में लोकतंत्र का बस्तित्व मारतीय जनता पर निर्मर

है। निर्वाचन के समय जनता को अपने मत इस प्रकार विमाजित करने चाहिये जिससे दो दलीय प्रणाली को प्रोत्साहन मिले ।

१. एम० के० रेडडो-'योतिटिक्त पार्टीज इन इन्डिया' (इन द इन्डियन रिब्यू, नवम्बर १६६४ प्र० ४२२) ।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

मारतीय सविवान एक जनतानिक सविवान है मत इतने दो विशेष मुद्दो पर विशेष स्था तथा है। सर्वप्रयम, विभिन्न सीमाएं जिनम सरकार के तीन प्रगो (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका समा तथा न्यायपालिका) को सविवान द्वारा स्थापित सधीय व्यवस्था में कार्य करना है। इस सबसे में सर्वेषण न्यायापत हो गूमिका एक सतुननक के समान है, नयोकि जहाँ सरकार ने अन्य प्रगाजना को उत्तेजित मावना से प्रमावित हो सकते हैं, वहाँ वेवल सर्वोच्च न्यायालय हो सरकार का एक ऐसा अग है जो निष्पक्षता एव शानिवूर्यक सरकार के कार्यों की व्यारपा सविवान के अनुवार करने, सरकार के विभिन्न धर्मों में सतुनन स्थापित कर सकता है। इसके प्रतिरक्त, सविवान में सववाद के सीमित सरकार के सिद्धानत के धन्तानेत सर्वोच्च न्यायालय नी एक विवेष मूमिका उत्तर सरकार के सदानत है। वह स्ववेच्च न्यायालय की सविवान के धनतान सर्वोच्च न्यायालय की सविवान की व्यारपा एवं सरकार करने का प्रविचार होता है।

हमारे सिवधान-निर्मातामों का यह विश्वास था कि सीमित सरकार जनतन के लिए प्रत्यावश्यन है। "परन्तु सिवधान में उन्होंने उस सिद्धान्त को समावेशित किए प्रत्यावश्यन है। "परन्तु सिवधान में उन्होंने उस सिद्धान्त को समावेशित किए जिसको (प्रमरोक्त को मुख्य न्यायाधीण मार्शक ने सीमित सरकार का प्रावश्यक तत्व माना है के सिवधान द्वारा व्यवस्थापिका की शक्तियो पर लागू की गई सीमाप्रो का धादर किया जाना चाहिये और सिद व्यवस्थापिका इन सीमाप्रो का उल्लंघन करती है तो उसके कार्य प्रवृंध है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से हमारे सिवधान के प्रनुष्केद १३ में विणत है।"

सिवयान के धनुच्छेद २५४ (१) में भी धवैष शब्द का उपयोग किया गया है। इस धनुच्छेद के अनुसार यदि किसी राज्य विचान समा द्वारा समवतीं सूची में उल्लिखित किसी विषण पर निर्मात कानून, किसी समीय कानून के विरुद्ध है, ऐसी स्थिति में राज्य विचान समा द्वारा निमित्त कानून धवैस होया।

१ डी० डी० बधु-कमेन्द्री धान द कान्स्टीट्युशन द्यांक इण्डिया, भाग-१ १६६४ पृ० १४६-४६ ।

गय राज्य में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष महत्व होता है। वह सविधान का रक्षक है। सविधान के किसी प्रावधान से सर्वधित शक्त को दूर करने के लिए सर्वोच्न न्यायालय को सम्विमान की व्यारवा करने का मधिकार है। इसके मति-रित, मारत में सपवाद के विकिष्ट स्वरूप के दिन्दिकोण से सर्वोच्च न्यायालय की मुमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय सघीय व्यवस्था मे, जैसा देखा जा चका है, तीन व्यवस्थापन संविद्यों का उत्लेख किया गया है । वे है-सघ, राज्य तथा समवर्ती सूचिया, जिनके द्वारा सघ और राज्य सरकारों के प्रयक-पृथक व्यवस्थापन क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है। यह कहने म नीई अतिशयोक्ति नही है कि किसी भी शक्ति विमाजन की प्रक्रिया में क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर सथ तथा राज्यों म बाद-विवाद वैदा होना स्वामाविक है। उदा-हरणायं-शतित विमाजन की माथा घरपण्ट होने के कारण दोनी पक्षी में किसी विषय के सम्बन्ध में विवाद पैदा हो सकता है। "धताएव ऐसे सारे विवादों का समाधान सविधान के जो सर्वोच्य कानून हैं, और जिसम शक्तियाँ केन्द्र तथा इकाइयाँ के मध्य विभाजित हैं, सन्दर्भ में किया जाना चाहिये । साथ ही न्याय मी माँग है कि इस तरह के विवादों का समाधान एक स्वतंत्र तथा निप्पक्ष सत्ता द्वारा किया जाये। सधीय सविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार का एक त्रपा जावा निर्माण विकास के स्वार्थित कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या है। यह विकास कार्या कार्या है। यह विकास कार्या कार्या कार्या है। यह विकास की आहमा करने वाली सर्वोच्य संस्था है, और क्षत्र हमा हुन होयों के विचासों के समाधान के लिए धनितम न्यायाधिकरण है। मारतीय सविधान द्वारा स्याधित सप व्यवस्था मे, मारतीय सर्वोज्य न्यायालय ना यह एक सब से महत्वपूर्ण कार्य है ।" र

द्वितीय, राज्य एव नागरिकों के सम्बन्धों के साव्यों में, सर्वोच्ध स्वायालय को सवियान के मृतुचीद १३ व २२ के मृतुवार नागरिकों के विनिन्न मृतुन्धिकारी के सरावन का धिकार है। वासक में सर्वोच्च स्वायालय का यह कार्य, सीकाम की सीमाम्री में राज्य सत्ता तथा नागरिक म्यावकारों के मध्य सम्बन्ध की रिचति में, अन्तानिक सनुकन स्थावित करना है। मूल मिकारों तथा सामाजिक नियम्बन में सामस्यत तथा सतुकन स्थावित करना वर्षित एवं महत्त्व जीव्य कार्य है किर मी मारतीय सर्वोच्च स्थायालय, हमारे सविद्यान के यो मुख्य मामारों, मूल मरिक नारों तथा सीम बच्चाम, को ध्यान में रख कर ही सविद्यान की व्यास्था

१. एम० बीव पायली---'इण्डियाज कान्स्टीव्यूकान, ११६२ पृ० २१६।

सर्वोच्च न्यायालय का संगठन

संविधान के अनुन्छेद १२४ के अनुसार सर्वोज्व न्यायालय के लिए प्रावधान किया गया है, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश और जब तक ससद कानून वना कर सख्या मे वृद्धि नहीं करती है, सात अन्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोज्व न्यायालय अधिनियम १९५६ द्वारा, न्यायाधीशों की सख्या सात सद कर पर गाँउ है। मुख्य न्यायाधीशा ससद की पूर्वानुमित से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से तब्द न्यायाधीशों में से तब्द न्यायाधीशों में निकृति की आवश्यवतानुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के नण पूर्ति की कारण कर संकेमा।

मुख्य न्यायाधीय की निवृक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद १२४ (२) के अन्तर्गत सर्वोच्च ग्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो से विचार-विमर्श करके करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशो भी निवृक्ति इस प्रक्रियानुसार राष्ट्रपति करता है, परन्तु इसके साथ मुख्य न्यायाधीश से परामर्थ लेना आवश्यक है।

संविधान के धनुष्टेद १२४ (३) के धनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नीचे दशयि धनुसार धर्हताएँ धावश्यक होगी ।

१—वह भारतीय नागरिक हो ।

२—िक्सी उच्च न्यायालय का कम से कम पांच वर्ष तक न्यायापिय रहा हो या कम से कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का श्रीममापक रहा हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार प्रसिद्ध विधि-साक्ष्यी हो ।

सर्वोच्च न्यापालय के न्यायापीश का कार्यकाल ६५ वर्ष की प्रायु पर्यन्त माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायापीश की राष्ट्रपति द्वारा ससद के दोनों सदनों में सम्पूर्ण सदस्यता के एवं उपस्थित तथा मतदान करते वालों के द्वे बहुमत से मतदान पारता होने पर, पदच्युत किया जा सकता है। सविधान के ध्रनुच्छेद १२४ (४) के ध्रनुतार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दो कारणों से पदच्युत किया जा सकता है; वे कारण इस प्रकार है—सिद्ध दुर्ध्यवहार तथा प्रतमता। यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करने की प्रक्रिया कठित है; इस कारण न्यायाधीश को प्रपत्त के स्ववच्चा प्राप्त होती है। उनके कार्यकाल के सम्बन्ध में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका प्रनुषित प्रमाव नहीं डाल सकती हैं।

मुख्य न्यायाधिपति का वेतन ४,००० रू० प्रति माह भीर सन्य न्यायाधीयो का वेतन ४,००० रू० प्रति माह है। प्रत्येक न्यायाधीया को रहने के लिए निःशुरक निवास स्थान धौर प्रपने कार्यों को करने के लिए यात्रा संवधी सुविधाएँ प्राप्त होगी। साधारणतया, न्यायाधीयों के वेतन तथा मत्तों में उनके लिए प्रहितकारक परिवर्तन नहीं किये जा सकते हैं, परन्तु राष्ट्रपति द्वारा धनुक्तेद ३६० के प्रस्तीत स्थिति से स्वापाधीमों के वेदन तथा मती में कमी की ला सकते हैं। स्वापाधीमों के वेदन तथा मती में कमी की ला सकते हैं। स्वापाधीमों के वेदन हम उच्छेद ११.१९ श्री श्री हो क्यों कि विचार से सादत की शक्ति हमें पर ये हैं। स्विचान के ये विभिन्न प्राचमान को न्यापाधीमों की निवर्षक, हटाने तथा वेदन एवं नती से सवधित हैं, सर्वोष्ट

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं कायं।

विदित्त राज्य के समय मारतीय सरकार प्रवित्तियम १८३१ के प्रस्तर्गत एक सचीय स्वायालय की स्वायान की नई यो। व परन्तु दस ज्यायालय की निर्वाय के किए विदित्त किलोगियदिय के प्रांतिक की जा सकती थी। १ इस पर यो इस सामेय ज्यायालय की १८३४ के स्विपित्रयम के प्रस्तानंत विध्यान की व्याख्या करने का प्रवित्तार प्राप्त था। सभीय न्यायालय के के दुस्त पर इस सामेय सापत ने इस सामायालय की भूमिला पर क्रांत्र सालते हुए स्वन्तिविद्य ऐतिहासिक शब्द कहे वो प्राप्त नारतीय सर्वोद्य व्याख्यात्र की भूमिला के लिए भी उपमुक्त गाने जा सनते हैं ——"वास्तर एव इसी है स्वतन्त एव नीसियों के उतार-श्वात के न प्रमातित होते हुए, इसका प्रमानिक करेन स्वित्तार दी अपूर्णस्था करता है की प्रमानिक को जो एक स्वतन तथा निष्यत पत्त के प्रमुक्त थी दिव्य की प्रमानिक को जो एक स्वतन तथा निष्यत पत्त है है शानिवृद्ध की दिव्य की स्वत्त का स्वतन्त है है हिस्स स्वतन्त है। इस्ति पहुंच में प्रस्त के प्रतिवाद की, उत्तक स्वतन्त कर प्रमान करना है मारत का स्वत्यान की, उत्तक स्वतन्त का सामाय के अपने हैं है इसारा यह स्वत्त प्रमान की, उत्तक विधान की, विद्य की स्वतन्त है एक स्वतन्त है। इस्ते प्रस्त के प्रस्त की दृष्टि से नही. परस्त के प्रतिवाद की, वृद्ध से स्वतन्त है प्रकात है, दिवस में सिय के विद्या के विद्य के निवत की भीति तथा प्रसान कि तथा की स्वतन्त है। कि विद्या के विद्य की तथा कि विद्या की विद्या के विद्या के विद्या की विद्या की विद्या के विद्या क

याने चलकर उनका बहुता है.—"मेरा निश्चित मत है कि सपीण न्यायालय संविष्यान की व्याव्या, कोई सौएचारिक या रूबी कानूनी मावना से प्रेरित होकर नहीं करेया । में भागा करता हूँ, यह न्यायालय, कि उन राजनीतिक प्रमादी तथा प्रवाहों को विनाद हारा संविद्यान को जीवनशक्ति प्राप्त होनी है, कानून के दायरे में स्वत्रजता पूर्वक कार्याविन्त होने देशा ॥"

सर मारिस गायर के उपर्युक्त क्यन, मारतीय सर्वोच्च ध्यायालय के लिए भी सही है. विशेषकर जबकि भारतीय सविधान द्वारा अमरीनी सविधान के विपरीत

१. एम० गायर-एफ० सी० झार० भाग-१ पृत्व, १६३८ ।

२ वही प्रव्या

न्यायिक सर्वोच्चता (जिसको प्रमरीकी सविधान में 'कानून की वैधिक प्रक्रिया' के सिद्धान्त पर माना गया है। की प्रपेशा व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता (जिसको मारतीय, सविधान में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के सिद्धान्त पर माना गया है। को मान्यता ही गई है। इस विषय पर विस्तृत रूप से प्रध्ययन, सर्वोच्च न्यायावय के त्यायिक पुनरवलोकन के प्रधिकार के प्रन्तगंत किया जायेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न कार्य इसके विभिन्न क्षेत्राधिकार में निहित हैं, जो स्राचीलिखित है।

१--प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार----प्रमुच्छेद १३१ के ग्रन्तगैत सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित मामलो पर प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है।

क--सघ सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य निवाद, या

ख—सम सरकार तथा एक याएक से अधिक राज्य एक पक्ष मे एव दूसरे पक्ष मे एक याएक से अधिक राज्य , या

ग—सप के दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद । ऐसे विवाद में किसी ऐसे कानून या तथ्य का प्रश्न निहित हो, जिस पर कोई कानूनी अधिकार आधारित है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का मारत से सधीय व्यवस्था की दृष्टि से विवेष महत्व है। सधीय राज्य का मूल सिद्धान्त प्राप्त विभाजन का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार सथ सरकार तथा राज्यों की सरकारों के मध्य मित्रयों का देववारा करते हुए विशिष्ट कोत्रों का निर्वारण किया खाता है। प्रसिद्धां के विभाजन के लिए सर्वोच्च स्था राज्यों के क्षेत्राधिकारों की पवित्रता को कामप रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की भूतिका अर्थिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यक्ति के विभाजन के सिद्धान के स्वय से उत्पत्त विज्ञात पर निर्मेष देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सर्विच्या के स्वयं में उत्पत्त विज्ञात की साम प्राप्त याज्य की सर्वाच्च के सर्वाच्च के स्वयं में उत्पत्त विज्ञात के सारे प्राप्तवाचा की सुक्त व्यायालय को सर्वोच्च विद्या के होतो एको के लिए न्याय के सर्वाच्च होने पत्त विज्ञा की समान रही। श्री वश्ली टेक्चन्द का सर्वोच्च का सामान की सुष्ट पर राज्य व्यवस्थापिकाओं का 'संगुतन चक्न' कहना उचित्र हो है। ' '

२—प्रपोतीय क्षेत्राधिकार—सर्वोच्च न्यायालय को राज्यो के व्यित्रप्त उच्च न्यायालयो प्रीर न्यायाधिकरणो के निर्णयो के सम्बन्ध मे प्रपील सुनने का प्रियक्तर है। सविधान के ग्रन्तगंत सर्वोच्च न्यायालय, दीवानी, फीजदारी एव

१ एम० पी॰ शर्मा-'व गर्वमेन्ट श्रांफ द इण्डियन रिपब्लिक' १८६० पु०२१४।

सबैधानिक मामको में अपीत सुनने के लिए देश का सर्वोच्च एव अन्तिम न्यामा-लय है। सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्नलिखित प्रकरणो की सबस में है।

क—सर्वेचानिक प्रकरण—धनुष्टेद १३२ (१) के धनुसार मारत में स्थापित उच्च स्थामत्व के किसी दीमानी, पोडदारों या धन्य विसी वार्यवाही में दिये गर्वे निव्य किसे या धनियम धारेश से, यदि उच्च व्यावालय प्रमाणित करता है कि प्रकरण में सविधान की व्यावसा का प्रका निहित है तो सर्वोच्च स्थामत्य में प्रमोण की जा सकती है। उन प्रकरणों के सर्वच में जिनके निष्ट उच्च समाम-लयों ने प्रमाणित करता धन्योद्धन वर्ष दिला है स्मित प्रदेश स्थापत्य सन्युष्ट है कि प्रकरण ऐसा है, जिससे सविधान को व्याव्या का प्रका निहित है तो धनुष्टेद १३२ (२) के धन्तमंत्र विशेष धनुमति झारा उच्च स्थामत्य सन्युष्ट है कि सर्वोच्च स्थापत्य में प्रमील सुनेश का ध्यीवरा है। धन्य यह स्थाप्ट है कि सर्वोच्च स्थापत्य को सर्वधानिक मामलों पर निर्धय देने का धनियम है। प्रधिकार है। सनुष्टेद १४५ (३) के सनुसार सर्वोच्च स्थापत्य की सर्वधानिक

स-दीवानी प्रकरण-दीवानी प्रकरण के सबय में, सिंद्यान के ख्रुट्युंट १२३ के धन्तर्गत यदि उच्च ग्यायालय यह प्रमाणित करता है कि प्रवरण धरील करने के तिए उपनुक्त है तो उच्च न्यायालय के निर्मय, दिक्की, या प्रतिन कारेश से सर्वोच्च न्यायालय को धरील की बा तरवी है। यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि प्रवरण गिहित मूच्य २० हवार से कम नहीं है या निर्मय से सवधित सम्पत्ति का मूच्य २० हवार से कम नहीं है, तो सर्वोच्च

न्यायालय को अपील की जा सकती है।

ग---फीजदारी प्रकरण अनुस्टेद १३४ के अन्तर्गत सर्वोड्च न्यायालय को,
किसी उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय अन्तिम आदेश का संस्ट से अपील की

किसी उच्च न्यायालय के ग्रान्तिम निषय भीन्तम आदश या खण्ड से अपाल । जा सकती है, यदि वह किसी निम्न न्यायालय के बरी करने के ग्रादेश पर —

१—अपीस होने पर, उस झादेश को रद् करके असियुक्त को मीत का दण्ड देता है, आ

र-- क्सी ग्रवीन न्यायासय से मुकदमा लेकर अभियुक्त को मीन का दण्ड देता है, या।

देता है, या। ३--- प्रमाणित करता है कि मुक्दमा सर्वोज्य न्यायालय में अपील करते के

4—प्रमाणित करता है कि मुक्टमा सर्वोज्य न्यायालय मे अपील करते के लिए उपयुक्त है।

सगद को, प्रनुञ्देद १३८ के ब्रन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के ग्रमीलीय क्षेत्रा विकार में विधि 'ढारा किसी मी ऐसे दिषय के सक्ष्य में जो कि सधीय सूची मे न्यावालय ने परामणं देने से इन्कार नहीं किया और न ही किसी मामले ने जब भी इस प्रकार का परामणं राष्ट्रपति को दिया गया उसने उसना पालन ने किया है। विशेषकर विशिष्ट निर्माण ने सक्यों से सार्वेष्ट स्थानायन प्रमेष पारामणं प्रविधी हो। विशेषकर विशिष्ट से सार्वेष्ट स्थानिकर से सार्व्यम से अध्यवस्थानिका पर एक प्रकार का प्रकार है। विशेष की सार्वाच्या करते हैं। स्थानिकर हैं से सार्व्यम से अपूर्ण हैं। इसे की व्याप्या करते हैं हुए केरल फिला क्षित्री स्थानिकर हैं से की सार्वाच्या है, एक ऐसा विशेषक सबनी प्रकार भी हो सहता है, जो अवस्थारिका के समक्ष किसी विशेषक सबन में है। सत्रेष्ट में यदि कोई विशेषक सर्व्यमित होने की समावता है, एक ऐसा विशेषक सबनी प्रकार में विशेषक स्थानिकर है। स्थानिकर की स्थानिकर करते हैं। स्थानिकर है। स्थानिकर स्थानिकर स्थानिकर है। स्थानिकर स्थानिकर

यहाँ पर कितपय, ऐसे मामलो के उदाहरण लिये जा सकते हैं, जिनमें राप्टपनि ने सर्वोच्च न्यादालय की सलाह ली।

(क) १९२१ म राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को प्रत्यायोगित विषान के सक्त एक नामला प्रेरित किया। इस मामले मे सर्वोच्च न्यायालय की सक्त हो तीन प्रियंतियमां (देहती साज एक्ट १९६९, द प्रजनेर-मारवाण एक्ट १६४० तसा पार्ट सी० स्टेट्स लाज एक्ट १९४०) के वतियप प्रावधानों को वेषता निर्धारित करने के तिए मानी गई थी। श्यायालय नार्वानुति के कोई सक्ताह न दे सक्ता। वरन्तु विधिक न्यायाधोंनों हारा दी गई प्रत्यापीतित विधान सवयी साताह महत्त्वपूर्ण थी। बहुसत के प्रत्याद व्यवस्थापन को प्रावधान कवियों को प्रत्या-प्रतिक त्यायाधीत ति विधान सवयी साताह का निर्धारण स्वयंत्र करता है प्रौद व्यवस्थापित को व्यवस्थापन सवयी नीति का निर्धारण स्वयंत्र करता हो प्रीद व्यवस्थापित को व्यवस्थापन सवयी नीति का निर्धारण स्वयंत्र करता हो प्रीद प्रयादानी को व्यवस्थापन सवयी नीति का निर्धारण स्वयंत्र करता हो हो मायानाव को हत्सक्षेत्र करते का स्विवर्ग है। भै

(स) २ जिलन्बर १४२७ को, केरल नियान समा ने एक वियोवक (केरल राज्य किया वियोवक) वारित बर केरल राज्य के जिला वियोवक के लिए के स्वाचन निया । वियोवक के लिएया आवामाने द्वारा राज्य सरनार को, निजी वियावकों को प्राप्त नियाक में तेने का प्रतिकार दिया गया। पुँकि, नियोवक में सम्पत्ति के प्राप्त नियावकों को प्राप्त नियावकों के प्राप्त नियावकों के प्राप्त के प्रतिकार नियाव के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्तक यो। केरल वियाव तमा में, वियोवक में वेषणा राष्ट्रपति की सहमति प्राप्तक यो। केरल वियाव तमा में, वियोवक को वेषणा

१. द दिल्ली लाज एक्ट, १९१२, ए० झाई० झार० १९४१, ए० सी० ३३२।

के प्रक्रन पर वर्ड मतमेद पैदा हो गये। फ्लस्वरूप राष्ट्रपति से मागकी गई कि विधेयक पर प्रपत्ती स्वीष्टति न दे, वर्षोकि इसके पुछ प्रावयान, यह वहा गया, ग्रावैयानित थे।

राष्ट्रपति ने यह मामला, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श ने लिए मेजा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो परामर्श दिया वह इस प्रकार है।

१—मूल प्रधिवारों के क्षेत्र को निर्वाधित वरने के लिए न्यायालय राज्य नीति-निर्देशक तत्वों से प्रतमित्र रहकर निर्णय नहीं दे सकता है, परन्तु उसको दोनों (भूल प्रविवारों तथा राज्य नीति निर्देशक तत्वा के बीच) में सामजस्य स्थापित करने का प्रदल वरना चाहिये।

२--- प्रानुच्छेद ३०(१) मे उल्लिखित सरक्षण घामिन तया मापा सबधी घल्प सह्यको की सारी शिक्षा सस्यामो के लिए हैं। इसके श्रतिरिक्त, यह सरकण अनु-दान प्रान्त सस्यामो के लिए भी है।

३---- प्रतुच्छेद २०(१) मे प्रस्तर्गत प्रदत्त मूल प्रधिकार क्षेत्र का निर्धारण, शिक्षा सस्याके दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है। सविधान ऐसी शिक्षा सस्या मे पढाये जाने वाले विषयों के सवय मे कोई सीमा नहीं लगाता है।

४—वास्तव में धनुष्टेंद्र ३० (१) का उद्देश्य प्रत्य सख्यनों को, बहुसत्यनों से उनने सरक्षण ने लिए एक डाल प्रदान करना है न कि एक सलवार, जिसने बल से वे बहुसर्यकों से कुछ प्राया नर सकें।

- (न) १६५८ में मारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मित्रयों ने एक समम्भीता किया, जिसके फलस्वरूप भारत में पाकिस्तान को घपनी मूमि का कुछ हिस्सा दिया। ससद में तथा बाहर इस समम्भीते को तीब प्रालोचना हुई। राष्ट्रपति ने इस मामले को सर्वोड्च क्यायालय की सम्मति जानने के लिए मेजा। सर्वोड्च न्यायालय की सम्मति-प्रमुखार, भारतीय भू-माग को, निसी विदेशी राज्य को हस्तान्तरण के लिए सविधान में सभीधन करता धावश्यक है।
- (प) एक ग्रन्थ मामला जो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्थ के लिए सेना पया उत्तरप्रदेश की विधान समा एव न्यायपालिका के मध्य हुए सपर्य से सवधित है। समाजवादी दल ने एक नायंत्रती श्री केशवदेवसिंह को विधान समा के ग्रन्थ हुए हा ग्या, परन्तु अने केशवसिंह ने ऐसा नहीं निया। अतएव प्रध्यक्ष होंगे के केशवसिंह को हिरासत से लेकर विधान समा में प्राप्त होंगे केशवसिंह को हिरासत से लेकर विधान समा में प्राप्त होंगे केशवसिंह को विधान समा ने श्री केशवसिंह को साम में प्राप्त ने भारे परिवास समा ने श्री केशवसिंह को सात दिन के साधारण कारावास का दण्ड दिया। परन्तु उच्च न्याया-स्य के सलतक खण्ड ने श्री केशवसिंह को जमानत पर रिहा करते का श्रादेश

दिया। उत्तरपरेश विधान सना ने उच्च न्यायानय वे इस म्राहेस को प्रत्ये विषयारिकारों का उत्तरप माना। तरास्वात् विधान समाने सादेस दिया है जिन
न्यायानीनों ने भी वेचकिंदि से दिया कर प्रति दिया सा उनकी दिरास्त
में लेकर सदन के समस प्रस्तुत किया जाये। परन्तु न्यायामीमों के विच्छ को है
विधिष्ट मारीप नहीं लगान मते थे। उच्च न्यायामीमों के विच्छ को है
विधिष्ट मारीप नहीं लगान मते थे। उच्च न्यायामीमों के विच्छ को है
दिया। दिनान समा ने न्याय मूर्ति वेग यमा सहण को बार्मिनव होने से रोक
दिया। दिनान समा ने न्याय मूर्ति वेग यमा सहण के हिरासन में सेने समी
प्रष्माक से मारीय को सामित्र के विच्छा निष्म के विद्यान परित क्यारित
हिया। दियान समा ने न्याय मूर्ति वेग यमा सहण के विद्यानिय परित
हिया है उपदेश को सामित्र के विच्छा ने विद्यान के विद्यानिय के पहले वियमानुमार मदसर दिया जाये। इसने पत्रस्वक्ष्य इताहाबाद उच्च न्यायानिय के रहे
न्यायानीमा को सण्डति ने मारीय जारी निया कि विद्यानसमा हारा परित
प्रस्ताव के दियानस्व को रोक दिया जाये।

उत्तर प्रदेश दिवान समा तथा न्यायपालिका के मध्य संघर्ष के तीन महत्वपूर्ण महे थे।

र—न्यायपालिका तथा विषानसमा के अधिकार और शक्तियों का सवर्ष ।
 र—विवानसमा के अधिकार तथा शक्तियाँ ।

३—यदि सन्य किनी राज्य म इसी प्रकार का सधर्ष पैदा होना है तो उसकी दर करने के क्या उपाय हैं?

द्वराज्यान् श्री जयमुखनाल हायी (राज्यमश्री, मृह-मत्रानय, मारन सरकार) ने तोकसमा म घोषिन किया कि राष्ट्रपति ने उपर्युक्त भामते को, सर्वोच्य न्यायालय

नी सम्मति प्राप्त करने के लिए मेज दिया है। नितम्बर ३०, १६६४ नो मुख्य न्यायाधीज श्री गजेन्द्रगटकर ने सर्वोच्च न्याया-

लय की बहुमन द्वारा दी गई राय को निम्नलिखित रूप से घोषिन किया । १—उत्तरप्रका उच्च न्यायालय के लवनऊ खण्डपीठ को थ्री केमवीबह की

- उत्तरप्रदेश उच्च त्यायात्व के सत्तनक खण्डपाठ को था कशवासत का याचिका, जिसम उन्होंने विधान समा द्वारा उनको दिने गय दण्ड को चुनौनी दी, सुनने का पूर्ण प्रावकार था।

२—श्री सोनोमन को, यो केशवांतह की तरफ से उच्च न्यायालय को याविका देने का प्रधिकार या और श्री केशवांतह को, विद्यान समा के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय को प्रयोज करने का प्रधिकार था।

रे—उत्तरप्रदेश विधान सभा का दो न्यायाचीशी तथा श्री सोलीमन को धपने समझ पेश करवान का ग्राधिकार, विधान सभा के क्षेत्र में नहीं था। विधान सभा

को उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का कोई प्रधिकार नहीं या।

४—इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खण्डपीठ को दोनो न्यायाधीशी की याचिचा सुनने का तथा विद्यान समा प्रध्यक्ष द्वारा उनके विरुद्ध जारी विधे हुए वारट को स्थमित करने वा पूर्ण प्रधिकार था।

मुख्य न्यायाघीश ने इस विषय पर प्रिषक वल दिया कि यदि विधान समा के किसी न्यायाघीश के विरुद्ध वारट जोरी नरने के दावे को, मान्यता दी जाती है तो इसने परिणाम स्वरूप न्यायपातिका नी स्वतत्रता के मूल-सिद्धान्त नो गहुरा धक्का लोगा। अपुन्धेद्ध ३२ के यज्जन न्यायालयों की अपुन्धेद २२६ के अन्तर्यंत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के सवय में कोई अपनाद नहीं हैं। यह तर्क प्रस्तुत करना कि नासरित अपने मूल-अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय की खारण नहीं से सकता, न्यायं ही होगा। अतएव, उत्तर प्रदेश की विधान समा तथा न्यायपातिका के समर्थ के सवय से सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चय ही एक मूल विद्वान्त की महत्ता पर अपने परामणं द्वारा वल दिया है कि न्यायपातिका सरकार के अपने आपने कार्य अपने (व्यवस्थापिका समा तथा ना विद्वान को सहता पर अपने परामणं द्वारा वल दिया है कि न्यायपातिका सरकार के अपने अपने कार्य की कर संकंगी।

मूल श्रधिकारो के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

भारतीय सविधान के ब्रध्याय तीन मे मारत के नागरिको के सात मूल-प्रधि-कारो का उल्लेख है। धनुच्छेद ३२ के प्रनुसार सर्वोच्च न्यागालय को मूल-प्रधिकारो की रक्षा करने के लिए घादेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। यह रिट निम्नलिखित प्रकार की है:—

१—परमादेश (मेन्डेमस), २—बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेबियास कारपस),

३—प्रतिपेच (प्राहिबिंगन), ४—उत्प्रेषण (सर्राट्योरेरी) और १.—प्राधिकार पृच्छा (क्वो बारण्टो) वास्तव में प्रतुच्छेद ३२ हारा नागरिको के मूल प्रिपेकारों का प्रतिक्रमण होने की स्थिति में नागरिकों के लिए उपचार की ध्यवस्था की गई है। यदि किसी नागरिक के मूल धिषकार का हनन होता है तो यह सर्वोच्च न्यायालय की सहायता लें सक्ता है।

सविषान के अनुन्देद १३ के अनुनार कोई भी कानून यदि मूल अधिकारो का हनन करता है तो उसनो अवैध माना जायेगा। अतः यह स्पष्ट है कि अनुन्देद १३ तथा अनुन्देद २१ के अनुनार नागरिकों के मूल प्रधिकारों के सरकाण की दृष्टि से सर्वेच्च न्यायासय की विशेष भूमिका ऐसी स्थिति मे अय्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है, जब कि व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा कानून या कार्यपासिका ने ऐसा गादेश परित किया है जो मूल अधिकारों के अधिकारों के अधिकारों के अधिकारों के स्वीव किया है जो मूल अधिकारों के अधिकारों के स्वीव किया है जो मूल अधिकारों का अतिकारण करता है। ऐसे कानून या आदेश की अधिक धोषित करने की अस्तिम जिम्मेदारी सर्वोच्च स्थापालय की ही है। "रमेश वापर

बनाम मद्रास राज्य' मे सर्वोच्च ग्यायालय का यह भत या कि अनुज्वेद ३२ द्वारा नागरिको ने भूत प्रविकारो की रक्षा करने के लिए एक प्राव्यासित उपचार दिया गया है, और दस उपचार के प्रविकार को स्वय सविधान में एक भूत प्रविकार माना गया है। इस बरह यह ग्यायालय भूत प्रविकारों का सरक्षण तथा ग्राव्यालय है। भै

व्यावर्गारिक वृद्धि से बरि सर्वोच्च ग्यायालय का उपर्युक्त भूमिया का परीक्षण विद्या जाये, तो यह बात होगा कि सर्वोच्च ग्यायालय में प्रपत्ती चिक्तयो स्वुच्योग, नागरियो ने मूल भविकारों के सरका के लिए विद्या है। ग्योपालय कराय गर्या पुरुष्टिम से सर्वोच्च ग्यायालय में इस उद्देश्य से निवार कि पिरोध मिला में मां भूवरमा में सार्व प्रवास में सर्वोच्च ग्यायालय में इस उद्देश्य से निवार का पिरोध में प्रविध्या के लिए सर्वाच्च में सार्व्यक्त से सार्व्यक्त का प्रवास प्रिकारों में सुरुष्टा में तिए सर्वोच्च ग्यायालय में निर्वा की हिएसा के निवार सार्व्यक्त ग्यायालय में नागरिकों के मूल भविच्या में तिए सर्वाच्च में स्वयं मिला स्वयं में स्वयं मिला स्वयं में स्वयं मिला में स्वयं में स्वयं मिला में स्वरं में स्वयं मिला में स्वयं मिला में स्वरं में स्वयं मिला स्वरं में स्वयं में स्वरं मिला स्वरं में स्वरं में स्वरं मिला सार्वा में यह मिला सार्वा में स्वरं मिला स्वरं में सार्वा में स्वरं मिला सार्वा में स्वरं मिला सार्वा में यह माला सा कि मूल प्रविद्यारों में सार्वोच्च सार्वा से महा सार्वा में सार्वा स्वरं में सार्वाच्च सार्वाच्य सार्वच्य सार्वाच्य सार्वच्य सार्वाच्य सार्वच्य सार्वच्य

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरवलोकन की शक्ति

बस्तुत न्यायिक पुतरसतीकन वा स्राप्तिकार ही सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय सरियान के सन्तर्गत एक सन्तुतन चक की भूमिका प्रदान करता है। भारतीय सरियान के सदमें में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्राव्यक सन्तुतन सीन प्रकार के मामनी में स्थापित किया जा सकता है.—

१--- मन ध्रविकारो तथा राजसत्ता के सबधो म ।

२--सथ तथा राज्यों के सबधों से ।

३ — सरकार के तीन धगो के एक दूसरे के सबसो मे ।

प्रतः हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि न्यायिक पुनरवलोकन के सिद्धान्त का क्या प्रयं है ? श्री श्री बी, बसु के प्रनुसार—"पुनरवलोकन का टिक्शनरी श्रयं—किसी

१. रमेश यापर बनाम महास राज्य-ए. ब्राई. ब्राट. १६४० एस.सी. १३४।

कार्यं का पुन धवलोकन करना है, जिससे गलती दूर की जा सकें। इस शब्द का प्राथमिक कानूनी अर्थ एक उच्च न्यायालय द्वारा अन्य न्यायालयों की दण्ड की आजा या डिकी का पुन' धवलोकन करना है। "" आयों उनका ही क्यन है— "-यायिक पुनरवलोकन को अमरीका के कानून में एक और तवनीकी महत्य है, जो इन्लेण्ड में हम प्राया जाता है। यह दो कानूनों सायारण एक मूल कानून के सिद्धान्त से उत्तर होता है। जो हो यह मान लिया जाता है कि एक मूल कानून है जो राजनीतिक प्रचाली में सारी व्यवस्थापन सत्ता का आधार तथा अती है, कलस्वरूप यदि किसी भी साधारण विधि निर्माण सस्या का नार्य मूल कानून के आवशानों के विरुद्ध है, तो वह अर्थ यहां शा। और इस तरह के व्यवस्थापन मार्य को अर्थ वे पीपित करने के लिए किसी अग को अधिकार होना चाहिए। अमरीकी न्यायपालिका ने सामान्य सहमति से यह कठिन कार्य धारण कर लिया है। यह न्यायिक पुनरवलोकन का प्रायमिक वर्ष है और मुख्य न्यायाधी मार्थाल जो न्यायिक पुनरवलोकन के प्रवर्तक माने जाते हैं, में इसी अर्थ के प्रहण

'सार्वजनिक वानून में न्यायिक पुनरवलीकन केवल व्यवस्थापिका के कार्यों के पुनरवलीकन तक ही सीमित नहीं है। जब सिवधान को एव बार देश का सबोंच्य कानून मान लिया है और सरकार के सारे अगो की शक्तियों को इसके प्रावधानी द्वारा सीमित समक लिया गया है, परिणाम स्वरूप न केवल व्यवस्थापिका समा के किन्तु कार्यपालिका के वे सारे प्रशासकीय कार्य अवैध होगे जो सिवधान के प्रावधानी का उल्लंघन करते हैं और न्यायालयो द्वारा उनकी अवैध मानना होगा है'।

सक्षेत मे जैसा श्री इ एस कारबीन का कहना है, "स्यायिक पुनरवलोकन न्यायालयो की शक्ति है जो उनके साधारण क्षेत्राधिकार मे पाई जाती है जिससे वे व्यवस्थापिका के कार्यों की सबैधानिकता पर उनको लागू करने, या ऐसे (कानूनो) को जिनको वे श्रवंष पासे हैं, लागू करने से इनकार करने का निर्णय लेते हैं। "प

जब एक लिखित सर्विधान द्वारा सधीय व्यवस्था तथा नागरिको के मूल प्रधिकारों के लिए प्राविधान किया जाता है तो वास्तव में सर्विधान में उन धार्तों

१ डो० डो० बसु पूर्वोक्तः पुस्तक पृ०१४६ ।

२ वही प्र०१५६।

३ ई० एस० कारवीन-'ऐसे झान बुडिसियल' रिख्यु (इन द एनसायकसोपिडियाः माफ सोशल साइन्सेस, भाग--द पृ० ४४७) ।

८. वही पृ०४५७।

शो स्वाप्ति किया जाता है जिनके तिए एक सार्वोच्च न्यायालय प्रायस्त है स्वयस्त तथा नार्यारनो है मूल प्रीपनार दिसी भी वितिष्ठ मित्राय मित्राय है स्वयस्त तथा नार्यारनो है मूल प्रीपनार दिसी भी वितिष्ठ मित्राय नार्यारने हैं । यदि स्वय सित्रात में विशिष्ठ से यह तिला भी नहीं गया है कि सिव्यान देश से सार्वोच्च नार्या, है एक प्रतिस्तार के सात्र मात्र से सार्वाच्च नार्या, है एक प्रतिस्तार के सात्र मात्र से हैं। यदि स्वयस्त के सात्र मात्र के सात्र मात्र से सार्वाच्च सात्र मात्र है । यदि सार्वाच्च सात्र मात्र है । यदि सार्वाच्च नार्या स्वयं मात्र सार्वाच्च नार्या सार्वाच्च नार्या सार्या सार्वाच्च ने याव्य सार्या सार्या सार्या सार्या के वित्र होने से नियान के कान्य ना सार्य मात्र सार्वाच्च ने याविष्य नुपरस्तीका नी सर्वोच्च भी सार्या मार्या सार्वाच्च ने याविष्य नुपरस्तीका नी सर्वोच्च में स्वयं स्व

भारत के सबिपान में प्रमंपीनी सबिपान के निवरीन सविधान की सर्वोच्चना के जिए कोई विशेष्ट अप्यापन नहीं है, किन्तु चूंकि सप्याप्त तथा मून भिवनारी कि विद्यानों को भारतीय सविधान में स्वीहृत निया पात्रा है, और सविधान में स्वीहृत निया पात्रा है, और सविधान से संबोधन करने का सबस को एकाजिकार प्राप्त नहीं है, यह भिवाना सवाया में स्वीदान करने को सवस को पत्राप्त के सवस प्राप्त के स्वाप्त का प्राप्त के मध्य प्राप्त के स्वाप्त के स्वाप्त का सवस प्राप्त के स्वाप्त का सवस्य के स्वाप्त के सवस्य का सवस्य के स्वाप्त के सवस्य की जाते हैं, और प्रमुक्त के बाविधान स्वाप्त तथी कि स्वाप्त के सवस्य सवस्य का स्वाप्त के स्वाप्त के सवस्य सवस्य का स्वाप्त के स्वाप्त के सवस्य का सवस्य के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के सवस्य के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वप्

इसने मिनिस्ति सविचान में मान्यता प्राप्त निये मूल मिनिशा मी सरकार पर इस प्रतिवस्य के रूप में हैं, जिनते निवद निर्मित नानून को ज्यायमाणिता सबैस पीरित कर मतनी है। सम्पत्तिन में इसी मुद्दे ना सम्प्रीत्र एन तरते हुए, 'मास्वरी बनाम मेटीलत' प्रकरण में निर्मय देते हुए न्यायित पुरुतस्तीतन के

१. डी॰ डी॰ बसु॰—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ॰ १५७।

सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया । इस प्रकरण में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारवरी की, परमादेश जारी करन के लिए दी गई याचिका की घस्बीकृत कर दिया। जनवा तर्वे था वि मारवरी की परमादेश सवधी याचिका, जी १७८६ के न्यायपालिका अधिनियम पर आधारित थी, अमान्य थी क्यों कि १७८९ का व्यापानिका स्वितियम स्वय सर्वेद्य था । मार्शेल वा वयन था-"व्यवस्थापिका की शक्तियाँ परिमापित एव सीमित हैं और चूंकि इन सीमाओं के सबध में कोई गलती न हो या उनको मुला न दिया जाय ग्रत सविधान लिखित रखा गया है। यदि सीमाग्रो का उल्लंघन उन लोगो द्वारा होता है, जिनको रोकने के लिए इन सीमामो को रखा गया है तो उन सीमाधी को लिखित रूप देने का बया उद्देश्य है ? सविधान या तो एक उच्च मूल कानून है, जिसको साधारण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तिन नहीं विया जा सनता है या यह सावारण वानुनो ने स्तर का है ग्रीर ग्रन्थ नाननो ने समान परिवर्तनशील है, जब मी व्यवस्थापिका ऐसा परि-वर्तन बरना चाहती है। यदि पहला विकल्प सत्य है तो एक बानुन जो सविधान के विरुद्ध है, कानून नहीं है। परन्तु यदि दूसरा विकल्प सत्य है तो लिखित सविधान उन लोगों ने मुखंतापूर्ण प्रयत्न है जिनके द्वारा निसी मक्ति को जो स्वरूप में ग्रसीमित है सीमित विया जाता है।"1

न्यायिक पूनरवलोक्त के श्रीयकार का श्रीचित्य बतलाते हुए, मुख्य स्थाया-धीश मार्गत ने तर्च प्रस्तुत किया या नि जहाँ वही भी लिखित सविधान है, और ऐसे सिवधान द्वारा सीमित शन्तियों की सरकारें तथा व्यवस्थापिकाए स्थापित की गई है, जैसी एव सघ राज्य मे होती हैं, और यदि सविवान मे उपयोग मे लाई मापा ऐसी है, जिसके अनुसार निर्धारित सीमाग्रो को लागू करना ग्रति-मावश्यव है, तो समक्ता चाहिये कि न्यायालयों को यह मादेश प्राप्त है कि इन निर्धारित सीमाग्री को लागू करें और त्यायाधीश सविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए ग्रपनी प्रतिज्ञानुसार विधित है, जो देश ने 'कातून की सर्वोच्चता' का प्रथम तत्व है।^२

ग्रमरीकी सविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरवलोकन के ग्रीध-नार ना विभिन्द रूप से नहीं उत्तेल नहीं है, परन्तु मुख्य न्यायाधीय मार्पल द्वारा दिये गये 'मार्परी वनाम मेडीसन' प्रनरण में निलंध के श्रृतुसार सर्वोज्य न्यायालय को न्यायिन पुनरवलीनन का प्रियक्तर प्राप्त हुखा है। इस मक्ति के श्रृतुसार

१ जे० मार्शस का उद्धहरण- जे ब्राइस द्वारा, द श्रमरीकन कामनवेल्य 4 \$464 go 288 I

२. एस० सी० डेस, 'दी इण्डियन बानस्टीट्युसन' १६६०, पृ० ३३६ । ŧ٥

सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून, या धन्य प्रियकारी द्वारा दिये प्रादेश या दिकी का, जिनको धनरीकी सर्विधान के विरुद्ध बतलाया गया है, पुनरवलोकन करने का अधिकार है।

"एक दिरान् प्रदेव की एक कहानी है, जिसने यह सुनकर कि सर्वोच्च त्यास्त्र को स्थापना, सर्विधान के सरक्षण भीर हुर बनुत के प्रवेध पोधित करते हुंच भी रहें भे, बेट सर्वोच्य के सरक्षण भीर कर प्रवेश पोधित करते हुंच भी रहें भे, बेट सर्वोच्य के सरक्षण भीर कर प्रवेश ने जिन को उदे आहा है, इंटें में विता दिये। कोई प्रास्थ ने ही कि वह उन्हें सोज नहीं कहा, क्यों कि सर्विध्य में इस विषय पर एक कर भी मुद्दें है।" वर्ष्ट्र प्रमरीका में मार्थित के सर्विध्य मार्य कर पर प्रकार के स्थापकार के प्रमान में स्वाचित्र मार्था के स्वच्य मार्थ के प्रमान के स्वच्य महत्व मार्थ मार्थ है। वा अपने स्वच्य के स्वच्य

मारत म सर्वोच्च न्यायालय पुतरवतोकन के प्रविकार का प्राचार प्रमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में, सवियान में श्रविक दृढ रूप से है, विशेषकर सर्वियान के दो प्रावयानों में यह आधार निहित है।

सर्वेत्रयम, मूल मीकारों नी दृष्टि से मृत्युद्ध १३ के मृतुसार यदि किसी कानूद दारा किसी दूल मिथार का उल्लंखन होता है तो उस कानून को मर्बंध मीधित किया जा सरवा है । सविष्यान के मृत्युद्ध १२ के मन्तर्गत प्रमें मूल मीबकारों का उल्लंधन होने पर बोई भी नागरिक सर्वेषानिक उपचार मान्य करते के किए सर्वोच्च व्यायालय की करण से सनता है। प्रत्युक्त सर्वोच्च व्याया-त्वा किसी भी कानून या सारेक ना पुत्रवत्तीकन, सर्विष्यान की व्यावसा करते हुए मूल मीबवारों के सरक्षण के लिए कर सनदा है।

२. जे॰ ब्राइस-पूर्वोक्त पुस्तक, पृ॰ २५१-५२।

३. वही

पृ० २७२-६३।

द्वितीय, प्रनुच्छेद २५४ के ब्रनुसार भारतीय सपीय व्यवस्था मे शक्ति विमाजन प्रणाली के अन्तर्गत सघ तथा राज्यों के क्षेत्राधिकार के निर्घारण के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को, जो विसी राज्य द्वारा प्रपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्मित किया गया है, ग्रवैष घोषित कर सकता है। ग्रनुच्छेद २४४ मे यह प्रावधान किया गया है कि समवर्ती सूची मे उल्लिखित किसी विषय पर यदि किसी राज्य विधान समा द्वारा निर्मित नानुन सघ ससद द्वारा निसी कानुन से सघर्ष मे है, ऐसी स्थिति मे राज्य कातून को अवैध माना जायेगा । अतएव, यह स्पष्ट है कि मारत में सर्वोच्च न्यायालय को सर्विधान के अन्तर्गत किसी भी विधि या नियम या ग्रादेश का पुनरवलोकन करने का श्रधिकार है, जिससे यह निर्घारित विया जा सके कि वह विधि या नियम या भादेश सविधान के भनुसार है या नहीं है। इसी मुद्दे पर बल देते हुए मुख्य न्यायाधीश भातजलि शास्त्री ने 'महास राज्य बनाम रीव' नामक प्रकरण में कहा- 'हम सोचते हैं कि यह उचित है कि यहाँ यह बतलाया जाये, जिस पर कभी च्यात नहीं दिया जाता है, कि हमारे सविधान में विधि के सविधान के अनुकूल होने के प्रश्न के लिए, न्यायिक पुनरवलीकन के लिए अमरीका के विपरीत जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्थापिका के नार्यों के पुनरवलोकन करने के लिए विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त कर ली है, विशिष्ट प्रावधान हैं।" सक्षेप मे, न्यायिक पुनरवलोकन का अधिवार साधारणतया, प्रत्येक राज्य मे सर्वोच्च न्यायालय को लिखित सविधान की सर्वोच्चता के सरक्षण के लिए प्राप्त होता है। श्री बसु का कहना सत्य है कि "जैसे मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने ग्रमरीकी सविधान के लिए कहा है, हमारे सिवधान द्वारा भी इस सिद्धान्त को जो कि सारे लिखित सिवधानों के लिए आवश्यक है, स्थापित तथा दृढ किया जाता है कि नोई मी नानून जो सिवधान के विरुद्ध है, सबैध है।"?

धतएव, मारत के सविधान की सर्वोच्चता के तीन कारण हैं, जो निम्मलिखित हैं १---सविधान में, सधवाद के सिद्धान्त की, प्रमुब्देद २४६-२६३ के प्रत्यांत सान्यता प्रदत्त कर सथ तथा राज्यों के लिए पृषक क्षेताधिकार निर्धारित करता।

२—सविधान के झप्याय तीन में नागरिकों के मूल भ्राधिकारों को मान्यता देना और मुल्क्ट्रेट १३ के आधार पर इस बात पर बन देना कि यदि कोई कानून भूत प्रविकारों से कभी करता है था भूल अधिकार समाप्त करता है, तो बहु मर्थिक होंगे।

१ पी० शास्त्री—मद्राप्त राज्यधनाम रोव, १९४२, एस० सी० धार० ५६ । २ डो० डो० बसु—पूर्वोक्त पुस्तक पु० १५६ ।

३—सिव्यान द्वारा ससद को सिविधान-संबोधन का एक प्रिषकार न देते हुए, सतद् तथा राज्य विधान सम्राम्नो को यह प्रिषकार देना (उन विधयो पर जो, दोनो सच तथा राज्यों के विए महत्वपुण हैं)।

इन कारणो द्वारा प्राप्त मारतीय सविधान की सर्वोज्यता को स्थिर रखने के लिए सर्वोज्य न्यायालय को न्यायिक पुनरवलोकन का प्रधिकार स्वतः प्राप्त

हमा है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरवलोकन के अधिकार पर सर्विधान द्वारा स्वापित सीमा के दो पहलू हैं। सर्वप्रयम, सरकार के तीन भगो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका भ्रोर न्यायपालिका के सबयो तथा सम तमा राज्यों ने सबयो की दिष्टि से, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरवलोकन की शक्ति का क्षेत्र, संविधान में इन विषयों पर विस्तृत प्रावधान तथा स्पष्टीकरण होने से सीमित है। भारत के संविधान में न सिर्फ सरकार के तीन अभी के समठन कार्यों तथा शक्तियों का निस्तृत उस्तेल है, निन्तु सभ तथा राज्यों के मध्य तीन मुणियों हारा निस्तृत क्य से सेवाधिकार का उस्तेल किया गया है। प्रमारीका के समियान में इस तरह संज्ञायिकार का विस्तृत उस्तेल नहीं है, कैवल १= विययों पर सम सरकार को प्रमारकार मार्थ है, जबति जैया समितार राज्यों को प्रस्त हैं। इस कारण अगरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने सविधान की व्याख्या करते हुए निहित शक्तियों के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके सब सरकार को ऐसी शक्तियों पर श्रविकार प्रदत्त किया है जो इन १० शक्तियों में तो निहित हैं परन्तु सविधान में उनका स्पष्ट उल्लेख नही है। सविधान नो विस्तृत रूप से ध्याख्या करने का ग्रविकार ग्रमरीकी सर्वोच्च म्यायालय का एक महत्वपूर्ण भविकार है। ग्रमरीकी सर्वोच्च न्यायालय भवने 'बौद्धिक मापदण्ड' से सर्विधान की विस्तृत व्याख्या कर सकता है। मारतीय न्यायपालिका को सविधान की व्याख्या करने के लिए अपनी नीति की उपयोग में लाने का ऐसा कोई भविकार नहीं है। चूंकि दोनो (सभीय तथा राज्य) ध्यव स्यापिका समायो ने क्षेत्राधिकारों का स्पष्ट एव विस्तृत रूप से, साथ ही एक विस्तृत क्षेत्र पर समवर्ती अधिकारो का उल्लेख किया गया है, और अविशिष्ट शक्तियाँ सथ ससद मे निहित की गई हैं, धत, सर्थोंच्य न्यायालय के क्षेत्राधिकारी को पृथक करने वाली रेखा मे परिवर्तन करने का कोई स्रविक स्रविकार नहीं है। "भारत मे, एक निहित शक्तियों के सिद्धान्त के प्रतिपादन करने का प्रधिकार श्रत्यन्त सीमित है, क्योंकि एक विषय की विस्तृत व्याख्या करने से किसी विषय से ग्रन्थ स्यान पर सथपं हो सनता है। प्रतएव न्यायपालिका की बौदिक कसरत को सविवान द्वारा निर्वारित सीमाझा भ ही दिल्लाना चाहिये। मारत म विधि का न्यासिक पुनरवलोकन धनुक्छेद २४६, जिसके झनुसार धपने क्षेत्र में प्रत्येक व्यय-स्थापिका समा सार्वमीम है, के धन्तगैत ही किया जा सकता है।"

भूमरीका मे सविधान वा सामान्यता के ग्रतिरिक्त, वैधिक प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस ग्राफ ला) के उपवन्य को ग्रपनाने के कारण, सर्वोच्न न्यायालय को सविवान की विस्तत व्यार्या करने का ग्रविकार प्राप्त है। प्रमरीकी सविधान म सारे विषयी पर सारत के सविधान के बिपरीत, विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप ग्रमरीकी सर्वोच्च न्यायालय को, श्रपते 'वौद्धिक मापदण्ड' का उपयोग ब रते हुए सविधान की व्याख्या एव स्पष्टीकरण करने का श्रधिकार प्राप्त हमा है। मतएव म्रमरीनी सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रमरीनी समाज की बदलती हुई सामाजिक, राजनीतिक एव श्राधिक परिस्थितियों के अनुसार, सविधान की व्याल्या 'वैधिक प्रक्रिया' (इयु प्रोसेस धाक ला) के आधार पर की है। परन्तु भारत का संविधान एक विस्तार पूर्वक लिखा सविधान है, जिसकी व्याख्या करते समग्र सर्वोच्च न्यायालय ग्रपने बौद्धिक मापदण्ड का उपयोग ग्रत्यन्त ही सीमित रूप से कर सकता है। "हमने न्यायिक पुनरवलोकन की स्थापना की है, तथा उसको मान्यता देते रहगे क्योंकि एक साधन के रूप में इसके द्वारा उस मूल उद्देश्य की प्राप्ति ही सके, जिसका समर्थन मूरव न्यायायीश मार्शल ने किया था. ग्रयात सता पर मूल कानन (सविधान) द्वारा सीमाग्रो को लागु करना, परन्त इस सीमा से बाहर जाकर हम, एक न्यायिक महामानव की राजनीतिक के स्यान पर स्वापित करने नो तैयार नहीं हैं, न्योंकि जैसा न्यायमूर्ति जेकसन ने कहा है कि, न्यायिक अपहरण अन्य अपहरण की तरह देश के लिए एक स्थाई अच्छाई सिद्ध नहीं हो सकता है। दे

भारतीय सविधान एक विस्तार पूर्वेक लिखित सविधान है। सविधान स्वय जनता की जीवित वाकी है, जिसकी भनिक्यक्ति करना सरकार के तीनो अयों वो विध्य जिम्मेदारी है। "अत्युक्त भ्रमरीका के विष्परित सर्वोक्त्व न्याधालय को सविधान की जीवित वाणी माना गया है, भारत में क्यस सविधान, किसी भी समय पर, प्रपनी प्रमिव्यक्ति करने में समयं है। नि सदेह न्याधामीश्रो को सविधान की वर्तमान स्थिति भृतुसार व्याख्या करना है, परन्तु यदि न्यासाधीश सलती करते हैं या जनता के हितों के विरुद्ध निर्णय देते हैं, तो यह जनता के प्रतिनिधियो

१. एस० सी० डेश-पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ३४५।

२. डो० डो० बसु—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १४५।

है, ग्रर्थात् (क) सर्वावत कानून ब्यवस्थापिका के क्षेत्र में है या नहीं है, ग्रीर (ख) वैधिक प्रक्रिया की सारी ग्रावस्यकताग्री को पूरा करता है या नही। व्यवस्यापिका द्वारा निर्मित बानून उसके क्षेत्राधिकार में हो सकता है, परन्तु यदि वह 'वैधिक' प्रक्रिया' के विरुद्ध है अर्थात् मान्यता प्राप्त प्राकृतिक कानून के सिद्धान्त के विरुद्ध है तो ग्रमरीनी स्यायालय उसे ग्रवैष घोषित करता है। मारतीय सविषान मे 'वैधिव' प्रक्रिया' उपवन्य की बजाय 'विधि सम्पन्न प्रत्निया' का है। यह मूल ग्रन्तर है और इसके द्वारा मारतीय सर्वोच्च न्यायालय को 'प्राकृतिक नानून' प्रयात-किसी विधि मे अन्तर्निहित अच्छाइयो-बुराइयो के अनुसार उसकी वैधानिकता निर्धारित करने की कसौटी को लागू करने से रोकता है।" यदि मारतीय ससदया किसी राज्य विद्यान समा द्वारा विदि का निर्माण अपने क्षेत्र मे किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी विधि को मान्यता देना होगा, क्योंकि मारतीय सर्वोच्च न्यायालय को किसी विधि का पुनरवलोकन इसलिए नहीं करना है कि उक्त विधि के ग्रीचित्य को उसकी ग्रन्तिनिहत ग्रन्छाई या बुराई के श्राघार पर निर्धारित कर सके, बत्ति इसलिए करना है कि यह निर्धारित किया जा सके कि उक्त विधि सवि-धान के अनुकृत है या नहीं, । सक्षेप में यह कहना उचित होगा कि अमरीकी न्यायालय ने विपरीत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय 'प्राकृतिक कानून' प्रयौत् 'वैधिक प्रक्रिया' की कसौटी का उपयोग न कर केवल सविधान को ही किसी विधि की वैधता निर्धारित करने के लिए कसौटी मानकर अपने निर्णय देगा।

प्रमरीका म, जैता देखा जा चुका है, 'वैधिन प्रक्रिया' के सिद्धान्त के प्रमुक्षार सर्वोच्च नपायान्त पपने 'विद्विक मायदण्ड' ना स्वतन्तापूर्वक उपयोग करता है। यद्यि वहां 'वैधिक प्रत्रिया' को परिमाधित नहीं विद्या गया है, इसके विभिन्न सर्वाधित प्रषे सम्पट हैं।

सामान्यत 'विधिव प्रत्रिया' वा तास्यव वैधानिकता, तकंतूर्णता, तथा निप्पक्षता से है धर्यत् जो निर्दुच, ध्रताकित तथा पक्षपातपूर्ण नही है। प्रत्येक मामले मे समरीवा में न्यायाधीय ही धर्मित रूप से निर्धारित करते हैं कि क्या कोई विधि, नियम, या धादेश, निरकुत धर्मिव या सावायात्र्य तो नहीं है। इसके पलस्व-रूप प्रमारीवा में 'न्यायपात्रिवा, की सर्वोच्चता के सिद्धान्त की उत्पत्ति होती है धीर सविधान वा धर्म न्यायाधीयों की न्याक्या पर निर्मंद हो जाता है। सारत में न्यायपात्रिवा के सर्वोच्चता के स्वाच्या पर स्वाप्त की सर्वोच्चता पर यायायात्रिवा के सर्वोच्चता पर यायायात्रिवा की सर्वोच्च न्यायायात्र्य की प्रमारी प्रतापत्ति स्वाप्त की सर्वोच्च न्यायात्र्य के स्वाप्त वीदिक मापदण्य वी प्रपिक उपयोग में साने की समावना नहीं है।

१. एम० पी० शर्मा—'पूर्वोक्त पुस्तक' पृ० २२१ ।

सक्षेप में, भारत के सविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के सीमित न्यायिक पूनरवलोकन के अधिकार के कारण निम्नलिखित हैं

१—सिविधान का विस्तारपूर्वक लिला होना, विशेषकर संघ तथा राज्य के मध्य शक्ति विभाजन का तीन सूचियो द्वारा प्रत्यन्त विस्तृत रूप से उल्लिखित होना।

२—सविचान के संशोधन प्रणाली के मनुवार सबद तवा राज्यविचान समाप्तें में सदिवान के स्वव्य को प्रतिम इन से नियारित करते की मासि होना ! मनुद्रें ध्यान ने रवना जिस्त है कि प्रमारीन के विचरीत, मारतीय समोप्त प्रयाली तारत है। प्रत्यूव मारत में सर्वोच्च प्रमालन द्वारा दिये गये निर्णय प्राचली तारत है। प्रत्यूव मारत में सर्वोच्च प्रमालन द्वारा दिये गये निर्णय सिवान के सवध में, विवेचकर, संविधान का समोपन कर पनटे जा सबते हैं। प्रमारीना में सविधान के समोपन की जिटल प्रक्रिया होने से यह प्रस्मात निर्णत है।

२—मारतीय सर्वांच्य न्यायालय वेचल विधि सम्यान प्रविधा के जपुतार ही । गंद प्रश्नुतार विधि की क्योटी को जपायों में सांगे के निष्य स्वतंत्र महित सकता है। गंद प्रश्नुतिक विधि को विधायों में सांगे के निष्य स्वतंत्र माराविक विधि या विधिक प्रविच निष्य या विधिक प्रविच निष्य या विधिक प्रविच निष्य या विधिक प्रविच के सांविक के सांगे एक महत्वपूर्ण भूतिका प्राप्त है, यही पर हम तात पर प्रकाश दालना तथा वत येता स्वामाणिक है कि सरकार के प्रयास सां से सपने को स्वतंत्र रहत हो यह सांविक स्वतंत्र पहुंची सर्वों को स्वतंत्र रहते हैं। एक जनतानिक सर्विचान की यह मृत प्रवस्तवत्ता है कि सामाणित स्वतंत्र सुर्वे स्वतंत्र कर स्वतंत्र है। एक जनतानिक सर्विचान की यह मृत प्रवस्तवत्ता है कि सामाणित स्वतंत्र सुर्वे के सर्वे कर सर्वे निष्य स्वतंत्र स्वतंत्र के स्वतंत्र कर स्वतंत्र के स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र के सर्वे कर सर्वे । माराविक सर्वों के स्वतंत्र के सर्वे कर सर्वे ने का प्रविचार ने का प्य

सर्वप्रयम्, बारतीय सथीय व्यवस्था के धन्तर्गत सर्वोच्च न्यायासय को सविधात द्वारा स्थापित विधिन सरकारा के क्षेत्राधिकारों की रक्षा करना है। इस सबसे में, सम सरकार एवं किसी राज्य सरकार या सरकारों में मत्तर्भेद होने पर सर्वोच्च न्यायासय को इन दोनों पक्षों के लिए निष्यक्षता पूर्वक निर्णय देना होगा।

डितीए, वर्षोच्च न्यासावव को नामरिकों के मूल प्रविकारों के सबय में भी विवाद की स्थिति में, निर्मय देने का संविकार है। वास्तव में मूल संविकार के लिए सविवान में यह प्रावधान बहुतत के निरकुत ज्यवहार पर एक निरन्तर सबरोध के रूप में है। सत्युव एक वनतानिक राज्य में को बहुतत पर सायारित है, सर्विकार में दूस सर्विकार, सरमास्थकों में लिए बहुतत की निरकुतता के निरद एक ठोस सामहासत है। भूतें में बह देता जा चुना है नि जहां तन न्यायाधीमों भी नियुक्ति, सेवा भी सतीं तथा पदच्युति पा प्रथम है, मारतीय सविधान द्वारा, उपर्युक्त मामकी भी दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय भी स्वतंत्रता बनाये रतने के तिए पर्याप्त प्रावधान निये गये हैं। न्यायपूर्ति सन्नू का कहता था—"यह देतना मिन्न है कि सविधान निर्मात निस्त तरह से, न्यायाधीशों भी स्वतंत्रता ने विषय में मुछ श्रीर श्रीयम

श्रत. यह स्पष्ट है कि 'सर्वोच्च न्यायालय' द्वारा, श्रपने न्यायिच पुनरवलीरन के प्रियिनार का उपयोग, जिससे व्यवस्थायिना एव कार्यपालिका के प्रवीप नार्यो पर प्रमाववाली रोच लगाई जा सके, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतनता पर निर्भर है। मारत के सार्वेजनिव जीवन में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतनता वा महत्व तीन प्रीर निम्नलितित कारणी से प्रत्योघन हो जाता है।

- (१) एक सुविकसित, समठित तथा प्रमायशाली जनमत का न होना ।
- (२) ससद में कार्यपालिका का, जो एक राजनीतिक दल द्वारा निर्मित की गई है, ब्रति शक्तिशाली होना ! ग्रीर,
 - (३) ससद मे एक संगठित तथा प्रभावशाली प्रतिपक्षी दल का न होना।

परन्तु सविधान ने लागू होने के परचात् ग्यायपालिकाग्नो ना स्वतन्नता पर सबसे गर्मीर प्रतिवरणक्ष प्रप्रस्वाहर से त्यायाधीयों के नार्यवाल ग्रीर सेवा निनृत्त होने के परचात् उननो नार्यपालिका द्वारा दिये गये लाम के रूप मे हैं। 'पृर्धे भी त्यायाधीयां है, जिनकी राजनीतिवर महत्वावाखारों है। सविधान मे वोई प्रावधान नहीं है, जिससे त्यायधीयों को चित्रों ऐसे पद के लिए उम्मीद करने से रोजन सा सचता है जो नार्यपालिका नी नियुक्ति के प्रावधान के ग्रन्तर्यत है।'' ऐसे कई उत्तहरण है जहां न्यायाधीयों को सेवा-निनृत्त होने के पत्रचात् नार्यपालिका हारा महत्वपूर्ण पदो पर नियुक्त निया गया। उदाहरण स्वस्त्र सेवा-निनृत्त होने के पत्रचात् नार्यपालिका हारा महत्वपूर्ण पदो पर नियुक्त निया गया। उदाहरण स्वस्त्र सेवा-निनृत्त होने के पत्रचात् भी सीठ सीठ विश्वचात् को पहले अहरसदयनो ने मामलो का सभी और वाद में विधि मंत्री नियुक्त क्या गया। शी सैयद फललकाली ने जड़िता का राज्यपाल हर्श्यर में नियुक्त किया गया। शी सैयद फललकाली ने जड़िता का राज्यपाल हर्श्यर में नियुक्त किया गया। शी सैयद फललकाली नत उद्योग हर्श्यर में नियुक्त किया गया। शी सैयद फललकाली नत उद्योग हर्श्य में त्याया स्वार्थ स्वर्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार

१.पो० एन० समू—जनरल श्राफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, श्रवटू० १६४८, पु० ६७।

२. कें व्यो राव-'पार्लियामेस्टरी डेमोक्रेसी इन इण्डिया', १६६१ पृ०-

भारतीय शामन धीर राजनीति २६६

श्रौर प्रकार के कार्यों को ग्रयन हाथों में नहीं ले सकेंगे।

कार्यपालिका के इस अप्रत्यक्ष श्रतिक्रमण से न्यायापालिका की स्वतत्रता की रक्षा ब'रने के लिए, सर्विधान में विशिष्ट रूप से यह प्रादेधान जोड़ा जाना चाहिये कि सेवारत तथा सेवा-निवृत न्यायाधीश, न्यायिक नायों के श्रलावा किसी

छागला को १९५८ म समरीका म भारत का राजदूत और तत्पश्वात् शिक्षा

मत्री नियुक्त किया गया।

राज्य-सरकार

मारत एक सप राज्य है। मारतीय सविधान के धन्तर्गत दो प्रकार की सरकारों के लिए प्रावधान किया गया है. १—सप (केन्द्रीय) सरकार तथा २—राज्यों की सरकार। सविधान को २६ जनवरी १९४० को लागू किया गया, उस समय से १९४६ में राज्य पुनर्गठन प्रियित्यम पारित होने तक, भारत में सच की इकाइयों (राज्यों) को पार शिष्यों में रखा गया या —

(क)—दस श्रेणी मे उन राज्यों को रखा गया था, जिनको ब्रिटिश राज्य ने दौरान ब्रिटिश-मारतीय-प्रान्तों के नाम से पुकारा जाता था। प्रत्येक ब्रिटिश-मारतीय प्रान्त का सासन एक गवनेर के अधीन होता था। इन राज्यों के नाम इस प्रकार के —उत्तरप्रदेश, महास, बस्बई, बिहार, मध्यप्रदेश, उडीसा, पजाब, तथा असम। इन राज्यों को 'क' भाग के राज्यों के नाम से पुकारा जाता था। इस्ट शे माया के आधार पर एक नये राज्य का निर्माण हुआ, जिसका आग्नर प्रदेश नाम विया गया सविधान के अन्तर्गत हन राज्यों का सध्यक्ष पवनेर होता है।

(क)—िद्वितीय, श्रेणी मे वे राज्य रक्षे गये थे, जिनका निर्माण देशी रियासती के भ्राघार पर हुमा या । इन राज्यों के नाम इस प्रकार थे —हैदराबाद, मैसूर, राजस्यान, सौराष्ट्र, मध्य भारत, पेस्सु, ट्रावनकोर-कोचीन श्रीर जम्मू-काश्मीर । इन राज्यों का माग 'ख' के राज्यों का नाम दिया गया या । इन राज्यों के

ध्यथ्य राजप्रमुख कहलाते थे।

(ग)—कतियय छोटे राज्यो को, या जिनको पूर्व में चीक कमिक्नर द्वारा प्रधा-चित किया जाता था, भाग 'ग' के राज्यो की सजा दी गई। इन राज्यो के नाम इस प्रकार ये —दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, कच्छ, भोषाल, हिमाचल-प्रदेश, मणीपुर त्रिपुरा, कच-विहार, और विद्या-प्रदेश।

(प)—इस श्रेणों म सण्डमान तथा निकोबार द्वीपों को रखा गया। केवल एक साधारण निम्नता को छोडकर, माग 'क' एव 'स' के राज्यों की सरकारों का सगठन एक समान था। माग 'क' के राज्यों के अध्यक्षों को राज्यपाल (गवर्नर) की सजा रो गई थी, जब कि माग 'ख' के राज्यों का प्रध्यक्ष राजप्रमुख कहनावा ची रोगे इस प्रकार के राज्यों में ससदीय सरकार को स्थापना की गई थी। स्रतः दोनो प्रकार के प्रध्यक्ष नाम मात्र के प्रधान थे, बाह्यविक नार्यपालिना मंत्रीमण्डल के रूप में ही थी जिसना प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व राज्य विद्यात समा के प्रति होता था।

नाग भा के राज्यों के सासन का सामित्य सारतीय राष्ट्रपति पर या, जो अपने मितिनिय जपराव्यक्तास (किन्दिनिंद प्रवर्गर) या मुख्य साहुल (क्षीफ कामीकर) की सहायता है , दा राज्यों में विधान समा तथा मंत्री मण्डल की । स्थापना कर सम्बद्धा था, परन्तु इन विधान समा तथा मंत्री मण्डल की । सायन वा प्रक्रियों माग के एवं खंके राज्यों से मित्र में । सस्य को इच्छानुसार पाग भा ने प्रवर्ण की विधान समाम का सम्याव्यक्त स्थापन किया निवाद मा समीन्यन हारा किया जाता था। या कुछ सदस्य निर्माण का मान्या की स्थापन समाम कर स्थापन पराव्यक्त स्थापन एक स्थापन स्थापन स्थापन एक स्थापन स्थापन स्थापन एक स्थापन स्थापन स्थापन एक स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

१९५६ में राज्य-पुनर्गठन धायोग के पुश्तावपर, मारत सप के राज्यों का पुनर्गठन राज्य पुनर्गगठन प्रिविचम १९५६ झरा एक नये झाबार पर किया गया। राज्यों के 'क' 'ख' 'प' एव 'प' श्रेणियों में वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन प्रिविचम १९५६ के सुश्लाव के प्रमुखार राज्यों को श्रव केवल यो श्रेणियों में रखा। ये जिन्म श्रेणियों हैं—

१ — सघ के राज्य तथा २ — सधीय म-भाग।

१—सप के राज्यों के नाम इस प्रकार ये—बान्धप्रदेश, ध्रसम, विहार, सम्बद्ध, नेरल, मध्यप्रदेश, महास, मैसूर, उडीसा, पजाय, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिमीवगाल, तथा जन्म ग्रीर कश्मीर।

२—सधीय भू भागो के नाम इन प्रकार थे-दिल्ली, हिमाचल प्रदेश मणीपुर, त्रिपुरा, मण्डमान लक्कावीब एव मिनिकाय द्वीप ।

१६५६ में राज्यों के पुनगंठन के बाद मी, कतिपय नये राज्यों की स्थापना की गई जो इस प्रकार है

१---१६६० में बम्बई राज्य को विमाजित करके, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य की स्वापना की गई।

२--१८६२ मे नागालैण्ड राज्य की स्थापना की गई।

३—१८६६ मे पजाब राज्य को विभाजित करके पजाब तथा हरियाणा राज्यो की स्थापना की गई।

४—१६७१ मे झसम राज्य के कतिपय पहाडी क्षेत्रो को मिलाकर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। ५---१६७१ में मणिपुर तथा त्रिपुरा वो सघ वे राज्यों के रूप म मान्यता की गर्दे।

द्सी प्रकार १९५६ के बाद सधीय क्षेत्रों की सख्याम मी वृद्धि हुई, जो इस प्रकार है।

१--१९६२ मे गोबा, डमन् तथा ड्यू को सघीय क्षेत्र बनाया गया ।

२—१६६३ मे पाण्डुचेरी को संघीय क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया।

३—१९६६ म चल्डीगढ को सचीय क्षेत्र बनाया गया। परन्तु १९७० म चण्डी-वाढ को पत्राव में मिला दिया गया।

४ — १६७२ म घ्ररणाचल (नेफा) तथा मिजोराम को समीय क्षेत्र बनाया गया है।

राज्य कार्यपालिका

सधीय कार्यवालिका के समान, राज्यों की कार्यपालिका का भी स्वरूप ससदा-रमक है। राज्य-कार्यपालिका के दो मान है। (क) राज्यपाल-जो कि राज्य नार्यपालिका का नाममान प्रधान है। (ख) मत्रीमण्डल-जिसको वास्तविक कार्य-पालिका के समान माना जा सकता है क्योंकि राज्य-सरकार की नीतियो तथा कार्यों के लिए, सविवान के मनुमार मनीमण्डल राज्य विधान सभा के प्रति उत्तर दांगी है।

राज्यपाल

सघ के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रिमार सविधान के अनुक्षेद्र १४४ के प्रत्यंत उप्लिखित है। राज्य-पाल का वार्षकाल पाँच वर्ष का होता है। किन्तु औपचारिक दृष्टि से राज्यपाल अपने पद राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यंत विध्यान रहेगा, प्रयांत् राज्यपाल को राष्ट्रपति हारा कमी भी पदच्युत किया जा सकता है। अमरीकी पढित स सय तथा राज्यों रोनो म अध्यक्षाराक प्रणाल के लागू होने के फलस्वरूप अमरीकी सथ के राज्यों के राज्यपाल नामान के नहीं, परन्तु वास्तविक शासक होते हैं, और इस कारण उनका निर्वाचन राज्य की जनता करती है।

मारत सथ के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इससे, प्रालोचकों का वहना है कि मारतीय राजनीति म कई बुराइयां पैदा हो गई हैं। उदाहरण स्वरूप प्रालोचनों का गहना है कि राज्यपाल वी नियुक्ति करने का राष्ट्रपति का परिवार साराज में केन्द्र में सत्तास्त्र दल का प्रिकित्तर हैं, जिससे केन्द्रीय सरकार राज्यों में राजनीतिक परिस्थितियां तो, हुख सीमा तक प्रकृती २७० इच्छानुसार मोड सकता है। इस सन्दर्भ में, विशेषकर १६४७ के दूसरे झाम-सुनाव के बाद, केरल राज्य में १६४६ में झायतुकातीन स्थिति की घोषणा करके राज्य-

के बाद, कैरत राज्य में १६४६ में भारत्कातीन स्थिति की घोषणा करके राज्य-शासन को केन्द्र सरकार द्वारा भपने हाथों में लेने का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, बर्गोक उस समय केरत विधान सना में शायवारी सरकार को, स्यय्ट बहुत्वत होने हुए भी, राज्यपात रामहक्त यब की संवर्गाका पर कि राज्य में सर्वेपानिक तब समाज हो गई थी, वर्षास्त कर दिया गया।

ह, बसाल उस समय करता स्वभाग सभा के आध्याया सरकार का, रूप र वृष्टि इंग्ले हुए मी, राज्यपात साम्हण्य स्व की सिमारिश पर कि राज्य में सर्वेयानिक तथ समाप्त हो गई थी, वर्षात्त कर दिया गया। कमी-कभी सतास्त्र दल के सेवा-निवृत या निर्वोचनों में हारे हुए सदस्यों को राज्यपात नियुत्त कर दिया जाता है। यह सम्मव है कि जो व्यक्ति प्रयोग जीवन

राज्यपात नियुत्त कर दिया जाता है। यह सम्मव है नि जो व्यक्ति अपने जीवन मे दीर्पमात तक नित्ती राजनीतिक दत्त ना सदस्य दहा है, यह राज्यपात नियुत्त होंगे पर निष्यात नहीं रहे हैं विज्ञेषण रहे हों निर्देश किया जा जा जा जा जा कर का कार की बगाडीर ऐसे दत्त के हाथी मे हो, विसान वह व्यक्ति राज्यपात नियुत्ता होंगे के पूर्व सदस्य गही रहा है। नैन्द्र में सदालक दल से तम्बार्यक जिल व्यक्तियों भी नियुत्तिर राज्यात के यह पर हुई, उनमें से कुछ के नाम रहा प्रकार है—जी

को तिबुक्ति राजपाल के पद पर हुँ हैं, जनम से कुछ के नाम इस प्रकॉर है—जी धनितदस्ताद जैन, श्री भी० थी० पिरि, श्री हाफ्ति मोहम्मद इसाहीम, श्री सत्य-नारायण किस्ता, श्री श्रीमदारायण एव श्री मोहन्ताल सुवादिया। कमी-कमी सेवा निबृद लोक्किया ध्यिकारीय राज्यशल के पद पर तिमुक्त क्वियं जाने हैं। कार्यरत प्रसासन के घणिकारियों के लिए यह एक लोम के तद्वा

है, जिससे प्रमासन पर बुरा प्रमाण पर सनका है। राज्यातन की नियुक्ति के सन्त्यम में कमी-कमी संविधत राज्य सरकार नी पत्र्या की सबहेतना की गई। १६६७ में परिचय बताल में श्री मर्मवीर की, तथा विहार में भी नानुनारों की नियुक्ति राज्यपत्त के यूद पर नी गई, जबकि बगाल

विहार ने शा नानूना का निशुक्त राज्यात के प्रदूष पर ना यह जवान वाता तथा विहार के सनुक्त मंत्री मण्डलों ने इन निष्ठुक्तियों ना तीब विदोध निया। प्रतप्त इन दोधों को समान्त करने के लिए राज्यपाल नी नियुक्ति के सबस में केन्द्र सरकार के लिए निम्मलिनित परम्पराधों का पालन करना सावस्थक होगा।

प्रविध्य इन दाया का समान्त करन के लिए राज्यपाल का ानवुरक्त के सबय म केन्द्र सरकार के लिए निम्नलिखित परम्पराघो का पालन करना ग्रावश्यक होगा । एक—राज्यपाल को निर्युक्ति, सबिधत राज्य की सरकार की सलाहानुसार

की जाये, दो—राज्यपाल के पद पर सेवा निवृत या चुनाव में हारे हुए व्यक्तियों की

दा—राज्यपाल क पद पर सवा निवृत या चुनाव म हार हुए व्यक्तियां वा नियुक्ति ने वी जाये,

तीन—राज्यपान पद पर, किसी घन्य राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाने, क्योंकि, वह स्थानीय राजनीति से ऊपर होगा धौर निष्यसता पूर्वक प्रभारे नार्य करेगा। अगद्दार में इस परप्परा का पालन किया गया है, विवास वा एवल भी अपूर्व में नी निवृक्ति के, जो धपने राज्य, पश्चिम वंशाह, के ही राज्यपाल नियक नियं से थे।

राज्यपाल के पद की योग्यताएँ

भारत के सविधान के धनुसार राज्यपाल के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं.—

१—मारत का नागरिक हो,

२— ३५ वर्षों से कम भायुकान हो,

२—राज्यपाल को ससद या निसी राज्य की विधान समाना सदस्य नहीं होना चाहिये।

४—वह सम सरकार या किसी राज्य सरकार के ब्रामीन लाम ने क्राय पद की प्रहण न करता हो। दो या दो से प्रिमक राज्यों के लिए एन ही राज्यपाल निमुक्त निया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के वेतन तथा मतो ने मार को राष्ट्रपति द्वारा निर्पारित नियमों के ब्रनुसार उन राज्यों को उठाना होगा।

राज्यपाल के बेतन व भरो .—राज्यपाल का येतन सविधान के अनुसार १,४०० रू० मासिक होगा, जब तक कि ससद द्वारा इसमे कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसके अतिरिक्त राज्यपाल को वे मत्ते प्राप्त होगे जो भारत में भवनें से को सविधान लालू होने के विधि विधे जोते थे। ससद बन्तून द्वारा राज्यपाल के वेतन, मत्तो एव विशेष सुविधाओं को निर्धारित कर सकती है। राज्यपाल के कार्यकाल में उसके बेतन तथा भतों में कमी नहीं की जा सबती है। राज्यपाल को निर्धारत में उसके बेतन तथा भतों में कमी नहीं की जा सबती है। राज्यपाल को निर्धारक भावास की सुविधा उपलब्ध होगी।

राज्यपाल के पद ग्रहण करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाचीश या उसकी भनुपस्थिति मे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख यह प्रतिज्ञा लेना प्रावश्यक है कि वह प्रपने पद तथा कर्तव्यो का पालन, सविधान तथा कानून की रक्षा और जनता थीर जनता की सेवा करेगा।

राज्यपाल को प्रतितयों एव कार्य— यह जात है कि सम तथा राज्यों में ससवीय पढ़ित की सविवान के अन्तर्गत स्थापना की गई है। अत भारत के स्व्युवीत एव राज्यों के राज्यपालों की सर्वधानिक स्थितियों में, कतियथ अपवादों को छोड़कर, समानता पाई जाती है। ससबीय पढ़ित के सत्यमें में दोनों नाममान के बासक हैं। सविधान के अनुक्देद १६३ (१) के अनुआर राज्यों के लिए एक मंत्री परिपद का प्रावधान किया गया है, जिसका कार्य, सिवाय उन मामलों के जिसके सवय में सविधान द्वारा राज्यपाल को स्विवतिक के उपयोग करने ना अधिकार विधान प्रावधान होरा राज्यपाल को स्विवतिक के उपयोग करने ना अधिकार विधान में है, राज्यपाल को उत्तक कार्यों में सहायता एव परामर्थ देना होगा। सविधान में इन विधयों के, सिवाय कि असान के सीमावतीं कीने के प्रशासन के लिए राज्युवित के अधिकार दिवा में उन विधयों के, सिवाय कि असान के सीमावतीं कीने के प्रशासन के लिए राज्युवित के अधिकार एवं किसी मंत्रविता

क्षेत्र की जिला परिषद के मध्य खनिज से प्राप्त माय सवधी विवाद के निषटारे के लिए, राज्यपाल की 'स्वविवेक' सबधी शक्तियों को परिमापित नहीं किया गया है। विसी विषय के सबय में राज्यपाल अपना स्वदिवेक उपयोग में ला सकता है या नही, यह निर्णय सेने का प्रधिकार स्वय राज्यपाल को ही है। धनुरुदेद १६३ (४) वे मनुसार जो कार्य राज्यपाल ने भ्रपने स्वविवेकानुसार किया है, उसकी वैपता वे सन्दर्भ में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। परन्तु व्यवहार में ग्रमी तर इस परम्परा को ही मान्यता दी गई है कि असम के राज्यपाल के सिवाय ग्रीर उसको भी वेचल ग्रसम के सीमावर्ती क्षेत्र तथा खनिज पदार्थी सबधी शुल्क विषयो, पर ही, श्रन्य राज्यो के राज्यपालो को साधारणतया स्वविवेत के सनुसार नार्यं करने वा प्रधिकार नहीं है। "एक सीमा तक, अनुच्छेद १६३ मे इन शब्दो को (स्वविवेकानुसार) रखना प्रारुप निर्माण-सवधी एक प्रव्यवस्था है।" क्योंकि केन्द्र ने सदश राज्यों मं भी ससदात्मक सरकार की सविधान द्वारा स्थापना की गई है, और इस सन्दर्भ में राज्यपाल की स्थिति राज्यों की सबैधानिक व्यवस्था मे नाममात्र की होनी चाहिये । तथापि, यह स्मरण रखना आवश्यक है कि सर्विधान निर्माण के दौरान विवाद में इस विषय पर बल दिया गया कि राज्यों में ससदात्मक पद्धित के होने के बावजूद भी राज्यपाल वह कड़ी है जिसके माध्यम से राज्य की केन्द्र से सर्वायत रखा जा सबता है और जिसके पतस्वहण सम्प्रण भारत म सर्वधानिक एकता समव हो सकती है। यह स्पष्ट है कि वेन्द्रीय सरकार तथा तप्रधानक प्रधानक हा तकला है। न क्रूरक है। का किस त्राम्य स्वादी है। जैसा निदित्त राज्य सरकारों के सर्वेषानिक सक्वों की मुख्य कडी राज्याला ही है। जैसा निदित्त है, मारतीय रिवहास से सक्क लेकर, सविषान सभा में बार दस विषय पर व्यान ग्राकपित किया गया या कि केन्द्रीय सरकार जय-जब सिधिल हुई, देश की एकता को भाषात पहुँचा, बतएव देश में एकता तथा स्थाधित्व के लिए राज्यपाल की सब तथा राज्य के मध्य एक महत्वपूर्ण संविधानिक बड़ी की भूमिका सिमान इस्त प्रत्य को गई। इस विषय पर अपने विश्वार प्रकट करते हुए एक गेहरू ने सरियान समा के कहा—"एक निर्वाचित स्थायनाल हुख सीमा तक, पृथवकारी प्राप्तीय प्रवृतियों की श्रीताहित कर सकता है और केन्द्र से सबय कम ही जायेंगे।" व प्रतएव सर्वैद्यानिक एकता तथा स्थायित्व बनाये रखने के लिए राज्य-पाल के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व के लिए सविधान में दो मूख्य-प्राधार स्थापित किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं १-प्रमुच्छेद १५५ के अन्तर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तथा २--राज्यपाल कार्यकाल अनुच्छेद १५६ (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के प्रसाद-पवन्ते रहेगा। अनुच्छेद ३५६ के अनुसार, यदि किसी राज्य

१. डी॰ डी॰ बसु—'कमेन्ट्री बन द कान्स्टीट्युशन ब्राफ इण्डिया 'पृ०४७५ । २. कान्स्टिटीएण्ट ब्रसेन्बसी डिबेट्स, मा—द, पृ०४५५ ।

ने सबैधानिक यन (सरकार) को सविधान के अनुसार चलाया जाना समय नही है, तो राज्यपाल यह सूबना राष्ट्रपति नो मेजेगा। राष्ट्रपति उक्त राज्य मे राज्य पाल के प्रतिवेदन पर सनटनालीन स्थिति नी घोषणा करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद १६५ के अनुसार सचीय सरकार को यह अधिकार है नि राज्य सरकारों को जननी नार्यपालिन सबधी मक्तियों ने उपयोग के लिए निर्देश के। यदि उन निर्देश का गालन मही होता है तो राष्ट्रपति, राज्य मे राज्यपाल मे प्रतिवेदन पर, सनट-कालीन स्थिति नी घोषणा नर सनता है। यह समय है कि यदि राज्य मे निसी ऐसे राजनीतिन दल की सरकार है, जो केन्द्रीय सतायद दल से मिन्न है तो वह राज्य सरकार नदाधित केम्प्रीय सरकार द्वारा अनुच्छेद २६५ ने अन्तर्गत विए निर्देश को प्राविवत करने मे हिस्किचाहट दिखाये, ऐसी स्थिति मे सबिधान के अनुसार राज्यपाल सम सरकार के निर्देशों का पालन करने के तिए स्वविवेद की शक्ति का उपयोग कर सकता है।

राष्ट्रपति के सद्दा, राष्ट्रपति के केवल राजनिक सैनिक तथा प्राप्त्कालीन ग्रापिकारो, को छोडकर, राज्यपाल की शक्तियों को पाँच श्रेणियों में रखा जा सकता है।

१—कार्यवालिका सवधी, २—व्यवस्थापन सवधी, ३—वित्तीय सवधी, ४—न्याय सवधी ५—श्रन्य शक्तियाँ। इन समस्त शक्तियों को राज्यपाल मश्रीमण्डल के, जिसको विधान सभा में बहुमत है, परामर्शानुसार ही प्रयुक्त करेगा।

१-कायंपालिका सबधी सिवतवां—राज्यपाल राज्य-कायंपालिका का प्रमुख है। राज्य की समस्य कार्यपालिका सबयी सित्यों वा उपयीप राज्यपाल हे नाम है हो हो रा द्वाय राज्य पाल से नाम है हो हो रा है। यदाि राज्य की सारी कार्यपालिका सबचित सार्तिकार राज्यपाल है हो हो रा है। यदाि राज्य की सारी कार्यपालिका सबचित सार्तिकार राज्यपाल में निहित है, बास्तव में, इन चािकयों ना उपयोग राज्यपाल में सिहत है, बास्तव के निगंधी सबची समस्य जानकारी प्राप्त करने ना प्रविकार है। सोरी मण्डल के निगंधी सबची समस्य जानकारी प्राप्त करने ना प्रविकार है। सोरी मण्डल के निगंधी का यह वत्तंत्र वे हैं निम्मीमण्डल के सुन्तार राज्यपाल को स्वत्त करें जिसकी माग राज्यपाल ने की है। मानुच्छेद १६७ के अनुसार राज्यपाल को मत्तव करें जिसकी माग राज्यपाल ने की है। मानुच्छेद १६७ के अनुसार राज्यपाल हारा मुर्टमाओं को किसी मंत्री के निगंध की मत्रीमण्डल के समस्य उपवेश हारा मुर्टमाओं को किसी संत्री के निगंध की मत्रीमण्डल के समस्य उपवेश हारा मुर्टमाओं का किसी मंत्री के निगंध की मत्रीमण्डल के समस्य पालिका सबस्यों बातियों का दायरा उजना ही है, जितना राज्य-सूची में उल्लिखत विषयों पर विधि निमाण नरने का दायरा राज्य विधान समा नो है। प्रयांत्र राज्यपाल के नार्यपालिका सबसी बातियों का नार्यपालिका सबसी असित्यों राज्य-सूची में उल्लिखत विषयों पर विधि निमाण नरने का दायरा राज्य विधान समा नो है। प्रयांत्र राज्यपाल है।

राज्यपाल को कतिपय महत्वपूर्ण नियुक्तियो करने का अधिकार है, जो निस-जिखित हैं ---

- (१) राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमत्री के पद पर नियुक्त करता है।
 (२) मख्यमत्री के परामर्श पर अन्य मत्रियों की नियक्ति करता है।
- (३) प्रतुच्देद १६५ के धनुसार राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति
- करता है।

 (४) अनुच्छेद ३१६ के अन्तर्गत राज्यपाल लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एव सदस्यों की निमृत्ति करता है।
- (५) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो की नियुक्त करने के लिए राज्यपाल से परामग्री लेना मावश्यक है ।

राज्यपाल को राज्य में सकटकालीन दिसति की घोषणा करने के सन्दर्भ में मृत्युद्ध ३५६ के धनवर्षज, मुख्य भूमिका प्रधान की गई है। जब राज्यपाल की सिवसास हो जाता है कि राज्य सरकार का समासन सिवधान के अप्रधानों के मृत्यार समय नहीं है, तो यह राष्ट्रपति को इस विषय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, धीर यदि राष्ट्रपति इस आधार पर राज्य में सन्दर्शनतिन स्थिति पीयित करता है तो राज्यपाल को केजीय सरकार के स्थियका के क्य में राज्य-शासन चलाने के लिए कहा जा सत्या है।

मनुष्टिर २७१ (1) हाए। राष्ट्रपति को मादेव हारा पनात तथा मान्य-प्रदेश विधान समाधी भी क्षेत्रीय मिनियमें स्थापित करने का मिक्सर है तथा वह एत क्षेत्रीय मिनियमें के उदित रूप से कार्य करने के विष् पान्यपत्त के विदेश उत्तरदायित का प्रावधान कर सकता है। मान्यप्रदेश तथा पनाव में इन क्षेत्रीय समितियों हारा उनके सेनापिकार में उत्तिवित विधयों पर दिया गया पदमर्ग, सरकार तथा राज्य विधान समा को साथारफत्या स्त्रीहत करना होगा, किन्यु यदि क्षेत्रीय समितियों तथा सरकार में, इस सन्दर्भ मे तन्यद हो जाता है तो राज्यपाल को म्रतिम निर्णय देने का सम्किरर है।

२---व्यवस्थापन संबधी शक्तियाँ---राज्वपाल को व्यवस्थापन संबधी कतिपय महत्वपूर्ण शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं।

१—राज्यपास को राज्य विधान-मण्डल के धविवेशन धायतित करने का प्राधिकार है, किन्तु देशे अधिकार को इस प्रकार उपयोग में साना होगा कि मानता मंत्रीय प्रिक्त के प्रमित्तन दिन तथा नये धायिकत के प्रमान दिन किन कि प्रमान कि किए के प्रमान तिहा होना चाहियों। राज्यपास विधान-मण्डल को स्थितित करने का ध्रीपकार मो

है। साधारणतमा, जब विवान समा मे मत्रीमण्डल नो बहुमत प्राप्त है, इन मिलियों का उपयोग राज्यपाल मत्रीमण्डल नी सम्मति ने मतुसार ही नरेगा। विन्तुल व मत्रीमण्डल नो विवान समा में बहुमत ना समर्थन नहीं रहा है तब राज्यपाल इन शक्तियों के उपयोग के लिए प्रप्ता स्विवेश ना उपयोग कर सजता है। इतने उदाहरण १६६७ में हुए चीचे धाम-चुनार ने परचात नई राज्यों में देखने नो मिले। जब इन राज्यों के मुख्य मत्रियों ने, जिननो विधान समा में बहुमत ना समर्थन नहीं रहा तब राज्यपाल ने रियान समाभी नो मग नरने नी सलाह थी, किन्तु परिस्थितियों नो देखते हुए राज्यपाल ने स्विवेश से ही निर्णय जिया।

२---राज्यपाल को विधान मण्डल को सबोधित करने का स्रविकार है। स्राम-चुनाव के परचात् विधान मण्डल को पहली बैठक तथा प्रतिवर्ष प्रथम बैठक को राज्यपाल सबोधित करता है।

३—राज्यपाल विधान मण्डल के निसी सदन के समक्ष विचारार्थ विधेषक के सब्बय में उक्त सदन को सदेश मेज सकता है और उस सदन का यह क्तंब्य होगा कि सदेश में उल्लिखित निषय पर शीझ विचार करें।

४—जब एक विषेषक राज्य विधान-मण्डल के एक या दोनो सदनो (जिस राज्य मे पान सदन है तो एक सदन द्वारा, तथा जिस राज्य मे दो सदन है, तो दोनो सदनो हारा) पारित हो गया हो, तो उसे राज्यपाल के समझ उसकी सहमिति के लिए प्रस्तुत निया जायेगा। राज्यपाल विदेषक को, या तो भपनी सहमिति दे सकता है या उस पर प्रपनी सहमित रोक सकता है, या विधेषक को विधान मण्डल मे पुतः विधार को तिथान मण्डल मे पुतः विधार को हो सा तिथान मण्डल मे पुतः विधार को हो सा तिथान मण्डल मे पुतः विधार को तिथान मण्डल मे पुतः विधार को हो हो राज्यपाल को प्राचित्र को विधार मण्डल मे पुतः विधार के लिए तिथान मण्डल पुतः विधार के तिथान मण्डल मे पुतः विधार मण्डल पुतः विधार को तिथान मण्डल मे पुतः विधार मण्डल पुतः विधार को तिथान मण्डल मे पुतः विधार मण्डल पुतः विधार मण्डल मे पुतः विधार मण्डल पुतः विधार मण्डल मे पुतः विधार मण्डल पुतः विधार मण्डल मे पुतः विधार मण्डल मे हिस्सी हो हो होगा।

४—राज्यपाल जिन विधेयको को राष्ट्रपति को सहमति के लिए सुरक्षित रखना है वे निम्मलिखित विषयों से सक्चित होंगे।

> क-जो निजी सम्पति के मनिवार्य मधिग्रहण के लिए है, या स-जो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कभी करने के लिए हैं।

६—राज्यपाल विषान परिपद के लगमग है सदस्यो को ऐसे लोगों में से मनोगीत करता है जिन्होंने साहित्य, क्ला, विज्ञान, समाजसेवा तथा सहकारिता के क्षेत्र में विज्ञिष्टता प्राप्त की है।

७---राज्यपाल, राज्य विधान समा के लिए ब्रान्त-मारतीय समुदाय के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यदि उसके विचार में इस सम्प्रदाय का विघान समा म पर्यान्त प्रतिनिधित्व नहीं है ।

-- राज्यपाल, विधान मण्डल के निसी सदस्य भी ग्रयोग्यता की स्थिति में, निर्वाचन भ्रायोग के परामर्शानुसार निर्णय दे सकता है।

 राज्यपाल को, अनुच्छेद २१३ के अन्तर्गत जब राज्य विधान मण्डल का ग्रधिवेशन नहीं हो रहा हो, प्रध्यादेश जारी करने का ग्रधिकार है, जो कि विधान मण्डल की नई बैठक के प्रारम्भ होने से ६ सप्ताह तक वैध होगे, यदि इसके पूर्व इनको विद्यान सभा द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता है। प्रत्येक प्रव्यादेश की शक्ति कानन के सदश होगी , परस्तु यदि कुछ ऐसे विषयों से सविति धध्यादेश लागू करना है, जिन पर विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति धावश्यक है तो, बिना राष्ट्रपति के निर्देश के इन विषयो पर भव्यादेश लागू नही किये जासकेंसे।

३-वित्तीय शक्तियाँ-राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ निम्नलिखित हैं -

(१) राज्य विधान सभा में किसी विस-विधेयक को बिना राज्यपाल की श्चनुशसा के राज्य विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। विधेयकों के वित्तीय मामलो से सबधित संशोधन के लिए राज्यपाल की सहमति प्रावश्यक है। परन्त राज्यपाल की सहमति किसी कर को कम या समाप्त करने के छहेत्रय से प्रस्तुत संशोधन के लिए भावश्यक नहीं है।

(२) राज्यपाल का यह उत्तरदायित्य है कि राज्य के वित्तीय दर्प के लिए, विधान सभा के समक्ष राज्य का वार्षिक आय-व्ययक प्रस्तुत करवाये। बिना राज्य-पाल की धनुमति के अनुदान की भाँग नहीं की जा सकती है,

(३) राज्यपाल विधान मण्डल से पुरक, प्रतिरिक्त या विशेष अनुदान की

मांग भी कर सकता है।

(४) अनुच्छेद २६७ के घनसार राज्य-ब्राकस्मिक निधि को उपयोग में लेने का अधिकार राज्यपाल को ही है। राज्यपाल किसी बाकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए बाकस्मिक निधि में से ब्रियम निधि दे सकता है।

४--न्याविक शक्तियाँ--राज्यपाल को न्याय के क्षेत्र में कतिपय शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं, जो राज्य नार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में काननों से सर्वधित हैं। इन काननों ने विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधी के दण्ड को वह कम कर सकता है, स्यगित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, तथा उसे क्षमा प्रदान कर सकता है।

५-राज्यपाल की ग्रन्य शक्तियाँ-(१) राज्य लोक सेवा भागोप द्वारा भपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रेपित किया जाता है जो उसकी राज्य मन्नी परिषद के समझ उसके विचाराये प्रस्तुत करवाता है। मंत्री परिषद की टिप्पणियाँ उक्त

२७७

विषय पर प्राप्त होने के पश्चात् राज्यपाल दोनो लेखो को विधान सभा के प्राप्यक्ष के पास मेजता है, जिससे उनको विधान सभा के विचार विभर्ष के लिए रखा जा सके।

(२) इसी प्रकार राज्यवाल राज्य के झाय व्यय पर महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन पर भी विचार करता है।

(३) यदि किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती सपीय क्षेत्र (मू-माग) का प्रशासक निवृत्तिः किया गया हो तो ऐसी स्थिति म उक्त सपीय क्षेत्र के सबय में राज्यपाल मत्री-मण्डल से स्वतन रह कर प्रपने कार्यों का सवालन कर सकता है।

(४) नागालैण्ड के राज्यपाल को सविधान के १३वे संशोधन के ग्रन्तगत दस वर्षों तक पिछड़े हुए दु-यान-सान ग्रादिम वासी क्षेत्र के प्रशासन का उत्तरदायित्व

सीपा गया है।

ग्रन्त में, राज्यपाल नी स्थित तथा शक्तियों नी दृष्टि से यह निष्कर्ण निकाला जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में राज्यपाल की एक श्रत्यधिक महत्वपूर्ण मूमिना है। राज्यपाल न बेंबल राज्य ना श्रम्यक्ष है, जहाँ सख्दीय प्रणाली को स्थापित किया गया है, यरन्तु नई मामलों में केन्द्रीय सरकार का श्रमिकर्ता मी है, श्रद्ध राज्यपाल को निष्यक्ष एव निष्ठावात होना श्रत्यावस्थक है।

राज्यों में सस्सदीय प्रणाली होने के कारण राज्यपाल, राज्य का सर्वेधानिक प्रमान है। यद्यिप नितयस मामलों में राज्यपाल को स्विविवेग के उपयोग करने की मित है निन्तु इन शक्तियों का प्रयोग जनित्त को देखते हुए ही किया जायेगा। व क्षाना उच्च ग्यायालय ने राज्यपाल की स्विति पर प्रनाश डालते हुए "सुनीत-कुमार बोस बनाम मुख्य सचित्र, पिचम न्याल", गामन प्रमत्या में बहा— "वर्तमान सवियान ने भ्रत्यांत विना मित्रयों की सलाह ने राज्यपाल कोई कार्य नहीं कर सबता है। सारत सरकार प्रधिनियम १६३५ के अन्तर्गत स्विति मिन्न भी। वर्तमान सवियान के सत्यांत स्विविवेक से या व्यक्तियत प्रधार पर कार्य करने वर्तमान सवियान के सत्यांत स्विविवेक से या व्यक्तियत प्रधार पर कार्य करने वर्तमान सवियान के सत्यांत स्विविवेक से या व्यक्तियत प्रप्तियों की सलाह से हो सार देशा गी।

१८६७ में चीये माम-चुनाव ने बाद भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुमा, कई राज्यों में काग्रेस का बहुमत समाप्त हो गया। मत इस परि-बर्तित स्थिति में राज्यपाल की मूमिका से सर्वधित कई महत्वपूर्ण प्रकृत सामने माये हैं। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं।

१—वियान समा ने सत्र नो बुलाने ने प्रायिकार ने सबंघ में नवस्वर, १६६७ में पश्चिम बगाल में राज्यपाल तथा मुख्यमत्री ने मध्य विवाद उत्पन्न हुग्रा ! राज्यपाल वियान समा की बैठक को पहले ध्यामन्नित करने के पक्ष में थे, जबकि मुख्यमंत्री का मत वा नि बैठन को नुष्ठ समय पत्रवात् ही धामितत निया जाये। इस सन्दर्भ में नेन्द्रीय विधि मशालय ने धनुष्ठेद १७४ (१) के धन्तर्यक्त यह सम्पोनरण दिया कि संवैधानिक तथा सैदानिक रूप से इस कि राज्याल को वी गई है नित्त धनित्त निर्णेत इस विषय पर मत्रव मनी का ही होगा।

ग्रमैल, १६७०, में इसी विषय पर पत्राव में राज्यपाल तथा मुख्यमती वादल के मध्य भतमेद पैदा हुमा। मुख्यमती बादल की इच्छा के विरद्ध राज्यपाल ने विभाग समा की बैठक ग्रामितित जी।

२—विधान समा को भग करने के सबध में क्या राज्यपाल को मुख्यमंत्री के पराममानुसार विधान सभा मन करना चाहिये ? क्या इस विषय पर वह स्वतवता पूर्वक निर्णय से सकता है।

३—वया राज्यपाल को मुत्रीमण्डल को ऐसी परिस्थिति में भी जवित मृत्री मण्डल को वियान समा में बहुमत प्राप्त है, वर्षास्त करने ता प्रक्रिकर है? विवेषकर यह प्रकृत से राज्यों (केरल तथा पत्रिकम क्यांत) के राज्यपालो हारा भागों मुत्री मिळकों को वर्षास्त करने के फलक्ष्मण साथ हो था हो?

११६६ में केरल में थी नमूत्रीयार की शाम्यवादी सरकार हो, जिसही (विधानसमा में स्पष्ट बहुनत प्रायत सा, वर्षात्त नरूँ, पाट्टपूरि सामत सामू विधान था। विधानसम्बद्ध केराव्यात श्री धर्मीदि में धरवासून्य सात सामू मण्डल को दिसबद, १६९७, में वर्षात्त वर श्री पी॰ सी॰ धीथ सो मुख्यानी तिपुक दिया। थी धर्मवीर को यह प्रतीत हुआ कि मुस्यमनी मुख्यों के मनी-मण्डल को विधान साम का दिसबाह नहीं था। उन्होंने भी मुख्यों को मनी-मण्डल को विधान साम का दिसबाह नहीं था। उन्होंने भी मुख्यों को हुएत विधान समा श्री बटक सो, मुद्द हात करने के लिए धार्मीयत करने को कहा कि उनस्ने में परकार को सास्त्र में विधान सम्बन्ध में यहुमत प्राप्त सा नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री ने विधान समा को धार्मीत्त नहीं निया, श्री धर्मवीर ने मन्त्री मण्डल को ब्रह्मत्व पर सास्त्रीत मंत्रीमण्डल सावदर बर्धात्त कर दिया। यह कार्य श्री धर्मवीर ने

ख-प्रमुच्धेद १६१ (१) के प्रमुसार राज्य ने लिए एक मनीमण्डल होगा, जिसमा कार्य राज्यपाल में उसके नार्यों म सहायका तथा परामकें देना होगा, शिवाय उन मामकी के जिनके लिए उसमो सविधान के प्रमुसार प्रथमी स्वेच्छा से मार्ये करता है।

तमापि श्रीधमंबीर द्वारा मत्री मण्डल नौ श्रक्षांत निर्म जाने के फ्लस्वरूप विभिन्न प्रतिक्रियाएँ हुई। वेन्द्रीय विधि मतालय ने प्रत्पमत मश्रीमण्डल नो बर्बास्त करने के राज्यपाल के इस कार्य को सबैद्यानिक माना । किन्तु धालोचनो का यह कहना या कि मन्नीमण्डल को पदच्युत करने का श्रीपनार वेचल विधान सम्रा में तिहित है और विधान समा के इस मधिकार को राज्यपाल नहीं हुइए सकता है। भ्रतएव यह श्रावयणक है कि राज्यपाल नी स्थित तथा नामों ने सबय मे स्वरूप ससदीय परम्पराम्नो का विकास होना चाहिये। इसने म्रतिरक्त, यह भी जनित होगा कि राज्यपाल के स्वैच्छापिकारों को स्यष्ट रूप से सविधान में परि-भाषित किया जाय।

राज्य-मती परिपद

मारतीय सविषात के प्रतुच्देद १६३ (१) के प्रतुतार राज्यों के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधात निया गया है जो राज्यपाल को उसके नायों में सहायदा तथा परामर्थ देगी, सिवाय जग मामलों के जिनके सबय में सिविषात के धन्यपेत वह 'स्विविक' से नामें कर सत्वता है। सिविषात में 'स्विविक' से नामें कर सत्वता है। सिविषात में 'स्विविक' शब्द नो परिसाषित नहीं किया गया है, किन्तु केवल प्रसाम के राज्यपाल में सम्बन्ध में सिविषात नहीं किया गया है, किन्तु केवल प्रसाम के राज्यपाल में सम्बन्ध में सिविषात में उत्तिलित है कि वह स्विविकानुसार राष्ट्रपति के प्रसिव्यत्ति के एवं स्विविकान से प्राविक देशों है स्वाधात के लिए उत्तरदायी है। यह प्रमत्त वह स्वविवेवक के प्रमत्त का प्रतिम निर्णायक भी वहीं होगा। यह सिविषात के प्रतुच्देद १६३ (२) से ही स्वष्ट है।

केन्द्रीय सरकार के समान राज्य सरवार भी ससदीय प्रणाली के मूल सिद्धान्तो पर प्राचारित हैं। ससदीय प्रणाली का मूल सिद्धान्त यह है नि मनी-परिपद (जास्त्रीक कार्यपालिका) प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका के नित्रवेत सदन के प्रति उत्तरदायी है तथा प्रप्रत्यक एक से सतदाता गण के प्रति उत्तरदायी है। सिव्धान के प्रमुख्य १६४ (४) के अनुसार राज्य के मनी मण्डल का सामूहिक उत्तरदायिद दाज्य पाम समान प्रति होणा। अत्तर्य, सामान्यत राज्यपाल को मनी परिपद के परामर्शनुसार कार्य करना होगा।

सावारणतथा, ध्राम चुनाव के पश्चात् अनुच्छेद १६४ (१) के अन्तर्गत वहुमत दल के नेता नी राज्यपाल मूल्यमत्री के पद पर नियुक्त करता है। तत्स्वमत राज्यपाल ध्रम्य मत्रियो मी नियुक्ति मुख्यमत्री के सलाह के अनुसार, करता है। वह स्पन्ट है कि जब आम चुनाव में किसी दल नो विधान समा में बहुमत आपत हुमा है तो राज्यपाल उसी दल के नेता को मूल्यमती नियुक्त मरेपा और उसकी अपने स्वविज्ञ के उपयोग में लाने की कोई आवश्यकता नहीं होंगी। किन्तु जब विसी दल नो विधान-समा में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है ती राज्य-पाल विधान सह के नेताको मुक्त के सुक्त के सुक्त के सुक्त के सुक्त के नेताको से सुक्त के नेताको सुक्त के सुक्त कहीं आपत होता है ती राज्य-पाल विधान सह के नेताको से मात्र मण्डल के सुक्त के लिए चर्चा करके मुख्य-

मंत्री की नियुक्ति अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। अनुन्धेद १६४ (१) के अत्यत्तेत मंत्री अपने यद पर राज्यपाल के 'असार पर्यंत्र' तक रहेंगे। मंदि मंत्री के पद पर नियुक्त हिमा गया व्यक्ति विचान मण्डल का सदस्य निवीचित होना आवश्यक है, अन्याया उसको मंत्री पद पर से हटना पडेगा। अपना पद पहुण करने के पूर्व अरोक मंत्री की पद के सबय में राज्यपाल हारा अपना पद पहुण करने के पूर्व अरोक मंत्री की पद के सबय में राज्यपाल हारा अपना पद विचान मंत्री है। अनुन्धेद १६३ (१) के अनुनार इस अन्य पर कि अनीमण्डल हारा राज्यपाल को कोई सम्मति या किस अनुनार इस अन्य पर कि अनीमण्डल हारा राज्यपाल को कोई सम्मति या किस अनुनार इस अन्य पर कि अनीमण्डल हारा राज्यपाल को कोई सम्मति या किस अनुनार इस अन्य पर कि अनीमण्डल हारा राज्यपाल को कोई सम्मति या किस अनुनार इस अन्य पर कि अनीमण्डल हारा राज्यपाल को कोई सम्मति या विचान अने सम्मति यो महै। किसी व्यक्ति सामित कोई अन्य नहीं की जा सकती है। इस कारण मित्रयों को सम्मति सामित कोई अन्य नाया स्वता है।

सिवधान द्वारा राज्य मनी-मध्डल के सदस्यों की सच्या निर्धारित नहीं की गई है। प्रतएव विभिन्न राज्यों में मित्रयों की सत्या निर्म-नित्र है। यद्यिष सिवसान में मित्रयों की विभिन्न श्रीमियों को नी उत्तिसिवत नहीं किया गया है, विभाग स्ववहारतः चार श्रीमयों में मित्रयों को वर्गीहत किया जाता है, जो निम्मानसार है —

- -(क) केबीनेट स्तर के मत्री,
- (ख) राज्य मधी,
- (ग) उपमत्री, तथा,
- (घ) ससदीय सचिव,

इन चारो प्रकार के मनियों से मितकर मधी-परिषद का गठन होता है। केवल केवीनेट स्तर के मधी हो मित्रमण्डल में होते हैं। प्रत्येक केवीनेट स्तर के मधी किसी न किसी मशात्य का बच्च्स होता है। क्ष्य श्रीणयों के मित्रयों का कार्य विषायी तथा प्रधासकीय क्षेत्रों में केवीनेट स्तर के मित्रयों को सहायता देना है।

सभीनव्यत के कार्य स्वया स्विधार — मनीनव्यत का कार्य राज्य सरकार की नीतियों का निर्माण करना है, जिन्हें सामार सर राज्य मातन का संस्थावत किया जाता है। यह स्वामानिक है कि नीति—निर्माण ना कार्य किया निर्माण से व्यविद्य होगा को राज्य तथा समर्थी मुश्यों में रहे गये हैं। इन नीतियों के विद्या किया विचान को स्वामीत छानव्यत है। पाय. इन नीतियों को कानुनी स्वयेता प्राव्यक हो आपत हो नीतियों को सनुनी स्वयेता प्राव्यक हो स्वाम तसा में बहुनत प्राप्त प्रवृत्त के विद्यान समा में बहुनत प्राप्त प्रवृत्त के प्रवृत्त कार्यों के विद्यान समा में सरस्ता पूर्वक पहुनी प्राप्त हो आती है।

मत्रीमण्टल का दूसरा प्रमुख कार्य है, प्रवासन के विभिन्न विमागों के मध्य आवश्यन सहयोग तथा समन्यय स्थापित नरना, जिससे समस्त प्रवासन को एक इनाई के रूप में सचालित दिया जा सके। प्रवासन के विभिन्न विभाग अपने में प्रथम, स्वतन तथा प्रास्तानिमेर नहीं हो सचते है। उनमें विभिन्न विषयो पर पारस्परिक सहयोग एवं समन्यय होना अस्यावश्यन है। इस सहयोग पर ही राज्य में प्राप्ति निर्मेर है।

राज्य वार्यपालिका तथा प्रशासन पर नियमण रखना मंत्री मण्डल का नार्ये है। चूँनि नार्यपालिका एव प्रशासन की दृष्टि से मंत्रीमण्डल राज्य विधान सर्ना के प्रति सामृहिक रूप से उत्तरदावी है व्रत विधान समा में बहुमत का विश्वास अपने प्रति दृढ बनावे रखने के लिए मंत्रीमण्डल ने शासान कुजलता, दसता एव तोककत्याण ने शाधार पर संगीतित करना चाहियं। ध्रतएव यह स्वामावित है कि मंत्री-मण्डल समस्त कार्यपालिका तथा प्रशासन सवयी क्रियाओं पर निगरानी रते। यदि शासन में दोच उत्तरत हो जाते है तो मंत्रियों को इसने लिए विधान समा के समक्ष जवाब देना होगा।

मत्रीमण्डल का एक प्रत्य महत्वपूर्ण वार्य यह है कि वह राज्य के वित्त प्रवासन को सुचार रूप से सवासित करने वा प्रावधान करे। यह राजनीति विधान का एक सत्य है कि समस्त प्रवासन की सफलता के लिए न केवल पर्याप्त वित्त होना प्रावध्यक है किन्तु एक दृढ आर्थिक व्यवस्था के लिए वित्त प्रवासन का समालन सही रूप से हो। उत्तम प्रवासन का उत्तरदायिस्व मत्रीमण्डल का है प्रतः मत्रीमण्डल का सह भी उत्तरदायिस्व हो जाता है कि राज्य का वित्त-प्रवासन भी उत्तम हो। राज्य की राज्य का वित्त-प्रवासन भी जातम हो। राज्य की राज्य का सम्वासन भी वित्तम हो। राज्य की राज्य वित्त मत्री नी हो विमम्दारी है।

सक्षेत्र में, राज्य मशीमण्डल राज्य शासन नी धुरी है। राज्य शासन नी सफतता मुख्य मशीमण्डल पर ही निर्मर रहती है। इस नारण मश्रियों को सस्तिया प्रणाली के अनुकृत प्रयन दायित्वों को सम्ताना तथा निभाना प्रत्यावश्यक है। सभीय मशीमण्डल के सन्दर्भ में प्रथ्ययन किया जा चुना है नि सत्तदीय पद्धति में मश्रियों के जार प्रकार ने उत्तरदायित्व होते हैं। जो इस प्रकार हैं।

?—मित्रयो के तकनीकी या श्रीपकारिक उत्तरदायित्व का मिद्धान्त ससदीय पढीत मे मित्रयो का श्रीपकारिक उत्तरदायित्व राज्याध्यक्ष के प्रति होता है। मारत सम के राज्यों मे मन्नोगण श्रीपकारिक रूप से राज्यपात के प्रति उत्तरदायी होते। मनुख्येद १६७ के धनुसार मृद्ध्यमंत्री का यह उत्तरदायित्व है कि—(क) राज्यपात को राज्य प्रशासन, ध्यदस्यापन के समस्त मामलो से सबधित राज्य मनी-परियद के निर्णयों से प्रवस्त करायें। (स) राज्य के प्रशासन तथा ध्यवस्थापन सबयी मामलो के सबय म राज्यपाल को वह समस्य जानकारी दे जो राज्यपाल बाहना है।

(ग) यदि राज्यपान की ऐसी इच्छा है तो मनीमण्डल के विचार-विमर्ध के लिए ऐसे मामल का प्रस्तुत करे दिस पर निर्मय किसी मन्त्री ने तिया है कि सु जिस

पर मनीमण्डल ने विचार नहीं निया या ।

२—मित्रयो न पारस्वरित उत्तरदायित का सिद्धानत—मनी-मण्डल एक इकाई के समात है। इसके सदस्यो को एक समिदित प्रमावशासी तथा एकतापूर्ण इकाई के रूप म कार्य करना धानवश्च है। यह कहने म कोई प्रतिन्वयोतित नहीं होगी सि प्रमावश्च में प्रमावशासित नहीं होगी सि प्रमावशासित वहां होगी सि प्रमावशासित वहां विवास प्रमावशासित एकता की माव-नामा पर धानतित एकता है।

इसने विपरीत, यदि मनीमण्डल में भगता और फट है तो निश्चय ही वह

स्थायी नहीं रह संदेगा।

१——दर्गिगाय उत्तरदाजित्व का सिदाला—प्रत्यक मश्री प्रमित विमाग के लिए स्मिनिग्य का से तरिवान से नीई । वर्डाम विधान का को सिवान से नोई मायान नहीं है कि मश्री व्यक्तियत कर से साथ विभाग का के प्रति उत्तरदाजी है कि भी स्वरक्त कर से साथ विभाग का मार्थ कर स्वरक्ति कर के साथ का सिद्धान से विभाग के प्रमुद्ध १६५ (१) म निद्धित है, जितके प्रमुद्ध र मश्री प्रमित पर पर राज्यत्व के 'प्रसाद पर्यन्त' वत ही रूपा। ससदीय प्रवित के सन्दर्भ में राज्याप्त के 'प्रसाद पर्यन्त' का तार्या प्रमुद्ध र प्रमुद्ध पर प्रमुद्ध पर प्राप्त के 'प्रसाद पर्यन्त' का तार्य मुख्यक्षी के 'प्रसाद पर्यन्त' है। प्रतिष्ठ मश्री व्यक्तियत कर से मुख्यमत्री के प्रति उत्तरदात्री होता। यह उत्ति होता है कि सिद्धान में मश्री के विचान समा के प्रति उत्तरदात्री होता। यह उत्ति होता है कि सिद्धान में मश्री के विचान समा के प्रति उत्तरत्त्री व तरास्तिवाद के सिद्धान्त के साल्या प्रस्ता की निवान समा के प्रति उत्तरत्त्रीय उत्तरस्तिवाद के सिद्धान के साल्या प्रस्ता की निवान समा के प्रति उत्तरत्त्रीय उत्तरस्तिवाद के सिद्धान्त को साल्या प्रस्ता की निवान का सिद्धान के साल्या प्रस्ता की निवान का सिद्धान के स्वत्य के स्वत्य के स्वत्य के सिद्धान के स्वत्य के सिद्धान के सिद

४—सत्तरीय पदिन ना मूल ग्रावार—मनीमण्डल के सामूहिन उत्तरदायित्व का निदान्त है। सविधान के मुद्ध द १६५ (१) म मनीमण्डल राज्य विधान समा के प्रति ग्रावंग गीतियो तथा कार्यों के विष् उत्तरदायी हाया। इस सिदान्त के मुतार मनीमण्डन का अस्तित्व वज तक बना रह सत्तरा है जब तन विधान समा म बहुमन का विश्वास उन्तरे प्रति है। दूतरे घाया में, यदि बहुमत वा विश्वास विधान समा म मनीमण्डल के प्रति न रह, वा एसी स्थित म बहु मशी-मण्डल मा हो बायन। । अटिक दश में मनीमण्डन की विधान समा के समम प्रत्या विश्वास बनाय रखन पर ही हिसरता प्राय्त होगी।

मूख्यमत्री

भारतीय सविवान के बनुच्छेर १६३ (१) के बनुसार मुख्यमत्री मनीमण्डन का . हरता है। मुख्यमत्री की निमुक्ति राज्यपान करता है। परन्तु मुख्यमत्री के पद पर केवल उसी राजनीतिक दस के नेता को नियुक्त किया जाता है जिसको ग्राम-चुनाव में राज्य विधान समा में बहुमत मिला है। यदि श्राम-चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल बुछ हद तक मुख्यमत्री की नियुक्ति में स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है।

मुख्यमध्रो के प्रमुख कार्य — १ - मनीमण्डल के ग्रष्यक्ष होने वे कारण वह मनी-मण्डल का गठन करता है। मुख्यमध्री की सम्मति पर ही राज्यपाल ग्रन्य मनियों की नियुक्ति करता है। मनीमण्डल के सगठन में मुख्यमध्री को प्रधान मनी के समान ग्रस्यिय शक्तियाँ प्राप्त है। यह उसकी इच्छा पर निर्मर करता है कि नौन व्यक्ति मधीमण्डल में रहे या न रहे।

२—मत्रीमण्डल के अध्यक्ष के नाते, मुख्यमधी मत्रीमण्डल की बैठको की ग्राध्यक्षता करना है। मत्रीमण्डल के निर्णयो पर मुख्यमत्री का महत्वपूर्ण प्रमाव होता है।

३— मुश्यमनी राज्यपाल तथा मनीमण्डल के मध्य सबैघानिक कडी के रूप मे कार्य करता है। अनुच्छेद १६७ के अनुतार मुख्यमनी राज्यपाल को, राज्य-शासन या व्यवस्थापन सम्बन्धी मनीमण्डल के निर्णयो से अवस्त कराता है। इसी प्रकार यदि राज्यपाल राज्य प्रशासन या प्रशासन या व्यवस्थापन सम्बन्धी किसी नियम पर जानकारी चाहता है तो मुख्यमत्री का यह वर्तव्य है कि यह जानकारी उसे प्रदत्त करे।

४—मुख्यमत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रयान है। समस्त प्रशासन पर उसको निरीक्षण करने वा प्राधकार प्राप्त है। वह शासनरूपी गाडी का चालक है, जिसके नेतृत्व मे शासन का सचालन होता है। मंत्रीमण्डल से सबघित विभिन्न विवादों के निरदारे की जिन्मेदारी मुख्यमत्री की ही है।

५—मुख्यमत्री विधान सभा का नेतृत्व मी करता है। विधान सभा मे सर-वारों नीतियो तथा कार्यों को घोषणा और स्पन्दीकरण करते का उत्तरदायित्व मुख्यमत्री पर ही है। वह विधान सभा में किसी मत्री द्वारा असतोषपूर्वक उत्तर विशे जाने की स्थिति में, सर्विधत विधय पर सदस्यों की शका को दूर करता है। वह सरकार का प्रमुख प्रवत्ता है और उसके वन्तव्य तथा शाक्वासन ग्रन्तिम रूप से प्राधिकारक माने जाते हैं।

यह स्वामाविक है कि मुख्यमती की स्थिति राज्यों में सवसय केन्द्र सरकार में प्रधान मत्री की स्थिति के समान है, क्योंकि दोनो क्षेत्रों में ससदीय प्रणाली स्थापित की गई है। अस राज्य में मुख्यमती की महत्ता वास्तविक शासक के रूप में है। राज्य का पुरा प्रशासन तत्र उसी के सकेतो पर सचालित होता है। वह राज्य मत्रीमण्डल का 'क्ष्यात' है। अत मत्रीमण्डल में उसके निर्णयों का ग्रस्यधिक महत्व होता है। ने समान हैं।

महाधिवक्ता

सियमान के मजुर्चेदर १९५ के मानार्गत साथ में प्रश्लेक राज्य के जिए महास्थित राजा ना प्रावचान स्थाय है। महासियतार की नियुक्ति राज्यवाल हारा, माने-मण्डल की सताह के मनुतार, को जाती है। केवल उस स्थित को महासियताना नियुक्त किया जा सत्ता है, जो उच्च स्थायता के स्थायाचीमा के यह के योग्य होंगा है। महासियताना ना कार्यकाल राज्यवाल के स्थाय योगा तम रहेगा। याता वेता है। महासियताना ना कार्यकाल राज्यवाल के प्रशास योगा के केवा योगा वेता है। महासियताना के कार्य राज्य के साथ स्थायता स्थायता के कार्य राज्य के साथ स्थायता केवा स्थायता स्थायता केवा स्थायता केवा स्थायता केवा स्थायता केवा स्थायता केवा स्थायता स्थायता केवा स्थायता केवा स्थायता स्थायता केवा स्थायता स्था

महाभिवस्ता राज्य सरकार को वन समस्त विषया पर नानूनी सम्मिति देते हैं जो उसने मेथित किये मते हैं । इसने मतिरिक्त, नानून हारा उसके कार्यों का गिर्पाण विण्या जा महता है। राज्य के धीर से उसन जायालय में बहु उन समस्त गामतों में पैरबी करता है, जिनमें राज्य एक पता में हैं पत्या की सरक से स्कृ उक्क स्वाधालय के समस्त क्षीतीय ता क्षेत्रवारी गामते में पैरबी करता है। महा-पिवला घरने नर्वता में राज्य के विच्य कियी गामते में नार्य नहीं नर सकता है। महा-पिवला घरने नर्वता में राज्य के विच्य कियी गामते में नार्य नहीं नर सकता है। महा-स्वता ऐसे प्रकरणों मामतों में मित्रपुत्त का बचाव गहीं नर सकता है। महा-नित्री पत्र करणों मा, जिनमें यस सक्तार के पत्र में पैरबी करता है। महा-पत्र को नित्रा सरकार की महामित्र स्वाच है। सह विशो नम्मती में उपयोग्धर के पर को नित्रा सरकार की महामित्रकार का नार्यक्ता समारत हो जाता है क्योंन-उत्तरी नित्रित राजनीतिक मामार पर नो जाती है।

राज्य विधान मण्डल

मारतीय सविधान ने धन्तर्गत भारतीय सध के प्रत्येक राज्य के लिये व्यव-स्थापन नार्यों के लिए एक विधान-मण्डल की स्थापना की गई है। साधारणतया, व्यवस्थापिका समा के सगठन की दो पढ़ितयों होती हैं। सर्वत्रयम, द्विस्तारामक, पद्धित के अन्तर्गत, व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, उच्च सदन तथा निम्न सदन, द्वितीय, एक सदनारमच पद्धित में व्यवस्थापिका वा केवल एक ही सदन होता है।

विधान-परिषद--- मारतीय सथ के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक पढ़ित है और ग्रन्थ राज्यो मे एक सदनात्मक पद्धति की व्यवस्था की गई है। ग्रतएव कुछ राज्यो में विधान मण्डल का निर्माण राज्यपाल तथा दो सदनों से होता है, श्रीर कुछ राज्यों में राज्यपाल तथा एक सदन द्वारा होता है। जिन राज्यों में दो सदन है, वहाँ उच्च सदन (द्वितीय सदन) को विधान परिषद की सज्ञा दी गई है, श्रीर निम्न सदन (प्रथम सदन) को विधान सभा कहा जाता है। श्रारम्म मे, जिन राज्यो म द्विसदनात्मक पद्धति को श्रपनाया गया, उनके नाम इस प्रकार हैं--वस्वई, विहार, मद्रास, उत्तर-प्रदेश, पश्चिम बगाल, पजाव और मैसूर । तत्पश्चात सवि-घान संशोधन अधिनियम १९५६ वे अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों में द्विसदनात्मक पद्धति की स्थापना की गई--म्राध्नप्रदेश, विहार, वस्वई, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, पजाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बगाल ग्रीर जम्म-काश्मीर । चार राज्यो राजस्थान केरल, धासाम, तथा उडीसा मे एक सदनात्मक पद्धति की व्यवस्था की गई। सविवान के ग्रनुच्छेद १६६ (१) के ग्रनुसार विवान परिपद (उच्च सदन) समाप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिनके अनुसार यदि राज्य विधान समा के समस्त सदस्यों के बहमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के है बहुमत से प्रस्ताव पारित करके यह माँग की जाती है कि विधान परिषद को समाप्त किया जाये, या जिस राज्य में यह सदन नहीं है, उपर्युक्त स्नाधार पर विधान समा प्रस्ताव पारित करती है कि उक्त राज्य मे प्रधान-परिपद स्थापित की जाये तो ससद कानुन द्वारा राज्य विधान-समा के प्रस्ताव के प्रमुसार विधान-'परिपद की समाप्ति या स्थापना के लिए प्रावधान करेगी। यह स्पष्ट है कि विद्यान-परिषद की स्थापना या समाप्ति मुख्यत उक्त राज्य की विधान सभा की इच्छा पर निर्मर है।

राज्य विधान-परिषद का संगठन राज्य विधान-परिषद के सदस्यों की संख्या उक्त राज्य की विधान-समा के सदस्यों की सख्या की दूसे अधिक नहीं होनी चाहिये, परन्तु किसी स्थिति मे विधान-परिषद के सदस्यों की सहया ४० से कम नहीं होनी चाहिये। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार से होगा।

(क) एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन एक निर्वाचन-मण्डल द्वारा होगा, जिसके सदस्य स्थानीय स्वशासन सस्यामी (नगरपालिका, जिला मण्डल या संसद

द्वारा निर्धारित ग्रन्य स्थानीय सस्याएँ) के सदस्य होंगे । (ख) एक बारह प्रश (क्रे) सदस्य राज्य में रहने वाले स्नातको द्वारा निर्वा-

चित्र किये जायेगे। (ग) एक बारह अश (क्रेंट्र) सदस्यों का निर्वाचन तीन वर्षों के **ध**नुभव के

- शिक्षक करेंगे जो राज्य में कम से कम माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं।
- (घ) एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन विधान-सभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगर ।
- (ड) शेष सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, जिन्होंने साहित्य. विधि, सहकारिता भान्दोलन तथा समाज सेवा क्षेत्र में ज्ञान या अनुसद प्राप्त क्या है।

कार्यकाल-राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में सेवा निवत होते हैं, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल ६ वर्षका है।

सदस्य की योग्यताएँ

१-प्रत्येक सदस्य नो भारत का नागरिक होना भावश्यक है।

२ — कम से कम ३० वर्षकी स्राय का होना चाहिये।

३-- भन्य योग्यता, जो ससद कानन द्वारा निर्धारित करती है।

कोई सदस्य राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनो का सदस्य नहीं हो सबता है भौर न ही दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मण्डल का सदस्य हो सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की बैठको से ६० या उससे अधिक दिनों बिना सदन की भनुमति के भनुपस्यित रहता है, तो उसका स्थान रिक्त माना आयेगा ।

निम्नलिखित भाषारी पर किसी व्यक्ति को विधान परिषद की सदस्यता के भयोग्य ठहराया जा सकता है :---

२८७

१---यदि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के घंधीन लाभ के पद पर है। यह प्रतिबन्ध केन्द्रीय या राज्य के मित्रयो तथा कानून द्वारा निर्धारित किसी ग्रन्य पद पर लागु नहीं होता है।

२ — यदि वह न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया है।

३---यदि वह दिवालिया है।

४—यदि बहु मारत ना नागरिक नहीं है या उसने निसी अन्य राज्य नी नागरिकता ग्रहण कर ली है या वह निसी भी अन्य देश ने प्रति राज्य मिक्त रखता है।

५—यदि वह किसी ससदीय वानून के अन्तर्गत प्रयोग्य होता है। उदाहरण स्वरूप १६५१ में ससद ढारा पारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १६५१ के अन्तर्गत न्यायालय ने उन व्यक्तियो को अयोग्य धापित विद्या है जो न्याथालय हारा दिण्डत हुए हैं, या जिनको निर्वाचन के सदय में अप्ट या अवैधानिक वार्यों के लिए दोपी पारा गया।

राज्य विधान परिषद नी बैठनो के लिए गण पूर्ति की सस्या उसने मुल सदस्या का सस्या ने एन दशाश सत्या नुहै या १० होगी। (इन दोनो म से जो नी सत्या प्रधिन होगी, वह गणपुर्ति नी सस्या होगी)।

विधान परिपद का एक प्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होता है, जिनना निर्वाचन विधान परिपद वे सदस वरते हैं इनको १४ दिन वे नोटिस पर विधान परिपद बहुनत से प्रस्ताव परिपद कर पदच्युत नर सकती है। दोनो पदाधिकारियों को वेतन तथा गती मानते हैं और इनके कार्य लगमग सधीय राज्य समा के ध्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के सदुश हैं।

विद्यान परिपद के कार्य तथा श्रविकार

विवान परिषद के विभिन्न कार्यों तथा ग्रधिकारों को तीन श्रेणियों में रखा. जासकता है।

१—स्पयस्यापन सबधी कार्य—द्वितीय सदन के नाते राज्य विद्यान परिषद को बानून निर्माण करने के सबय में सिवधान द्वारा कुछ कार्य प्रदत्त किये गय हैं। साधारण—विषयेयन (वित्त विधेयक को छोडकर) को किसी भी सदन म प्रस्तुत विद्या का सबता है जो दोरों, सर्ट्यो द्वार प्रारेख्त होंने पर्दे राज्यपाल की सहमित से बानून वन सकेगा। यदि दोनो सदनों ने विधेयक पर मतनेद हो जाता है तो विधान समा द्वारा उसी सत्र में या नये सत्र में विधेयक के पुत्र पारित होने पर राज्यपाल की सहमित से विधेयक को कानून माना जायगा। यदि विषेयन विधान समा द्वारा पारित कर दिया गया है भीर विधान परियद के विवार-निमर्ग के लिए या है निन्तु विधान परियद कम पर कों है तर्गयालन कार्यवाही नहीं करती है तो विषेयन को विधान परियद में प्रसुत्त करन के तीन माह पर्यवाद विधान समा उसे पुत्र-पारित कर समनी है। तब पुत्र-उत्तर विधेयन को विधान परियद के समझ प्रसुत्त विधा जायेगा किन्तु यदि विधान परियद विधेयन को द्वारावीहन करती है या ऐसे सभीतन करती है जो विधान समा को प्रमान्य है ता विधेयक को उस हालत में पारित माना जायेगा, जेता कि मृत्तत. विधान समा निर्माद किंग के परवाद मी कार्य प्रमान करियो की समा द्वारा हुकरे बार पारित होंने के परवाद मी वाई प्यान नहीं देती तो परियद ने समझ विधेयक प्रसुत्त करने के एक माह पत्रवात् विध्यक का दोनों द्वारा पारित माना जायेगा। धन सात्रास्थ विध्यकों के सव्यत्त विधान परियद, विधान-समा, हत्यत्त पारित करने के परवाद मी के प्रदेश का प्रमान परियद,

२—ियतीय कार्य —िवतीय नानतों में विचान परिपाद के प्रीवकार लगनग पान्य ग्रमा ने प्रनिकारों के नमान ही हैं। वित्त ग्रा कर विदेशक नो विधान-लायदा मस्तानिक नहीं विचा जा स्वत्ता है। विचान सभा में पारित होने के परवाद विदान विदेशक को विधान परिपाद के विचार विधान की निता सेवा जाना है। विचान परिपाद को घरने सुमावों को १४ दिनों में देते आरिंग प्रत्यादा वित्त विवेदन विचा विचान परिपाद के मुमावों के १४ दिन के प्रणान कानून वन जाया। समुख्येद १५६ (३) के प्रमुखार विधान सभा विधान परिपाद ने मुमावों को सस्वीहत कर सकती है।

३—वार्षे पालिका सम्बाची साहिता।—साधीय प्रणानी में सभीमण्डल का उत्तरवायित्व व्यवस्थापित समा के निवंति सबन के प्रति होना है। गर्याप उच्च सत्वत्व हार्य मानीमण्डल की भानीचान पर लेते से स्वादा (प्रमीसण्डल) को प्रणान हमीचा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तथापि इनका प्रमान नगष्य नहीं हो सक्ता। घतः पर्यापित्त (प्रमीसण्डल) के नियम के निवाद उच्च सहस में प्रमान सक्त के स्वयम ने नहत हुने जा सकते हैं। विधान परियद में सदस्य साईवितक महत्व के विषयों पर बहुन कर, मरलार का मार्थ दर्गन कर सहते हैं, कोशि यह सन्ध है कि विध्यान समा में मनीसण्डल ने सपने जुनत के सायार पर जल्ववाती किसी ऐते विध्यत्व को पारित करना दिवा हो जो नृदिपूर्ण है। चूलि निम्म सदस के सक्तों को जुनता में विधान परियद के सत्तर धारिक परिषक्त तथा मनुस्ती होने हैं, भाः सह स्वामाधिक है कि वहण का स्वाद परिषक तथा सनुस्ती इनने हैं। स्वाद स्वामाधिक है कि वहण का स्वाद परिषक को होता है। हम नशर विधान परियद सम्बन्ध रूप से नार्यपाला को प्रमत परिवक्त

राज्य विधान सभा

राज्य विद्यान मण्डल का निम्न सदन विद्यान समा है। यह राज्यों में जनता का प्रतिनिधि सदन है। इस दृष्टि से यह सधीय ससद के निम्न सदन लोकसमा के समान हैं।

सगठन--राज्य विधान सभा के सदस्यों की सख्या सबधित राज्य की जनसंख्या के सदर्भ मे ५०० से अधिक तथा ६० से कम नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक जन-गणना के पश्चात, प्रत्येक राज्य की विधान सभा के सदस्यों की सख्या को श्रीर राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों में विमाजन पूर्नीनधारित किया जाता है। अधिकतर निर्वाचन क्षेत्र एकल-सदस्य हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य निर्वाचित होता है । सदस्यो ना निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार पद्धति के धनुसार होता है। सविधान द्वारा श्रनुसूचित जातियो तथा ग्रादिम जातियो के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद ३३२ के अनुसार अनुसुचित जातियो तथा धनस्चित ग्रादिम जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के श्रमुपात में प्रत्येक राज्य की विधान समा में स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। श्रसम की विधान समा मे स्वायत्त ग्रादिम जिलो के प्रतिनिधियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये है। किसी भी राज्य का राज्यपाल विधान सभा में झारल भारतीय समाज के प्रतिनिधियों को मनोनीत बर सकता है, यदि उसके विचार में इस समाज को विधान समा मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। प्रारम्भ मे अनुसूचित जातियो, अनुसूचित ग्रादिम जातियो तथा ग्राग्ल भारतीय प्रतिनिधियो के लिए विधान सभा में स्थान सुरक्षित करने के सर्वैद्यानिक प्रावधान सर्विद्यान के लागू होने के समय से दस वर्ष के लिए थे किन्तु सविधान मे ब्राठवें संशोधन (संशोधन ब्रिधिनियम १६४६) द्वारा इसमे दस वर्षे की विद्धि की गई है।

विभिन्न राज्यों की विधान समाध्रों के सदस्यों की सख्या निम्नानुसार है :—

१--- प्रान्ध्य प्रदेश-२८७:

२----ग्रसम-१२६, ३---बिहार-३१८;

४--गुजरात-१६८,

५—हरियाणा~≈१:

६--जम्मु-वष्मीर-७४:

७--केरल-१३३;

५—-मध्यप्रदेश--२१६: ६--मद्रास-२३४:

१०--महाराष्ट्र-२७०:

```
११—मैसर-२१६;
१२—उडीसा–१४०:
१३--पजाब-१०४,
```

१४—राजस्यान-१६४;

१५--उत्तरप्रदेश-४२५:

१६--पश्चिम वगाल-२८०.

१७--दिल्ली-५६;

१८--हिमाचल प्रदेश-६०:

१६--मणिपूर-३०;

२०-- विपुरा-३०;

कार्यकाल-सामान्यत राज्य विधान समा का कार्यकाल ५ वर्ष का होता है। जब देश में सक्टकालीन स्थिति घोषित हो चुकी है तब विधान सभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए क्तिनी भी बार ससद के कानून द्वारा बढाया जा सकता है। परत सक्टकालीन उदयोषणा के समाप्त श्रीने पर किसी भी स्थिति में विधान सभा का कार्यकाल ६ माह से व्यविक समय तक नहीं बढाया जा सकता है। यदि विधान समा म भंशीमण्डल को बहमत का समर्थन समाप्त हो जाता है, तथा अन्य कोई राजनीतिक दल वैक्लिय सरकार निर्माण करने में असमर्थ है तो विधान समा को पाँच वर्ष पर्व भी राज्यपाल द्वारा भग किया जा सकता है।

विधान सभा के सदस्यों के लिए जो योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं वे निम्न-

लिखित हैं .--

(१) वह मारत का नागरिक हो।

(२) उसकी धायुकम से कम २५ वर्ष की हो ।

(३) ससदीय कानून द्वारा निर्धारित श्रन्थ योग्यताश्रो को पूरा करता हो ।

अनुच्छेद १७२ के अनुसार कोई व्यक्ति दोनो सदनो का सदस्य नहीं हो सकता

है, भौर न दो या दो से अधिक राज्य विधान मण्डलो का सदस्य हो सकता है। निम्नलिखित कारणों के बाधार पर कोई ब्यक्ति विधान सभा का सदस्य नही

हो सक्ताः ---

१—यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाम के पद पर है।

२--यदि वह न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया है।

३—यदि वह दीवालिया है।

 प्यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने किसी विदेशी नागरिकता को प्रहण कर लिया है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या मिवन रसन्त है।

५---यदि ससद के किसी कानून के अन्तर्गत अयोग्य है।

राज्य विभान समा ना निर्वाचन वयस्य मताधिवार वे सिद्धान्त पर सम्यन्त्र होता है। प्रवीत् प्रत्येव नायरिव वो जिसवी आयु २१ वर्ष से वम नही है, मत-दान वा अधिकार है। यदि वह उस क्षेत्र वा निवासी है, पागल नही है, और जिसवी अट्या अवैद्यानिव वार्य वे लिए दिण्डत न वियागया है।

विधान समा के दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं-(ग्र) ग्रध्यक्ष (स्पीकर),(ब)उपाध्यक्ष (डिस्टी स्पीकर) । प्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनो ना निर्वाचन विधान समा द्वारा होता है। प्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत करने का ग्रधिकार विधान-समा को है। इसम ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत करन के लिए १४ दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए । यदि विधान समा बहुमत से यह प्रस्ताव पारित वर देती है तो प्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्यत माना जायेगा। यदि श्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन की सदस्यता छोड देता है तो वह मध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर नही रहेगा । यदि ग्रध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष द्वारा ग्रध्यक्ष के कार्य किये जायेंगे। यदि ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनो ने पद रित्त हैं तो राज्यपाल ग्रस्थाई रूप से विधान सभा ने निसी भी सदस्य को उस पद पर नियुक्त करगा । यदि श्रध्यक्ष तथा उपा-ध्यक्ष दोनो सदन नी बैठन से अनुपस्थित हैं तो सदन के नियमों के अनुसार, वार्यवाहव श्रध्यक्ष सदन की कार्यवाही सचालित वरेगा। सदन की जिस बैटक मे ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने पदच्युत नरने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हो रहा है वह उस बैठक की श्रध्यक्षता नहीं करेगा, तथापि उसे सदन में उपस्थित रहने, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने तथा प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार है। प्राच्यक्ष तथा उपाच्यस को विधान मण्डल द्वारा पारित कानून के अन्तर्गत वेतन तथा मत्ते मिलते हैं। ये वेतन तथा मत्ते राज्य की सचित निधि मे से दिये जाते हैं। राज्य विधान समा के प्रध्यक्ष तथा कार्यों की स्थिति लोक्समा के श्रध्यक्ष के सद्म है। लोरसमा ने प्रध्यक्ष के समान विधान समा ने प्रध्यक्ष को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होना ग्रावश्यक है।

विधान समा के ग्रध्यक्ष ने निम्नलिखित नार्य हैं।

१—वह सदन की ग्रध्यक्षता करता है।

२ - सदन मे प्रश्नो तया प्रस्तावो के रखने के लिए उसकी धनुमति स्रावश्यक है।

३--- प्रध्यदा द्वारा हो सदन की कार्यवाहियों के लिए समय निर्धारित किया जाता है।

४--प्रत्यक्ष सदन ने नेता ने परामशं से सदन नी नार्यवाहियों का क्रम तथा मापणों ने लिए समयाविध निर्धारित नरता है।

१—वह सदन में शान्ति, व्यवस्था तथा अनुशासन बनाये रखता है स्रोर विसी सदस्य नो सदन के नियमों के उल्लंबन नरने पर उसे निय्नायित कर

भारतीय शासन भीर राजनीति

सकता है। सदन में गमीर श्रज्ञान्ति की स्थिति में ब्रध्यक्ष सदन को स्थिगत कर

282

सकता है। ६---प्रध्यक्ष सदन की विभिन्न समितियों के घ्रध्यक्षी की सूची सैपार करता

है। यह सदन की प्रवर एव ध्रत्य समितियों के लिए ग्रध्यक्ष मनीनीत करता है। ७—सदन के नियमों को व्याख्या करने का ग्रधिकार ग्रध्यक्ष को ही है। उसके निर्णयों को चुनौनी नहीं दी जा सकती।

म-- विसी विषेयक के सबध म कि वह विषेयक, वित्त विषेयक या साधारण विषेयक है अध्यान का निर्णय अन्तिम है !

सभीप म, विधान समा का अध्यान सदस्यों के प्रविकारों का सरहाक है। नि संदेह प्रध्यक्त की यह भूमितन इस पर निर्मार है कि वह प्रभने काणों मे स्वतंत्र क्या निप्पत्त है या नहीं। अध्यक्त के पद भी प्रतिष्ठा को बनाने पत्तने ना उत्तर-दायित नुष्ठ भाषा में स्वयं प्रध्यक्त को है, और बुद्ध माना में सदन के सदस्यों पर निर्मार नदता है। इस सन्दर्भ म, जहाँ तक प्रध्यक्त की पूमित्त का प्रस्त है, भारत के वई राज्यों ने प्रध्यक्तों ने पद भी प्रतिष्ठा को प्रपन्ने क्षानी व नायों से पहुले प्र यक्ता पहुँच्या। महाँ हाल हो के दो उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(१) दिसान्तर १६६६) में राज्याल भी पर्ववित्त ने नुस्तानी औ सजय मुनर्जी के मनी पण्डल नो बस्तीत कर दिया क्योंक की मुनर्जी ने विवान समा की बढ़क की जुलाने में भीर यह जात करने में कि बात्तव में जनके मनीमण्डल को विधान समा की बढ़क की जुलाने में भीर यह जात करने में कि बात्तव में जनके मनीमण्डल को विधान समा न हमूनत प्राप्त का वा नार्नी, हिम्मिन्याहर दिखाई । अवदार श्री पर्ववीर सो यह तथा कि भी मुकर्जी की सरकार कर जिल्होंने भी यो को कि पोश को मुख्य मा । भी मुकर्जी ममी मण्डल को वर्जात कर उन्होंने भी यो को कि पोश को मुख्य मनी नियुक्त किया। वरमान्तर का मुख्य समी नियुक्त किया। वरमन्तर कुमार स्टार्जी ने, किन्ती प्रथम में भी गी शी किया में भी के मान्तर की म

२—हुसरे मामले में पत्राव को विधान सम्मा के म्रध्यक्ष ने विधान समा का महस्तात् स्वर्गात कर दिवा, निकके पत्तक्षवर विधान समा द्वारा वर्गायक माम व्यवक पारित नहीं किया जा सका। इसका नतीजा यह इपा कि राज्यपाल ने स्थ्यादेश द्वारा विधान समा को बैठक मामित्र वर साध-व्यवक पारित करवाया। उस धवनस पर विधान समा को बैठक मामित्र वर साध-व्यवक पारित करवाया।

इन उदाहरणो से स्पष्ट हो जाता है कि कतियय मामलो म स्वय प्रध्यक्षी ने पद की प्रतिष्ठा पर अपने प्रवैधानिक कार्यों द्वारा धाषाठ पहुँचाया है। इसके विपरीत नई राज्यां नी विचान समाम्रो म मुख सदस्या ने प्रपंते प्रमद्भ व्यवहार से प्रप्यक्ष पद ना मनादर निया है। उदाहरण स्वरूप १९५६ म उत्तर प्रदेश विचान समा म विचान समा मार्गल नो प्रव्यक्ष ने प्रादेशानुसार समस्य पुनिस नी मदद निर्मा क्यों के स्वरूप समाम्रेश पुनिस नी मदद निर्मा क्यों ने स्वरूप समाम्रेश ने स्वरूप ने महार्य ने महार्य उन्ने सदन ने बाहर जाने ने प्रादेश ना उल्लंघन निया। इसी प्रनार सितम्बर १९५६ म पश्चिम नमा नी विचान समा म स्थिति ने यह रूप निया ति नायेस दल तथा विरोधी दन (साम्यवादी दन) ने सदस्यों ने भ्रससदीय माया ना प्रयोग नरते हुए एन स्तरे पत्र कु कु ने । व्यति-प्रसारण यन मत्री मण्डल ने सदस्यों ने प्रीरेप के गये। इसते प्रतिकृत पर्वे। कु स्तरे राज्य ने स्वरूप स्वरूप ने स्वर

राज्य विषान सभा के प्रधिकार-राज्य विधान समा ने विभिन्न कार्यों को चार श्रीणयो म विभाजित किया जा सकता है।

१--व्यवस्थापन सत्रधी कार्यं,

२--वित्तीय कार्यं,

३--नार्यपालिका तथा प्रशासन का नियन्त्रण तथा,

४---राष्ट्रपति ने निर्वाचन सबधी नार्य ।

१-प्यवस्थापन सबयो नार्थ-राज्य विधान समा का प्रमुख नार्थ विधि निर्माण करता है। राज्य विधान समा को राज्य मुत्री म उल्लिखित विषयो पर विधि निर्माण करते का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, राज्य विधान समा को समयतीं मुत्री का उल्लिखित विषयो पर विधि निर्माण करते का अधिकार है। विश्व सिंध विक्रिक्त विधान सम्बद्धों मुत्री से उल्लिखित विधान सम्बद्धों को समयतीं मुत्री मे उल्लिखित विधान सत्तव राज्य विधान मण्डली को समयतीं मुत्री मे उल्लिखित विधान पर नामून निर्माण करते का अधिकार है। विज्यु इस मुत्री म उल्लिखित विधान पर नामून निर्माण करते का अधिकार है। विज्यु इस मुत्री म उल्लिखित विधान पर निर्मात साथ का स्वान समा द्वारा निर्मात का नुत्र का स्थाप का स्वान का स्थाप क

संविधान द्वारा राज्य विधान मण्डलो पर विधि निर्माण के सबस मे निस्न-निक्षित सीमाएँ लगायी गई हैं।

- (क) कतिपय नातृन जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित निये गये हैं, बिना राष्ट्रपति की धनुमित ने बैच नहीं माने जा सनते हैं। उदाहरण करण धनुरदेद ३० के कतुसार समर्गत प्रविद्यहण करने की सिए बानृन अहुन्छेद १२४ के अहुन् सार समतर्थी हुन्यों से उन्हिलविज दिसी विषय पर पारित नृतृन निनन सपर, सबद द्वारा उसी विषय पर पारित, निशी नातृन से हैं। धनुन्छेद २०६ के धनु-सार ऐसे राज्य कानृन जिनने द्वारा ऐसी सम्पन्ति के प्रधानिवय पर नर सागू निया गया है, औ समद ने नानृन द्वारा सार्वजनिक जीवन के लिए धावम्यन नियारित नी है।
- (त) कडिएम विषयक राज्य विचान मण्डल के क्सी भी सदन म बिना राज्युपति की पूर्व सम्मति के प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अनुष्येद १०४ (ती) के सनुसार ऐसे विषयन जिनका उद्देश्य सार्वजनिक हिव में राज्य के सन्दर मा बाहर ब्यापार माणिज्य मा तेम-येन करने जी स्वतनता पर प्रतिचन्त सामान है।
- (ग) साधारणतया चारतीय सविचान में समवाद के सिद्धान्त नो समनाने के फलान्वरूप राज्य सुत्री में उल्लिबित विषयो पर नेवल राज्य विचान मण्डल ही विचि निर्माण कर सकते हैं। किन्तु सविचान मं उसके कविचय कारवाद मी हैं, विविध सम्वर्णत सथ सत्तर राज्य मुखी में बणित विषय पर कानून बना सकती है। वे परिविधिता हम प्रकार हैं।
- (१) मनुष्येद २४१ के बनुसार विष ससय का उच्च सदन (राज्य समा) दो रिहाई बहुमत के सामार पर यह प्रस्ताव पारित करती है कि दान्द्रीय हित भ पाज्य मुभी से उल्लिखित किसी विषय पर ससद को कानून बनाने ना परिकार होगा।
- (२) यदि देश में सकटकाशीन स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति ने की है तो अनुक्षेद २५० के अनुसार समद राज्य सूची में विशत किसी भी विषय पर कानून निर्माण कर सकती है।
- (३) यदि सभ के किसी राज्य की सरकार को सविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं बलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद १५६ के प्रन्तर्गत राज्य विधान मण्डस नो स्थमित कर उसकी शकितयाँ ससद में निहित कर सकता है।

पान्य विधान समा थे साधारण तथा पन विधेयक रोनो प्रस्तुन तिये जा यक्ते हैं। प्रस्तुत व्यवस्थापन सबसी शक्तियाँ विधान समा में ही निहित्त हैं। न्योंकि त्रीर एक विधेयक विधान समा द्वारा पार्टित हो जाना है परन्तु विधान परिषद (प्रदि राज्य में विधान परिषद हैं) उसका विरोध करती है तो विधान समा के उसी था नवे सन्न में विषेषक को पुनः पारित करने से तथा राज्यपाल की सहमति के पहचात् विषेपक को बानून का रूप प्राप्त हो जामेगा। यदि निषी विदेषक को राज्य समा द्वारा पारित कर विधान परिषद के विचार-विमां के किए मेंजा गया है प्रोर विधान परिषद के विचार-विमां के किए मेंजा गया है प्रोर विधान परिषद उस पर वोई निर्मयास्मव कार्यवाही नहीं करती है तो विधान समा उस विवेषक को विधान परिषद में प्रस्तुत करने की तिथि के तीन माह पश्चात् पुन पारित कर सकती है। तत्पप्रचात् विधेषक की विधान परिषद में समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, किन्तु यदि विधान परिषद विधेषक को प्रमाण के तो विधान परिषद विधेषक को प्रमाण के तो विधान परिषद विधेषक प्रमाण के तो विधान परिषद विधेषक प्रमाण के तो विधान परिषद विधेषक प्रमाण के तो विधान समा के प्रमाण के तो विधान समा के पारित किया था। यदि विधान-परिषद विधेषक पर पर विधान समा ने पारित किया था। यदि विधान-परिषद विधेषक पर विधान परिषद के तमक विधेषक प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह पश्चात्, विधान परिषद के तमक विधेषक प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह पश्चात्, विधान विधान परिषद के तमक विधेषक प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह पश्चात्, विधान विधेषक तमक विधेषक परित में विधान विधान परिषद के तमक विधेषक प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह पश्चात्, विधान विधेषक वे दोनो तको हारा पारित माना जावेगा।

२—विस्तीय सिन्तयाँ—विधान सभा को राज्य की सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था पर
रित्यवण रहता है। वित्त वियेपको को केवल विधान सभा में ही प्रस्तावित किया
जा सकता है। यदि विसी राज्य में विधान परिषद विज्ञ केवल सदन) भी है तो वित्तविपेयक विधान सभा में पारित होने के पक्षात् विधान परिपद के समक्ष प्रस्तुत
किया जाना चाहिये। परन्तु विधान-परिपद के वित्त विषेयक के प्राप्त होने के
भीवह दिनों में, उसको प्राप्त विधेयक वर विचान सह विधान समा को वापिस
मेजना होगा। यदि सस समयाविष में विधेयक के विधान समा को नापिस
करती है या विधेयक पर जो धापतियाँ उठाती है, वे विधान समा को नामय नहीं
है तो विधेयक को दोनो सदनो द्वारा पारित मान तिया जानेगा।

प्रत्येक दितीय वर्ष के धारम्म मे बाधित झाय-स्ययन को विद्यान समा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। स्यय के समस्त प्रस्तावों का विद्यान समा के समक्ष रक्षना धायस्य है उपन्य जिस स्थय को बाधिक धाय पर दिवाया गया है उस पर पर नेवल निवार विमर्ज हो सकता है, परन्तु मतदान नहीं किया जा सकता है। प्रस्ता कथा प्रस्ताव निवान समा मे समक्ष प्रनुदान मांगों के स्था मे प्रस्तुत निये जा सकते हैं। धाउतान सक्षी में पर मतदान करने का धायबार नेवल विद्यान समा में हो है। विद्यान समा अनुदान की राधि को धायबार नेवल विद्यान समा नो ही है। विद्यान समा अनुदान की राधि को धायबार विद्यान समा स्वाप्त के धायुसार निवी नी राज्य मे विना विद्यान समा की धायुसार कि कोई कर लागू नहीं निया जा सनवा है। प्रतएव राज्य के विद्या धान सवधी स्ववस्था पर राज्य विद्यान समा ना पूर्ण नियम्बण है।

(३) कार्यभातिका तथा प्रसातन पर नियत्रण—मारतीय संधीय सरकार की मित दाज्यों में औ ससदीय प्रणाली लागू नो गई है। दोनों स्तर पर वार्यभाविन । तथा प्रसातन की व्यवस्थापिन (निम्मतदन) के प्रति उत्तरदायों माना प्रथा राज्यों में नार्यभाविकाएँ (मशीमण्डल) प्रपले कार्यों तथा गीतियों के निए विधान समायों के प्रति उत्तरदायों हैं। सलदीय पदित की एक विशेषना यह है कि कार्यभाविका (मशीमण्डल) के सदस्य व्यवस्थापिना सना के सदस्य भी होते हैं, इस कारण, व्यवस्थापिका कार्यभाविका को, विस्तर सामानो द्वारा सरस्या पूर्वक तथा प्रतास प्रसाद करें हि तथा प्रतास प्रवास प्रवास तथा प्रतास प्रतास प्रवास तथा प्रवास तथा प्रवास तथा प्रवास तथा प्रवास तथा है।

प्राय जिन सायनी द्वारा विधान सभा कार्यपालिका को प्राप्त निषयण में रखती है, वे प्रक्त, पूरक प्रका, स्वापन, प्रस्ताव, तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सायन प्रियक्सास प्रस्ताव के रूप में हैं। सत्येप में राज्य विधान सभा कार्य-पालिका तथा प्रशासन पर नियमण रखकर, उसे स्वस्य तथा सक्षम बनाने में सहायक है।

राज्य विधान मण्डल के कार्यों ना बाय्ययन करते हुए यही उपयुक्त होगा कि राज्यों में विधि निर्माण का भी अध्ययन किया जाने। विधि-निर्माण-कार्य दो प्रकार के विभेषकों से सर्वाचित हैं। साधारण विधेषक तथा किन विभेषक।

(१) साधारण विधेयक-साधारण विधेयको को विधान मण्टल के किसी मी सदन मे प्रस्तुत किया जा सत्ता है। विधेयक के विधि के रूप मे पारित होंने के लिए प्रत्येक सदन में तीन वरणो से निकलना होता है। दूर तीन बरणो को सदन हारा विधेयक को तीन वाचनों के रूप में देखा जा सकता है।

विषेयक का प्रयम वायन तव होता है, जबकि सदम में उते प्रवृत्त किया जाता है। विषेयक का सदन में प्रवृत्त करता एक प्रीपशारित नगरें है। को सदस्य के बें सदस्य विषेयक को सदन में प्रवृत्त करता है, वह एक सिक्त भारण देता है। परिस्पारतुतार इस विवेयक पर कोई वहस नहीं होती है। यदि सदस्य विषेयक को प्रवृत्त करते के लिए स्पीइती प्रदत्त करता है तो को सदस्य विषेयक को प्रवृत्त कर रहां है के सुद्राद में मिर्चयक प्रवृत्त कर रहां है के सुद्राद कर रहां है के सुद्राद में मिर्चयक प्रवृत्त कर रहां है को सदस्य को विषयक प्रवृत्त कर का प्रवृत्त कर का प्रवृत्त कर का प्रवृत्त कर का प्रवृत्त करते के सदस्य को विषयक वर स्पर्यक्रियक प्रवृत्त करते के स्वत्ताव को विषयक प्रवृत्त करते के प्रवृत्त करते के प्रवृत्त करते के प्रवृत्त करते के स्वत्त विषयक है। इसके साम ही स्पीयी सदस्य में प्रपारत करता कर सम्बन्ध के स्वत्त के प्रवृत्त करता के प्रवृत्त करता के प्रवृत्त करता है। इसके साम ही स्पीयी सदस्य में प्रपारत करता कर सम्बन्ध है। स्वत्त साम ही स्वयंवक को प्रवृत्त वाता कार्योग। विषयक के स्वृत्त होने के सम्वत्त दसकी भावन स्वयंवक को प्रवृत्त करता वाता कार्योग।

मे प्रकाशित किया जाता है । यजट मे विद्येषक के प्रकाशित होने पर विद्येषक का प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है ।

द्वितीय याचन में निषेपन पर दो प्रकार से विचार विमर्श विया जाता है। सर्वप्रथम, निषेपक पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। यहाँ पर जिस सदस्य ने विषेपक का प्रवर्तन किया है, वह निम्नलिखिस निसी एक प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है।

(क) विषेयक पर तुरन्त या भविष्य में किसी तिथि से विचार-विमर्श ब्रारम्म किया जाये।

(ख) विघेयक को सदन की प्रवर सामित के समक्ष रखा जाये।

(ग) यदि राज्य में दो सदन हैं तो विधेयक को सदन की संयुक्त समिति के समक्ष रखा जाये, या।

(म) विधेयक को जनमत ज्ञात करने के लिए प्रसारित किया जाये । इस चरण मे विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य विधेयक के उद्देश्यो की स्पष्ट करता है, तथा विधेयक सबधी प्रावश्यक जानकारी सदन को देता है । बहुस विधेयक के सिद्धान्तो तक ही सीमित रहती है । इस स्तर पर विधेयक मे कोई सचीयन नहीं हो सकेगा ।

द्वितीय, विषेषक पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श किया जाता है। प्रयांत् विचयन के विमिन्न सख्दों, भागों, सनुसूचियों, तथा सगोपनो पर एक-एक कर विचार विमन्न स्था जायेगा। विचयक को सदन की प्रवर सीमिर्त के है। सदन के ग्राप्त सक्ता है। प्रवर समित्र के प्राप्त १० से १५ तक सदस्य होते है। सदन के ग्राप्त द्वारा समित्र वे प्रथम को मनोनीत किया जाता है। प्रवर समित्रि का कार्य विवेषक के विभिन्न सख्दों, तथा भागों का गहराई से परीक्षण करना है। इस सन्दर्भ मे समित्र आवश्यक कामजात तथा साध्य प्राप्त कर सकती है। समित्र वन व्यक्तियों के प्रतिनिध्यों को भी धामजित कर सकती है जिनके हित विधेयक से सवयित हैं, ग्रन्त मे समित्र का ग्रम्सण प्रमा प्रतिवेदन सदन के समल प्रस्तुत वरता है। तरम्बनात् सदन में विशेषक का मृतीय वाचन ग्रारम्म होगा।

लुताय वाचन-मह विधेयक का प्रतितम चरण कहनाता है। इस स्थिति मे यह प्रस्ताव रखा जाता है कि विधेयक को पारित किया जाये। साधारणाताय ह प्रस्ताव रखा जाता है कि विधेयक को पारित किया जाये। साधारणाताय स्था स्था में कोई ससीधन प्रस्तावित या प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। वहस इसी विषय पर सीमित रहती है कि विधेयक को स्थीकृत या प्रस्तीकृत किया जाये। जब विधेयक सरस द्वारा पारित हो जाता है, तो जनको दूसरे सदन में मेंज दिया जाता है, यदि राज्य में दूसरा सदन है। उससे जियेयक को पारित करने की प्रक्रिया पहले सदन की प्रक्रिया के समान ही होगी। दोनो सदनों से विधेयक के पारित होने के पश्चात्,

उसे राज्यपाल की सहमति के लिए फेज दिया जाता है। राज्यपाल की सहमति प्राप्त होने पर विषेपक को सरकारी मजट में राज्य विकान मज्दल के कानून के रूप में प्रकाशित किया जाता है। जिल विजेष विषेपकों के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, वे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने पर ही जानून वन मजेते।

(*) बिक्त सिर्धेयक—जिल विशेषक केवल राज्य विधान मण्डल के निचले सदन में ही प्रवृत किये जा सनते हैं, धर्मातृ किल विधेषण को विधान विरुद्ध महावित नहीं किया आयेगा। किसी प्रश्न के सबय में कि विधेषण विदेश विधेषण हैं। सिर्मा प्रशासन के सिर्धाय किये किये किये किया नियं हो प्रतिमान सामा के सम्प्रदा का निर्धेय हो प्रतिमान माना आयेगा। वित्त-विदेशक को विधान समा में राज्याना को पूर्वादुस्ति की विना प्रवृत नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक विशोव वर्ष राज्याना राज्य विधान समा के समा वार्षिण स्थान-व्यवक प्रस्तुत करनार्याणा । वार्षिक साम व्यवाक विवाद के समा वार्षिण साम व्यवाक विश्व के समा वार्षिण साम व्यवाक प्रयान का करना किया वार्षिय। अपूर्वदेह २०२ (३) के अनुसार विस्वनिविद्य राज्य का उल्लेख किया जाना वार्षिय। अपूर्वदेह २०२ (३) के अनुसार विस्वनिविद्य राज्य विद्या विद्य

१-—राज्यपाल के बेतन तथा भन्ने तथा उसके पद से सर्वायत धन्य व्यय ।

२--राज्य विधान समा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा विधान परिपद के आध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भते।

३--राज्य पर भारित ऋण सया उसका व्याज, निक्षेप निधि व्यय ।

३--राज्य पर भारत ऋण तथा उसका व्याज, निक्षप निध व्यय ४--जव्य न्यायालय के न्यायाधीण के बेतन तथा मने ।

५—वह पन राणि जो किसी स्यायालय या विवायन व्यपिकरण के निर्णय या डिकी के अस्तर्गत देना है।

६—प्रस्य कोई व्यय जो सविधान या राज्य सविधान मण्डल द्वारा इस निधि
में समावेशित क्या पोणित किया गया है। इसके प्रतिरिक्त सविधान द्वारा निम्न निषित क्या राज्य सवित निधि में से किये जायेंगे।

१—मनुःकेद २२६ (३) के अनुसार उच्च न्यासालय के प्रमासकीय व्या जिसमे उच्च न्यायालय के प्रधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, ससे एवं सेवा-निवृति भी सन्मिलित हैं।

२--- अनुच्छेद ३२२ के अनुसार राज्य लोक सेवा धायोग द्वारा किये गये व्यय सर्वाधत पन राणि जिससे आयोग के कर्मचारियों के वेतन, मत्ते और सेवा-वृति भी ग्रामिल है।

भी वामिल है।

यद्यपि राज्य की सचित निधि में उल्लिखित काय पर राज्य विधान मण्डल में

कादान नहीं किया जा सकता है। परस्त राज्य विधान समा में सचित निधि से

उल्लिखित व्यय के प्रनुमानो पर बहुत की जासकती है। प्रत्य व्यय को विधार समा में प्रतुदान को मौनो के रूप में प्रस्तुज किया जाता है। विधार समा को प्रनुदान की मौनो पर विभार विमय गरने और इनको स्वीहत या घरवीहत या कम करने का प्रधिकार है। तथापि विधान समा को नये प्रमुदान के प्रस्ताव कराने का या प्रनुदान की मौनो में वृद्धि करने का प्रधिकार नहीं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष वे प्रारम्भ मे राज्य विधान समा मे वित्त मधी वार्षित प्राय व्यवन प्रस्तुत करता है। मुख दिनो तक इस पर यहत भी जाती है। विधान समा वे सदस्यों नो इस समय सरहार तो नीतियों ने परीशण वर्षा या प्रवसर मी प्राप्त होता है।

तत्पत्रचात् घनुदानो की माग पर मतदान क्या जाता है। प्रत्येन विभाग थे तिए सबिपत गन्नी द्वारा पृथक अनुदान की भौग की जाती है। यह स्वामाधित है कि यह एक ऐसा अवसर है जब विधान सभा के सदस्य विभाग की नीतियो तथा वार्यों का सूक्ष्म परीक्षण करते हैं। कोई भी सदस्य अनुदान की मांग को यम या अस्वीष्टत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

धनुदान की मागो पर मतदान होने ने पश्चात् राज्य विधान समा द्वारा स्वीहत मांगो तथा सचित निषि में निहित क्या के भाषार पर वार्षिक विनियोग विपेयन कमाणा जाता है। इस वियेवन को विधान समा में प्रस्तुत किया जाता है। इस वियेवन को विधान समा में प्रस्तुत किया जाता है। इस वियेवन में किया जाता परिवर्तन करने का कोई सबोधन प्रस्तावित हो निष्या जा सकता है। विनियोग वियेयक को मानून निर्माण प्रक्रिया के विमिन्न बरलों से सफतता पूर्वक निक्वने पर विधान समा द्वारा पार्रित माना जायेना और प्रदि उक्त राज्य में विधान परिषद (उच्च तदन) है तो विधान समा के प्रस्था हारा उक्त वियेवक को पित वियेवन प्रमाणित करके विधान परिषद के विधान समा के प्रस्था हारा उक्त वियेवक को पित वियेवन प्रमाणित करके विधान परिषद के विधान समा के

ग्रन्त में विधान समा द्वारा वित्त विधेयन पारित किया जाता है। वित्त विषेयक पारित करने का उद्देश्य राज्य की ग्राय के उन साधनो को निर्धारित वरना है, जिनवे द्वारा भागामी वर्ष के ब्यय वे लिए प्रावधान किया जा सवे।

राज्य-म्यायपालिका

मारतीय सघ के प्रत्येक राज्य में सिंवधान के धन्तर्यत एक उच्च ग्यासानय को व्यवस्था की गई है। सिंवधान के धन्तर्यत सबद की यह भी धींपकार है कि दो यो से धिक राज्यों के सिंव एक हो उच्च व्यायानय की स्थापना करें। राज्य की न्यायिक प्रणानी में उच्च न्यायानय का स्थान शिवद पर है।

उच्च घ्यायातय का सगडन-प्रत्येक उच्च ग्यायातय में एक मुख्य ग्याया-स्वार क्षि क्षण ग्यायाभीच होते हैं, विजनी सच्या राष्ट्रपति एक धारिक हारा निर्माणित रुता है। मुक्त ग्यायाभीच निर्मुक्त राष्ट्रपति मारत के सर्वोच्च ग्यायातय ने मुख्य ग्यायाभिचति तथा सर्वापत राज्य के राज्यपत्त के परागानित्वार करता है। धम्य न्यायाभीको नी निर्मुण्ति राष्ट्रपति राज्य उच्च ग्यायातक के प्रकृत ग्यायाभीक ने प्रयाननीवार करता है।

स्वित्यान सक्षेपन प्रारंगिनय १६४६ द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्यागे, प्रतिरक्ति स्वा कार्यवाहक न्यायाधीको की निवृक्ति करने ना प्रधिकार दिया गया है। प्रतिरक्ति न्यायाधीको की निवृक्ति राष्ट्रपति द्वारा दो वर्ष से प्रधिक समय के निवृत्य नहीं की जा तकती है। दिसी स्वाथी न्यायाधीय नी प्रपृत्तिकार्ति में, या जब सह न्यायाधीय, नुक्त न्यायाधीय के पद पर कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति उक्ते स्थान पर कार्यवाहक न्यायाधीय निवृक्ति कर सकता है।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ-१-मारत का उसे नागरिक होना चाहिये।

२—मारत में किसी न्यायायिक पद पर कम से कम दस वर्ष तक रहा हो या उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम दस वर्ष तक वकालत करने का भन्मव हो।

कार्यकाल-मूनत सविधान से यह प्रावधान या कि एक न्यायाधीश धपने पर पर ६० वर्ष की आधु तक रहेला। परन्तु सविधान के परहतु सक्षेत्रक (सविधान कार्यक्त स्पितित्वन १६६३) द्वारा एक आधु से वृद्धि नर रो गयी है। यह यह आधु ६२ वर्ष कर दी गयी है। यदि सबार दो तिहाई बहुमत से निसी न्यायाधीश के विरद्ध उनके दुरानार या सक्षमता के कारण प्रस्तान करती है तो राष्ट्रपति उक्न न्यायाघीश को पदव्युत करेगा । नोई भी न्यायाघीश राष्ट्रपति को ग्रपना त्याग-पत्र प्रस्तुन कर पद-स्थाग सकता है ।

न्यायाघीमों के बेतन—उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाघीम की चार हजार एमंद्रे तथा प्रत्य न्यायाघीमों को तीन हजार पांच सी रुपये प्रतिमाह बेतन दिया जाता है । ससद विधि द्वारा न्यायाघीमों के मते छुद्दियों तथा सेवा-बृत्ति सबधी नियम निर्मारित नरती है। त्यायाघीमों के कार्यका में उनके वेतन, मते आदि के कटीनी नहीं को जा सकती है। हनके वेतन मत्ती का व्यय राज्य-सचित निधि में से होने के चारण न्यायाघीम स्वतन्ता पूर्वक प्रपोन का व्यय राज्य-सचित निधि में से होने के चारण न्यायाघीम स्वतन्ता पूर्वक प्रपोन का व्यय राज्य-सचित निधि में उत्तिनित विध्ययो पर मतदान नहीं हो सकता है। प्रत्युत ससद तथा राज्य विधान समा न्यायाघीमों के वेतन में कमी नहीं कर सकती है। तथापि, विसीय सरुट काल की स्थिति में न्यायाघीमों के वेतन में कमी नेति नरीनों की जा सकती है।

न्यायाधीशो की स्वतत्रता-उत्तम न्यायिक प्रशासन के लिए यह अति आव-

, श्यक है कि न्यायाधीश श्रपने नार्यों को स्वतत्रता पूर्वक कर सकें।

सर्विवान में उच्च न्यायालयों के न्यायावीशों नी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान विये गये हैं। वे निम्नलिखित हैं।

सर्वश्रयम, नियुनित नी दृष्टि से न्यायाधीशो की नियुनित सविधान द्वारा निर्मारित योध्यतानुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायासय के मुख्य न्यायाधीय नी नियुनित राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायासय के मुख्य न्यायाधि-पति के परामर्श पर करता है, तथा श्रन्य न्यायाधीशो की नियुनित उच्च न्यायासय ने मुदर न्यायाधीश के परामर्श द्वारा नरता है।

द्वितीय, नार्यकाल की दृष्टि से न्यायाधीको को सिवधान के अनुसार ६२ वर्ष भी आयु तक अपने पद पर रहने ना अधिकार है। सिवधान में स्पष्ट रूप से दो कारणों का उल्लेख है, जिनने आधार पर ही क्यों ग्यायाधीय को परच्युत किया जा सनता है। इन कारणों के आधार पर राष्ट्रपति अपने बादेशों द्वारा क्यों न्यायाधीय नो परच्युत कर सकता है किन्तु राष्ट्रपति का आदेश तसद द्वारा दो तिहार्ष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर आधारित होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि न तो राष्ट्रपति नो भीर न ही ससद को निसी न्यायाधीश नो परच्युत नरने ना एकाधिकार है।

तृतीय, न्यायाघीशो के वेतन सविषान द्वारा निर्धारित है, धीर इनका ध्याय राज्य-सवित निषि पर मारित है। इसके प्रतिरिक्त, न्यायाघीशो के मसे तथा दृष्ट्रियों भीर सेवा-वृत्ति सवयी प्रियकार ससदीय कानून द्वारा निर्धारित निये जाते हैं, भीर उनके कार्यकाल मे उनकी हानि की दृष्टि से इनमें कोई परिवर्तन नहीं दिया जा सकता है। चतुर्व, राज्य उज्च-म्यामालय के प्रशासकीय व्यय भी राज्य सचित-निधि पर भारित हैं।

उपर्युक्त तथ्यो के भ्राधार पर यह कहा जा सकता है कि वे भ्रपने वार्य क्षेत्र मे पूर्णत स्वनत्र हैं।

उच्च न्यायालयो के कार्य तथा क्षेत्राधिकार

साधारणन एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वाधित राज्य तक सीमित है। घरन्तु धविधान के सात्र सं सहोयन से (सहोधन ध्रायिन्यस १६४६) दो या यो स ध्रायिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है सीद दस न्यायालय के सेवाधिकार को सर्वाधित साथिय भू माग में सागू दिया जा सकता है। १६४६ के सहोथन प्रायिन्यम के धन्तर्गत नजकता उच्च न्यायालय के सेवाधिकार को सण्डमान-निनोधार द्वीपों के सबध में, केतर उच्च न्यायालय केरियाल्यार को स्वत्याद, निर्माव्य तथा समीन योगों हमो व्योव होणे के सबस में तथा प्रवाद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को दिल्ली के सबस में सागू दिया गया। १६६० में दिल्ली के लिए एमक उच्च न्यायालय स्थापित निया गया। उच्च न्यायालयों के प्रीवादक के अंत्राधिकार है।

१--प्रारम्भिकतया २--अपीलीय।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार—(क) उच्च न्यायालयो को केवल निम्नलिखित विषयों के सब्ब में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है।

१--जल सेना विमाग (एडमिरलटी)

१—नव समा विमान (एडामरलटा

२—वसीयन

२—वसायत,

३--विवाह सवधी,

४--न्यायालय अपमान सथा,

५--कम्पनी-कान्न ।

(क) परन्तु कवस्ता, बन्धर्व तमा महास के उच्च व्यायासयों को प्रथमे क्षेत्रों में योवनी तथा फीजदारी मामनो में प्रारम्भिक सेत्राधिकार प्राप्त हैं। सित्रपान कर्युव्यत् २१% के प्रयुक्त उच्च व्यायासय का बेताधिकार बैहा ही होगा, जैदा कि ११% में सिव्यान सार्ग्न होने के पूर्व का कर्यायास्त्र के स्वाप्त सार्ग्न होने के पूर्व का स्वाप्त सार्ग्न होने के पूर्व का स्वाप्त सार्ग्न सार्ग्न स्वाप्त सार्ग्न स्वाप्त सार्ग्न स्वाप्त सार्ग्न स्वाप्त सार्ग्न स्वाप्त स्वाप्त सार्ग्न स्वाप्त स्वाप्

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार इत न्यायालयो को निक्नलिखित मामलो मे प्राप्त याः (१) ऐसे दीवानी मुकदमे इनमे प्रारम्म किये जा सकते थे जिनका मूल्य दो. हजार रुपये से प्रथिक होता था।

(२) ऐसे फोअदारी मुकदमें जो प्रेसीडेन्सी मजिल्ट्रेटो द्वारा मेजे जाते थे, इनके द्वारा सुने जा सकते थे। मारतीय सविधान के अन्तर्गत इस स्थिति में कोई परि-वर्तन नहीं किया गया है। अतएव इन तीन उच्च न्यायालयों को उपर्युक्त मामली, में प्रारम्भिक अधिकार प्राप्त है।

 (ग) मारतीय सविवान के अनुच्छेद २२५ के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को राजस्व तथा उसकी वसूली से सब्धित प्रकरणों को प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार में

सुनने का ग्रश्निकार मी दिया गया है।

(प) सिवधान के अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों के मूल अधि-कारों के सरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदिश या लेख लागू करने के अधिकार प्राप्त हैं। विभिन्न लेख इस प्रकार के हैं — (१) बन्दी प्रत्यक्षीकरण, (२) परमा-देश, (३) प्रतिपेग, (४) उदयग, (४) अधिकार-पुच्छा।

उच्च न्यायालय द्वारा ये लेख अपने क्षेत्राधिकार से सवधित राज्य में किसी भी व्यक्ति, मता या सरकार ने विषट जारी किये जा सकते हैं।

ध्योतीय क्षेत्राधिकार—प्रशीतीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायासय को दीवानी, फोजदारी तथा मालगुजारी मुरुदमो पर निम्न श्रेणी के न्यायासयो के निर्णय के विरुद्ध घरील में स्वीकार करने का प्रीषकार है। इसके प्रतिरिक्त प्राय-कर, विक्री-कर, आदि प्रकरणो के निए स्वाधित न्यायाधिकरणो के निर्णयो के विरुद्ध उच्च न्यायालयों को प्रशीत की जा सकती है।

सविधान के प्रन्तर्गत उच्च न्यामालयों को प्रन्य भी कुछ कार्य सीपे गये हैं जो निम्नलिखित हैं।

प्रनुच्छेद २२७ के प्रमुत्तार प्रयोक्षण का प्रियकार प्रदान किया गया है। इस प्रियकार के सन्दर्ग में उच्च न्यायानय को प्रपत्ने प्रधीनस्य न्यायानयो तथा न्यायापिकरणो का (सैनिक-न्यायापिकरणो को छोडकर) प्रधीक्षण (निरीक्षण), करने का प्रसिचार है। इस प्रियकार के प्रन्तर्गत उच्च न्यायालय निम्न कार्य कर सकता है।

१--उच्च न्यायालय धपने भ्रयोन न्यायालय के कार्यों का विवरण उससे मांग सकता है।

२---उच्च न्यायालय प्रपने भ्रघीन न्यायालय की कार्य प्रणाली को निर्धारित करने के लिए नियम बना सकता है।

१ - उच्च न्यायालय प्रपने प्रधीन न्यायालयों के प्रमिलेखो तथा कागजाती के रखने के लिए प्रादेश दे सकता है। Y---उच्च न्यायालय किमी प्रकरण की एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय की विचार या निर्णय के लिए मेज सकता है।

५---उच्च न्यायातय अपने अधीन त्यायातय म छेरिक, तिपिक तया अप अधिकारियो तथा वकील और अमिनायको के शुरू विश्वित कर मुकता है।

भनुन्धेद २२६ ने मनुसार यदि उन्ह न्यावातय ने नित्रया हो जाता है नि मामान में नित्र ने नी के प्यावातय ने समझ ऐसा अरंग्य है जिसमें सिवाया ने व्याव्या के तिए भी नान्ती प्रकार निर्देश है वो वह स्वय उत्त प्रकरण पर स्थिपर करके निर्णय दे सकता है, या उक्त कानूनी प्रकार पर निर्णय कर प्रकार निर्णय की एक प्रति स्थीनस्य न्यावायय की मेनेया। ऐसी स्थिति में धर्मीनस्य न्यायावय प्रकार निर्णय कर न्यावायय की मेरीया। ऐसी स्थिति में धर्मीनस्य न्यायावय

मारत के सर्वोड्य व्यायातय के समान प्रत्येक राज्य ना उच्च व्यायातय भी एक प्रतितेल व्यायातय है। एक भनिलेख व्यायातय के नाते उच्च व्यायातय के प्रमिलेख व्यय व्यायालयों के समण साध्य के रण म प्रस्तुत दिय जा सकते हैं। किसी व्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उच्च व्यायालय के भनिसेसी की भैया-निकता पर सहंद्र नहीं व्यवस दिया जा सकता है।

उल्ल स्थापातव के भिषकारियों तथा वर्मवारियों की नियुक्ति मुख्य न्याया-शीश या उसके द्वारा भिष्ठत कोई सन्य न्यायाभीश करता है। उच्च न्यायानत के कर्मवारियों को तेना वर्तों का निर्धारण मुख्य न्यायाभीश ही वरता है। यरन्तु इनके बेतन मसे, पवनश्य तथा सेवा वृत्ति के सबब में निवसों के लिए राज्यपान की स्वोकृति वावश्यक है।

सविधान के मतुष्टेद २३५ के मनुसार जिला न्यायालयो और उनने अधी-तस्य न्यायालयो के नियंत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय मे तिहित हैं।

मनुष्येद २,६ के मनुषार न्याधिक वर्दों को यो श्रीवयों में रखा नया है, की सनिविद्य हैं (!)-ज्य क्षेत्रों में जो वर रहे तर हैं हैं वह प्रवार हैं हैं कि सा वरार हैं के हिंदा हैं कि सा वरार हैं के हिंदा है जिस से अपने हैं कि सा वरार हैं के हिंदा है कि सा वरार हैं के हिंदा है कि सा वर्दा है के सा वर्दा है कि उचकी कम से के मा ता वर्दा वर्दा है कि उचकी कम से कम सात वर्दा वर्दा करा है कि उचकी कम से कम सात वर्दा वर्दा करा है कि उचकी कम से कम सात वर्दा वर्दा करा है कि उचकी कम से कम सात वर्दा वर्दा करा है कि उचकी कम से कम सात वर्दा वर्दा करा है कि उचकी कम से कम सात वर्दा वर्दा करा है कि उचकी कम से कम सात वर्दा वर्दा करा है कि उचकी कम से कम सात वर्दा वर्दा करा है कि उचकी कम से कम सात वर्दा वर्दा करा है कि उचकी कम से कम सात वर्दा वर्दा हो हो पा उचका है कि उचकी कम से कम सात वर्दा वर्दा हो हो पा उचका हो है।

(n) निम्न श्रेणी में जो पद रखें गये हैं, वे समस्त न्यायिक पद जो जिला न्यायाधीय, सत्र न्यायाचीय, दीवानी न्यायालय के न्यायाधीय, सहायक न्याया- धीक्ष, तथा सत्र न्यायाधीय, लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीय एव मुख्य प्रेमीडेन्सी न्यायाधीय के पदो से निम्न स्तर के हैं। इस दूसरी श्रेणी म न्यायिक पदो पर नियुक्ति राज्यपाल राज्य लोक सेवा श्रायोग तथा सवधित राज्य के उच्च न्याया-स्त्रय के परामर्थ पर करता है।

उच्च न्यायालय के ब्रधीनस्य न्यायालय

राज्य में उच्च न्यायालय के ब्राधीन तीन प्रकार के न्यायालय हैं। वे इस प्रकार हैं —

१--फौजदारी न्यायालय २-दीवानी न्यायालय, तथा ३-मालगुजारी न्याया-लय ।

१—फीजदारी त्यायालय—प्रत्येक जिले में उच्च श्रेणी का फीजदारी त्याया-सन्द सन्न (श्रेणस्) न्यायालय है। इस त्यायालय के त्यायाणीय की सन-त्याया-पीश कहते है। सन-त्यायाणीश की सहायता के लिए सहायक सन-त्यायाणीय होते हैं। सन-त्यायाणीय के प्रधीन तीन प्रकार के त्यायाणीय होते हैं। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट तथा हुतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट ।

प्रथम श्रेगी मिनिस्ट्रेट दो वर्ष तक का कारावास भीर एक हजार रुपये ना दण्ड दे सतता है। द्वितीय श्रेणी का मिनिस्ट्रेट छे. माह का कारावास भीर तीन सो रुपये का दण्ड दे सकता है, धोर तृतीय श्रेणी का मिन्द्रेट एक माह का नारावास तथा पंचात रुपये का दण्ड दे सकता है। सन-न्यायाधीय प्रथम श्रेणी के मिनिस्ट्रेट के निर्णयों के विरुद्ध प्रयोज सुनता है। सन-न्यायाधीय को मृत्यु दण्ड मिनिस्ट्रेट के निर्णयों के विरुद्ध प्रयोज सुनता है। सन-न्यायाधीय को मृत्यु दण्ड मानिस्ट्रेट के निर्णयों के विरुद्ध प्रयोज सुनता है। सन-न्यायाधीय को मृत्यु दण्ड मानिस्ट्रेट के निर्णयों के विरुद्ध प्रयोज सुनता है। सन-न्यायाधीय को मृत्यु दण्ड स्थायाधीय को स्थाय स्थाय का स्थाय स्याय स्थाय स्याय स्थाय स्य

२—दीवानी न्यायालय—प्रत्येक जिले मे उच्च श्रेणी वा दीवानी न्यायालय, जिला न्यायाणीय का न्यायालय (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) होता है। वस्तुस्थिति यह है कि एक ही व्यक्तिसप्त (सिक्स) न्यायाणीय तथा जिला न्यायाणीय का पद प्रहुण किये रहता है। कोजवारी प्रकरणों को मुनते समय वह सत्र-न्यायाणीय कहा जाता है। परन्तु जब दीवानी प्रकरणों को मुनत है तब उसे जिला-न्यायाणीय कहा जाता है। जिला-न्यायाणीय के न्यायालय को दीवानी मामलों मे प्रारम्भिक तथा क्रणीकीय होनी प्रवाद के सेवाणिकार प्राप्त हैं। प्रीर विषय कानूनों के सवय में, जैसे—उत्तर्पाकार कानून, प्रमामावक और प्रतिपास्य कानून, विवाद-विच्छेद कानून तथा प्राप्तीय दिवालियां कानून के सेवाणिकार कानून सेवाह-विच्छेद कानून तथा प्राप्तीय दिवालियां कानून के सेवाणिकार कानून सेवाह-विच्छेद कानून तथा प्राप्तीय दिवालियां कानून के सेवाणिकार कानून के सेवाणिकार कानून के सेवाणिकार कानून के सेवाणिकार कानून के सामकार सेवाणी मामलों में सेवाणिकार रखने वाले प्रमीनस्य न्यायालयों के निरीक्षण करने का प्राप्तकार है।

जिला त्यापाधीस के त्यायालय के नीचे सिविल जब, मुखिक, लघुनाद त्याया-लय, तथा पदायती प्रदालते होती हैं।

=-मालगुनारी त्यायालय-देलचु बोई राज्य में सबसे उच्च मालगुनारी

२—मालगुनारी न्यायालय —रेवन्यु बीई राज्य मे सबसे उच्च मालगुनारी न्यायालय होता है। इसके द्वारा कमिननरी के निर्माण के विरुद्ध प्रणील मुनी जातो है। कमिननर के प्रणीन, निलाणिश वसा सहायन निलाणिश के न्यायालय होते हैं, और इनके प्रणीन तहसीनदार तथा नाणव तहसीनदार होते हैं। इस न्यायालय हारा भूमि या समारा सबयी प्रकरणी पर निर्णय दिया जाता है।

संघ तथा राज्य-संबध

भारतीय सविधान ने लागू होने ने पूर्व मारत सरनार प्रधिनियम १६३४ ने अन्तर्यंत मारत मे त्रिटिश राज्य ने दौरान, तीन प्रनार नी राजनीतिन इनाइसी भी। प्रयम—न्यारह ब्रिटिश मारतीय प्रान्त थे। इनने नाम इस प्रनार हैं—मद्रास, स्वन्ध, त्याल, ससम, उत्तरप्रदेश, पजाव, उत्तर-पिचमी सीमानतीं प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, सिन्य तथा उड़ीसा। प्रत्यक ब्रिटिश मारतीय प्रान्त ना प्रशासनीय प्रमुत प्र-राज्यपात होता था।

तृतीय—६ मुल्य प्रायुक्त प्रान्त थे । उनके नाम इस प्रकार हैं—'विटिश वलूचि-स्तान, दिल्ली, प्रजमेर-मेरवाडा, बुर्ग, ग्रण्डमान निकोबार द्वीप धौर पन्त-पिपलोटा ।

भारतीय सविधान के अनुच्छेद ३ के अनुसार भारत एक सम है। जब १६५० में सविधान लागू निया गया तब मूलतः चार प्रकार की राजनीतिक इकाइयो की स्थापना की गई। ये निम्निलिखित हैं।

१—माग 'क' वे राज्य प्रसम, घोध्र, बिहार, बस्बई, मध्यप्रदेश, मद्रात, उद्देशा, पजाब, उत्तरप्रदेश, परिचम बागल । बाहतद में ये राज्य पूर्व के प्रिटिश मारतीय प्रान्त थे । मारतीय प्रसिचान के प्रन्तगैत इनमें से प्रत्येच राज्य कर प्रमासतीय प्रमुख राज्य कर प्रमासतीय प्रमुख राज्य कर प्रमासतीय प्रमुख राज्यपात होता था ।

२—माग 'त' के राज्य—हैदराबाद, जम्मू कश्मीद, मध्य-भारत, मैसूर, पेन्सू, राज्यस्थान, सीराप्ट्र, त्रायणकोर कीचीन थे। सिवधान लागू होने से पूर्व ये राज्य देती रियासतो में रूप में थे। भारतीय सविधान ने धन्तमंत भाग 'त' के प्रत्येक राज्य का प्रशासकीय प्रमुख राज्य मा प्रशासकीय प्रमुख राज्य का प्रशासकीय प्रमुख राज्य मा

३—माग 'ग' वे राज्य—'ग्रजमेर, मोपाल, वुर्गे, हिमाचल-प्रदेश, बच्छ, मणिपुर, प्रिपुरा, विच्छ्य प्रदेश।

४—मार्ग 'घ' के राज्य—घण्डमान-निकोबार द्वीप । मार्ग 'ग' सथा 'प' ने राज्य केन्द्रीय प्रणासित राज्य पे । केन्द्र सरकार द्वारा इनका प्रणासन

उपराज्यात या मुख्य-मापुल या किसी राज्य सरकार ने माध्यम से किया अलगामा।

कद मारनीय सविधान का निर्माण हो रहा था तब समिधान समा के मध्यक्ष द्वारा एक समिति निमृत्ति की गई। उस समिति की 'दर-समिति' की सका दी गई थी। इस समिति को यह कार्य सौंपा गया था कि सारत में राज्यों की मापा के माबार पर पुनर्गठन के प्रश्न की जीव करे । १६४= में 'दर-सॉर्मान' ने मापा ने माभार पर राज्य के पुतर्गेठन ने किरुद्ध अपना अनिवेदन दिया। त पश्चान् काग्रेस ने १९४८ में अपने जयपुर अधिदेशन में एक समिनि की नियुक्ति की, जिसमे सीन सदस्य थ, पर जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लममाई पटेल, तथा डॉ॰ पट्टामि सीवारामेंबा। भपने प्रतिवेदन में १६४६ में इस समिति ने कहा 'समिति राज्यों ने मुनर्गंडन ने लिए आदा के झायार की स्वीकृत करनी है।' किन्तु राज्यों का पुनर्गठन उस समय उपदुत्त नहीं या, तथापि पारस्परिक समभौनी के आधार पर निर्धाप्ति क्षेत्रों में नमें राज्यों ना निर्माण किया जाना समय था। इस भाषार पर दक्षिण भारत में भाधा क्षेत्र में तमे राज्य का अपापना वास्ता संसद था। परन्तु कुछ नारणवर, जैसे-'राज्यानी' के प्रश्न पर कोई निश्चित समनीता शही हो सबा और आधा के निर्माण को स्थापन कर दिया गया। परन्तु जनना के भान्दोलन तथा भी राष्ट्रलू के उपवास करने के फलस्परूप मृत्यु हो जान पर भाष्ट्र अदेश की स्थापना १६५३ में हुई ।

अदश पा स्थापना १८८२ म हुद। १९५२ में क्षाक्रप्रदेश की स्थापना होने से भाषा के धाषार पर राज्यों के

भुवरंकन के सान्दोक्तन को सकित गति मिली।

दिवानस २२, १६४६, को घपान मानी प० नेहरू के सहद से पोपना को कि
राज्यों ने पुनर्गकन के प्रान्त को निर्मालना पूर्वक कोनते के लिए एक उन्च स्तरीय
सामोग नियुक्त निया जातेगा। तत्त्वत्वान् होना वस्त्यीय राज्य पुनर्गकन सामोग नियुक्त निया गता। उत्त हस्त्याम सूनक इस मामोग के सम्यान थे। सी तैयत क्षत्रकासो तथा सरवार के एमक पोणकर एस सामोग के सम्यान थे। सी तैयत के। राज्य पुनर्गकन सामोग ने प्रारंग सरकार को सम्यान प्राप्त कर के स्तर्य को पहना १११४ को प्रस्तुत निया। मामोग के प्राप्त में प्राप्त मानत सम्य की एकना तथा एक पाड़ीयमा पर विशेष क्य के जन निया। सामोग के एक मानत सम्य की एकना तथा एक पाड़ीयमा पर विशेष क्य के जन निया। सामोग के एक मानत स्त्रम का स्त्रम को स्त्रम स्त्रम स्त्रम स्त्रम स्त्रम स्त्रम स्त्रम स्त्रम को स्त्रम स्

१—विभिन्न राज्य, सम की इकाइयों के रूप से।

२—वे भू-माग जो केन्द्र द्वारा मासित होगे।

राज्य पुनर्गठन म्रायोग के विभिन्न सुक्तावो पर राज्य पुनर्गठन म्रायिनियम १९४६ तथा सवियान सवीयन अधिनियम (सातवौ सशीयन) ससद द्वारा पारित जिया गया।

राज्य पुनर्पठन ग्राधिनियम १९४६ तथा सविधान सभोधन ग्राधिनियम १९४६ (सातवें सभोधन) के ग्रन्तगंत मारत सथ में राज्यों ना पुनर्पठन करने ने फलस्व-रूप १४ राज्यों तथा ६ सधीय भू-मागों नी स्थापना नी गई। य १४ राज्य निम्नितिखित थे .—

१—धान्ध्रप्रदेश, २-प्रसम, ३-विहार, ४-वन्धई, १-वेरस, ६-मध्यप्रदेश, ७-मद्रास, ६-मैसूर, ६-उडीसा, १०-पजाव, ११-राजस्थान, १२-उत्तरप्रदेश, १३-पश्चिम बनाल, तथा १४- जम्मु-कस्मीर ।

इनके प्रतिरिक्त ६ सधीय भू-माग इस प्रकार थे।

१—दिल्ली, २-हिमाचल प्रदेश, ३-मणिपुर, ४-त्रिपुरा, ५-प्रण्डमान-निकोवार द्वीप तथा ६-लक्क्टीप-मिनववाय तथा धमीनदीवी द्वीप ।

१ मई १८६० को मारतीय राजनीतिक नक्यों में पुन. परिवर्तन हुमा जब बन्बई को दो राज्यो—महाराष्ट्र और पुत्ररात में विमाजित कर दिवा गया। स्वाराष्ट्र कोर पुत्ररात में विमाजित कर दिवा गया। स्वारा नगर-हैकेंदी तथा ने बन्दिक ने सुत्र कराये गये दो क्षेत्रों—नदादरा नगर-हैकेंदी तथा ने बन्दिक नम् ने समेप पूनाप का स्तर दिया गया। इसी प्रकार 'पाण्डुकेरी' को, जो पूर्व म क्रान्स ना एक उत्तिरेश था, एक समीय भूनाप के रूप में मानवता दो गई। १९६२ म एक नये राज्य नागालिक का निर्माण किया गया। स्वापित किये गये और इतने साथ ही हुस समय के लिए पण्डीगढ ने केन्द्र-वार्तापत केष्म के पाण्डीगढ ने केन्द्र-वार्तापत केष्म के साथ ही हुस समय के लिए पण्डीगढ ने केन्द्र-वार्तापत केष्म के साथ ही हुस समय के लिए पण्डीगढ ने केन्द्र-वार्तापत केष्म हो एक स्वायत पढ़ाडी राज्य नी स्वापत्त की मई जितका नाम सीवार्य राज्य रक्षा गया। मेशालय तथा प्रसम ने लिए एक ही राज्याच का प्रावयान किया गया। दोनो राज्यो—मसम तथा मेशालय के लिए समुक्त उच्च व्यायात्तात तथा लोक सेवा प्रायोग की स्वापना गी गई। किन्दु नेपालय के लिए सफुक्त उच्च व्यायात्तात तथा लोक सेवा प्रसायोग किया गया। नुस्न वियो पर मेपालय राज्य को कानून निर्मण करते ने प्रसिवर दिये गये। वे निस्नितरित हैं।

विशा, द्रिप, सहकारिता, चिकित्सा, स्वास्थ्य, यातावात, गृह उद्योग, न्याय तथा राजस्व । अत्य विषय, जैसे—सिचाई, विवसी, बाट नियन्त्रण, बटे उद्योग, जल-परिवाहन, बडे मार्ग झादि ससम राज्य के क्षेत्र झिखकार से छोड विसे समें। ३१० भारतीय गासन घीर

जनवरी २५, १६७१ में हिमाचल प्रदेश को सब के एक राज्य के रूप में मान्यता दो गई। दिसम्बर १६७१ में २७वें सविधान सशोधन द्वारा तीन नये राज्यों की स्थापना की गई है। ये हैं—मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा।

इनके प्रतिरिक्त, २७वें समोघन प्रधिनियम १६७१ के प्रन्तगंत दो सपीय भू माग भी स्वापित किये गये। ये हैं—निजोराम तथा प्रस्णाचल प्रदेश। सब मास्त सुष में निम्नलिखित राज्य हैं:—

१-मान्ध्रप्रदेस, २-मान्स, ३-बिहार, ४-महाराष्ट्र, ४-मुजरात, ६-वेरत, ७-मध्य प्रदेश, ६-तमिलनाड, ६-मेमूर, १०-उडीमा, ११-पत्राव, १२-उत्तर प्रदेश, १३-हिमाचल प्रदेश, १४-यश्चिम बगाल, १४-राजस्थान, १६-यम्मू-

कस्मीर, १७ इरियाना, १८-मेघानध, १६-मणिपुर, तथा २०-निपुरा । इती प्रकार समीय मू-मागो मे वृद्धि हुई है; सौर ने निम्नतिषित हैं :— १-निस्ती, २-सण्डमान-निकोबार द्वीत, ३-सक्वादोव, मिनोबबाय, तथा समीनदीनी द्वीर, ४-दादरा नगर हवेती, ४-मोबा-बमन्-वृद्ध, ९-पाण्ड्येरी, ७-मिजोरास, तथा «-स्वराणस प्रदेश।

सधीय भू-भागों ना प्रशासन सधीय सरकार द्वारा निया जाता है। निन्तु सप के राज्यों नो सविषान द्वारा पुषक क्षेत्राधिकार प्रदत्त किये गये हैं।

भारतीय सविवान के प्रतानत सभीय व्यवस्था को मान्यता प्रयत्त की यह है। इस सकते मे, सविवान द्वारा दो प्रकारी की सरकारी-सधीय और राज्य सरकारी की स्थावना की गई है। दोनो प्रकार नी सरकारी के पृथक स्रतिस्व तथा पृथक क्षेत्राधिकार है। परमु स्थियान के पत्तर्गत सभ तथा राज्यों के सबयों भी तीन

भागो मे विभाजित किया जा सकता है।

१—सघ तथा राज्यो के व्यवस्थापन सम्बन्ध,

२—सघ तथा राज्यो के प्रशासकीय सम्बन्ध, और

३-सघ तथा राज्य के वित्तीय सम्बन्ध ।

१—सघ तथा राज्यो के व्यवस्थापन सम्बन्ध

सच तथा राज्यो के व्यवस्थापन सम्बन्ध ना प्राययन सविधान में उत्तिसित तीन विभिन्न व्यवस्थापन सम्बन्धी मूर्णियों के दूरिक्शेस के करना धावश्यक है। सचवार के मूल तिद्धान्त (शक्ति विभावन के तिद्धान्त) नो, मारतीय धर्मियान में तीन व्यवस्थापन सम्बन्धी सुन्तियों के धायार पर ठीस रूप दिवा गया है धर्मीतृ इन तीन मुच्यों द्वारा सम धीर राज्य सरकारों के मध्य शवित विभावन क्या गया है जिससे इन सरकारों के क्षेत्राध्वितर स्पष्ट रूप से निपर्मित कर विदे गये हैं। वेदीन मुच्यितिमान तिस्तित है:—

- (क) सप सूची—सप सूची मे १७ विषय हैं, जिन पर केवल सप-ससद कानून यना सनती है। इनमे मुख्य विषय हैं—प्रतिरक्षा, चैरेशिव सवय, सिम्पा, युढ, शान्ति, सशस्य सेना, अणु धनित, रेल, समुद्रीपप, बाधु मार्ग, शान-सार और टेली-फोन, सपीय लोन च्रण, मुद्रा और उत्तका निर्माण विदेशों से ब्यापा, प्रगरिंग्य-व्यापार और वाणिज्य, मारतीय रिजर्व वैन, विसीय निगम, बीमा, रादान और सन्तिज वदार्थ तेल सस्यानो ना विवास, उद्योग नियन्त्रण, सधीय लोन सेवाएँ, निर्वाचन (सप भीर राज्य), सर्वोच्च न्यायालय ना सगठन और निर्माण, प्रायवर, नागरित्ता, तथा विदेशियों ना नागरिशोदरण, राष्ट्रीय महत्व ने उद्योग, नमक उद्योग, दिल्ली, वनारस और स्रतीगढ़ विश्वविद्यालय, सप भीर त्यापो ना लेखा-परीक्षण और लेखानन, राष्ट्रीय महत्व ने वैज्ञानिक और तवनीकी सस्यान, ऐति-शांतिक स्मारण, मस्त्य, अफीन, समाचार पत्र के विश्वयन्त प्रांदि।
- (स) राज्य गूली—राज्य सूची मे ६६ विषय हैं। राज्य सूची मे उत्लिखित विषयों पर साधारणतया सघवाद के सिद्धान्त के प्रमुक्त राज्य विधान मण्डली को नानून निर्माण करते हा सिक्कार प्राप्त है। वितय विधेष विरिक्षितियों मे जिनका लक्ष्म स्थर इस ते सविधान मे किनका साम करते हैं। वरन्त का सविधान मे किनका साम राज्य है। वरन्त हो विषयों पर कानून बना सकती है। वरन्त सामदा विषयों पर राज्य विधान मण्डलों का ही सोपाधनार है। राज्य सूची मे कुछ मुख्य विधय वस प्रमार है—राज्य सूची मे कुछ मुख्य विधय वस प्रमार है—राज्य लोक प्रमुक्त मांच और तोज, सार्वजनिक कानून कीर व्यवस्था, विस्ता हो स्थानिय स्वास्थान, सार्वजनिक स्वास्थ्य विविद्याल, पणु हुए, पशुणासन, सिवाई, वन उद्योग और वाणिज्य, प्राप्त सुमार मनोरजन कर, छिबगृह, राज्य सोक सेवाएं, राज्य लोक सेवा प्रायोग, भूमिकर, हृषि भाग कर, सिवाब समावार पत्रों के प्रस्य वस्तुष्ठी पर विषयकर, वाहन कर, पष्ट भीर नावों पर कर, व्यवसाय तथा जीविका पर कर, विद्युत कर, सद्दा स्था जूमा साई
- (म) समर्वती मूची—समर्वती मूची मे ४० विषय उल्लिखित हूँ। इन विषयो पर सभीम ससद तथा राज्य विधान भण्डलो नो विधि निर्माण वरते से समर्वती स्विभान समर्वती स्विभान सम्बद्धी स्विभान प्राप्त हैं। सिवधान के अनुच्छेद २५४ के अनुसार यदि इस सूची मे उल्लिखित किसी विषय पर सधीय ससद तथा किसी राज्य विधान मण्डल द्वारा कानून निर्मत दिया जाता है और दोनो कानूनो मे समर्थ है तो जिस हद तक राज्य वानून ना सभीय वानून से सपर्य है, राज्य कानून को उस हद तक प्रवेष माना जायेगा। परन्तु विद्या स्वाप स्वाप ना सभीय वानून से सपर्य है, राज्य कानून को उस हद तक प्रवेष माना जायेगा। परन्तु विद्या स्वाप ना स्वाप ना सम्बद्धी प्रश्वात यदि को इराज स्वाप पर कानून निर्माण करने ने पश्चात यदि को इराज स्वाप पर कानून निर्माण करने है तुसकी राज्य विद्या के विष्य प्रदिक्त रखने के पश्चात उसकी सहस्रति मिल गई है तो राज्य वानून मान्य होगा। परन्तु सभीय

ससद तत्पन्नात् उत्तर राज्य नानून नो परिवर्तिन या समाप्त नर सनती है। डा॰ एम॰ पी॰ शर्मा ने एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है। "हम मान लें कि एक राज्य कानुन, उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश विधान सभा का कानुन, जिसके द्वारा प्रेस की स्वतत्रता पर कुछ प्रतिवय लगाये गये हैं, कानून की पुस्तक मे रखा जाता है। सधीय ससद एक कानून पारित करती है जिससे यह प्रतिबन्ध हटा दिये जाते हैं। श्रव सधीय कानून लागू होगा और उत्तर प्रदेश का नानून जिस सीमा में संघीय कानून से विरोध में है, उस सीमा तक प्रवैध होगा। तत्पश्चात्, उत्तर प्रदेश विधान समा एक और कानून पारित करती है, जिसके द्वारा उन प्रतिवन्यों को जो सधीय कानून द्वारा ह्या दिये गये थे, पुन सायू वर दिया जाता है। अब उत्तर प्रदेश के कानून को राज्यपान द्वारा राष्ट्र-पति ने विचार के लिए सुरक्षित रखना होगा। भीर यदि राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए अपनी सहमति देना है तो यह कानून (उत्तर प्रदेश का) पहले सबीय कानून से सबर्प में होन के बावजूद भी बैंध होगा । यदि संधीय संसद उत्तर प्रदेश म प्रेस को स्वतंत्र करने के लिए पुन एक कानून पारित

करना चाहनी है तो वह ऐसा कर सकती है।"

समवर्ती सूची में मुक्ट विषय इस प्रकार हैं। इण्ड विचि, दण्ड प्रक्रिया, निवारक निरोध (नजरवन्दी), दीवानी प्रक्रिया, विवाह तथा विवाह विच्छेद (तलान), दिवालियापन, उत्तराधिनार, सम्मत्ति का (तिवाय कृषि सवधी) हस्तान्तरण, सविदा, खाळ पदार्थी तथा अन्य वस्तुओं मे मिलावट, पागलपन, साध्य तथा प्रतिज्ञा, श्रोपविया तथा विष, श्रोपविया तथा श्चन्य वस्तुएँ, भाषिक तथा सामाजिक परियोजनाएँ, व्यापार सघ, श्रम विवाद श्रीर श्रम नल्याण, कानून, चिकित्सा तथा श्रन्य व्यवसाय, समाचार पत्र तथा प्रेस, पुस्तकों, जीवन मरण के ग्रांकडे, श्रीद्योगिक वस्तुएँ, खाद्य-पदार्थ, पशु-मोजन कच्ची हई, हई के बीज तथा कच्चे जूट का उत्पादन तथा वितरण, अन्यत्र जाने

बाले शरणाधियों की सम्पति ग्रादि ।

मारतीय सविधान में धवशिष्ट शक्तियों ने लिए धनुच्छेद २४६ में प्रावधान किया गया है। अविधाट शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं, जो उपर्युक्त तीन सुवियों में उल्लिखित नहीं हैं। भारत में प्रविशय शक्तियों को संघीय सरकार में निहित क्या गया है। समेरिका, झास्ट्रेलिया, तथा स्वीजरलैण्ड मे श्रवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकारो को प्राप्त हैं, जबकि केनेडा में ये शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार में निहित हैं।

१. एम० पी० शर्मा-'द गर्वमेन्ट ग्राफ द इण्डियन रिपब्सिक, १६६१ 20 50 1

मारतीय मिलवान में समवाद के सिद्धान्त को प्रयताने के फलस्वरूप सम प्रीर राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार घलग-प्रलग निर्वादित नियेग्ये हैं, तथापि कतिपय ऐसी परिस्थितों का सिववान में उल्लेख निया गया है जिनमें सध ससद राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सदेगी। ये परिस्थितियाँ निम्मितिशत हैं

१—सल ससद राज्य-मुलो मे लिल्लालिन किसी विषय पर अनुच्छेद २४६ के ग्रस्तगैत कानून निर्माण कर सकती है, यदि राज्य विद्यान समा न दो तिहाई बहुमत से प्रस्तान लारित किया है जि उक्त विषय का महत्व राष्ट्रीय हो गया है। राज्य विद्यान समा का यह प्रस्ताव एक वर्ष तक रहेगा। राज्य समा इस प्रकार के प्रस्ताव को प्रते तक रहेगा। राज्य समा इस प्रकार के प्रस्ताव को प्रते के प्रस्ताव हो। सभ ससद हारा इस प्रकार के को वानून पारित किया जाते है, वे राज्य विद्यान समा द्वारा पारित प्रस्ताव की समयाविध मे समाप्त होने के ६ साह बाद तक वैद्य माने लायेंगे।

२—प्रतृचेद्वद ३५२ के प्रन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जब सक्टकालीन उद्घोषणा को जायेगी तब सपीय सबद, प्रतृच्देद २५० के घनुसार, किसी भी विषय पर , (राज्य सूची म उल्लिखित विषयो सहित) मारत या मारत के किसी प्रदेश के तिल् कानून निर्माण कर सक्तेगी । सबद द्वारा पारित इस प्रकार के कानून सकट-काफीन उद्योगणा के समाप्त होने के ६ माह के बाद समाप्त हो जायेगे ।

२—मनुच्छेद २५२ वे धनुसार यदि दो या दो से धिषक राज्य विधान मण्डलो ने प्रस्ताव पारित विधा है कि ससद उन राज्यो के लिए राज्य सूची मे उल्लिखित किसी विधय या विषयो पर कानून निर्माण करे तो ससद को उन राज्यो के सबध मे राज्य सूची म उल्लिखित विषयो पर कानून निर्माण करने का प्रधिकार प्राप्त होगा ।

४५- प्रमुच्छेद १५३ के प्रनुतार सधीय ससद को किसी सिंध समझौते या जयसाँग, जीसपीय सरकार ने निसी विदेश या विदेशों से की है या किसी प्रन्तराष्ट्रीय सम्मेलन, समुदाय या अन्य सहया ने निर्णय के क्रियान्ययन के लिए कानून-निर्माण नरने ना प्रीयनार है। इस प्रनार ससद हारा निर्मत कानून सुध के किसी भी राज्य या समस भारत में लागु होगा।

५—मदि मनुच्छेद ३५६ के धन्तर्गत सम के किसी राज्य में उक्त राज्य में सबैधानिक मन्न के सामक्ष्य होने के नारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हो, तो राष्ट्रपति उद्योगका द्वारा सक्त को उक्त राज्य के लिए राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून निर्माण करने के लिए प्रायिक्त कर सकता है। ससद स्वयं इन श्रालियों के उपयोग करने के विषया पर प्राप्त को अनुच्छेद ३५७ (१) व (२) के प्रन्तर्गत यह शक्ति प्रयान कर सकती है, और उसकी अधिकृत कर

सकती है कि किसी प्रन्य प्राधिकारी को जिसका राष्ट्रपति उल्लेख करता है, यह सक्ति प्रदत्त की जाये।

६—सम के विजिल्ल राज्यों में राज्यपाल प्र करी के क्य में है, जिसकी सभीय तथा राज्य सातानों को किराय सहत्वपूर्ण जियमों के सरकार में जोड़ा जाता है। राज्यपाल को यह मुश्तिका उस समय विश्वस्त के स्वत्यं में जोड़ा जाता है। राज्य सरकार को सविधान के प्राचमानों के प्रतुसार नहीं चलाया जा सकता है। राज्य विधान-पठली हारा पारिल किताय कियाय-पठला सभीय किया के सामग्री में पठलिस्ति किया विचार को समयी परिल से सामग्री में उद्यानिक स्वत्यं के सामग्री किया को सामग्री की सामग्री की सामग्री की सामग्री की सामग्री की प्रतुष्टेंद २६ के प्रत्यं की समुख्य के क्या पत्र विक्रम दे पत्र हों ऐसा क्या प्रतुष्टेंद २६ के प्रत्यं की समुख्य के क्या पत्र विक्रम पत्र हों ऐसा पर्युद्धें के स्वत्य पत्र विक्रम पत्र हों ऐसा पत्र प्रतुष्टें के प्रतुष्टेंद २६ के प्रतिकृति किया करेंद्र के सामग्री के प्रतार प्रत्य के पत्र हों ऐसा क्या पारिकार, पारत प्रत्य की पत्र पत्र विक्रम पत्र विक्रम की प्रतिकृति के सामग्री की प्रतार प्रयुक्त की प्रतिकृति के स्वत्यं की सम्वाप्त की प्रतिकृति के सुद्धित है हो सम्वप्ति है। स्वत्यं ति की सम्वप्ति है। स्वत्यं ति सम्वप्ति के सुद्धित के सुद्धित है सम्वप्ति है। सम्वप्ति है। सम्वप्ति है सुद्धित के सुद्धिति है सुद्धित विक्रम का सम्वप्ति है। सम्वप्ति है। सम्वप्ति है सुद्धिति है सुद्धित है सु

सदियान के उपर्युक्त प्रावधान भारत में सभीय सरनार को शिनगावी रखते में सहायक हुए हैं। इनके बारण तीवयान के पत्रकृत सकाय के निवसान होने के अपनारत भी हुए प्रतासन प्रवृत्ति को भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्वान प्राप्त हुए। हुए प्रार्थक प्रवृत्ति की भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्वान पर कानून बनाने ने लिए प्रतिष्ठत करने के पत्रस्वप्य इन प्राध्यानी ना प्रभाव पर होता है कि रहते सप्त पर्याप्त के एक पुत्र कुट को, को प्राप्ती ने बताई है, नियन्यण म ताया जा सक्वा है। वह है—"के दीम सरकार की किए विमाजन के कारण देश के प्राप्तरिक तथा बाह्य मानली के प्रयत्म करने के सब्य में क्ष्मानी !"

२--सघ तथा राज्यो के प्रशासकीय संबंध

सवित संपीय व्यवस्था भ शतियो ना विनाजन वरते हुए सी प्रवार की सरकारी—केंद्रीय तथा राज्यों की सरकारों के लिए क्षेत्राधिवार पुष्यत किया तथा है, सम्बाद का रादेवम, जीना <u>मीठ काशती ने</u> बताया है, राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों की स्वायतता की हात्तिव करना है। सम्बाद के प्रत्यतंत ही राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों की स्वायत्ता दोनो समन हो सकते हैं। राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों नी स्वायतता मा सावारण तथा समान महत क्रमत है। है किया राज्यों के स्वायत्ता

१. वही पृ० =३।

ने दावे उस हद तर स्थीष्टत नहीं जिसे जा सर्वेंगे जिससे राष्ट्रीय एकता पर आयात पहुँचने की सभावना होगी। राष्ट्रीय एकता के सन्दर्गम यह पहना सत्य है कि समस्त राष्ट्र की एक प्रकासकीय इकाई मानते हुए ही राष्ट्रीय एकता की नीव दढ़ भी जा सन्ती है।

भारतीय सविधान ने भारतीत सभीय तथा राज्यों ने प्रचासकीय सवधी ना विक्रेपण करने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि राष्ट्रीय एक्का की दृष्टि से सधीय सरकार को राज्यों ने सबध में कतियब प्रशासकीय मस्तियों प्रदत्त की गई हैं जिनका प्रध्यपन दो विषयों ने प्राधार पर किया जा सनता है।

- (क) राज्या पर प्रशासकीय नियमण हेतु संघीत सरकार में साधन, श्रीर
- (स) ध्र'तर्राज्यीय सहयोग तथा सच सरकार वी भूमिना

व राज्यो पर प्रशासकीय नियन्त्रण वे लिए संघीय सरकार वे साधन

सामा यत सघीय सरकार राज्यों नी सरकार पर पाँच साधनों से प्रशासनीय निम्न त्रण उपयोग में सा सबसे हैं।

स्वेश्वयम सविधान द्वारा सधीय सरवार को राज्यों की सरकारों को निर्देश देने का धिकार रिया गया है। सविधान के अनुस्तेद के २५६ के अनुसार राज्य सरारा या यह नर्तव्य है कि ससद द्वारा पारित विधि को भाग्यता में 1 होती सरारा या यह नर्तव्य है कि ससद द्वारा पारित विधि को भाग्यता में 1 होती स्वार अनुस्तर २५० के अनुसार राज्य सरकारों का यह भी कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र म सथ की नार्यपालिका सिक के उपयोग में न कोई रकावट द्वारा धोर न कोई पण्यात करें। उपर्युक्त अनुस्तेदों के अनुसार सच सरकार द्वारा राज्य सरकारों निर्देश विधि का सकते हैं। सविधान के अनुस्तेद २६५ में यह स्पष्ट प्राथात है कि यदि सब की नायपालिका सक्ति के प्रयोग में दिये गये कि ही निर्देशों का अनुस्तेद करने में मा या उनकी प्रभावी करते से कोई राज्य सवलत हुआ है तो वहाँ, राष्ट्रपति के सित्य यह मानना विधि समत है कि ऐसी स्थिति उपस्प्र हों गई है जिसम राज्य या माग्रन सविधान के प्रावचानों के प्रवृत्वत हों स्वाया या सकता है। इसका यह समित्राय है कि अब कोई राज्य, साम की कार्यवालिका द्वारा दिव विदेशों का पानन नहीं करता है तब राष्ट्रपति मनुष्येद ३५६ के स तमत यह द्वारोपणा वर सकता है कि राज्य का वार्यानिक-पत्र समाधात हो पूना है धोर इसने कनस्वरूष राज्य की सरकार में समस्त या कुछ वार्यों वो स्वय से सकता है।

सपीय सरवार राज्यो की सरवारों नो अनुन्छेद २१७ (२) के अनुसार राज्यों में राष्ट्रीय या सैनिव वे महत्व व सवार साधनों के निर्माण करने और बनाये रुतने के लिए निर्देश दे सकती हैं । सवार साधनों एक ऐसा विषय है, जिसका उस्लेख पत्रम, राज्या वो सभीय सरकार द्वारा वित्तीय ध्रतुवान दिया जाता है वधिक राज्यो वी ध्राय के विभिन्न स्रोत उनकी जित्तीय ध्रावस्थवताध्रो को पूरा करने के लिए पर्याप्तनहीं हैं। राज्यों को वित्तीय ध्रतुवान देने के लिए ध्रतुच्छेद २०५ के ध्रतुसार सधीय सबद को कानून निर्माण करने का ध्रियकार है और इस प्रनार राज्यों को प्रदत्त वित्तीय ध्रतुवान का व्यय सारत की सचित निधि में से निया जायेगा। इसके ध्रावित्कि, सवियान म दो प्रकार के विवाट ध्रतुवानो का उल्लेख है, जो निम्ननिरित्त हैं।

१—मारत सरकार को सहमति से किसी राज्य द्वारा प्रमुपूषित जातियों के करवाण या प्रमुपूषित क्षेत्रों के प्रमासा के स्तर को उन्नत करने के लिए प्रमनाई गई योजनाओं के लिए प्रमुदान जिसका व्यय मारत की सचित-निधि पर मारित होगा।

२--- ग्रसम म ग्रादिम जनजाति व विकास क लिए ग्रनुदान ।

वित्तीय श्रनुदान के माध्यम से सधीय सरकार राज्यां पर प्रमावशाली नियन्त्रण रखती है।

ख ग्रन्तर्राज्यीय सहयोग तथा सध सरकार की भूमिका

िनमी भी सधीय व्यवस्था म इनाइयो (राज्यो) म पारस्परित सहयोग होना आति आवण्यन है। मदापि राज्यो नो सत्ता नी इंग्टि से पृषन क्षेत्राविनार प्राप्त होते हैं, तथापि राज्यो एनता ने लिए राज्यों ने पारस्परित सहयोग तथा सह अस्तित्व ने सिद्धान्तों के भाषार पर नाम नरना होगा। भारतीय सविधान में राज्यों ने सारस्परित सहयोग के तिए निम्नतिखित विषयों पर विशेष रूप से बल दिया गया है।

१----गण तथा राज्यों वी सार्वजनिक क्रियाधो, धनिलेखो तथा न्यायिक गायंवाहियों की स्थित अनुष्टेद २६१ (१) वे अनुसार मारत के राज्य क्षेत्र में सर्वज, सच की धौर प्रत्यक राज्य की सांवजनिक विचाधो, प्रमिलेखो, धौर न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विक्वास और पूरो मान्यता दी जायेगी। परन्तु का त्रायों, प्रमिलेखो और कार्यवाहियों की सिद्धि की रीति और कार्यों तथा उनके प्रसाय का नियारण ससद निमित-विधि द्वारा उपप्रीचन रीति के मनुसार होगा। इसने प्रतिक्ति कारत को स्वित की सिद्धि की रायायाखा द्वारा दिये गर्य अनितम निर्णयों या आदेश सारत राज्य की में कही भी निष्यादन योग्य होंगे।

२—प्रन्तर्रामीय नदी यानदियों ने जला ने सबय में विवाद—प्रमुख्छेद २६२ (१) ने प्रनुसार ससद विधि द्वारा निसी धन्तर्राज्यीय नदीया नदियो के जल के प्रयोग, विजरण या नियन्त्रण के बारे में किसी विजाद या प्रार्थना पर न्याय निर्णयन का प्राथमान कर सकती है। इस प्रकार के विजाद के सबय में सबद विशि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सार्थक न्यायानय, न ख्यास कोई-सामानस प्रकास क्षेत्राधिकार प्रयोग म लेगा।

३—सन्तरांग्यीय परिषद—धनुन्देद २६३ के प्रत्यमंत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए एक प्रत्यरंग्यीय परिषद का प्रावपान किया गया है। यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि जनहित में धावस्थक है तो वह धन्तरांज्यीय परिषद के स्थापना करेगा । इस धन्तरांज्यीय-परिषद के निम्मलितित काय होने ।

एक — राज्यों के मध्य विवादों का परीक्षण करना तथा उन पर परामशें देना।

हो—ऐसी जाँच तथा विवेचना करना जिसमे कुछ या समस्त राज्य या सप या कुछ राज्यो का सामान्य हित निहित है।

तीन—ऐसे विषय पर धुभाव देना और विजोपकर ऐसे विषय के सबय में भीति तथा कार्यों में बेहतर समन्वय के लिए सुभाव देना। राष्ट्रपति, जब इस प्रकार की अपनर्राज्यीय परिषय की स्थापना करता है वह उसके भागों, सगठन तथा कार्यप्रणानी को निर्धारित वरिता।

Y—श्रेत्रीय परिषद—राज्य पुनर्गठम अधिनयम १८५६ के सन्तर्गत सम्पूर्ण भारत सम के लिए क्षेत्रों की एक परियोजना को प्रयोक क्षेत्र में सामू किया गया। क कतियय राज्य हैं, जिनके लिए एक क्षेत्रीय परिषद है। सम्पूर्ण भारत के लिए निम्मलियित पाँच क्षेत्र निर्वादित किये गये हैं—

१—उत्तरी क्षेत्र—पजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, दिश्ली तथा हिमाचल प्रदेश हैं।

२--मध्य क्षेत्र---उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश ।

३—पूर्वी क्षेत्र—विहार, पश्चिम बगाल, उडीसा, मणिपुर ग्रीर त्रिपुरा ।

४--पश्चिमी क्षेत्र--- महाराष्ट्र, गुजरात तथा मैसूर क्षेत्र ।

५—दक्षिणी क्षेत्र—महाराष्ट्र, गुजरात तथा मसूर क्षत्र ।

प्रत्येत क्षेत्र के तिए एक क्षेत्रीय परिष्य है तिक्षमे एक स्थीय मत्री रहेशा वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत क्षित्रा जायेगा। क्षेत्र के प्राच्यो के मुख्यनत्री, क्षेत्र, के प्रत्येक राज्य के हो से हो भन्नी जो राज्यपात द्वारा मनोनीत क्षित्रे जायेंगे तथा क्षेत्र के प्रत्येक सभीय भून्याप से दो क्षेत्रत, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत क्षित्रे जार्येगे, क्षेत्रीय परिवद के सदस्य होंगे। म्रोर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेषकर म्रादिम जाति क्षेत्र के लिए राज्यपाल का परामग्र दाता भी उनत क्षेत्रीय परिवद मे सम्मिलित किया जायेगा। क्षेत्रीय परिवद मे सधीय मत्री क्षेत्रीय परिवद का मध्यक्ष होगा, म्रोर प्रत्येक मुख्य मत्री एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष रहेगा।

क्षेत्रीय परिपद में कतिपय परामतं दाताघों को भी सम्मिलित किया जायेगा, जो इस प्रकार हैं—योजना धायोग का प्रतिनिधि धौर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव घौर विकास धायुक्त । इन परामर्थ दाताघों को विवाद में माग क्षेत्र वा धायकार है, किन्तु वे मतदान नहीं कर सकते हैं।

क्षेत्रीय परिपद की बैठक तथा स्थान प्रध्यक्ष द्वारा निर्धारित विया जाता है। परिपद की बैठक का स्थान, क्षेत्र के किसी राज्य में ही होना चाहिये। परिपद प्रपत्ने कार्यों के सम्पादन के लिए समितियों का निर्माण कर सकती है। परिपद के सिवालय के प्रियेक्तारियों के ब्यय का मार, सिव्य के बैठन के सिवाय, केन्द्रीय सरकार पर है। क्षेत्रीय परिपदों के कार्य जन समस्त विषयों से सबिवत होंगे जिनमें क्षेत्र के समस्त या कुछ राज्य या सथ और एक या प्रयिक राज्य राज्य की स्वर्धीय तर्हें। क्षेत्रीय परिपद स क्षेत्र के सिता सरकार को ऐसे विषयों पर परामर्थ देती है। मुख्यत क्षेत्रीय परिपद निम्नलिखित प्रक्षा पर विचार विमर्थ करती तथा परामर्थ देती है।

एक-—ग्राधिक तथा सामाजिक योजनाम्रो से सविवत कोई सामान्य हित का विषय ।

दो-सीमा विवाद, सापा पर भाषारित ग्रस्य सख्यक, ग्रीर अन्तर्राज्यीय भावागमन से सर्वाघत कोई विषय ।

तीन—राज्य पुतर्गठन अधिनियम १९५६ के ब्रन्तर्गत राज्यो के पुतर्गठन से सवधित कोई मी मामला ।

सक्षेत्र मे परिषदो की स्थापना का उद्देश्य सघीय सरकार के सहयोग से अन्तर्राज्यीय विवादो का समाधान करना है।

५—सप भीर राज्यों म व्यापार वाणिज्य और लेन देन—सिवधान के मनुष्ट्रेद ३०१ के धनुसार सारत राज्य क्षेत्र मे सर्वत व्यापार वाणिज्य धीर तेन-देन की स्वतन्त्रता है। परन्तु प्रनुष्ट्रेद ३०२ के धनुसार ससद विधि द्वारा एक राज्य भीर दूसरे राज्य के बीच धपना मारत राज्य क्षेत्र के किसी माग के मीतर व्यापात वाणिज्य व लेन-देन की स्वतन्त्रता पर ऐसे प्रतिवन्त्र लगा सकेगी, जो लोकहिन मे प्रपेक्ति हैं।

ग्रनुरुद्धेद ३०३ (१) के ग्रनुसार सविधान की सातवी प्रनुमुखी मे निहित तीन सिवयों में (सप, राज्य तथा समवर्ती) से किसी में ब्यापार-वाणिज्य सवधी किसी विषय के ग्राधार पर न तो ससद को भौर न राज्यों ने विधान मण्डल को कोई ऐसी बिधि बनाने की शक्ति होगी, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से प्रविमान देती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच नोई विमेद करती है। परन्तु अनुच्छेद ३०३ (२) के अनुसार ससद को ऐसी विशेष परिस्थित में यह अधिकार होगा कि कोई ऐसी विधि बनाये जिससे किसी राज्य को यह अधिमान दिया जायेगा या एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच विमेद होगा, जब ससद उक्त विधि-द्वारा यह घोषित करे कि मारत राज्य क्षेत्र के विसी भाग में वस्तुग्रों की दुर्लमता के बारण उत्पन हुई स्थिति से निवटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना श्रावश्यक है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जबकि अनुच्छेद ३०३ (२) के अनुसार ससद को वस्तुयों की दूर्लमता के शारण ऐसी विधि निर्माण वरने का भविकार जिससे किसी राज्य को दूसरे राज्य से श्रीधमान मिलता है या दो राज्यो में विमेद होता है, किसी राज्य विधान मण्डल को कोई ऐसी विधि निर्माण करने का ग्रधिकार नहीं है, जिससे किसी राज्य को व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से दूसरे राज्य से प्रविमान प्राप्त हो या दो राज्यों में विमेद हो।

समुच्छेर ३०४ (क) के समुतार राग्य का विभाग मण्डल, विधि हारा प्राप्त राग्यों से सामार के सर्व क्षेत्र पर कोई ऐसा कर लगा मक्ता है, जो उसे राग्य में किंग्य जा जलादिव की ही व्याचुधी एर कोई ऐसा कर लगा मक्ता है, जो उसे राग्य में किंग्य का जलादिव की ही विच्यु की एर स्वता है। निज्ञ हम प्रकार कि जसे हैं कि कोई कि यह में में प्रवृद्धि के प्रमुख्य राग्य की कोई कि स्वता हम प्रकार के सामार प्राप्त के नी किंग्य का राग्य की सामार प्रचार के नी किंग्य का सामार की स्वतान मण्डल में, विधि हारा उस राग्य के साम या उससे क्यायार वानियम और देल-देन की स्वतान पर ऐसे मुलिगुक्त निलं-यन लगाने ना समित्र हमें को लोक हिल में स्वतीवत है। परजु हस उद्देश्य में किसी भी विषयक या समीधन की विधान-मण्डल में पुर व्यक्तिक के लिए राष्ट्रपति की युवीमुपति प्राप्तका की स्वापानी के प्रवास में सम्पर्दाणीय व्यापार-वानियम से स्वत्य विधान के प्राप्तपानी के साम्यानी के साम्या

परत में सम्परियोध व्यापार-वाणियन से सबसित सविधान के प्रावधानी के क्रियान्यान के लिए धनुब्हेंट ३०० के सन्तर्गत सक्तर एक प्राधिवारी की नियुक्ति करेगी तथा उनकी ऐसी महित्यों और वर्तव्य सींच सवती है जो वह मावस्थन सामि ।

३-सथ तथा राज्यों के वित्तीय संबंध

संपीय व्यवस्था म, संपीय तथा राज्यों की सरकारों में सविधान के प्रत्यात पाक्तियों का बेंटवारा प्रावस्थक है, किन्तु शक्ति के बेंटवारे के साथ विसीय सावती का बेंटवारा भी भरवना भाकस्थक है। क्योंकि बिना वर्षान्त विसीय सावती के विनिन्न शक्तियो वा कोई धर्य नहीं होगा। मत सामारणयता प्रत्येक समीय अवस्था सब मे तथा राज्यों की सरकारों का, प्रपने वित्तीय साथनो पर स्वतंत्र और पृथन नियन्त्रण होता है जिससे वे प्रपने क्षेत्रायिकारों के प्रत्यर्गत विनिन्न कार्यों को स्वतंत्रत पूर्वक कर सकें। समीय वित्तीय व्यवस्था नी प्रदर्श प्रवाली वह होगी जिसमे स्वय्ट रूप से राजस्य के शती वा विनाजन सम तथा राज्यों के मध्य म विचा गया है जिससे दोनों पक्षों में से प्रत्येक नो एक दूसरे से स्वतंत्र बनाया जा तकें। तथा हि जिससे दोनों पक्षों में से प्रत्येक नो एक दूसरे संस्वतंत्र बनाया जा तकें। तथा पि कुछ ही सधीय देश इसकी प्राप्त कर सकें हैं।"

बस्तुत व्यवहार में संघीय देशों में सब और राज्यों के वित्तीय सबयों के दृष्टिकोण से कोई एक सामान्य पद्धति को नहीं धपनाया गया है। विन्तु प्रत्येक संघीय राज्य में देश की मुविधा के प्रमुक्तार प्रपत्नी पद्धति का विकास हुआ है। यद्याप प्रमित्का में साव तथा राज्यों के लिए पृथक वित्तीय क्षोतों का प्रावधान है, विन्तु वहां पर सो राज्यों को संधीय प्रमुद्धान देने की भाववयनता पैदा हुई। केनेहा तथा सावदृष्टिवा में सवीय (केन्द्रीय) सरकार राज्यों की वित्तीय स्रोतों में प्रपत्ना योगदान देती है, व्योंकि राज्यों के प्राव के साधन पर्योग्त नहीं हैं।

मारतवर्ष म सिवधान के अन्तर्गत सप तथा राज्यों के मध्य तीन सूचियों द्वारा शक्ति विमाजन ने साथ जो आय के साधनों था विमाजन किया गया है, वह न तो पूर्णतया स्वच्ट है धौर न सम्पूर्ण है। इससे राज्यों को जननी आवश्य-कतामों से वहुत कम दिया गया है, भौर सिवधान के अनेक प्रत्य प्रावधाना द्वारा, जिनका जदेव्य सच के होतों के बुख मांग को राज्यों को विभिन्न रूप मे हस्तान्त-रित करना है प्रवस्तित तथा पूरा विधा जाता है।

मारतीय सम के राज्यों को दूण रूप से उन करा से प्राप्त प्राय पर ध्रिपतार है, जो राज्य सूची म जित्तिति हैं। सम सरकार को उन करों से सारी प्राय प्राप्त होती है जिनका उत्सेख सम सूची मे किया गया है। इसके प्रतिस्तित, सम सप्तार को उन करा से प्राप्त प्राय पर भी धर्मियार है, जिनका उत्सेख किसी सूची म नहीं किया गया है। समवर्ती सूची म करो वा पोई उल्लेख नहीं है। राज्यों का राज्य सूची के प्रत्यंत लगाय करा की प्राय राज्यों का प्राप्त सूची के प्रत्यंत लगाय करा की प्राय राज्यों को प्राप्त है सब सरकार में सम सूची व प्रत्यंत लगाय गये गुंछ करों की प्राय को पूर्णतया या कुछ प्रया म राज्यों को देना होगा।

सप्र तथा राज्या के वित्तीय समझावा म्राच्ययन निम्नेलिखित म्राघारो पर वियाजा सकता है।

१. वही पृ० ६६

कः सच तथा राज्यों के मध्य राजस्य का वितरथ—सथ सरकार को मास्तीय सविधान के प्रत्यति चार प्रकार के करो से प्राप्त प्राप्त को पूर्ण क्षेत्र या कुछ प्रश्न मे राज्यों को देना होयी। यह निम्मतिवित है। अनुकोर १६० के प्रनुतार।

१—सप सरकार द्वारा लगाये, किन्तु राज्यो द्वारा सगृहोत तथा विनियोजित गुल्क विनित्तम पत्र, चेक, प्रामेसरी नोट्स, माल, प्रसवाव वा माटा, हृष्टियां, बीमा छादि पर स्टाम्स जुरुक तथा स्वादनो घीर ऐसे भूगार सायन जिनके निर्माण में यह का उपयोग होता है।

२—सप द्वारा लगाये भीर सगृहीत परन्तु राज्यो नो दिये जाने वाले व'र-प्रतुच्छेद २६६ के प्रमुसार ये निम्नलिखित हैं —

(एक) कृषि-भूमि के म्रतिरिक्त, भ्रम्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर।

- (दो) कृषि भूमि के अतिरिक्त, ग्रन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क।
- (क्षेत्र) रेल, समुद्र तथा वायु हारा माल मौर यात्रियों को ले जाने पर सीमान्त कर।
 - (चार) रेल तथा वस्तुधो के भाडे पर कर।
 - (पौच) शेयर याजार तथा सटटा बाजार के लेन देन पर स्टाम्प शुल्क के फ्रांतिरिक्त फ्रन्य कर।
 - (छ)समाचार पत्रों के क्रय विक्रय झौर उनमें प्रवाशित विज्ञापनों।
- पर कर। (सात) घन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के सिलसिले म माल के कथ विकस्य

पर कर । ३—सथ द्वारा लगाये व सब्हीत धायकर जिनका विभाजन संघ व राज्यो के मध्य महोता है। धानुष्टेद २७० के धनुसार संघीय भू-भागो के लिये निर्धारित

मध्य म होता है। अपुरुष्ठ २७० के अनुसार समाय भूर-माना के तिया निर्मारित रागि तमा समीय क्यम को काटकर तैय धायकर की रागि का विमाजन सम व राज्यों में राष्ट्रपति विस्तीय धारोगों के प्रतिवेदन पर विचार करने के परचात् घादेश द्वारा करता है। अनुरुद्धेद २०१ के अनुसार ससद विभिन्न करों की जो कि अनुरुद्धेद २६६ व

अनुन्धद २०१ के अनुसार संसद विभिन्न करा की कि अनुन्धद २६६ व २७० में उल्लिखित है। सप के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु अधिकार द्वारा वृद्धि कर सकेगी।

४—सप द्वारा लगाये गये तथा सबहोत कर जिनका विमाजन सम य राज्यों के मध्य होता है,—ये कर इस प्रकार के हैं—स्वाई धौर प्रवृक्षार सबची बातुसों को छोडकर प्रत्य बस्तुस्रों पर लगाये उत्पादन शुरुकः। सा संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायक ब्रमुदान—मारतीय सविदान में सब सरकार के राजस्य स्रोत से तीन प्रकार के सहायक ब्रमुदान राज्यों को दिये जाते हैं।

१— प्रजुच्छेद २७३ के प्रमुसार प्रसम, विहार, जडीसा तथा पश्चिम वगान को जूट धीर जूट से निमित वस्तुषी पर निर्मात् कर के बदले में सप सरवार द्वारा प्रमुदान दिया जाता है। राष्ट्रपति प्रमुदान की राशि निर्मादत करता है। इन राज्यों को श्रुप्तान जब तक दिया जावेगा, जब तक भारत सरकार द्वारा जूट या जूट के निमित वस्तुषी पर जुल्क लगाया जाता है, या सिवधान के प्रारम से दस वर्ष तक इन दोनों में से जो भी पहले हो, उसके होने तक।

२— प्रमुख्देद २७५ के प्रन्तगैत ससद को यह ग्रिपकार है कि सप के किसी राज्य को जिसको वित्तीय श्रद्धान की प्रावस्थकता है, सहायक प्रमुखन प्रदत करें। कित मात्रा में यह श्रद्धान दिया जाना चाहिये, दसना निर्धारण करने का प्रिकार ससद को है। संधीय सरकार का यह मितिरकत वर्त्तच्य है कि राज्ये हारा मनुस्थित प्रादिम जातियों में कस्याण हेतु प्रारम्भ में गई योजनाधों मो पूरा करने के लिए और श्रद्धाश्वित संबों के प्रशासनिक स्तर को ऊँचा करने हेतु सहायक श्रद्धालय प्रदास करें। सविधान द्वारा असन के धादिम क्षेत्रों के विवास हेतु विशेष सहायक प्रदास के किया प्रावस के स्वादम के प्रावस के स्वादम के साथ सहायक प्रदास के लिये प्रावसान किया गया है।

३— अनुच्छेर २६२ के अन्तर्गत संघीय व राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि नित्ती भी सार्वजनित उद्देश की पूर्ति हेतु सहायक अनुदान प्रश्त करे। इसके बावजूद भी नि वह विषय संसद व राज्य विधान मण्डल के व्यवस्थापन के शायरे मे न हो।

ग. पारस्परिक करों से सध तथा राज्यों की मुक्ति-१---धनुच्छेद २८५ के भन्तगंत जब तक ससद कानून द्वारा कोई प्रावधान न करे, राज्य सरकारें सथ की सम्पति पर कर नहीं लगा सकती हैं।

२ — मनुच्छेद २०७ के मनुसार मारत सरकार या रेल द्वारा उपयोग मे ली जाने वासी विजली पर विना ससद की घनुमति के राज्यो द्वारा किसी प्रकार का घल्म नहीं सगाया जा सकता है।

१-- मनुब्बेंट २८६ के मन्तर्गत विना राष्ट्रपति की प्रतुमित के कोई राज्य, ऐसे प्राधिकरण द्वारा दिये गये या नियन्त्रित पानी या विजली पर शुक्क नही लगा सबता जो मन्तराज्यीय नदियो या नदी-दूतो (याटियो) के विकास या विनियम के तिए स्थापित किया गया है।

४-मन्ब्छेद २८६के मनुसार सध सरकार को राज्यो की सम्पति तथा प्राथ पर कर लगाने का प्रधिकार नहीं है। परन्तु किसी राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाते व्यावार या व्यवसाय को सधीय करों से मुक्ति तब ही मिल सवेगी, जब ससद कानून द्वारा यह घोषित करती है कि एसा व्यापार या व्यवसाय राज्य सरकार के कार्यों का मांग है।

य सच सवा राज्यों की क्या नेते की शक्ति-सविधान के मनुष्येद २६२ के सुतार समीय सरनार को मारत की सचितनियि नी प्रतिभूति पर क्या कीने ना प्रतिकार है। हिन्दु देश दिवाय पर ससद वानून हाद सीमाएँ लगा सनती है। राज्यों को मारतीय प्रदेश में राज्य सचित निधि की प्रतिभूति पर कण्य लेने ना अधिकार है। राज्या ने क्या लेने के प्रियार पर सिवागन हारा कुछ सीमाएँ स्थी पर्दि की देश प्रपार हैं—

१--राज्यो द्वारा भारत म ही ऋण लिया जा सकता है।

२—यदि राज्य सरकार ने प्रपना पुराना ऋण सभ सरकार के प्रति चुना न दिया है तो नये काण सेने के लिए सम सरकार की धनमति प्रावश्यक होगी ।

३—राज्य विधान मध्डल राज्य सरकार के ऋष लेने के ग्रीयकार पर सीमाएँ सवा सन्ती है।

अनुच्छेद २६३ के अनुसार सवीय सरकार राज्यों को ससद द्वारा निर्पारित शतों के अनुसार खण देसकती है।

इ. दिल्लीय सलय कालीन उद्योधका :- अतुन्धेद १६० के अनुसार राष्ट्रपति को विश्वाचा हो जाता है कि ऐसी स्थिति थेदा हो नई है, जिससे मारत तथा उसके निसी राज्य थेन के निसी नाम का विसीय स्वाध्यक्ष या प्रथम सन्दर्भ है तो वह निसीय सकरकालीन उद्योधका कर सकता है। इस सन्दर्भ में सच-सरकार राज्यों को सरकारों को विल्ला अवस्था के सवय में आदेश तथा निर्देश दें साम स्वाध्यक्ष साथ के साथ में साथ निर्देश दें में साथ में मार्थ के साथ में साथ मार्थ साथ मार्थ के साथ मार्थ साथ मार्थ के साथ मार्थ की साथ मार्थ के साथ मार्थ के साथ मार्थ के साथ मार्थ की साथ मार्थ के साथ मार्थ की साथ मार्थ के साथ मार्थ के साथ मार्थ की साथ मार्थ के साथ मार्य के साथ मार्थ के साथ मार्य के साथ मार्थ के साथ मार्थ के साथ मार्थ के साथ मार्थ के साथ मार्य के साथ मार्य के साथ मार्थ के साथ मार्थ के साथ मार्थ के साथ मार्थ के साथ मार्य का साथ मार्य के साथ मार्

च-पन्त में, सब तथा राज्यों के वितीय सबयों की दृष्टि से, नियन्त्रक तथा महालेखा परीसक की भूमित भी सत्ययिक महत्वपूर्व है। तिवन्त्रक तथा महालेखा परीसक की निवृत्त राष्ट्रपति करती है तथा सहद द्वारा उसकी राज्यों के लेखा के सबय में कार्य तथा सिवार की ती पर नियन्त्रण सामालेखा है। राज्यों के लेखी पर नियन्त्रण तथा महातेखा परीसन का पूरा नियन्त्रण रहता है।

संघ तथा राज्यों के विभिन्न सवयों का अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तीनो, व्यवस्थापन, प्रशासकीय तथा वित्तीय क्षेत्रों में सघ सरकार को राज्य सरकारों की ग्रपक्षा ग्रत्यधिक ग्रधिकार प्राप्त हैं। सविधान निर्माताग्रो ने सघीय सरकार नो सशक रखने के लिए इन क्षेत्रों में पर्याप्त शक्तियाँ दी है । सधीय सरवार की स्थिति, उन स्थितिया म और अधिव शक्तिशाली हो जाती है, जब केन्द्र तथा राज्य सरकार एक ही राजनीतिक दल द्वारा स्थापित है। भारतीय राजनीति मे १८६७ के चतुर्व ग्राम-चुनाव के पूर्व लगभग सभी राज्यों भे (केरल को छोडकर) कांग्रेस सरकारें थी। केन्द्र में भी कांग्रेस दल सत्तारूढ था। केन्द्र तया राज्यों की सरकारों की नीतिया में एक्स्पता थी, भीर यदि किसी राज्य तथा केन्द्र में विवाद उठता था तो उसको दलीय प्रनुशासन के ग्राघार पर राजुनीतिक स्तर पर मुलभाया जाता था। परन्तु चौथे ग्राम-चुनाव के पश्चात पर्द राज्यो म गैर-काग्रेसी सरकारें स्थापित हुई। कई बार गैर-काग्रेसी सरकारों ने केन्द्रीय सरकार पर उसने प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार गा धाराप लगाया, विशेषकर दूसरे धाम चुनाव (१६५७) के बाद जब केरल में थी नम्बूद्रीपाद की साम्यवादी सरकार को, जिसे वर्खास्त किये जाने के मन्तिम क्षण तक केरल विधान-मण्डल मे बहुमत प्राप्त था, केन्द्र सरकार ने चर्लास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया। केन्द्रीय सरकार के इस कार्यकी देश म वडी धालोचना हुई। इसी प्रकार जब पश्चिम बगाल के राज्यपाल धर्मवीर ने १६६७ में श्री श्रजय मकर्जी की सरवार को बर्जास्त किया तब उसकी भी ग्रालोचना हुई ।

इस सन्दर्भ म विरोधी दलो द्वारा राज्यपाल की मूमिका की विशेष रूप स कडी धालोचना की गई। राज्यपाल की मूमिका के सदय म यह कहा गया कि राज्यपाल ने केन्द्र में सत्तारुढ दल के हितों को घ्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के विरुद्ध पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया।

धान में यह नहना उचित होगा वि विशो मी संयोव व्यवस्था की सफलता के लिए सस सरनार तथा राज्यों को सरकारों में सनी क्षेत्रों में पारस्वरिक्ष सहमाग होगा धति प्रावश्यक है। समझद जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, राष्ट्रीय एनता तथा राज्यों (इनाइयों) की स्वायतता के समझ्य तथा सामजस्य पर साधा-रित एक सिद्धान है। राष्ट्रीय पुनता की दृष्टि से सम की इकाइयों का यह कर्त-प्रहे कि प्रविद्धान के क्रिक्टर्स के क्ष्मण्ड करान्ये उसके ने न्यूपर तकों ने न्यूपर तकों ने न्यूपर तकों ने स्वायतता के सन्यु रेता विपरनवारों प्रवृत्तियों को रोखें। सभ के राज्यों की स्वायतता के सन्यु में दूसरी प्रोर केन्द्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों की स्वायतता का सविधान के प्रत्यांत पोधण करें। विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर राजनीतिक तथा वितीय क्षेत्रों म समीय सरकार को राज्यों के प्रति उदार और सहनवीत होना सावश्यक है।

सथ एव राज्यों में, राज्यपालों को नियुक्ति के विषय पर नेन्द्रीय सरकार को गभीरता-पूर्वक विचार करने के पश्चात् ही राज्यपाल को निमुक्त करना चाहिये। स्वस्य परम्परामी को स्थापित करने के लिए राज्यपाल के पद की निर्वासित या सेवा-निवृत्त राजनीतिज्ञो का शरणस्थान न बना दिया जाये । राज्य-पाल के पद पर, निष्ठावान निष्पक्ष, तथा उच्च बौद्धिक तथा नैतिक स्तर के

व्यक्तियों को ही मनीनीत करना चाहिये, क्योंकि, चौथे माम-चुनाव के पश्चात् परिवृतित राजनीति में राज्यपाल को नुद्ध परिस्थितियों मे प्रपने स्वेन्छाधिकारो को उपयोग मे लाना होगा । प्रशासकीय सुधार भाषीम ने सघ तथा राज्यो के सबस के बियद पर अपने प्रतिबंदन में राज्यपालों के स्वेच्छाधिकारों के सबध में सुफाव दिया है, कि चुंकि सदिघान मे राज्यपाल के स्वेच्छाधिकारो को परिमापित नहीं किया गया है, इसलिए यह कार्य धन्तर्राज्यीय परिचद की सौंपा जाना चाहिये ।

. सघ तथा राज्यों के विसीय सबधो के सन्दर्भ में सविधान में राज्यों के धाय के साधन सीमित है। झत राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए सघ सरवार पर निर्मर रहना पडता है, विशेषकर राज्यो नो पचवर्षीय योजनाम्रो के लिए अशास-कीय मुपार ब्रायोग ने सुमाव दिया है कि प्रत्येन पचवर्षीय योजना के ब्रायम्म मे राज्य के भाग के सातों को सघ भीर राज्यों के मध्य भावत्रयकतानुसार विमाजित करने के लिए एक वित्त प्रायोग की निवृक्ति होनी चाहिये।

भारतीय सविधान के दायरे में सब तथा राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग के लिए पर्याप्त प्रावधान है, जिसके धाधार पर सम्बाद के दोनो लक्ष्यों

-- राप्टीय एकता तथा राज्यों की स्वायत्तता को प्राप्त किया जा सकता है।

लोक सेवा ग्रायोग

भारतीय सिवधान में अनुच्देद ३१४ ने अनुसार सम के लिए एन लीन सेवा आयोग तथा प्रत्येन राज्य में तिए एन लीन सेवा आयोग तथा प्रत्येन राज्य में तिए एन लीन सेवा आयोग ना प्रावधान निया गया है। परमु अदि दो मा दो से प्रिवच नाज्यों ने विधान-महतो हारा ससद नो उनने लिए एन सनुत लोग तेवा आयोग स्वाधित नर मा प्रताव पारित नर प्रधिकृत निया जाता है, तो ससद इन राज्यों ने लिए एन सनुत्त लोग तेवा आयोग में स्वाधना मरेगी। निसी राज्य ने राज्यपाल ने निवेदन पर, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हों। ने पश्चात संधीय लोग सेवा आयोग उनत राज्य ने लोक सेवा आयोग अपना हों। ने पश्चात संधीय लोग सेवा आयोग उनत राज्य ने लोक सेवा आयोग ने नार्यों ने मरेगा।

सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल—सप लोग सेवा धायोग तथा समुक्त लोग सेवा धायोग ने घट्यक्ष घीर सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति न रता है। राज्य लोग सेवा धायोग ने प्रध्यक्ष तथा सदस्यों नी नियुक्ति राज्यपाल न रता है। सप लोग सेवा धायोग तथा राज्य लोग सेवा धायोग ने धाये सदस्य ऐसे होने चाहिए जो मारत सरनार मा निसी राज्य सरनार ने घ्रायोन नम से नम इस वर्ष तम सेवा-रत रहे हो।

त्त पर होन सेवा प्रायोग तथा सबुक्त प्रायोग ने सदस्यो नी सस्या राष्ट्रपति निर्मारित नरता है। सप लोन सेवा प्रायोग मे एक प्रध्यक्ष घोर सात सदस्य है। राज्य तीन सेवा प्रायोग ने सदस्यों की सरवा राज्यपात निर्मास्ति नरता है। सावारणतवा राज्य लोन सेवा प्रायोग ने सीन सदस्य होते हैं जिनम से एन प्रध्यक्ष होता है।

सप तपा राज्य लोन सेवा भ्रायोगों ने सदस्यों का नार्यनाल छ यर्प ना या सप लोन सेवा भ्रायोग ने सदस्यों ने ६५ वर्ष तपा राज्य लोन सेवा भ्रायोग के सदस्यों ने लिए ६० उपने की भ्रायु प्राप्त होने तक (त्रो भी इनमें से पहले ही वह लागू होगा) का है।

सप भीर राज्य सोक सेवा धायोग के सबस्यों को पदस्युति—सथ भीर राज्य सोन सेवा भायोग ने भ्रष्यक्ष तथा सबस्यों नो राष्ट्रपति दुराचार ने नारण भ्रादेश द्वारा, जबनि इस विषय पर सर्वोष्य न्यायालय ने ज्ञांच नरके राष्ट्रपति को भ्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, पदच्युत कर सकता है। आँच ने दौरान राष्ट्रपति सदस्य को निसन्वित कर सनता है।

लोक सेवा झायोग के ग्रम्थक्ष तथा किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा निम्न-विखित किसी कारण के ग्राधार पर भी पदच्युत किया जा सकता है, यदि,

क-वह दिवालिया हो, या

स—वह प्रपने कार्यवाल मे कोई प्रत्य सर्वतनिक कार्य स्वीकार कर सेता है, या ग—राष्ट्रपति की सम्मति मे वह व्यक्ति मानसिक या कारीरिक दुवंतता के

कारण प्रवने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो गया है 1 प्रतन्त्रेद ३१७ के बनसार यदि मारन सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा

स्त्रु-द्धः २६७ के स्तुतार याद मारण सरकार या निकार पाय सरकार कार या इनके वास्त्रे क्यि यदि किसी सिवार या करार से लोक सेवा झायोग के झण्यझ या सदस्य का सम्बन्ध हो तो दसको दुराचार समझा जायेगा, झौर इस झायार पर उसको परच्युन किया जा सकेगा ।

सा स तो ह तेवा प्रामोग के प्राप्त को , जुनदेद ह १६ के प्रनुतार , उसके कार्य के लक्ष के समान्त होने के प्रवास तथा या विश्वी राज्य सरकार के प्रयोग विश्वी पर एद पून नियुक्त कहीं विश्वा का सकता है। सम वहा राज्य को के से वा प्रायोग के सदस्यों को उनका कार्यकाल समान्त होने के पत्रवाद उसी यद पर पुत नियुक्त नहीं विश्वा का स्वता है। परन्तु सम तीक से वा प्रायोग के सरक्यों के नयंकाल समान्त होने पर उनको राज्य लीक देवा प्रायोग के प्रप्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। किसी राज्य लीक देवा प्रायोग के प्रप्यक्ष को उत्तरे नार्य- काल कर सामान्त होने पर तम लीक देवा प्रायोग के प्रप्यक्ष मा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उत्तरे नार्य- क्षा के स्वा स्वायोग के प्रप्यक्ष मा सदस्य के उत्तरे नार्य- क्षा के स्व प्रायोग के प्रप्यक्ष मा सदस्य के पत्र नियुक्त किया जा सकता है। उत्तर नार्य- क्षा के स्व प्रायोग के प्रप्यक्ष मा सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। राज्य तोक देवा प्रायोग के प्रप्यक्ष में, उनका क्षान्तिक समान्त्र मा त्र ति के प्रप्यक्ष या सदस्य के पत्र पर नियुक्त विया जा सकता है। विषय मा दा नियुक्त नहीं के सम त्या राज्य लोक तेवा प्रायोग के स्व प्रयाग को के तेवा प्रायोग के स्व स्व विद्या का सकते हैं। स्वय मा पर पर नियुक्त नहीं कि सम सकते हैं। स्वय ना तेव तेवा प्रायोग के स्व स्व सा सहते तेवा साची के तेवा साची के तेवा साची के तेवा साची के तेवा सा सा करते हैं।

सोक सेवा आयोग के कार्य-मितियो तथा क्षेत्राविकारों के तिमानन के स्वार एक साथे राज्य में, दी प्रकारों की सरकार होती है, केन्द्रीय (सर्वाध सरकार) तथा राज्य गरकारों आ स्वरंग विमिन वाणों के समामन के निष्ध योगी प्रकार की सरकारों के लिए पूचन चीक देवाओं की आवश्यक्त होती है। मारतीय दिवाल के सदर्गत भी, सर्वाय व्यवस्था होते के सारण, चीक सेवाओं की, मुस्त दे भी मार्ग में रखा गया है। यह निम्मानुवार है—

१ सघीय (वेन्द्रीय) लोव सेवाएँ-सघीय लोव सेवाएँ सघीय विषयो वे प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। बुद्ध सधीय विषयों के जदाहरण इस प्रकार है-विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, प्रायवर, डाव तथा तार व्यवस्था, रेल घादि । इन सेवाग्रो से सवधित ग्रधिकारियो की नियुत्ति, पदोनित, प्रशिक्षण, श्रनुशासन, सेवा-निवृत्ति ग्रादि से सम्बन्धित समस्त मामले वेन्द्रीय (संघीय) सरवार वे नियत्रण में हैं। मुख्यत इन विषयों के समय में केन्द्रीय सरकार संघ लोक सवा के परामर्श से नार्यं करती है।

२ राज्य लोग सेवाएँ--राज्य लोग सेवाब्रो नी स्यापना का उद्देश्य राज्य से संबंधित विषयों का प्रशासन करना है। राज्यों ने क्षेत्राधिकार में कुछ विषयों के उदाहरण निम्नलिखित हैं-राजस्व, शृधि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पणुपालन, पुलिस ग्रादि । इन राज्य-सेवाम्रो से सर्वाधा मधिकारियो की नियुक्ति, पदीनति, प्रशिक्षण, प्रतुशासन, सेवा निवृत्ति ग्रादि समस्त मामले राज्य सरवार के नियमण मे हैं। इन विषयो वे सवध मे राज्य सरकार राज्य-लोक सेवा आयोग की परामशं से काम करती है।

सधीय (वेन्द्रीय) यथा राज्य सेवाप्रो के धतिरिक्त, सविधान मे श्रिराल भारतीय सेवामी के लिए अनुच्छेद ३१२ वे अनगैत प्रावधान विया गया है। ये प्रखिल मारतीय सेवाएँ केन्द्र एवं रिज्यो दोनो के लिए समान रूप से हैं। सवियान मे दो प्रस्तित भारतीय सेवाग्री का उल्लेख है (1) भारतीय प्रशासकीय सेवा, तथा (11) भारतीय पुलिस सेवा । सविवान ने अनुच्छेद ३१२ (1) के अनु-सार ससद अन्य घोलन भारतीय सेवाओं की स्थापना बर सकती है, यदि वह चे बहमत से यह प्रस्ताव पारित करती है कि राज्टीय हिन में ऐसी सेवा की स्थापना गरना ग्रावश्यन है।

जैसा विदित हो चुका है, भारतीय प्रशासनीय सेवा, सघ तथा राज्यों के समान उपयोग ने लिए हैं। भारतीय प्रशासकीय तथा ग्रन्थ ग्रखिल भारतीय सेवाम्रोभे नियुक्ति सप सरकार सधीय लोक सेवा म्रायोग द्वारा म्रायोजित परीक्षाम्रो ने प्राचार पर नरती है। फिर सच सरकार इन प्रशासकीय ग्रधिकारियों को सच के विभिन्न राज्यों में नियुक्त गरती है। इन प्रशासकीय अधिकारियों का थोड़ा वार्षकाल केन्द्रीय सरकार की सेवा से भी सर्वावत रहता है। प्रशासकीय अधि-नारियों ने इस ब्रादान-प्रदान से सब तथा राज्यों दोनों को लाभ है, क्योंकि जहाँ इनके माध्यम से केन्द्रीय सरवार को राज्यों की स्थिति का ज्ञान होता है वही राज्यों को इन से केन्द्रीय सरकार की नीतियों तथा परियोजनात्रों के सबय में जानकारी प्राप्त होती है।

भारतीय प्रशासकीय सेवा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अधि-कारी 'सामान्यता-प्रधान' प्रणासकीय श्रधिकारी होते है ग्रयति, उनकी योग्यताग्री तथा सामान्य दक्षता की दृष्टि से उनते यह मंदेशा की वा सकती है कि वे विभिन्न प्रकार के पदो पर कार्य करने मे सक्षम हैं। उदाहरण स्कल्प मारतीय प्रभामकीय सेवा के प्रिकारियों की निमुक्ति कभी कानून व्यवस्था, कभी राजस्व, कभी वापार आणि कर होती है।

राग छ । मारतीय सविधात के अनुच्छेद ३२० के अन्तर्गत तीक सेवा धायोग के कार्य निम्नानुसाम होये---

१ सघ तथा राज्य लोक मेवा आयोग मध तथा राज्यों के अधीन विभिन्न

लोक सेवाघों म मरती करने के लिए परीक्षाधों का घायी बन करेंगे। र दो या दो से धायक राज्यों के धनुरोज पर उनके निए लोक सेवाघों में विभेष सीध्यना शास प्रत्याहियों की मुख्ती के लिए सब सोक सेवा घायोग द्वारा

सपुत्त योजनामो ना निर्माण तथा जियान्वयन करना । ३. निम्नलिखिन विषयो पर सथ लोक मेवा स्रायोग तथा राज्य सोक सेवा

ग्रायोग सघ तथा सद्यान राज्य सरकार को सलाह देंगे ।

(क) ऐसा कोई मी विषय जो धर्मितिक पदो पर धर्मितिक लोक सेवा में मरती के लिए उनको प्रेपित किया गया हो।

(स) उन मिद्धातो के सबन में जिनके झानार पर नियुक्तियों, पद्मेनित तथा

एक सेवा से अन्य सेवा में स्थानान्तरण करता है। (ग) लोक सेवाओं में अनुशासन-सक्वी मामले।

(प) सरनारी वर्मनारियों के उन दावों के सबस म जिनके मनुसार उनके विरद्ध सरनारी कार्यों के करने के बारण की यई कानूबी कार्रवाई के फलस्वरूप

व्यय वहन करना पडता है। (ह) निश्ची सरकारी कर्मचारी द्वारा धर्मनिक पद पर कार्य करते हुए यदि

त्रिमी क्षति का शिकार होना पड़ता है तो सेवा निवृति सबनी उसका दावा 1

४ सेवामो ने सबय में ब्रन्य नोई नाय जो सनद द्वारा सथ लोक नेवा श्रायोग

ै, त्राचा न स्वयं न अन्य नाइ नाय जा समय द्वारा स्वयं ताह नाया आयोग और राज्य निवान समा द्वारा राज्य सोह सेवा आयोग नो सौंबा गया है।

दत्त. तम लोन सेवामो ने तिए सथ लोन हेवा मानोग तथा राज्य लोह सेवामो ने तिए राज्य लोन हेवा मानोग से सर्वधित सरकार को नुद्धी, नियुक्ति, र् पर्दोजिं, स्थानान्तरम, मनुसुन्तन, रावों मादि मामलो मे परामर्स लेना मात-मक है।

अनुरुद्धेर २२० वे अनुसार सनिधान राष्ट्रपति तथा राज्यपातो को ऐसे नियम ननाने के लिए अधिष्टत करती है, जिनमें उन निषयो का उल्लेख होगा जिन पर स्रोक संदर आयोग से परामर्थ सेने की आवरयकना नहीं होगी। इस तरह. ग्रनुष्वेद २२० के प्रनुसार, पिछडे वर्षों, ग्रनुपूचित जातियों के पक्ष में नियुक्तियों या पदी को सुरक्षित करने के लिए लोक सेवा श्रायोग से परामर्थ लेने की कोई श्रावश्यकता नहीं हैं। परन्तु श्रनुष्टेद २२० के धन्तमंत यह ग्रावश्यक है कि इस प्रकार के नियमों को जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उन विषयों को निर्धारित करने में लिए बनाये जाते हैं जिनके सवय म लोक सेवा श्रायोग से रामार्थों तेत ग्रावश्यन नहीं हो जे उन्हें सबिवत ब्यवस्थापिका (सय के लिए ससद तथा राज्य के लिए विधान सभा) के समक्ष रखा जाये। ससद या राज्य विधान समा को ऐसे नियमों म परिवर्तन करने का पूर्ण श्राधकार प्राप्त होगा।

सिवधान के अनुष्डेद २२३ के अनुसार सम आयोग तथा राज्य आयोग का यह कर्तव्य है कि प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को प्रस्तुत करें जिससे उनको अपने कार्यों का विवरण देना होगा। । तरपचात राष्ट्रपति और राज्यपाल तुरत ऐसे प्रतिवेदन को ससद तथा राज्य विधान मटक समस्य लेक के साथ रहेगा जिसमें कारणों को तहत उन प्रकरणों का उल्लेख होगा, जिन पर लोक सेवा आयोग के मुकाव स्थीवृद्ध नहीं किये गये।

स्रोक सेवा ध्रायोग के सदस्यों को स्वतप्रता—लोग सेवाध्यों में नियुक्ति प्रत्याधियों की योग्यताध्रों के ध्राधार पर हो गी जानी चाहिए, जिसने प्रधासन में
स्वच्छता तथा दशता अगत की जा सगे । यदि प्रधासन में योग्य ध्रीयकारियों की
नियुक्ति नहीं होती है तो प्रधासन में इसने कत्तरवरूप उत्पन्न हुई शुदियों से समस्त राष्ट्र गी प्रगति श्रवचद्ध हो सबती है। प्रतिएव, प्रधासकीय प्रधिकारियों की
योग्यता के ध्राधार पर भरती, नियुक्ति तथा पदोन्तित धादि के लिए एग स्वतन निष्पत तथा निष्ठायान सस्या का होना ध्रतिमावययन है जो बाह्य प्रमावी से स्वतन रहकर, निष्पत्रतापूर्वक प्रयने कार्यों वो कर सकेगी। मारतीय सविधान निर्माताग्रों ने इन मुद्दों की दृष्टिकीण से लोक सेवा ध्रायोग के सदस्यों की स्वतन्नत्रता ने लिए निम्नतिवित्रत प्रावधान किये हैं।

्रीसदस्यो का कार्यवाल सविधान द्वारा निर्धारित है, छोर किसी सदस्य को पुन वसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

२ लोक सेवा के अध्यक्ष या सदस्य को सवियान में निर्धारित प्रक्षियानुसार ही पदस्युत किया जा सकता है। अनुस्त्ये द १७ (१) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायानय को लोन सेवा आयोग के किसी सदस्य के दुराचार के साम्यत्ये की प्रतिवाद किये जाने पर प्रति सर्वोच्च स्थायानय जीच करने के उपरात राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन देता है जि उक्त सदस्य पर लगाया दुराचार का धारीप सत्य है, तो राष्ट्रपति एक धार्यक द्वारा उस सदस्य को पदस्युत कर सकता है।

रे किसी भी सदस्य के पद से सम्रधित शर्ती को उसके कार्यकाल में उसके चुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता है। लोक सेवा झायोग के सदस्यों के वेतन तथा मत्ते भ्रीर श्रचासकीय व्यय सचित निवि पर मास्ति हैं। भ्रतएव सभ भ्रीर राज्य लोक सेवा श्रायोगों के सदस्यों ने बेतन तथा मत्तों के सबध में ससद तवा राज्य विधान महतों में मतदान नहीं किया जा संवता है।

Y सुप्त प्रीर राज्यों के लोक सेवा आयोगों ने प्रध्यक्षों और सदस्यों को मुख प्रपंतादा को छोडकर, पुन उसी पर या किसी सरकारी पद पर निवुक्त नहीं क्या जा सकता है। ये प्रपंताद निम्नानुसार हैं।

(क) राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष, सब लोक सेवा ब्रायोग के अध्यक्ष या

सदस्य के पद पर नियुक्त किया जा सकता है !

(स) किसी राज्य लोक सेवा प्रायोग के सदस्य को मध लोक सेवा प्रायोग के प्रध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त क्या जा सकता है, या उसे उसी या प्रभ्य राज्य लोक सेवा प्रायोग के प्रध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

(ग) सघीय लोक सेवा धायोग के सदस्य को सघ लोक सेवा धायोग या

किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

१ नीक सेवा भागोगो द्वारा अपने कार्यों को निष्पसनापूर्वक तथा स्वतनता-पूर्वक न रने के लिए सविधान निर्माताओं ने इनके सदस्यों की <u>परिषम्बता</u> पर भी वल दिया। इस कारण उन्हाने सच लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सेवा निवृत्त होने वी आयु क्रमण <u>पैसल</u> और साठ वर्ष निर्माखित की है।

मारत में तोक देखा सारोगों के लिए सविधान मं प्रावधान करने हैं इनते ।

एक विषेध महत्व प्राप्त हुमा है। इन्लंध तथा समरीवा मं तोक तेवा धायोगों को स्वाप्ता व्यवस्थानिक हारा पारित कानून के बाबार पर हुई है। तथारि, मारतीय सिवान में, तोक तेवा धायोगा के सबध में कित्यम महत्वपूर्ण ग्रहतीयों के स्वप्ट उत्तेख की प्रमुक्तियों में, तथारे मं तक्षेत्र मं मारतीय सिवान में, तोक तेवा धायोगा कि तथा महत्वपूर्ण ग्रहतीयों के स्वप्ट उत्तेख की प्रमुक्तिया पर विशेष राज्यों में, स्वप्ता मं तक्षेत्र में तथा मं तक्षेत्र प्राप्त में, स्वप्ता मं तक्षेत्र में प्राप्त में स्वप्त मं तक्षेत्र प्राप्त में तथा प्राप्त ने स्वप्त में की स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में तथा प्राप्त ने स्वप्त में स्वप्त स्वप्त में स्वप्त में

ग्रन्थानुकमणिका भइयर एस० पो० एण्ड श्रीनवासन बार०—'रट्डीज इन इण्डियन डेमोर्रसी'

(भ्रलाइड पब्लिशसं, बम्बई, १६६४) श्रवलेभा बरोविच सी० एच०-'वा स्टीटयूशनल डेनलपमेन्ट इन इण्डिया' (भ्रावसफोडं युनि० प्रेस, १६५७) बेनजीं ए० सी०-'दी मेकिंग ब्राफ द वान्स्टीट्यूशन जिल्द-र (ए० मुक्जी एण्ड बो० बलबत्ता, १९४८) बेनजी डी॰ एन०-'सम ग्रास्पेक्ट्स भाफ द इण्डियस नान्स्टीट्यशन' (दी बल्डें प्रेस, बलकत्ता, १६६२) बेनजों श्री • एन • — 'ग्रवर फण्डा मेन्टल राईट्स' (द वर्ल्ड प्रेस, कलकत्ता, १९६०) बस डो॰ डो॰-'वमे-टी मान दि नान्स्टीट्यूशन माफ इण्डिया, जिल्द--१, २, (एस० सी० सरवार एण्ड सन्स वलकत्ता १६६४) भाग्भरी सी॰ पी॰--'पवितक एडमिनीस्ट्रेशन' (जय प्रवाशनाय एण्ड वी० १६६०) बाइस लाई जे॰ - 'माडर्न डेमोग्रेसी, जिल्द-- २. (भेवभिलन एण्ड वो, न्यूयार्व १६२६) बाइस लार्ड जे०-'दि श्रमेरियन कामनवेत्थ, जिल्द-१', (भेकमिलन एण्ड को, न्युबार्क, १८६८) चागना एम० सी-'द इनडिविज्युल एण्ड द स्टेट' (एशिया पब्लिशिंग हाऊस, १६५८) कारियन ई० एस०-'द डोक्टाइन भाफ ज्युडिशियल रिब्यु' (प्रिन्सटन, १६१४) कार्यान ई० एस०—'द कोटं स्रोबर दि कान्स्टीट्यूशन' (प्रिन्सटन, १६३८) दास एस० सी०-'द कान्स्टीट्यूगन भ्राफ इण्डिया, ए कम्प्रेटिव्ह स्टेडी, (चैतन्य पहिलाशिंग हाउस, मलाहाबाद, १६६०) वयाल एस॰—'दि नान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया' w/ (मलाहाबाद ला एजेन्सी, १६६४)

```
( $$$ )
```

हायसी ए० वी०—'ता माठ दि कालसीट्यूयर' (भेकमियन एएड को, निमिटेट, सन्दन, १६६६) फाईनर एख०—'प्योरी एटट प्रेविटस माठ माटन गर्बमेन्ट'

काइनर एवं के — स्थात एक प्राप्त असर मान्य प्रमान (हेनरी होन्ट एल्ड को क्यूयार्क १६४०)

(हनरा हा॰= एस्ट काठ न्यूयाक (१६२०) शाडींगच डी॰ झार०—'इस्डियन प्लानिक एष्ट व्यानिक कमीयन' (हरानड लाक्नी इल्स्टोट्यूट म्राफ्न पानिटिकल सादस्स

ग्रहमदाबाद, १६४८)

गबेन्द्रगड़कर यो॰ बो॰—'ता तिवर्डी एन्ट सोहित्यत्र अस्टिश' (एकिया पब्लिकिन हाउम बम्बई, १९६४)

गार्नर हे व हत्यपु--पीनिटिक्य सादम्य एक गर्वपेन्ट

(धमरीकत दक्ष कमानी, न्यूबार्क, १६३२)

गेटेस ग्रार० सी०-पोलिटिङ र साइन्न

(द वन्डें प्रेस कनकत्ता, १६५४)

म्बेडहिल ए०—'दि रियब्लिक ग्राफ इंग्डिया' (तन्दन, १८५१)

भीत्स एव० भार०—'द दिव्य कान्स्टीट्ट्यून'

प्राप्त एवर आर्थ--- ५ ।त्र इस काल्टाच्च्यन (बार्ज एवन एवट धनविन सिमि० सन्दन, १६३०)

गुप्ता एम० औ०--'म्रान्वेन्ट्स भार दि इण्डियन नामसीट्यूमत'

(सन्द्रल बुक डीवो, प्रलाहाबाद, १८६४ एवं १९५६ दोनो) हास्त्रवा जी० ए०—'डिनेमान भाक डेनोइंडिक पालिडिक्स द्रल इस्टिया'

(भानक पेरेस, बस्बर्ट, १८६६) हस्सूमनी ए० पी०-'सम प्रोन्तेस्स ब्राफ एडमिनीस्ट्रेटिव सा इस इस्टिया'

(एमिया पन्तिमित हाउन बन्दर्ड, १९६४) हिंदायन उन्ताह एम॰—'मेरीजेमी दून इन्टिया एप्ट दि प्टूडिशियल भीतेस'

(एपिया पब्लिमिस हाउस, बस्दर्श, १८६५) बेना बी॰ बी॰—'पानियासेन्से बसेटीड दन इन्टिया'

(मार्टान्टिक्त दुक एवरती, क्लक्सा, १९६६) बैनिस्त सरक भारक-पार्टिक्टर

(क्रेम्बिज सुनिवर्सिटी प्रेस, १६५३)

विनाब सर॰ माई०--'सम करेक्टरिन्ड, माठ काल्ट्राट्यूनन माठ इंग्टिया' (माकाकोड युनि० मेठ १६१२) वेनिग्ब सर० माई०--कडीनेट, मुक्तिल्ट

(केम्बन युनि० प्रेस १६५६)

```
( ३३४ )
```

जोशी जी० एन०—'ग्रास्पेतट्स ग्राफ इण्डियन कारस्टीट्यूशल ला' (युनिसिटी ब्राफ वम्बई, १६६५) जोशी जी० एन० - दि बास्टीटयुशन धाफ इण्डिया' मेकमिलन एण्ड को० १६४२) कारजी एम० सी० जे०—'बास्स्टीटयशन भ्राफ इण्डिया' (मेट्रोपोलिटन युक कम्पनी, देहली १६५०) कपुर ए० सी०—'सेलेक्ट बान्सटीटयुशन्स' (बाद एण्ड को० देहली, १६६०) कश्यव एस० सी०-'टि पालिटियम ग्राफ डिफेक्शन' (पज्लिशंड ग्रण्डर दि घारपीसिस घाफ इन्स्टीटयुट) साल ए० बो०-'दि० इण्डियन पालियामेन्ट' (चैतन्य पर्व्लिशिंग हाउस मलाहाबाद १६५६) ास्त्री एच० जै०-'रिवलेक्शन्स ग्रान दि वान्स्टीटयशन' (भेनचेस्टर यूनि० प्रेस, १६५१) लास्की एच० जे०—'ए ग्रामर भ्राफ पालिटिक्स' (जार्ज एलेन एण्ड घनविन लिमि० लन्दन, १६३०) लास्की एव० जे०-'पालियामेन्टी गुर्वमेन्ट इन इंग्लैण्ड' (जाई एलेन एण्ड अनविन लिमि० लन्दन ११३८) लो सर० एस०—'द गर्वमेन्ट ग्राफ इंग्लैण्ड' (ग्ररनेस्ट वेन लिभि॰ लन्दन, १६३४) मैकाईवर घार० एम०-'द माडने क्टेट' (मानसफोर्ड प्रेस, लन्दन, १६२६) में सर० टो॰ इ॰—'ए॰ ट्रीटोज ग्रान दि ला, प्रिविलेज, प्रोसिडिंग्ज एण्ड युजेज ग्राफ प्रालिमाग्रेस्ट' (बटरवर्थ लन्दन, १२वा सस्करण) मिल जै॰ एस॰—'ग्रान रिपजेन्टेटिव्ह गवर्मेन्ट' (लागमेन्स ग्रीन एण्ड को० लब्दन, १६६१) मिल जे० एस०-'ग्रान लिवटी' (बेसित ब्लेनबेल, धानसफोडं, १६४८) कार्नेनिक बी० बी० - 'फीर्य जनरल इलेक्शन प्रोबलेम्स एण्ड पोलिसीज' (सालवानी पश्लिशिंग हाउस, १६६७) मीरिस जोन्स इल्यू॰ एच०-'पालियामेन्ट इन इण्डिया' लागमेन्स ग्रीन एण्ड की० लन्दन १९५७)

```
5-1982 (111)
              म्पर भार०-- 'हाऊ दिटेन इज गवनंड'
                            (लन्दन, १६३८)
               मशी के॰ एम॰—'दि प्रेसिडेण्ट घण्डर दि इण्डियन कान्सटीटयुगन'
                               (भारतीय विद्या भवन, बम्बई, १६६३)
               नरसिंह चार के॰ टी॰—'दि क्वीन्टइसेन्स ग्राफ नेहरू'
                                    (जार्ज एलेन एण्ड धनविन, लिमि० लभ्दन,
               म्यूभेन सिगमण्ड-भाइन पोलिटिकल, पार्टीज
                               (यूनिवर्सिटी ब्राफ शिकागो, ब्रेस, १६५६)
               पालमर एन० डो॰—'दि इण्डियन पोलिटिक्ल सिस्टम'
                                 (जार्ज एलेन एण्ड धनविन, लन्दन, १६६१)
               पायली एम॰ बी०- 'इण्डियाज कान्स्टीटयुशन'
                                 (एशिया पब्लिणिंग हाउस, बम्बई, १६६२)
               राय के॰ बी॰-'पालियामेन्टी हेमोब्रेसी माफ इण्डिया'
                             (दि वर्ल्ड प्रेस, कलकत्ता, १६६०)
               सन्यानम के०-'टान्सीशन इन इण्डिया'
                             (एशिया पब्लिशिग हाउस, बस्वई, १६६४)
चीवस ए
               शर्मा एम॰ पो॰--'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ध्यौरी एण्ड प्रेक्टिस'
                               (किताय महल भलाहाबाद, १६६०)
               एम • पी • शर्मा- 'दि गर्वमेन्ट छाफ इण्डियन रिपब्लिक'
                               (किताव महल, घलाहावाद, १६६१)
हाल्लपा
                शर्मा एस० ग्रार०-- 'दि सुप्रिम कोट इन दि इण्डियन कान्स्टीटयुशन
                                  (राजपास एण्ड सन्स, देहली, १६५६)
हस्सूमन
                श्रीनिवासन एन०—'डेमोक्रेटिक गवमेंन्ट इन इण्डिया'
                                 (द वर्ल्ड प्रेस लिमि० कलक्ता. १९५४)
                स्टेबर्ट एम॰—'ब्रिटिश एप्रीच ट् पालिटिक्ल एनेलीसिस'
```

हिदायत (जार्ज ऐलन एड धनविन लिमि॰ लन्दन, १६३६) जेना वं

मूरी एस०-११६२ इतेवशनस ए पोलिटिनल एनेलीसिस मधा परिलकेशनस, न्य देहली, १६६२) टोपे टी॰ के॰—'दि कानस्टीट्यूशन आफ इण्डिया'

(पापूलर प्रकाशन, बम्बई, १६६३) जैनिप्ज व्हियर के ब्री - 'फेडरल गवर्मेन्ट' (ब्राक्सफोर्ड युनिवसिटी प्रेस, लन्दन, १६५६)

जैनिग्ज

दावसी १

फाईनर

गाडगिल

गजेरद्रगः

मार्ने र है

गेटेल प्र

•लेडहिं

जैनिक

संदर्भ ग्रिमिलेख तथा मूल स्रोत

द्यात उण्डिया रिपोर्टर । बारम्टीटयाण्ट ग्रमेम्बली डिवेटम १९४६-४६ ।

हाफ्ट कान्स्टीटयुणन ग्राफ इण्डिया

इलेक्शन कमीशन्स रिपोर्ट आन दि फस्ट जनरल इलेक्शन इन इण्टिया, जि॰ १-२ (१९५१-१९५२ न्य देहली, १९५५)

इस्टीमेट बमेटी (सेन्ट्रन) रिपोर्ट न० २ (१६५०-५१)

इस्टीमेट रमेटी (सेन्टल) स्पिट न० ६. (१६५३ ४४) द्दरीमेड बमेटी (मेन्टल) रिपोर्ट न० २० (१६५७-५६)

इण्डियन इलेक्शन कमीशरम, रिपोर्ट ग्रान द सेकेन्ड जनग्ल इलेक्शनस इन इण्डिया

इस १६४७-४८ देहली नेहरज स्पीचेज, १९५६-१९५७, जित्द-३,

(द पब्लिकेशन डिबिजन मिनिस्टी द्याफ इन्फारमेसन एण्ड

ब्राडरास्टीम गर्वमेन्ट म्राफ इण्डिया १६४८) से गन्ड फाइन इयर प्लान--- डाप्ट ब्राख्ट लाइन, फरनरी, १९५६

सुत्रिम बोर्ट रिपार्टस

दि नान्स्टीट्यूसन माप इण्डिया १९६३

दि इण्डियन प्रोविजनल पालियामेण्ट डिवेट्स १६५०-१६४२ इण्डिया बीट्स-ए सीर्स बुक मान इण्डियन इलेक्शन्स,

(सम्गादित—ग्रार चन्दीदास)

डब्ल्यू मोर हाउस, बलाकं एण्ड छार फान्टेरा पापुलर प्रशासन बम्बई १६६=

सन्दर्भ पत्रिकाएँ तथा समाचार पत्र

ए'सी, प्रलं सी०-मिनिस्टीयल रिसपान्म निटीज दि उण्डियन रिव्यु, जनवरी, १६६०

वैनर्जो डी॰ एन॰-'पोजिसन श्राफ द प्रेसिडेण्ट खाफ इडिया'

(माडने रिव्य दिम ० १६५०)

चौधरी पी० सी०-'इथिनस एण्ड इलोन्टोरल उमोक्नेसी' (इन सेमानार न० ३० परवरी १९४६)

(दि वाइटल स्नीचेज एण्ड डान्यूमेन्टस ग्राफ दि है० जित्द-र

(दि इण्डियन रिव्य मिनम्बर १६५६)

न० १८ जुलाई, १४, १६६२)

(दि इण्डिपन रिव्यू नवस्पर १६६४)

(जिल्द ७ मार्च २४, १६६८) सप्र पो० एन०--'इन दि जरनल ग्राफ पब्लिक एटमिनिस्टेशन'

(सेमीनार नं० ३०, फर० १६६२)

रोस के० धार०-'इण्डियाज १६४७ इलेक्जन्य-पार इस्टर्न सर्वे. २६. मई १६४०। सबसेना के र सीर-'विदर दृष्डियन हैमोब्रेसी सोजियेन्स्ट कांग्रेसमेन'

मसाती एम० एल०-'पार्टी पोलिटिक्न इन इण्डिया'

रेडी एम० के०--'पीलिटिवल पार्टीज इन इण्डिया'

(ब्रस्ट्बर, १६४८) सोमजी ए० एव०-'मोटीवेशन एण्ड श्रोपेनण्डा'

(सेमीनार नं० ३२ फरवरी, १६६२)

डायसी १ काईनर

गाडगिल

गतेन्द्रमः

गार्ने र वे रेटेल घ

। लेडहिर

ग्रीव्स ए गुप्ता ए

हास्लपा

हस्सूमन हिंदायर

जेता बं

जैनिक

जेनिग्ज

जैनिक

धर्मा के०-'मनी एण्ड घोटम'



KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

NATURE